न्यायधर्मसभा

न्याय संदर्भ

Justice References

न्याय को ही राष्ट्रीय धर्म बनाओ!
समस्त राष्ट्रीय समस्याओं से छुटकारा पाओ!!

लेखक

श्री अरविन्द 'अंकुर'

न्यायधर्मसभा

जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार (उत्तरांचल)

फोन : 01334 - 244760, मोबाइल : 09319360554

वेबसाइट : www.nyayadharmsabha.org

ईमेल : info@nyayadharmsabha.org

न्यायसंदर्भ

1) भारतीय संविधान के ध्येय और उद्देश्य :- *हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को 'सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार-अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता (पारस्परिक प्रेम) बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26-11-1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् 2006 विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।* **-(भारतीय संविधान की उद्देशिका)**

2) *सभी मनुष्य जन्म से ही गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से स्वतन्त्र और समान हैं। उन्हें बुद्धि और अंतश्चेतना प्रदान की गई है। उन्हें परस्पर भ्रातृत्व की भावना से कार्य करना चाहिए।*

-(संयुक्तराष्ट्रसंघ द्वारा अंगीकृत मानवाधिकार की घोषणा, 1948)

3) *राज्य विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों (कार्यों) में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।*

-(भारतीय संविधान, 44वाँ संशोधन 1978, अनुच्छेद 38)

4) *जब तक प्रत्येक सदस्य की गरिमा की रक्षा न की जाए तब तक बंधुता की स्थापना नहीं हो सकती। अतएव उद्देशिका में यह कहा गया है कि भारत में राज्य व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करेगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान मूल अधिकार की प्रत्याभूति देता है जिससे कि यदि उसके अधिकारों का हनन होता है तो वह अपने न्यूनतम अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवृत्त करा सकता है। यह ध्यान में रखते हुए कि यदि व्यक्ति को अभाव और दुःख से छुटकारा न मिले तो ये प्रवर्तनीय अधिकार उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। संविधान के भाग-4 में बहुत से निदेश सम्मिलित किए गए हैं जिनमें राज्य को दिशा निर्देश दिया गया है कि वह अपनी आर्थिक और सामाजिक नीतियों की इसप्रकार रचना करे कि ''पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समानरूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो'' {अनुच्छेद 39(क)}, ''काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएँ हों'' {अनुच्छेद 42}, और ''शिष्ट जीवनस्तर और अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएँ तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त हों'' {अनुच्छेद 43}। हमारे उच्चतम न्यायलय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि गरिमा का अधिकार मूल अधिकार है।*

-(आचार्य डा. दुर्गादास बसु, भारत का संविधान : एक परिचय)

5) *भूतकाल में लोकतन्त्र को राजनीतिक लोकतन्त्र के रूप में ही पहचाना गया जिसमें मोटे तौर से एक व्यक्ति का एक मत होता है। किन्तु मत का उस व्यक्ति के लिए कोई महत्त्व नहीं होता जो निर्धन और निर्बल है या ऐसे व्यक्ति के लिए जो भूखा है और भूख से मर रहा है, राजनीतिक लोकतन्त्र अपने आप में पर्याप्त नहीं है। उसका आर्थिक लोकतन्त्र और समानता में धीरे-धीरे वृद्धि करने के लिए और जीवन की सुख-सुविधाओं को दूसरों तक पहुँचाने के लिए तथा सभी असमानताओं को हटाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।* **-(जवाहरलालनेहरू; संसदीय लोकतन्त्र पर गोष्ठी में उद्घाटन भाषण; 25/02/1956)**

6) *यदि राजनीतिक लोकतन्त्र का आधार सामाजिक लोकतन्त्र नहीं है तो वह नष्ट हो जाएगा। सामाजिक लोकतन्त्र का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है वह जीवनपद्धति जो स्वतन्त्रता, समानता और बंधुता को मान्यता देती है। जिसमें ये तीनों अलग-अलग न माने जाकर त्रिमूर्ति के रूप में माने जाते हैं। वे इस त्रिमूर्ति का एकीकरण हैं। इस अर्थ में यदि एक को हम दूसरे से अलग कर दें तो लोकतन्त्र का आशय निष्फल हो जाएगा। स्वतन्त्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, समानता को स्वतन्त्रता से पृथक नहीं किया जा सकता। इसीप्रकार स्वतन्त्रता और समानता को बंधुत्व से विलग नहीं किया जा सकता।*

-(डा. भीमराव अम्बेडकर; संविधानसभा के समापनभाषण में)

7) सामाजिक न्याय मूल अधिकार है। सामाजिक न्याय सामाजिक ढाँचे के विभिन्न समूहों और/या वर्गों या व्यक्तियों के प्रतिद्वन्दात्मक दावों या हितों में विधि द्वारा सामंजस्य पैदा करके सामाजिक असंतुलन को दूर करने का व्यापक रूप है जिसके द्वारा ही लोक कल्याणकारी राज्य बनाना संभव होगा। इन तीनों को विधिसम्मत शासन के अधीन सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और राजनीतिक न्याय देकर सुरक्षित एवं संरक्षित किया जाना है। सही अर्थ में लोकतन्त्र की स्थापना तभी हो सकेगी जब स्वतन्त्र और सभ्य जीवन के लिए आवश्यक न्यूनतम अधिकार समुदाय के प्रत्येक सदस्य को सुनिश्चित हो जाते हैं। (संविधान की) उद्देशिका में व्यक्ति के इन आवश्यक अधिकारों का उल्लेख किया गया है।

-(डा. दुर्गादासबसु, न्यायाधीश; भारत का संविधान : एक परिचय)

***8) आर्थिक न्याय :-** निदेशक तत्त्वों के अनुसार राज्य का उद्देश्य जिनके पास धन है उनसे छीनकर निर्धनता का उन्मूलन करना नहीं है बल्कि राष्ट्रीय धन और संपत्ति-स्रोतों में अनेक गुना वृद्धि करके उनका उन सभी लोगों में साम्यपूर्ण वितरण करना है जो उत्पादन में अपना अभिदाय करते हैं। जिस सीमा तक हम उस उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे उस सीमा तक हमारे इस उपमहाद्वीप में आर्थिक लोकतन्त्र स्थापित होगा। संक्षेप में आर्थिक न्याय का लक्ष्य आर्थिक लोकतन्त्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। आर्थिक न्याय का आदर्श प्रतिष्ठा की समानता लाना और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा और अवसर की असमानता को दूर करके जीवन को सार्थक और सर्वोत्तम जीने योग्य बनाना है।*

-(डा. दुर्गादासबसु, न्यायाधीश; भारत का संविधान : एक परिचय)

***9)** यद्यपि मैं धर्म के नियमों की निन्दा करता हूँ, इसका अर्थ यह न लगाया जाए कि धर्म की आवश्यकता ही नहीं। इसके विपरीत मैं 'बर्क' के कथन से सहमत हूँ, जो कहता है : "सच्चा धर्म समाज की नींव है, जिस पर सब नागरिक सरकारें टिकी हुई हों।"*

परिणामतः जब मैं यह अनुरोध करता हूँ कि जीवन के ऐसे पुराने नियम समाप्त कर दिए जाएँ, तब मैं यह देखने को उत्सुक हूँ कि इसका स्थान 'धर्म के सिद्धान्त' ले लें, तभी हम दावा कर सकते हैं कि यही सच्चा धर्म है। वास्तव में, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि धर्म आवश्यक है। इसलिये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि धर्म में सुधार को मैं एक आवश्यक पहलू मानता हूँ।

आपको अपने धर्म को बचाने को एक नया सैद्धान्तिक आधार देना होगा, जो स्वतन्त्रता (सत्य), समानता (न्याय) और भाईचारे (प्रेम) के, संक्षेप में, प्रजातन्त्र के अनुरूप हो। मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ। लेकिन मुझे बताया गया है कि ऐसे धार्मिक सिद्धान्त जो स्वतन्त्रता (सत्य), समानता (न्याय) और भाईचारे (प्रेम) के अनुरूप हों, उन्हें विदेश से लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसप्रकार के सिद्धान्त उपनिषदों में वर्णित हैं। ***-(डा. भीमराव अम्बेडकर, सम्पूर्ण वाङ्मय, खण्ड : 1)***

10)** जो गरीब लोग इधर-उधर भटक रहे हैं, जिनके पास कोई काम (रोजगार) नहीं है, जिन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती और जो भूख से मर रहे हैं, जो निरन्तर कचोटने वाली गरीबी के शिकार हैं वे संविधान या उसकी विधि का गर्व नहीं कर सकते।* ***-(डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति का भाषण)

11)** आज सबसे बड़ी समस्या इस राष्ट्र में गरीबी की है। मेरा प्रयास रहेगा कि सबको न्याय मिले। जो पिछड़ गए हैं, उन्हें रोजगार के अवसर मिलें। जो सदियों से तिरस्कृत रहे हैं, उनका कल्याण हमारा लक्ष्य बने।* ***-(लालबहादुरशास्त्री : प्रधानमन्त्री के रूप में प्रथम भाषण, 9/6/1964)

***12)** गरीबी मानवाधिकारों का उल्लंघन है। केवल आर्थिक आय ही गरीबी का कारण नहीं है। मानवाधिकार की दृष्टि से गरीबी को हम मूलभूत मानवाधिकारों की उपेक्षा अथवा उल्लंघन के रूप में परिभाषित करते हैं।*

-(अर्जुन के. सेनगुप्ता : मानवाधिकारविशेषज्ञ, राज्यसभासदस्य, दि हिन्दू, 18/11/05)

13) *कोई भी व्यवस्था तब तक ही स्वयं को जीवित रख सकती है, जब तक वह बदलते समय और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप यह साबित न कर दे कि इसमें आम आदमी की जरूरतों को पूरा करने की इच्छाशक्ति है। वह देश जहाँ राष्ट्र का एक बहुसंख्यक वर्ग दाने-दाने को तरस रहा हो, जहाँ वह महज जीने के लिए सारी ऊर्जा से जूझ रहा हो, वैसा वर्ग कुछ नेताओं के विलासितापूर्ण जीवन को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। ऐसे में कोई भी पार्टी या संविधान जब तक साधारण आदमी की जरूरतें नहीं पूरी करेंगे, समय का अन्तराल उनके अस्तित्व को स्वयं समाप्त कर देगा।*

-(इन्दिरागाँधी : प्रधानमन्त्री; 28 अक्टूबर, 1975, कॉमनवेल्थ सांसदों के समक्ष दिल्ली में दिये गये भाषण का अंश)

14) *यह संसदीय लोकतन्त्र और संविधान समय के अन्तराल में औंधे मुँह जा गिरा है। अतः न तो आज कोई राजनीतिक पार्टी ही ऐसी है, जो जनता की भलाई की सोच सके और न ही यह संविधान इतना प्रभावशाली है कि वह ऐसा करवा सके। कब तक यह खेल चलता रहेगा? क्या हमारे पास इतनी भी अक्ल नहीं कि इसका निदान हम खोज सकें? इस बिन्दु पर हम संविधान को संशोधित क्यों नहीं करते? क्या हमारा आचरण विक्षिप्तों जैसा आचरण नहीं है। क्या हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पागल हैं। इस प्रश्न का किसी के पास कोई जबाव नहीं। सब लोग स्वार्थ में अन्धे हैं और जनता तटस्थ है। भारत के वे लोग जिन्होंने प्रजातान्त्रिक प्रणाली के प्रचलित ढंग को अपने स्वार्थ के लिए देश को लूटने का पर्याय बना दिया है, उनके षड्यन्त्रों को विफल करना होगा, यह वक्त की पुकार है। मूल ढाँचे सहित अगर संविधान न बदला गया, तो दीमकों के कारण यह राष्ट्र तबाह हो जाएगा।*

-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 06/09/05)

15) *अपनी गिरी हुई दशा में हम यह मान लेते हैं कि कानून जो कहता है उसे करना हमारा फर्ज है, ध र्म है। अगर लोग एक बार यह समझ लें कि जो कानून हमें अन्यायकारी जान पड़े उसको मानना नामर्दी है तो फिर किसी का जोर जुल्म हमें बाँधने में समर्थ नहीं हो सकता। यह स्वराज्य की कुंजी है। यह मानना नास्तिकपन और वहम है कि बहुसंख्यक की बात अल्पसंख्यक को माननी ही चाहिए। ऐसी मिसालें हजारों मिलेंगी जिनमें बहुतों की कही हुई बात गलत और थोड़ों की कही हुई बात सही साबित हुई है। दुनिया में जितने भी सुधार हुए हैं सभी थोड़े से आदमियों की कोशिशों से हुए हैं, जिन्होंने बहुतों के विरोध का सामना करते हुए उनके लिए यत्न किया। ठगों के गाँव में अधिकांश जन तो यही कहेंगे कि ठगविद्या सीखनी ही चाहिए। तो क्या साधु पुरुष भी ठग बन जाए? हर्गिज नहीं। अन्यायकारी कानून को भी मानना, पालना हम पर फर्ज है, यह वहम जब तक हमारे दिमाग से दूर न होगा तब तक हमारी गुलामी जाने वाली नहीं और केवल सत्याग्रही ऐसे वहम को दूर कर सकता है।* ***-(महात्मा गाँधी, ग्रन्थ : मेरे सपनों का भारत)***

16) *सारे के सारे महान संविधानविदों ने एक ही स्वर में जो राय व्यक्त की थी, उसका आशय ये था कि 70% से 75% तक जो लोग ग्रामीण और जंगली क्षेत्रों में रहते थे, उनका जीवन स्तर ऐसा था कि न पेट में रोटी थी, न शरीर पर वस्त्र, न शिर पर छत। जिस राष्ट्र की तीन-चौथाई आबादी रोटी, कपड़ा, मकान से महरूम थी, उन्हें वयस्क मताधिकार की बात कहकर समानता का दावा करना कितनी बड़ी धृष्टता थी। इसे सबसे पहले डा. अम्बेडकर ने ही महसूस किया था। मूलतः डा. अम्बेडकर के मन में आरक्षण जैसी कोई अवधारणा नहीं थी। एक बार गाँधी जी जो अनशन पर बैठे थे, उनकी जान बचाने के लिए उन्होंने आरक्षण को स्वीकार किया था। वरना उनकी सदा से ये धारणा थी कि जाति के आधार पर शोषण बन्द हो। शोषितों को पर्याप्त संरक्षण मिले ताकि समाज की मुख्य धारा में आकर वे प्रतियोगिता की भावना से आगे बढ़ सकें। अगर इन्हें स्थायी तौर पर आरक्षण की बैसाखियाँ प्रदान की गईं, तो ये पंगु हो जाएँगे, ऐसा डा. अम्बेडकर का मानना था।* ***-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक, पंजाबकेसरी,*** *15/07/04)*

17) *गरीबी हटाने का संकल्प तो हर नेता और प्रशासन लेता है। लेकिन ऐसा काम कोई भी नहीं करता जिससे गरीब अपनी गरीबी दूर कर सके। नेता बनते ही राजसी ठाठ-बाठ की जिन्दगी छप्पर फाड़कर मिल जाती है। अपनी गरीबी भूल जाती है, देश के गरीबों की गरीबी भी भूल जाती है। आज देश के गरीब की स्थिति ऐसी है कि कोई भी गरीब युवक ईमानदारी से अपनी रोटी नहीं कमा सकता। उसे मजबूर होकर*

बेईमानी या अपराध का सहारा लेना पड़ता है। गरीब का बेटा आँख खोलते ही कोई नौकरी ढूँढने की कोशिश करता है। हरेक को नौकरी मिलती नहीं। रिक्शा किराए पर लेकर मेहनत करने निकलते ही उसे पुलिस वाले मिल जाते हैं। जो कानून की आड़ लेकर उसे मेहनत से रोटी कमाने नहीं देते। उससे बदसलूकियाँ करते हैं। थप्पड़ और डण्डे मारते हैं, उसके पहियों की हवा निकालते हैं, मार-मार कर सड़क से हटाते हैं। यही हाल पटरी के खोमचे वालों का भी किया जाता है। जरूरत है कि प्रशासन इतनी तादात में छोटी-छोटी दुकानें बनाए और उन्हें दे। कहने को डी.डी.ए. वाले दुकान बनाते हैं, लेकिन क्या एक मजदूर का बेटा डी.डी.ए. की एक दुकान किराए से ले सकता है, खरीदना तो उसके कल्पना में भी नहीं हो सकता। केवल दिल्ली में ही हजारों ऐसी सड़कें हैं, जहाँ लाखों दुकानें बन सकती हैं। एक दुकान से एक पूरे परिवार की गरीबी दूर हो सकती है। गरीब आदमी दुकान पर बैठकर कुछ न कुछ बनाएगा और बेचेगा। अपना भी गुजारा कर लेगा और उत्पादन भी बढ़ जाएगा। उसे बेईमानी या अपराध के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं होगी। अपराध भी कम होंगे। प्रशासन की भी आय बढ़ेगी। शायद ये लोग आवाज सुन लें और उन गरीबों को कुछ फायदा हो जाए, जो दिन-रात सड़कों पर फटेहाल जीवनयापन कर रहे हैं। आवारा, पागल, कुत्तों की तरह जी रहे हैं और कुत्तों की तरह ही मर जाएँगे। जिन्हें जीवनभर अपनी चारपाई तक नसीब नहीं होती।

-(ओमकुमार, पश्चिमपुरी, दिल्ली; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 10/07/04)

18) *धनी देशों के अन्दर भी एक बड़ी खाई है- अमीरों के स्वास्थ्य में और सबसे गरीब एक तिहाई लोगों के स्वास्थ्य में। विश्वव्यवस्था को जरा गहराई से देखें। सन् 48 से पहले सारे पश्चिमी देश उपनिवेशक थे और गरीब विकासशील दुनिया इन साम्राज्यवादियों का उपनिवेश थी, जो इनके द्वारा लूटी गई। धनी इसलिए धनी है, क्योंकि उन्होंने गरीबों को लूटा है। 'जनस्वास्थ्यसभा' के अध्ययन कहते हैं- भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की दशा खराब है। आदिवासियों की स्थिति शोचनीय है और महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर पुरुषों से ज्यादा गिरा हुआ है। साधनसम्पन्न लोगों की छोटी सी संख्या के पास ये सुविधाएँ सबसे ज्यादा हैं। वंचित वर्ग के पास आय कम है। इसलिए भोजन और बुनियादी सुविधाएँ कम हैं तथा वे खराब परिस्थितियों में रहते हैं और काम करते हैं। निर्धन लोग अमानवीय परिस्थितियों में जीवनयापन करते हैं। अक्सर पशुओं से भी बदतर जीवन जीते हैं। दूसरी ओर धनी लोग विलासिता व फिजूलखर्ची का जीवन व्यतीत करते हैं। जरा इन असमानताओं को देखें :-*

क) *यूरोप व अमरीका में इत्र व सुगन्ध पर किया गया कुल खर्च 12 अरब डालर पूरे संसार की महिलाओं को प्रजनन स्वास्थ्य की देखभाल के लिए काफी है।*

ख) *केवल एक देश अमरीका में सौन्दर्य प्रसाधनों पर किया जाने वाला खर्च पूरे संसार में बुनियादी शिक्षा मुहैया करवा सकता है।*

ग) *अकेले यूरोप में खरीदी जाने वाली मदिरा की कीमत 105 अरब डालर है, जो पूर विश्व की बुनियादी सामाजिक सेवाएँ स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता आदि प्रदान करने के व्यय (40 अरब डालर) का ढाई गुना है।*

घ) *विश्व का सैन्य खर्च लगभग 780 अरब डालर है, जो सबको स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता देने के खर्च का 20 गुना है।*

ङ) *विश्व के तीन सर्वाधिक धनी व्यक्तियों की कुल सम्पत्ति निर्धनतम 48 देशों के सकल घरेलू उत्पाद से ज्यादा है और सर्वाधिक धनी 32 व्यक्तियों की सम्पदा पूरे एशिया के सकल घरेलू उत्पाद से ज्यादा है।*

च) *यदि विश्व के सबसे अमीर 225 लोग अपने धन का मात्र 4% भी दान कर दें, तो सारे विश्व के लोगों को बुनियादी सामाजिक सेवाएँ दी जा सकती हैं।*

ये आँकड़े 1998 के हैं जनाब! कमजोर लोगों के साथ सक्रिय रूप से भेदभाव किया जाता है और उन्हें अर्थव्यवस्था और समाज से दरकिनार कर दिया जाता है। इससे जीवन की बुनियादी सुविधाएँ भी उनकी पहुँच से दूर हो जाती हैं। गरीब लोग शक्तिहीन हैं और शक्तिहीन ही गरीब हैं। यह सरकार का कर्तव्य है कि इन असमानताओं का हल करे। सामाजिक सेवाओं की प्राप्ति के लिए संघर्ष असल में भेदभाव और असमानताओं के विरुद्ध संघर्ष है। एक-एक व्यक्ति को वे न्यूनतम भौतिक सुविधाएँ मिलनी चाहिए, जो एक मानवीय अस्तित्व के लिए जरूरी हैं। सरकारों को यह सुनिश्चित करने में विफल होने पर माफ नहीं किया जा सकता। कवि सुब्रमण्यम भारती के शब्द याद आते हैं- ***''यदि एक भी व्यक्ति के पास खाने के लिए भोजन न हो, तो ऐसी दुनिया मिटा दी जानी चाहिए।''***

कहीं गरीब को रोटी नहीं है खाने में।
कहीं छलक रही है नग्नता पैमाने में।।
-(संजीव कौरा, लाइटहाउस, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 02/03/04)

19) जनता का घोषणापत्र :- *देश की सभी संस्थाएँ, चाहे वह संसद हो, सुप्रीमकोर्ट हो या पुलिस हो, सभी जनता के पैसे पर चलती हैं और जनता के हित के लिए ही बनी हैं, इसलिए जनता ही सर्वोपरि है। जनता के हित को अनदेखा करने की किसी में भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। जनता से बड़ा कोई कानून नहीं है, क्योंकि कानून भी जनता की सहमति से ही बनता है। इसलिए आज हमारे देश में जो मुद्दे हैं, समस्याएँ हैं, उन्हें सुलझाना ही हर समस्या का दायित्व है। जो कानून हमारी समस्याओं के समाधान में रोड़े अटकाता है, उस कानून को बदलना होगा या खत्म करना होगा।*

-(राजीवराणा, आवाज-ए-खबरदार, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 02/03/2004)

20) समस्यापुर के गरीबूमल :- *समस्यापुर में रहता है- गरीबूमल। शहर से टूटी ईंटों की सड़क जाती है- गाँव समस्यापुर को। इसी समस्यापुर में रहता है- बेचारा गरीबूमल। एक दिन उससे मेरी मुलाकात हो गई। मैंने उसका साक्षात्कार लेना चाहा, तो वह दुःखी हो गया और कहने लगा कि जो भी यहाँ आता है, कुछ न कुछ लेना ही चाहता है। प्रस्तुत हैं गरीबूमल से लिए गए साक्षात्कार के प्रमुख अंश-*

नाम? - गरीबूमल।

पिता का नाम? - निराशमल।

रहते कहाँ हो? - समस्यापुर में।

जन्म कब हुआ? - आजादी के दिन।

कहाँ तक पढ़े हो? - अँगूठा लगाता हूँ।

जमीन कितनी है? - चार एकड़ थी, चोरी हो गई।

किसने चुराई? - गाँव के साहूकार ने।

रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? - कोई फायदा नहीं, कर्ज के कागजात पर मेरा अँगूठा साहूकार ने अपने पास पहले से ही लगवा लिया है।

बच्चे कितने हैं? - तीन लड़के और पाँच लड़कियाँ।

परिवार नियोजन ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया? - तीन बच्चों के बाद ऑपरेशन करवाया था, फिर भी बच्चे पैदा होते गए।

क्या बच्चे स्कूल जाते हैं? - दो-तीन साल पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं।

क्यों? - जब मजदूरी करके ही पेट पालना है, तो पढ़ा-लिखा कर बेकार क्यों बनाऊँ!

परिवार कैसे पालते हो? - सब मजदूरी करते हैं।

मजदूरी कितनी मिलती है? - कभी चालीस रुपये, कभी तीस रुपये।

तुम्हारी प्रमुख समस्या क्या है? - क्या करोगे जानकर!

सरकार को बताऊँगा! - क्या होगा उससे?

सरकार को जानकारी होने पर वह उसके निराकरण का उपाय करेगी।

सरकार पर भरोसा नहीं है साहब!

क्यों? - सरकार ने कितनी समस्याओं को हल किया है! वह जिस समस्या को हल करने लगती है, वह समस्या पहले से भी ज्यादा उलझ जाती है।

वोट किसे देते हो? – किसी को नहीं।

ऐसा क्यों? – क्योंकि मेरी नजर में सब चोर हैं, कोई सही उम्मीदवाद खड़ा नहीं हुआ।

अपने गाँव के बारे में क्या कहना चाहते हो? – समस्यापुर में मँहगाई की मार, गरीबी की फटकार, कर्जे का भार, बेकारी की चीत्कार मची हुई है। भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी, मिलावट, भुखमरी, संक्रामक बीमारी और शोषण से ग्रस्त है– समस्यापुर। यहाँ के लोग समस्याओं के मकड़जाल में फँसे हुए हैं।

सरकार से क्या आशा रखते हो? – झूठी घोषणाएँ, खोखले आश्वासन, कोरे वादे।

देश के बारे में क्या जानते हो? – सोने की चिड़िया मिट्टी का ढेर बनती जा रही है, जिसमें गरीबी के दीमक, बेरोजगारी के बिच्छू, भ्रष्टाचार के अजगर पनप रहे हैं, देश रसातल में जा रहा है।

तुम्हारे गाँव में कौन–कौन सी सुविधाएँ हैं? – आने–जाने के लिए टूटी सड़क, पाँच कक्षाओं में एक शिक्षक की सुविधा, बिजली रहते हुए लालटेन जलाने की सुविधा, गम भुलाने के लिए देशी ठर्रा।

तुम्हारा मनपसन्द भोजन? – सूखी रोटी चटनी के साथ।

मनपसन्द गाना? – जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों।

खाली समय में क्या करते हो? – दुःखी होता हूँ।

तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? – लक्ष्यहीन जीवन से मुक्ति पाना।

कोई सन्देश देना चाहते हो? – लोग दुःखी बनकर जीने का अभ्यास करें, इसके सिवा कोई चारा नहीं!

इतना कहकर गरीबूमल फिर दुःखी हो गया। मैं भी दुःखी मन से समस्यापुर के गरीबूमल से विदा लेकर वापस लौट आया। ***-(लेखक : दर्शनबराड़, दैनिक पंजाबकेसरी)***

21) 'इज इण्डिया शाइनिंग'? *जब से सरकार ने भारत–उदय और इण्डिया–शाइनिंग के बड़े–बड़े विज्ञापन प्रकाशित करवाए हैं, विपक्ष के साथ इस मामले में तीखा वाद–विवाद शुरु हो गया है। आपत्ति आधारहीन भी नहीं है। आखिर जिस देश में दुनिया के सबसे अधिक गरीब, बीमार, निरक्षर, कमजोर, बेघर, वंचित रहते हैं, वह कैसे दावा कर सकता है कि वह चमक रहा है। यूरोप के कुछ देशों की जनसंख्या से अधिक लोग तो यहाँ अभी भी खुले आकाश के नीचे फुटपाथों पर सोते हैं। भूख है, कुपोषण है, लाचारी है। 13 करोड़ लोगों के लिए अभी स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं हैं। 22 करोड़ के लिए पीने का पानी नहीं है। 70% जनसंख्या के लिए सफाई की व्यवस्था नहीं है। अनाज के भण्डार लबालब हैं। लेकिन अभी भी उड़ीसा जैसे प्रदेशों में लोग भूख से मर रहे हैं। कई प्रदेशों में कर्ज में डूबा किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। इनमें पंजाब जैसा समृद्ध प्रदेश भी शामिल है, जिसने देश को हरित क्रान्ति दी है। करोड़ों बेरोजगार हैं। रेलवे के एक गैंगमैन के पद के लिए हजारों आवेदन आते हैं। सरकारी शिक्षा का बुरा हाल है। अनेक असंख्य स्कूल हैं, जहाँ सही इमारत भी नहीं है। कम्प्यूटर का तो सवाल ही नहीं है। भ्रष्टाचार चरमसीमा पर है। केन्द्रीय मन्त्री रिश्वत लेते और मुख्यमन्त्री रिश्वत देते पकड़े गए हैं। लोकसेवा आयोग जैसी संस्थाओं में भ्रष्टाचार सेंध कर गया है। अब तो न्यायपालिका भी अछूती नहीं रही। अपराध बढ़ा है। अपराधियों और कानून के रक्षक में कई जगह अन्तर कम हो गया है। जैसा तेलगी मामले में पकड़े गए महाराष्ट्र के वरिष्ठ पुलिस अफसर। बहुत कुछ बहुत गलत है और बहुत बहुत कुछ सही करना बाकी है। गोदाम भरे पेट खाली की स्थिति क्यों है? सरकारी अस्पतालों की हालत बुरी है और यहाँ बिहार जैसे प्रान्त भी हैं, जहाँ अराजक स्थिति है। कौन सा देश है, जहाँ समस्याएँ नहीं हैं। क्या अमरीका में अपराध, बेरोजगारी, असन्तोष नहीं है। हमारे साथ ही आजाद हुआ पड़ोसी पाकिस्तान अपनी करतूतों के कारण अपनी ही गन्दगी में डूब रहा है। नेपाल में माओवादी हावी हैं। चीन में लोकतन्त्र नहीं है, हमारे जैसा खुला प्रेस नहीं है, नागरिक आजादी नहीं है। वह हमसे भी अधिक समस्याओं से ग्रस्त है। केवल उनकी खबरें बाहर नहीं आती। हमें सचमुच अभी मीलों सफर करना है। भारत अभी उस तरह नहीं चमक रहा, जैसे हम सब चाहते हैं। लेकिन अँधेरा कम हो रहा है, इसे और कम करना है।* ***-(चन्द्रमोहन, सम्पादक-वीरप्रताप, लेख : मर्यादाएँ, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 25/02/04)***

22) चुनाव मुहिम में मतदाताओं को रिझाने या यूँ कहिए कि उनकी आँखों में धूल झोंकने के लिए किसी न किसी टकसाली नारे को ईजाद करना आवश्यक होता है। इस मामले में श्रीमती इन्दिरा गाँधी सबकी गुरु रहीं। उन्होंने 1969 में 'गरीबी हटाओ' का चुनावी नारा देकर न केवल अपने विरोधियों को धूल चटाई बल्कि धड़ल्ले से चुनाव भी जीते। बाद में उनकी नकल करके अनेक पार्टियों ने ऐसे लुभावने नारे गढ़े। परन्तु जहाँ तक गरीबी उन्मूलन का सम्बन्ध है, वह आज भी नारों के शोर से दबी आम लोगों की विश्वसनीयता से खेल रही है। भाजपा का 'फील गुड' फैक्टर भी इन्हीं कभी न वफा होने वाले वायदों की एक कड़ीमात्र है। इस मुद्दे पर 1500 करोड़ रुपये लुटाकर इसका प्रचार करने का क्या कोई नैतिक तुक है। बड़े भइया की देखा-देखी छुटभइयों ने भी लोगों को अपनी-अपनी सरकारों के काम से लोगों को अवगत कराने के बहाने चुनावी मुहिम पर इश्तिहारबाजी के लिए सरकारी खजाने के मुँह खोल दिए। यही हाल लगभग सभी राज्य सरकारों का है।

जब तक इस देश में 'लॉ एण्ड आर्डर' की स्थिति में 'फीलगुड' फैक्टर नहीं आता, लोगों को अपने रोजमर्रा के कामों में बिना रिश्वत दिए या बिना परेशानी के सफलता नहीं मिलती, गरीबी सही अर्थों में दूर नहीं होती और बेरोजगारी का खात्मा नहीं होता, देश की उन्नति के लिए सरकार मतदाताओं को उच्छृंखल ढंग से रिझाना बन्द करके कड़े कदम नहीं उठाती, तब तक 'फीलगुड' का नारा भी 'गरीबी हटाओ' की तरह खोखला ही लगेगा। अच्छा होता अगर आज के फीलगुड की नीव हमारे अपने आदर्शों पर टिकी होती-**'ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयात्॥'** अर्थात् सभी जन, सभी वर्ग सुखी रहें स्वस्थ रहें, सभी प्राणी पवित्रता के दर्शन करें इत्यादि। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 56 वर्षों के बाद इतना भर मानना कोई बड़ी बात तो नहीं ? **-(ईश्वरडाबरा, सैलानी की कलम से, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 19/02/04)**

23) अगर इस सबके साथ-साथ आर्थिक समानता का प्रचार न किया गया, तो यह सब निकम्मा समझना चाहिए। आर्थिक समानता का यह अर्थ हरगिज नहीं है कि हर एक के पास धन की समान राशि होगी। मगर यह अर्थ जरूर है कि हर एक के पास ऐसा घर-बार, वस्त्र और खाने-पीने का समान होगा कि जिससे वह सुख से रह सके। और जो घातक असमानता आज मौजूद है, वह केवल अहिंसक उपायों से ही नष्ट होगी। **-(महात्मा गाँधी, ग्रन्थ : मेरे सपनों का भारत)**

24) मेरे लिए 'देशप्रेम' और 'मानवप्रेम' में कोई भेद नहीं है; दोनों एक ही हैं। मैं देशप्रेमी हूँ, क्योंकि मैं मानवप्रेमी हूँ। मेरा देशप्रेम वर्जनशील नहीं है। मैं भारत के हित की सेवा के लिए इंग्लैण्ड या जर्मनी का नुकसान नहीं करूँगा। जीवन की मेरी योजना में साम्राज्यवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। देशप्रेमी की जीवननीति किसी कुल या कबीले के अधिपति की जीवननीति से भिन्न नहीं है। और यदि कोई देशप्रेमी उतना ही उग्र मानवप्रेमी नहीं है, तो कहना चाहिए कि उसके देशप्रेम में उतनी न्यूनता है। वैयक्तिक आचरण और राजनीतिक आचरण में कोई विरोध नहीं है; सदाचार का नियम दोनों में लागू होता है। जिस तरह देशप्रेम का धर्म हमें आज यह सिखाता है कि व्यक्ति को परिवार के लिए, परिवार को ग्राम के लिए, ग्राम को जनपद के लिए और जनपद को प्रदेश के लिए मरना सीखना चाहिए, इसी तरह किसी देश को स्वतन्त्र इसलिए होना चाहिए कि वह आवश्यकता होने पर संसार के कल्याण के लिए अपना बलिदान दे सके। इसलिए राष्ट्रवादी की मेरी कल्पना यह है कि मेरा देश इसलिए स्वाधीन हो कि प्रयोजन उपस्थित होने पर सारा ही देश मानवजाति की प्राणरक्षा के लिए स्वेच्छापूर्वक मृत्यु का आलिंगन करे। उसमें जातिद्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरी कामना है कि हमारा राष्ट्रप्रेम ऐसा ही हो। **-(महात्मा गाँधी, ग्रन्थ : मेरे सपनों का भारत)**

25) जातपाँत के बारे में मैंने बहुत बार कहा है। यह समाज का 'फालतू अंग' है और तरक्की के रास्ते में रुकावट जैसा है। हम सब पूरी तरह बराबर हैं। लेकिन बराबरी आत्मा की है, शरीर की नहीं। इसलिए यह मानसिक अवस्था की बात है। **-(महात्मा गाँधी, ग्रन्थ : मेरे सपनों का भारत)**

26) भारत के सामने आज दो रास्ते हैं : वह चाहे तो पश्चिम के 'शक्ति ही अधिकार है' वाले सिद्धान्त को अपनाए और चलाए या पूर्व के इस सिद्धान्त पर दृढ़ रहे और उसी की विजय के लिए अपनी सारी ताकत लगाए कि 'सत्य की ही जीत होती है'; सत्य में हार कभी है ही नहीं; और ताकतवर तथा कमजोर, दोनों को न्याय पाने का समान अधिकार है। **-(महात्मा गाँधी, ग्रन्थ : मेरे सपनों का भारत)**

27) *भूखों मरता आदमी अन्य सब बातों से पहले अपनी भूख बुझाने का ही विचार करता है। वह रोटी का एक टुकड़ा पाने के लिए अपनी स्वतन्त्रता और अपना सबकुछ बेच डालेगा। भारत में लाखों आदमियों की आज ऐसी ही स्थिति है। उनकी दृष्टि में स्वतन्त्रता, ईश्वर और ऐसे दूसरे शब्द निरर्थक है। वे उनके कानों को कड़वे लगते हैं, अगर हम इन लोगों में स्वराज्य के लिए भावना पैदा करना चाहते हैं, तो हमें उन्हें काम (रोजगार) देना होगा। ऐसा काम जिसे वे आसानी से कर सकें और जो उन्हें कम से कम पेट भरने के साधन मुहैया कर सकें।* ***-(महात्मा गाँधी, ग्रन्थ : मेरे सपनों का भारत)***

28) *वर्गयुद्ध भारत के मूलस्वभाव के खिलाफ है। भारत में समान न्याय और सबके बुनियादी हकों (मूलाधिकारों) के विशाल आधार पर स्थापित एक उदार किस्म का साम्यवाद निर्माण करने की क्षमता है।* ***'मेरे सपने के रामराज्य में सबके अधिकार सुरक्षित होंगे।'*** ***-(महात्मा गाँधी, ग्रन्थ : मेरे सपनों का भारत)***

29) *सच्चा समाजवाद तो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है जो हमें सिखा गए हैं कि 'सकल भूमि गोपाल की'। इसमें कहीं मेरी और तेरी की सीमाएँ नहीं हैं। गोपाल यानी भगवान। आधुनिक भाषा में गोपाल यानी राष्ट्र यानी जनता। जमीन और दूसरी सारी सम्पत्ति उसकी है जो उसके लिए काम करे। दुःख इस बात का है कि किसान और मजदूर या तो इस सरल सत्य को जानते नहीं हैं या यों कहो कि उन्हें इसे जानने नहीं दिया गया है। मैं सदा से यह मानता आया हूँ कि नीचे से नीचे और कमजोर से कमजोर के प्रति हम जोर-जबरजस्ती से सामाजिक न्याय का पालन नहीं कर सकते। मैं यह भी मानता आया हूँ कि पतित से पतित लोगों को भी मुनासिब तालीम (समुचित शिक्षा) दी जाय तो अहिंसक साधना द्वारा सबप्रकार के अत्याचारों का प्रतिकार किया जा सकता है।* ***-(महात्मा गाँधी, ग्रन्थ : मेरे सपनों का भारत)***

30) *हम ऐसी जड़ समानता का निर्माण नहीं करना चाहते जिसमें कोई आदमी योग्यताओं का पूरा-पूरा उपयोग ही न कर सके। ऐसा समाज अन्त में नष्ट हुए बिना नहीं रह सकता।*

-(महात्मा गाँधी, ग्रन्थ : मेरे सपनों का भारत)

31) *अन्यायी यदि अपना अन्याय दूर नहीं करता तो वह अपना नाश खुद ही कर डालता है।*

-(महात्मा गाँधी, ग्रन्थ : मेरे सपनों का भारत)

32) *जो अर्थशास्त्र बलवानों को निर्बलों का शोषण करके धन का संग्रह करने की सुविधा देता है, उसे शास्त्र का नाम नहीं दिया जा सकता। वह तो एक झूँठी चीज है, जिससे हमें कोई लाभ नहीं हो सकता। जिसे अपनाकर हम मृत्यु को न्योता देंगे। सच्चा अर्थशास्त्र तो सामाजिक न्याय की हिमायत करता है। वह समानभाव से सबकी भलाई का, जिसमें कमजोर भी शामिल है, प्रयत्न करता है। और वह सभ्यजनोचित सुन्दर जीवन के लिए अनिवार्य है। मैं ऐसी ही स्थिति लाना चाहता हूँ जिसमें सबका सामाजिक दर्जा समान माना जाय।* ***-(महात्मा गाँधी, ग्रन्थ : मेरे सपनों का भारत)***

33) *आर्थिक समानता का मतलब है- जगत में सबके पास समान सम्पत्ति का होना, यानी सबके पास इतनी सम्पत्ति का होना कि जिससे वे अपनी कुदरती आवश्यकताएँ पूरी कर सकें। कुदरत ने ही एक आदमी का हाजमा अगर नाजुक बनाया हो और वह केवल पाँच ही तोला अन्न खा सके, और दूसरों को बीस तोला अन्न खाने की आवश्यकता हो, तो दोनों की अपनी पाचनशक्ति के अनुसार अन्न मिलना चाहिए। सारे समाज की रचना इस आदर्श के आधार पर होनी चाहिए। अहिंसक समाज का दूसरा आदर्श नहीं रखना चाहिए। पूर्ण आदर्श तक हम कभी नहीं पहुँच सकते। मगर उसे नजर में रखकर हम व्यवस्था करें। जिस हद तक हम इस आदर्श को पहुँच सकेंगे, उसी हदतक सुख और संतोष प्राप्त करेंगे और उसी हदतक सामाजिक अहिंसा सिद्ध हुई कही जा सकेगी।*

-(महात्मा गाँधी, ग्रन्थ : मेरे सपनों का भारत)

34) *किसी को भी भोजन और वस्त्र का अभाव नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हर एक को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त काम (रोजगार) मिलना चाहिए ..... (और यह आदर्श सबके लिए तभी प्राप्त हो सकता है जब) जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी उत्पादन के साधन जनता के नियंत्रण में हों। वे सबको मुक्तरूप से उपलब्ध होने चाहिए जैसे हवा और पानी है, दूसरों के शोषण के लिए इन्हें व्यापार का साधन नहीं बनाया जाना चाहिए।* ***-(महात्मा गाँधी, ग्रन्थ : मेरे सपनों का भारत)***

35) *मेरी राय में न सिर्फ भारत की बल्कि सारी दुनिया की, अर्थरचना ऐसी होनी चाहिए कि किसी को भी अन्न और वस्त्र के अभाव की तकलीफ न सहनी पड़े। दूसरे शब्दों में हर एक को इतना काम अवश्य मिल जाना चाहिए कि वह अपने खाने-पहनने की जरूरतें पूरी कर सके। और यह आदर्श निरपवाद रूप से तभी कार्यान्वित किया जा सकता है, जब जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं के उत्पादन के साधन जनता के नियंत्रण में रहें। वे हर एक को बिना किसी बाधा के उसी तरह उपलब्ध होने चाहिए जिस तरह कि भगवान की दी हुई हवा और पानी हमें उपलब्ध है, किसी भी हालत में दूसरों के शोषण के लिए चलाए जाने वाले व्यापार का वाहन न बनें। किसी भी देश, राष्ट्र या समुदाय का उन पर अधिकार अन्यायपूर्ण होगा। हम आज न केवल अपने इस दुःखी देश में, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी, जो गरीबी देखते हैं, उसका कारण इस सरल सिद्धान्त की उपेक्षा ही है। मैं अर्थविद्या और नीतिविद्या में कोई भेद नहीं करता। जिस अर्थविद्या से व्यक्ति या राष्ट्र के नैतिक कल्याण को हानि पहुँचती हो, उसे मैं अनीतिमय और पापपूर्ण कहूँगा। उदाहरण के लिए जो अर्थविद्या किसी देश को किसी दूसरे देश का शोषण करने की अनुमति देती है, वह अनैतिक है। जो मजदूरों को योग्य मेहनताना नहीं देते और उनके परिश्रम का शोषण करते हैं, उनसे वस्तुएँ खरीदना या उन वस्तुओं का उपयोग करना पापपूर्ण है।* ***-(महात्मा गाँधी, ग्रन्थ : मेरे सपनों का भारत)***

36) *भारत में लाखों लोग ऐसे हैं, जिन्हें दिन में केवल एक ही बार खाकर संतोष कर लेना पड़ता है और उनके उस भोजन में भी सूखी रोटी और चुटकीभर नमक के सिवा और कुछ नहीं होता। हमारे पास जो कुछ भी है, उस पर हमें और आपको तब तक कोई अधिकार नहीं है, जब तक इन लोगों के पास पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए अन्न नहीं हो जाता। हममें और आपमें ज्यादा समझ होने की आशा की जाती है।*
-(महात्मा गाँधी, ग्रन्थ : मेरे सपनों का भारत)

37) *स्वराज्य एक पवित्र शब्द है, वह एक वैदिक शब्द है, जिसका अर्थ आत्मशासन या आत्मसंयम है। स्वराज्य से मेरा अभिप्राय लोकसम्मति के अनुसार होने वाला भारतवर्ष का शासन है। सच्चा स्वराज्य थोड़े से लोगों द्वारा सत्ता प्राप्त कर लेने से नहीं, बल्कि जब सत्ता का दुरुपयोग होता हो, तब सब लोगों के द्वारा उसका प्रतिकार करने की क्षमता प्राप्त करके हासिल किया जा सकता है। वह स्वराज्य सबके लिए है, सबके कल्याण के लिए होगा। सबकी गिनती में किसान तो आते ही हैं किन्तु लूले, लँगड़े, अन्धे और भूख से मरने वाले लाखों-करोड़ों मेहनतकश मजदूर भी आते हैं। मेरे लिए स्वराज्य का अर्थ सब लोगों का राज्य, न्याय का राज्य है। जीवन की जिन आवश्यकताओं का उपभोग राजा और अमीर लोग करते हैं, वही गरीबों को भी सुलभ होनी चाहिए इसमें फर्क के लिए स्थान नहीं हो सकता। मुझे इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है कि हमारा स्वराज्य तब तक पूर्ण स्वराज्य नहीं होगा जब तक वह गरीबों को ये सारी सुविधाएँ देने की व्यवस्था नहीं कर देता। अगर स्वराज्य का अर्थ हमें सभ्य बनाना और हमारी सभ्यता को अधिक शुद्ध तथा मजबूत बनाना न हो तो वह किसी कीमत का नहीं होगा। हमारी सभ्यता का मूलतत्त्व ही यह है कि हम अपने सब कामों में चाहे वे निजी हों या सार्वजनिक नीति के पालन को सर्वोच्च स्थान देते हैं। स्वराज्य में कोई किसी का शत्रु नहीं होता। सारी जनता की भलाई का सामान्य उद्देश्य सिद्ध करने में हर एक अपना अभीष्ठ योग देता है। सब पढ़-लिख सकते हैं और उनका ज्ञान दिन-दिन बढ़ता रहता है। बीमारी और रोग कम से कम हो जाएँ ऐसी व्यवस्था की जाती है। कोई कंगाल नहीं होता और चाहने वालों को काम अवश्य मिल जाता है। उसमें ऐसा नहीं हो सकता, होना नहीं चाहिए कि चन्द अमीर तो रत्नजड़ित महलों में रहें और लाखों-करोड़ों ऐसी मनहूस झोपड़ियों में जिनमें हवा और प्रकाश का प्रवेश न हो। अहिंसक स्वराज्य में न्यायपूर्ण अधिकारों का किसी के भी द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता। और इसी तरह किसी को कोई*

अन्यायपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। सुसंगठित राज्य में किसी के न्यायशील अधिकार का किसी दूसरे के द्वारा छीना जाना असंभव होना चाहिए। बराबरी की मेहनत करके भी दूसरों को जो चीज नहीं मिलती है, वह खुद भी किसी को नहीं लेनी चाहिए। ऐसा समाज जरूर ही बहुत ऊँचे दर्जे की सभ्यता वाला होगा।

-(महात्मा गाँधी, ग्रन्थ : मेरे सपनों का भारत)

38) *मैं जानता हूँ कि मानवमात्र (अर्थात् सभी मनुष्यों) की आत्मा एक है, शरीर भिन्न-भिन्न हैं, पर अंतरतत्त्व एक है। मानवजगत में राजकीय, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक जो भी क्रान्ति करनी होगी जहाँ-जहाँ नये मूल्य स्थापित करने होंगे, वहाँ इस आंतरिक एकता को मानकर ही हम आगे बढ़ सकेंगे। इस बुनियादी एकता के सत्य में से ही अहिंसा (प्रेम) का धर्म निकलता है। मानवता की एक जमात की भावना बिना रखे मानव इस पृथ्वी पर टिक ही नहीं सकता।* ***-(महात्मा गाँधी, संतचेतना नामक ग्रंथ में प्रकाशित वक्तव्य)***

39) *जो लोग खुदा की आयतों को नहीं मानते और नबियों (ऋषियों) को नाहक (अन्यायपूर्वक) कत्ल करते हैं। और जो इंसाफ (न्याय) करने का हुक्म देते हैं, उन्हें भी मार डालते हैं, उनको दुःख देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो। ये ऐसे लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद हैं।*

-(कुरआनमजीद, मंजिल : 1, सूरा : 3, आयत : 21)

40) *और अगर फैसला करना चाहो तो इंसाफ (न्याय) का फैसला करना कि खुदा इंसाफ (न्याय) करने वालों को दोस्त रखता है।* ***-(कुरआनमजीद, मंजिल : 2, सूरा : 5, आयत : 42)***

41) *खुदा तुमको इंसाफ (न्याय) और एहसान (पुण्य) करने और रिश्तेदारों को सहयोग देने का हुक्म देता है और बेहयाई और नामाकूल कामों से और सरकशी (हत्या) से मना करता है और तुम्हें नसीहत (सलाह) देता है कि तुम याद रखो।* ***-(कुरआनमजीद, मंजिल : 3, सूरा : 26, आयत : 90)***

42) एक फरीक (पक्ष) दूसरे पर ज्यादती करे तो ज्यादती करने वाले से लड़ो। दोनों फरीक (पक्षों) में बराबरी के साथ सुलह करा दो। और इंसाफ से काम लो कि खुदा इंसाफ (न्याय) करने वालों को पसंद करता है।

-(कुरआनमजीद, मंजिल : 6, सूरा : 49, आयत : 9)

43) *जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है और जो कुछ इन दोनों के बीच में है और जो कुछ मिट्टी के नीचे है, सब उसी का है। और अगर तुम पुकार कर बात कहो तो वह तो छिपे भेद और बहुत छिपी बात तक को जानता है। (वही) माबूद है उसके सिवा कोई माबूद (आधार या अस्तित्व) नहीं है।*

-(कुरआनमजीद, मंजिल : 4, सूरा : 20, आयत : 6 से 8 तक)

44) *'जो अन्याय करता है, वह अन्याय करता रहे। और जो मलिन (पापी) है, वह मलिन (पापी) बना रहे। और जो धर्मी (न्यायनिष्ठ) है, वह धर्मी (न्यायनिष्ठ) बना रहे। और जो पवित्र (पुण्यात्मा) है, वह पवित्र (पुण्यात्मा) बना रहे। देख! मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमिगा, पहिला और पिछला, आदि और अन्त हूँ। धन्य हैं वे लोग जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा।'*

-(बाइबिल, नयानियम, प्रकाशित वाक्य)

45) *'क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे ? सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं ? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे ? तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय न करें ?' (6:2-3) 'परन्तु सचमुच तुममें बड़ा दोष तो यह है, कि आपस में मुकद्दमा करते हो। अन्याय करते और हानि पहुँचाते हो, और वह भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते, कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे ?' (6:7:8)।* ***-(बाइबिल, नयानियम, 1-कुरिन्थियों)***

46) *तब यीशु ने कहा कि मैं इस जगत् में न्याय के लिए आया हूँ।* ***-(बाइबिल, नयानियम, यूहन्ना, 9:39)***

47) *मुँह देखकर न्याय न चुकाओ, परन्तु ठीक-ठीक न्याय चुकाओ।* ***-(बाइबिल, नयानियम, यूहन्ना, 7:24)***

48) *पर हे फरीसियों! तुम पर हाय! तुम पोदीने और सुदाव का, और सब भाँति के साग-पात का दसवाँ अंश (दान) देते हो। परन्तु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते।* ***-(बाइबिल, नयानियम, लूका, 11:42)***

49) *मानवजीवन में धर्म के पूर्ण उदय से स्वाभाविक (प्राकृतिक) असमानताओं के रहते हुए भी, मानव उच्चतम सामंजस्य में रहने की योग्यता प्राप्त करेगा। यह एक लँगड़े और अंधे के सहयोग के समान है। लँगड़े आदमी को टाँग मिल जाती है और अंधे को आँख। सहयोग की भावना असमानता की कटुता दूर कर देती है। व्यक्ति और समाज के सम्बन्धों का हमारा दृष्टिकोण संघर्ष का न होकर सभी व्यक्तियों में उस एक सत्य के विराजमान होने के बोध से उत्पन्न सामंजस्य और सहयोग का रहा है। व्यक्ति सामाजिक व्यक्तित्व का एक सजीव अंग होता है। व्यक्ति और समाज दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं। परिणामतः दोनों ही एक दूसरे से शक्ति प्राप्त करते हुए लाभान्वित होते हैं।*

-(माधवरावसदाशिवरावगोलवलकर, राष्ट्रीयस्वयंसेवकसंघ., ग्रन्थ : विचारनवनीत)

50) *वे लोग साम्प्रदायिक कहे जाएँगे, जो देश के प्रति निष्ठा रखते हुए भी शेष समाज से अलग, अपने पंथ, बिरादरी, भाषा और तथाकथित जाति के आधार पर सोचते हों, और अपने मर्यादित लाभ एवं राजनीतिक सत्ता के उपभोग के निमित्त ऐसे विशेष अधिकारों व सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हों जो समाज के सर्वसामान्य व्यक्तियों को उपलब्ध न हों और इस उद्देश्य से वे दूसरों के साथ घृणा व द्वेष भी करते हों, उनका विरोध करते हों तथा कभी-कभी हिंसात्मक उपायों का भी अवलंबन करते हों।*

-(माधवरावसदाशिवरावगोलवलकर, राष्ट्रीयस्वयंसेवकसंघ., ग्रन्थ : समग्रदर्शन खण्ड-4)

51) *हमने मानव के समग्र एवं संकलित रूप का थोड़ा विचार किया है। इस आधार पर हम भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों के साथ राष्ट्रीयता, लोकतन्त्र, समता और विश्व की एकता के आदर्शों को समन्वित रूप में रख सकें। इनके बीच का विरोध नष्ट होकर वे परस्पर पूरक हों। तभी मानव अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और जीवनोद्देश्य को प्राप्त कर सकेगा।* ***-(दीनदयाल उपाध्याय, ग्रन्थ : कर्तृत्व एवं विचार, पृष्ठ : 431)***

52) *हम यह तो स्वीकार करते हैं कि जीवन में अनेकता और विविधता है किन्तु उसके मूल में निहित एकता को खोज निकालने का हमने सदैव प्रयत्न किया है। यह प्रयत्न पूर्णतः वैज्ञानिक है। विज्ञानवेत्ता का प्रयत्न रहता है कि वह जगत में दिखने वाली अव्यवस्था में से व्यवस्था ढूँढ निकाले। उसके नियमों का पता लगाए और तदनुसार व्यवहार के नियम बनाए। रसायनशास्त्रियों ने सम्पूर्ण भौतिक जगत में से कुछ आधारभूत तत्त्व (Elements) ढूँढ़ निकाले तथा बताया कि सृष्टि उनसे ही बनी है। भौतिकी उससे भी आगे गई। उसने उन तत्त्वों के मूल में निहितशक्ति अर्थात चेतना को ढूँढ़ निकाला। आज सम्पूर्ण जगत में चेतना का आविष्कार है।* ***-(दीनदयाल उपाध्याय, ग्रन्थ : कर्तृत्व एवं विचार, पृष्ठ : 426)***

53) *विश्व का ज्ञान और आज तक की अपनी सम्पूर्ण परम्परा के आधार पर हम ऐसे भारत का निर्माण करेंगे, जो हमारे पूर्वजों के भारत से भी अधिक गौरवशाली होगा, जिसमें जन्मा मानव अपने व्यक्तित्व का विकास करता हुआ, सम्पूर्ण मानवता ही नहीं, अपितु सृष्टि के साथ एकात्मता का साक्षात्कार कर 'नर से नारायण' बनने में समर्थ हो सकेगा। यह हमारी संस्कृति का शाश्वत, दैवी और प्रवाहमान रूप है। चौराहे पर खड़े विश्वमानव के लिए यही हमारा दिग्दर्शन है। भगवान हमें शक्ति दें कि हम इस कार्य में सफल हों, यही प्रार्थना है।* ***-(दीनदयाल उपाध्याय, ग्रन्थ : कर्तृत्व एवं विचार, पृष्ठ : 414)***

54) *21वीं सदी में नवयुग की संपूर्ण व्यवस्था एकता (प्रेम) और समता (न्याय) के सिद्धान्तों पर निर्धारित होगी। हर क्षेत्र में, हर प्रसंग में उन्हीं का बोलबाला दृष्टिगोचर होगा। 'वसुधैव-कुटुम्बकम्' का आदर्श अब समाजवाद, समूहवाद, संगठनवाद, एकीकरण का विधान बनकर समय के अनुरूप कार्यान्वित होगा।*

-(श्रीरामशर्मा आचार्य, अखण्डज्योति, नवम्बर 1988)

55) *एक और प्रश्न है- क्या यह व्यवहार्य है? वर्तमान समाज में क्या इसे कार्यरूप में परिणत किया जा सकता है? इसका उत्तर यह है कि सत्य प्राचीन अथवा आधुनिक किसी समाज का सम्मान नहीं करता। समाज को ही सत्य का सम्मान करना पड़ेगा, अन्यथा समाज नष्ट हो जाएगा। समाजों को सत्य के अनुरूप ढाला जाना चाहिए, सत्य को समाज के अनुरूप अपने को ढालना नहीं पड़ता। यदि निःस्वार्थता के समान महान सत्य समाज में कार्यरूप में परिणत न किया जा सकता हो, तो ऐसे समाज को छोड़कर वन में चले जाना ही बेहतर है।*

यदि तुम ऐसा समाज नहीं गढ़ सकते, जिसमें सर्वोच्च सत्य को स्थान मिले, तो धिक्कार है अपने बाहुबल पर तुम्हारे मिथ्या अभिमान को! धिक्कार है अपनी पाश्चात्य संस्थाओं पर तुम्हारे वृथा घमण्ड को! अपनी महत्ता और श्रेष्ठता की तुम क्यों व्यर्थ शेखी बघारते हो, यदि दिन-रात तुम यही कहते रहो कि "यह अव्यवहार्य है!" यदि ऐसा ही हो तो, फिर अपने समाज पर इतना घमण्ड क्यों करते हो? वही समाज सबसे श्रेष्ठ है, जहाँ सर्वोच्च सत्य को कार्य में परिणत किया जा सकता है- यही मेरा मत है। और यदि समाज इस समय उच्चतम सत्य को स्थान देने में समर्थ नहीं है, तो उसे इस योग्य बनाओ। और जितना शीघ्र तुम ऐसा कर सको, उतना ही अच्छा। ***-(स्वामी विवेकानन्द, ग्रन्थ : ज्ञानयोग)***

56) *अज्ञान ही सब दुःखों का कारण है, और मूलभूत अज्ञान तो यही है कि जो अनन्तस्वरूप है, वह अपने को सान्त (सीमित) मानकर रोता है, चिल्लाता है। समस्त अज्ञान का आधार यही है कि हम अविनाशी, नित्य शुद्ध पूर्ण आत्मा होते हुए भी सोचते हैं कि हम छोटे-छोटे मन हैं; हम छोटी-छोटी देहमात्र हैं; यही समस्त स्वार्थपरता की जड़ है। ज्यों ही मैं अपने को क्षुद्रदेह समझ बैठता हूँ, त्यों ही मैं संसार के अन्यान्य शरीरों के सुख-दुःख की कोई परवाह न करते हुए केवल अपने शरीर की रक्षा में, केवल उसे सुन्दर बनाने के प्रयत्न में लग जाता हूँ। उस समय मैं तुमसे भिन्न हो जाता हूँ। ज्यों ही यह भेदज्ञान आता है, त्यों ही वह सब प्रकार के अमंगल के द्वार खोल देता है और सर्वविध दुःखों की उत्पत्ति करता है। अतः पूर्वोक्त सत्ज्ञान की प्राप्ति से लाभ यह होगा कि यदि वर्तमान मानवजाति का एक बिल्कुल छोटा सा अंश भी इस क्षुद्र संकीर्ण और स्वार्थीभाव का त्याग कर सकें, तो कल ही यह संसार स्वर्ग में परिणत हो जायेगा।*

-(स्वामी विवेकानन्द, ग्रन्थ : ज्ञानयोग)

57) *माँ! मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि एक दिन मेरा देश आजाद हो जायेगा। लेकिन मुझे शक है कि गोरे साहबों द्वारा खाली की गई कुर्सियों पर ब्राउन साहब बैठ जायेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि घिसीपिटी पुरानी (अन्याय) व्यवस्था जो प्रगति के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी है, को नष्ट किये बिना कोई परिवर्तन संभव नहीं है। दार्शनिकों ने विश्व की अनेक प्रकार से व्याख्याएँ की हैं, लेकिन असली मुद्दा इसमें परिवर्तन का है- जो केवल क्रान्ति से ही संभव है।* ***-(सरदार भगत, शहादत से पूर्व माँ विद्यावती को लिखे गये पत्र का अंश)***

58) *'आलीशान भवनों और गंदी झोपड़ियों में रहने वालों के बीच की खाई को यदि शीघ्र नहीं पाटा गया तो इस दिशा में खूनी क्रांति को कोई टाल नहीं सकता।'* ***-(महात्मा गाँधी)***

59) *'अँग्रेजों को हटाने मात्र से ही स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र-सम्पदा का समान वितरण ही वास्तविक स्वतंत्रता कहलायेगी'।* ***-(सुभाषचन्द्र बोस)***

60) *'जातिविहीन समाज की स्थापना के बिना स्वराज्य प्राप्ति का कोई महत्व नहीं है।'*

-(डा० भीमराव अम्बेडकर)

61) मनुष्य उसी को कहना जो कि मननशील होकर स्वात्मवत् अन्यों के सुख-दुःख और लाभ-हानि को समझे। अन्यायकारीबलवान से भी न डरे और धर्मात्मानिर्बल से भी डरता रहे। इतना ही नहीं किन्तु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं की, चाहे वह महा अनाथ, निर्बल और गुणरहित क्यों न हों उनकी रक्षा, उन्नति और प्रियाचरण करे और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती, सनाथ, महाबलवान और गुणवान भी हो तथापि उसका नाश, अवनति और अप्रियाचरण सदा किया करे अर्थात् जहाँ तक हो सके वहाँ तक अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करे। इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही जाएँ, परन्तु इस मनुष्यपन रूप धर्म से पृथक कभी न होएँ। 'निन्दन्तु नीतिनिपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः'।

-(स्वामी दयानन्दसरस्वती, आर्यसमाज, ग्रंथ : सत्यार्थप्रकाश)

62) प्रकृति, समाज, (परिवार) और व्यक्ति के बीच परिपूर्ण सन्तुलन की आचार-संहिता प्रकट होगी- भारतराष्ट्र की पुनर्स्थापना से। पर्यावरण सम्बन्धी सभी प्रश्नों और समस्याओं के समाधान के लिए- भारतराष्ट्र की पुनर्स्थापना आवश्यक। एकांगिता, कट्टरवाद, साम्प्रदायिक उन्माद, अलगाववाद, अभाव, अज्ञान और असुरक्षा से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय- भारतराष्ट्र की पुनर्स्थापना। भारत की एकता-अखण्डता स्थापित करके भाईचारा, साम्प्रदायिक सद्भाव एवं सबको रोजी-रोटी देने की सम्यक् व्यवस्था करने का नाम है- भारतराष्ट्र। पूजास्थल, पूजापद्धति, गुरुपरम्पराओं की स्वतन्त्रता, एक ही बगीचे में अलग-अलग रंग और सुगन्ध के फूलों को अपनी तरह विकसित होने और खिलने का परिपूर्ण अवसर मिलेगा- भारतराष्ट्र में। किसी के प्रति नफरत नहीं, किसी की उपेक्षा नहीं, किसी का तुष्टिकरण नहीं, समष्टि की सुखशान्ति के सभी विचारों का परिपूर्ण आदर लेकिन समाजविरोधी, प्रकृति के प्रति कृतघ्नता, अनाचार, समाज और व्यक्ति के प्रति नफरत के विचारों तथा आचारों की स्वार्थी और प्रभुत्त्ववादी व्यवस्थाओं का उन्मूलन किया जाएगा- भारतराष्ट्र में। क्योंकि इसकी मूल मान्यता है- धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो।

-(स्वामी वासुदेवाचार्य, सन्तचेतना, धर्म एवं राजनीति : वैकल्पिक चिन्तन)

63) लम्बे समय से धर्मनीति का सम्बन्ध मनुष्य की व्यक्तिगत मुक्ति या निर्वाणमार्ग से ही माना गया है। इसीलिए आमतौर पर धर्म का क्षेत्र पूजापाठ, उपासना, साधना तक ही सीमित है। इस मान्यता ने धर्म के क्षेत्र और धर्म की नीति को सीमित बना दिया है। लेकिन भारत में जिस धर्मविचार का चिन्तन हुआ है, वह मात्र व्यक्तिगत मुक्ति का माध्यम नहीं है। भारतीय चिन्तन के अनुसार संसार की शोषित, पीड़ित, दलित मानवता को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दासता से मुक्ति दिलाने की नीति का नाम धर्मनीति ही है। आधुनिक समाज में धर्म के नाम से एक चिढ़ सी पैदा हो गई है। धर्मनीति से चिढ़ पैदा होना स्वाभाविक है, क्योंकि धनपतियों, राजनीतिज्ञों और प्रशासकों की मिली-जुली साँठ-गाँठ ने स्वार्थवश धर्म को बहुत सीमित कर दिया है। परन्तु भारतीय परम्परा कहती है कि अनीति, अन्याय, दुराचार के विरुद्ध लड़ना धर्म ही है। गीता, रामायण, महाभारत, भागवत्पुराण, दुर्गासप्तसती आदि सभी में धर्मयुद्ध का उपदेश है। अतः धर्म की सच्ची नीति धर्मयुद्ध के द्वारा व्यक्ति तथा समाज को अनीति, अन्याय, शोषण और दमन से मुक्ति दिलाना है।

वर्तमान युग में राजतन्त्र ने शस्त्रों-अस्त्रों से लैस होकर धर्मविरुद्ध आचरण करना शुरु कर दिया है। यह राजतन्त्र चाहे जन प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता हो, चाहे मजदूर की तानाशाही के नाम पर हो या मात्र सेवा के नाम पर हो, सबका मूल चरित्र 90% जनता का 10% द्वारा शोषण ही है। इसलिए सब प्रकार की कुसत्ताओं के खिलाफ, शोषण के विरुद्ध तथा सामाजिक अन्याय और कुरीतियों के विरुद्ध धर्मयुद्ध करना आज की धर्मनीति है। इस नीति के अन्तर्गत संसार के सब धर्मप्रेमियों को संगठित कर विश्व-कल्याण के लिए, मानवधर्म की प्रतिष्ठा के लिए आधुनिक वैज्ञानिक संदर्भों में युगानुकूल पद्धति से धर्मयुद्ध की नीति निर्धारित करना जरूरी हो गया है। सार्वभौम धर्मभावना इस धर्मनीति का आधार बनेगी। इसी के निर्देशन में, शोषित, पीड़ित, दलित मानवता का मुक्ति संग्राम छेड़ना होगा।

-(स्वामी गिरीशानन्द, सन्तचेतना, धर्म एवं राजनीति : वैकल्पिक चिन्तन)

64) *सार्वभौम धर्म की शक्ति को उजागर करने के लिए सभी पंथों, सम्प्रदायों को उदारतापूर्वक एकजुट होना होगा। साथ ही सामयिक चुनौती का मुकाबला करने के लिए हिम्मत से धर्म उद्घोष करना होगा। उद्घोष के आधार बिन्दु निम्नलिखित हो सकते हैं :–*

1. *सभी सम्प्रदायों के प्रमुख व्यक्तियों तथा संवेदनशील मनीषियों की सहमति से वैज्ञानिक युग की चुनौतियों को स्वीकार करके उनका समाधान करने के लिए एक सार्वभौम धर्मपंथ का निर्धारण किया जाए तथा भारत में सबके लिए समान कानूनों की व्यवस्था हो।*
2. *पांथिक सम्प्रदायों की भावनात्मक विभिन्नताओं का आदर करते हुए, सद्भाव, प्रेम और करुणा के बुनियादी आधारों को प्रधानता दी जाए। पांथिक सम्प्रदायों में दूसरों के प्रति घृणाभाव और क्रूरभावों को पैदा करने वाले कर्मकाण्डों का बहिष्कार किया जाए।*
3. *राज्य केवल व्यापक व्यवस्थाओं के लिए नियम–उपनियम बनाए। मानव के व्यक्तिगत तथा भावनात्मक जीवन के नियमों में दखल न दे। जो भी नियम–उपनियम बने, वे सभी नागरिकों के लिए बिना भेदभाव के समानरूप से प्रभावी हों। सम्प्रदाय विशेष को ध्यान में रखकर कोई कानून न बने।*
4. *सभी पूजास्थल, राज्य के नियन्त्रण से मुक्त हों। इसके लिए सभी पंथों की मिली–जुली धर्मपरिषद् जिम्मेदार हो। यह धर्मपरिषद् विश्व–बन्धुत्व के आधार पर गठित हो और उसी आधार पर काम करे।*
5. *धर्मप्रेमियों को सभी धर्मस्थलों पर पूजा करने की खुली सुविधा हो।*
6. *धर्म को भाषा, राष्ट्र, पूजापद्धतियों और पूजाघरों के दायरों में न बाँधा जाए। धर्म सार्वभौम हो। उसके मूलभूत सिद्धान्त भी सार्वभौम हों।*

इसप्रकार विज्ञानयुग की आवश्यकताओं के आधार पर सार्वभौम युगधर्म की स्थापना से संसार में आम आदमी की सुख–शान्ति सुरक्षित होगी। धर्म के मूलभूत आधार सत्य, मुहब्बत (प्रेम), रहम (पुण्य) मजबूत बनेंगे। अस्त्र–शस्त्रों की होड़ पर नियन्त्रण करके संसार को सर्वनाश की ओर बढ़ने से बचाया जा सकेगा, विघटनकारी असहिष्णु सम्प्रदायवाद समाप्त होगा। उच्छृंखल राजतन्त्र सार्वभौम (न्यायरूपी) धर्मनीति से नियन्त्रित और अनुशासित होगा। ऐसा होने पर संसार को संहारक शक्तियों की कठपुतली नहीं बनना पड़ेगा। साथ ही सम्प्रदायवाद और आतंकवाद का शिकार होने से दुनिया को बचाया जा सकेगा।

-(महन्त श्री रामस्वरूप, सन्तचेतना, धर्म एवं राजनीति : वैकल्पिक चिन्तन)

65) *न केवल भारत में बल्कि सारी दुनिया में असन्तुलन, अन्याय, अत्याचार का साम्राज्य फैला हुआ है। धर्म भारतीय जीवन का मेरुदण्ड है। परन्तु वर्तमान भारत में धर्म को केवल परलोक की चीज बनाकर संकुचित कर दिया है और जनजीवन को धर्मनिरपेक्ष, भ्रष्ट संसदीय राज्यतन्त्र के हाथ में सौंप दिया है। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि जनजीवन पर छाई अधर्म की काली छाया को मिटाना आवश्यक हो गया है। धार्मिक पुरुष एकजुट होकर अधर्मरूपी राज्यतन्त्र की काली छाया को मिटाने हेतु धर्मयुद्ध भी करने के लिए मजबूर हो गए हैं।* ***-(श्री केदारस्वामी, सन्तचेतना, धर्म एवं राजनीति : वैकल्पिक चिन्तन)***

66) *भावी संविधान ऐसा हो– जिससे नागरिकों का अभिक्रम प्रगटे तथा समाज की एकता और देश की अखण्डता सुरक्षित रहे। व्यक्ति के अन्तर में नैतिकता, राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना जागृत हो। राष्ट्र की प्रत्येक वस्तु में आत्मभाव हो, स्वार्थ का त्याग हो। सभी नर–नारी सर्वहित में रत रहें। देश में न कोई शोषक रहे और न कोई शोषित हो। वैकल्पिक व्यवस्था लाने के लिए देश की सभी राजनीतिक पार्टियाँ समाप्त की जाएँ। प्रत्येक ग्राम, मुहल्ला या क्षेत्र में अपनी आबादी के अनुपात से पार्टीविहीन पंचायतों की स्थापना करें। हर पंचायत अपने ही क्षेत्र के पाँच चरित्रवान व्यक्तियों का यथासंभव सर्व सम्मति से चयन करें।*

-(स्वामी हीरानन्द, सन्तचेतना, धर्म एवं राजनीति : वैकल्पिक चिन्तन)

67) *न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य अपने क्षेत्र की सुरक्षा और विकास के कार्य पंचायत के अधीन होंगे। प्रत्येक क्षेत्रवासी को रोजी–रोटी, रहने का स्थान देने की जिम्मेदारी पंचायत की होगी। अपने क्षेत्र के उत्पादित कच्चे माल से बनने वाली वस्तुओं का निर्माण करने की व्यवस्था पंचायत करेगी। अपने क्षेत्र के 'कर' भी पंचायत निर्धारित करेगी और वसूल भी कर सकेगी। जो कार्य पंचायत की एक इकाई की शक्ति तथा सामर्थ्य से*

बाहर है, उसे दस पंचायतों की इकाई मिलकर करे। उससे अधिक सामर्थ्य की आवश्यकता होने पर सौ या हजार की इकाई मिलकर करें। प्रत्येक पंचायत एक-दूसरे के यहाँ के विकास कार्यों के प्रयोग, उत्पादन, शिक्षा, सुरक्षा आदि व्यवस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठाए। अपने अनुभव दूसरों को बताए। पंचायत क्षेत्र के अल्पसंख्यक, जाति या सम्प्रदाय विशेष के व्यक्ति को पंचायत के पंच या बहुसंख्यक प्रताड़ित न करें, हानि न पहुँचाएँ, गरीबी से ऊपर उठाने में बाधक न बनें आदि आदि।

जीवन की अन्य व्यवस्थाओं के विषय में भी पंचायत सामयिक तथा दूरगामी आवश्यकताओं को समझकर नीति निर्धारण करने की शक्ति रखेगी। न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य विविध विषयों से सम्बन्धित नीतियों का निर्धारण मानवकेन्द्रित मूल्यों को पोषण देने हेतु होगा।

-(स्वामी हीरानन्द, सन्तचेतना, धर्म एवं राजनीति : वैकल्पिक चिन्तन)

68) *जिस देश के रहने वालों के बीच सहज स्वाभाविकता, पारस्परिकता, स्वावलम्बन और साझेदारी के गुण जितने अधिक हों, वह देश उतना ही विकसित है। यह होगी विकास की नयी परिभाषा। इसप्रकार नयी विश्वक्रान्ति का आधार मानव और मानवता होगी। राजनीतिक और आर्थिक नीतियों की दिशा सन्तुलित करने के लिए मनुष्य, समाज और प्रकृति के बीच पारस्परिक पूरकभाव को विकसित करना होगा। निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को तेज करना होगा। सबल राष्ट्रों को निर्बल राष्ट्रों के शोषण का रास्ता छोड़ना होगा। श्रम और बुद्धि के आर्थिक-सामाजिक मूल्यांकन का भेद मिटाना होगा। काले-गोरे का नस्लभेद, ऊँच-नीच का जातिभेद साम्प्रदायिक विद्वेष तथा राज्यवादी राष्ट्रीयता के भेदभाव को मिटाने के लिए विश्वस्तर पर एक वैचारिक आन्दोलन खड़ा करना होगा। कहना होगा-**"सच्चे विकास के लिए प्रतिद्वन्द्विता नहीं, सहयोग आवश्यक है।"***

सहयोगी समाज में आधुनिक विषमतामूलक समाज का अन्त होगा। समता पर आधारित समाज बनेगा। भौगोलिक राजनीतिक राष्ट्रीय राज्यों की सीमाएँ नहीं रहेंगी। युद्धों का अन्त होगा। राष्ट्रीय सीमाएँ सांस्कृतिक एकता की जोड़ (कड़ी) होंगी। मूल्यपरिवर्तन की इस महान वैचारिक क्रान्ति से व्यक्ति, समाज और प्रकृति के बीच एक सन्तुलन पैदा होगा तथा व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक ही सब समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। यही है विश्वक्रान्ति की वैचारिक पृष्ठभूमि का संकेत।

-(स्वामी हंसदास जी, सन्तचेतना, धर्म एवं राजनीति : वैकल्पिक चिन्तन)

69) *"मैं सब जीवों और प्राणियों में एक ऐसी समरसता का अनुभव करता हूँ कि मेरे लिए इसका कोई अर्थ नहीं है कि व्यक्ति का जीवन कहाँ से आरम्भ होता है और उसका अन्त कहाँ होता है?" (अलबर्ट आइंस्टीन)।*

(सन्तचेतना, धर्म एवं राजनीति : वैकल्पिक चिन्तन)

70) *पश्चिमी जगत में राजकीय व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और आर्थिक समानता का संघर्ष आज भी जारी है। कार्ल मार्क्स के सिद्धान्त को लेकर लेनिन ने आर्थिक समानता लाने के लिए जिस व्यवस्था को स्थापित किया, उसमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का गला घोट दिया गया था। यूरोप व अमेरिका की पूँजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति की स्वतन्त्रता (आर्थिक स्वामित्व) को कायम रखा गया तो आर्थिक समानता की बलि चढ़ानी पड़ी। जाहिर है कि राजतन्त्र की संसदीय शासनपद्धति द्वारा स्वतन्त्रता और आर्थिक समानता दोनों में से किसी एक को ही प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान राजनीतिक ढाँचों में दोनों को प्राप्त करना शक्य नहीं है।*

विज्ञान तथा टेक्नॉलॉजी ने जो उपलब्धियाँ व्यक्ति के हाथ में रख दी हैं, उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आर्थिक समानता और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू बनाए जा सकते हैं, बशर्ते मानवसमाज की बुनियाद स्वशासन पर, (न्यायरूपी) धर्म पर आधारित हो। जब तक समाज शासन की बागडोर किसी अन्य के हाथों में रखेगा, तक तब संसार में आर्थिक समानता और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अभाव बना ही रहेगा। ***-(स्वामी प्रज्ञानन्दतीर्थ, सन्तचेतना, धर्म एवं राजनीति : वैकल्पिक चिन्तन)***

71) *अमरीका के महान अध्यक्ष जार्ज वाशिंगटन ने सोलहवीं सदी में अपने को 'मानवता के महान गणराज्य' का सदस्य घोषित किया। एक दृष्टा की हैसियत से उन्होंने कहा था-"मैं देख रहा हूँ कि समस्त मानवजाति एक विशाल परिवार की भाँति एकता की तरफ बढ़ रही है। स्वतन्त्रता और सामूहिकता का जो बीज हमने अमरीका में बोया है, वह विश्वभर में फैलेगा। एक दिन 'संयुक्त योरोप' भी बनेगा।"*

-(स्वामी सत्यदेव, सन्तचेतना, धर्म एवं राजनीति : वैकल्पिक चिन्तन)

72) *स्वतन्त्रता तथा आर्थिक समानता दोनों माँगों को एक साथ पूरी करने के लिए व्यवस्था का स्वयंशासी अर्थात् स्वायत्त होना बहुत जरूरी है। स्वायत्त व्यवस्था में अभाव की पूर्ति तथा नियन्त्रण के लिए कोई अन्य बाहरी घटक जिम्मेदार नहीं होता। स्वायत्त व्यवस्था खुद-मुखतारी अर्थात् स्वयं अपना शासन करने से आएगी। भारतीय ऋषियों ने इसके लिए एक सूत्र प्रस्तुत किया है-''**न वै राज्यं न राजाऽऽसीन्न दण्डो न च दाण्डिकः। धर्मेणैव प्रजा सर्वाः रक्षन्ति रम परस्परम्।**'' अर्थात् जहाँ न राज्य है और न उसके आश्रित लोग। दण्डव्यवस्था से मुक्त सभी लोग धर्म (न्याय) पूर्वक परस्पर रक्षा करते हैं। यह व्यवस्था धर्म से पैदा होगी, इसको हम पंचगणतन्त्र भी कह सकते हैं।*

पंचगणतन्त्र की सारी व्यवस्था चार आधारों पर खड़ी होगी- स्वाभाविक सहजता (सत्य), पारस्परिकता (प्रेम), स्वयंप्रेरणा (न्याय), साझेदारी (पुण्य)। ये चारों आधार भारत की पुरानी पंचायती गणतन्त्र व्यवस्था में मौजूद रहे हैं। इन्हीं को नये सन्दर्भ में सामयिक आवश्यकता के अनुसार स्वशासन का आधार बनाना होगा। इसप्रकार नये युग में राज्य के दमन, पूँजी के शोषण तथा सम्प्रदायवादी संकीर्ण रूढ़िवादिता से मुक्ति पाने के लिए धर्मसापेक्ष पंचगणतन्त्र की स्थापना करनी होगी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत छोटे-छोटे पंचगणों में जीवन की प्राथमिक जरूरतों को पूरी करने तथा प्राथमिक समस्याओं को हल करने की पूरी शक्ति और अधिकार निहित होंगे। ***-(स्वामी मुक्तानन्द, सत्तचेतना, धर्म एवं राजनीति : वैकल्पिक चिन्तन)***

73) *नई राजनीतिक व्यवस्था पंचगणतन्त्र के रूप में विकसित होगी। इसका सामयिक सन्दर्भों में विकास किया जाएगा। भारतीय जीवन में ग्राम का अर्थ कभी भी कूपमण्डूक जीवन नहीं रहा है। ऋग्वेद के ऋषि ने कहा था-''**विश्वं तुष्टं ग्रामेऽरिमन् अनातुरम्।**'' अर्थात् हमारे ग्राम में परिपुष्ट विश्व का दर्शन होना चाहिए। आगे ऋषि कहता है-''**अनु जनान् यतते पंचधीराः।**'' अर्थात् बुद्धिमान ज्ञानीजन पंचगणों के निर्णय का अनुसरण करते हैं। इन्हीं आधारों पर राजनीतिक क्रान्ति का सूत्रपात होगा तथा पंचगणतन्त्र कायम होगा। अब आधुनिक भारत का राजनीतिक ढाँचा इसप्रकार हो सकता है- प्रत्येक ग्राम या मुहल्ले के पाँच चरित्रवान व्यक्तियों का चुनाव यथासंभव सर्वसम्मति से किया जाए और उनकी पंचसमिति स्थापित की जाए। ऐसी दस स्थानीय गणपंच समितियों को मिलाकर जनपद गणपरिषद् का गठन किया जाए। बीस जनपद गणपंच परिषदों को मिलाकर एक क्षेत्रीय गणपंच परिषद् बनेगी। हर एक क्षेत्रीय गणपंच परिषद् से एक-एक प्रतिनिधि लेकर जो गठन होगा, वह राष्ट्रीय गणपंच संघ कहलाएगा। आगे जाकर सभी राष्ट्रों के राष्ट्रीय गणपंच संघों से एक-एक प्रतिनिधि लेकर एक विश्व गणपंच महासंघ स्थापित किया जाएगा। प्राथमिक गणपंच समितियाँ अपने में पूर्ण स्वायत्त और स्वतन्त्र होंगी। कोई भी एक गणपंच समिति दूसरे के अधीन नहीं होगी और न कोई किसी से छोटी या बड़ी होगी। सभी गणपंच इकाइयाँ परस्पर पूरकभाव से कार्य करेंगी। सर्वोदय का पूरा दायित्व गणपंच समिति का होगा। प्रत्येक क्षेत्रवासी को रोजगार देना, उसके सत्त्व (बौद्धिक शिक्षा) और अस्मिता की रक्षा का आश्वासन देना भी गणपंच समिति की जिम्मेदारी होगी। आसपास की गणपंच समितियाँ मिलकर निर्माण और विकास की बड़ी-बड़ी योजनाएँ भी चला सकेंगी। क्षेत्रीय प्राकृतिक सम्पदा, औद्योगीकरण तथा आबादी (जनसंख्या) का नियन्त्रण भी गणपंच समितियों के जिम्मे होगा। इसप्रकार प्रत्येक गणपंच समिति अपने में पूर्ण भी होगी और दूसरों के साथ परस्पर पूरक भी। इन आधारों पर बनी व्यवस्था स्वशासन की स्वावलम्बी व्यवस्था होगी, जिसमें समानता और स्वतन्त्रता दोनों को प्राप्त किया जा सकेगा। भारतीय चिन्तन में स्वशासित व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए बुनियादी आधार पहले से ही मौजूद हैं। इनको सामयिक सन्दर्भ करके परिपुष्ट करके पंचगणतन्त्र का विकास किया जा सकता है। पंचगणतन्त्र की आर्थिकनीति में ऊर्जा, धनशक्ति और पोषण के स्रोतों पर एकाधिकार नहीं रहेगा। ये तीनों विकेन्द्रित व स्वावलम्बन के आधार पर हर एक को प्राप्त होंगे। विकेन्द्रित व स्वावलम्बी अर्थनीति में कमजोरों को भी आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर रहते हैं। अर्थनीति की मजबूती इसी में है कि वह कमजोरों को भी पुष्ट करे। क्योंकि किसी भी जंजीर की ताकत उसकी सभी कड़ियों की समान मजबूती पर निर्भर करती है। पंचगणतन्त्र की अर्थनीति ऐसी हो जो कमजोरों को भी पुष्ट तथा प्रतिभासम्पन्न (शिक्षित) बनाए। साथ-साथ शिक्षा का भी सम्बन्ध है। शिक्षा की परिभाषा करते हुए महर्षि अरविन्द ने कहा है- ''भगवान ने मनुष्य को परिपूर्णता के साथ पैदा किया है। शिक्षा वह कला है जिसके द्वारा मनुष्य अपने पूर्णत्व को प्रकट करता है। इसप्रकार गुरु का कार्य शिष्य को वह कला सिखाना हो जाता है, जिससे वह अपने परिपूर्ण व्यक्तित्व का प्रकटीकरण कर सके।'' परिपूर्ण*

व्यक्तित्व के प्रकटीकरण की कला सीखने के बाद कोई व्यक्ति बेरोजगार रह ही नहीं सकता। जीवन में आजीविका के धन्धों के समाधान (Job Solution) की समस्याएँ भी पैदा नहीं होंगी। उपरोक्त आधारों पर खड़ी धर्मसापेक्ष गणतन्त्र व्यवस्था स्वशासित और स्वायत्त होकर सतत् प्रगति करती हुई प्रवाहित होती रहेगी।

-(स्वामी मुक्तानन्द, सन्तचेतना, धर्म एवं राजनीति : वैकल्पिक चिन्तन)

74) *बहाई धर्म परमात्मा और उसके अवतारों की एकता को स्वीकार करता है, सत्य की स्वतन्त्र और अप्रतिबन्धित उपलब्धि के सिद्धान्त का समर्थन और पोषण करता है, सभी प्रकार के अन्धविश्वासों और पूर्वाग्रहों की निन्दा करता है, यह शिक्षा देता है कि धर्म का आधारभूत उद्देश्य होता है– प्रेम और समन्वय उत्पन्न करना, कि उसे विज्ञान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, और केवल धर्म ही एक सुव्यवस्थित और प्रगतिशील समाज के निर्माण का एकमात्र और अंतिम आधार है। यह मानवहृदयों में स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान अवसरों, समान अधिकारों और समान सुविधाओं के सिद्धान्त की उद्भावना करता है, अनिवार्य शिक्षा का प्रतिपादन करता है, अत्यधिक गरीबी और अत्यधिक अमीरी के उन्मूलन का समर्थन करता है, सेवा की भावना से किए गए काम को ईश्वराराधना का ऊँचा दर्जा देता है, एक अन्तर्राष्ट्रीय सहायक की भाषा अपनाए जाने का समर्थन करता है और स्थायी विश्वव्यापी शान्ति की स्थापना के लिए आवश्यक साधनों को जुटाता है।* ***-(शोगी एफेन्दी, बहाई धर्म के संरक्षक)***

75) *विश्व में मंगल और सभी राष्ट्रों को खुश देखने की हमारी केवल इच्छा है, फिर भी वे दुःख पहुँचाने वाले हमें अकल्याणकारी और देशद्रोही समझते हैं और जेल तथा निष्कासन की सजा देते हैं। सभी राष्ट्रों का एक धर्म हो, इन्सान का इन्सान से भाईचारा हो, मानवजाति में प्रेम तथा एकता की जंजीरें और दृढ़ हों तथा जातियों के परस्पर मतभेद समाप्त हो जाएँ। आखिर इसमें कौन सी बुराई है ?.... खैर ऐसा ही होगा। ये सभी दुःख, बर्बादी फैलाने वाले युद्ध अवश्य समाप्त होंगे और महानतम शान्ति का साम्राज्य अवश्य आएगा.... एक आदमी को केवल यही गर्व नहीं होना चाहिए कि वह एक देशभक्त है अपितु संपूर्ण मानवजाति से प्रेम करने में ही उसे गर्व होना चाहिए।*

अन्य बातों के अतिरिक्त यही वे 'बहा' द्वारा कही गयी बातें हैं जो मुझे अभी भी याद हैं। अब यह उन पाठकों पर निर्भर करता है जो सोचें कि इन सिद्धान्तों की प्रतिक्रिया क्या मृत्यु और बंधन हैं ? या इन सिद्धान्तों के प्रचार से कुछ खोने के बजाय संसार अधिक पा सकेगा या नहीं ?

-(बहाईधर्म : एक परिचय, ग्लोरिया फैजी)

76) *जीवन की सभी अच्छी वस्तुएँ यहाँ हमारे आनन्द के लिए हैं और यदि हम जीवन के आनंदों को अस्वीकार कर दें तो हम ईश्वर के पास नहीं जा पाएँगे। फिर भी हमें यह अनुभव करना चाहिए कि हमारा निर्माण इस पृथ्वी पर एक पशु का जीवन बिताने और केवल अपने भौतिक लाभों के ही अन्दर लिप्त रहने के लिए नहीं हुआ है। हम यहाँ पर एक उद्देश्य के लिए आए हैं।*

कोई व्यक्ति भले ही उसका व्यक्तिगत जीवन कितना ही अच्छा क्यों न हो जब तक वह शेष मानवजाति के साथ मिलकर रहना और काम करना सीख नहीं जाता, तब तक इस पृथ्वी पर अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं करता। ***-(बहाईधर्म : एक परिचय, ग्लोरिया फैजी)***

77) *ओ आत्मा के पुत्र! मेरी दृष्टि में सबसे अधिक प्रिय न्याय है, अतः तुम मेरी कामना करते हो तो न्याय से जी न चुराओ और उसकी उपेक्षा मत करो, क्योंकि शायद मैं तुम्हारा विश्वास करूँ।*

तुम न्याय के द्वारा ही अपनी आँखों से, न कि दूसरों की आँखों से देख पाओगे और अपने ही ज्ञान से, न कि अपने पड़ोसी के ज्ञान से सकल पदार्थों को समझोगे। इस पर तुम अपने दिल में सोचो, तुम्हें क्या बनना शोभा देगा ? 'न्याय' निश्चय ही मेरा तुम्हें वरदान है तथा मेरी प्रेममय करुणा का संकेत है। हमेशा अपनी आँखों के सामने न्याय को रखो। ***(2)***

ओ मनुष्य के पुत्र! जब तक तुम स्वयं एक पापी हो तब तक दूसरों के पाप पर उसाँसें मत भरो, यदि इस आदेश को तुम भंग करोगे तो तुम्हें अभिशाप मिलेगा और इस बात का मैं साक्षी हूँ। ***(27)***

ओ अस्तित्व के पुत्र! जो आरोप तुझे अपने विषय में पंसद नहीं है वह अन्य आत्मा पर भी

मत लगाओ। तुम स्वयं जो आचरण नहीं करते उसका उपदेश दूसरों को न दो। यह तुम्हें मेरा आदेश है, इसका पालन करो। ***(29)***

ओ आत्मा के पुत्र! प्रत्येक दिन को तुम प्रलय का दिन मानो, क्योंकि मृत्यु का आगमन अघोषित होगा और तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा।

ओ मनुष्य के पुत्र! तुम चाहे आकाश की गहनता को भी तीव्रगति से पार कर लो और अंतरिक्ष के कोने-कोने में घूम लो तो भी तुम्हें हमारे आदेश को समर्पित हुए बिना तथा हमारे समक्ष विनम्रता में खड़े रहे बिना आराम नहीं मिल सकेगा। ***(40)***

ओ आत्मा की संतान! तुम्हारे हृदय में मेरा निवास है, मेरे अवतरण के लिए उसे निर्मल बनाओ। तुम्हारे अंतरतम् में मेरे प्राकट्य का स्थान है, मेरे स्वरूप के प्रतिबिम्ब के लिए उसे स्वच्छ करो।

ओ मनुष्य के पुत्र! तुमने अपने मनःतरंगों और कोरी कल्पनाओं में बहुत दिन गँवा दिए हैं। कब तक तुम सोये रहोगे? निद्रा से उठो। देखो सूर्य मध्याकाश में चमक रहा है। उठोगे तो यह तुम पर भी अपना सौन्दर्यपूर्ण प्रकाश डालेगा। ***(62)।*** ***-(निगूढ़वचन, बहाउल्लाह के ईश्वरीय संदेश)***

78) *''पहले संसार का शासन ताकत से चलता था और पुरुष ने स्त्री पर अपनी प्रभुता बना ली थी, केवल इसी कारणवश कि वह शरीर और मस्तिष्क दोनों से अधिक शक्तिशाली और आक्रमणकारी था। परन्तु संतुलन तो स्थापित होना शुरु हो गया है। शक्ति अपना प्रभाव खो रही है और मानसिक जागरूकता, सहज ज्ञान, प्रेम तथा सेवा के आत्मिक गुण जिनमें स्त्रियाँ मजबूत हैं अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं, अतः नये युग में पौरुषिक गुण कम होंगे और यह स्त्रियों के आदर्शों से अधिक जुड़ा होगा या और सही कहें तो यह एक ऐसा युग होगा जब सभ्यता के दोनों तत्त्व स्त्री और पुरुष में और अच्छी तरह से संतुलन स्थापित होगा।'' (बी.एन.ई. : 56)।*

-(बहाईधर्म : एक परिचय, ग्लोरिया फैजी)

79) *''वह दिन आ रहा है जब दुनिया के सभी लोग एक विश्वभाषा और लिपि ग्रहण करेंगे। जब ऐसा हो जाएगा तब किसी भी शहर में कोई व्यक्ति जाए तो वह ऐसा ही महसूस करेगा कि मानो अपने घर में प्रवेश कर रहा हो।'' (बी.आर. : 76)।* ***-(बहाईधर्म : एक परिचय, ग्लोरिया फैजी)***

80) *शिक्षा के विषय में बहाउल्लाह के उपदेश बिल्कुल स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा कि ''निश्चित रूप से प्रत्येक पिता को अपने पुत्रों और पुत्रियों को शिक्षित कराना चाहिए।''*

''अपने पुत्र को या किसी और के बच्चों को शिक्षा देना मेरे बच्चों में से किसी एक को शिक्षा देने के बराबर है।'' ***(बी.डब्लू.एफ. : 200)***

''विद्यालयों को सर्वप्रथम बच्चों को धर्म (आचरण) के सिद्धान्तों में पारंगत करना चाहिए ... परन्तु इसप्रकार कि वे अनाड़ी उन्मादकता और संकीर्ण मनोवृत्ति के द्वारा बच्चों को क्षति न पहुँचाए।'' ***(पी.बी.एल. : 25)***

यदि माता-पिता अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन न कर सकें तो समुदाय को सामुदायिक जमाराशि (राष्ट्रकोष) द्वारा उनकी शिक्षा का खर्च उठाना चाहिए। ***-(बहाईधर्म : एक परिचय, ग्लोरिया फैजी)***

81) *पूर्ण समानता जहाँ तक धन का संबंध है, असंभव है क्योंकि लोगों की समर्थता और रुचि भिन्न है। यदि हमें समानरूप से रहने को विवश किया जाए तो विश्व-व्यवस्था बिगड़ जाएगी। समाज को किसी भी आलसी अमीर या गरीब व्यक्ति को दूसरे के परिश्रम के फल पर जीवित रहने की अनुमति बिल्कुल नहीं देनी चाहिए।*

''भविष्य में संभव नहीं होगा कि यह लोग दूसरों के श्रम पर संपत्ति का ढेर जमा करें। अमीर खुद से हिस्सा बाँटेंगे। वे धीरे-धीरे प्राकृतिक रूप से स्वेच्छापूर्वक इस बात को मानेंगे। यह युद्ध या खूनखराबे से कभी भी संभव नहीं होगा।'' (बी.एन.ई.152)। ***-(बहाईधर्म : एक परिचय, ग्लोरिया फैजी)***

82) *मानवजाति समुदाय, नगर, राज्य और भिन्न राष्ट्र बनाने के चरणों से गुजर चुकी है। अब एक विश्व-परिवार की स्थापना का समय आ गया है। एक समय आवश्यक था कि आपस में लड़ने वाली विभिन्न जातियों और वर्गों को जोड़कर एक राष्ट्र बनाया जाए। उस समय देश के लिए प्रेम, प्रशंसायोग्य और सबसे ऊँची वफादारी माना जाता था। आज अनेक प्रकार की राष्ट्रीयता मानवजाति की एकता में एक रोड़ा है। बहाउल्लाह कहते हैं :-*

''अपने ही देश से प्रेम करना गर्व की बात नहीं है, गर्व की बात तो है समग्र विश्व से प्रेम करना।'' (जी.डब्लू.बी. : 95)

नवीन विश्व-व्यवस्था में कोई भी दुर्बल राष्ट्र न होने के कारण दुनिया के लोग समानरूप में मिलेंगे, उनकी सरकारें अपने लोगों का विश्व-संसद में प्रतिनिधित्व करेंगी जो सभी देशों की संपत्ति और मानवजाति की खुशियों के बारे में फिक्र करेंगी।

भविष्य का विश्व-परिवार न केवल प्रत्येक राष्ट्र की स्वायत्तता और प्रत्येक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सुरक्षित रखेगा बल्कि दुनिया की सभी हुकूमतों से माँग करेगा कि वे अपने शस्त्रों के अधिकार को छोड़ दें। केवल अपनी सीमा में व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही वे हथियार रखें।

एक विश्व-परिवार की सरकार अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के सहारे राष्ट्रों की आवश्यकतापूर्ति के लिए उनके बीच संबन्धों को बनाए रखने के लिए आवश्यक कानूनों को अमल में लाएगी और किसी झगड़े के उठ खड़े होने पर एक विश्व-न्यायालय हल निकालेगा चाहे दोनों पक्ष उसका हस्तक्षेप न चाहें।

इस पृथ्वी के ढेरों साधनों को संसार के सभी लोगों के हितों के लिए प्रयुक्त किया जाएगा और रुपया, भार तथा नाप-तोल की एक समान प्रणाली के द्वारा राष्ट्रों के आपसी व्यवहार को सरल और सुविधाजनक बनाया जाएगा।

संगठित और युद्ध के अभिशाप से मुक्त मानवता ऐसे लक्ष्यों जैसे जीवनस्तर को उठाना, शिक्षा का प्रसार, बीमारियों की रोकथाम, विज्ञान की उन्नति, कला के विकास और पृथ्वी पर मानवजाति के भौतिक विकास के साथ आध्यात्मिक विकास की पूर्ति के लिए ढेरों साधन और शक्ति खर्च करेगी। इसप्रकार एक विश्व-सभ्यता बनेगी जिसमें प्रत्येक जाति और देश अपना अधिकतम सहयोग देंगे। ***-(बहाईधर्म : एक परिचय, ग्लोरिया फैजी)***

83) *''समस्त विश्व एक देश है और समस्त मानव इसके नागरिक हैं।'' (जी.डब्लू.बी.249)*

''एकता का छायामण्डल उठ चुका है, एक-दूसरे को अपरिचित मत समझो। तुम सब एक ही पेड़ के फल हो और एक ही शाख की पत्तियाँ हो।'' (जी.डब्लू.बी. : 217)

''ऐ दुनिया के झगड़ा करने वाले लोगों, एकता की ओर बढ़ो और इसके प्रकाश की शोभा से खुद को कान्तिवान करो। एक साथ इकट्ठा होओ और ईश्वर के लिए अपने मध्य झगड़े की किसी भी वजह को जड़ से उखाड़ दो।'' (जी.डब्लू.बी. : 216)

''सभी लोगों का जन्म सदैव विकासशील सभ्यता की ओर आगे ले जाने के लिए हुआ है ... जंगल के जानवरों की तरह रहना मनुष्य के लिए योग्य नहीं है, सहनशीलता, दया, सहिष्णुता और पृथ्वी के सभी लोगों और सजीव प्राणियों के प्रति कृपा वे गुण हैं जो मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं।'' (जी.डब्लू.बी. : 214)

''सत्कार्य और वफादारी के अनुयायियों को दुनिया के सभी लोगों से उल्लासपूर्वक, मित्रता की सुगंध के साथ हाथ मिलाना चाहिए क्योंकि संगठन सदैव एकत्व और सुसंवादिता के अनुकूल होता है और एकत्व तथा सुसंवादिता के कारण ही विश्व-व्यवस्था और राष्ट्रों का जीवन संभव है।'' (बी.डब्लू.एफ. : 168)

''वह सचमुच एक मानव है जो आज संपूर्ण मानवजाति के लिए स्वयं को अर्पित कर देता है।'' (जी.डब्लू.बी. : 249)

''तुम साक्षी हो कि दुनिया पर प्रतिदिन कैसी नयी विपत्तियाँ आ रही हैं। इसके दुःख प्रतिदिन और बढ़ रहे हैं ... इसकी बीमारी अब अत्यंत निराशाजनक स्थिति में पहुँच चुकी है। क्योंकि हमने सच्चे चिकित्सक को इलाज करने से निषेध कर दिया है जबकि अनाड़ी चिकित्सकों को चुनकर उन्हें चिकित्सा करने की छूट दे दी है।'' (जी.डब्लू.बी. : 39)

जिनके पास अधिकार है, उनका कर्तव्य है कि सभी चीजों के अंदर विवेक से कार्य करें। विवेक की सीमा से परे कोई भी चीज लाभदायक प्रभाव नहीं डालेगी। उदाहरणार्थ- स्वतन्त्रता, सभ्यता और ऐसी ही चीजों को देखो। कितने ही जानकार लोग आज उनका पक्ष लें इनकी अतिशयता का भी मनुष्य पर बुरा

प्रभाव होता है। मानव आखिर कब तक भटकता रहेगा? अन्याय का दौर कब तक चलेगा? शासन में गड़बड़ और दुःख कब तक रहेंगे? सभ्यता के मुख पर झगड़ों, मतभेदों का कलंक कब तक लगा रहेगा? खेद है, निराशा की हवा प्रत्येक दिशा में बह रही है। जैसे-जैसे आज की व्यवस्था खेदपूर्वक दोषवान दिख रही है वैसे-वैसे आने वाले तूफान और कष्टों के चिन्ह स्पष्ट हो रहे हैं।'' (जी.डब्लू.बी. : 215)

... सावधान रहो कि तुमसे किसी के प्रति अन्याय न हो चाहे वह राई के दाने जितना छोटा क्यों न हो ...

अपने मतभेद सुलझाओ और शस्त्रों को कम करो जिससे तुम्हारा खर्च का भार हल्का हो सके। विवेक की सीमाओं का कभी उल्लंघन न करो और न ही अत्यंत खर्चीले व्यक्तियों में तुम्हारी गिनती हो।

तुम्हें ज्ञात हो कि तुम्हारे मध्य रहने वाले निर्धन, ईश्वर के विश्वस्त हैं। तुम्हें जागरूक होना पड़ेगा कि तुम उसके विश्वास को धोखा न दो और गरीबों के प्रति अन्यायी न बनो। (जी.डब्लू.बी. : 249)

एक सत्य ईश्वर मेरा साक्षी है। (जी.डब्लू.बी. : 285)

ईश्वर हमें एकता का प्रकाश प्रदान करे, जो पूरी दुनिया को स्वयं में लपेट ले और सभी लोगों के मस्तकों पर 'राज्य ईश्वर का है' की मुहर अंकित हो जाए। (जी.डब्लू.बी.:11)।

-(बहाईधर्म : एक परिचय, ग्लोरिया फैजी)

84) *सभी मनुष्यों में सबसे अधिक लापरवाह वह है जो बिना किसी कारण झगड़ा करता है और अपने भाई को दबाकर आगे बढ़ना चाहता है। कहो, भ्राताओं, कर्म को, न कि शब्दों को अपना आभूषण बनाओ। (एच.डब्लू. : 94)।*

-(बहाईधर्म : एक परिचय, ग्लोरिया फैजी)

85) *शीघ्र ही वर्तमान व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और इसके स्थान पर एक नई व्यवस्था का विस्तार होगा। (बहाउल्लाह, जी.डब्लू.बी. : 7)*

मानवसन्तानों की खुशहाली और शान्ति की उन्नति के लिए ध्यान दो। पृथ्वी के सभी लोगों और प्राणियों की शिक्षा के लिए पूरी इच्छा और मन लगा दो। यह संभवतः आपस में फूट पैदा करने वाले अनमेल को महामहिमामय शक्ति द्वारा मिटा देगी। पूरी मानवजाति की एक ही व्यवस्था होगी और वे एक शहर के निवासियों के समान होंगे। (जी.डब्लू.बी. : 332)

जिन लोगों को ईश्वर ने अन्तर्दृष्टि प्रदान की है वे अवश्य पहचान लेंगे कि ईश्वर के दिए उपदेश विश्व की व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च साधनों का निर्माण करते हैं। (जी.डब्लू.बी. : 330)

ईश्वर के मुख से निकले प्रत्येक शब्द में ऐसा गुरुत्व होता है यदि मानव इस सत्य को समझे तो वह इसे नया जीवन प्रदान कर सकता है। आगामी दिनों में वह किसी देखी न सुनी वस्तु से सत्य ही हमारा साक्षात्कार कराएगा। (जी.डब्लू.बी. : 141)

ओ मेरे प्रभु! अपने सेवकों के दिलों को एकता की डोर से जोड़ो और उन पर अपने महान उद्देश्य को प्रकट करो। जिससे वे तुम्हारी आज्ञा का अनुसरण और तुम्हारे कानून (न्याय) का पालन करें। ओ ईश्वर! उनके प्रयासों में उनकी सहायता करो और तुम्हारी सेवा करने के लिए उन्हें शक्ति दो। ओ प्रभु! उन्हें खुद पर ही मत छोड़ो परन्तु उनके कदमों को अपने ज्ञान (सत्य) के प्रकाश से मार्गदर्शन दो और प्रेम से उनके हृदयों को आनन्द से भर दो। सत्य ही, तुम ही उनकी सहायता करने वाले और स्वामी हो। (जी.डब्लू.बी. : 61)

हमें अपनी सरकार का आज्ञापालक और शुभचिन्तक होना चाहिए। एक न्यायी राजा से विश्वासघात को स्वयं ईश्वर से विश्वासघात मानो और सरकार का बुरा चाहना ईश्वरीय धर्म का उल्लंघन है। (बी.आर. : 308)।

-(बहाईधर्म : एक परिचय, ग्लोरिया फैजी)

86) *क्या आपने कभी किसी जंगल की एक खेत से तुलना की है? वन में पेड़ अव्यवस्थित रूप में पैदा होते हैं; घनी झाड़ियाँ और उलझी हुई बेलें होती हैं। खेत की सीमाएँ निधारित होती हैं, हल चला हुआ होता है। नहरों तथा नालों का जाल सा बिछा होता है। कहीं पर मकई बोई होती है तो कहीं पर गन्ने का खेत होता है।*

एक अव्यवस्थित जंगल और खेत में क्या अन्तर है?

खेत की प्रत्येक वस्तु में आप एक व्यवस्था देखते हैं जबकि जंगल में कोई व्यवस्था नहीं होती। खेत में प्रत्येक वस्तु की ओर ध्यान दिया जाता है और उसकी चौकसी की जाती है जबकि जंगल में प्रत्येक वस्तु आकस्मिक और अव्यवस्थित रूप में पैदा होती है। जहाँ कहीं भी व्यवस्था होती है, उसके पीछे अवश्य ही कोई उद्देश्य होता है।

-(नई फुलवाड़ी : हूशनन्द फत्हेआजम)

87) *जब दुनिया के लोग ईश्वर के संदेश की सच्चाई (सत्ज्ञान) स्वीकार कर और जागरूक होकर उसके लिए आध्यात्मिक तथा सामाजिक नियमों पर आधारित एक नया समाज बनाने के लिए काम करेंगे, तब महानतम शान्ति आएगी और अतीत के ईश्वर दूतों की शान्ति और न्याय के स्वर्णिम युग की भविष्यवाणी सत्य होगी।*

-(बहाईधर्म : एक परिचय, ग्लोरिया फैजी)

88) *भगवान बहाउल्लाह हमें बताते हैं कि संसार की सभी वस्तुओं में से 'न्याय' को वे अधिक महत्त्व देते हैं :–*

''हे आत्मा के पुत्र! मेरी दृष्टि में सर्वप्रिय वस्तु न्याय है। यदि तू मेरी कामना करता है तो उससे विमुख न हो।''

''प्रत्येक मानव का दैनिक भोजन पर जन्मसिद्ध अधिकार है जिसके द्वारा वे जीवित रहते हैं अथवा जीविका उपार्जन के साधनों में समान अवसर हों।।''

''लोगों की परिस्थितियों की व्यवस्था अवश्य ही ऐसी हो कि दरिद्रता का सर्वथा लोप हो जाए, कि यथासंभव प्रत्येक व्यक्ति अपनी श्रेणी और पद के अनुसार सुख तथा समृद्धि में भागीदार बने।''

''हम अपने बीच एक ओर उन लोगों को देखते हैं जो धन के भार में दबे हुए हैं और दूसरी ओर उन भाग्यहीनों को जो बिना किसी आधार के भूख से तड़पते हैं– वे जिनके पास बहुत से राजमहल हैं और वे जिनके पास सिर छुपाने को भी स्थान नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें भाँति–भाँति के मूल्यवान तथा स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हैं जबकि दूसरों को जीवित रहने के लिए रोटी के टुकड़े भी पूरी मात्रा में प्राप्त नहीं होते। कुछ व्यक्ति मखमली, समूरी तथा उत्तम वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दूसरों के पास अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए अपर्याप्त घटिया तथा सादे वस्त्र मुश्किल से होते हैं।''

''यह परिस्थिति उचित नहीं और अवश्य ही सुधारी जानी चाहिए।''

''निश्चित रूप से कुछ व्यक्तियों के अत्यन्त धनी तथा दूसरों के शोकपूर्ण हद तक निर्धन होने के कारण एक संस्था की आवश्यकता है जो इन परिस्थितियों पर काबू पा सके तथा इन्हें सुधार सके। ध नि कता को सीमित करना उतना ही आवश्यक है जितना कि निर्धनता को रोकना। इनमें से किसी की भी अधिकता अच्छी नहीं।''

जब हम देखते हैं कि निर्धनता को भुखमरी की सीमा तक बढ़ने दिया जा रहा है तो यह इस बात का निश्चित प्रतीक है कि हमें कहीं न कहीं अत्याचार सहना पड़ेगा। इस विषय में लोग अवश्य ही कुछ न कुछ उद्यम करने और उन परिस्थितियों के बदलने में देर न करें जो लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या को अत्यन्त निर्धनता की चक्की में पीस देती है''। ***-(नई फुलवाड़ी : हूशमन्द फत्हेआजम)***

89) *संसार में गलतफहमियों के कारणों में से एक यह भी है कि लोग एक–दूसरे की भाषा नहीं समझते। प्रत्येक देश की भाषा भिन्न है और जब कोई व्यक्ति अपने देश से संसार के किसी अन्य भाग में जाता है तो ऐसा अनुभव करता है जैसे वह अपरिचितों के बीच है।*

भाषा का अन्तर कई बार भ्रमों का कारण बन जाता है। जिससे भयानक कलह तथा झगड़े पैदा हो सकते हैं। उदाहरणस्वरूप अपने सृष्टा का नाम ही लीजिए, हिन्दी भाषा में उसे 'ईश्वर', अरबी में 'अल्लाह' और अंग्रेजी में 'गॉड' कहा जाता है। अज्ञानी लोग सोचते हैं कि गॉड, ईश्वर अथवा अल्लाह से भिन्न है और इन भिन्न–भिन्न नामों को लेकर वे एक–दूसरे से लड़ते–झगड़ते रहते हैं। जब लोग एक ही सामान्य विश्वभाषा बोल सकेंगे तो वे महसूस करेंगे कि सृष्टा एक ही है जिसका वे सब हवाला दे रहे हैं। यही बात उनके बीच से भ्रमों को दूर कर देगी। ***-(नई फुलवाड़ी : हूशमन्द फत्हेआजम)***

90) *यदि आप किसी कबूतर के एक डैने के पर काट दें तो चाहे उसका दूसरा डैना कितना ही मजबूत क्यों न हो, वह उड़ नहीं सकेगा क्योंकि पक्षी को उड़ने के लिए दो पंखों की आवश्यकता होती है।*

अब्दुल–बहा कहते हैं :– ''मानवजाति एक पक्षी के समान है, जिसके दो पंख हैं, एक पुरुष दूसरा स्त्री। जब तक दोनों पंख मजबूत न होंगे और एक साँझी शक्ति द्वारा हिलाए न जाएँगे, तब तक पक्षी आकाश में ऊँची उड़ान नहीं भर सकता।'' पुनः वे कहते हैं :–

''भगवान ने सभी प्राणियों को जोड़ों में उत्पन्न किया है। मनुष्य, पशु या वनस्पति, इन तीनों सृष्टियों की सभी वस्तुएँ दो प्रकार के लिंगों में हैं और उनमें पूर्ण समानता है।''

''वनस्पति जगत में नर और मादा पौधे होते हैं, उन्हें समान अधिकार प्राप्त हैं, चाहे फलवान वृक्ष को फलहीन वृक्ष से उत्तम ही कहा जाए।''

''पशु जगत में हम देखते हैं कि नर और मादा को समान अधिकार प्राप्त हैं, तथा उनमें से प्रत्येक को अपनी जाति के लाभ प्राप्त हैं।''

''अब हमने देखा है कि प्रकृति के निचले दो क्षेत्रों में एक लिंग की दूसरे लिंग से श्रेष्ठता का कोई प्रश्न नहीं है। मानवसंसार में हम बहुत बड़ा अन्तर पाते हैं, स्त्रीजाति से ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे वह दीन हो और उन्हें समान अधिकार तथा विशेषाधिकार नहीं दिए जाते। यह दशा प्राकृतिक नहीं है बल्कि अज्ञान के कारण है। दैवीसृष्टि में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। ईश्वर की दृष्टि में कोई भी जाति दूसरी जाति से श्रेष्ठ नहीं है।''

क्योंकि प्रभु की कृपा पुरुष तथा स्त्री दोनों को ही प्राप्त होती है, हमें उनमें भेद नहीं करना चाहिए। समाज में पुरुष के कर्तव्य स्त्री के कर्तव्यों से चाहे भिन्न हों परन्तु उसके अधिकार तथा विशेषाधिकार अवश्य ही समान हों। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि स्त्री में पुरुष से कम गुण हैं। पिछले युगों में स्त्रियों को वैसी शिक्षा तथा अवसर प्राप्त न थे जैसे पुरुषों को और यही कारण है कि वे अपनी विभिन्न क्षमताओं का विकास नहीं कर सकीं। ***-(नई फुलवाड़ी : हूशमन्द फत्हेआजम)***

91) *''सावधान! ऐसा न हो कि तुम अपने आप को अपने पड़ोसियों से अधिमान्यता दो।'' –(बहाउल्लाह)*

''स्वयं अपने तथा दूसरों के प्रति ईमानदार बनो ताकि तुम्हारे कार्यों द्वारा हमारे वफादार सेवकों में न्याय के प्रमाण प्रत्यक्ष हों।'' –(बहाउल्लाह)

''मानव सद्गुणों में सबसे अधिक मौलिक सद्गुण न्याय है। तुम्हारा सभी वस्तुओं का मूल्यांकन अवश्य ही इस पर आधारित हो।'' –(बहाउल्लाह)

''कहो ऐ ज्ञानयुक्त हृदय के मानवों! अपने निर्णय में न्याय का पालन करो। जो व्यक्ति अपने निर्णय में अन्यायी है, वह मनुष्य के पद को प्रतिष्ठित करने वाले गुणों से वंचित है।'' –(बहाउल्लाह)

''अपने पड़ोसी के पदार्थ के साथ विश्वासघातपूर्ण व्यवहार न करो, पृथ्वी पर विश्वासपात्र बनो और निर्बलों को उन वस्तुओं से वंचित न रखो जो प्रभु ने अपनी कृपा द्वारा तुम्हें प्रदान की हैं। निस्सन्देह जो कुछ तुम्हारे पास है, वह उससे दुगुना तुम्हें देगा।'' –(बहाउल्लाह)। ***-(नई फुलवाड़ी : हूशमन्द फत्हेआजम)***

92) *अपने समय को आलस्य तथा बेकारी में मत गँवाओ तथा अपने आप को उसमें व्यस्त करो जो तुम्हारे तथा तुम्हारे अतिरिक्त दूसरों के लिए लाभप्रद हो। इसप्रकार इस पाटी में, जिसके क्षितिज में विद्वता तथा दैवी वाणी का सूर्य चमक रहा है, इस विषय के बारे में आज्ञा हुई है। ईश्वर के सम्मुख सबसे ज्यादा घृणित व्यक्ति वह है जो बैठे–बैठे भिक्षा माँगता है। कारणों को उत्पन्न करने वाले प्रभु पर विश्वास करते हुए साधनों की रस्सी को थाम लो। प्रत्येक आत्मा जो अपने आपको किसी कला या व्यापार में व्यस्त करती है, यह प्रभु के सामने आराधना मानी जाएगी। निश्चय ही यह उसकी महान तथा बृहद् कृपा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है''।* ***-(नई फुलवाड़ी : हूशमन्द फत्हेआजम)***

93) *'बहाउल्लाह' की आज्ञाओं में से एक यह है कि प्रत्येक बच्चा चाहे वह लड़का हो या लड़की, अवश्य ही शिक्षा प्राप्त करे। यदि माँ–बाप अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की अवहेलना करते हैं तो वे प्रभु के सामने उत्तरदायी हैं। 'बहाउल्लाह' का यह उपदेश है :–*

''आज्ञा है कि प्रत्येक पिता अपने पुत्रों और पुत्रियों को लिखने–पढ़ने की शिक्षा दें। जो मनुष्य (इस मामले में) इस आज्ञा की उपेक्षा करता है यदि वह धनी है तो न्यायमंदिर (सरकार) के पदाधिकारियों को चाहिए कि उससे उतना धन हासिल कर लें, जितना उसके बच्चों की शिक्षा के लिए पर्याप्त हो, अन्यथा (यदि माँ–बाप इस योग्य न हों) तो इस बात का भार न्यायमंदिर (सरकार) के ऊपर होगा।''

शिक्षा अवश्य ही हमें अन्धविश्वासों, पक्षपातों तथा प्रकृति के पंजों से स्वतन्त्र करे। अब्दुल–बहा कहते हैं :–

''और परमपवित्र बहाउल्लाह के उपदेशों में है मनुष्य की स्वतन्त्रता, कि मानसिक सामर्थ्य द्वारा उसे स्वतन्त्र तथा नैसर्गिक संसार की आधीनता से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि जितनी अवधि तक मनुष्य प्रकृति के अधीन है उतनी अवधि तक वह हिंसक पशु है क्योंकि जीवनसंघर्ष नैसर्गिक संसार की आवश्यकताओं में से एक है। जीवनसंघर्ष का यह तत्त्व समस्त अनर्थों का स्रोत तथा प्रमुख क्लेश है''। ***-(नई फुलवाड़ी : हूशमन्द फत्हेआजम)***

94) *"ज्ञान मनुष्यों के लिए पंखों जैसा या कहीं चलने के लिए सीढ़ी के समान है। ज्ञान प्राप्त करना सबके लिए आवश्यक है परन्तु ऐसे विज्ञानों का, जिनसे संसार के लोगों का भला हो, ऐसे विज्ञानों का नहीं जो शब्द से आरम्भ होकर शब्दों पर ही समाप्त हो जाएँ। संसार के लोगों में कला-कौशल और विज्ञान जानने वालों का बड़ा अधिकार होता है। वास्तव में मनुष्य की सच्ची सम्पत्ति उसका ज्ञान ही है। ज्ञान ही सम्मान, सम्पत्ति, हर्ष, आनन्द, सुख और उन्नति का साधन है।"* ***-(बहाउल्लाह, नई फुलवाड़ी : हूशमन्द फत्हेआजम)***

95) *मध्यकाल के अन्धकार युग में सामन्ती व्यवस्था जिन दिनों चल रही थी, उन दिनों समर्थ लोग असमर्थों को अपनी इच्छानुसार चलाते थे। उन्हें पशुओं की तरह प्रतिबन्धित जीवन जीना पड़ता था। "जिसकी लाठी उसकी भैंस" वाला जंगली कानून चलता था। जिसप्रकार मनुष्य पशुओं को पालते और उनकी शरीरसम्पदा का लाभ उठाते हैं वैसा ही व्यवहार समर्थजन असमर्थों के साथ करते थे। उन्हें न विरोध करने का अवसर मिलता था, न अपनी कठिनाई बताने का। अनीति को मिटाने, जूझने के प्रयास में वे असफल ही रहते थे। यह सिलसिला लम्बी अवधि तक चला। दुर्बलों को, असंगठितों को, असंगठित जनों के समर्थकों को विविधा-विधि अनाचार सहने पड़े। तब इन दुर्व्यवहारों को सामाजिक मान्यता भी मिली हुई थी। पति का अधिकार था कि पत्नी से चाहे जैसा व्यवहार करे। उसे चाहे जिस स्थिति में रहने के लिये विवश करे। परित्याग कर दे अथवा मार भी डाले। नारी कुछ कर नहीं सकती थी। विरोध की उसमें हिम्मत न थी। दूसरों को इसमें दखल देने का अधिकार न था। ऐसी दशा में विवशता को शिरोधार्य करते रहने के अतिरिक्त असमर्थों, असंगठितों के पास कोई चारा भी न था। जो भोगना पड़ता था, उसे भाग्यविधान कहकर अनदेखा किया जाता था। यही भारत की उन दिनों मानसिकता थी।*

दास-दासी प्रथा उन्हीं दिनों धड़ल्ले से चली थी। समर्थ अपने शस्त्रबल, शरीरबल, और सैन्यबल के सहारे किन्हीं को भी बलात् पकड़ लेते थे। उन्हें बन्धनों में बाँधकर इच्छानुसार चलाते, बेचते, खरीदते, दान देते रहते थे। प्रजा पर राजा का अधिकार था। प्रजाजन राजा की सम्पत्ति माने जाते थे। उनकी सम्पदा को जब चाहे तब जब्त कर सकते थे या जितना भाग लेना चाहें, उतना कररूप में जबरदस्ती वसूली कर लेते थे।

इसे आतंक का राज कह सकते हैं। राजा, सामन्त, सेनापति, अमीर, जागीरदार, जमींदार, साहूकार अपने चंगुल में फँसे हुए लोगों के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते थे। न्यायभाव जैसी कोई बात नहीं थी। राजा का धर्म ही प्रजा का धर्म बन जाता था, व्यक्तियों को स्वेच्छापूर्वक अपने लिये धर्म चुनने या बदलने, छोड़ने जैसा अधिकार न था। इस दयनीय स्थिति में मनुष्यजाति के दुर्बलपक्षों को पिछले दिनों लम्बी अवधि तक रहना पड़ा है।

समय ने करवट बदली। युग बदला, विवेक जगा और शक्ति सामन्तों के हाथ से निकलकर सामान्य जनों के हाथ आई। इसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन सामने आये। इनमें सबसे बड़ी बात हुई- मानवी मौलिक अधिकारों को मान्यता मिलना। न्याय और औचित्य को प्रश्रय मिला। असमर्थों में बदला लेने की या अपने बलबूते चलती हुई मनमर्जी को रोक सकने की प्रत्यक्ष सामर्थ्य तो थी नहीं, तो भी लोकचेतना ने ऐसा वातावरण बनाया जिससे विवेक और न्याय के औचित्य की आवश्यकता समझी और समझाई जाने लगी। प्रजाजनों के संख्याबल के औचित्य को अपनाए जाने का दबाव पड़ने से हर क्षेत्र में, हर देश में ऐसी हवा बही कि न कोई मुकदमा चला, न कोई संघर्ष हुआ पर न्याय के समर्थकों की एक समर्थ सेना सर्वत्र एकत्र उठ खड़ी हुई और उसने अपने ढंग से संघर्ष भी किए और परिवर्तनों को भी माहौल बनाया।

इन दिनों मनुष्य के मौलिक अधिकारों का उपयोग कर सकने के प्रचलन चल पड़े हैं। वाणी की, लेखनी की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, मानवी समता की मान्यताएँ मिल गई हैं, मिल रही हैं। मतदान द्वारा सरकारें बनाने का प्रवाह भी सर्वत्र चलता देखा जा सकता है। जिनकी दाढ़ों में आधिपत्य का चस्का लगा हुआ है वे उस जनाधिकार को निरस्त करने के भी कम प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। सफलता को असफलता की दिशा में घसीटने के लिये प्रतिक्रियावादी कमजोर नहीं लग रहे हैं। फिर भी बहती प्रचण्ड धारा को देर तक रोके रह सकना किसी के भी वश की बात नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के नस्लवादी संघर्ष को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है।

सर्वसाधारण को युगचेतना के उभार और अवलोकन से परिचित कराया जा रहा है कि मनुष्यमात्र को समानता अपनाते हुए सहयोगपूर्वक रहना चाहिए। ***'जियो और जीने दो'*** *का सिद्धान्त अपनाना चाहिए। अपने को किसी से बढ़कर नहीं मानना चाहिए और किन्हीं की विवशताओं का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। परम्पराओं की दुहाई देकर पिछली भूलों पर चलते रहे, अनौचित्यों को पूर्ववर्ती प्रथा-प्रचलन कहकर*

युगचेतना के कार्य में अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहिए।

जहाँ अनौचित्य की भूली-बिसरी स्मृतियों को फिर से कार्यान्वित करने के लिये प्रतिगामी प्रयास किये जा रहे हों वहाँ आगे बढ़कर रोकथाम करनी ही चाहिए। अनौचित्य का विरोध किया जाना चाहिए। उसे असफल बनाने के लिये असहयोग से लेकर संघर्ष तक के यथासम्भव कदम उठाने चाहिए। दुर्बलपक्ष अनीति का शिकार हो रहा हो तो उसे साहस प्रदान करना चाहिए तथा समर्थन भी। समता और एकता का सार्वभौम प्रचलन भलीप्रकार स्थिर हो सके और अपने पैर इतनी मजबूती से जमा सके कि उन्हें उखाड़ सकना किसी के लिये भी संभव न हो सके। इसी के निमित्त अपना नैतिक और क्रियात्मक प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान करना चाहिए। यही है समय की पुकार, युग की माँग, औचित्य की गुहार। उसे भलीप्रकार सुना व समझा जाना चाहिए।

मानवी अधिकारों के हनन में जहाँ अत्याचारीवर्गों की ज्यादतियाँ काम करती हैं, वहाँ एक कारण यह भी रहा है कि उत्पीड़ितों ने बहुसंख्यक होते हुए भी अपने अधिकारों के प्रति जागरुकता प्रकट नहीं की। उस मान को, उस गौरव को भी उसने भुला दिया। यदि उन्होंने अपने को, अपनी शक्ति को, मौलिक अधिकार भावना को अपने अन्दर जगाया होता, तो इतने प्रयत्न से भी अनाचारियों के सीने ठनके होते और भावी विद्रोह की सम्भावना को समझते हुए सुधार परिवर्तन की नीति अपनाई होती। भले ही वह धीमी रही होती, पर दबाव तो उससे निश्चित रूप से हल्का हुआ होता।

संसार के विभिन्न भागों पर राजतन्त्र का, साम्राज्यवाद का, पूँजीवाद का बोलबाला रहा है। इसका अनौचित्य उत्पीड़क और पीड़ित दोनों ही समझते रहे हैं, पर लम्बे समय तक यथास्थिति बनी रही। कारण यही था कि शोषित वर्ग ने या तो आवाज उठाई ही नहीं या उठाई तो वह धीमी एवं असंगठित थी। जैसे ही साहस उभरा और अनीति के प्रति विद्रोह पर उतारू हुआ, वहाँ परिस्थितियाँ तुरन्त बदलीं। भले ही आरम्भ में शोषकों ने दमन का आश्रय लिया हो, पर वह दबाव बहुत समय तक जारी नहीं रह सका। दुर्बल होते हुए भी नीतिपक्ष जीता और अपने अधिकार वापस लेकर रहा। जागरुकों को सफलता मिल चुकी है। आवश्यकता इस बात की है कि मानवीय मौलिक अधिकारों की यथार्थता एवं आवश्यकता से जन-जन को अवगत कराया जाय। इसीप्रकार शोषित जागेंगे और शोषक दबेंगे। ***-(श्रीराम शर्मा आचार्य, ग्रन्थ : धर्मतत्त्व का दर्शन और मर्म)***

96) *अधिकांश लोग समाजवाद अथवा साम्यवाद को आधुनिक समय का आन्दोलन समझते हैं और इसकी उत्पत्ति कल-कारखानों से मानते हैं। यह कथन एक सीमा तक सही माना जा सकता है, वास्तव में साम्यवाद का सिद्धान्त और उसका आन्तरिक भाव नवीन नहीं है। उसका जन्म उसी समय हो गया था जब मनुष्य ने जंगली अवस्था से निकलकर गाँव और कस्बों का निर्माण किया था। तभी से कुछ लोग शक्ति, उद्योग, चालाकी अथवा संयोग के फल से सम्पत्तिशाली बन गये और बहुत से निर्बलता, साहसहीनता, भोलेपन अथवा प्राकृतिक कोप से दरिद्र हो गये। अमीरों ने गरीबों को सताना, लूटना और गुलाम बनाकर सेवा कराना आरम्भ किया, जिसके फलस्वरूप गरीबों में असन्तोष का भाव पैदा होने लगा।*

इसप्रकार यह अमीरों और गरीबों अथवा अधिकारसम्पन्न और अधिकारविहीन लोगों का संघर्ष अति प्राचीनकाल से होता आया है। इस कलह में जिन लोगों ने गरीबों के पक्ष का समर्थन किया अथवा जिन्होंने इन लड़ाई-झगड़ों का अंत करके समाज में न्याय और शान्ति की स्थापना करने की चेष्टा की, वे वास्तव में अपने समय के साम्यवादी ही थे, चाहे उनकी भाषा आज से सर्वथा भिन्न रही हो और चाहे उनका संगठन आर्थिक आधारों के बजाय धार्मिक या आध्यात्मिक सिद्धान्तों पर हुआ हो। पाठकों को शायद यह बात कुछ असंगत सी प्रतीत हो, पर हमारे ख्याल से महावीर, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद आदि जितने महान् धर्मप्रचारक हुए हैं, वे सब इसी श्रेणी के व्यक्ति थे और उनके जीवनकार्य का सारांश यही था। यह बात दूसरी है कि उनके पश्चात स्वार्थी और अवसरवादी लोग उनके संगठनों में घुस गये और कुछ ही समय में उन्होंने मूलवस्तु की कायापलट कर दी।

ऐतिहासिक काल के पूर्व की अवस्था का विवेचन तो हम स्थानाभाव के कारण कर नहीं सकते, पर यह सर्वविदित है कि वैदिकयुग का भारतीय समाज, समानता और भ्रातृभाव के सिद्धान्तों पर आधारित था। उस समय मनुष्यों की तो क्या बात, यहाँ के ऋषि-मुनियों ने प्राणिमात्र से मैत्रीभाव रखने का उपदेश दिया था और 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' के सिद्धान्त की संसार भर में घोषणा कर दी थी।

इसप्रकार साम्यवाद या समाजवाद की भावना हजारों वर्षों से ***'सामाजिक न्याय'*** *की स्थापना का*

प्रयत्न करती आयी है, पर कुछ व्यक्तियों की स्वार्थ और अपहरण की प्रवृत्तियों ने सदैव उसको दबाने और अन्याय तथा शोषण की प्रणाली को जारी रखने का प्रयत्न किया है। होते-होते हम वर्तमान समय में आ पहुँचे हैं, जबकि पूँजीवाद अपनी चरमसीमा पर पहुँच गया है और सत्य भी यह है कि जब तक कोई सामाजिक प्रणाली अपनी चरमसीमा पर नहीं पहुँच जाती, तब तक स्वाभाविक रूप से उसका अन्त भी नहीं हो सकता। यही अवस्था अब पूँजीवादी-प्रणाली की हो रही है, पर वह अब भी अपनी स्वाभाविक मृत्यु से मरने को तैयार नहीं, वरन् अपने साथ समस्त संसार का विनाश करने की धमकी दे रही है।

पूँजीवाद की एकत्रित शक्ति को देखते हुए यह असम्भव नहीं कि वह अपनी धमकी को कार्यरूप में परिणत करके संसार में प्रलयकाण्ड उपस्थित कर दे पर साथ ही यह भी अटल सत्य है कि पूँजीवाद चाहे कितनी भी बड़ी नाशलीला क्यों न कर दिखलाये और संसार की प्रगति को सौ-दो-सौ वर्षों के लिये रुद्ध कर दे, पर अब उसका अन्त अवश्यंभावी है और उसका स्थान समाजवादी प्रणाली ही ग्रहण करेगी, क्योंकि यही प्रकृति और मानवधर्म का निर्देश है। ***-(श्रीराम शर्मा आचार्य, ग्रन्थ : धर्मतत्त्व का दर्शन और मर्म)***

97) *हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि जिस जाति की जनता में विद्या-बुद्धि का जितना अधिक प्रचार है, वह जाति उतनी ही उन्नत है। भारतवर्ष के सत्यानाश का मूलकारण यही है कि देश की सम्पूर्ण विद्या-बुद्धि राजशासन और दम्भ के बल से केवल मुट्ठीभर लोगों के अधिकार में रखी गयी है। यदि हमें फिर से उन्नति करनी है, तो हमको उसी मार्ग पर चलना होगा, अर्थात जनता में विद्या का प्रचार करना होगा। आधी सदी से समाज-सुधार की धूम मची हुई है। मैंने दस वर्ष तक भारत के अनेकानेक स्थानों में घूमकर देखा कि देश में समाज सुधारक समितियों की बाढ़ सी आयी है। परन्तु जिनका रुधिर शोषण करके हमारे 'भद्र लोगों' ने अपना यह खिताब प्राप्त किया है और कर रहे हैं, उन बेचारों के लिये एक भी सभा नजर न आयी! मुसलमान लोग कितने सिपाही लाये थे? यहाँ अंग्रेज कितने हैं? चाँदी के छः सिक्कों के लिये अपने बाप और भाई के गले पर चाकू फेरनेवाले लाखों आदमी सिवा भारत के और कहाँ मिल सकते हैं? सात सौ वर्षों के मुसलमानी शासनकाल में छः करोड़ मुसलमान, और सौ वर्षों के ईसाईराज्य में बीस लाख ईसाई कैसे बने? मौलिकता ने देश को क्यों बिल्कुल त्याग दिया है? क्यों हमारे सुदक्ष शिल्पी यूरोपवालों के साथ बराबरी करने में असमर्थ होकर दिनोंदिन दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं? किस बल से जर्मन कारीगरों ने अँगरेज कारीगरों के कई सदियों के दृढ़ प्रतिष्ठित आसन को हिला दिया?*

केवल शिक्षा! शिक्षा! शिक्षा! यूरोप के बहुतेरे नगरों में घूमते हुए वहाँ के गरीबों तक के लिये अमन-चैन और शिक्षा की सुविधाओं को देखकर अपने यहाँ के गरीबों की बात याद आती थी और मैं आँसू बहाता था। यह अन्तर क्यों हुआ? उत्तर मिला- शिक्षा! शिक्षा से आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास से अन्तर्निहित ब्रह्मभाव जाग उठता है। किन्तु हमारा ब्रह्मभाव क्रमशः निद्रित, संकुचित होता जा रहा है। न्यूयार्क में मैं देखता था आइरिश उपनिवेशवासियों को आते हुए अँगरेजों के पैर से कुचले हुए, कान्तिहीन, निःसम्बल, अतिदरिद्र और महामूर्ख, साथ में एक लाठी और उसके सिरे पर लटकती हुई फटे कपड़ों की एक छोटी सी गठरी। उनकी चाल और चितवन में डर ही डर समाया रहता था। छः महीनों बाद यही दृश्य बिल्कुल बदल गया। अब वह तनकर चल रहा है, उसकी वेशभूषा बदल गयी है, उसकी चाल और चितवन में पहले का डर दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा कैसे हुआ? उत्तर में हमारा वेदान्त कहता है कि वह आइरिश अपने देश में चारो तरफ घृणा से घिरा रहता था- सारी प्रकृति एक स्वर से उस कह रही थी, "बच्चू तुझे और आशा नहीं है, तू गुलाम ही पैदा हुआ है और सदा गुलाम ही बना रहेगा।" आजन्म यह सुनते-सुनते बच्चू को उसी का विश्वास हो गया और बच्चू ने अपने को सम्मोहित कर डाला कि वह अतिनीच है। उसका ब्रह्मभाव संकुचित हो गया। परन्तु जब उसने अमेरिका में पैर रखे, तो चारो ओर से ध्वनि सुनाई पड़ने लगी, "बच्चू तू भी वही मनुष्य है, जो हम लोग हैं। जो कुछ हुआ है, सब मनुष्यों ने ही किया है। तेरे और मेरे समान आदमी सबकुछ कर सकते हैं। साहसी बन उठ!" बच्चू ने सिर उठाया और देखा कि बात तो ठीक ही है- बस उसके अन्दर सोता हुआ ब्रह्मभाव जाग उठा, मानो स्वयं प्रकृति ने ही कहा- "उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरान्निबोधत्"- उठो, जागो, और ध्येय को प्राप्ति तक रुको मत।

इसीप्रकार हमारे लड़के जो शिक्षा पा रहे हैं, वह भी बड़ी अभावात्मक (Negative) है। स्कूल के लड़के इससे सीखते तो कुछ भी नहीं, वरन् जो कुछ अपना है, उसका भी नाश हो जाता है।

-(स्वामी विवेकानन्द, ग्रन्थ : हे भारत! उठो, जागो!)

98) *उन्नति की पहली शर्त है – स्वाधीनता। मनुष्य को जिसप्रकार विचार और वाणी में स्वाधीनता मिलनी चाहिए, वैसे ही उसे खान-पान, रहन-सहन, विवाह आदि हर एक बात में स्वाधीनता मिलनी चाहिए- जब तक कि उसके द्वारा दूसरों को कोई हानि नहीं पहुँचती।*

हम मूर्खों की तरह भौतिकसभ्यता की निन्दा किया करते हैं। और क्यों न करें, अंगूर खट्टे जो हैं! भारत की आध्यात्मिक सभ्यता की श्रेष्ठता को स्वीकार करने पर भी यह मानना ही पड़ेगा कि सारे भारतवर्ष में एक लाख से अधिक यथार्थ धार्मिक नर-नारी नहीं है। अब प्रश्न यह है कि क्या इन मुट्ठीभर लोगों की धार्मिक उन्नति के लिये भारत के तीस करोड़ अधिवासियों को बर्बरों का सा जीवन व्यतीत करना और भूखों मरना होगा? क्यों एक भी आदमी भूखों मरे? मुसलमानों के लिये हिन्दुओं को जीतना कैसे सम्भव हुआ? हिन्दुओं का भौतिकसभ्यता का निरादर करना ही इसका कारण था। मुसलमानों ने ही इन्हें दर्जी द्वारा सिले हुए कपड़े पहनने तक सिखलाया! क्या ही अच्छा होता, यदि हिन्दू, मुसलमानों से साफ ढंग से खाने का उपाय भी सीख लेते, ताकि रास्ते की धूल भोजन के साथ न मिलने पाती! भौतिकसभ्यता, नहीं-नहीं, भोगविलास की भी जरुरत है- क्योंकि उससे गरीबों को काम मिलता है। अन्न! अन्न! अन्न चाहिए! मुझे तो इस पर विश्वास नहीं होता कि जो भगवान मुझे यहाँ पर अन्न नहीं दे सकता, वह स्वर्ग में मुझे अनन्त सुख देगा। भारत को उठाना होगा, गरीबों को दो रोटी देनी होगी, शिक्षा का विस्तार करना होगा और पुरोहिती की बुराइयों को ऐसा धक्का देना होगा कि वे चक्कर खाती हुई एकदम अतलांतिक महासागर में जा गिरें! ब्राह्मण हो या संन्यासी- किसी की बुराई को क्षमा न मिलनी चाहिए। ऐसा करना होगा, जिससे पुरोहिती की बुराइयों और सामाजिक अत्याचारों का कहीं नाम-निशान तक न रहे, सब के लिये अन्न अधिक सुलभ हो जाये और सब को अधिकाधिक सुविधा मिलती रहे।

स्वाधीनता पाने का अधिकार उसे नहीं, जो स्वयं औरों को स्वाधीनता देने को तैयार न हो। मान लो, अंग्रेजों ने सब अधिकार तुम्हारे हाथों में सौंप दिये। तो होगा क्या? तब तो तुम प्रजा को दबाओगे और उन्हें कुछ भी अधिकार न दोगे। गुलाम तो शक्ति चाहता है- दूसरों को गुलाम बनाने के लिये।

इसीलिये अब केवल अपने धर्म पर जोर देकर तथा समाज को स्वतन्त्रता देकर इस कार्य को धीरे-धीरे सिद्ध करना है। पुराने धर्म से पुरोहिती छल को उखाड़ फेंको और इससे तुम्हें संसार में सर्वोत्तम धर्म प्राप्त हो जायेगा। समझ गये न मेरी बात? भारतीय धर्म के आधार पर क्या तुम यूरोप जैसा समाज बना सकते हो? मुझे विश्वास है कि यह सम्भव है, और होना भी चाहिए। इसके लिये सबसे अच्छा उपाय है- मध्यभारत में एक उपनिवेश की स्थापना करना, जहाँ वे ही लोग रहेंगे, जो तुम्हारे विचारों को मानेंगे। फिर ये ही मुट्ठीभर लोग सारे संसार में उन विचारों का विस्तार करेंगे। इस कार्य के लिये धन की आवश्यकता है सही, पर यह धन आ ही जायेगा। इस बीच एक केन्द्र-समिति बनाओ और भारतभर में उसकी शाखाएँ खोलते जाओ। अभी केवल धर्मभित्ति पर ही इस समिति की स्थापना करो और किसी उथल-पुथल मचा देने वाले सामाजिक सुधार का प्रचार मत करो। हाँ, मूर्खताप्रसूत कुसंस्कारों को सहारा न देना। 'सबका समान अधिकार है', सभी समान हैं'- ये जो तत्त्व पूर्वकाल में आचार्य शंकर, रामानुज और चैतन्य आदि द्वारा प्रचारित हुए थे, उन्हीं के आधार पर समाज को पुनः गठित करने का प्रयत्न करो।

उत्साह से हृदय भर लो और सब जगह फैल जाओ। काम करो, काम करो। नेतृत्व करते समय सब के दास हो जाओ, निःस्वार्थ होओ और कभी एक मित्र को, पीठ पीछे दूसरे मित्र की निन्दा करते मत सुनो। सब संगठनों का सत्यानाश इसी से होता हैं अनन्त धैर्य रखो, तभी सफलता तुम्हारे हाथ आयेगी। काम करो; काम करो; दूसरों के हित के लिये काम करना ही जीवन का लक्षण है।

मैं चाहता हूँ कि हममें किसीप्रकार की कपटता, कोई दुरंगी चाल, कोई दुष्टता न रहे। मैं सदैव प्रभु पर निर्भर रहा हूँ- सत्य पर निर्भर रहा हूँ, जो दिन के प्रकाश की भाँति उज्ज्वल है। दुराचार की गन्ध या बदनीयती का नाम तक न रहने पाये।

किसीप्रकार का टालमटोल या छिपे तौर बदमाशी या गुप्त शठता हम में न रहे- पर्दे की आड़ में कुछ न किया जाय। गुरु का विशेष कृपापात्र होने को कोई भी दावा न करे। चाहे धन आये या न आये; आदमी मिले या न मिले; क्या तुम्हारे पास प्रेम है? क्या तुम्हें ईश्वर पर भरोसा है? बस, आगे बढ़ो, तुम्हें कोई रोक न सकेगा।

भारत में लोग अधिक से अधिक मेरी प्रशंसा भर कर सकते हैं- पर वे किसी काम के लिये एक पैसा भी न देंगे। और दें भी तो कहाँ से? वे स्वयं भिखारी हैं न? फिर गत दो हजार या उससे भी अधिक वर्षों से वे परोपकार करने की वृत्ति ही खो बैठे हैं। ***-(स्वामी विवेकानन्द, ग्रन्थ : हे भारत! उठो, जागो!)***

99) *कोई भी मनुष्य या जाति अपने को दूसरों से अलग रखकर जी नहीं सकती, और जहाँ कहीं भी गौरव, नीति या पवित्रता की भ्रान्त धारणा के वशीभूत हो ऐसा प्रयत्न किया गया, उसका परिणाम उस पृथक होने वाले पक्ष के लिये सदैव घातक सिद्ध हुआ।*

मेरी समझ में, भारतवर्ष के पतन और अवनति का का एकमात्र मुख्य कारण था– जाति के चारों ओर रीति–रिवाजों की एक दीवार खड़ी कर देना, जिनकी भित्ति दूसरों के प्रति घृणा पर स्थापित थी, और जिसका यथार्थ उद्देश्य प्राचीन काल में हिन्दू–जाति को आसपासवाली बौद्ध जातियों के संसर्ग से अलग रखना था।

दूसरों से घृणा करते रहने पर कोई भी स्वयं अवनत हुए बिना नहीं रह सकता। धर्मनीति के इस अचूक नियम का जाज्वल्य प्रमाण– इसका अनिवार्य फल– यह हुआ कि जो जाति सभी प्राचीन जातियों में सर्वश्रेष्ठ थी, वही आज पृथ्वी की समस्त जातियों में एक तुच्छ और घृणा की वस्तु हो गयी है। जिस नियम का आविष्कार और विवेचन पहले–पहले हमारे ही पूर्वजों ने किया था, आज हमी लोग उस नियम की अचूक क्रिया के प्रत्यक्ष दृष्टान्तस्वरूप हो गये हैं।

लेन–देन ही संसार का नियम है; और यदि भारत फिर से उठना चाहे, तो यह परमावश्यक है कि वह अपने रत्नों को बाहर लाकर पृथ्वी की जातियों में बिखेर दे, और उसके बदले में वे जो कुछ दें, उसे सहर्ष ग्रहण करे। विस्तार ही जीवन है और संकीर्णता मृत्यु। प्रेम ही जीवन है और द्वेष ही मृत्यु। हमारा नाश उसी दिन से आरम्भ हो गया, जब से हम अन्यान्य जातियों से घृणा करने लगे; और जब तक हम पुनः इस जीवनस्वरूप विस्तार को नहीं अपनाते, हम किसी भी तरह अपनी इस मृत्यु को नहीं रोक सकते।

अतएव हमें संसार की सभी जातियों से मिलना–जुलना पड़ेगा। प्रत्येक हिन्दू, जो भ्रमण करने को विदेश जाता है, उन सैकड़ों मनुष्यों से अपने देश को अधिक लाभ पहुँचाता है, जो केवल कुसंस्कार और स्वार्थपरता की समष्टि है और जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य– 'न खाय न खाने दे' कहावत के अनुसार– 'न अपना हित करना है, न पराये का'। पाश्चात्य जातियों ने जातीय जीवन के जो आश्चर्यजनक प्रासाद बनाये हैं, वे चरित्ररूपी सुदृढ़ स्तम्भों पर खड़े हैं। और हम लोग भी जब तक ऐसे सैकड़ों उत्कृष्ट चरित्र नहीं गढ़ते तब तक हमारे लिये इस जाति या उस जाति के विरुद्ध अपना असन्तोष प्रकट करना निरर्थक है।

क्या वे लोग स्वाधीनता पाने योग्य हैं, जो दूसरों को स्वाधीनता देने के लिये प्रस्तुत नहीं! आइये, व्यर्थ का असन्तोष प्रकट करते हुए शक्तिक्षय करने के बदले हम धीरता के साथ और पुरुषोचित रूप से काम में लग जायँ। मेरा तो यह पूर्ण विश्वास है कि संसार की कोई भी शक्ति किसी से वह चीज अलग नहीं रख सकती, जिसके लिये वह सचमुच योग्य हो। अतीत तो हमारा गौरवमय था ही, पर मुझे हार्दिक विश्वास है कि भविष्य और भी गौरवमय होगा। ***–(स्वामी विवेकानन्द, ग्रन्थ : हे भारत! उठो, जागो!)***

100) *भारतवर्ष के सभी अनर्थों की जड़ है– जनसाधारण की गरीबी। अपने निम्न श्रेणीवालों के प्रति हमारा एकमात्र कर्तव्य है– उन्हें शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कि इस संसार में तुम भी मनुष्य हो, तुम लोग भी प्रयत्न करने पर अपनी सब प्रकार की उन्नति कर सकते हो। अभी वे लोग यह भाव खो बैठे हैं। हमारे जनसाधारण और देशी राजाओं (सरकारों) के सम्मुख यही एक विस्तृत कार्यक्षेत्र पड़ हुआ है। अब तक इस ओर कुछ काम नहीं हुआ। पुरोहिती शक्ति और विदेशी विजेतागण सदियों से उन्हें कुचलते रहे हैं, जिसके फलस्वरूप भारत के गरीब बेचारे यह तक भूल गये हैं कि वे भी मनुष्य हैं। उनमें विचार पैदा करना होगा। उनके चारों ओर दुनिया में क्या–क्या हो रहा है, इस सम्बन्ध में उनकी आँखें खोल देनी होंगी; बस, फिर वे अपनी मुक्ति स्वयं सिद्ध कर लेंगे। उनमें विचार पैदा कर दो– बस, उन्हें उसी एक सहायता की आवश्यकता है और शेष सबकुछ इसके फलस्वरूप आप ही हो जायेगा। हमारा कर्तव्य है उनमें भावों का संचार कर देना, बाकी सब वे स्वयं कर लेंगे। भारतवर्ष में बस यही करना है।* ***–(स्वामी विवेकानन्द, ग्रन्थ : हे भारत! उठो, जागो!)***

101) *मेरा दृढ़ विश्वास है कि शीघ्र ही वह शुभ दिन आ रहा है; और भारतवर्ष जिस श्रेष्ठता का किसी काल में भी अधिकारी नहीं था, शीघ्र ही उस श्रेष्ठता का अधिकारी होगा। प्राचीन ऋषियों की अपेक्षा श्रेष्ठतर ऋषियों का आविर्भाव होगा और तुम्हारे पुरखे अपने वंशधरों की इस अभूतपूर्व उन्नति से बड़े संतुष्ट होंगे। इतना ही नहीं, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, वे परलोक में अपने–अपने स्थानों से अपने वंशजों को इसप्रकार महिमान्वित और महत्त्वशाली देखकर अपने को महा गौरवान्वित समझेंगे।*

हे भाइयों! हम सभी लोगों को इस समय कठिन परिश्रम करना होगा। अब सोने का समय नहीं है। हमारे कार्यों पर भारत का भविष्य निर्भर है। यह देखो, भारतमाता धीरे-धीरे आँखे खोल रही है। वह कुछ ही देर सोई थी। उठो उसे जगाओ और पहले की अपेक्षा और भी गौरवमण्डित करके भक्तिभाव से उसे उसके चिरन्तन पद पर प्रतिष्ठित कर दो! ***-(स्वामी विवेकानन्द, ग्रन्थ : हे भारत! उठो, जागो!)***

102) *एक विकसित भारत के सपने को आर्थिक सुधारों तथा अन्य उपायों से साकार करने का प्रयास करते समय हमें 'नोबल पुरस्कार प्राप्त' अर्थशास्त्री 'अमर्त्यसेन' के निम्नलिखित कथन को हमेशा जेहन में रखना होगा– ''मुख्य मुद्दा है, सब लोगों को सब प्रकार के अवसर प्रदान करना। लेकिन, आज इन अवसरों को दिए जाने के बारे में समझौते किए जाते रहे हैं, उनको निष्क्रिय बनाने के उद्देश्य से कानून बनाए जाते रहे हैं, नौकरशाहों द्वारा नियंत्रण लगाए जाते रहे हैं। इसप्रकार के सब अवरोधों को समाप्त करना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। बड़े पैमाने पर सामाजिक अवसर देने का काम महज 'बाजारों को आजाद' करके पूरा नहीं होगा। उसके लिए खास-तौर पर, शैक्षणिक सुविधाओं और स्वास्थ्य-रक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का देशव्यापी विस्तार करके इन सुविधाओं को आमदनी और साधनों के भेदभाव के बिना सब भारतीयों को देना पड़ेगा। इसके लिए आवश्यक है ऐसी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक योजनाओं का क्रियान्वयन, जो हर प्रकार की असमानताओं को समाप्त कर सके। जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन हमारे देश के करोड़ों लोग एक नए आजाद माहौल में जाकर देश को और ज्यादा खुशहाल और गतिशील बनाने में मददगार हो सकेंगे।''*

-(डा. ए.पी.जे.अब्दुलकलाम : राष्ट्रपति, ग्रन्थ : भारत 2020 : नवनिर्माण की रूपरेखा)

103) *गरीब को सभी तुच्छ समझते हैं। वे उसके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं चाहते। वह उनके पीछे चिल्लाता दौड़ता है। लेकिन वे ध्यान नहीं देते।* ***-(बाइबिल, ओल्डटेस्टामेन्ट, कहावत, 19:7)***

104) *किसी देश को कब विकसित माना जाता है ? इस बात का पता चलता है, उस देश की दौलत से। उसके लोगों की खुशहाली और अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी हैसियत से। और वह देश कितना दौलतमन्द है, इसका पता चलता है उसकी जी.एन.पी. यानि उसका कुल उत्पाद, जी.डी.पी. यानि कुल घरेलू उत्पाद, भुगतानों की बकाया रकम, विदेशी विनिमय मुद्रा की सुरक्षित निधि, आर्थिक विकास की दर, प्रतिव्यक्ति आय आदि से। इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (आयात और निर्यात दोनों) की मात्रा तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में उसकी हिस्सेदारी की मात्रा– इन दोनों क्षेत्रों में उसके विकास की दर भी यह संकेत देती है कि उसकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है। और उसमें कमाई हुई दौलत को सँभाले रखने और उसे लगातार बढ़ाते रहने की कूवत है या नहीं ?*

ये आर्थिक संकेत वैसे अपने आप में काफी वजन रखते हैं। लेकिन वे काफी कुछ छिपा भी जाते हैं। जैसे देश के मामूली आदमी की तंगहाली व दुर्दशा की बात।

हैदराबाद स्थित डी.आर.डी.एल. (सुरक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला) से जुड़े रहने की अवधि के दौरान मुझे जो अनुभव हुए, उनके बारे में मैंने और राजन ने काफी बातचीत की है, काफी सोचा-विचारा भी है। वहाँ काम करते समय मैं जिन तीन व्यक्तियों के सम्पर्क में आया, वे मेरे लिए प्रतीक बन गए– उन चन्द सवालों और समस्याओं के, जिनका हल पाने के लिए मैं लगातार जूझ रहा था। पहला व्यक्ति, वेंकट दो बेटों और एक बेटी का पिता था। उसके तीनों बच्चे स्नातक थे और अच्छे पदों पर काम करते थे। उसी इलाके में रहता था– कुप्पू, जो तीन बेटों का पिता था। वह सिर्फ एक बेटे को ही पढ़ा लिखा सका था और किराए के घर में रहता था। इसीप्रकार तीसरा व्यक्ति करुप्पन दो बेटियों और एक बेटे का पिता था, उसकी नौकरी अंशकालिक थी। गरीब होने की वजह से वह अपनी किसी सन्तान को पढ़ा नहीं पाया था। उसके घर भी बदलते रहते थे। क्योंकि उसके लिए अपने बच्चों को गैरमामूली न सही, मामूली और औसत किस्म की जिन्दगी मुहैया करना मुमकिन नहीं था। ताकि वे खुशहाल लोगों की तरह पूरी जिन्दगी जी सकें। ऐसे धन्धे से जुड़ सकें, जो उन्हें अच्छी सेहत, रोजमर्रा की जिन्दगी चैन से बिताने के मौके दे सके। विकसित भारत का यही एक सपना है– हमारा।

प्रतिव्यक्ति आय लोगों की औसत आय को ही जताती है। वह यह नहीं जताती कि हर देशवासी के पास उतना धन है। इसका आँकड़ा अमीरों और गरीबों– दोनों की आमदनियों के औसत से निकाला जाता है। प्रतिव्यक्ति आय का यह आँकड़ा यह भी नहीं जताता कि किसी एक देश या एक राज्य या एक क्षेत्र की खुशहाली विश्व स्तर पर तुलनाओं के लिए एक जैसी है।

-(डा. ए.पी.जे.अब्दुलकलाम : राष्ट्रपति, ग्रन्थ : भारत 2020 : नवनिर्माण की रूपरेखा)

105) *जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जरूरी कई और सुझावों का जिक्र भी किया जा सकता है। गाँधी जी का कहना था कि देश के लिए किए गए हर काम की कसौटी यह होनी चाहिए कि उसके द्वारा देश के सबसे गरीब और पिछड़े आदमी के आँसू पोंछे जा सकते हैं या नहीं। उनका मानना था कि जब ऐसा दिन आएगा, तभी यह माना जाएगा कि हमारा राष्ट्र सुखी राष्ट्र हो गया है।*

नेहरू जी के मन में भी सम्पूर्ण भारत को सुखी और खुशहाल बनाने का सपना पलता रहता था। उनका मानना था कि यह तभी मुमकिन है, जब देश में फैली निरक्षरता, गरीबी, बीमारियाँ, अज्ञान मिटे और हर देशवासी को आगे बढ़ने के अवसर मिलें। अन्यथा देश के विकास की प्रगति अवरुद्ध रहेगी। लेकिन मौजूदा हालात में उनका अपेक्षाकृत आसान लक्ष्य भी पूरा होता दिखाई नहीं देता।

जब भारत आजाद हुआ, तब मैं किशोर था। रेडियो पर आने वाली खबरों को सुनकर हम सबको मालूम पड़ता कि दिल्ली में क्या हो दिल्ली में क्या हो रहा है। इस दौरान आजादी के बाद के मतवाले कर देने वाले दिनों में मुझे एक ऐसी खबर सुनने को मिली, जिसने मुझे हिलाकर रख दिया था। यह वह जमाना था, जब सारा मुल्क आजादी का जश्न मना रहा था। देश के नेता दिल्ली में जमा होकर उस तात्कालिक कार्य (राजगद्दी) के बारे में सोच-विचार कर रहे थे, जो उन्हें अपने सामने दिखाई दे रहा था। लेकिन ठीक उसी समय राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जिन्हें वास्तव में सत्ता के केन्द्रस्थल पर होना चाहिए था, वहाँ से बहुत दूर 'नोआखाली' में थे, दंगों से पीड़ित असहाय लोगों के बीच। साम्प्रदायिक दंगों के शिकार बने इन अभागे लोगों के घावों पर मरहम लगाते हुए, उन्हें सांत्वना प्रदान करते हुए। उन्होंने अपने विश्वास में पूरी आस्था की अभिव्यक्ति दिखाकर जिस अद्‌भुत साहस का परिचय दिया, वह बेमिसाल घटना थी। सब भारतीयों की बेहतरी और कल्याण के प्रति इसी प्रकार की गहरी और अडिग आस्था के आधार पर ही हमने एक विकसित भारत का सपना देखा है।

-(डा. ए.पी.जे.अब्दुलकलाम : राष्ट्रपति, ग्रन्थ : भारत 2020 : नवनिर्माण की रुपरेखा)

106) *देश के करोड़ों गरीब लोगों की गरीबी जल्द से जल्द दूर करने (मिसाल के तौर पर 2010 तक) और जरूरतों को पूरा करने वाली बातें एकदम साफ हैं कि देश के हर निवासी को उम्दा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, हुनर हासिल करने के मौके, रोजगार के मौके आदि मिलने चाहिए। इसके अलावा भारत को सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर होना होगा, देश की क्षमताओं को बढ़ाना होगा और देश के लिए ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, जिससे हर क्षेत्र में सुधार होता रहे और व्यवस्था अडिग रहे। क्या भारत अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेगा? क्या वह उन रास्तों पर चल सकेगा, जिन पर चल कर उसकी सब जरूरतें पूरी होती हैं।*

-(डा. ए.पी.जे.अब्दुलकलाम : राष्ट्रपति, ग्रन्थ : भारत 2020 : नवनिर्माण की रुपरेखा)

107) *भारत एक विशाल देश है, जहाँ अनेक प्रदेश है, जुदा-जुदा क्षमताएँ हैं, कमजोरियाँ हैं। इन लोगों की पृष्ठभूमियाँ भी जुदा-जुदा हैं। कुछ को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिली है, श्रेष्ठतम प्रशिक्षण मिला है। अच्छा अनुभव पाने का संयोग मिला है। किन्तु कुछ ऐसे हैं, जिन्हें कम शिक्षा मिली है, कम प्रशिक्षण मिला है और बेहतर प्रदर्शन करने के कम अवसर मिले हैं। और कुछ ऐसे अभागे भी हैं, जिन्हें महज जीने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है और उनकी सारी जिन्दगी सिर्फ जिन्दा रहने की कोशिश में ही बीत जाती है। उन्हें कभी-कभी अवसर भी मिले हैं, मगर न के बराबर।* ***-(डा. ए.पी.जे.अब्दुलकलाम : राष्ट्रपति, ग्रन्थ : भारत 2020 : नवनिर्माण की रुपरेखा)***

108) *आज देश के 40% लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। उनके लिए जीना मुहाल हो गया है और हर दिन उनके सामने एक समस्या बनकर आता है। उनके पास अक्सर मामूली चीजों को खरीदने लायक पैसे भी नहीं होते, कभी-कभी तो अगले दिन या रात के लिए भी नहीं।*

-(डा. ए.पी.जे.अब्दुलकलाम : राष्ट्रपति, ग्रन्थ : भारत 2020 : नवनिर्माण की रुपरेखा)

109) *पूर्व प्रधानमन्त्री आई. के. गुजराल ने 1998 में हैदराबाद में आयोजित विज्ञान सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए, हमारी मूलभूत सुखसुविधाओं के बारे में एक बड़ी दिलचस्प व अनोखी बात कही थी। उन्होंने कहा था, ''मैं अपने सामने मंच पर आसीन गणमान्य व्यक्तियों को देख रहा हूँ। हरेक के सामने मिनरल वाटर से भरी एक-एक बोतल रखी है। उन्हें देखकर मुझे तीन वर्गों के भारतीयों की याद आ रही है। पहले वर्ग में वे भारतीय*

आते हैं, जो बोतलबन्द पानी पीने और खरीदने की हैसियत रखते हैं। दूसरे वर्ग में भारतीय आते हैं, जो उस पानी का ही इस्तेमाल करते हैं, जो उनके घरों में लगे नलों से उन्हें प्राप्त होता है, या वे आसपास लगे किसी नल या पम्प से ऐसा पानी प्राप्त करते हैं, जिसकी न साफ होने की गारण्टी होती है और न ही वक्त पर आने और मिलने की। और, तीसरे वर्ग में वे भारतीय आते हैं, जिनके लिए पानी पाना रोजमर्रा की एक समस्या है, और वे कैसा भी गन्दला और प्रदूषित पानी क्यों न हो, उसे पीने और इस्तेमाल करने को तैयार रहते हैं।'' उन्होंने आगे कहा कि आजादी के पचास साल बाद भी ऐसी स्थिति का बने रहना राष्ट्रीय शर्म की बात है। बदकिस्मती से अगर हमने इस (आर्थिक न्याय) के बारे में तथा स्वास्थ्य रक्षा आदि दूसरे मुद्दों के बारे में कुछ नहीं किया, तो अगले दस साल बाद भी, हम इसी बात को दोहराते रहेंगे।

अन्तिम विश्लेषण में कहा जाएगा कि किसी समाज की सफलता का फैसला उसके इस कसौटी पर खरा उतरने की काबिलियत पर ही होगा कि उसने अपने लोगों के लिए पर्याप्त और उचित स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की हैं या नहीं। इस कसौटी पर खरा उतरने के लिए समाज के लिए इतना ही काफी नहीं है कि उसने रोगों और बीमारियों का इलाज करने की व्यवस्था की है या नहीं।

-(डा. ए.पी.जे.अब्दुलकलाम : राष्ट्रपति, ग्रन्थ : भारत 2020 : नवनिर्माण की रुपरेखा)

110) *रहने और काम करने के स्थानों का साफ-सुथरा होना और उनमें उन्नत पर्यावरण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होना बहुत जरूरी है। आने वाले वर्षों में हमें फैक्ट्रियों के अन्दर के तथा खुले स्थानों जहाँ कामगार काम करते हैं, के पर्यावरण का भी साफ-सुथरा और स्वास्थ्यप्रद होने की जरूरत पर भी जोर देना होगा। असल में सारे सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ सुरक्षित रखना हर सरकार का राष्ट्रीय मिशन हो जाना चाहिए। सिर्फ संभ्रान्त व्यक्तियों के लिए ही नहीं साधारण भारतीयों को भी स्वास्थ्यदायक वातावरण और पर्यावरण में जीने, रहने और काम करने का पूरा अधिकार है।*

-(डा. ए.पी.जे.अब्दुलकलाम : राष्ट्रपति, ग्रन्थ : भारत 2020 : नवनिर्माण की रुपरेखा)

111) *यदि हम भारत को एक विकसित देश के रूप में देखना चाहते हैं, तो हमें अक्रियता की इस दयनीय स्थिति से उबरना होगा। यदि इसके लिए कानूनों और कार्यप्रणाली को बदलना भी पड़े, तो उन्हें भी बदल डालना चाहिए। हमें समग्रतावादी और अन्तःप्रज्ञात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा।*

-(डा. ए.पी.जे.अब्दुलकलाम : राष्ट्रपति, ग्रन्थ : भारत 2020 : नवनिर्माण की रुपरेखा)

112) सरकार की भूमिका :- *सरकार को पहला काम यह करना होगा कि वह सार्वजनिक हित के महत्त्वपूर्ण मुद्दों जैसे सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा तवज्जो दे। वह समाज के कमजोर वर्गों की हालत में दूरगामी सुधार लाने के उद्देश्य से पारदर्शी कार्यविधियों (रोजगार आदि) पर अमल करे। पिछली भूलों और गलतियों को भुलाकर उसे उद्धारक की भूमिका निभानी होगी। उसे हमेशा यह याद रखना होगा कि उसकी सब क्रियाशीलताओं का अन्तिम ध्येय है- भारत को एक विकसित देश की हैसियत दिलाना और एक ऐसे भारत की रचना करना जहाँ सब गरीबी से मुक्त हों।*

-(डा. ए.पी.जे.अब्दुलकलाम : राष्ट्रपति, ग्रन्थ : भारत 2020 : नवनिर्माण की रुपरेखा)

113) *पुस्तक के पहले अध्याय में हमने कुप्पू और करुप्पन का जिक्र किया था। वे प्रतिनिधि हैं- देश की आबादी के 60% लोगों के। दोनों में आगे बढ़ने की इच्छा है, मन है। दोनों मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा की कमी की वजह से मौजूदा हालात में बेहतर काम नहीं पा सकते और न अपनी जीवनशैली को सुधार सकते हैं। क्या हम इस दुश्चक्र को तोड़ पाएँगे ?*

भारतीयों को उच्च श्रेणी की शिक्षा प्राप्त करने और अपनी प्रवीणताओं का विकास करने के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। मगर अवसर उपलब्ध कराने का काम उन प्रचलित तरीकों से नहीं हो सकता, जो आजकल गाँव के स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं के रूप में कस्बों और नगरों में मौजूद है। सबको शिक्षा का लाभ दिलाने के उद्देश्य से गाँवों के समूहों का अच्छी सड़कों द्वारा शहर के शिक्षा केन्द्रों से जुड़ा रहना निहायत जरूरी है, ताकि किसी को किसी प्रकार की असुविधा न हो। गाँवों के इन समूहों में सब विद्यार्थियों

को उच्च कोटि की शिक्षा उपलब्ध होगी। शिक्षा के अलावा वहाँ स्वास्थ्य की सब सुविधाएँ भी मुहैया करायी जाएँगी। लोग आसानी से गाँवों की यात्रा कर सकेंगे। अच्छी से अच्छी शिक्षा और सब हुनरों की तालीम ले सकेंगे। तकनीकी निपुणता के अलावा हमारे देश को चाहिए– श्रेष्ठ राजनीतिक और सामान्य प्रबन्धन की योग्यता, जो देश भर में इस मिशन को लागू कर सके। कहीं ऐसा न हो कि कुप्पू और करुप्पनों के बच्चों और उनके भी बच्चों को उन्हीं परेशानियों से जूझना पड़े, जिनसे ये आज ये दोनों जूझ रहे हैं। हम 2020 तक सब परेशानियों से मुक्त भारत में जीने की कामना करें।

-(डा. ए.पी.जे.अब्दुलकलाम : राष्ट्रपति, ग्रन्थ : भारत 2020 : नवनिर्माण की रुपरेखा)

114) *अन्त में हमें विश्वास है कि मिशनों का एकीकरण होगा और उन्हें समायोजित रुप में एकीकृत किया जाएगा। सब लोगों के सामने नई–नई कार्यशीलताएँ जन्म लेंगी और राष्ट्र दूसरी परिकल्पना को जन्म देगा। आवश्यक वित्तीय प्रबन्धन और मानवीय संसाधन वे लोग मुहैया कराएँगे, जिनके मानस ज्वलित हो चुके होंगे। इसलिए हमने यह सपना देखा है। हमारा सपना है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके एक महान राष्ट्र की दूसरी परिकल्पना को मान्यता प्रदान करने का। भारत 2020 से पूर्व एक विकसित देश के रूप में उद्भूत होगा।* ***-(डा. ए.पी.जे.अब्दुलकलाम : राष्ट्रपति, ग्रन्थ : भारत 2020 : नवनिर्माण की रुपरेखा)***

115) *लोकतन्त्र में जनता की सत्ता का जन्म बन्दूक की नली से नहीं, बल्कि मतपेटियों से होता है। उग्रवादी समूह अपनी लोकप्रियता की आजमाइश चुनाव में करें।*

हर उस राजनीतिक समूह को अपनी लोकप्रियता की आजमाइश चुनाव में करनी चाहिए, जो जनता के या उनके किसी हिस्से के हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। जाएँ और लोगों से कहें कि वे आपको वोट दें। विधायिका में आएँ और वे कानून बनाएँ जो आप चाहते हैं।

यह एक अहम उदारवादी उसूल है। हमारा लोकतन्त्र हमें अपने मकसद को बुलंद करने और लोगों को अपने पक्ष में करने की आजादी देता है। किसी भी राजनीतिक गुट को मीडिया के जरिए अपने विचार रखने का पूरा हक है। ***-(डा. मनमोहन जी : प्रधानमन्त्री भारतसरकार, पंजाबकेसरी, 22/08/2005)***

116) *स्वतन्त्रता, न्याय और शान्ति के लिए मानवाधिकार का विशेष महत्त्व है। हमें इन अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कार्य करना है। मानवता की भावना को सुदृढ़ करने, नागरिकों को शोषण से बचाने, उनमें मानवीय गुणों को विकसित करने, भाईचारे को मजबूत करने एवं परस्पर सौहार्द को बढ़ाने में भी इन अधिकारों की अहम भूमिका है और हमें जाति, सम्प्रदाय एवं धर्मभेद से ऊपर उठकर इस दिशा में मानवकल्याण के लिए कार्य करना होगा। यही मानवता के प्रति हमारा सच्चा योगदान है। हमें भेदभाव को समाप्त कर एक आदर्श समाज के निर्माण में भी अपना योगदान देना है।* ***-(एन.डी.तिवारी, मुख्यमन्त्री, उत्तरांचल सरकार, पंजाबकेसरी, 11/12/05)***

117) *अन्धेर नगरी चौपट राज– सामान्य शासनव्यवस्था की ध्वस्त हुई इमारत ही हमारा लोकतन्त्र का वह मन्दिर है, जहाँ 15 अगस्त, 1947 को एक आस्था की किरण, एक उम्मीद, एक विश्वास ने अवतरित होकर देशवासियों में नये प्राण फूँके थे। शासन के हर स्तर पर हमारी असफलताएँ और ये पूरी बेशर्मी के साथ ढाँपे रखने की शासकीय साजिश आखिरकार पूरी व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध होगी। आखिर हम किसे बेवकूफ बना रहे हैं। अपने ही घर को आग लगाकर कहीं दीवाली मनाई जाती है। अपनों को लूटकर धनी होने का आवरण (ढोंग) अन्ततः एक दिन दीवाला ही बनाएगा। स्थानीय स्तर से उच्च स्तर तक कहीं भी कोई शासन नाम की चीज नहीं है। गोपनीयता की आड़ में निरीह, गरीब, लाचार देशवासियों का प्रतिदिन शिकार उनकी मजबूरियों से बलात्कार, उनका हर तरह से उत्पीड़न एक भयानक खेल है, जो हर तालूके, हर जिले, हर नगर व हर प्रान्त में खेला जाता है। सत्ता ही सबकी धुरी बन गयी है। चाटुकारिता, भाई–भतीजावाद व धनलोलुपता शासन के अनिवार्य अंग बन गए हैं। जिनके बिना कोई पद, पदोन्नति या कार्यसमीक्षा असंभव है। भड़वागीरी और दलाली का दूसरा नाम शासनकार्यसेवा हो गया है। चारित्रिक रूप से सम्पूर्ण राष्ट्र एक ऐसे दलदल में फँस गया है, जिससे निकलने के बजाय और धँसते जाना ही हमारी नियति मान ली गई है। इस सम्पूर्ण क्षय को तुरन्त रोकना होगा अन्यथा दीमक से भी खतरनाक यह रोग हमारा भी अस्तित्व समाप्त कर देगा। राष्ट्र समाज से बनता है और समाज व्यक्तियों से। हमें स्वयं कुछ करना होगा। सवाल सीधा है कि क्या आप तैयार हैं?* ***-(लेखक : नवनीत, पंजाबकेसरी, 10/02//04)***

118) *'कहीं मासूम कोई भूख से मर जाता है। कहीं लाखों टन अनाज पड़ा सड़ जाता है।। जिम्मेदार चैन से क्यों सो जाता है। हमारे खून में उबाल क्यों नहीं आता है।।' भारत के लिए खाद्य का मामला क्यों महत्त्वपूर्ण है ? इसका बुनियादी कारण यह है कि भारत में लम्बे समय से भूख और कुपोषण की समस्या चारों ओर फैली हुई है। भारत में गरीबों की कुल संख्या 1993–94 के 32 करोड़ की तुलना में 1997–98 में 30.4 करोड़ आँकलित की गई और यह तब है, जब गरीबों को एक औसत व्यक्ति के लिए जरूरी न्यूनतम बुनियादी कैलोरी का खर्च वहन करने में असमर्थता के रूप में परिभाषित किया जाता है। मजदूरी में किसी तरह की गिरावट चाहे वह रुपये के रूप में हो या मुद्रा स्फीति के कारण हो। इसका भी अनाज की खपत पर बुरा प्रभाव होगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि इस सदी के पहले पचास वर्षों में भारत अकाल और महामारी के शिकंजे में फँसा रहा। आज भी गरीबी और वितरण की दोषपूर्ण नीतियों के कारण भुखमरी से होने वाली मौतों का सिलसिला जारी है। ये बताने में कोई हर्ज नहीं कि करोड़ों रुपये का गेहूँ विगत वर्षों में भारतीय खाद्य निगम ने समुद्र में सड़ाकर फेंका है। गरीबी की रेखा के नीचे वालों को सस्ता चावल और गेहूँ की योजनाएँ चलाई गई हैं। किन्तु लोगों की क्रयशक्ति ही न हो, तो वे खरीदेंगे कैसे ? खाद्यसुरक्षा का मसला लोगों की क्रयशक्ति से भी जुड़ा है, रोजगार और उसकी स्थितियों से जुड़ा है, देश में होने वाली आत्महत्याओं से भी जुड़ा है। क्या कोई ईमानदार पहल खाद्यसुरक्षा के मूल को भी सुधारने की होगी ?*

-(लेखक : संजीवकौरा, लाइटहाउस, पंजाबकेसरी, 10/02/04)

119) *पिछले सप्ताह मैं कर्नाटक गयी। लौटने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुँची हूँ कि हमारे इस भारत महान की समस्या यह नहीं है कि इण्डिया (शहरी) और भारत (गाँव) में फासले बढ़ रहे हैं। जहाँ आम भारतीय चाहता है कि देश तरक्की करे, आगे बढ़े, विचार धारा चाहे कोई भी हो, वहीं हमारे अधिकतर नेताओं और अधिकारियों की मानसिकता अभी तक पिछली सदी के बीच कहीं अटकी पड़ी है। मैं कर्नाटक उद्योगपति सज्जन जिन्दल के साथ गयी। हम मुम्बई से उनके निजी विमान में रवाना हुए, विजयनगर के लिए। विजयनगर की पहाड़ियों में छिपी हैं, वह कच्चे लोहे की खानें जिससे इस्पात बनता है। इन्हीं खानों के कारण सज्जन जिन्दल यहाँ पहुँचे थे, कोई दस वर्ष पूर्व इस्पात का कारखाना लगाने। सज्जन जिन्दल का कहना है– ''यकीन कीजिए जब हम यहाँ आए थे, तो यहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ सड़क तक नहीं थी। इस नगर को देखकर यकीन करना मुश्किल है।'' विद्यानगर आज एक ऐसा सुन्दर आधुनिक शहर है कि इसको अगर हम माडल मानकर जगह–जगह इसके अनुरूप शहरों का निर्माण करें तो अपने इस पुराने भारत देश की छवि ही बदल जाए। चौड़ी साफ–सुथरी सड़कों के किनारे फूलों भरे वृक्ष, आवासीय इलाके, ऐसे कि गरीब से गरीब मजदूर भी यहाँ इज्जत से रह सकता है। मनोरंजन के लिए हर तरह के साधन हैं– क्लब, स्टेडियम, रेस्टोरेन्ट। औद्योगिक शहर होने के बावजूद वातावरण इतना साफ और सुहावना है कि यहाँ जो लोग रहते हैं, वे अन्यत्र रहना पसन्द नहीं करेंगे। इसके कई हिस्सों में इतने पेड़ लगाए हुए है कि उन्हें देखकर यह एहसास ही नहीं होता कि यह क्षेत्र एक बड़े इस्पात कारखाने का चेत्र है। वह एक उद्यान सा लगता है। तो यह था मेरी इस कर्नाटकयात्रा का पहला अनुभव। विद्यानगर हम्पी से थोड़ी दूर है। श्री जिन्दल से इण्टरव्यू खत्म होने के बाद मैं वहाँ के लिए रवाना हुई। हम्पी के बारे में पढ़ा–सुना बहुत है, क्योंकि दुनिया के प्राचीन शहरों में हम्पी का नाम अंकोरवाट और पेट्रा के स्तर पर गिना जाता है। किसी और देश में हम्पी के खंडहरों को राष्ट्रीय खजाना माना जाता। लेकिन क्योंकि यह भारतदेश है, इसलिए यहाँ की कोई परवाह नहीं की जाती। हम्पी हो या कोई और हमारे नेताओं को क्या ? विद्यानगर से निकलते ही सड़क ऐसी टूटी, गढ्ढों से भरी मिली कि मैंने अपने कन्नड़ गाइड से पूछा कि क्या हम्पी के लिए यही मेनरोड है। जी हाँ! मुस्कुराते हुए उसने कहा। यह नेशनल हाइवे नम्बर 63 है। बरसात के बाद इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई। इसलिए सड़क का यह हाल है। वैसे भी यह सड़क कोई खास अच्छी नहीं है। गाइड ने बताया कि 9 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक हम्पी देखने आते हैं– हर साल। भारतीय पर्यटक तो उससे भी कहीं अधिक आते हैं और हम्पी पहुँचने से पहले वे क्या देखते हैं– हमारे गाँव की गरीबी, जो हर दर्जे तक दयनीय है। कच्ची झोपड़ियाँ उनके बीच में कुछ इक्के–दुक्के पक्के मकान उभरते हुए से दिखाई देते हैं। अधनंगे बच्चे, आवारा कुत्ते और सूअर इधर–उधर पसरे पड़े दिखाई देते हैं। यही है असली भारत। सदियों की गरीबी का इलाज (संसाधनों का समुचित वितरण किए बिना) शायद आसान नहीं, लेकिन सड़क का इलाज तो है– सज्जन जिन्दल अपने पैसों से सड़क बनाने को तैयार हैं। लेकिन भारतसरकार से कोई जबाव नहीं। कौन है जो देश के हित की बात दिल में रखे हुए हो ? कौन सा राजनीतिज्ञ है, जिसको इस बदनसीब देश के गौरवपूर्ण इतिहास की फि है ? क्या यहाष पर हम–आपको ही आगे बढ़ना होगा ? शायद, क्योंकि हर बार हमको हमारे शासक धोखा देते रहे हैं।*

-(स्तम्भलेखिका : तवलीन, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 14/01/2006)

120) 2005 के वर्णित व उपेक्षित :- राजनीतिक गतिविधियों से सम्बन्धित खबरों व लेखों ने मीडिया में प्रमुखता से कवरेज पाई। परन्तु देश की बड़ी आबादी से जुड़ी बुनियादी समस्याओं जैसे भुखमरी, पेयजल का अभाव, बेरोजगारी, गरीबी और गरीबी के कारण अशिक्षा व बीमारी बच्चों की उपेक्षा कुपोषण, पर्यावरण प्रदूषण, आबादी का बोझ, भ्रष्टाचार, लटकता न्याय, बिजली का अभाव, गाँव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, छोटे किसानों की बदतर हालत, मजदूरों, कामगारों को सरकारों द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी व सुविधाएँ न मिलना, गलत सर्वे आदि पर खबरों व लेखों को मीडिया ने नगण्य जगह दिया। किसी सरकार ने भी आम आदमी की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया।

-(डा. जयप्रकाश आर्य, मंगोलपुरी, दिल्ली, पंजाबकेसरी 14/01/2006)

121) पूर्व मुख्यचुनाव आयुक्त श्री लिंगदोह सेवानिवृत्त हुए हैं। बड़ी शालीनता से उन्होंने अपने विदाई समारोह में भाग लिया। ज्यादा कुछ नहीं बोले। बाद में पत्रकारों को प्रश्नों के उत्तर में दो ही बातें दोहराईं :-

क) मैं अगले दस जनम भी राजनीति में आना पसन्द नहीं करुँगा।

ख) मुझे इन राजनीतिज्ञों के साथ बैठने में भी प्रसन्नता नहीं होती।

जाते-जाते एक बात और कह गए- ''अभी तो हालात अच्छे नहीं हैं। अगर पढ़े-लिखे और सुसंस्कृत व्यक्ति इसमें आ जाएँ, तो बात और है।''

उनकी पीड़ा राजनीतिज्ञों से क्या थी, उसे समझा जा सकता है। उन्होंने कामना की-''**काश! पढ़े-लिखे और सुसंस्कृत व्यक्ति राजनीति में आते? केवल शिक्षा ही नहीं उच्च संस्कार भी चाहिए।**''

सचमुच बड़ी सारगर्भित है, उनकी टिप्पणी। संसद में कुछ ऐसे लोग हैं, जो बोलते हैं, तो लगता है अभी उछलेंगे और दूसरे की गरदन पकड़ लेंगे। न तो शब्दों में नियंत्रण है, न ही बॉडी लैंग्वेज (देहमुद्रा) शरीफों जैसी है, न ही सदन के लिए आदरभाव। ऐसे लोग लोकसभा अध्यक्ष के आसन तक पहुँचकर भी जो आचरण करते हैं, वह बड़ा ही अफसोसजनक है। जब हम स्वतन्त्रता की गोल्डनजुबली मना रहे थे, अर्थात् 1997 का वर्ष, उस समय अपने भाषण के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय के. आर. नारायणन ने दर्दभरी भाषा में कहा था-''**हमें अपना अन्तर्निरीक्षण करना होगा कि हमारा संविधान स्वयं असफल हो गया या कि हमने उसे असफल कर दिया।**'' उस समय इस एक वाक्य की बड़ी चर्चा हुई थी। भारत के प्रथम नागरिक की भाषा से जाहिर था कि- '**हमारा संविधान असफल हो चुका है।**'

-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 09/02/04)

122) हमारा भारत गरीब क्यों है? हमारी जनसंख्या का 30% प्रतिदिन 1 डालर से भी कम आय में गुजारा करता है। हमारे देश में अनपढ़ लोगों की संख्या विश्व में सबसे अधिक क्यों है ? हमारी सरकारी स्वास्थ्य-सेवाओं का स्तर इतना गिरा हुआ क्यों है कि एक गरीब भारतीय भी निजी चिकित्सकों व नीम-हकीमों के पास जाता है। एक अन्तर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार विश्व में निजी चिकित्सालयों में चिकित्सा कराने वालों में भारत के लोगों की सर्वाधिक संख्या है। यह 80% से भी अधिक है। हमारे समाजकल्याण का स्तर इतना खराब क्यों है कि कभी फसल खराब होने पर या मानूसन न आने पर गरीबों में से गरीब भूख से मरने लगते हैं। ये वे प्रश्न हैं जो उन भारतीयों द्वारा पूछे जाने चाहिए, जो इतना पढ़े-लिखे हैं कि समाचार पत्र पढ़ सकें। परन्तु वे यह प्रश्न पूछते नहीं हैं क्योंकि पत्रकार उनसे इस बारे में कुछ पूछते नहीं। इसका परिणाम यह होता है कि एक औसत भारतीय यही सोचता रह जाता है कि हमारा देश इसलिए गरीब है क्योंकि विदेशियों ने एक लम्बे समय तक हम पर राज किया या फिर वाणिज्यिक वैश्वीकरण के कारण या ऐसे ही किसी अन्य कारण से। वे समझ नहीं सके कि सही आर्थिक नीति न अपनाई जाए, तो प्रायः देश गरीब ही रह जाते हैं और भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। भले ही मुखर व प्रभावशाली उद्योगपतियों के लिए उत्पादन एवं व्यापार के नियम कुछ बदल गए हैं परन्तु पुराने नियम निर्धनतम लोगों के लिए अभी भी वही हैं। जब वे अपने बदहाल गाँवों से शहरों व कस्बों में भागकर आते हैं और बेरोजगारी के कारण सड़कों पर फेरी लगाने जैसा कोई छोटा-मोटा काम करते हैं, तो उन्हें रोज पुलिसवालों और नगरपालिका वालों का डर खाए रहता है। इस स्तर पर कोई सुधार नहीं हुआ। इसलिए उन्हें लाइसेंस और परमिट की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए उन्हें पुलिसवालों और अधिकारियों को मोटी रिश्वत देनी पड़ती है। एक अनपढ़ भारतीय भी जानता है कि भारत में अधिकतर भ्रष्टाचार किसी न किसी रूप में सरकार से जुड़ा है।

-(स्तम्भलेखिका : तवलीन, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 07/02/04)

123) राष्ट्रपति (अब्दुलकलाम) जी का स्वप्न इस देश को 2020 तक कहाँ से कहाँ ले जाने का है ? वह इस राष्ट्र को विश्वशक्ति के रूप में देख रहे हैं और अब वह जिस पद पर आसीन हैं, वह धीरे-धीरे सबसे वाकिफ होते जा रहे हैं। जिसे यथार्थबोध नहीं, जिसे राष्ट्रबोध नहीं, जिसे नीतिबोध नहीं, उसे अध्यात्म की शिक्षा क्या समझ में आएगी ? इसका उत्तर हम कहाँ ढूँढें ? राष्ट्रपति जिस मनुष्य की कल्पना कर रहे हैं, वह एक आदर्श मनुष्य है। एक ऐसा मनुष्य जिसे अपना कोई स्वार्थ नहीं और जो राष्ट्र को ही अपना सबकुछ समझता हो, कहाँ से आए ऐसी देशप्रेम की भावना ? ऐसे में राष्ट्र को कौन दिशा देगा ? 'दिनकर' की बड़ी सुन्दर पंक्तियाँ हैं :-

कुछ समझ नहीं आता रहस्य ये क्या है?
जाने भारत में बहती कौन हवा है?
गमलों में जो उगे सुरम्य सुदल हैं।
किन्तु भूमि के वृक्ष दीन-दुर्बल हैं।
जब तक है ये वैषम्य समाज सड़ेगा।
कैसे हो करके एक ये देश बढ़ेगा?

आज से 40 वर्ष पूर्व 'दिनकर' ने इन पंक्तियों को रचकर हमारी दशा का वर्णन ही नहीं किया था बल्कि आने वाले सारे भारत की रूपरेखा खींचकर रख दी थी। जब से देश आजाद हुआ है, हम (वैषम्य की) कलाकारी ही तो करते आ रहे हैं। **-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक, पंजाबकेसरी, 05/02/04)**

124) आँकड़ों की भूलभुलैया बनाकर देश को समझाने की कोशिश की जा रही है कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की तादाद घट गई है। संयुक्त राष्ट्र की मानवविकास की पिछली रिपोर्ट ने खुलासा किया था कि भारत में 34.08% लोग नितान्त निर्धनता में जीवनयापन कर रहे हैं, जो दो समय की रोटी का भी इन्तजाम नहीं कर सकते। खुद भारतसरकार के आँकड़े बताते हैं कि देश में 26 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो भूखे पेट सोते हैं, वह भी ऐसी स्थिति में जबकि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अनाज भरा पड़ा है। कुछ लोगों को खुशनुमा एहसास हो रहा है, लेकिन जो भूखे पेट सो रहे हैं, उन्हें कैसा एहसास हो रहा होगा ? देश की आबादी का 70% से अधिक आज भी कृषि पर निर्भर है। इसका परिणाम क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं। देहातों से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और शहरों में जाकर नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विकास के साथ रोजगार न बढ़ना एक खतरनाक स्थिति है। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से सरकार का हाथ खींचना भारत जैसे देश के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। लोकसभा चुनावों के मौके पर बेरोजगारी, पीने के पानी की समस्या, आबादी के बढ़ने की तेज रफ्तार, देश को विकसित तथा पिछड़े राज्यों के आधार पर बाँटने की सोच, संसदीय गरिमा और उसके गिरते स्तर जैसे तमाम मुद्दे हैं, जिन पर गम्भीरता से विचारकर जनता के सामने जाने की जरूरत है।

-(चन्द्रशेखर, पूर्व प्रधानमन्त्री, भारतसरकार, पंजाबकेसरी, 01/02/04)

125) इण्डिया टुडे पत्रिका द्वारा हाल ही के सर्वेक्षण 'द स्टेट आफ स्टेट' में हिमाचल प्रदेश के विकास के अनेक सूचकों का मूल्यांकन कर इसे पाँचवे स्थान पर आँका है। इस पत्रिका के सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है- 'बड़ा हो या छोटा, इसका कोई अन्तर नहीं पर उसे कैसा शासन प्राप्त हुआ है, इस बात का फर्क पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के विस्तार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के सृजन की दिशा में क्रान्तिकारी विकास हुआ है। यहाँ साक्षरता दर 1991 में 63% थी जो 2001 में बढ़कर 77% तक पहुँच गई। प्रदेश के लगभग सभी गाँव में बिजली प्राप्त है तथा 90% से अधिक गाँवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या जो 1993-94 में 29% थी, 1999-2000 में घटकर 8% रह गई। इस सारे विकास का श्रेय यहाँ सत्तासीन रहे लोगों को जाता है।

-(पंजाबकेसरी, दिल्ली, 25/01/2004)

126) भारत में जितने भी अपराध होते हैं, संविधान की आड़ में होते हैं और हम अवाक देखते रह जाते हैं। पुलिस महानिदेशक स्तर का व्यक्ति केन्द्र सरकार को यह रिपोर्ट सौंपता है कि एक जेल का संचालन जेल में बैठे एक देशद्रोही सांसद के द्वारा हो रहा है। तो भी जनता न तो उद्वेलित होती है और न सरकार

को कोई फर्क पड़ता है। सरकार उसी ईमानदार अफसर पर कार्यवाही करने की साजिश रचती है। अजब तमाशा है। राजनीतिक पार्टियों के स्वार्थ सर्वोपरि हैं। राजनीतिक पार्टियों के गठबन्धन सर्वोपरि हैं। देशप्रेम और राष्ट्रहित से इन्हें क्या लेना-देना। इस संविधान ने राष्ट्र की उन्नति में हर पल, हर क्षण रोड़े अटकाए हैं। यह पूर्णतः विदेशी भी होता तो भी कुछ बात थी इसने तो बस भनुमति के पिटारे की शक्ल धारण कर ली है। हमारा पूरा संविधान विसंगतियों से भरा पड़ा है। कुछ उदाहरण देखें –

क) *नगर निगमों में स्वीपर के पद के लिए 'सातवीं कक्षा पास' योग्यता चाहिए। परन्तु सांसद के लिए किसी शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं है।*

ख) *यह संविधान एक दुर्दान्त अपराधी को भी गृहराज्य मन्त्री बनने से नहीं रोक सकता। आपको तसलिमुद्दीन का उदाहरण बताने की जरूरत है क्या?*

ग) *मैजिक नम्बर की व्यवस्था गठबन्धनों को ब्लैकमेलिंग की आग में झोंक देती है। कोई उपाय नहीं, सांसद खरीदिए, सांसद बेचिए।*

घ) *संसद में सांसद का आचरण कैसा हो, कितना शालीन हो, इस पर एक शब्द भी नहीं। परन्तु एक-दूसरे को वीभत्स गालियाँ भी देने का इन्हें विशेषाधिकार है। कोई कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकता।*

ङ) *सेवानिवृत्ति की आयु दुनिया की सारी सेवाओं में है। परन्तु 120 वर्ष की आयु में भी ये लोग राजनीति कर सकते हैं।*

च) *सारा संविधान भारी विसंगतियों से भरा पड़ा है। न जाने हम कब सुधरेंगे?*

-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 13/01/2004)

127) *बिहार की व्यथा-कथा कहाँ से आरम्भ करें? कहाँ से अन्त? इस राज्य की बदहाली का वर्णन करें या वहाँ की भयंकर असुरक्षा, अपहरण व्यवसाय, हत्या, लूट और बेकारी का। जनता की बेकदरी की चर्चा करें या नेताओं की अकर्मण्यता की। हर दौड़ में पिछड़ रहे बिहार की बात एक लेख में खत्म नहीं हो सकती। बिहार एक ऐसा बीमार राज्य है, जिसका इलाज करने वाले स्वयं ही बीमार हैं। वे राजनैतिक जातीय, मानसिक, बौद्धिक, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, हिंसा, हत्या, अपहरण आदि सभी बीमारियों के शिकार हैं। शिक्षा, रोजगार, पूँजीनिवेश और प्रशासनिक व्यवस्था के इन्डेक्स में बिहार को ढूँढ पाना आसान नहीं। किन्तु इसके बाद भी इन मुद्दों पर बिहार में चर्चा नहीं होती, रैलियाँ नहीं होती, प्रदर्शन नहीं होते। आश्चर्य होता है कि बिहार में गरीबी, बेरोजगारी और अपराध का बोलबाला होने के बावजूद कहीं कोई व्यापक और संगठित असंतोष नहीं फूटता। कुछ समाज विज्ञानी इसे वहाँ के अद्भुत समाज रसायन का परिणाम मानते हैं। उनके अनुसार संघर्ष वहाँ होता है, जहाँ कुछ प्राप्त होने की अभिलाषा या उम्मीद होती है। बिहार में किसी को भी सरकार से कुछ प्राप्त होने की अभिलाषा या उम्मीद नहीं है। बिहार के गाँवों, कस्बों और शहरों का आप दौरा कीजिए। अस्सी फीसदी कामकाजी लोग बिहार से बाहर हैं। अच्छी पढ़ाई और अच्छी कमाई की इच्छा रखने वाले बिहार छोड़ देते हैं। रह जाते हैं, सिर्फ वे जो लाचार हैं, नाउम्मीद हैं। संभवतः बिहार पहला ऐसा राज्य है, जहाँ नेता खुद के अपराधी होने पर भी गर्व करते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि होने के बावजूद अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि छिपाने की जरूरत नहीं समझते। हत्या, अपहरण में सीधे लिप्त होने वाले विधायक और सांसद यूँ घूमते हैं, जैसे जंगल के अपने-अपने इलाके में विचरण करने वाले जंगली जानवर।*

-(भानुप्रतापशुक्ल : स्तम्भकार, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 12/01/2004)

128) *तेज तर्रार और बिना लाग-लपेट के अपनी बात कहने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त जे. एम. लिंगदोह ने राजनेताओं पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए उन्हें एक ऐसा 'कैन्सर' करार दिया है, जिसका फिलहाल कोई इलाज नहीं है। उनका कहना है कि ''**इस समय देश में एक भी ऐसा नेता नहीं है, जो लोकतन्त्र और लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो।**'' बी.बी.सी. वर्ल्ड पर 'हार्ड टॉक इण्डिया' कार्यक्रम में करण थापर को दिए साक्षात्कार में उन्होंने राजनेताओं और नौकरशाहों को लेकर उनकी नाराजगी के बारे में किए गए सवालों के जबाव में कहा कि ''**इनमें से शायद ही कोई किसी काम का हो।**'' उन्होंने कहा-''**राजनीतिज्ञ ऐसे घातक कैन्सर के समान हैं। कैन्सर का अभी तक कोई इलाज नहीं ढूँढा गया है और यदि भविष्य में कोई कारगर इलाज खोज भी लिया गया तो हमें राजनेताओं के लिए कोई और नाम खोजना होगा।**'' यह पूछने पर कि क्या उनका बयान भारतीय लोकतन्त्र पर दोषारोपण करने वाला नहीं है। उन्होंने कहा-''**लोकतन्त्र का मतलब केवल चुनावप्रक्रिया नहीं है। लोकतन्त्र माने निजी स्वतन्त्रता और***

उसका अधिकतम स्तर तक सम्मान किए जाने की भावना है। मुझे नहीं लगता कि इस समय हमारे आसपास ऐसा कोई नेता है, जिसे सही मायने में लोकतन्त्र की भावना की चिन्ता है।'' इस सवाल पर कि क्या उनके कहने का मतलब यह है कि मौजूदा समय में ऐसे लोग इस पर राज कर रहे हैं, जो इसके हकदार नहीं हैं, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा–''इतना आगे जाना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ काफी हद तक यह बात सही है।'' राजनेताओं के खिलाफ ध ोखेबाजी शब्द का इस्तेमाल किए जाने के सम्बन्ध में पूछने पर उन्होंने कहा कि ''यह और कोई बोलने की कोशिश नहीं कर रहा है।'' उन्होंने कहा–''यह अजीब सा लगता है, लेकिन किसी को तो करना ही होगा। मुझे लगता है कि हर कोई उनके तलुवे चाटने में लगा है और वे फूले नहीं समा रहे हैं। किसी को तो उन्हें बताना होगा कि वे उतने प्यारे नहीं लग रहे, जितना वे खुद को सोचते हैं।'' ***-(एक समाचार, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 26/12/2003)***

129) नेताजी को मतदाता का पत्र :- *आदरणीय नेताजी, जयभारत! उम्मीद है कि चुनाव की भागदौड़ के बाद अब घर पर बैठकर कलुवा से हाथ–पैर दबवाकर मालिश करवा रहे होंगे। इन्हीं कलुवाओं के उत्थान के नाम पर आपने अब तक वोट माँगे हैं। यह थकान भी इन्हीं कलुवाओं की दी हुई है, तो थकान उतारने का नैतिक दायित्व भी तो इन्हीं कलुवाओं का हुआ न। पिछले दिनों टमाटर, मटर की तुलना में हम वोटर के भाव अच्छे रहे। हमारी भी खूब पूछ हुई। मुहल्ले में तमाम नेता हमें खरीदने के लिए आते रहे। हमें ललचाई नजरों से देखते रहे थे। मगर अब हमारी हालत खाली सिलिण्डर या पिछले वर्ष के पुराने कैलेण्डर सरीखी हो गयी है। वही हम हैं, वही हमारी उंगली है, वही इलेक्ट्रानिक मशीन है लेकिन अब हम हम नहीं रहे और तुम तुम नहीं रहे। कितना बड़ा फर्क आ गया है। अभी कुछ दिन पहले की ही तो बात है। तुम जीप से आए थे। जीप में झण्डा, बैनर, पूड़ी–सब्जी के पैकेट, औरतों के लिए पार्टी के निशान वाली बिन्दी और आदमियों के लिए पाउच लेकर आए थे। हमने वोटिंग मशीन पर अपनी उंगली क्या धर दी मानो अब हमारी उंगली ही बेकार हो गयी। जी करता है कि इस उंगली को काटकर फेंक दूँ। आखिर यह हमारे अब किस काम की है। पता नहीं अब यह किसी काम आए या नहीं। अगले चुनाव तक यह उंगली रहे न रहे। लॉ एण्ड आर्डर को देखते हुए कहा नहीं जा सकता है कि हम ही रहेंगे या नहीं। वाह! तुमने खूब लड़ाई लड़ी। विपक्षियों को दारू पी–पी करके खूब कोसा। शब्दों तक के वस्त्र खींच लिए। तुमने तो कमाल ही कर दिया। दूसरे नेताओं की ऐसी धज्जियाँ उड़ाईं कि देखने वाले देखते ही रह गए। मेरा बेटा शालू मुझसे पूछ रहा था कि ''पापा! साइबेरिया के सारस भारत में एक ही बार क्यों दिखाई देते हैं?'' मैंने उसे समझाया कि बेटा वे साइबेरियन सारस हैं। सीजन में वे भारत आते हैं इसके बाद विलुप्त हो जाते हैं। जबकि भारतीय नेता खासकर जीते हुए प्रतिनिधि तो एक बार दिखाई देते हैं, उसके बाद पाँच साल के लिए विलुप्त हो जाते हैं। ये तो साइबेरियन सारस से भी ज्यादा दुर्लभ हैं। बेटा पूछने लगा ''पापा ये जीतने के बाद दुर्लभ क्यों हो जाते हैं।'' मैंने उसे समझाया कि जो चुनाव में खर्च किया है, उसको सूद समेत वसूलने के लिए राजधानी चले जाते हैं।'' अबकी बार तो तुम वायदा करके गए हो कि इस बार गायब नहीं होगे, क्षेत्र का विकास करोगे, हमारे क्षेत्र को अपना घर समझोगे। लेकिन जब से चुनाव हुए हैं, तुम कहाँ छिप गए, दिखाई ही नहीं दिए। हमारे घर के बाहर तुम्हारा फोटो वाला चुनावी पोस्टर चिपका हुआ है। तुमने हर बार वायदे किए, इस बार तो और बढ़–चढ़कर वायदे किए हैं। हर हाथ को काम हर जेब में दाम। देखो हमारे हाथ को काम, जेब में दाम आता है कि नही। तुमने खूब लुभावने सपने हमें दिखाए हैं। अब उनको साकार करने का वक्त आ गया है। तुमने वोट माँगा, हमने दिया। जिताने को कहा, हमने जिता दिया। अब हमारा भाग्य भी जगाओ। हमने अपना फर्ज निभा दिया, अब तुम अपना कर्ज उतार दो। हमारी पत्नी वंदना ने सात शुक्रवार के व्रत बोल दिए हैं। हमने पूछा कि तुमने क्या माँगा है तो कहने लगी कि ''हमने क्षेत्र के प्रतिनिधि के लिए सत्बुद्धि माँगी है। यह भी माँगा है कि उनकी स्मरणशक्ति न खोने पाए। उन्होंने जो कुछ कहा है, जो भी संकल्प लिए हैं, उन्हें पूरा करने की इच्छाशक्ति ईश्वर जरूर उन्हें प्रदान करे। डाकविभाग का भरोसा नहीं रहा है इसलिए यह पत्र बैरंग भेज रहा हूँ। तुम्हारा अभागा मतदाता।*

-[संजीवसक्सेना, एस.आई.(एन.), पुलिसकार्यालय, फतेहगढ़, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 26/12/2003]

130) दरिद्रता के भयावह चेहरे :- *गरीबों के जीवन में केवल गरीबी नहीं होती बल्कि लोगों के पेट में अन्न के दाने नहीं होते, हाथों में रोजगार नहीं होता और जिन्दगी में सम्मान नहीं होता। मध्यप्रदेश में सहरिया आदिवासियों का बहुत बड़ा वर्ग है, जो दरिद्रता का ऐसा ही जीवन जी रहा है। भुखमरी से अकालमौत मरना उनकी नियति बन चुकी है। सरकार ने लगातार उपेक्षा करके उनकी जिन्दगी के पन्ने बिखेर दिए। अपनी जिन्दगी को नये सिरे से शुरु करने का कोई विकल्प न देख वे हताशा भरे दिन गुजार रहे हैं। ग्वालियर चम्बल अंचल के 4.5 लाख आदिवासी आज भुखमरी से मर रहे हैं, जिसका किसी सरकारी रिकॉर्ड में कोई जिक्र नहीं है। यह आदिवासी समाज हमेशा जंगलों पर निर्भर रहा है। यह समुदाय जंगलों से मिलने वाली गोंद और चिरौंजी के बदले अनाज खरीदता रहा। यहाँ से मिलने वाली सियारी लकड़ी से डलिया बनाकर वह छह महीने की जरूरतें पूरी करता रहा। लेकिन उनकी खुशियों में आग तब लगी जब सरकार ने उन जंगलों को अपने अधिकार में लेकर उसे ठेकेदारों को सौंप दिया। ठेकेदारों ने जंगल पूरी तरह साफ कर दिए। इससे सहरियाओं को गोंद, चिरौंजी और सियारी लकड़ी की भारी किल्लत हो गई। मजबूरन कुछ आदिवासियों ने अपना मूलस्थान शिवपुरी, गुना, श्योपुर आदि को छोड़कर दो वक्त की रोटी के लिए दिल्ली, जयपुर आदि बड़े शहरों की ओर पलायन किया। जो रह गए, वे अपने ही गाँव में वैकल्पिक रोजगार की तलाश करने लगे। गाँव के सम्पन्न किसानों, साहूकारों ने सूखे के दो सालों तक तो उन्हें इस शर्त पर कर्ज दिया कि बदले में वे उनकी खदान और खेत में काम करते रहेंगे। कुछ ने जंगल में पैदा होने वाली समा के बीज का दलिया और रोटी खाना शुरु किया। लेकिन सूखे के चलते समा का बीज पूरी तरह से पका न होने की वजह से बच्चे और बूढ़े उसे पचा नहीं पाए। नतीजतन कई लोगों की मौत हो गई।*

गाँव के लोगों को दो से पाँच किलोमीटर से पानी ढोकर लाना पड़ रहा है। वह भी ऐसी स्थिति में जबकि उन्हें काम की तलाश करने में ज्यादा समय झोंकने की जरूरत पड़ रही है। शहडोल जिले की भाठडाँड पंचायत की तैराशा बाई ने अपने दस साल के बेटे को अपने सम्पन्न पड़ोसी को दे दिया, जहाँ वह जानवर चराने का काम करता है। जिसके बदले में उसे खाने को रोटी और पहनने को पुराने कपड़े मिल जाते हैं।

अब सरकार की संवेदनशीलता पर सवालिया निशान गहराता जा रहा है। अधिकारी पूरी तरह से भूल गए हैं कि लोगों के जीवनयापन के अवसर उन्होंने ही छीन लिए हैं। मजदूरों को चार साल पहले किए गए काम की मजदूरी के 200 रुपये अभी तक नहीं मिले हैं। जबकि ठेकेदार को तीन लाख रुपये काम पूरा होने से पहले ही मिल जाते हैं। अब सवाल परिस्थितियों और नजरिये को बदलने की जरूरत का है।

-(सचिनकुमारजैन, धरमा; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 10/12/03)

131) *शिक्षा राज्य के हाथ में ऐसा वैचारिक औजार है, जिसे सामाजिक ढाँचे की संरचना में बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत में शिक्षा का राष्ट्रीय ढाँचा औपनिवेशिक पूँजीवाद के दौर में ही खड़ा हुआ है। ''**विदेशों के हाथ बिकी मेरी सरकार, शिक्षा की कौन सुनेगा पुकार? सदियों से हम कर रहे हैं चीत्कार, अँधेरा हर तरफ बेशुमार ॥**''*

*साक्षरता अभियान और सर्वशिक्षा अभियान जैसी अवास्तविक शैक्षिक परियोजनाएँ देश के सार्वजनिक शैक्षिक ढाँचे पर हो रहे जबरदस्त हमले को छिपाने के लिए तैयार किए गए मुखौटे हैं। ये बदलाव अभूतपूर्व है। कहना न होगा कि इन बदलावों में हमारी प्रिय मातृभूमि के विकास और यहाँ तक कि उसकी बुनियादी एकता को नष्ट करने की खतरनाक क्षमता है। अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता के अधीन कार्य कर रही हमारी सरकारों की तमाम शैक्षिक पहलों का सार यही निकलता है कि ''**आम जन के लिए साक्षरता और खास लोगों के लिए शिक्षा**।'' इसे विडम्बना ही कहा जाएगा कि मण्डलीकृत और बहुजनीकृत राजनीतिक माहौल में समाज के कमजोर तबके मसलन जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक और महिलाएँ खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऊध वर्गामी मध्यवर्ग सार्वजनिक शिक्षा संस्थाओं से अलग होकर शैक्षिक उत्कृष्टता के हरे-भरे बाग में विचरण कर रहा है। यही हाल हमारे इस स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौर में मुसलमानों को शिक्षित की गई अलीगढ़, जामिया व जाकिरहुसैन जैसी राष्ट्रीय परियोजनाओं का है। ये अब बीते हुए युग का सपना बनकर रह गई हैं। अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान भयानक अशिक्षा और बेरोजगारी के बोझ तले दबे हुए हैं। यह है हमारी शिक्षा का इतिहास और उसका नष्ट होता स्वरूप, जिसे बचाना है। ''**उठो इकठ्ठे चलना है। दुश्मन को अब ढलना है॥ हक अपने ले करके रहेंगे। शिक्षा का सूर्य निकलना है॥**'' **-(सचिनकुमारजैन, धरमा; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 10/12/03)***

132) *पहली बात इस देश का राजनेता चाहे वह किसी भी दल से सम्बन्धित हो, आज इस कदर स्वार्थी, अहंकेन्द्रित, मतलबपरस्त, रीढ़विहीन और अविश्वसनीय हो गया है कि अगर उसके स्वहित और स्वार्थ के सामने राष्ट्रहित भी टकराव की मुद्रा में आते हैं या उसके दोगले राजनीतिक समीकरणों के समक्ष राष्ट्र की एकता, अखण्डता और प्रभुसत्ता भी आ खड़ी होती है, तो वह राष्ट्र की मर्यादा को तार-तार कर देगा। राष्ट्र की अखण्डता को दाँव पर लगा देगा परन्तु अपने स्वार्थ से बाज न आएगा।*

दूसरी बात किसी भी राजनेता से चाहे वह 1000 कसमें क्यों न खाए, आप सत्यनिष्ठ होने की कल्पना भी न करें। राजनेता सच नहीं बोल सकता। यह नहीं है कि अपवाद के तौर पर कुछ अच्छे लोग नहीं। दस-पाँच अच्छे आदमी हो सकते हैं, पर वे भी सच्चे नहीं हो सकते। इनकी मजबूरी भी है। यह मजबूरी इन्हें असत्य का अवलम्बन लेने पर मजबूर कर देती है। **-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 15/12/03)**

133) *सारे देश में सैंकड़ों पार्टियाँ बन गईं। शैक्षणिक योग्यता का कोई लेना-देना नहीं था। बड़े-बड़े संगीन अपराधों के आरोपी भी चुनाव लड़कर संसद और विधानसभाओं में स्थान पाने लगे। सारे राष्ट्र ने विस्फारित नयनों से देखा कि घोटालेबाज, गुटकेबाज और डकैतों तथा खून और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के आरोपी भी इस ओर खिंचे आने लगे। सारा राष्ट्र यह दुर्दशा देखकर चिन्तित हो गया कि ऐसे लोग मन्त्री भी बनना शुरु हो गए हैं। मनोज नरूला नामक एक व्यक्ति ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की कि भारत की स्वच्छ छवि को देखते हुए यह अच्छा नहीं लगता कि कुछ अपराधी छवि वाले लोग मंत्रिमण्डल में आ गए हैं, मंत्री बने रहें। उन्हें हटाने के निर्देश दिए जाएँ। माननीय अटार्नी जनरल का कहना था कि संविधान में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। संविधान तो यह कहता है, कि अगर कोई भी व्यक्ति सांसद है, तो प्रधानमन्त्री उसे अपने मंत्रिमण्डल में ले सकते हैं। यह उनका निर्णय है और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। एक और वकील जो वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने बड़े दर्द से कहा, ''माननीय सर, अगर यही हाल रहा, तो मंत्रिमण्डल अपराधियों से भर जाएगा।'' परन्तु कोर्ट के पास ऐसा कोई सम्वैधानिक विकल्प नहीं था कि ऐसी स्थिति में कुछ कर पाते। भारत का प्रजातन्त्र काँप रहा है, पर कोई कुछ कर नहीं पा रहा।* **-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 01/09/05)**

134) *वर्षा के काले बादल, सावन के महीने में जब आकाश में मँडराते देखता हूँ, तो मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है कि विनाश के काले बादल हमारे चारों ओर मँडरा रहे हैं। अनिष्ट की काली छाया मैं आज चारों ओर महसूस कर रहा हूँ। नियति ने जाने-अनजाने जिन लोगों को हमारे सिर पर राज करने के लिए बैठा दिया है, मैं आज उन्हें भी दोष नहीं दूँगा। राष्ट्र के मूल्यों से खेलना जिनकी संस्कृति बन चुकी हैक, राजनीति जिनके लिए व्यापार है, मंत्रिपद जिनके लिए लूट का सुनहरा अवसर है, राष्ट्रधर्म से जिन्हें कोई मतलब नहीं, धर्मनिरपेक्षता जिनके सर पर चढ़कर बोल रही है, तुष्टिकरण जिनकी रग-रग में समा चुका है, ऐसे बेईमान और भ्रष्ट शिखंडियों से न तो पहले राष्ट्र को कोई उम्मीदें थीं और न आज भी हैं। यह सम्पादकीय मैं पाखण्डियों और कायरों के लिए नहीं लिख रहा।* **-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 22/07/04)**

135) *आज मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि राजनीति ने हमें इतना अन्धा कर दिया है कि न तो हमें अपनी दिशा से मतलब रह गया है और न अपनी दशा से।*

जिस संविधान को इसके तथाकथित रचयिता डा. अम्बेडकर आग में भस्मीभूत कर देना चाहते थे, उसे किन लोगों ने सर पर उठा रख हुआ है, वैसे चेहरों को पहचानना होगा। ये वही लोग हैं, जो संविधान की आड़ में समाज में हर प्रकार का दुष्कृत्य करते हुए भी सत्तासुख भोग रहे हैं। कैसे हो समस्या का निदान? कौन बताएगा समाधान? कैसे बचेंगे राष्ट्र के मूल्य? ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ।

-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 17/07/04)

136) *अभी हाल ही में अखबारों में यह खबर छपी कि मुम्बई में एक भिखारी है, जिसका नाम है- संभाजी काले। यह एक ऐसे भिखारी परिवार का मुखिया है, जो खार ट्रैफिक सिग्नल के पास बैठकर भीख माँगने का धन्धा करता है। पास ही विरार में उसका एक थ्री बेडरुम का फ्लैट है, जो उसने किराए पर दे रखा*

है। बैंक में उसके 50 हजार रुपये किसी आपात काल के लिए हमेशा रहते हैं। वह मारुति कार पर भीख माँगने आता है। कई कम्पनियों के शेयर उसने ले रखे हैं। वहाँ के सामाजिक विकास केन्द्र के सचिव 'विजय मरांडे' यह बताते हैं कि यह काले परिवार और उनसे प्रेरणा पाए हजारों लोग अपने को भिक्षुक कहे जाने से बड़ा दुःख मनाते हैं और उनका कहना है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर करें कि उनकी मेहनत देखते हुए इन्हें श्रमवीर कहलाने का हक दिया जाए और इनका दर्जा उनसे ऊपर रखा जाए, जो हर पाँच वर्ष में सिर्फ एक बार भीख माँगने निकलते हैं और फिर भी ऐश करते हैं।

यह कोई आम भिखारी नहीं, बल्कि हमारे देश के भाग्यनिर्माता लोकसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए हाथ जोड़े घर-घर जाकर वोटों की भीख माँगते हैं। मासूम चेहरे बनाए, भोली-भाली जनता की भावनाओं से खेलकर और झूठे वायदों के बलपर जब ये 'वोटभिक्षुक' चुनाव में जीतने के बाद मंत्री बन जाते हैं, तो फिर पाँच वर्ष के लिए भिखारी से राजा बनकर माल काटते हैं और गरीब जनता के माल पर गुलछर्रे उड़ाते हैं। ये राजनीतिक भिखारी बेहद ढीठ और बेशर्म हैं, जो पैसे और सत्ता के लिए अपनी मातृभूमि को भी बेच सकते हैं। भगवान इनको सद्‌बुद्धि दे। ***-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक, पंजाबकेसरी, 12/07/04)***

137) *आज आम आदमी से पूछें कि वह किस पीड़ा में जी रहा है? उसे कितनी घुटन महसूस हो रही है? राजनीति के नाम पर लुटेरों के गिरोह बन गए हैं। कभी एक गिरोह लूटता है, कभी दूसरा गिरोह लूटता है। एक गिरोह दूसरे गिरोह पर लांछन लगाता है- तू चोर, तू अपराधी, तू घोटालेबाज, तूने यूरिया का माल हड़पा, तूने लखूभाई को लूटा, तूने यूटी स्कैम किए, तूने बोफोर्स घोटाला करवाया, तूने दंगे करवाये'' तो दूसरा गिरोह कहता है- ''तू कौन सा दूध का धोया है, अपना गिरेबान देख। बड़े तहलके तेरे राज में मचे, पेट्रोलपम्प की बंदरबाँट हुई, गुजरात में दानवता नंगी नाचती रही, जमीनें संघसंस्थानों को कौड़ियों के दाम बेचीं, ताबूतों को नहीं बख्शा, जरा अपना गिरेबाँ भी झाँक।'' इसके बाद दोनों गिरोह साथ मिलकर सारे राष्ट्र को चिढ़ाते हैं- ''देखो भारत चमक रहा है, आप फीलगुड करें।'' उद्‌घोष करते हैं- ''हमारा हाथ आम आदमी के साथ।'' दोनों दावा करते हैं- ''हम महान हैं, हमें वोट दो, हमें जिताओ, राष्ट्र की रक्षा करो, भारतदेश महान।'' आम आदमी परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि शक्लोसूरत से तो ये लोग आम इंसानों जैसे लगते हैं, परन्तु इनका व्यवहार इंसानों जैसा नहीं है। लगता ही नहीं कि ये इसी पृथ्वी ग्रह के प्राणी हैं। इनके तो दर्शनमात्र से जीवन में ग्रहण लग सकता है। मुझे लगता है, इस व्यवस्था में नेता, अफसरशाही और पुलिस से भी ज्यादा कोई बेईमान है, तो इस देश का बुद्धिजीवी है। वह अपना फर्ज भूल गया है। उसकी कलम पद्मविभूषण और पद्मश्री जैसे पुरस्कारों के लिए लिखने लगी है। उसका लावा बर्फ बन चुका है। राष्ट्र इस षड़यन्त्र को भी देखे। न जाने कब हमें होश आएगा।*

-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक, पंजाबकेसरी, 03/07/04)

138) *मैं 2 सितम्बर, 1953 के दिन को एक ऐतिहासिक दिन मानता हूँ। उस दिन आन्ध्रप्रदेश स्टेट विधेयक पर बहस हो रही थी। गृहमन्त्री काटजू, बंगाल से बी.सी. घोष, उड़ीसा से श्री एस.एन. द्विवेदी उसमें भाग ले रहे थे। बात-बात में डा. अम्बेडकर उद्वेलित हो उठे। उन्होंने संसद में कहा- ''लोग मुझे कहते हैं, तुमने संविधान रचा। मेरा उत्तर है, मैं तो केवल एक भाड़े का टट्टू था। मुझे जो कहा गया, मैंने अपनी इच्छा के विपरीत किया।'' जब बहस आगे बढ़ी और किसी बात पर उनके स्वाभिमान पर फिर संविधान निर्माण को लेकर व्यंग कसा गया, तो वे चीत्कार उठे- ''लोग कहते हैं, मैंने संविधान बनाया लेकिन मुझे मौका मिले तो मैं पहला व्यक्ति होऊँगा, जो इसे सरेआम जला दूँ।'' सनद् रहे ये बात बाबा साहब कह रहे हैं। आज कोई दूसरा सांसद ऐसा कहे तो 'शिखंडी' आसमान शिर पर उठा लेंगे, तोड़-फोड़ शुरु कर देंगे। जिस संविधान को बाबा साहब जला देने के इच्छुक थे, वह संविधान कैसा है? (अर्थात् वह कितना न्यायशील है?)*

-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक, पंजाबकेसरी, 10/06/04)

139) *बॉलीवुड कभी नहीं हारता, अपराधी कभी नहीं हारता, थैलीशाह कभी नहीं हारता, यह कड़ुआ सच है। आने वाली सरकार सांसदों की वोटों को देखकर नहीं, उनके संस्कारों (गुणवत्ताओं) को देखकर चलेगी, तो बड़ा ही शुभ होगा।* ***-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक, पंजाबकेसरी, 16/05/04)***

140) राजनीति धीरे-धीरे ही सही, भारत के सामान्यजन की बुनियादी उदारता का क्षरण कर रही है। ऐसा यदि अब हो रहा है, तो वह हमारे विभाजक राजनीति और सत्ता के भूखे धूर्त लोगों की ही मेहरबानी है। लोगों को अपने भरोसे छोड़ दें, तो वे भारतीय के तौर पर ही खुश हैं। हमारे सैनिक, हमारे खिलाड़ी, हमारे वैज्ञानिक, हमारे अभियन्ता, हमारे श्रमिक और किसान हिन्दू, मुसलमान और ईसाई हैं। वे भारतीय के रूप में ही काम करते हैं। यही वास्तविक भारत है। वह भारत जिसमें सैंकड़ों धार्मिक व सांस्कृतिक पुष्प कुसुमित हो रहे हैं। जहाँ एकमात्र विभाजन धनी और निर्धन के रूप में ही है। निर्धन जन सभी धर्मों में हैं और वही वास्तविक बहुमत में हैं। जिस दिन हमारी राजनीति और राजनीतिज्ञ इस हकीकत को मान लेंगे और निर्धन के हितसाधन में प्रवृत्त हो जाएँगे, उसी दिन सही अर्थों में भारत का एक महान राष्ट्र के रूप में उदय होगा। (लेख : आखिर भाजपा को भी साम्प्रदायिकता त्यागनी पड़ी)

-(सुमेरकौल, स्तम्भकार, पंजाबकेसरी, दिल्ली, मई-2004)

141) जब तक पढ़े-लिखे विचारवान लोग वोट देने के लिए आगे नहीं आएँगे, तब तक ऐसे लोग चुनाव जीतकर संसद व विधानसभाओं में पहुँचते रहेंगे, जिनपर अक्सर घोटाले करने या माफिया सरगना होने के अरोपों के कारण उँगलियाँ उठती रहती हैं। जनता में कुछ ऐसे लोग हैं, जो आर्थिक तौर पर अभी भी पीछे हैं। उनमें से कुछ लोग लालच में फँस जाते हैं, तो कुछ का झुकाव जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद आदि की तरफ हो जाता है। हम समझते हैं कि सभी जागरूक लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए क्योंकि जो लोग चुनकर जाएँगे, उनपर ही कानून बनाने तथा देश को सही दिशा में ले जाने की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने ही आम जनता के लिए अस्पताल, स्कूल, सड़कें, बिजली, पानी तथा अन्य जनकल्याणकारी सुविधाएँ उपलब्ध करानी हैं। उन पर ही देश की सुरक्षा तथा अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी होगी। लोगों के सामने सभी दलों की सच्चाई सामने आ गई है, तथा इस हमाम में सभी पार्टियाँ नंगी हैं। वोट देते समय इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हम उसी को अपना वोट दें, जिसे हम अपेक्षाकृत अधिक गुणवान समझें तथा जो निम्नलिखित गुणों की कसौटी पर पूरा उतरता हो :-

क) जो चरित्रवान, सिद्धान्तवादी, शिक्षित, विवेकवान, प्रभावशाली, पारदर्शी व्यक्तित्व और सादगीपूर्ण जीवन वाला है।
ख) जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि न हो तथा उस पर ऐसे आरोपों में मुकदमे न हों।
ग) ईमानदार हो और भ्रष्ट तरीकों से अपनी जेबें न भरने वाला हो।
घ) क्षेत्र के सभी वर्गों के लोगों से मेलजोल रखने वाला, उनके सुख-दुःख में काम आने वाला, उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करने वाला हो तथा जिससे सभी लोग आसानी से मिल सकें।
ङ) अपने क्षेत्र, प्रदेश तथा देश की समस्याओं की जानकारी रखता हो तथा उनके समाधान में समर्थ हो। जो संसद में अपनी बात तथा इलाके की समस्याओं को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर सके।
च) जनहित व देशहित को सबसे ऊपर समझने वाला हो।
छ) जातिवादी, साम्प्रदायिक और संकुचित क्षेत्रवादी तथा भाई-भतीजावादी न हो।
ज) राष्ट्र को स्वावलम्बी बनाने के लिए संकल्पबद्ध हो। देश की एकता व अखण्डता के विरुद्ध आचरण न करता हो।
झ) लोगों से झूठे वादे कर उन्हें गुमराह न करता हो। जिसे संसद में भेजकर आप और आपका निर्वाचन क्षेत्र गौरवान्वित अनुभव करे।

-(विजय, सम्पादक, पंजाबकेसरी, 05/05/04)

142) यहाँ चुनाव में किन्नरों से लेकर फिल्मों वाले तक नाचे। हर बूथ पर लूटपाट हुई। हर नस्ल के अपराधी चुनाव लड़ रहे हैं। हत्यारे, खूनी, डाकू सब सांसद बनने की तैयारी कर रहे हैं, पर हमारा संविधान चुप है। हमारा कानून चुप है। आज एक प्रश्न भारत के सामने यक्षप्रश्न की तरह मुँह बाए खड़ा है। भारतवर्ष के संविधान में शैक्षणिक योग्यता या अन्य योग्यताओं का कहीं जिक्र नहीं है। वयस्क मताधिकार ही प्रजातन्त्र की रीढ़ है और यहाँ के वयस्क की जो बौद्धिक क्षमता छोटे पर्दे पर नजर आती है, हेलीकॉप्टर को दण्डवत प्रणाम करके वोट देने का वायदा करते हैं, तो लगता है कि जिन अन्धी गलियों से हम गुजर रहे हैं, उनका अन्त क्या होगा ? भारत के चुनाव आयोग का जब यह मानना है कि सांसद का चुनाव कम से कम 20 लाख रुपये से लड़ा जा सकता है, तो कैसे आम शिक्षित व्यक्ति इस पर आकर्षित हो ? किसी जंगल में 20 शेर हों, 5 हजार भेड़िए हों, 2 लाख गधे हों और वहाँ हमारा संविधान लागू हो जाए, तो उस जंगल की जो गति होगी, वही इस राष्ट्र की हो रही है। भारत एक गहरे षड़यन्त्र से गुजर रहा है, जो षड़यन्त्र सिर्फ 543 लोगों के हित में है।

सत्ता के षड़यन्त्र में, हवा हुई मशगूल।
गमलों में सजने लगे, नागफनी के फूल॥

-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक, पंजाबकेसरी, 01/05/04)

143) *''आने वाले भारत का स्वरूप कैसा होगा, उसकी हम सहज की कल्पना कर सकते हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं। हम अच्छे से अच्छे सच्चरित्र और राष्ट्रप्रेमी युवकों को राजनीति में अवसर देंगे। ताकि वे भविष्य में एक सर्वोत्कृष्ट भारत की कल्पना को साकार कर सकें।'' उपरोक्त उद्‌गार एक विदेशी पत्रिका को दिए साक्षात्कार में 13 मई, 1964 को पण्डित नेहरू ने प्रकट किए। दुर्भाग्यवश ठीक इसके 2 सप्ताह बाद ही उनका निधन हो गया। क्वालिटी और क्वान्टिटी अर्थात् योग्यता और संख्या– दो बातें हमारे संविधान में हैं। इन पर गहन विचार और समीक्षा होनी चाहिए। संविधान में संख्या को स्पष्टतः और ज्यादा ध्यान देकर परिभाषित किया गया है, जबकि योग्यता को गौण कर दिया गया है। चुनाव के अलावा भी हमारे संविधान में बहुत कुछ है। मैं यहाँ सिर्फ प्राक्कथन नीतिनिर्देशक तत्त्व अधिकार और नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की बात करना चाहूँगा– ''संविधान की दृष्टि है कि भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में चमके जहाँ हर व्यक्ति को न्याय मिले, वह न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में हो, समानता की भावना का उदय हो, जाति–पाँति के आधार पर कोई बड़ा–छोटा न हो, सभी को उचित अवसर मिले, धार्मिक आधार पर शोषण न हो, धर्म को मानने की आजादी हो, गाँव के आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुँचे, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता हो, पंचायत प्रणाली विकसित हो, एक ही प्रकार की न्यायिक प्रणाली हो तथा साथ ही संविधान अनुच्छेद 51(A) निर्वाह में हरेक नागरिक से अपेक्षा भी रखता है कि वह इन पावन उद्‌देश्यों के लिए तन, मन, धन से लगे, अपनी विरासत सँभाले, पर्यावरण शुद्ध रखे। राष्ट्रीयता ही जिनके केन्द्र में हो।'' एक आम व्यक्ति को संविधान में उपरोक्त बातें मिलती हैं। प्रश्न यह उठता है कि क्या इन महान उद्‌देश्यों और लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए किसी भी हालत में और किसी भी परिस्थिति में चोरों, बदमाशों, बेईमानों, अपराधियों, हत्यारों एवं बलात्कारियों की भी कोई भूमिका हो सकती है? यह यक्षप्रश्न है, इसे अनुत्तरित नहीं रहना चाहिए। एक स्वर में जन–जन से यही आवाज उठेगी– नहीं, कदापि नहीं हो सकती। प्रश्न उठता है, ऐसे में किया क्या जा सकता है? कार्यपालिका की भी अपनी सीमाएँ हैं। अतः टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मीडिया की अपनी भूमिका जनजागरण की है। अतः वह ऐसे विषयों पर जनता को शिक्षित तो कर सकता है, पर उसके पास अन्य अधिकार नहीं हैं। ऐसे में विधायिका अगर शब्दों (कानूनों) की आड़ में संविधान के महान लक्ष्य का उपहास करती है, बड़े–बड़े पाखण्डी नेता जो संसद में तो राष्ट्रप्रेम की बातें करते हैं, पर दुर्दान्त अपराधियों के संरक्षण में हैं। मूलढाँचा–मूलढाँचा चिल्लाकर राष्ट्र की प्रगति को बाधित नहीं किया जा सकता। आज देश परिवर्तन माँगता है। ताकि कोई भी हत्यारा, स्मगलर, चोर, बलात्कारी चुनाव लड़ना तो दूर, इस ओर देखने का साहस भी न कर सके। वोटरों और सांसदों–विधायकों की शैक्षणिक योग्यता से लेकर अन्य ऐसी योग्यताएँ भी हों ताकि प्रत्याशी को इण्डियन पॉलिटिकल सर्विस जैसा लिखित या मौखिक इम्तिहान अवश्य उत्तीर्ण करना पड़े। गलित कुष्ठ की तरह सड़ांध मारती आरक्षण की अवधारणा को प्रशान्त महासागर में डुबो दिया जाए। विशुद्ध योग्यता चाहिए। इस राष्ट्र को (नेतृत्व हेतु) किसी कूड़े–कचरे की जरूरत नहीं। जो मेधावी विद्यार्थी उच्च परीक्षाएँ पास कर सकते हैं, वैसे लोग यदि राजनीति में आ जाएँ, तो कमाल हो सकता है। न्यायपालिका से एक ही अपेक्षा है :–*

जमीन दी है तो थोड़ा सा आसमान भी दे।
नजर जो दी है तो लफ्जों से कोई नाम भी दे॥

हमारे प्रख्यात न्यायमूर्ति इतिहास रचें। इस बार तो शायद कचरा मंत्रिमण्डल हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन 2009 से नये युग की शुरुआत करनी ही होगी।

-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक, पंजाबकेसरी, अप्रैल-2004)

144) *प्रमुख वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, पत्रकारों तथा समाजकर्मियों ने यहाँ (नई दिल्ली में) एक सभा में राजनीतिक दलों पर जनजीवन के महत्त्वपूर्ण मुद्‌दों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए लोगों का आह्‌वान किया कि वे हर चुनावक्षेत्र में राजनीतिक पार्टियों तथा नेताओं से इन मुद्‌दों पर जवाब तलब करें। गैरसरकारी संगठन **'आजादी बचाओ आन्दोलन'** के तत्वावधान में आयोजित इस सभा की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद् प्रो. यशपाल ने सरकारी नीतियों के केन्द्र में जनता को लाने की जरूरत बताते हुए कहा कि इसके लिए स्वयं लोगों को पेशकदमी करनी होगी। उन्होंने कहा कि एक सच्चा लोकतन्त्र तब आएगा, जब चुनावी सभाओं में जनता बोले, नेता सुने। सभा में गरीब बस्ती से आए लोगों ने बताया कि सुरक्षा गार्डों, घर–घर कोरियर पहुँचाने वालों और दुकानों, फैक्ट्रियों में जी–तोड़ काम करने वाले अधिकांश लोगों को आज 2 हजार रुपये महीने से भी कम वेतन मिलता है।*

-(एक समाचार, पंजाबकेसरी, 05/03/2004)

145) *राजनीति की क्या परिभाषा होनी चाहिए, आज की परिस्थितियों को देखकर समझना मुश्किल नहीं–* ***''राजनीति मानवता से अधिक ऐसे लोगों की भीड़ की बकवास है, जिन्हें अपना गिरहबाँ झाँकने में कोई दिलचस्पी नहीं, परन्तु दूसरों के सद्‌गुण भी जिन्हें जहर लगते हैं। अतः यह शाश्वत दुष्टता का ही पर्याय है।''***

''जबकि धर्म का मतलब है– 'धारण करने योग्य'। क्षमा, करुणा, दया, परहित (अर्थात् सत्य, प्रेम, न्याय, पुण्य)– ये सब धारण करने योग्य हैं। अतः जो इन्हें धारण करता है, वह धार्मिक है।''

ऐसे में राजनीति क्या धर्म के साथ रह सकती है? राजनीति सड़े हुए लोगों की दुर्गन्ध है। धर्म स्थितप्रज्ञ महापुरुषों की सुगन्ध है। अतः राजनीति और धर्म का क्या मेल? लेकिन एक तीसरी श्रेणी भी है– बाह्य वेशभूषा से एक व्यक्ति धार्मिक लग रहा है, परन्तु अन्दर ही अन्दर जिसके हृदय में राजनीति ही अठखेलियाँ करती है। मैं ऐसे लोगों को धार्मिक की श्रेणी में नहीं रखता। वे निकृष्टतम हैं, वे रँगे सियार हैं। भगवान कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष ने भी नीतिमर्मज्ञ होने के बावजूद यह कभी नहीं कहा कि मैं हर एक युग में राजनीति की स्थापना करने के लिए आता हूँ। वे कहते हैं, मैं धर्म (न्याय) की स्थापना और दुष्टों के नाश के लिए आता हूँ। जिस दिन राष्ट्र ने भगवान कृष्ण के वचनों का मर्म समझ लिया, धर्म की स्थापना हो जाएगी और साथ ही दुष्टों का नाश भी स्वतः हो जाएगा। भगवान के वचन हैं– ***''धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृताम्।''*** *इसीलिए आज का राजनेता धर्म से घबराया हुआ है। उसे पता है, जिस दिन राष्ट्र 'धर्मप्राण' हुआ राजनेता समाप्त हो जाएगा। उसे ऐसी जगह दफना दिया जाएगा, जहाँ से फिर वह निकलकर न आ सके। इसी डर से उसने एक शब्द गढ़ लिया है– धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ आप स्वयं समझ लें– जो सारे मानवीय गुणों से विमुख हो, उसी को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है।*

-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 05/03/2004)

146) *वस्तुतः नेहरू जी और इन्दिरा जी ने संविधान को वास्तविक प्रजातन्त्र के अनुरूप इसलिए नहीं बनने दिया, क्योंकि उन्हें योग्यता से बड़ी घबराहट होती थी। इन दोनों के प्रबल व्यक्तित्व में एक प्रचण्ड तानाशाह छिपा था।* ***-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 21/02/2004)***

147) *किसको-किसको वोट दूँ :-* *'आया समय बड़ा बेढंगा। आज आदमी बना लफंगा।। इन्हीं की काली करतूतों से बना ये मुल्क मशान। कितना बदल गया इंसान।।' सारे राष्ट्र ने देख लिया है कि किसी के पास कहने को कुछ भी नहीं है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अब वक्त आ गया है कि व्यक्ति को पहचाना जाए। अच्छे, भले, चरित्रवान और बेदाग व्यक्ति को अवश्य जिताएँ। पार्टियों का जमाना तो गया। कैसे सारे योग्य लोग एक ही झण्डे के नीचे आएँ, इसे विचार करने की जरूरत है। इस चेतना को जाग्रत करना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए।* ***-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 02/12/03)***

148) *भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सांसद जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने कहा है कि मानवता को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए* ***'वसुधैव-कुटुम्बकम्'*** *की नीति पर चलना होगा। रुड़की में इण्टरनेशनल गुडविल सोसायटी ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए डाक्टर रंगनाथ मिश्रा ने कहा कि– आज देश में ऐसी संस्थाओं की जरूरत है, जो मानवता की बात करने के साथ ही 'विश्व–बन्धुत्व' एवं आपसी सौहार्द बढ़ाने के प्रति समर्पित हों। अपने सांस्कृतिक एवं धार्मिक मूल्यों से सीखने का आह्वान करते हुए जस्टिस मिश्रा ने कहा कि युद्ध से मानवता को बचाना एवं शान्ति स्थापित करना सभी का दायित्व है। भारत सदैव शान्ति का पक्षधर रहा है एवं भविष्य में भी ऐसे प्रयत्न होने चाहिए।* ***-(एक समाचार : पंजाबकेसरी, दिल्ली, 01/12/03)***

149) *भारतीय राजनीति मात्र तीन सौ परिवारों तक सीमित है। यद्यपि लोकतन्त्र में बादशाहत के लिए कोई जगह नहीं। हर व्यवसाय में डिग्री की जरूरत लेकिन राजनीति ऐसा पेशा है, जहाँ बेटा बड़ी आसानी से बाप की राह को अपना सकता है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से देखा जाए, तो भारत की राजनीति पर पिछले पचपन सालों में तीन सौ परिवारों का ही वर्चस्व रहा है। बेशक यह एक नई बात नहीं है। जवाहर लाल नेहरू से इन्दिरा गाँधी तक, इन्दिरा गाँधी से राजीव गाँधी और राजीव गाँधी से सोनिया गाँधी तक यही स्वतन्त्र भारत की कहानी है।* ***-(वीरजा चौधरी, राजनीतिक संवाददाता : पंजाबकेसरी, दिल्ली, 30/11/03)***

150) भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को जीने की गारण्टी दी गई है, जिसमें आश्रय का हक भी शामिल है। लेकिन संविधान बनने के पचास से ज्यादा वर्ष बीत जाने के बाद भी करीब 6.5 करोड़ भारतीय सड़कों पर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। अकेले दिल्ली में ही लगभग 1 लाख व्यक्ति फुटपाथ और सड़कों पर एवं फ्लाई ओवर के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संयुक्त पुलिस आयुक्त आमोदकण्ठ कहते हैं कि सरकार की आवास नीति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को आवास का हक है। लेकिन अब भी करोड़ों व्यक्ति खुले आसमान के नीचे मौसम की मार झेलकर जीने को मजबूर हैं। मौसम के अनुसार बेघरों की समस्या का जिक्र करते हुए कण्ठ कहते हैं– ठंड में तो उनका बुरा हाल हो जाता है। पिछले साल 3040 शव पाए गए थे। ये मौते ठंड से हुई थीं। 'एक्शन एड इण्डिया' के निदेशक हर्षमंदर कहते हैं– अगर आवास और झुग्गियों की समस्या पर काबू पाना है, तो शहरी योजना हमें गरीबों और बेघरों को केन्द्र में रखकर बनानी होगी। पलायन रोकने पर भी ध्यान देना होगा तथा उन स्थानों पर रोजगार उपलब्ध कराने होंगे, जहाँ काम बन्द हो रहे हैं। राजधानी में बेघरों की दशा और उनके प्रति राज्य प्रशासन की संवेदनहीनता कई बार उजागर की जा चुकी है। **-(एक समाचार : पंजाबकेसरी, दिल्ली, 26/11/03)**

151) **'मेरा भारत भूखा सो रहा, कुछ करना है। हर मोड़ पर बच्चा रो रहा कुछ करना है॥ बहुत बड़ी शक्ति हैं हम जागो तो। भविष्य हमारा खो रहा कुछ करना है॥'** कुछ ही दिन पहले अखबार में एक खबर पढ़ी कि देश के केन्द्रीय राज्यमंत्री ने स्वीकार किया है कि संयुक्तराष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम ने रिपोर्ट में लिखा है कि भारत में तेइस करोड़ लोगों को प्रतिदिन भोजन नहीं मिल पाता। लगभग हर चौथा भारतीय भूखा सोता है। यानि अमरीका की आबादी के बराबर लोग भूखे सोते हैं। आजादी के समय की आधी आबादी का पेट खाली है, कल्याणकारी राज्य में। मेरा 'भूखा भारत महान और फिर नींद नहीं'। कोई अधिक खाकर बीमार और कोई न खाने से बीमार। ज्यादा खाने से बीमार हो रहे लोग और न खाने से कमजोर शरीर वाले बीमार होते फिर मरते लोग। इसमें सम्बन्ध तो कहीं है ही और गहरा सम्बन्ध है। देश के विकास में वृद्धि हो रही है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बढ़ा है। रुपया डालर के मुकाबले मजबूत हो रहा है। देश चहुँमुखी विकास के पथ पर अग्रसर है। इस जी.डी.पी. में टाटा, बिड़ला, अम्बानी सबकी आमदनी जुड़ी है। खेतों में काम कर रहे तीस-चालीस रुपये वाले मजदूरों की भी, और 'मजदूर-हाटों' पर दिनभर बैठकर शाम को खाली वापस लौटने वाले मजदूरों की आमदनी भी। यदि लोग भूखे हैं, तो सबसे आसान है, जनसंख्या को दोष दे दो या कह दो कि लोग निकम्मे हैं, कामचोर हैं। शिवाकासी में जहाँ दुनियाभर के पटाखे बनते हैं, वहाँ बच्चा पाँच-छह साल की उम्र से ही काम करना शुरु कर देता है, तीस-चालीस की उम्र तक खाँसते-खाँसते पस्त हो जाता है कि काम लायक नहीं बचता। तो बच्चे तो ढेर चाहिएँ, जो कमाकर दे सकें। अब इनका जोड़ बिठा लिया जाए, दुनियाभर का पैसा एक छोटे समूह के पास है। उन्होंने पैसे के बल पर संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। क्योंकि सबकुछ उनके पास है। इसलिए बहुसंख्य उनका अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम है। बहुत सीधा गणित है। जब सबकुछ उनके पास है, तो दानधर्म करके धर्मात्मा भी वे ही बनते हैं। बीमारी बढ़ने का मतलब है– दवा कम्पनी का विकास, उत्पादन में वृद्धि, जी.डी.पी. में वृद्धि, परन्तु भूख बनाए रखो। **'इक सर्प निगल रहा है, मेरे भारत की सन्तानों को। कोई और लूट रहा है, यहाँ दबे खजानों को॥'** **-(संजीवकौरा, लाइटहाउस : पंजाबकेसरी, दिल्ली, 25/11/03)**

152) लोग उंगली उठाएँगे हमारी आपराधिक तटस्थता पर और इतिहास पूछेगा– ''संसदीय प्रजातन्त्र की आड़ में कुछ लोगों ने राष्ट्र को लूटकर खोखला कर दिया और सारा भारत सोया रहा।'' तो हमारा क्या जबाव होगा ? शायद हमारा जबाव कुछ न हो। हम भी एक इतिहास बन चुके होंगे तब तक शायद। डाक्टर बशीरबद्र ने सचमुच बड़ी हिम्मत जुटायी होगी, तब काँग्रेस ने 1984 में राष्ट्रव्यापी दंगे करवाए और उन्होंने काँग्रेसी नेताओं से एक मुशायरे में पूछा :–

तू इधर-उधर की न बात कर, ये बता कि कारवाँ क्यों लुटा।
हमें रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है॥

काँग्रेसी नेताओं ने जबाव क्या देना था ? बस दिन में बगलें झाँकने लगे। वक्त के शायर ने राज खोला :–

मैं बताऊँ कारवाँ क्यों लुटा, तेरा रहजनों से था वास्ता।
मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे मलाल है॥

शायद शायर ही पूछ सकता है– ऐसे सवाल इन राजनीतिज्ञों से। उसकी कलम को खुदा ने शफा बख्शी है। 'दिनकर' जैसा कवि ही इस भाषा में डाँट सकता है :–

समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध।
जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध।।

आज प्रजातन्त्र बचा कहाँ कि प्रजा की कोई सुने ? पहले ये प्रजातन्त्र से भीड़तन्त्र बना, भीड़तन्त्र से भेड़तन्त्र बना और अब यह भेड़तन्त्र से अपराधतन्त्र हो गया है। काश आज भारत में अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की समझ का कोई व्यक्ति होता और उसने आज के प्रजातन्त्र की नग्नता देखी होती, तो कहने पर मजबूर हो जाता– India's democracy is government of the criminals for the criminals and by the criminals. भारत की लोकतान्त्रिक सरकार यानि अपराधियों की अपराधियों द्वारा और अपराधियों के लिए। हो सकता है कुछ ड्राइंगरूम के वीर, जो दिन–रात अपने वातानुकूलित कमरों में बैठकर बेलगाम कलम से शब्दों के बलात्कार द्वारा उत्पन्न नपुंसक क्रान्ति से युगपरिवर्तन के दिवास्वप्न देखा करते हैं। उन्हें उपरोक्त परिभाषा अच्छी न लगे। परन्तु आज भी मैं बिहार, उत्तरप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा और बंगाल के हजारों वोटिंग बूथ ऐसे दिखला सकता हूँ, जहाँ जनता वोट नहीं देती। जनता के वोट नहीं देने से मेरा आशय यह नहीं कि वहाँ वोट पड़ते नहीं। वोट पड़ते हैं और खूब पड़ते हैं, लेकिन खूँखार अपराधियों के हुक्मनामे लोगों को जारी होते हैं कि खबरदार कोई वोट न दे! अपराधी वोट देते हैं, अपराधी जीतते हैं, और जीतने पर सरकार में शामिल होते हैं और अपराधियों का उस सरकार को संरक्षण होता है। अब आप समझे, यह हैं हमारा लोकतन्त्र और ऐसी हैं हमारी सरकारें। है किसी में हिम्मत जो झुठलाए इन तथ्यों को। ***–(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 24/11/2003)***

153) *असम में खून की होली खेलने के पीछे कौन ? – पूर्वोत्तर भारत में हिन्दीभाषियों के खिलाफ जो अभियान शुरु हुआ, उसकी पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालना भी जरूरी है। भारतीय रेलवे में 1982 से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती बन्द है तथा इस समय डेढ़ लाख पद रिक्त हैं। यही लोग रेलपटरियों की देखभाल करते हैं। पटरी की समुचित देखभाल न होने के कारण जब दुर्घटनाओं की बाढ़ आयी तो रेलबोर्ड की नींद टूटी। रेलबोर्ड ने गतवर्ष 32 हजार चतुर्थ श्रेणी के नये कर्मचारी भर्ती करने का फैसला किया। कहा जाता है कि इन पदों के लिए 80 लाख बेरोजगारों ने प्रार्थनापत्र दिए। उम्मीदवारों में लाखों स्नात्कोत्तर, इंजीनियर, एम.बी.ए. आदि उच्चशिक्षा प्राप्त बेरोजगार भी थे। हालाँकि रेलवे की चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के लिए आठवीं कक्षा पास होना ही काफी है। मगर वर्षों से बेरोजगारी का अभिशाप झेल रहे उम्मीदवार चतुर्थ श्रेणी की नौकरियाँ करने के लिए ही बेकरार थे। कहा जाता है कि इन 80 लाख प्रार्थनापत्रों की जाँच करने के बाद रेल विभाग ने 55 लाख उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देने के लिए छाँटा। देशभर में 52 परीक्षाकेन्द्र बनाए गए। इनमें से एक परीक्षाकेन्द्र असम के प्रमुखनगर गोवाहाटी में भी था। रेलवे एक्ट की धारा 16 के तहत एवं उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार रेलवे की नौकरियाँ सभी देशवासियों के लिए खुली हुई हैं। इसलिए गोवाहाटी में परीक्षा देने के लिए कई बिहारी उम्मीदवार भी पहुँचे। कहा जाता है कि कुछ असमी नेताओं ने इन बिहारी उम्मीदवारों को परीक्षा देने से जबरन रोका। इसी सिलसिले में कुछ महिलाओं से मारपीट भी हुई। इसके बाद बिहार से पूर्वोत्तर जाने वाली और वहाँ से दिल्ली जाने वाली विभिन्न रेलगाड़ियों पर हमलों का सिलसिला शुरु हो गया। इन गाड़ियों के रेल के डिब्बों से असमी यात्रियों को चुन–चुन कर हुल्लड़बाजों ने घसीटकर बाहर निकाला और उनसे डटकर मारपीट हुई और उनका सामान लूट लिया गया। इसके अतिरिक्त महिलाओं के साथ सरेआम बलात्कार की भी घटनाएँ हुईं। हैरानी की बात है कि बिहार पुलिस ने इनमें से एक भी वारदात की एफ.आई.आर. दर्ज करने की जरूरत नहीं समझी। जब इन लज्जाजनक घटनाओं की खबर असम में पहुँची तो वहाँ इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। दंगाइयों ने बिहारियों और अन्य हिन्दीभाषी लोगों के घरों और दुकानों पर हमले शुरु कर दिए। पुलिस की मौजूदगी में निर्दोषों की हत्याएँ कह गईं।* ***–(मनमोहन शर्मा, स्तम्भकार, दिल्लीदरबार, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 24/11/03)***

154) हम करें राष्ट्र आराधन :- भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग ने कुछ चौंकाने वाले आँकड़े प्रस्तुत किए हैं। इसके मुताबिक 'भारतवर्ष में हर 10 मिनट में एक दहेजहत्या हो जाती है। हर 4 मिनट पर एक अपहरण, हर 54 मिनट पर एक बलात्कार और हर 26 मिनट पर एक छेड़खानी की घटना दर्ज की जाती है।' उपरोक्त आँकड़ों का आधार वे सूचनाएँ या शिकायतें हैं, जो थानों में प्राथमिकी के रूप में या न्यायिक दण्डाधिकारियों के समक्ष दर्ज होती हैं। जबकि वास्तविक स्थिति कितनी भयावह होगी, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। ऐसी खबरें मैं जब कभी पढ़ता हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा दुःख और आक्रोश किसके लिए महसूस होता है, उसे जानकर शायद आप चौंकें, परन्तु इसे लिखना तो होगा ही :–

क) सबसे ज्यादा कोफ्त मैं उन पाखण्डी नेताओं से महसूस करता हूँ जिनको नारी गरिमा से कुछ लेना–देना नहीं।

ख) उसके बाद मेरी दृष्टि उन महात्माओं पर वक्र होती है, टेलीविजन पर जिनकी गिनती कुकुरमुत्तों की तरह बढ़ती चली जा रही है। आज चार राज्यों के चुनाव होने बाकी हैं। हर पार्टी के नेता सिंहगर्जना कर रहे हैं। किसी के पास भी सिवा एक–दूसरे की निन्दा के एक भी सकारात्मक मुद्दा नहीं है। अगर कोई हाई–फाई बलात्कार का मामला होता, शायद वह भी उछल रहा होता। परन्तु अगर ये आँकड़े सच हैं, तो राष्ट्रीय शर्म की बात है। अगर सारे जहाँ से अच्छा यह हिन्दोस्ताँ है हमारा और इसका यह हाल है, तो यह सारे जहाँ से थोड़ा भी खराब होता, तो इसकी क्या स्थिति रहती, आप समझ सकते हैं। यह जो हर चैनल पर नये–नये गाडमेन और गाडेसेस यानि स्वामी जी, महाराज जी और साध्वियाँ प्रवचन देते हैं। ज्यादातर इनमें से विशुद्ध व्यापारी हैं। ऐसा मैं महसूस करता हूँ। ये पेट के विकारों पर काम आने वाले चूर्ण से लेकर महायोगराज गुग्गुल, हाथीछाप अगरबत्ती और केशनिखार तेल तक बेच रहे हैं। किसी की कोई सामाजिक प्रतिबद्धता नहीं। मैं ऐसे तथाकथित गुरुओं के कई चेलों से मिला हूँ। वह अपने गुरुजी की फोटो दिखाकर बड़ी शान से कहते हैं– यह देखिए, यह फलाने मन्त्री उनकी आराधना कर रहे हैं! फलाने मन्त्री उनकी चरणवन्दना कर रहे हैं!

जो साधु राजनीतिज्ञों के सहारे स्वयं को महान सिद्ध करना चाहता है, उससे सावधान रहने की जरूरत है। राजनेताओं की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि साधु दस नम्बरी है। उसकी परछाई से भी बचा जाना चाहिए। इन राजनेताओं का धर्म से क्या लेना–देना। यह तो स्वयं समाज की कोढ़ हैं। ऐसे लोग क्या करेंगे, नारी मर्यादा की रक्षा। **-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 23/11/2003)**

155) अमीर और गरीब बचपन के बीच की दूरियाँ बढ़ रही है, जिससे भावी दुनिया की भयावह तस्वीर उभर रही है। सारे विकास और समृद्धि के बावजूद दुनिया पहले से बेहतर नहीं बन रही है। बल्कि यह सामाजिक, राजनीतिक असन्तोष के ज्वालामुखी पर बैठी है, जो कभी भी फट सकता है। आर्थिक गैरबराबरी (असमानता) और संसाधनों का अन्यायसंगत बँटवारा आज इतना भीषण बन गया है कि मानवता के भविष्य पर ही खतरा पैदा हो गया है। हम किन बच्चों के सरोकार की चर्चा कर रहे हैं। उन कुछ बच्चों की जो सर्वसुविधासम्पन्न विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं या उन बच्चों की जो बिना भवन, बिना सुविधा के घटिया शिक्षा हासिल कर रहे हैं। आज छह में एक बच्चा अच्छी शिक्षा हासिल कर रहा है जबकि छह में से पाँच बच्चे बुनियादी सुविधाओं के अभावा से जूझ रहे हैं। यह एक भयावह स्थिति होगी कि पाँच अभावग्रस्त बच्चे एक भाग्यशाली बच्चे के खिलाफ खड़े हो जाएँगे। यह स्थिति दुनिया में विनाशकारी राजनीतिक सामाजिक परिणाम सामने लाएगी। (तत्कालीन मानवसंसाधनविकास मन्त्री के रूप में नई दिल्ली में अध्यापकों शिक्षाविदों और छात्रों को सम्बोधन एवं दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारा बच्चों के सरोकार विषय पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया गया वक्तव्य।)

-(मुरलीमनोहरजोशी, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 23/11/2003)

156) एक तरफ (संविधान में) प्राक्कथन से लेकर नीतिनिर्देशकतत्त्व, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य चीख–चीखकर कहते हैं, सारे भारतीय एक समान हैं। दूसरी तरफ आदिवासी, मूलवासी, अगड़े, पिछड़े, अनुसूचित, बैकवर्ड, जनजाति आदि के नाम पर राजनेताओं ने वोटों के चक्कर में भारत की महान विरासत अनेकता में एकता को छिन्न–भिन्न कर दिया, आरक्षण के विषबीज बो दिए, क्षेत्रीयता को आसमान पर चढ़ा दिया, योग्यता को ताक पर रख दिया। चुनावी क्षेत्रों को जाति के आधार पर बाँट दिया और अब जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में क्षेत्रीय आधार पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, तो

रेलवे की चतुर्थ श्रेणियों की नौकरियों के लिए यदि पूर्वोत्तर राज्यों में बिहारी बन्धु भी भाग्य आजमाना चाहें और आँख की किरकिरी बन जाएँ, यह कहाँ तक जायज है? इस राष्ट्र ने अगर अपनी विरासत से छेड़-छाड़ न की होती, तो ऐसी समस्याएँ कभी भी पैदा न होतीं। भगवान कृष्ण के वचन हैं-**'चारों वर्ण मेरी ही सृष्टि हैं। मैंने उन्हें गुणों-कर्मों के द्वार विभक्त किया है।'** काश! इस राष्ट्र में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की वैज्ञानिकता को सही परिदृश्य में समझा गया होता। काश! गुणों और कर्मों के विभाजन पर तथ्यपरक दृष्टि डाली गई होती। शास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं। बात योग्यता की है। काश! हमारे संविधानविदों ने गणतन्त्र को ही आधार बनाकर राष्ट्र की रूपरेखा बनाई होती, तो राष्ट्र में समदर्शिता का उदय होता। हमारे भारतवासी एक हैं, एक ही माटी के बेटे हैं, हम सब धरतीपुत्र हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के बृहद गुलदस्ते के हम विभिन्न रंगरूपों में खिले फूल हैं। हमें जाति-पाति की संकीर्णता से ऊपर उठना होगा। आओ एक नई शुरुआत करें। 'खून से तरबतर, करके हर रहगुजर, थक गए जानवर, जो हुआ सो हुआ।' **-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक, पंजाबकेसरी, 22/11/03)**

157) देश को आजाद हुए आधी शताब्दी बीत चुकी है। हमारे साथ आजाद हुए छोटे-छोटे देश प्रगति की दौड़ में हमसे आगे निकल चुके हैं। लेकिन हम आज भी जातिवाद, साम्प्रदायिकता (पंथवाद) और क्षेत्रवाद में ही उलझे हुए हैं। आज भूख, गरीबी, सामाजिक अन्याय, राजनीतिक के अपराधीकरण तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि मजहब, साम्प्रदायिकता (पंथभेद), अगड़ावर्ग, पिछड़ावर्ग जैसे निरर्थक मुद्दों को उछाला जा रहा है। सत्ताधारी और विपक्ष दोनों ही इनसे लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि देश पुनः क्षेत्रवाद व प्रान्तवाद की संकुचित भावना से घिरता जा रहा है और यह हिंसक टकराव का रूप लेता जा रहा है। भारत से जो लोग विदेशों में गए हैं, वहाँ वे सांसद, विधायक, प्रीमियर आदि बने हैं तथा औद्योगिक व व्यावसायिक जगत में भी शीर्ष पर पहुँच गए हैं। लेकिन वहाँ उनके प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना की खबरें सुनने को नहीं मिलतीं। संचार और परिवहन साधनों के विस्तार ने आज दुनिया को एक वैश्विक गाँव में परिवर्तित कर दिया है और यूरोपीय यूनियन जैसे संगठनों के देश एक-दूसरे के नागरिकों के लिए अपने यहाँ रोजगार के दरवाजे खोल रहे हैं। लेकिन यह सोचकर दुःख होता है कि हम आज भी संकुचित मनोवृत्तियों के कारण जातिवाद, प्रान्तवाद की भावनाओं में जकड़े हुए हैं और इनसे उबर नहीं पा रहे तथा अपने ही देश की एक भाग में दूसरे भाग के लोगों को सहन करने को तैयार नहीं हैं। **-(विजय, सम्पादक, पंजाबकेसरी, 21/11/2003)**

158) धर्मो रक्षति रक्षितः :- राजनीतिज्ञों को भी नैतिकता की बात करने का अधिकार है क्या? मैं अपवादों की बात नहीं करता। चन्द लोग अपवाद हो सकते हैं। लेकिन नेताओं से ज्यादा मेरा अभियोग दिल्ली पर है। दिल्ली सच नहीं जानती। दिल्ली सच से कोसों दूर है। दिल्ली षड़यन्त्र रचती है। दिल्ली दिलवालों की नहीं रही। दिल्ली क्या जाने छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों की व्यथा? दिल्ली क्या जाने आदिवासी वीरपुत्रों की गाथा? इसीलिए 'दिनकर' ने दिल्ली को कोसते हुए कहा था :-

तू न ऐंठ मदमाती दिल्ली, मत फिर यूँ इतराती दिल्ली।।
अविदित नहीं हमें तेरी, कितनी कठोर है छाती दिल्ली।।
हाय! छिनी भूखों की रोटी, अर्धनग्न का छिना वसन है।
मजदूरों के कौर छिने हैं, जिन पर उनका लगा दसन है।।
-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक, पंजाबकेसरी, 21/11/2003)

159) मैं जब पाँचवी कक्षा का विद्यार्थी था, तो भारत के बारे में उसमें एक कविता पढ़ता था। आज एकाध पद ही स्मरण रह गया है :-

यहाँ देवता भी तन धरकर आने को ललचाते।
धन्य भाग हम यहाँ जन्म ले पढ़ते-लिखते गाते।।
यहाँ न टिकता पाप देर तक, पुण्य कभी न हारा।
यह भारत देश हमारा, यह भारत देश हमारा।।

भारत पर हमें गर्व होना ही चाहिए। परन्तु भारत में ही जगदलपुर, बस्तर, जसपुर, सरगुजा आदि ऐसे इलाके हैं, जहाँ के कुछ रहने वाले शायद आपको पाषाणयुग की याद दिला दें। करीब-करीब पूर्णतः नग्न और

पत्थरों के औजारों से आज भी शिकार करने वाले लोग हैं। कोई आँख यहाँ नम हुए बिना नहीं रहती। बड़े से बड़ा कठोर दिल भी पिघल जाएगा। उसकी आत्मा काँप उठेगी। आज उस इलाके में बड़े-बड़े पोस्टर लगे हैं। हेमा, जूही, प्रीतीजिन्टा और स्मृतिमल्होत्रा उर्फ तुलसी का शीघ्र ही शुभागमन! क्या मैं पूछ सकता हूँ- इनकी वहाँ क्या प्रासंगिकता ? क्या सम्बन्धित पार्टियाँ अपना आत्मनिरीक्षण करेंगी ? इन फिल्मी कलाकारों को ले जाना प्रत्यक्ष या परोक्ष एक भावनात्मक शोषण है। और इस शोषण की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण में एक प्रत्याशी ने कहा- कि वह आगामी चुनाव में कैबरे डांसरों की मदद से चुनाव जीतकर दिखाएँगे। न जाने आज हम किस मुकाम से गुजर रहे हैं, जहाँ सच कोई बोलना नहीं चाहता, सच कोई सुनना नहीं चाहता। आप कल्पना करें कि सात दिनों से भूखे-प्यासे किसी व्यक्ति के सामने नाचती प्रीतीजिन्टा और हाथ में पंजे या कमल की तस्वीर। कब होश आएगा इस मुल्क को ? ***-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक, पंजाबकेसरी, 20/11/2003)***

160) *पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जिस भावना से लागू किया गया था, वह भावना राजनीति के चलते समाप्त हो गई है। कुछ दबंग एवं पहले से ही आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सम्पन्न वर्ग विभिन्न राजनीतिक दलों पर अपना दबाव बनाकर अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची में अपने आप को शामिल कराने में कामयाब हो गए। इन सम्पन्न वर्गों के लोग कई राज्यों के मुख्यमन्त्री, केन्द्रीय मन्त्री एवं बड़े-बड़े सरकारी ओहदों पर विराजमान हैं। जिस वर्ग के प्रधानमन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री भी बन चुके हैं, वे भी आज वोट की राजनीति के चलते पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल कर लिए गए हैं। अतः दिल्ली व कई राज्यों व केन्द्र में भी एक सम्पन्न वर्ग ही सम्पूर्ण आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं तथा वास्तविक पिछड़े वर्ग आज भी हाशिए पर खड़े हैं।*

-(प्रदीपकुमार, शीदीपुरा, करोलबाग, नई दिल्ली, पंजाबकेसरी, 19/11/2003)

161) *है कोई जबाव सरकार के पास ? आतंकवाद, बेरोजगारी, शोषण, भ्रष्टाचार, नेताओं का गिरता स्तर, सरकार की विफलता आदि को लेकर सरकार हर मोर्चे पर पिछले कई दशक से असफल हो रही है। भ्रष्ट और आपराधिक छवि वाले लोग हमारी राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। वे राजनीति में आकर हमारे भाग्यविधाता बने हुए हैं। आपराधिक और भ्रष्ट नेता ही उपरोक्त विषय का कारण हैं। इन लोगों को कैसे राजनीति से दूर रखा जाए ? आतंकवाद का मुख्य कारण है- बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शोषण, अयोग्य नेता। हर समस्या का हल होता है। पर ये बेईमान, भ्रष्ट, राक्षस, देशद्रोही, अयोग्य नेताओं के बस की बात नहीं है। ये शराब में लिप्त रहने वाले नेता क्या जानते हैं कि देश का किसान और मजदूर कैसे जीवन बिता रहा है।* ***-(राजू, आवाज-ए-खबरदार, पंजाबकेसरी, 18/11/2003)***

162) *राजनीति बहुत गन्दी हो गई है और उसकी अपनी सीमाएँ हैं। मुझ जैसा व्यक्ति उसके लिए मिसफिट है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में छात्रों और शिक्षकों के साथ लम्बे संवाद में मुझे लगा कि छात्रों को राजनेता शब्द से घृणा हो गई है। छात्रों के मन में ढेर सारे सवाल हैं। वे जानना चाहते हैं कि राजनेताओं को इतने ऐशोआराम कहाँ से मिल रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे मेरे खर्च और आमदनी के बारे में भी अनेक सवाल किए। देश और जनता की सेवा करने के लिए केवल राजनीति ही एकमात्र माध्यम नहीं है। मैंने भी इस देश की सेवा करने के लिए गैर राजनीतिक रास्ता अख्तियार किया है। मौजूदा दौर में राजनीति जनसेवा की राह से भटक गई है। यह मूल्यों की ओर केन्द्रित होने की बजाय सत्ता के आवाजाही के खेल में तब्दील हो गई है। राजनेता सत्तालोलुप और राजनीति आम आदमी के हितसाधन से दूर है। समाज की नहीं देश के लिए भी यह खतरनाक स्थिति है। राजनीति के संकीर्ण दायरे से ऊपर बृहद् पैमाने पर काम करने के लिए मैंने गैरराजनीतिक रास्ता अख्तियार किया है।* ***-(गोविन्दाचार्य, पंजाबकेसरी, 14/11/2003)***

163) *अनिवासी भारतीयों का एक समूह भारत आया। कुछ नेता उनसे मिले और उनसे राष्ट्रहित में यहाँ पूँजीनिवेश करने का आग्रह किया। अनिवासी भारतीयों ने तुरन्त लाखों डालर स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय खोलने के लिए दान कर दिए। भविष्य में भी इसी तरह और धनराशि भेजने का वायदा किया। अब वे राष्ट्रपिता महात्मागाँधी को श्रद्धान्जलि अर्पित करने हेतु रवाना हुए। गाँधीजी की मूर्ति के सम्मुख पहुँचकर ज्यों ही उन्होंने शीश नवाए, गाँधीजी की मूर्ति की आँखों से आँसू टपकने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था- गाँधी जी रो क्यों रहे हैं ? तभी किसी को ध्यान आयाा कि कुछ लोग दिवंगत आत्माओं का आवाहन*

कर उनसे बात करवाते हैं। उनसे सम्पर्क कर गाँधी जी की आत्मा का आवाहन किया गया। गाँधी जी की आत्मा पहली पुकार में ही आ गई। अनिवासी भारतीय आगे बढ़े और उनसे रोने का कारण पूछा। गाँधी जी ने आह्लादित स्वर में कहा–''**मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि विदेशों में रहते हुए भी तुम सब अपने राष्ट्र को भूले नहीं।**'' अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई यहाँ देशहित में निःस्वार्थ भाव से दान कर रहे हो। गाँधी जी के मुख से अपने लिए ऐसे प्रशंसात्मक उद्गार सुनकर समस्त अनिवासी भारतीय गदगद होकर विदा हुए। अब नेतागण आए। उन नेताओं के आते ही गाँधी जी जोर–जोर से रोने लगे। ऐसा लगता था, जैसे नेताओं को देखकर गाँधी जी को अपार कष्ट हो रहा हो। पूछने पर वे हाय–हाय करने लगे और बोले–''**इन अनिवासियों से कुछ तो सीख लो। ये अपनी तिजोरी का धन देशसेवा के लिए दे रहे हैं और तुम लोग देशसेवा के धन से अपनी तिजोरी भर रहे हो!**'' गाँधी जी की ऐसी फटकार सुनते ही वे नेतागण भाग खड़े हुए। गाँधी जी का यह न्याय देखकर जनता खुशी से नाचने लगी। जय–जयकार करती हुई जनता मूर्ति के सामने आयी तो गाँधी जी पुनः रोने लगे। इस बार उनका रुदन कुछ इस ढंग का था, जैसे वह रोते हुए अपने समक्ष खड़े लोगों पर खीझ रहे हों। हैरान जनता ने कारण पूछा तो गाँधी जी ने ठंडी साँस ली और बोले–''**क्या इसी दिन के लिए आजादी के दीवानों ने कुर्बानियाँ दी थीं कि तुम विदेशी लुटेरे के हाथों से निकलकर देशी लुटेरों के हाथों में फँस जाओ!**'' ''लेकिन बापू! हम क्या कर सकते हैं''– जनता ने अपनी मजबूरी जताई। इस पर गाँधी जी बोले– ''अरे! सबकुछ जो तुम्हारे हाथों में हमने सौंपा है।'' गाँधी जी ने जनता की अक्ल पर तरस खाया और बोले–''**मेरे पास तो कोई साधन नहीं था फिर भी मैंने विदेशी लुटेरों को भगा दिया। तुम्हारे हाथों में तो वोट का हथियार है। तुम बजाय इन लुटेरों से पीछा छुड़ाने के वापस इन्हीं को चुन लेते हो और फिर मुझे दोष देते हो कि मजबूरी का नाम महात्मा गाँधी !**''

-(व्यंगकथा : प्रकाश माहेश्वरी, खण्डवा, पंजाबकेसरी, 14/11/2003)

164) झूठे प्रजातन्त्र की सच्ची दास्ताँ (4) :- आज हमारे प्रजातन्त्र का स्तर इस कदर गिर चुका है जहाँ बड़े–बड़े घोटालेबाज न केवल सांसद बनकर प्रजातन्त्र की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि दूसरे देशों में एक माडल के रूप में भेजे जाते हैं। एक बार जो गद्दीनशीं हो गया, उसे यह मर्ज कैंसर की तरह लग जाता है। इस राजनीति में कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। योग्यता का इस विधायिका में कोई स्थान नहीं है। जब तक किसी को सुप्रीमकोर्ट से अन्तिम रूप से सजा नहीं मिल जाती, वह निर्दोष है। कानून की धीमी गति तो आप समझते ही हैं। फिर वोट कैसे प्राप्त होती है, जान लें! बड़े से बड़े अपराधी की प्रासंगिकता क्यों है, इसे भी पहचान लें! पिछले चुनाव में बाँदा क्षेत्र में एक पोस्टर लगा था–'**मोहर लगेगी हाथी पर, नहीं तो गोली लगेगी छाती पर, लाश मिलेगी घाटी पर।**'

-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 06/11/2003)

165) झूठे प्रजातन्त्र की सच्ची दास्ताँ (2) :- मुझसे कई लोग प्रश्न करते हैं– आज के परिप्रेक्ष्य में। जब चारों तरफ ह्रास होता जा रहा है, हम राष्ट्र के पुनर्निर्माण का कार्य कहाँ से प्रारम्भ करें। मेरा एक ही जबाव होता है– क्रान्तिकारियों से किए गए दुर्व्यवहार के लिए हमें क्षमा माँगनी होगी। जिन स्वतन्त्रता सेनानियों ने 1947 से पूर्व स्वतन्त्रता समर में भाग लिया, वे कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। किन्तु हजारों शहीद ऐसे थे, जो गुमनाम रह गए। जनता उनका इतिहास जाने। उनके सामने पश्चाताप किया जाए कि– ''हम शपथ लेते हैं कि भारत को इसका वह गौरव प्रदान करने की हर संभव कोशिश करेंगे, जो गौरव हमारी वैदिक परम्परा में वर्णित है। हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करेंगे। हम हर अपराधी को उसका उचित स्थान जेल (कारागृह) में दिलाएँगे। कोई चोर–उचक्का संसद या विधानसभा तक पहुँचने की कल्पना नहीं कर सकेगा। हमें स्वतन्त्रता सेनानी के चरणरज की कसम है, हम निष्ठापूर्वक कर्तव्यपथ की ओर बढ़ेंगे। वास्तविक स्वतन्त्रता सेनानियों को इससे ज्यादा खुशी क्या होगी! उन्हें लगेगा कि उनकी मेहनत बेकार नहीं गई। अभी हाल ही की बात है, आजाद हिन्द फौज के सेनानियों का दिल्ली में सम्मान किया गया। इनमें से कुछ लोगों ने जब अपने उद्गार प्रकट किए, तो लगा, ये किसी शाश्वत सत्य का उद्घोष कर रहे हैं। एक व्यक्ति तो इतने भावुक थे कि आज के नेताओं को कोसते हुए बोले–''**इनसे तो अच्छे अँग्रेज ही थे। उनका कोई चरित्र तो था। ये जो आज के नेता हैं, चरित्र किसे कहते हैं, इसकी दूर-दूर तक इन्हें समझ नहीं है। ये तो इंसानों के वेश में शैतान लगते हैं। भगवान राष्ट्र की दुर्गति से पहले हमें उठा लो।**'' ये बोल स्वतन्त्रता सेनानियों के हैं। क्या भारतवर्ष में इन बोलों की कद्र की गई ?

-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 04/11/2003)

166) भारत में संविधान तो रचा गया, सब कुछ बड़ी सावधानी से हुआ, लेकिन एक सबसे बड़ी भूल जाने-अनजाने वह कर गए। हमारे संविधानविदों ने बड़े प्रजातन्त्रों की नकल कर ली। जब विधायकों की योग्यता का प्रश्न आया तो बस इतना ही कहा गया कि उसे बालिग होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, विक्षिप्त नहीं होना चाहिए आदि। ऐसी ही योग्यता उन्होंने सांसदों के लिए रख दी। एक तरफ शैक्षणिक योग्यता की कोई बात नहीं थी और दूसरी तरफ इस बात की तो कल्पना भी नहीं की थी कि एक दुर्दान्त से दुर्दान्त अपराधी भी उपरोक्त योग्यताएँ रखता है। एक स्मगलर या देशद्रोही भी भारत का नागरिक हो सकता है। वयस्क की परिभाषा पहले 21 वर्ष उम्र की गई। बाद में इसे 18 वर्ष कर दिया गया। इनसे किन कामों की अपेक्षा की गई आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे। संसद में दो-तिहाई लोग अगर चाहें तो मिलकर देश का कानून बना सकते हैं। ऐसा कानून जो सुप्रीम कोर्ट को भी मंजूर करना होगा।

एक दक्षिणभारतीय प्रोफेसर के उद्‌गार जो उन्होंने 1952 में व्यक्त किए, उनको मैंने पहले भी लिखा था। वह सज्जन मद्रास के रहने वाले थे। अँग्रेजी के प्राध्यापक और 1952 में ही रिटायर हुए थे। उस समय पहली संसद का गठन होना था। वह चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने संविधान का अध्ययन भी किया था। उन्होंने अपने उद्‌गार प्रकट किए- ''मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूँ और राष्ट्रसेवा में अपनी भूमिका अदा करूँ। सेवानिवृत्ति के बाद मैंने संविधान का अध्ययन किया तो पाया कि सांसदों को कानून बनाने का भी अधिकार है। मैं कानून का कभी विद्यार्थी नहीं रहा। मुझे इसका कुछ भी पता नहीं था। अतः मैंने चुनाव लड़ना एक अनैतिक कृत्य समझा।''

-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 22/10/03)

167) एक कहावत है कि एक मछली सारे तालाब को खराब कर देती है। यदि नेता भ्रष्ट हो, तो सारा समाज ही भ्रष्ट हो जाए, तो कोई अचम्भा नहीं। वैसे भी पानी ऊपर से नीचे को ही जाता है, नीचे से ऊपर को नहीं। अतः नेता को सच्चरित्रवान होना अत्यन्त आवश्यक है। जनता में सभी तरह के लोग हैं और यह एक वृहद् नाम है, जिसे एक साथ सुधारना कभी संभव नहीं हुआ है और न होगा। उदाहरण नेताओं का ही होता है, जनता का नहीं। भ्रष्टाचार विषबेल है, जो नेताओं में फल-फूल रही है, जिसके कारण जनता भी भ्रष्ट होती जा रही है, जिस पर अंकुश लगाना जरूरी है। यह तभी संभव होगा, जब लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता हमारा नेतृत्व करें। तभी उल्टी गंगा बहनी बन्द होगी।

-(धेवरचन्दगोदीका, आवाज-ए-ख़बरदार, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 21/10/2003)

168) हमारा प्रजातन्त्र : कौन सी प्रणाली सर्वोत्कृष्ट (2) :- आइए एक झलक देखें कि हमारे संविधान के नीतिनिर्देशक सिद्धान्तों में क्या है :-

क) राज्यों को एक ऐसे कल्याणकारी प्रदेशों का दर्जा दिया जाए, जो सर्वकल्याणकारी है।

ख) सभी स्त्री पुरुषों को समान आजीविका (रोजगार) का अधिकार हो, कोई भेदभाव न हो।

ग) आर्थिक ढाँचा इस तरह से निर्मित हो कि पूँजी केवल कुछ ऐसे लोगों के हाथों में सीमित न हो जाए, जो जब चाहें बाजार का संतुलन बिगाड़ सकें।

घ) समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान हो।

ङ) राष्ट्र के बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए।

च) सभी स्त्रियों को समुचित इलाज की सुविधा हो।

छ) सत्ता का विकेन्द्रीकरण पंचायत स्तर तक हो और पंचायतें अच्छी तरह विधिसम्मत कार्य करें

ज) उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी हो।

झ) सामान्य नागरिक संहिता बने।

ट) कृषि और पशुसंरक्षण पूरी क्षमता से हो।

ठ) न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग-अलग कार्य करें।

ड) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए सरकार सतत् प्रयासरत हो।

आप उपरोक्त एक-एक विन्दु पर विचार करेंगे, तो आपको इस बात की अनुभूति होगी कि इन तत्त्वों में सचमुच केवल नीति ही नहीं, नैतिकता भी है। मुझे महात्मा गाँधी की एक उक्ति याद आती है। उन्होंने कहा था- ''तुम अगर कुछ सामाजिक कार्य करने जा रहे हो, तो सबसे पहले तुम्हारे मस्तिष्क में

यह बात कौंधनी चाहिए कि तुम्हारे कार्य से समाज के आखिरी मनुष्य को क्या फायदा मिलेगा ? अगर उससे उसको फायदा मिलता है, तो समझो तुम्हारा कार्य एक नैतिक कार्य है।'' संविधान के नीतिनिर्देशकतत्त्वों में गाँव की सोंधी मिट्टी की महक है। आखिरी आदमी के साथ तक अन्याय न हो। इसमें उसके लिए प्रावध ाान है। वह शिक्षित व स्वस्थ हो। हमारी कृषि उन्नत हो। उद्योग मनुष्य को स्वावलम्बी बनाए। एक जैसा कानून हो। रोजगार के समान अवसर हों। क्या नहीं है इन तत्त्वों में।

न्यायप्रणाली में प्राकृतिक न्याय का स्थान सर्वोपरि है। प्राकृतिक न्याय का स्रोत हमारी आत्मा होती है। जब संविधान रचा जा रहा था, तो उस दौरान दो बातें हमारे संविधानविदों ने बड़ी शिद्दत से महसूस कीं, जिनका उल्लेख बार-बार संविधानसभा में होता रहा। पहली बात थी- ''भारतवर्ष में कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता, जो प्राकृतिक न्याय की दैविक अवधारणा के विपरीत हो। अगर गलती से भी ऐसा कोई कानून बन गया और न्याय प्रदान करने के संदर्भ में इस जजों के द्वारा प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध पाया जाए, तो जजों का यह कर्तव्य हो कि वह लिखे हुए कानून की तुलना में अतिरिक्त प्राकृतिक न्याय को ही मस्तिष्क में रखकर फैसला प्रदान करे।'' दूसरी बात जिस पर सर्वसम्मति हुई, वह यह थी कि ''न्याय प्रदान करना महज एक मशीनीप्रक्रिया जैसा आम आदमी को नहीं लगना चाहिए। उसे लगना भी चाहिए कि सचमुच न्याय हो रहा है।'' ***-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 21/10/2003)***

169) आज सत्याग्रह शब्द का प्रयोग बहुत प्रचलित है। सत्याग्रह की अवधारणा गाँधी जी ने दी। सरकार गाँधी की समाधि पर करोड़ों रुपये खर्च करती है। प्रायः राजनीतिक दल गाँधी जी के नाम का इस्तेमाल भी करते हैं। मगर कोशिश यही होती है कि उनके विचारों को दबा दिया जाए, काले ग्रेनाइट में। परन्तु विचार न तो मरता है, न खत्म होता है। जब जहर ज्यादा बढ़ता है तभी अमृत की वर्षा होती है। अँधेरा गाढ़ा होने के बाद अवश्य सूरज निकलता है और प्रकाश का महत्त्व भी तो हमें रात में ही समझ आता है।

आज भी काले पत्थरों की समाधि में दबे शहीदों की आवाज आती है।
कितना भी भुलाना चाहे कोई सत्य की ज्योति चमक जाती है॥

'सत्य' शब्द 'सत्' से बना है। सत् का अर्थ है- अस्ति। सत्य अर्थात् अस्तित्व। सत्य के बिना दूसरी किसी चीज की हस्ती नहीं। परमेश्वर का सच्चा नाम ही 'सत्' है अर्थात् 'सत्य' है। इसलिए परमेश्वर सत्य है। यह कहने की अपेक्षा 'सत्य ही परमेश्वर है' कहना अधिक योग्य है। 'कर्ता' के बिना, सरदार के बिना हमारा काम नहीं चलता। इस कारण परमेश्वर नाम तो लगेगा ही। सत् या सत्य ही परमेश्वर का सच्चा नाम है और जो पूरा अर्थ प्रकट करने वाला है। गाँधी जी की भावनाओं का प्रत्यक्षरूप है- सत्याग्रह।

शरीरबल का उपयोग करना, गोला-बारूद काम में लाना सत्याग्रह के खिलाफ है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें जो पसन्द है, वह दूसरे आदमी से हम जबरन करवाना चाहते हैं। अगर यह सही हो तो फिर वह सामने वाला आदमी भी अपनी पसन्द का काम हमसे करवाने के लिए हम पर गोला-बारूद चलाने का हकदार है। इस तरह तो हम कभी एक राय पर पहुँचेंगे ही नहीं। जो लोग ऐसा मानते हैं कि जो कानून खुद को नापसन्द है, उसे मानने के लिए आदमी बँधा हुआ नहीं है। उन्हें तो सत्याग्रह को ही सही साधन मानना चाहिए। वरना बड़ा विकट नतीजा आएगा। राजतन्त्र में ब्रिटिशतन्त्र में भारत की जनता जीकर देख चुकी है। तन्त्र की प्रबलता अधिक और जन की महत्ता जरूर कम हुई है। ऐसे में सत्याग्रह ही जन की महत्ता को बढ़ा सकता है। 'सत्य की ताकत दोनों जहाँ में याद रहेगी। इसके लिए मरकर लोग खुदा हो गए।।'

-(संजीवकौरा, लाइटहाउस, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 14/10/2003)

170) मुख्य चुनाव आयुक्त का पद एक अति महत्त्वपूर्ण सम्वैधानिक पद है। इस पद पर आसीन व्यक्ति को हटाने के लिए वही प्रक्रिया है, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से और प्रमाणित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इस पद पर आज माननीय जे.एम.लिंगदोह साहब आसीन हैं। दो दिन पूर्व वह पटना गए थे। इस पद पर आसीन व्यक्ति राजनेताओं के चरित्र से इतने अधिक वाकिफ होते हैं कि लोग इनके मुख से राजनीतिज्ञों की जन्मपत्री सुनना चाहते हैं। लोग देश की वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं। यह एक ऐसा पद है, जो भयमुक्त है। अतः इसी

पद के ऊपर आसीन व्यक्ति से वर्तमान प्रजातन्त्र की असली नब्ज को पकड़ा जा सकता है। मैं साधुवाद देता हूँ इस व्यक्ति को क्योंकि इन्होंने जो भी उद्‌गार प्रकट किए, उससे हमारी आँखे खुल जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश आज हम आँखे होते हुए भी अन्धे बने हुए हैं। जनाब लिंगदोह पटना के सेन्ट जेवियर्स स्कूल में बोल रहे थे। जो विषय बोलने के लिए चुना गया था, वह था–**'चुनावी प्रक्रिया में नैतिकता कैसे आए?'** मुख्य चुनाव आयुक्त निर्भीक होकर बोले– **''स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराना चुनाव आयोग का सबसे बड़ा कर्तव्य है। लेकिन इसमें सबसे बड़े बाधक वे अपराधी हैं, जो राजनीति में घुस आए हैं। और वह पैसा भी है, जो अनधिकृतरूप से इसमें खर्च किया जाता है। राजनीति आज के दिन एक धन्धा हो गई है और राजनीतिज्ञ इस लूट के सबसे बड़े हिस्सेदार हैं।''** मैं उनकी बातों को सुनकर चमत्कृत हो गया। सचमुच जिस राष्ट्र में राजनीति एक धन्धा हो और नेता लुटेरे, उस राष्ट्र की महिमा का गान चाहें हम डंके की चोट के साथ विदेशी मन्चों पर करते रहें, परन्तु निर्वाचन आयोग जिन्हें धन्धेबाज और लुटेरा घोषित करे, उसके पक्ष में चाहे और कोई भी दलील दी जाए, उसका अब दो कौड़ी भी महत्त्व नहीं। अपवादों को तो लिंगदोह भी मानते हैं, पर अपवाद तो मात्र अपवाद होते हैं। वे कभी नियम नहीं हो सकते। आज के दौर का तो कवि भी यह कहने को मजबूर हो गया है :–

तस्कर बिल्डर-माफिया, लूट अपहरण क्लेश।
हाथ दलालों के बिका, गाँधी तेरा देश।।

किसने इस देश को दलालों के हाथ बेचने की जुर्रत की, जरा उसका खुलासा भी सुनिए। लिंगदोह ने स्पष्ट कहा– **''दिल्ली के हाईकोर्ट ने सिर्फ इतना कहा था कि भविष्य में चुनावी प्रत्याशियों को आपराधिक रिकार्ड, चल-अचल सम्पत्ति का विवरण और शैक्षणिक योग्यता देना आवश्यक है, तो सारी पार्टियों ने मिलकर (इसके विपरीत) कानून बनाने की जुर्रत की और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। वे किन्हें बचाना चाहते थे।''** एक ही बात बार–बार माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त की बातों से झलक रही थी– ''अपराधियों और राजनेताओं का आपसी गहरा सम्बन्ध है। अतः भारतवर्ष में प्रजातन्त्र का भविष्य सुरक्षित नहीं है। ये सारे नौटंकीबाज जो राष्ट्र के पटल पर नजर आते हैं, इन्होंने कोई राष्ट्र का गौरव नहीं बढ़ाया। कोई करोड़ों का पशुचारा खा गया। कोई सांसदों की खरीद–फरोख्त कर रहा है। कोई यूनिया डकार गया। कोई आई.बी. के कागजों से धोखाधड़ी कर रहा है। कोई ताज के बहाने करोड़ों रुपयों से अपना घर भर रहा है। कोई मनुष्यों को जिन्दा ही जला रहा है। कोई दंगे करवा रहा है। कोई मस्जिद गिरवा रहा है। जिस दिन जनता जागृत हो जाएगी, तूफान खड़ा हो जाएगा। ये सारे के सारे बेईमान अब अच्छी तरह समझ लें। बाकी श्री लिंगदोह को उनकी स्पष्टवादिता के लिए हम साधुवाद देते हैं। **-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 11/10/2003)**

171) हमारे नेता अन्धे, बहरे, बेईमान हो चुके हैं। वह शराब और शबाब में रात–दिन डूबे रहते हैं। इन बेईमानों का देश और लोगों से कोई वास्ता नहीं रहा है। ये सिर्फ वोट के समय ही जनता के सामने आते हैं और छल–कपट करके इलेक्शन जीतते हैं। जिन नेताओं को जेल में या फाँसी के तख्ते पर होना चाहिए था, वह हमारी संसद और विधानसभाओं में बैठकर हमारे भाग्यविधाता बने हुए हैं। लगता है आजादी के लिए एक और लड़ाई लड़नी होगी, तभी इन बेईमानों से निजात मिलेगी। मौत वह है जो जुल्मों को मिटाते–मिटाते मिले। जो आजादी हमारे देशभक्तों ने भारतभूमि को अपने खून से सींचकर प्राप्त की है, उसको हम इन कायर और अयोग्य नेताओं के हाथ का खिलौना नहीं बनने देंगे।

-(अनुज नरूला, माडलटाउन, दिल्ली, आवाज-ए-खबरदार, पंजाबकेसरी, 10/10/2003)

172) किसानों की दुर्गति- सरकारें निष्क्रिय व समाज खामोश :- आज देश के लगभग हर राज्य के किसान के लिए आत्महत्या करके कर्जों और गरीबी से मुक्ति पाना उसकी जीवनशैली का हिस्सा बन चुका है। आजतक सरकार ने उन्हें इसप्रकार के अतिवादी कदम उठाने से रोकने का कोई विधिवत उपाय नहीं किया। ताजे आँकड़ों के अनुसार कर्नाटक में लगभग 500 किसान कर्जों के चक्रव्यूह से आजाद होने के लिए आत्महत्याएँ कर चुके हैं। इसी तरह आन्ध्रप्रदेश में 400 और ध्यान से सुनिए दिल थाम कर। सारे देश के अन्नदाता बने पंजाब में एक गैरसरकारी आँकड़े के अनुसार 500 किसान अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। शायद इन आत्महत्याओं के और भी कुछ कारण रहे हों परन्तु अधिकतर मामले उन किसानों के हैं, जो कृषि की कमजोर, जर्जर और घिसी–पिटी आर्थिकता से गरीबी के जाल में फँसकर कर्जों के बोझ से पिस रहे हैं।

कइयों को तो यह विश्वास है कि आत्महत्या द्वारा अपनी बलि देकर वह अपने परिवार को कर्ज से मुक्त करा देंगे और खुद भी सरकारी कर्जा वसूलने वाली एजेन्सियों के हाथों बदनामी और रुसवाई से बच जाएँगे। सरकार आर्थिक स्रोतों के न होने का रोना रोती है। निठल्ले सरकारी कर्मचारियों को बेकार बैठने की मोटी तनख्वाहें देती है और मन्त्रियों तथा विधायकों के लिए लेटेस्ट माडल की कारें भी खरीदती है एवं उनके भत्ते भी बढ़ाती है। धन की कमी केवल गाम्यजीवन को ऊँचा उठाने के लिए है।

-(ईश्वरडाबरा, सैलानी की कलन से, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 09/10/2003)

173) *मजबूरी, बेबसी इंसान को किस कदर मजबूर कर देती है, इसके कई बाद बड़े दर्दनाक उदाहरण हमारे सामने आते हैं। ऐसी हालत में ऐसे व्यक्तियों से उनका हर तरह से शोषण करते हुए कुछ भी कराया जा सकता है। ऐसी ही लाचारी का जीता-जागता उदाहरण छत्तीसगढ़ में रायपुर के डबलचौकी के सिवनी ग्राम के मध्य देखने को मिलता है, जहाँ सूचनाक्रान्ति और आई.टी. के क्षेत्र में दुनियाभर में अग्रणी इस आधुनिक भारत में आज भी महिलाएँ व लड़कियाँ बैलों की भाँति खुद खेतों में हल खींचने को विवश हैं। इस विकट काम के बदले में उन्हें इतनी मजदूरी मिलती है, कि उन्हें दो जून की रोटी भी भरपेट मयस्सर नहीं होती। हैरत की बात तो यह है कि विकसित देशों की श्रेणी में भारत को ले जा रहे महामहिम राष्ट्रपति डाक्टर कलाम को भी जमीनी जिन्दगी की ये दर्दनाक सूरतें नजर नहीं आती। इस क्षेत्र के सम्पन्न किसान मात्र कुछ रुपये या सेर-सवासेर अनाज देकर दिनभर महिलाओं को हल में जोतते हैं और पुरुष मजदूरों को चार से दस रुपये में वर्ष भर के लिए नौकर के रूप में बंधक बना लेते हैं। यह पैसा दवा-दारू या आपात परिस्थितियों में खर्च हो जाता है और मजबूरन पेट भरने के लिए महिलाओं को दिहाड़ी पर काम करना पड़ता है। लेकिन प्रशासन इन सब हकीकतों से रुबरु होते हुए भी अन्जान बने रहने का नाटक करता है। इतना ही नहीं इनमें से सुन्दर महिलाओं का यौनशोषण तो आम बात है। कुछ को इसके लिए श्रम में सहूलियतें देकर राजी किया जाता है तो कुछ से बलात्कार होता है और बेचारी ये गरीब महिलाएँ इसके लिए चाहकर भी कभी आवाज नहीं उठा पातीं। अगर कोई ऐसी कोशिश करती भी हैं, तो सत्ताशीर्ष अथवा प्रशासन में बैठे लोगों तक उनकी आवाज पहुँचती ही नहीं है। जिन आदिवासी महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार अनेक योजनाओं के नाम पर अरबों रुपये चट करती है, उन्हीं महिलाओं की यह दशा शासन की नीतियों वरन मानवीय संवेदनाओं के मुँह पर भी एक करारा तमाचा ही है। हकीकत की पोल खोलती ऐसी घटनाएँ हमें यह विचार करने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम वाकई वैज्ञानिक युग में जीने वाले सभ्य इंसान हैं?*

-(संजीवदुबे, एम.सी.एन., पंजाबकेसरी, दिल्ली, 07/10/2003)

174) *मुम्बई के ओबराय होटल में गरीबी पर आयोजिक एक काँफ्रेंस से प्रेरित होकर इस वर्ष मैंने मैरीन ड्राइव में जाकर उन लोगों के चेहरे निकट से देखने तथा उनकी दशा जानने का प्रयास किया, जिन्हें महात्मा गाँधी जी गरीबों में भी गरीब यानि दरिद्र नारायण कहा करते थे। मैंने वहाँ जो कुछ देखा, उसकी एक झलक यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। गाँधी जी के जन्मदिवस पर यह उपयुक्त होगा कि हम इन निर्धनतम व्यक्तियों की दशा को गहराई से देखें और इस बात को समझने का प्रयास करें कि आखिर ये लोग इसप्रकार निरन्तर गरीब क्यों रह गए? आखिर इनकी निर्धनता का कारण क्या है? थोड़ी दूर चलकर आप इन गरीब बच्चों से भी मिलें। इनमें से कुछ बच्चे तो मुश्किल से चल पा रहे थे। कुछ कबूतरों के साथ खेल रहे थे तथा सड़क पर आवारा फिरने वाले कुत्तों से कुछ पशुप्रेमियों द्वारा फेंके गए मैरी बिस्किट के टुकड़ों को झपटने के लिए लड़-झगड़ रहे थे। शायद कोई उदार व्यक्ति एक सो रहे लड़के के पास एक अनखुला पैकेट रख गया था। यह लड़का देखने में इस शहर में नया-नया आया लग रहा था। वह नंगे पैर था और दस साल से अधिक उम्र का नहीं लगता था। उसके पैर देखकर लगता था कि वह अपनी उम्र से ज्यादा काम करने के कारण अस्वाभाविक रूप से अधिक उम्र का हो गया था। उसके पाँव काफी कड़े व विवाई से भरे लगते थे। उसके पास ही नाटी व उलझे बालों वाली एक औरत बैठी थी, जिसके हाव-भाव भी काफी अजीबोगरीब से थे। उसने एक मैलाकुचैला गाउन जैसा कपड़ा पहना हुआ था। लगता था कि उसने जब से अपना घर छोड़ा होगा, अगर उसका कभी घर रहा होगा, तब से उसने इसे शायद ही कभी उतारा हो। इसके अलावा और भी औरतें थीं, जो मैलेकुचैले चीथड़े जैसे कपड़े पहने अपने अधनंगे बच्चों के पास बैठी हुई थीं। वे*

इसप्रकार थकी-थकी सी लगती थीं कि अपने बच्चों की आँखों तथा नाक पर बैठने वाली मक्खियों को उड़ाने की ओर भी ध्यान नहीं दे रही थीं। ट्रैफिक लाइटों पर कुष्ठरोगी तथा अजीबोगरीब बीमारियों से ग्रस्त भिखारी मँडराते दिखाई देते हैं। एक व्यक्ति अपनी कमीज उठाकर अपनी पीठ में पड़ी गाँठे दिखा रहा था तो दूसरा अपने पाँवों के घावों को दिखा रहा था, जिन पर मक्खियाँ भिनभिना थीं।

लगभग हर भारतीय शहर में इसी प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं। आइए मैं आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ओबराय होटल में लेकर चलती हूँ। यह काँफ्रेंस 'क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफ इण्डिया लिमिटेड' (क्रिस्टिल) द्वारा विश्वबैंक की रिपोर्ट 'इण्डिया सस्टेनिंग रिफॉर्म रिड्यूसिंग पॉवर्टी' पर आयोजित की गई थी। अर्थशास्त्रियों तथा अन्य विद्वानों ने गरीबी और सुधारों पर अपने रोचक भाषण दिए। लेकिन निजीरूप से मैंने पाया कि विश्वबैंक की रिपोर्ट वहाँ दिए गए भाषणों की अपेक्षा अपने आप में अत्यन्त रोचक थी। क्योंकि यह गरीबी के बारे में एक गाइडबुक से कम नहीं थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के गरीब लोगों में आधे से अधिक बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा तथा उत्तरप्रदेश में रहते हैं। इनमें से दो-तिहाई गरीब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। गाँवों में गरीबों का अधिकांश तबका कृषिमजदूरों का है। उनमें से अधिकांश छोटे किसान तथा दैनिक कृषिमजदूर हैं। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अधिकांश लोग अन्य जातियों की तुलना में कुछ अधिक ही गरीब हैं। उनका रहन-सहन भी काफी निम्नस्तर का है। इसके अतिरिक्त लिंगभेद से जुड़ी अनेक समस्याएँ भी उनके सामने सामाजिक रोड़ा बनी हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार 80 के दशक के मुकाबले हम अब कम ही गरीब हैं। हमारी गरीबी का स्तर 44.5 प्रतिशत से घटकर 28. 6 प्रतिशत तक आ गया है। लेकिन विश्वबैंक की रिपोर्ट में जो बात मुझे सबसे रोचक लगी, वह इसमें दिए गए आँकड़े नहीं बल्कि हमारी सरकार की फिजूलखर्ची तथा खराब प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जो कि मूलतः हमारी गरीबी के लिए जिम्मेदार है।

विश्वबैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकांश लोग खासकर निर्धन राज्यों में अपने कार्यस्थलों में अनुपस्थित ही रहते हैं। ये अनुपस्थित कर्मचारी अपने वेतनभत्ते भी लेते हैं। फिर इसमें आश्चर्य की क्या बात कि जनता के पैसे का सही रूप में वांछित परिणाम सामने नहीं आ पाता है। 1998-99 में सड़कों तथा अन्य निर्माणकार्यों के रखरखाव पर 2.80 अरब रुपये खर्च आया जबकि तत्सम्बन्धी विभागीय वेतन और प्रशासन आदि पर 3.40 अरब रुपये का खर्च आया। ऐसी हालत में अगर भारतीय सड़कें विश्वभर में सर्वाधिक बुरी हालत में हैं, तो इस पर आश्चर्य क्यों होना चाहिए? अगर हम महात्म गाँधी जी की जयन्ती पर उन्हें केवल दिखावे की श्रद्धांजलि अर्पित करने के बजाय कुछ करने का संकल्प करें और उसके अनुरुप कार्य करें, तो हम गरीबी उन्मूलन की दिशा में चमत्कार कर सकते हैं। जिस दिन हमारे राजनेता सच्चे मन से गरीबी की इस गंभीरतम समस्या को जड़मूल से उखाड़ने का फैसला कर लेंगे, तो सबसे पहले यह होगा कि हमारे सभी प्रकार के दिखावटी 'गरीबी निवारण कार्यक्रम' समाप्त हो जाएँगे। इसी तरह से काम करने की आवश्यकता शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी है। आज जो हालत है, उसे जानने के लिए केवल आपको मुम्बई की मैरीन ड्राइव का एक पैदल चक्कर लगाना ही काफी होगा। **-(तवलीन, स्तम्भकार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 04/10/2003)**

175) गाँधी जी आज होते तो सबसे दुःखी व्यक्ति होते। गाँधी जयन्ती अब केवल औपचारिकता ही रह गई है। गाँधी ने अपने द्वारा सम्पादित साप्ताहिक 'हरिजन' के 22 सितम्बर, 1946 के अंक में लिखा था- ''राज्य आपके सेक्यूलर कल्याण, स्वास्थ्य, संचार, विदेशी मामलों, मुद्रा आदि की देखभाल करेगा। आपके धर्म अथवा मेरे धर्म की नहीं। वह हर व्यक्ति का निजी मामला है।'' उन्होंने कहा था- ''आप किसी भी धर्म, जाति या मत से सम्बद्ध हो सकते हैं। इसका इस बुनियादी सिद्धान्त से कोई वास्ता नहीं कि हम सब एक ही राज्य के नागरिक हैं।''

सादगी अब कोई गुण नहीं रह गई। कमजोर हिकारत की निगाह से देखे जाते हैं। 'जिसमें ताकत है वही श्रेष्ठ है' का विचार बढ़ा है। गाँधी की यह अवधारणा थी कि धनीजन सम्पदा के न्यासी (Trusty) हों। उनका यह विचार नहीं चल पाया। धनी और अधिक धनी तथा गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। ग्राम जिन्हें गाँधी जी देवताओं का वास बताया करते थे, स्वतन्त्रता के 55 वर्ष बाद भी उसी हालत में हैं। विकास से उन्हें ज्यादा लाभ नहीं हुआ। शहरों में सब सुविधाएँ उपलब्ध होती जा रही हैं। विवादों को अहिंसक तरीके से हल करने का गाँधी का मन्त्र दुनिया ही नहीं भारत ने भी भुला दिया है।

-(कुलदीपनैयर, स्तम्भकार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 01/10/2003)

176) जनसंघ व भाजपा के बाद अब आगे क्या? :- *लम्बी यात्रा के हजारों सहभागी अब पूरी तरह निराश! सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को उसके मूल के साथ उत्तरोत्तर बढ़ाने वाली प्रणाली ही किसी देश की सकारात्मक और पोषण राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था हो सकती है। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने सनातन राष्ट्रीय मूल्यों का अनुसरण न करे, तो उस देश के नागरिकों को उस व्यवस्था को तुरन्त बदल देना चाहिए। हमारा इतिहास ऐसे जागृत पुरुषों से भरा पड़ा है, जिन्होंने किसी की माँग पर नहीं, अपनी अन्तरात्मा की आवाज पर व्यक्तिगत वैभव की दुनिया छोड़कर राष्ट्रहित का पथरीला मार्ग स्वीकार किया था। जो लोग सत्ता और सुविधा के मद में होते हैं, उन्हें न परिवर्तन की आहट सुनाई देती है और न बदलाहट की आवश्यकता महसूस होती है। जनसंघ से लेकर भाजपा के गठन तक की यात्रा में जो भी सहभागी रहा है, वह आज हताश और निराश इसलिए नहीं है कि सत्ता की भागीदारी या ओहदे के बँटवारे से उसको कोई शिकायत है। बल्कि उसकी निराशा का यदि कोई एक कारण है, तो वह है– भाजपा का उन सिद्धान्तों ('रामप्रताप विषमता खोई' आदि) और मुद्दों (सच्चाई, न्यायशीलता आदि) से पूरी तरह किनारा कर लेना, जिनके पोषण में हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जीवन के दशक ही नहीं लगभग एक शताब्दी झोंक दी। पिछले एक दशक में पार्टी में भटकन के कारण घुटन अनुभव कर रहे लोग अब बेचैन हो उठे हैं, जो इस आशा में पार्टी को ढो रहे थे कि शायद उसमें बुद्धि और प्राण आ जाएँ। उनमें अब एक नई पार्टी और नई व्यवस्था के लिए अकुलाहट बढ़ने लगी है। ये ऐसे लोग हैं, सत्ता की एवज में सिद्धान्तों, आदर्शों और संगठन को मृत्युशैया पर नहीं डाल सकते हैं।*

सत्ता पर कुंडली मारे बैठी काँग्रेस को हटाकर उसी के माडल पर सत्ता प्रतिष्ठान के संचालन करने का कार्यक्रम नहीं बना था अन्यथा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन का प्रतिपादन न किया होता।

-(भानुप्रताप शुक्ल, स्तम्भकार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 29/09/2003)

177) ऐसी सरकारों से हम बाज आए :- *अपने वोटबैंक को स्वच्छ प्रशासन पर तरजीह देने की ही नीति का परिणाम है कि आज सरकार ने लगभग हर राज्य में अपने तीन बड़े दायित्वों शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक प्रबन्धन से हाथ खींच लिए हैं। अपनी इन तीनों महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारियों को काफी हद तक बाजारवाद व मुनाफेबाजी के रहमोकरम पर छोड़ दिया गया है। क्या प्रजातन्त्र के पाश्चात्य संस्करण का अनुसरण करना अब हमारे लिए लोकहित से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। प्रजातन्त्र के सहारे ही टिकाऊ प्रशासनतन्त्र बनता है। जिससे आम आदमी तक सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य व सुदृढ़ नागरिक प्रबन्धन की सुविधाएँ पहुँचती हैं। जनता की बेबसी का इलाज करने के बजाय वोटों के सौदागर खुद अपने ही शैक्षणिक संस्थान खोलकर न सिर्फ लाखों में फीस बटोरते हैं, बल्कि सुयोग्य परन्तु निर्धन विद्यार्थियों को साइडलाइन करके धनी परन्तु नालायक व अय्याश अमीरजादों को खैंच–खाँचकर डाक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या नेता बना रहे हैं। शिक्षा जगत के लिए यह एक बड़ी त्रासदी है।*

आम नागरिक कम से कम यह तवक्को (अपेक्षा) रखता है कि गली–मुहल्ले साफ–सुथरे रहें। गैरजिम्मेवार लोगों से मिली–भगत करके घूँस खाकर कर्मचारी उन्हें नाजायज भवननिर्माण या अतिक्रमण न करने दें और बिजली, पानी आदि की सप्लाई ठीक ढंग से हो। राजनीतिज्ञों को इसमें कोई एतराज नहीं अगर चुंगी उगाही व नगर की सफाई का निजीकरण करके उन्हें संवेदनहीन और लूटमार की मानसिकता वाले ठेकेदारों के हवाले कर दिया जाए। जिसको अपना 'कट' (हिस्सा) चाहिए, वह तो ठेकेदार से मिल जाएगा। फिर क्यों न निजीकरण करो। अपने प्रशासनिक दायित्व त्यागो तथा खुद तो चैन की वंशी बजाओ और करदाताओं को नृशंस व्यापारियों के हवाले कर दो। शिक्षा, स्वास्थ्य और साफ–सुथरा स्थानीय प्रशासन हर प्रजातान्त्रिक देश में ये तीनों एक सुदृढ़ और ईमानदार सरकार के कर्तव्यों में गिने जाते हैं। सरकार अच्छी है, जनहित में उसकी रुचि है या नहीं, इन्हीं क्षेत्रों में उसकी परख होती है। नाममात्र की रीढ़विहीन सरकार के होने, न होने के विषय पर भी एक पब्लिक डिबेट हो जानी चाहिए।

-(ईश्वरडाबरा, सैलानी की कलम से; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 18/09/2003)

178) सफेद पट्टी से ढका शिर, क्षत-विक्षत हाथ-पैर, थका शरीर और इन सबसे ऊपर मासूम, उन्मुक्त खिलखिलाहट। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के छठवें माले में यह लड़की सलमा है। पिछले छह महीनों से सलमा बिहार के जहानाबाद से दिल्ली आकर जिस तरह की मजबूर, पीड़ादायक जिन्दगी जी रही थी, उससे यह जीवन कहीं बेहतर था। न मालकिन की डाँट का डर, न छड़ की मार, न गरम इस्त्री (प्रेस) और न ही भूख। कुछ भी तो नहीं था- इस वार्ड में। दरअसल गरम प्रेस से बुरी तरह झुलसाई गई सलमा और शरीर पर पड़े नोंचने और काटने के निशान खुद अपनी कहानी बयाँ करते हैं। गरीबी की मार, सात भाई-बहनों और माँ-बाप का विशाल परिवार उस पर पिता का अपंग होना- इन सबसे जूझती सलमा की माँ ने उसे दिल्ली में बटला हाउस जामिया निवासी एक दम्पत्ति के यहाँ घरेलू नौकरानी बनाकर भेज दिया। तेरह वर्षीय सलमा की कीतम आँकी गई- उसकी बड़ी बहन के निकाह में होने वाले कुछ खर्चों के बराबर। सलमा बताती है कि उसकी माँ भी मालकिन के किसी रिश्तेदार के यहाँ काम करती है। पुश्तों से वे दिल्ली के इस परिवार की सेवा करते चले आ रहे हैं। सलमा की ये दशा वाकई सोचने को विवश करती है कि कहीं यह समाज में छिपा हुआ सामन्तवाद तो नहीं। अगर ऐसा नहीं है, तो यह कैसे संभव है कि एक ही जाति विशेष के ये लोग पुश्त दर पुश्त मालिकों की सेवा करने को मजबूर हैं। सलमा बताती है- मालकिन कभी सब्जी में नमक कम होने पर नोंचती, तो कभी रोटी सही न फूलने पर छड़ी से मारती। उस दिन मालकिन शायद बहुत गुस्से में थी, जब सलमा अपनी छोटी मालकिन को स्कूलबस में बैठाकर वापिस लौटी थी। उसके पूछने पर कि क्या अब आपके चाय-नाश्ते का इंतजाम करूँ? मालकिन आग-बबूला हो उठीं। उसने गरम इस्त्री सलमा की टाँगों पर दाग दी। सिहरी सलमा फिर काँपती आवाज में आगे बताती है कि उसके शिर पर लोहे की छड़ से कई वार करके मालकिन ने उसे कमरे में बन्द कर दिया। अगले पन्द्रह दिन बिना मरहम पट्टी व बिना किसी खाने के वह घायल पैर व शिर की चोट लिए काम करती रही। बहरहाल पन्द्रह दिनों बाद मालकिन का मिजाज फिर किसी बात पर गरम हुआ और सलमा के शिर पर लगी चोट को जिसमें कि अब तक मवाद (पस) पड़ चुका था, फिर लोहे की छड़ों का वार सहना पड़ा। सलमा की इस चीख ने आस-पड़ोस की दो-तीन महिलाओं की सोई संवेदना को झकझोरा और उन्होंने एक गैरसरकारी संगठन 'बचपन बचाओ आन्दोलन' की मदद से सलमा को मुक्त करवाकर गंभीर हालत में एम्स में दाखिल करवाया।

सोचने की बात यह है कि सलमा का यह मामला ऐसा पहला या अन्तिम मामला नहीं है। महानगरों में ऐसे मामले आए दिन सुनने या देखने को मिलते हैं। अभी सलमा पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई होगी कि पिछले दिनों दिल्ली के ही महरौली स्थित एक व्यापारी ने अपने यहाँ कार्यरत ग्यारहवर्षीय एक नौकर 'उमेश' को चाकू से गले पर वार करके मार डाला। खोजबीन करने पर मालूम हुआ कि उस व्यापारी को उमेश द्वारा पकाया गया भोजन रुचिकर न लगने के कारण यह हादसा हुआ। बालश्रमिक (निषेध व नियमन) कानून 1986 में भी घरेलू नौकर के काम को खतरनाक न मानते हुए वर्जित श्रेणी के बाहर रखा गया है। कामकाजी स्थितियों को लेकर कुछ कानून भले ही बना दिए गए हों, लेकिन घर में कार्यरत ये अदृश्य गुलाम अगर अपनी गुहार लगाना भी चाहें तो नहीं लगा सकेंगे।

यदि आँकड़ों पर ध्यान दें, तो भारत सरकार द्वारा तैयार श्रमशक्ति रिपोर्ट 1998 में दर्ज किया गया है कि घरेलू नौकर के क्षेत्र में लड़कियों की संख्या लड़कों से ढाई गुना ज्यादा है (6 लाख 20 हजार लड़कों की तुलना में 16 लाख 80 हजार लड़कियाँ)। कैथोलिक बिशप्स काँफ्रेंस ऑफ इण्डिया द्वारा किए गए 12 शहरों के सर्वेक्षण में 78% लड़कियाँ ही घरों में काम करती पायी गईं। कहना न होगा कि इनमें से अधिकांश शारीरिक, मानसिक एवं यौनशोषण की शिकार हैं। तेरह-चौदह वर्ष की उम्र से ही शोषित रहना जहाँ इन लड़कियों ने भी अपनी नियति मान लिया है, वहीं समाज ने भी इस अदृश्य गुलामी को मूल नैतिक समर्थन दिया हुआ है। भले ही सरकार और गैरसरकारी संगठन 8 मार्च को जोरशोर से महिला दिवस मनाएँ, परन्तु मालिकों के घरों में कैद ये बालाएँ तो उस दिन ही महिला दिवस मना पाएँगी, जिस दिन समाज इनकी मुक्ति को समर्थन देगा, आवाज उठाएगा। **-(शेफाली चतुर्वेदी, ग्रासरूट फीचर्स; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 16/09/2003)**

179) अमीर और गरीब देशों के बीच जारी तीखे मतभेदों का कोई समाधान नहीं निकल पाने के कारण विश्वव्यापार संगठन की वार्ता बिना किसी नतीजे के ध्वस्त हो गई। कोई घोषणापत्र जारी नहीं किया गया। केन्या के प्रतिनिधि जार्ज ओड्यूर ओंगवान ने बताया- ''मतभेद काफी तीखे थे। इन मतभेदों को दूर करना असंभव था।'' **-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 16/09/2003)**

180) *प्रदेश की जनता को इस (राममन्दिरनिर्माण) आन्दोलन से कोई लेना–देना नहीं है। वह इसे पूरी तरह नकार देगी और श्री आडवाणी को हताशा हाथ लगेगी। आडवाणी का चलेगा– अयोध्या आन्दोलन, हमारा चलेगा– उत्तरप्रदेश का विकास आन्दोलन। जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार आदि चाहिए, मन्दिर नहीं। इसलिए वह स्वयं मन्दिर आन्दोलन के बारे में फैसला कर लेगी।*

-(मुलायम जी यादव, मुख्यमन्त्री, उ.प्र.; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 13/09/2003)

181) भारत में अल्पसंख्यक समुदाय सर्वाधिक सुरक्षित :- *वस्तुतः अल्पसंख्यक शब्द एक आधुनिक शब्द है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, इसके हजारों वर्ष के इतिहास में कभी भी इसप्रकार की अवधारणा कहीं नहीं दिखाई दी। समस्त मुगलकाल में भी कहीं इस शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। यहाँ तक कि भारत में ब्रिटिश तथा पुर्तगाली शासन के दौरान ईसाइयों ने भी स्वयं को भारतीय समाज द्वारा किसी प्रकार से अलग–थलग महसूस नहीं किया। इसप्रकार अल्पसंख्यक शब्द जनसांख्यिकी से प्रभावित नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से गढ़ा गया शब्द है। आर्थिकरूप से सम्पन्न लोगों के लिए तो यह शब्द कोई मायने नहीं रखता चाहे वे किसी भी समुदाय के क्यों न हों। भारत के लिए लोकतन्त्र इतना आवश्यक क्यों है? इसलिए कि यह एक सभ्य समाज के संचालन के लिए अत्यन्त आवश्यक है। यह सत्ता के शान्तिपूर्ण हस्तांतरण का एक माध्यम है, जिसमें जनता अपने असन्तोष अथवा नाराजगी को व्यक्त कर सत्ता परिवर्तित कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि समाज में सभी वर्गों की आवाज सुनी जाए, उनके असन्तोष को दूर किया जाए। आतंकवाद से निपटने का यही एकमात्र तरीका है।* ***-(एम.जे.अकबर, स्तम्भकार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 05/09/2003)***

182) ब्राजील में 1000 गुलामों को मुक्त कराया :- *ब्राजील सरकार ने उत्तरपूर्वी प्रान्त में दो काफी बागानों से 1000 गुलामों को मुक्त कराया। श्रममंत्रालय मार्सेलो काम्पोस ने बताया कि इन गुलामों की स्थिति बहुत ही दुःखदायी थी और इन्हें पर्याप्त भोजन आवास तथा स्वास्थ्य जैसी सुविधाएँ भी नहीं दी जा रही थीं।*
–(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 03/09/2003)

183) हमारे सन्त महात्मा राष्ट्रीय व सामाजिक समस्याओं की ओर भी ध्यान दें :- *ईश्वरीय पुरुषों या स्त्रियों के लिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं होता। मैं जानता हूँ कि वे अपने अनुयायियों की बड़ी संख्या को शान्ति प्रदान करते हैं और उनसे उन्हें जो चढ़ावा मिलता है, उससे वे स्कूल, कालेज व अस्पताल खोलते हैं। परन्तु ज्यादातर समय वे पूजास्थल बनाने और अपने प्रशंसकों को दर्शन देने, भजन गाने व उपदेश देने में व्यतीत करते हैं। उनके खिलाफ मेरे मन में केवल यह है कि वे हमारे देश के सामने उपस्थित समस्याओं को अपने से क्यों नहीं जोड़ते?* ***-(खुशवन्त जी, सुप्रसिद्ध पत्रकार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 30/08/2003)***

184) *मैं सरकार पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता। मैं देश के लोगों को टूटती मर्यादाओं की यह वीभत्स परिणिति अवश्य दिखलाना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के शिखंडी (राजनेता) आज उस मुकाम पर पहुँच गए हैं, जहाँ उन्हें बड़े से बड़ा विस्फोट जलते मानवों के शव, बिखरते माँस के लोथड़े, उजड़ते सुहाग, टूटती चूड़ियाँ, विधवाओं का क्रन्दन बिलखते बच्चे, सूनी आँखें और मानवीय चीत्कार कुछ भी उद्वेलित नहीं करते। आप इनके मगरमच्छी चरित्र को देखें– इनके चेहरे की ओढ़ी हुई उदासी और इनके छद्म वक्तव्यों को सुनें। इन सबके पीछे आपको कभी कोई मानवीय संवेदना नहीं मिलेगी।* ***-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 27/08/2003)***

185) अफ्रीका का जल्लाद तानाशाह : ईदी अमीन :- *1971 से 1979 तक युगांडा के डिक्टेटर (तानाशाह) रहे ईदी अमीन की जब पिछले हफ्ते साउदी अरब में मृत्यु हुइ तो आधी दुनिया को पता तक न था कि अपने वक्त में युगांडा का जल्लाद कहलाने वाला ईदी अमीन अभी तक जिन्दा था और वह भी साउदी अरब जैसे पाक–साफ कट्टर धार्मिकता वाले मुल्क में। ईदी अमीन बैंक ऑफ युगांडा को अपनी बपौती समझ वहाँ से मनमाने पैसे निकलवा कर पहले से ही अरब देशों में काफी इन्वेस्टमेन्ट कर बैठा था। हर जालिम शासक को पता होता है कि उसका अन्त में क्या हश्र होगा। सो भागने की तैयारी पहले ही कर रखी थी। अपने मुसलमान होने का इसने न सिर्फ अरब देशों बल्कि इस्राइल में भी खूब फायदा उठाया। लीबिया का कर्नल गद्दाफी जो खुद एक अर्धविक्षिप्त*

और जुनूनी तानाशाह है, ईदी अमीन का खास दोस्त था। एक दिन इस 6 फुट 4 इंच के दैत्याकार मांस के पहाड़ 52 वर्ष के ईदी अमीन ने गद्दाफी की 14 वर्ष की बेटी पर हाथ साफ करने की कोशिश की। तब कर्नल गद्दाफी ने इस मवाली को लीबिया से निकाल बाहर किया। बाद में युगांडा और तंजानिया के काफिरों द्वारा एक सच्चे मुसलमान को दर-बदर कर देने की दुहाई देकर यह शैतान साउदी अरब में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गया और अपनी चारों बीबियों के साथ वहाँ जब तक जिन्दा रहा अपने दबाए हुए धन के बल पर ऐश करता रहा। कहते हैं कि युगांडा के 1 लाख लोगों के खून का इल्जाम इसकी गर्दन पर है। ईदी को हत्याएँ करने का इतना ही शौक था, जितना कि उसे इंसानी मांस को खाने का शौक या शौकिया बलात्कार करने की आदत। इंसानी शिरों को धड़ से अलग करके उन्हें पेपरवेट की तरह अपनी टेबल पर सजाने में ईदी को बहुत मजा आता था। युगांडा के भूतपूर्व सेनाध्यक्ष और युगांडा के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के शिरों से यही काम लिया गया। अपने निजी तालाब में पाले मगरमच्छों को निवाले के रूप में अपने अतिथियों को पेश करना भी इसका शुगल था। ईदी अमीन की पत्नी होना भी जोखिम से खाली नहीं था। अपनी एक पत्नी पर इसे सन्देह था कि उसके पेट का बच्चा किसी और का है। तब ईदी ने प्रसूति के समय सर्जन को कहकर पहले तो उसके सारे अंग कटवाए फिर सर्जन को हुक्म दिया कि उसकी टाँगे उसके कन्धों पर लगा दो और बाँहें टाँगों की जगह।

यह अनपढ़ डिक्टेटर जब एक विश्वविद्यालय के हॉल में कन्वोकेशनल एड्रेस (दीक्षान्त भाषण) दे रहा था, तो बीच भाषण में इसकी पारखी निगाह एक सेक्सी डील-डौल की अफ्रीकन युवती पर पड़ी। दिलफेंक तानाशाह ने तुरन्त कन्वोकेशन भाषण बन्द करके उसे स्टेज पर बुलाया और घोषणा की कि युगांडा के विदेशमन्त्री को बर्खास्त करके उस युवती को विदेशमन्त्री बनाया जाता है। बाद में इसप्रकार मन्त्री बनी युवती ने ईदी के हाथों अपनी संभावित हत्या के डर से युगांडा से भागकर अपनी जान बचाई।

एक और अफ्रीकन सुन्दरी के साथ उसने ऐसी ही घटिया हरकत की। शादी की पहली ही रात को बेडरूम में कार्नेस पर रखे अपने पहले पति के कटे शिर को देखकर उसकी चीखें निकल गईं। उसी हालत में वह ईदी की वासना का शिकार बनी। शैतान के इस अवतार को शुरु-शुरु में युगांडा के उपनिवेशी शासक अँग्रेजों की शह मिली। अपनी उलूल-जुलूल हरकतों से यह उनको हँसाता रहता था तथा इसी हँसोड़पने पर वह ऐसे रीझे कि अर्धशिक्षित होने पर भी इसे सेना में बड़ा अफसर बना दिया। हमें भी इससे सबक लेना चाहिए। हँसा-हँसा कर जोकर बने नेताओं की बातों में आ जाना खतरनाक हो सकता है।

-(ईश्वरडाबरा, सैलानी की कलम से; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 21/08/2003)

186) वंचितों को उनके हक दीजिए :- *दुनिया का कोई भी धर्म या कानून इस बात का समर्थन नहीं करता कि एक आदमी गन्दे नाले या किसी रेल की पटरी के पास पैदा हो। वहीं वयस्क होकर शादी करके अपने लिए बच्चे पैदा करे और एक दिन वहीं मर जाए। ऐसी व्यवस्था ईश्वर ने नहीं बनायी। इसे कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने निजी लाभ के लिए विकसित कर लिया है। सामाजिक एवं आर्थिक असमानता के चलते आज हमारे देश के करोड़ों लोग ऐसा ही नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। इसने तो ईसामसीह को ही सलीब पर टाँग दिया था। झुग्गी वाले हों या चर्च नेतृत्व के सताए लोग, उनका सिर्फ शोषण ही चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में ही ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है, जिनका सवेरा ही रोज नई-नई समस्याओं के साथ शुरु होता है। इनमें से अधिकतर आबादी दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ियों में ही रहती है। पूरा साल इनके झोपड़े सरकार के विभिन्न निकाय तोड़ते ही रहते हैं और सरकार अपनी चाल चलती ही रहती है। यमुनापार की 70 झुग्गी बस्तियाँ ऐसी हालात में बसी हैं, जो आदमी के रहने लायक जगह ही नहीं है। दरअसल दलित ईसाइयों के शोषण की परम्परा बन चुकी है। हमने जब-जब आवाज उठाई चर्च नेतृत्व ने हमेशा ही दबाने की कोशिश की। आखिर यह कब तक चलेगा ? ईसाई धर्म के नाम पर मिशनरियों से धन लेने वाले लोग धर्मपरिवर्तन में यकीन तो रखते हैं, लेकिन दलित ईसाई के उत्थान के बारे में नहीं सोचते। प्रभु यीशु और मदर मैरी में आस्था जताने वाले लोग केवल आडम्बर रचते हैं। सच बात तो यह है कि वे ईसाई धर्म के रक्षक नहीं भक्षक हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दलित ईसाई और झोपड़पट्टी वाले एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।*

झुग्गी बस्तियाँ आज दिल्ली की वास्तविकता बन चुकी हैं, जिससे समाज या राजनीतिक पार्टियाँ मुँह नहीं चुरा सकतीं। अब प्रबुद्ध नागरिकों को यह सोचना होगा कि जो उपहार और योग्यताएँ ईश्वर ने हमें दी हैं, वे केवल हमारे उपयोग के लिए ही नहीं हैं, वे दूसरों के उपयोग के लिए भी हैं। हर व्यक्ति

चाहे वह किसी भी जाति या किसी भी धर्म का क्यों न हो, उसे उसका सम्मान से जीने का हक मिलना ही चाहिए। अब लम्बे समय तक समस्याओं से जूझती इस वंचित आबादी को केवल वोटबैंक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक या सामाजिक संदर्भ में वंचितों को उनका वाजिब हक तुरन्त दिया जाना चाहिए। दलित ईसाइयों को एकजुट होकर चर्च नेतृत्व के खिलाफ लड़ना होगा ताकि वे उसके शोषण से बच सकें। सवाल यह है कि दलित ईसाइयों का शोषण कब तक चलेगा।

-(आर.एल.फ्रांसिस, अध्यक्ष, दलित ईसाई स्वतन्त्रता आन्दोलन; धर्म-कर्म अंक; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 08/09/03)

187) धर्मपरिवर्तन : दलित ईसाई और चर्च :- *नई दिल्ली स्थित स्पीकर हॉल, विट्ठल भाई पटेल हाउस में 'पुअर क्रिश्चियन लिबरेशन मूवमेन्ट' के प्रतिनिधियों का एक दिवसीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में धर्मपरिवर्तन के बाद दलित ईसाईयों के सामाजिक, आर्थिक स्थिति पर गहन विचार-विमर्श किया गया।*

आजादी के पाँच दशक बाद भी दलित ईसाइयों की स्थिति दयनीय बनी हुई है और चर्च नेतृत्व ने कभी भी धर्मान्तरण के स्वार्थ के परे देखा ही नहीं है। मूवमेन्ट के अध्यक्ष आर.एल.फ्रांसिस ने कहा कि चर्च नेतृत्व का पूरा जोर दलितों को चर्च के दायरे में लाने का है, न कि उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बदलने या सुधारने का। दलित ईसाइयों के बच्चे निरक्षर और बालमजदूरी करने को मजबूर हैं। धर्मान्तरण आज विवाद का मुख्य केन्द्र बन गया है। दलितों की मुक्ति में चर्चनेतृत्व की कोई रुचि नहीं रही। उत्पीड़न, रोजमर्रा का संघर्ष, देश के विभिन्न भागों में व्याप्त जातिवाद, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय की तलाश और चर्च ढाँचे में अपने अधिकारों को पाने हेतु उनका संघर्ष- इनमें से किसी में भी चर्चनेतृत्व की कोई रुचि नहीं है। यहाँ तक कि चर्चनेतृत्व ईसाइयत के अन्दर ही जातिवाद को समाप्त नही कर पाया है। मूवमेन्ट की उत्तरप्रदेश शाखा के अध्यक्ष श्री महरबान जेम्स ने कहा कि आज दलित ईसाई भुखमरी के कगार पर है। वे दूसरे के खेतों एवं घरों में काम करके अपना जीवन चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चर्च के पास संसाधनों का अंबार लगा हुआ है। श्री बलबीर पुंज, राज्यसभा सदस्य ने मूवमेन्ट के प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि धर्मपरिवर्तन सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति को बदलने का पैरामीटर (पैमाना) नहीं हो रहा। जो दलित लोग मसीहियत की या यीशु की शरण में आए हैं, आज आजादी के पचास साल बाद भी उनकी दयनीय स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि उनके लिए कुछ भी नहीं बदला है।

-(शैनुअल मैसी, धर्म-कर्म अंक; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 25/08/2003)

188) भुखमरी के कगार पर हैं कई थारू परिवार :- *भारत-नेपाल सीमा की उत्तरांचल की तलहटी में निवास करने वाले थारू (राणा) भारत में भोलेपन और अशिक्षा के कारण सभी राजनीतिक दल, गैरराजनीतिक संगठन, ईसाई मिशनरियाँ व व्याापारियों ने इनका जमकर शोषण किया है। सरकार इसके लिए कम दोषी नहीं, जो इनके लिए योजनाएँ तो बनाती है लेकिन वे मात्र कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं, जिसके चलते कई थारू परिवार आज भुखमरी के कगार पर पहुँच गए हैं। ब्रिटिशकाल में थारू जनजाति के भोलेपन को देखकर सरकार ने थारू भूमि की खरीद-ब्रिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। परन्तु आजाद भारत में इनकी जमीनों की खूब लूट मचाई गई। आज से सौ वर्ष पूर्व थारू वर्ग धनी था। परन्तु अब ज्यादातर थारू परिवार गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इनकी दयनीय स्थिति का कारण सभी राजनीतिक दलों, गैरसरकारी संगठनों, ईसाई मिशनरियों और व्यापारी वर्गों द्वारा इन्हें चन्द लालच देकर इन्हें गुमराह कर इनकी जमीन हड़पना रहा है। ज्ञात रहे कि इससे पूर्व तराई का क्षेत्र वनक्षेत्र था। थारुओं ने कठोर परिश्रम करके इस भूमि को स्वर्गभूमि बनाया, जो इस समय सोना उगल रही है, जिससे कि पूरे उत्तरांचल का पेट भर रहा है। सोना उगल रही भूमि को देखकर पश्चिम पाकिस्तान से सिख, पूर्वी पाकिस्तान से बंगाली, भूतपूर्व सैनिक, कुमाऊँ के कुमैया व पूर्वान्चल के लोग यहाँ आकर स्थाई रूप से बस गए। ईसाई मिशनरियों की गिद्ध आँख इनके इर्द-गिर्द घूमने लगी। कई गाँवों में इन्होंने अपनी चर्च बनाई तथा थारुओं की गरीबी, पिछड़ापन, अशिक्षा का लाभ उठाकर इन्हें थोड़ा लालच देकर उनका धर्मान्तरण कर रहे हैं।*

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 24/08/2003)

189) आने वाली नस्लें हमें इसलिए नहीं स्मरण रखेंगी कि हमने कितने मन्दिर बनवाए। हमें इसलिए नहीं याद किया जाएगा कि हमने कितनी मस्जिदों या चर्चों का निर्माण किया। हमें इसलिए भी लोग नहीं स्मरण रखेंगे कि हमने कितने गुरुद्वारे बनवाए। बल्कि हमें लोग इसलिए याद रखेंगे कि हमें उन्हें कितना सुरक्षित और समृद्ध भारत दे सके।
-(राष्ट्रपति श्री ए.पी.जे.अब्दुलकलाम; स्वतन्त्रता दिवस की पूर्वसंध्या पर दिए गए भाषण का अंश; 14/08/2003)

190) सामाजिक न्याय के बिना स्वतन्त्रता अधूरी है।
-(प्रधानमन्त्री अटलबिहारीवाजपेयी; सरकारीविज्ञापन; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 15/08/2003)

191) सामाजिक समता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है।
-(डा. सत्यनारायणजटिया, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्री, भारतसरकार; सरकारीविज्ञापन; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 15/08/2003)

192) बेरोजगारी की मार ने गाँवों की भूमिका पर ही प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। भारत की आत्मा गाँव में बसती है। किन्तु राजस्थान, बिहार, झारखण्ड, बंगाल, उड़ीसा में हजारों नहीं लाखों गाँव हैं, जहाँ पीने को पानी तक नहीं मिलता। इन गाँवों में जाने का कोई रास्ता तक नहीं है। करोड़ों लोग आदिवासी इलाकों में आज भी पाषाणयुग में जी रहे हैं। न पेट में अन्न है न पीने को पानी है। ऐसे में करोड़ों लोग इन प्रदेशों से पलायन करके पंजाब, दिल्ली, हरियाणा या अन्य महानगरों में आजीविका की तलाश में आते हैं और महानगरों की चकाचौंध में गुम हो जाते हैं। जहाँ तक राष्ट्र का सवाल है, विधायिका पूर्णतः भ्रष्ट है और नौकरशाही (प्रशासन) की बात ही करनी व्यर्थ है। संसद में नेताओं की शालीनता आज किससे छिपी है। इन्हीं के सहारे आज देश चल रहा है। संविधान के कोमल अनुच्छेदों का सहारा लेकर एक से एक अपराधी जिनकी जगह जेल में होनी चाहिए, वे हमारे भाग्यविधाता हो गए हैं। लोग हजारों करोड़ रुपये का पशुचारा खाकर भी हीरो बने हुए हैं और दूसरे देश का मीडिया उन जोकरों को हमारा आदर्श बताकर हमारा उपहास कर रहा है। यहाँ बोफोर्स जैसे भी घोटाले हुए। सांसद भी खरीदे और बेचे गए। यहाँ हमारे शासकों ने इमरजेन्सी लगाकर प्रजातन्त्र का गला भी घोंटा और 1984 में प्रजा का नरसंहार भी हुआ। अभी पिछले वर्ष गुजरात में जो भी घटा, उससे हमारे संवेदनशील प्रधानमन्त्री का शिर तो झुका पर जिसके कारण शिर झुका, उसे ही कहा– ''जाओ राजधर्म निभाओ।'' आज वहाँ राजधर्म तांडव के रूप में निभाया जा रहा है। बिहार जैसे राज्य में रोज अपहरण होते हैं। परन्तु हर अपराध की जड़ें महारथियों तक पहुँच जाती हैं। राजनीति में कैसे–कैसे लोग हैं। आज सारा भारत जल रहा है। विदेशी षड़यन्त्र कश्मीर में उफान पर है। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम सब गहरे षड़यन्त्रों के शिकार हैं। उत्तरप्रदेश में अगर एक दलित महिला को अपना जन्मदिन मनाने के लिए इमरजेन्सी फण्ड से अगर 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो तमिलनाडु में एक महिला नेत्री की वाकशैली सारी सीमाओं का अतिक्रमण करती नजर आ रही है। ये कैसी आजादी है? आज सब मस्त हैं। मयखानों में पाँच गुना अधिक भीड़ है। ट्रेनों में कोई टिकट नहीं लेना चाहता। आज अपराध अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ राज्यों में 7 गुना अधिक बढ़ चुके हैं। यह कैसी आजादी? वाह रे आजादी! आज दिल भर आया, स्वयं को रोक न सका। **-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 15/08/2003)**

193) राजनीति के अपराधीकरण और चुनावों में धनबल तथा बाहुबल के प्रयोग पर रातोंरात रोक लगाना संभव नहीं है। अलबत्ता चुनावी चन्दे पर आयकर में छूट देने से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चन्दे और खर्च पर नजर रखी जा सकेगी। निगमित क्षेत्रों और बड़े औद्योगिक घरानों से चन्दे को आयकर में छूट देना भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहनाना नहीं है। **-(अरुणजेटली, कानूनमन्त्री, भारतसरकार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 05/08/2003)**

194) क्या प्रजातन्त्र का यही मतलब है कि आगरा के कुछ तथाकथित बड़े परन्तु वास्तव में अधर्म और कुसंस्कारों में पले, बड़े घरों के युवक अपनी ही शिक्षिका से ही बलात्कार कर दें और सारा प्रशासन अपराधियों के संरक्षण में ही लगा रहे। जो सत्य का खुलासा करे, वही सस्पेन्ड हो जाए, यह प्रजातन्त्र का कौन सा रूप है? कि जीवनरक्षक औषधियों का नकली निर्माण करने वालों का बिजनिस केवल बिहार में जब 50 करोड़ रुपये से 1 अरब तक है, तो सारे राष्ट्र के क्या आँकड़े होंगे? यह सारे का सारा तन्त्र ही सड़ांध मार रहा है कि इनके खिलाफ आप आवाज भी उठाते हैं, तो एक ही प्रतिक्रिया सामने मिलती है– राजनीति के इस हमाम में विपक्ष

और सत्ताधारी दोनों ही नंगे हैं। भारतवर्ष में जो तन्त्र विकसित हो चुका है, वस्तुतः वह एक ऐसा अपराधतन्त्र है, जिसके समक्ष कभी-कभी न्यायपालिका भी अपने को असहाय पाती है। एक न्यायाधीश ने कभी अपने फैसले में टिप्पणी की- ''भारत में दो प्रकार के प्राणी हैं। एक अमीरों और बाहुबलियों के लिए दूसरा गरीबों के लिए। शक्तिशाली अगर जेल भी जाए, तो जेल में भी एअरकण्डीशनर लग जाएँगे। परन्तु गरीब की बात करनी व्यर्थ है। प्रभावशाली की बेटी का अपहरण हो जाए, तो दुर्दान्त आतंकवादियों के समक्ष गृहमन्त्री जैसे लोग भी घुटने टेक दें, पर आम आदमी की बेटियाँ तो मानो प्रताड़ित होकर मरने योग्य ही हैं। मैं नहीं जानता, यह कैसा तन्त्र है?''

-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 05/08/2003)

195) *आर्थिक अभाव और बेरोजगारी से तंग आकर युवा दम्पत्ति ने आज अपने घर पर आत्मदाह कर लिया। दोनों को बुरी तरह से झुलसी हालत में क्षेत्रवासी दून अस्पताल लेकर आए, जहाँ चिकित्सकों के अनुसार दोनों लगभग 95% जल गए हैं। रजत थापा पिछले एक लम्बे समय से बेरोजगार चल रहा था, जिस कारण उसका अपनी पत्नी के साथ भी वाद-विवाद हो जाता था। शादी के बाद उनके तीन बच्चे हो जाने से आर्थिक तंगी और बिगड़ने लगी, जिससे तंग आकर आज जब उनके तीनों बच्चे स्कूल जा रहे थे- दोनों ने अपने कमरे में मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्मदाह कर लिया।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 05/08/2003)***

196) *धनलोलुपता के सामने रेलवे पुलिस की मानवीय संवेदनाएँ किस हद तक खत्म हो गईं हैं, इसका जीवन्त प्रमाण उस समय मिला जब आर.पी.एफ. कर्मियों ने ट्रेन में चने बेचकर जीवनयापन करने वाले एक नेत्रहीन बुजुर्ग से न केवल सामान और रुपये लूट लिए बल्कि उसे मारपीटकर अधमरा कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम खाताखेड़ी का मूल निवासी बुजुर्ग इस्लाम उर्फ सूरदास जन्म से नेत्रहीन है। वह पिछले 20 वर्षों से रुढ़की रेलवे स्टेशन से जाने वाली ट्रेनों में खाने-पीने का सामान बेचकर जीवनयापन करता है। आज सुबह जब इस्लाम नित्य की भाँति सामान बेच रहा था, तो उसे आर.पी.एफ. जवानों ने पकड़ लिया, ट्रेन में सामान बेचने से मना किया। जब इस्लाम ने उनसे रहम की गुहार की, तो पुलिसकर्मी बिफर गए। उन्होंने न केवल सूरदास के सामान और 63 रुपये लूट लिए बल्कि उसे पीट-पीटकर अधमरा कर दिया।*

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 02/08/2003)

197) बैंगलूर की चकाचौंध से दूर ग्रामीण कर्नाटक बहुत गरीब :- *बैंगलूर शहर खूबसूरती से विकसित किया गया है। रहने के लिए यह शहर शानदार है, क्योंकि यहाँ हर चीज उपलब्ध है। यहाँ अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल है, अपार्टमेन्ट वाली इमारतें हैं, जिनके अपने हेल्थक्लब और धोबीघाट हैं। इसके अलावा शहर में मनोरंजन और खरीददारी की ऐसी सुविधाएँ हैं कि आपको कभी मुम्बई या दिल्ली की याद ही नहीं आती। नये शहर के बाजारों में घूमते हुए मैं अक्सर हमारे उन कम सुविधासम्पन्न लोगों से बात कर रही थी, जिन्हें राजनीतिज्ञों ने 'आम आदमी' की संज्ञा दे रखी है। बातचीत के अनुसार जो रहस्योद्घाटन हुआ उसके अनुसार सरकार ने बैंगलूर के बाहर कुछ नहीं किया। दो कन्नरों, शकील और कुमार के शब्दों में किसान के लिए कुछ नहीं किया गया और देहातों में कोई काम नहीं हुआ। मैं उनकी बातों को खारिज कर देती यदि अगले दिन मैं हुबली और वहाँ से बागलकोट तक का तीन घण्टे का सड़क का सफर न करती। यह ऐसी सड़क थी, जो बिहार के स्तर से भी घटिया थी। लेकिन इससे भी अधिक फर्क नहीं पड़ता यदि मैंने कुछ गाँवों में सरकार की उपलब्धियों के सबूत न देखे होते- मैंने ऐसे गाँवों को देखा, जो निर्धनता की मिसाल पेश कर रहे थे। इन गाँवों को देखकर ऐसा लगा मानो मैं विकासशील दक्षिण राज्य के गाँवों में नहीं बल्कि बिहार या उत्तरप्रदेश के गाँवों में घूम रही हूँ। हुबली और बागलकोट के बीच मैंने ऐसे गाँव देखे जो सदियों पीछे रह गए हैं। इन गाँवों में लोग फूस और कीचड़ से बने झोपड़ों में रहते हैं। जहाँ कृषि का एकमात्र उपकरण पुराना हल है। गाँवों में न ट्रैक्टर हैं, न सिंचाई का कोई चिन्ह और न ही जीवनस्तर बताने लायक कोई उपभोक्ता वस्तु। मैंने इस क्षेत्र में एकमात्र उपभोक्ता गतिविधि देखी, जब सूखी टाँगों और लटके मुँह वाले लोगों को प्लास्टिक के पहियों वाली बैरों में पानी ले जाते देखा। कर्नाटक के एक हिस्से में सिर्फ पानी ही एकमात्र उपभोक्ता वस्तु है। यात्रा के दौरान मेरे साथी विजय माल्या नवगठित जनतापार्टी के सदस्य थे। जब मैंने इस भयावह निर्धनता को देखकर आह भरी, तो वे हँसने लगे और कहा- ''हम जिन क्षेत्रों से गुजर रहे हैं, वे बीदर और गुलबर्गा जिलों की तुलना में अधिक सम्पन्न हैं। मैंने आज तक हुबली और बागलकोट के बीच की सड़क जितनी खराब सड़क कहीं नहीं देखी। इससे साबित होता है कि आधारभूत ढाँचा सरकार*

की प्राथमिकताओं में नहीं है। जबकि अच्छी सड़कों के बिना समृद्धि नहीं आ सकती। इन गाँवों को देखकर ऐसा लगता है, जैसे इन्हें जानबूझकर पिछड़ा रखा गया है ताकि वहाँ के लोगों को कभी यह पता न चल सके कि उनको अपने राजनेताओं से क्या माँग करनी चाहिए। रास्ते में उन्हें एक भी सेटेलाइट डिश, टी.वी. एरियल या एस.टी.डी. के लिए पब्लिक टेलीफोन बूथ नहीं दिखा। वर्तमान और पिछली सरकारें क्या करती रहीं? जबाव है– बैंगलूर के विकास को छोड़कर अन्यत्र कुछ नहीं किया। अपनी यात्रा के दौरान मैंने सुना कि विश्वहिन्दूपरिषद के मुखर नेता प्रवीणतोगड़िया पड़ोस में हैं। हमेशा की तरह वह अल्पसंख्यकवाद और मुस्लिमों के खिलाफ बोल रहे थे। यदि उन्हें कुछ दिखाई देता तो शायद वह यह देखते कि कर्नाटक की समस्याएँ घृणा फैलाने से हल नहीं होंगी।

ग्रामीण कर्नाटक को जरूरत है– पीने के पानी की, सड़कों की, सिंचाई और बिजली की और एक ऐसे मुख्यमन्त्री की जो बैंगलूर से बाहर भी देखता हो। ***-(तवलीन, स्तम्भकार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 02/08/2003)***

198) *22 जुलाई को इराक के अपदस्थ तानाशाह सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे उदय और कुशय अमरीकन सेना के साथ उत्तरी इराक के मोसुल शहर में हुई मुठभेड़ में मारे गए। ये दोनों ही बगदाद पर अमरीकी सेना द्वारा कब्जा कर लिए जाने के बाद से ही फरार हो गए थे। अमरीकी सरकार व सेना सद्दाम हुसैन, उसके इन दोनों बेटों तथा अन्य 53 सहयोगियों की तलाश में पिछले एक माह से निरन्तर प्रयास कर रही है। सद्दाम को पकड़ने के लिए ढाई करोड़ डालर तथा उसके दोनों बेटों पर डेढ़-डेढ़ करोड़ डालर का ईनाम घोषित किया गया है। सद्दाम और उसके बेटों को अपने निकटवर्ती लोगों पर भी विश्वास नहीं रह गया था। बताया जाता है कि अपने इसी भय के कारण उदय ने अपने 18 अंगरक्षकों की भी हत्या कर डाली ताकि वे विश्वासघात करके उसे पकड़वा न दें। 36 वर्षीय उदय और 34 वर्षीय कुशय, दोनों ही सद्दाम हुसैन के शासन में क्रूर अधिकारियों के रूप में माने जाते थे। उदय शुरु से ही शराब व औरतों का शोषक रहा है। उसे दूसरों को यातनाएँ देकर आनन्द आता था। बगदाद के कई क्लब उसकी ऐय्याशी के अड्डे थे। खूबसूरत लड़कियों का अपहरण कर उन्हें अपनी वासना का शिकार बनाना उसका व्यसन था। अनेक दुल्हनों का अपहरण कर उनसे बलात्कार किए जाने की घटनाएँ इराकवासियों से सुनी जा सकती हैं। वह अपने नजदीकी से नजदीकी व्यक्ति की हत्या इसलिए करवा देता था कि कहीं उसकी जघन्यता की कहानियाँ बाहर न आ जाएँ। उदय की क्रूरताओं पर उसे सद्दाम ने एक माह जेल में भी डलवा दिया था, परन्तु बाद में उसे फिर महत्त्वपूर्ण पद दे दिया। मँहगे घोड़े रखना, हेलीकाप्टर चलाना, मँहगे कपड़े पहनना व सरकारी बैंकों से अन्धाधुन्ध पैसे निकालकर उड़ाना उसका शौक था। क्रूरता में कुशय भी कम नहीं था। उसने शिया विद्रोह को कुचलने में जो बर्बरता दिखाई थी, उससे इराकी आज भी सिहर उठते हैं। इन दोनों को ही सद्दाम के बाद इराक में क्रूरता का पर्याय माना जाता था।* ***-(विशेष लेख, न्यूजवीक से साभार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 01/08/2003)***

199) शिक्षापद्धति आत्महत्या करने को प्रेरित कर रही है :- *साहिबाबाद में सी.पी.एम.टी. का रिजल्ट खराब होने पर 20 वर्षीया छात्रा द्वारा सल्फास खाकर आत्महत्या करना आज की शिक्षापद्धति का नतीजा है। इन दर्दनाक आत्महत्याओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बहुत जरूरी है। पढ़ाई का बढ़ता बोझ देश के भविष्य के लिए खतरनाक संकेत है। परीक्षापद्धति में भी क्रान्तिकारी सुधार लाए बिना स्थिति में बदलाव असंभव है।*

-(बलरामघावला, आवाज-ए-खबरदार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 01/08/2003)

200) माडल स्कूलों की भरमार जैसे कुकुरमुत्तों की बहार :- *जहाँ एक ओर भारत के राष्ट्रपति भारत को 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने का सपना देख रहे हैं, वही दूसरी ओर राष्ट्र का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों की शिक्षा का स्तर अन्धकार में है। शहर में परचून की दुकानों की तरह गली-गली में खुले माडल स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ कमाई है। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि यहाँ नर्सरी से लेकर आठवीं तक जहाँ बच्चे की पढ़ाई का नाजुक समय होता है, जिसमें मूलरूप से बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और शारीरिक विकास का समय होता है, वहीं दु:ख की बात यह है कि इन स्कूलों में ज्यादातर शिक्षक आठवीं, नौंवी, दसवीं फेल तक हैं। स्कूल के मालिक अपने फायदे के लिए इन्हें रखते हैं, क्योंकि ये पाँच सौ से आठ सौ रुपये तनख्वाह में भी काम कर लेते हैं। इनके पास कोई प्रशिक्षण या अनुभव भी नहीं होता। सरकार से हमारा अनुरोध है कि ऐसे स्कूलों की मान्यता पर रोक लगाए और श्रेष्ठ स्कूलों द्वारा बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाए।* ***-(बलवन्त रावत, आवाज-ए-खबरदार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 01/08/2003)***

201) साउदी अरब में मृत्युशैया पर पड़ा युगांडा का पूर्व तानाशाह ईदी अमीन अपने दुश्मनों के शिर काटकर फ्रिज में रखा करता था। इतना ही नहीं एक बार अपने मेहमानों को उसके प्रति बगावत की बात नहीं सोचने की चेतावनी देने के लिए अमीन ने इन शिरों को खाने की मेज पर भी सजाया था। पिछले 25 वर्षों में साउदी अरब में आरामदेह निर्वासित जीवन बिताने के बाद बीमार अमीन शायद अपने अपराधों की सजा पाए बिना ही मर जाएगा। 75 वर्ष से भी अधिक उम्र पार कर चुका अमीन अपराधों के मुकदमों का सामना किए बगैर छूट जाने वाला एकमात्र तानाशाह नहीं है। हैती में 15 वर्ष के क्रूर शासन के बाद जनता के भारी विरोध आन्दोलन के पश्चात 1986 में देश छोड़कर भागा जीन क्लाव्द भी इन दिनों फ्रांस में अपनी लाल रंग की फेरारी कार में घूमता देखा जा सकता है। इथियोपिया के आतंक का पर्याय रहा शासक मेंगीस्तू हेल मरियम इन दिनों जिम्बाबवे में आराम की निर्वासित जिन्दगी बसर कर रहा है। अमीन से भी क्रूर रहा युगांडा का मिल्टन आबोटे इन दिनों जाम्बिया में है। जबकि जार्जियों को शरण देने वाला पैराग्वे का अल्फ्रेडो स्ट्रोएसर इन दिनों ब्राजील में है। सिएरालियोन में युद्ध अपराध के लिए वांछित लाइबेरिया का चार्ल्स टेलर नाइजीरिया में शरण लिए हुए है। **-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 01/08/2003)**

202) जनता ही अब देश को वर्तमान संकट से उबार सकती है, जनता की मौलिक समस्याओं से किसी को सरोकार नहीं :- आज जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियाँ मैदान में हैं, उनका जनता की मौलिक समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। उनका लक्ष्य सत्ता पर कब्जा करना और अपने स्वार्थों की पूर्ति करना है। प्रधानमन्त्री हर साल एक करोड़ रोजगार मुहैया कराने की बात करते हैं और दूसरी ओर बेरोजगारों की फौज बढ़ती ही जाती है। इसी कारण आज की युवा पीढ़ी निराश और हताश है। स्थिति अत्यन्त ही गंभीर है। सरकार अपने कर्मचारियों की संख्या में 10 प्रतिशत कटौती करके अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारना चाहती है। दूसरी तरफ बजट का 89 प्रतिशत कर्जों की अदायगी में चला जाता है। केवल 11 प्रतिशत विकास कार्यों के लिए बचता है। अगले 10-5 वर्षों में विकास के लिए कोई पैसा नहीं बचेगा। दुनिया के सारे विकसित देश मिलकर भी भारत की मदद करें तो भी बढ़ते हुए संकट से उबरना मुश्किल है।

देश की राजनीतिक स्थिति यह है कि इस समय दो मोर्चे आमने-सामने हैं। लेकिन दोनों एक-दूसरे के विकल्प नहीं हैं, क्योंकि दोनों एक ही नीति का अनुसरण करने वाले हैं। इस समय जो नेतृत्व है, उसके लिए किसी तीसरी शक्ति का गठन असंभव है, लेकिन यदि जनता एक होकर खड़ी हो जाए, तो जनता की पहल से देश लोकतन्त्र के रास्ते पर लौट सकता है। आज की परिस्थितियों में भी यह संभव है। हमें आशा है कि जनता एक बार फिर अपनी अन्तर्निहित शक्ति का प्रदर्शन करेगी और देश को संकट से उबारने के लिए कटिबद्ध होगी। (विशेष लेख) **-(चन्द्रशेखर, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, भारतसरकार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 30/07/2003)**

203) मानवाधिकार का वास्तविक उद्देश्य रंग, जाति, धर्म व सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्य को लेकर मानव के बीच कोई भेदभाव न करना है। जबकि वर्तमान परिदृश्य में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, न्याय व अधिकार के क्षेत्र में मानवता को बाँटा जा रहा है। मानवाधिकार आन्दोलन की वास्तविक शुरुआत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय विश्वयुद्ध से हुई। जब 16 वर्ष बाद भी यूरोपीय राष्ट्र सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार की बहाली के पक्षधर नहीं थे, तब 4 दिसम्बर 1950 में यू.एन.ओ. द्वारा मानवाधिकार के विषय में प्रथम प्रस्ताव पास किया गया था। इस प्रयास में कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन सामने आए। मानव अधिकारों से व्यक्ति को सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक भावनाओं को समझने में सफलता मिली है, जिसके प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिगत हुए हैं। आज मानवाधिकार के ही प्रभाव से विश्व की कुल 66% जनता प्रेम की स्वतन्त्रता का लाभ उठा रही है व लगभग 37 हजार गैरसरकारी संस्थाएँ इस प्रयोग में कार्यरत हैं। आज मानव को विश्वभर में टेलीविजन और प्रकाशन के क्षेत्र में मिली हुई सुविधा सामाजिक अधिकारों की ओर संकेत करती है। एक अच्छी शासन व्यवस्था में मानवाधिकार से ही अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं।

आज समाज में महिलाशिक्षा का अभाव और दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना भी मानवाधिकार के मार्ग में बाधक है। उन्होंने आम जीवन में मानवाधिकार की रक्षा के लिए प्रशासन को चुस्त व दुरुस्त रहने पर भी जोर दिया।

-(एम.एम.वैंकटचलैया, मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 30/07/2003)

204) *उग्रवादी संगठन रोजगार की तलाश में भटक रहे गरीब और मध्यम वर्ग के युवाओं को संगठन में भर्ती करने के साथ ही पाक अधिकृत कश्मीर से अपनी उग्रवादी गतिविधियाँ बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान के प्रमुख साप्ताहिक 'दि फ्राइडे टाइम्स' ने लिखा है कि युवा जेहादी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। जब उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता, तो वे उग्रवादी संगठनों में शामिल हो जाते हैं, जो उन्हें भोजन और आसरे के साथ ही शहादत के जरिए जन्नत नसीब कराने का सपना दिखाते हैं।*

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 28/07/2003)

205) देश के प्राइमरी स्कूलों की स्थिति वाकई खराब :- *नवोदय विद्यालय की डिजाइनिंग करके पूरे देश में नाम कमाने वाले सी.बी.आर.आई. के निदेशक डा. वी.के.माथुर को इस बात पर बेहद अफसोस है कि बड़ी मेहनत से तैयार किए गए उन भवनों की अब सही देख-रेख नहीं हो रही है। प्राइमरी विद्यालयों की हालत काफी खराब है। वहीं इन स्कूलों के भवनों पर खर्च करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। इसलिए अभी भी देश में करीब ढाई लाख प्राइमरी विद्यालयों की कमी है।* ***-(दैनिकजागरण, देहरादून; 26/07/2003)***

206) *देश में प्राथमिक शिक्षा की हालत लगातार बदतर हो रही है। करोड़ों रुपये पानी की तरह बह रहे हैं और नतीजे बदतर हैं। केन्द्र की वाजपेयी सरकार ने 86वें संशोधन के जरिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिलाया है पर सरकारी स्कूल प्रायः खाली हैं। राज्य सरकारें स्कूल चलो अभियान चलाती हैं। अभियान टाँय-टाँय फिस्स हो रहे हैं। अभिभावक बेसिक सरकारी स्कूलों से मुँह बिराते हैं। गरीब कमजोर बच्चों के अभिभावक भी कम वेतन वाले अप्रशिक्षित अध्यापकों से सम्बन्धित मँहगे पब्लिक स्कूलों में ही मँहगी फीस देकर बच्चों को पढ़ाना बेहतर मान रहे हैं। शिक्षा के लिए जागृति बढ़ी है। परन्तु सरकारी बेसिक शिक्षा प्रबन्धन के प्रति घृणा। जनता और संस्कृति की गुणवत्ता ही किसी राष्ट्र के लिए मूल प्राण होती है। शिक्षा संस्कार देती है, विनय देती है, ज्ञान देती है, व्यक्ति और राष्ट्र के अन्तर्सम्बन्ध बताती है। प्राथमिक शिक्षा ही किसी व्यक्ति की प्राणऊर्जा में बीज बनकर विराट होती है। वैदिक ऋषियों ने अशिक्षा को तमस या अन्धकार कहा है और शिक्षा को ज्योति या प्रकाश कहा है। लेकिन सारी दुनिया को सुशिक्षित और ज्ञानी बनाने का दावा करने वाले भारत की अपनी प्राथमिक शिक्षाव्यवस्था अपाहिज है। भारत में तरह-तरह के फूल हैं। यों सभी बच्चे भारतमाता की सन्तान हैं, भारत का भविष्य हैं। परन्तु बड़ों के बच्चों के लिए बड़े स्कूल हैं। यहाँ अँग्रेजी में पढ़ाई होती है। इनकी किताबें अँग्रेजी में हैं। इनके महापुरुष अलग हैं। जबकि गरीबों के लिए अलग स्कूल हैं। मास्साहब मोटी तनख्वाह पाते हैं, स्कूल कम आते हैं। यहाँ मातृभाषा पढ़ाई जाती है। पढ़ाये जाने के विषय राज्य सरकारें तय करती हैं। इन स्कूलों के आधे से ज्यादा बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तरप्रदेश में 56 फीसदी बच्चे बेसिक शिक्षा पूरी करने के पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। केन्द्र में बीते वर्ष उत्तरप्रदेश को सर्वशिक्षा अभियान की दुरुस्ती के लिए 800 करोड़ रुपये दिए। राज्यसरकार के बोदे अधिकारी यह रकम ठीक से खर्च ही न कर पाए। केन्द्रीय मानवसंसाधन विभाग ने राज्य परियोजना द्वारा माँगे गए 1100 करोड़ रुपयों के बदले 1200 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। यहाँ अध्यापकों की स्थिति भयावह है। उपस्थिति और भी चिन्ताजनक है। परिस्थिति यह है कि 40 बच्चों पर 1 अध्यापक का अनुपात गड़बड़ाया है। एक अध्यापक वाले स्कूलों में बच्चे दिनभर हुल्लड़ करते हैं। मुंशी जी कभी-कभार आकर दस्तखत मारते हैं। फिर दिखाई ही नहीं पड़ते। अध्यापकों की यूनियनें तगड़ी हैं। वे वेतनवृद्धि, डी.ए. और सुखसुविधाओं को लेकर बड़ा लड़ाकू रुख अपनाती हैं पर शैक्षिक गुणवत्ता के नाम पर वे कोई कारगर प्रस्ताव भी नहीं ला पाती हैं। मुस्लिम अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाते हैं। उनका पाठ्यक्रम अलग है।*

अध्यापन भारत का आदरणीय कर्तव्य है लेकिन कर्तव्यबोध का कहीं पता नहीं। राजनीति यहाँ भी अपना गुल खिला रही है। अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए बनी शिक्षामित्रयोजना शिक्षाव्यवस्था पर भद्दा मजाक है। गाँव के तगड़े परिवारों की बहू-बेटियाँ शिक्षामित्र हैं। वे सिर्फ मानदेय लेते हैं। शिक्षा से उनकी कोई मित्रता है ही नहीं। भारत में शिक्षा की प्यास पुरानी है। अँग्रेजी राज्य में 1935 में शिक्षासम्बन्धी केन्द्रीय परामर्श बोर्ड बना। लेकिन शिक्षा 'बड़ों' (अमीरों) तक सीमित रही। भारत के अपने सत्ताधीश भी आजादी के 37 साल तक देश के लिए कोई शिक्षानीति नहीं बना सके। बेशक संविधान के

नीतिनिर्देशकतत्त्वों (अनुच्छेद 45) में राज्य पर 10 साल के भीतर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी डाली गई परन्तु राष्ट्रीय शिक्षानीति 1986 में बनी। यह 1992 में संशोधित भी हुई। सातवीं व आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं में बेशक प्राथमिक शिक्षा को ठीक-ठाक प्राथमिकता दी गई। 1992 की संशोधित शिक्षानीति कार्ययोजना में 14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षाव्यवस्था की शपथ ली गई। नवीं पंचवर्षीय योजना (1997 से 2002) में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के संकल्प व्यक्त किए गए। वर्ष 2005 तक देश को सम्पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य भी लिया गया। प्राथमिक शिक्षा ही राष्ट्रजीवन की बुनियाद है। बुनियाद ही गड़बड़ है।

-(हृदयनारायणदीक्षित, उ.प्र.सरकार के पूर्व मन्त्री; दैनिकजागरण देहरादून, 26/07/2003)

207) संविधान की कसौटी पर सरकार :- *हमारे ऋषियों ने किसी राज्य की महानता उसके आकार तथा धनसम्पत्ति से नहीं बल्कि राज्य में नागरिकों की भलाई के लिए होने वाले लोकप्रशासन में न्याय तथा न्यायसंगत कार्यों से आँकी थी। इसलिए जब किसी राज्यसत्ता के कार्यों का मूल्यांकन होगा, तो यह देखा जाएगा कि उसने समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना और लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए अपनी परम्पराओं एवं संवैधानिक व्यवस्था को किस सीमा तक किस तरह से लागू किया है। आज जब हम संविधान की कसौटी पर अपनी राज्य की सत्ता का मूल्यांकन करते हैं, तो कोई बहुत आशाजनक तस्वीर सामने नहीं आती है। आर्थिक सुधार और वाणिज्यिक वैश्वीकरण की नीतियों से सामाजिक विषमता घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। एक राष्ट्र के रूप में भारतीय संविधान एक ऐसी समाजवादी व्यवस्था के ढाँचे का निर्धारण करता है, जिसमें सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय सुलभ हो। राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में न्यायोचित व्यवस्था हो। इसका यह अर्थ है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी नीति का अनुसरण करे कि सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका निर्वाह के उपयुक्त साधनों का अधिकार प्राप्त हो। समाज में भौतिक संसाधनों पर इसप्रकार स्वामित्व एवं नियंत्रण हो कि उनका वितरण सामान्य हित की सुरक्षा कर सके। आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस ढंग से हो कि धन एवं उत्पादन के साधनों का कुछ एक व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रीकरण न हो और न ही जनसाधारण का अहित हो। श्रमिकों, स्त्रियों एवं पुरुषों और छोटी आयु के बच्चों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरुपयोग न हो और नागरिकों को ऐसे पेशों को अपनाने के लिए बाध्य न होना पड़े जो उनकी आयु अथवा शक्ति के अनुकूल न हों। बच्चों एवं नवयुवकों की शोषण से रक्षा की जाए। ये संविधान में वर्णित ऐसे नीतिनिर्देशक सिद्धान्त हैं कि राज्य को विधिनिर्माण एवं निर्णयप्रक्रियाओं में सदैव ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सामाजिक विषमता बढ़ रही है। देश की पूँजी और संसाधनों का कुछ लोगों में केन्द्रीकरण होता जा रहा है।*

संविधान के नीतिनिर्देशकतत्त्व नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं और वे उन आर्थिक, सामाजिक एवं न्यायिक आदर्शों का उल्लेख करते हैं, जिन्हें व्यवहार में लाना राज्य का कर्तव्य है। भारतीय संविधान न केवल राजनैतिक प्रजातन्त्र के रूप में निर्धारण करता है, बल्कि एक आर्थिक प्रजातन्त्र के आदर्शों का प्रस्तुतिकरण भी करता है, जिसका अर्थ है- भारत में एक समाजवादी समाज की स्थापना की जाए। संविधान में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि राज्य अनुच्छेद (46) के अनुसार बड़ी सावधानी एवं तत्परता के साथ समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की सुरक्षा करेगा और उनको सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा। इसका मतलब साफ है कि संविधान यह मानकर चलता है कि धन एवं उत्पादन के साधन कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रित न हों और भौतिक संसाधनों के ऊपर इसप्रकार से स्वामित्व एवं नियंत्रण हो कि आर्थिक प्रगति का सब नागरिकों को समान लाभ हो। भारत में समाजवादी समाज के स्वरुप का यही सैद्धान्तिक मूलाधार है। आर्थिक न्याय का सिद्धान्त उस समाज के चिन्तन का प्रतिफल है, जिसने भारत में गरीबी एवं आर्थिक कुप्रबन्धन की समस्या की ओर तात्कालिक ध्यान देने पर बल दिया, जो एक क्रान्तिकारी प्रेरणा के समकक्ष है।

भारतीय संविधान में समाजवादी सहमति है। इसीलिए राज्य के नीतिनिर्देशकतत्त्वों के अन्तर्गत ऐसी सामाजिक व्यवस्था की बात कहीं गई है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि वह लोककल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा एवं विभिन्न कार्यों में लगे हुए लोगों के समूह के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं के अवसर की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।

-(निरंकार, स्तम्भलेखक; दैनिकजागरण, देहरादून, 26/07/2003)

208) *बहुमत के आधार पर कानून तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन देश नहीं चलाए जा सकते। देश सहमति के आधार पर ही चलता है। जहाँ तक समान नागरिक आचार संहिता लागू करने का सवाल है, यह तभी लागू की जानी चाहिए जब समाज की सहमति हासिल हो जाए। कोई चीज जबरजस्ती थोपने से तनाव पैदा होगा। दूसरे धर्म की बात छोड़िए, एक ही धर्म की अलग-अलग जातियों में अलग-अलग परम्पराएँ हैं। उन परम्पराओं को कानून के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता। उच्चशिक्षा मँहगी किया जाना समाज के कमजोर वर्ग के लड़के-लड़कियों को उच्चशिक्षा से वंचित किए जाने की साजिश है।*

-(पूर्व प्रधानमन्त्री विश्वनाथप्रताप जी; दैनिकजागरण, देहरादून, 25/07/2003)

209) समान नागरिक संहिता :- *सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 118 को असम्वैधानिक करार देते हुए संसद को समान नागरिक संहिता के निर्माण का जो निर्देश दिया, वह एक ऐतिहासिक निर्णय है। संसद को इस निर्णय पर गंभीरतापूर्वक विचार करना ही चाहिए। यह विचार इस दृष्टि से होना चाहिए कि कैसे इस मुद्दे पर आम राय कायम हो और समान नागरिक संहिता का निर्माण किया जा सके। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद (44) स्पष्ट रूप से समान नागरिक संहिता के निर्माण की बात करता है और ऐसी संहिता का निर्माण राष्ट्रीय एकता को और अधिक बल प्रदान करने में भी सहायक होगा। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने यह बिल्कुल सही कहा कि सभी धार्मिक समुदायों पर शासन करने वाली एक समान संहिता होनी ही चाहिए। किन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का विरोध शुरु हो गया। यह कुछ और नहीं बल्कि परोक्षरूप से सर्वोच्च न्यायालय और साथ ही संविधान की अवहेलना ही है। निश्चितरूप से यह अवहेलना मात्र इसलिए की जा रही है ताकि साम्प्रदायिक आधार पर वोटबैंक की जो राजनीति हो रही है, वह जारी रह सके। यह स्थिति तब है, जब विश्व के तमाम देशों में समान नागरिक संहिता लागू है। यही नहीं स्वयं भारत में गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। आखिर जब देश के एक प्रान्त में समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है, तो फिर सारे देश में क्यों नहीं। निस्सन्देह ऐसा भी नहीं है कि गोवा में केवल एक समुदाय या एक मजहब के लोग ही रहते हों। जब गोवा के मुसलमानों को समान नागरिक संहिता स्वीकार है, तब फिर देश के कुछ मुस्लिम संगठन और साथ ही राजनीतिक दल समान नागरिक संहिता का विरोध किस आधार पर कर रहे हैं। यह दुःखद है कि राजनीतिक दल जानबूझकर यह समझने के लिए तैयार नहीं हैं कि समान नागरिक संहिता का निर्माण न केवल राष्ट्र के लोगों को एकता और समानता के मजबूत धागे में बाँधेगा बल्कि विभिन्न समुदायों में व्याप्त बुराइयों को भी दूर करने में सहायक होगा। यह ऐसा मुद्दा नहीं है, जिसे ठण्डे बस्ते में डाला जाए। यह तो वह मुद्दा है जिस पर यथाशीघ्र विचारविमर्श किया जाना चाहिए। वैसे भी इस मामले में बहुत देरी हो चुकी है और इस देरी के अनेक दुष्परिणाम राष्ट्र को भोगने पड़ेंगे।* ***-(सम्पादकीय, दैनिकजागरण, देहरादून, 25/07/2003)***

210) *मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले के मुरलीखेड़ा गाँव में अतिकुपोषित बच्चों के पेट पूरे शरीर के वजन से भी भारी हो गए हैं। इसीलिए इस जगह का नाम ही बड़े पेट का गाँव पड़ गया है। इस गाँव में 60-70 आदिवासी परिवार रहते हैं। यहाँ एक से पाँच वर्ष के 30 बच्चे हैं, जो हाथ-पैर के वजन से अधिक पेट का भार लिए घूमते हैं। जिला चिकित्सालय के शिशु रोग विशेषज्ञ डा. रवि गर्ग ने बताया कि इस बीमारी का कारण कुपोषण है। वनसुरक्षा समिति मुरलीखेड़ा के अध्यक्ष नानकराम ने बताया कि बच्चों में कुपोषण का कारण गरीबी और अशिक्षा है। आदिवासी लोग अशिक्षा के कारण बच्चों का उचित इलाज न कराकर उन पर झाड़-फूँक, डमा और चंचुआ करते हैं। चंचुआ प्रक्रिया के दौरान हँसिए को लाल गरम कर पेट पर रख दिया जाता है। गाँव की 45 वर्षीय महिला द्रौपदीबाई ने बताया कि उसके बच्चे भगवान भरोसे जी रहे हैं। बच्चों को अच्छा खाना खिलाने के लिए पैसे और साधन नहीं है। उसने गरीबों और गाँवों के लिए संचालित योजनाओं के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 22/07/2003)***

211) *विगत दिनों मेरठ पुलिस ने कच्छा-बनियानधारी बदमाशों के आतंक से बौखलाकर अपनी झेंप और नाकामी मिटाने के उद्देश्य से तीन निर्दोषों को जिस प्रकार मौत के घाट उतार कर पुलिसविभाग की छवि धूमिल की और जनता में पुलिस विभाग के प्रति अविश्वास की भावना बढ़ाई वह निन्दनीय है। यह एक अकेली घटना नहीं है। पुलिस ने न जाने कितने निर्दोष, निरपराध लोगों की हत्या की है। कोई व्यक्ति निर्दोष हो और फर्जी मुठभेड़ के नाम पर उसकी हत्या कर दी जाए, तो यह कैसा न्याय है। पता नहीं मानवाधिकार आयोग क्यों धृतराष्ट्र बना बैठा*

है। पुलिस निर्दोषों को घरों में से, रास्तों में से उठाकर हत्या करती जा रही है। उस पर आयोग कुछ करने में असमर्थ है। मेरठ की घटना एक अकेली घटना नहीं। इससे पूर्व की न जाने कितने शरीफ, निर्दोष लोगों की फर्जी मुठभेड़ें दिखाकर हत्या कर दी गई। झूठी वाहवाही लूटने के चक्कर में न जाने कितनी बहनों का शृंगार पोंछा गया। कितने लोगों की आँख का तारा, सहारा छिन गया। कितने मासूम बच्चों के शिर से बाप का साया उठ गया। कैसी विडम्बना है? कैसा लोकतन्त्र है? कैसा न्याय है? जो अपराधी हैं, वे मौज मार रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं।
-(डा. सत्येन्द्रकुमारशर्मा, चाँदपुर, बिजनौर; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 15/07/2003)

212) *'हिन्दुत्व की संकीर्ण भावना' पार्टी (भाजपा) को स्वीकार नहीं है। पार्टी के मुस्लिम विरोधी छवि के कारण उसकी प्रशासनिक क्षमता को नुकसान हो रहा है। कोई भी हमें दुश्मन जैसा न माने। मुस्लिम विरोधी छवि से हमारी शासन क्षमता और योग्यता को भी नुकसान होता है। लोग सड़क, गरीबी और कृषि को लेकर चिन्तित हैं।*
-(उपप्रधानमन्त्री लालकृष्ण आडवाणी; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 14/07/2003)

213) *भारत के संविधान में जो सेक्यूलिरिजम का सिद्धान्त है, मेरी सलाह है कि इसे सारे राष्ट्रों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। सहिष्णुता एक वैश्विक आदर्श बननी चाहिए। इसका विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को मानने वाले लोगों पर एक दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और वह शान्ति और सहअस्तित्व की भावना को दूर-दूर तक फैला सकेंगे।*
-(प्रधानमन्त्री अटलबिहारीवाजपेयी; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 11/07/2003)

214) *इस सवाल पर गंभीरता से विचार किया जाए कि सार्वजनिक पदों पर आसीन राजनीतिज्ञों के लिए भी अनिवार्यतः रिटायरमेन्ट की कोई आयु तय होनी चाहिए या नहीं। कुछ इने-गिने लोगों के अलावा अथवा निजी कामधन्धों को छोड़कर हर क्षेत्र में सेवानिवृत्ति की एक आयु निर्धारित है। यदि आप एक निश्चित आयु हो जाने के बाद एक लिपिक तो क्या चपरासी रहने के लिए भी फिट नहीं रह पाते तो फिर इस बात के पक्ष में क्या तर्क दिया जा सकता है कि आप एक मन्त्री अथवा मुख्यमन्त्री अथवा प्रधानमन्त्री पद पर आसीन रहने के लिए फिट हैं। इस मुद्दे का केन्द्रविन्दु यह है कि राजनीति में बढ़ती आयु के बावजूद लोगों के इसमें लिप्त रहने का सिलसिला कहाँ तक कायम है। हमारे देश में वाजपेयी ही प्रधानमन्त्री पद पर आसीन सर्वाधिक वयोवृद्ध व्यक्ति नहीं हैं। बल्कि मोरारजी देसाई तो तब 82 वर्ष के थे, जब वह प्रधानमन्त्री बने। उनके कार्यकाल में उनके दो वरिष्ठतम सहयोगी भी ऐसे ही वयोवृद्ध थे। यह सिलसिला केन्द्र तक ही सीमित नहीं है। ज्योतिबसु तब वाजपेयी से भी कई वर्ष अधिक आयु के थे, जब उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री का पद छोड़ा। अब 90 वर्ष के हो जाने पर भी वह मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं। अन्य दलों में कई ऐसे प्रभावी नेता हैं, जो जीवन के 70 के दशक को छू रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के एक अखबार द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार राज्यपालों में से जो सबसे कम आयु वाले हैं, वह 71 वर्ष की आयु के हैं और ज्यादातर 80 वर्ष का आँकड़ा छूने को हैं। जबकि दो लोग 81 वर्ष की आयु वाले हैं। राज्यपालों में से वृद्धतम राज्यपाल 85 वर्ष के हैं। ये महामहिम कभी एक राज्य की राजधानी में आसन जमाते हैं तो कभी दूसरे राज्य में आसीन कर दिए जाते हैं। रिटायर होने की चर्चा तो इस पर भी सामने नहीं आती। ऐसा भी नहीं है कि राज्यपाल के पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति के लिए असाधारण योग्यता की कोई शर्त है। बढ़ी आयु का यह सिलसिला तो चाहे उच्च सम्वैधानिक पद हों या सरकारी सत्तापद, अति की स्थिति को छू रहे हैं। परिणामतः ऐसे दृश्य आम हैं, जब सदनों में किसी विधेयक पर बहस होती है, तो कई बार वयोवृद्ध मन्त्री तो क्या प्रधानमन्त्री तक भी ऊँघते पाए गए हैं। सार्वजनिक समारोहों में ऐसे दृश्य नजर आते हैं जबकि राज्यपाल अपने शयनकक्षों में विश्राम करना ही बेहतर मानते हैं।* ***-(सुमेरकौल, स्तम्भकार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 10/07/2003)***

215) *आजादी के इतने दशक बाद भी महिलाओं को विशेषकर मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा का अधिकार पूरी तरह से नहीं मिला है। शिक्षा के लिए उसे कई प्रकार की चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। कहीं पुरुषवादी मानसिकता तो कहीं धार्मिक कट्टरवाद के कारण अनेक लड़कियों को या तो पढ़ने का अवसर नहीं मिलता या मिलता भी है तो पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर चिन्ताजनक स्तर पर है, जो अनेक पिछड़े देशों की तुलना में भी कम है। यद्यपि 1988 के बाद कुछ मुस्लिम समुदाय के बड़े नेताओं, मौलवियों, मुल्लाओं, शिक्षाविदों ने मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के लिए सतत् प्रयास किए। उनके लिए बेहतर वातावरण का निर्माण किया, विद्यालय खुलवाए। लेकिन मुस्लिम महिलाओं को साक्षरता की दिशा में अपेक्षित सफलता नहीं मिली।* ***-(राधारस्तोगी, विमैन फीचर्स सर्विस; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 08/07/2003)***

216) उत्तरांचल में हाईस्कूल एवं इण्टर के परीक्षापरिणाम निकलते ही कई छात्र-छात्राओं द्वारा आत्महत्या एवं आत्महत्या के प्रयासों से सरकार पर निर्भर राज्य की लचर शिक्षाव्यवस्था की पोल खुल गई। परिणाम घोषित किए जाते ही कोटद्वार गढ़वाल के नन्दपुर गाँव की तीन लड़कियों ने जहर खा लिया। इनमें से भगवती तथा रेखा को तो डाक्टरों ने बचा लिया लेकिन 16 वर्षीय कविता की जान परीक्षापरिणाम की भेंट चढ़ ही गई। गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल में एक दर्जन से अधिक बच्चों ने फेल होने पर इसी तरह आत्महत्या के प्रयास किए। जबकि कसूर छात्र-छात्राओं का कम किन्तु व्यवस्था का अधिक था। क्योंकि उन्हें पढ़ाने के लिए स्कूल में शिक्षक ही नहीं थे। राज्य के शिक्षापरिषद द्वारा संचालित इस वर्ष की हाईस्कूल परीक्षा में कुल 190344 परीक्षार्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 109491 फेल हो गए। जो 80853 परीक्षार्थी पास हुए, उनमें से भी 34420 तृतीय श्रेणी तथा 43429 द्वितीय श्रेणी में पास हुए। जबकि 60% से अधिक अंक पाने वालों की संख्या मात्र 4677 रही। बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों के छात्रों के फेल होने तथा आत्महत्या के लिए मजबूर होने का कारण शिक्षकों का भारी अभाव माना जा रहा है। प्रदेश के शिक्षामन्त्री नरेन्द्र भण्डारी के अनुसार राज्य के सरकारी हाईस्कूलों में 2199 तथा इण्टर कालेजों में 2183 शिक्षकों की कमी है। यह कमी भी विज्ञान एवं गणित जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों की है। शिक्षकों की कमी के साथ ही राज्य सरकार शिक्षकों की गैरहाजिरी की समस्या से भी जूझ रही है। सुदूरवर्ती स्कूलों, कालेजों में शिक्षकों द्वारा महीने में केवल एक दिन सारे माह की हाजिरी लगाने या केवल वेतन लेने के लिए स्कूल पहुँचने की शिकायतें आम हैं। ऐसी स्थिति में पहाड़ी राज्य के विद्यार्थियों का फेल होना स्वाभाविक ही है। प्रदेश के प्राइमरी एवं मिडिल स्कूलों में आज की तारीख में 6351 शिक्षकों की कमी है। **-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 02/07/2003)**

217) देश की अर्थनीतियाँ सम्पन्न वर्ग की पोषक और गरीबों की शोषक हैं :- अर्थशास्त्रियों के एक सम्मेलन में कहा गया है कि देश की वर्तमान अर्थनीतियाँ कल्याणकारी नहीं हैं। ये पूरी तरह सम्पन्न वर्ग की पोषक हैं तथा इनमें गरीबवर्ग की उपेक्षा की गई है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में आयोजित इण्डियन एकोनॉमिक एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अर्थशास्त्रियों ने यह विचार व्यक्त किए। इस बैठक में देश की वर्तमान बिगड़ती आर्थिक परिस्थितियों पर अर्थशास्त्रियों ने गंभीर चिन्ता व्यक्त की।

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 30/06/2003)

218) उत्तरप्रदेश के बिजनौर जनपद में 5000 से अधिक बालक जहाँ मजदूरी कर परिवार का आर्थिक सहारा बने हुए हैं, वहीं लगभग 80000 बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। शिक्षाविभाग के सूत्रों ने बताया- सर्वशिक्षा अभियान के तहत जनपद में कराए गए परिवार सर्वेक्षण की रिपोर्ट में रहस्योद्घाटन किया है कि 5564 बालक-बालिकाएँ स्कूल जाने की उम्र में मजदूरी करके बालश्रम उन्मूलन कार्यक्रम की असलियत बता रहे हैं।

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 21/06/2003)

219) लड़कियाँ आगे ही आगे :- जब भी परीक्षापरिणाम सामने आते हैं, लड़कियाँ आगे होती हैं। बहुधा वे सर्वप्रथम भी होती हैं। प्रायः प्राप्तांकों के प्रतिशत तथा मेरिटसूची में भी शीर्ष स्थानों पर ही रहती हैं। पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न राज्य सरकारों के बोर्डों की पाँचवीं, आठवीं, मैट्रिक, इण्टर की परीक्षाओं में भी प्रथम स्थान व मेरिटसूची में आने वाली लड़कियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। सी.बी.एस.ई., संघ अथवा राज्य लोकसेवा आयोगों की आई.ए.एस., पी.एस.सी. व अन्य परीक्षाओं में भी लड़कियाँ मेरिट में शीर्ष स्थानों पर आने लगी हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों के परिणामों में भी लड़कियाँ ही मेरिटसूची के शीर्ष पर दिखाई देती हैं।

-(विजय, सम्पादकीय; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 17/06/2003)

220) संविधान के नीतिनिर्देशक तत्त्वों में भी इसके प्राक्कथन के मूलदर्शन की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद-36 से अनुच्छेद-51 तक नीतिनिर्देशक तत्त्वों को समाहित किया गया है। इसे मैं संविधान की आत्मा कहता हूँ। इनमें संविधान का यथार्थ बोध है। यह भारत का वास्तविक दर्पण है। राष्ट्र का स्वरूप कैसा हो, इसकी इसमें बड़ी सुन्दर कल्पना की गई है। कल्पना शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया कि नीतिनिर्देशक तत्त्वों को हम कोर्ट में नहीं ले जा सकते। हम किसी भी उच्च न्यायालय

में यह याचिका दायर नहीं कर सकते कि अनुच्छेद–44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। अतः न्यायालय यह निर्देश दे कि इसे लागू किया जाए। यह संविधान के निर्माताओं का एक स्वप्न था, जिसे वे साकार देखना चाहते थे। आइए थोड़ा इस ओर ध्यान दें। इस स्वप्न में झाँकें। अनुच्छेद–38 इस बात की घोषणा करता है कि राज्य हर हाल में इस दिशा की ओर प्रयत्नशील रहेंगे कि इस कल्याणकारी राज्य में यथासंभव कदम उठाए जाएँ ताकि कोई भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से वंचित न हो। अनुच्छेद–39 के निर्देश इसप्रकार हैं :–

➪ जीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार।
➪ पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार।
➪ आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार।
➪ समान न्याय का अधिकार।
➪ काम पाने का अधिकार।
➪ बेकारी, बुढ़ापा या अन्य विसंगतियों के कारण लोकसहायता पाने का अधिकार।
➪ काम की न्यायसंगत और न्यायोचित दशा का अधिकार।
➪ बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का आधिकार।

इसके अलावा भी नागरिकों के निम्नलिखित मूल अधिकार हैं, जो अपने आप में श्रेष्ठतम हैं :–

➪ समता का अधिकार।
➪ विशिष्ट स्वतन्त्रता का अधिकार।
➪ शोषण के विरुद्ध अधिकार।
➪ धन की स्वतन्त्रता का अधिकार।
➪ संस्कृति व शिक्षा सम्बन्धी अधिकार।
➪ सम्पत्ति का अधिकार।
➪ सम्वैधानिक उपचारों का अधिकार।

इंग्लैण्ड में कोई लिखित संविधान नहीं है। वहाँ पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जिक्र नहीं है। परन्तु अमरीका में मौलिक अधिकार हैं, जिनकी तर्ज पर भारत के मौलिक अधिकार लिए गए हैं। प्राक्कथन, मौलिक अधिकार, नीतिनिर्देशकतत्त्व और संविधान की आत्मा का जब हम बिना पूर्वाग्रहों के अध ययन करते हैं, तो पाते हैं कि भारत के संविधान में व्यक्ति की निजता, उसकी गरिमा और उसकी स्वतन्त्रता इतना ख्याल रखा गया है, जितना विश्व के और किसी संविधान में नहीं रखा गया। परन्तु साथ ही हम यह देखकर हैरान भी हो जाते हैं कि भारत का आम नागरिक आज जितना दुःखी है, जितना शोषित है, उतना दूसरा कोई है भी नहीं। इतने महिमामण्डित संविधान के रहते आज समस्याएँ बढ़ती चली जा रही हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति संविधान की आड़ में न केवल ऐश कर रहे हैं बल्कि हमारे भाग्यविधाता भी बने हुए हैं। ऐसे में बाबा साहब के वचन याद आते हैं। उन्होंने कहा था– ''संविधान में जो कुछ लिखित है, वह तो महत्त्वपूर्ण है ही परन्तु जो कुछ लिखित नहीं, वह उससे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण है।''

–(अश्विनीकुमार, सम्पादकीय; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 16/06/2003)

221) ईराक में लोकतन्त्र समर्थकों पर इस्लामी कट्टरपंथियों के व्यापक हिंसक हमले :– *ईरान की राजधानी तेहरान में शनिवार को इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा जानलेवा हिंसक हमलों के बावजूद रविवार को फिर सैंकड़ों की तादाद में लोकतन्त्र समर्थक प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर आए। कट्टरपंथियों ने इन प्रदर्शनकारियों पर चाकुओं और अन्य हथियारों से भीषण हमला किया था। छात्रों को विरोधप्रदर्शन से निपटने के लिए ईरान सरकार के हिंसक तरीके की निन्दा करते हुए अमरीका ने गिरफ्तार छात्रों की तुरन्त रिहाई की माँग की।*

–(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 16/06/2003)

222) सूक्ष्मता से समता है, स्थूलता से विषमता है :– *जो कुछ भी दृष्टि में आ रहा है, जिसे हाथ से पकड़ा जा सकता है, जिसके पास पाँव से चलकर जाया जा सकता है, जिह्वा जिसका स्वाद ले रही है, वह सब कुछ स्थूल है। किन्तु जिसे देखा–सुना नहीं जा सकता, जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, जो पकड़ में आने वाला नहीं है, वही सूक्ष्म है।*

स्थूल द्वैत पैदा करता है। वही भेददृष्टि का कारण है। उसी ने ही विषमता को जन्म दिया है। जबकि सूक्ष्म अद्वैत का जन्मदाता है, अभेददृष्टि का कर्ता है तथा समता पैदा करता है। स्थूलभाव अनात्मभाव माना गया है तथा सूक्ष्मभाव को आत्मभाव स्वीकार किया गया है। अनात्मभाव हमारी अविद्या का कारण है तथा आत्मभाव विद्या का मूल है। केवल आत्मा में समता है, अन्य सभी तत्त्वों में विषमता ही मिलेगी। यदि आत्मा में समता नहीं होती तो व्यापकता कहाँ से आ जाती। व्यापकता के कारण ही निर्भयता आती है। अन्यथा एक-दूसरे से भय ही लगता है। जीव शान्त नहीं रह सकता। समता और विषमता का खेल अनादिकाल से चला आ रहा है। जीव के हृदय में देवभाव (समत्व) जागता तो है, परन्तु जब दैत्यभाव प्रभावित कर जाता है, तो विषमता जीव को दबोच लेती है। प्रत्येक जीव में आत्मा तो एकसमान है, परन्तु प्रत्येक जीव का अन्तःकरण (मन, बुद्धि, चित्त, अहं) भिन्न-भिन्न प्रकार की क्रियाओं और भावों वाला है। सभी के मन की अनुकूलता-प्रतिकूलता, संकल्प-विकल्प में भिन्नता है। सभी का अनुरोध-विरोध एक जैसा नहीं है। कोई कामी है, कोई निष्कामी है। परमपिता परमात्मा ने उद्भिज, स्वेदज, जेरज एवं जरायुज- चार प्रकार के जीव पैदा किए हैं, जिनमें आकार के आधार पर तो विषमता है, परन्तु निराकार आत्मा के आधार पर समता है। यही समता ही 'जियो और जीने दो' का भाव पैदा करती है। हिंसा की वृत्ति को नष्ट करती है। यही हम सबको ऐसे ब्रह्म की प्रतीति कराती है, जिसे हम आत्मा का नाम देते हैं। तुझमें ब्रह्म मुझमें ब्रह्म सबमें ब्रह्म समाया है। कर लो सभी से प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है।। यहीं पर पहुँचकर दैत्य, देव, मानव और पशु एक हो जाते हैं, क्योंकि सभी में आत्मब्रह्म विद्यमान है। यही सर्वात्मभाव ही जीव को प्रेरित करता है जिसके बल पर समता पैदा होती है और जीवन में समरसता आ जाती है। ॐ तत् सत्!

-(डा. रेणुबृज जालन्धर; धर्मकर्म अंक, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 09/06/2003)

223) शासनव्यवस्था : संक्रान्तिकाल में उभरकर आ रहा है आध्यात्मिक समाजवाद :- *आज विश्व संक्रमण काल से गुजर रहा है। भयंकर उथल-पुथल भरे इस वर्तमान काल के पीछे मानवीय विकास का एक लम्बा इतिहास समाहित है। प्रारम्भिक स्तर में मनुष्य शारीरिक दृष्टि से बलशाली था। परन्तु वह कल्पना और विचारणा के क्षेत्र में मन्द था। पी.लीबरमैन अपनी पुस्तक 'मैन ऑन ह्यूमन इवोल्यूशन' में कहते हैं कि इस काल में शारीरिक वीरता ही सर्वश्रेष्ठ गुण था। आवश्यकता भी इसी की थी। इसके पश्चात मानसिक संकल्पना और भावना का उदय हुआ, जिससे परिवारव्यवस्था पनपी, समाज सुसंगठित हुआ। शारीरिक विकास के पश्चात कालक्रम में बौद्धिक विकास रूपी नये आयाम (कल्पना एवं विचारणा) का विकास हुआ। सभ्यता का नया स्वरूप दिखाई देने लगा। पुरानी मान्यताओं के स्थान पर नये आधार गढ़े गए। सब कुछ बदलाव की चरमसीमा तक पहुँच गया। यही है वह संक्रमण काल जिसमें हम जी रहे हैं। बौद्धिक समाज की अवस्था अत्यन्त खतरनाक सिद्ध हो रही है। इस समाज में बुद्धि की कृति एवं विकृति दोनों अवस्थाएँ हैं। एक ओर जहाँ बुद्धि ने चमत्कार किया, वहीं उसकी विकृतियों ने समूचे मानवसमाज को संकट में डाल दिया। बीसवीं शताब्दी के समाज का अवलोकन करने पर पता चलता है- यह रूसो के प्रजातन्त्र मार्क्स के साम्यवाद और नीत्से के नास्तिकवाद के इर्द-गिर्द घूमता रहा। प्रजातन्त्रवादी आँधी ने राजतन्त्र को उखाड़ फेंका। प्रजातन्त्र के प्रबल वेग के परिणामस्वरूप दुनिया के अधिकांश देशों में प्रजातन्त्र शासन स्थापित हुआ। अपना देश भी 55 सालों से प्रजातन्त्रात्मक शासनपद्धति से चल रहा है। अमेरिका का लोकतन्त्र एक मिसाल है। लोकतन्त्र की परिकल्पना मानवसमाज को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए विकसित की गई। यह आपसी विचार-विमर्श परस्पर सहयोग, सहिष्णुता, उदारता के गुणों से विकसित तथा पल्लवित होता है। स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव पर ही लोकतन्त्र का भविष्य सुरक्षित रहता है। किन्तु यह प्रजातन्त्र प्रजा के हाथों से निकलकर अवांछनीय तत्त्वों के पास पहुँच जाने से यह संकटों से घिर गया है। प्रजा के स्थान पर निहित स्वार्थी लोगों ने इसे अपने अधिकारक्षेत्रों में ले लिया है। प्रजा तो मात्र मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। जब प्रजातन्त्र से प्रजा की आस्था एवं विश्वास उठ जाता है, तो वह अधिनायकवाद में बदल जाता है। पाकिस्तान जैसे देश इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। अमेरिका एवं फ्रांस में राष्ट्रपति शासन भी कोई कारगर उपाय नहीं दे पा रहा है। लैटिन अमेरिका, जापान एवं अफ्रीका के कई देश भी इसी समस्या से त्रस्त हैं। अपने देश का प्रजातन्त्र भी मर्यादा और लोकतन्त्र की सारी सीमाओं को लाँघ चुका है। इतिहास प्रसिद्ध घोटाले एवं महाभ्रष्टाचार, चुनाव में धाँधली इसी का परिणाम है।*

प्रजातन्त्र ने जैसे प्रजा के लिए प्रारम्भिक आकर्षण पैदा किया ठीक उसी तरह साम्यवाद का भी

आरम्भिक उत्साह कम नहीं था। आर्थिक समानता का नारा निर्धन और अभावग्रस्त वर्ग को बहुत आकर्षक लगा। इस लुभावने नारे और सुखद स्वप्नों ने समाज में हलचल मचा दी। अनेक देश साम्यवादी बन गए। जो नहीं बन सके वहाँ भी साम्यवाद से प्रभावित लोगों की संख्या कम नहीं रही। भारत में इसका प्रवेश प्रायः छठे दशक में हुआ। साम्यवाद का सर्वमान्य एवं प्रचलित अर्थ है– उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर लोगों के नाम पर जनता की सरकार का नियंत्रण। समाजवाद के अनुसार पूँजी पर अधिकार व्यक्ति का नहीं वरन् सरकार का होना चाहिए। यह व्यक्तिगत पूँजीवाद का विरोधी है एवं सरकारी पूँजीवाद का समर्थक है। साम्यवाद को समता के आदर्श के साथ जोड़ा गया। किन्तु साम्यवाद में समता की सोच आधी-अधूरी है। तथापि आकर्षक के इस जाल में सोवियत रूस, चीन, वियतनाम और यूरोप के कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया। समय के प्रवाह में साम्यवाद के दोष उभरकर सामने आए। साम्यवाद ने सर्वप्रथम व्यक्तिगत चेतना को समाप्त कर दिया। व्यक्ति को शासन का मूक-बधिर गुलाम होकर जीने के लिए विवश होना पड़ा। ईस्टरमेन के अनुसार साम्यवादी शासकों में निर्दोष व्यक्तियों के खून बहाने का आँकलन करने में स्टालिन एक झील, हिटलर छोटा तालाब और मुसोलिनी एक कुएँ के सदृश ठहरेंगे। स्वतन्त्रता की चाह ने जनविद्रोह ने सर्वप्रथम सोवियतरूस को विखंडित कर डाला। भले ही चीन आज सबसे बड़ा साम्यवादी देश है, परन्तु इसकी सामाजिक दशा अत्यन्त विस्फोटक है। चीन के तियानमैन चौक में हुए निहत्थे नवयुवकों का नरसंहार इसकी जलती चिन्गारी है। जिन देशों में अभी भी साम्यवादी शासन या उसका प्रभाव मौजूद है, वे भी परिवर्तन की तीव्र माँग करने लगे हैं।

पूँजीवाद को आर्थिक एकाधिकारवाद भी कहा जा सकता है। पूँजीवाद छल, बल, कौशल के साथ शोषण का पर्याय है। विकसित देश विकासशील देशों में पूँजीनिवेश करके उसके सारे कच्चे माल पर अधिकार करने पर तुले हुए हैं। पेटेन्ट कानून इसीलिए विनिर्मित किया गया है। आर्थिक विकास की असमानता के फलस्वरूप विश्व अर्थव्यवस्था की पूँजीवादी पद्धति का संकट अधिक गंभीर हो गया है। अमेरिकी पूँजीवाद ने नवउपनिवेशवाद का सहारा लिया है तथा अनेक विकासशील देशों को अपने जाल में फँसा लिया है।

पीटर एफ. ड्रकर ने अपनी प्रसिद्ध कृति 'इस कैपिटैलिज्म कमिंग टु एन इण्ड' में उल्लेख किया है कि विश्व इस समय अपने इतिहास के अद्भुत मोड़ पर है। साम्यवाद मर चुका है। समाजवाद रास्ते से हट गया है और यही हाल पूँजीवाद का भी है।

धर्म एक ऐसी वस्तु है, जो व्यक्ति तथा समाज को बाँधती है। धर्म समाज और जीवन की व्यवस्था और दिशा है। इसे यदि जीवन से निकाल दिया जाए, तो जीवन अव्यवस्थित और दिशाहीन हो जाता है। धर्म से विलगाव का अर्थ है– समाज की पूरी व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर देना। किन्तु तथाकथित बुद्धिवादी धर्म को अफीम की गोली कहते हैं और उसे प्रगति का अवरोधक ठहराते हैं। वस्तुतः यह धर्म नहीं है, जिसके लिए ऐसा कहा गया है। जिसकी ओट में समाज के अत्याचारी और अनाचारी तत्त्वों ने मानवता को अगणित बार चोट पहुँचाई है। तथा जिसके नाम पर जितना शोषण, हिंसा एवं नरसंहार हुआ, शायद ही किसी अन्य वजह से हुआ हो।

उपर्युक्त विचारधाराओं की विफलता के संदर्भ में धार्मिक समाज को ही एकमात्र विकल्प मानते हैं। धार्मिक समाज की परिकल्पना धार्मिक रीति-नीति को ही अपना कर ही संभव है। इसमें बाह्य अनुशासनों, नीतियों, कानूनों के स्थान पर मनुष्य के सद्गुणों, सत्प्रवृत्तियों, सद्भावों को उभारने-विकसित करने वाले उपचारों की प्रधानता होगी। यह व्यवस्था मात्र एक परिकल्पना भी नहीं है। बल्कि आज की आवश्यकता और कल की सुनिश्चित संभावना है। धार्मिक समाजवाद में एकता और समता की भावना प्रबल होगी। इसी की सुखद परिणति ही अगले दिनों विश्वधर्म, विश्वसंस्कृति, विश्वभाषा और विश्वराष्ट्र के रूप में दिखाई पड़ेगी। धार्मिक समाज की भावी व्यवस्था ऋषितन्त्र द्वारा संचालित होगी। व्यवस्थाक्रम में इसके तीन स्तर होंगे– इन्हें ही राजर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि के रूप में अलंकृत किया जा सकता है। धार्मिक समाज की भावी व्यवस्था के पाँच मुख्य आयाम होंगे। इस समाज में प्रज्ञावान व्यक्तियों का वर्चस्व होगा। यही उच्चस्तरीय व्यक्ति समाज का नेतृत्व कर सकेंगे। धार्मिक समाज में इनका प्रमुख योगदान रहेगा। लोकतन्त्र का विकेन्द्रीकरण होगा। पंचायती व्यवस्था ही अपना क्रमिक विकास करके विश्वशासन सँभालेगी। न्याय की समूची प्रक्रिया का हल 'मानवमात्र एकसमान' के सूत्र से मिल सकेगा। अर्थव्यवस्था उत्पादन एवं वितरण के बीच सामंजस्य की व्यवस्था है। पूँजी पर व्यक्तिगत अधिकार के बदले समाज का अधिकार होना चाहिए। इस समाज में हर व्यक्ति को अपने क्षमता के अनुरूप श्रम एवं आवश्यकता के अनुसार साधन मिलेगा। शिक्षण का एक नया तन्त्र विकसित करने की आवश्यकता है, जहाँ शिक्षा का कैदमुक्त और सार्वभौमिक हो।

-(अखण्डज्योति, जून, २००३)

224) *बाइबिल एक प्रजातान्त्रिक धार्मिक ग्रन्थ है। इसके अनुसार सभी को शान्ति एवं एकता में रखना चाहिए एवं दूसरे के अधिकारों का हनन करने से संकोच करना चाहिए। बाइबिल में सभी को स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा, सद्भावना व स्वायत्तता का अधिकार प्राप्त है। कलीसिया (मानवसमाज) के पथसंचालन के लिए पवित्र बाइबिल में साफ दिशानिर्देश दिए गए हैं। आजादी के 55 साल बीत जाने के बाद भी देश के 2 करोड़ दलित ईसाइयों का विकास न हो पाना चर्चनेतृत्व के लिए गहन चिन्तन का विषय है। बहुसंख्यक दलित ईसाइयों की चर्च संस्थानों में कोई भूमिका नहीं। चर्च ढाँचे पर पूरा एकाधिकार मुट्ठीभर लोगों का है। दलित ईसाइयों को सीढ़ी के रुप में इस्तेमाल करते हुए चर्चनेतृत्व लगातार अपना विकास करता जा रहा है। लेकिन चर्चनेतृत्व को यह बात याद रखनी चाहिए कि वह लम्बे समय तक दलित ईसाइयों को स्वर्ग-नर्क के कुचक्र में फाँसकर नहीं रख सकता। मौजूदा समय में देशभर में 25000 से ज्यादा विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले संगठन हैं, जिनको प्रतिवर्ष 4000 करोड़ रुपयों का अनुदान प्राप्त होता है। इन संगठनों में 60 से 70% चर्च संगठन हैं, जिनकी कार्य करने की शैली का दलित ईसाइयों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है।*

केन्द्र व राज्य सरकारें इस मामले में दलित ईसाइयों के व्यापक हित को देखते हुए कोड आफ कण्डक्ट लागू करें। **-(आर.एल.फ्रांसिस, अध्यक्ष, पी.सी.एल.एन.; पंजाबकेसरी, 02/06/2003)**

225) विफल राष्ट्र :- *अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए हाल ही में मुझे एक अभावग्रस्त व विफल राष्ट्र का दौरा करने का अवसर मिला। यह देश प्रकृति की खूबसूरती से सराबोर होने के साथ-साथ हर तरह के संसाधनों से भी समृद्ध था। लेकिन अब यह बर्बाद हो चुका है तथा इसे पूर्णतः छिन्न-भिन्न किया जा चुका है। दूसरे देशों से लोग व्यापार करने या सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यहाँ आते गए और यहाँ मालिक बन बैठे और जो यहाँ के मूल निवासी थे, वे उनके गुलाम व मजदूर बन गए। एक लम्बे अर्से से यहाँ के मूल निवासी यानि गुलाम चोरी-डकैती की कला भी सीख चुके हैं और वे अपने मालिकों, रक्षकों, अपहार्कों, प्रशिक्षकों व परामर्शदाताओं से हाथ मिला चुके हैं, जिसमें कसाईपन भी साथ जुड़ा हुआ है और उनके पास घातक हथियार भी हैं। इस तरह अब ठगी के साथ हिंसक शोषण यहाँ की बपौती या पैतृक सम्पत्ति है। यहाँ शक्तिशाली हमेशा जीतते हैं क्योंकि उनके पास अत्यन्त घातक शक्ति है। वास्तव में यहाँ के क्षेत्रीय चोर व डकैत विदेशी अपहार्कों के साथ मिल गए और अपने ही लोगों का कत्ल करने लगे। यह सब मैंने वहाँ देखा। यहाँ दूर-दूर तक ऐसे घर नजर आ रहे हैं, जो नष्ट हो चुके हैं और जिनकी छतें ही नहीं हैं। इन घरों के मालिक आज भी इनके चारों ओर डेरा डाले हुए हैं। मानो वे किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। इस देश का बड़ा भाग संसारभर से अलग-थलग हो गया है। यहाँ संचारसाधन नष्ट हो चुके हैं। यह देश राज्य व जिलों में बँटा हुआ नहीं है, बल्कि यह देश जागीरों में बँटा हुआ है, जिन्हें कबीलों के सरदार व मुखिया सँभालते हैं। इन मुखियाओं की भी अपनी कहानी है। ये लोग बहुपत्नी प्रथा में विश्वास रखते हैं। एक-एक के पास दर्जनों रखैलें हैं और सैंकड़ों बच्चे। यहाँ जवान लड़कियों को तोहफे के तौर पर दिया जाता है। यही इनकी जीवनशैली है। यहाँ स्कूल तो है लेकिन बहुत कम और उच्चशिक्षा तो यहाँ एक सपनामात्र है। एक समय था जब यहाँ स्कूल भी थे। लेकिन सबकुछ इन लोगों के कसाईपन ने खत्म कर दिया। पुरुषों का शराब पीना एक आम बात है। जवान लड़कियों के साथ छेड़-छाड़ व उनका शोषण एक आम बात है। कम शब्दों में कहा जाए, तो यहाँ एक ऐसा परिवेश कायम है, जिसमें कोई औरत या लड़की सुरक्षित नहीं है। औरत को पशुओं के समान समझा जाता है। उनका काम पुरुषों को संतुष्ट करना और उनके लिए बच्चे पैदा करना है। बहुत सी औरतें बच्चे पैदा करते-करते दम भी तोड़ देती हैं और बहुत से पुरुष एड्स जैसी भयंकर बीमारी से पीड़ित हैं। इस देश का परिवेश ऐसा है कि यह खुद ही हत्यारों को पोषित करता है। इस अभावग्रस्त राष्ट्र के पास ऐसा बहुत कुछ है, जिसके लिए आप इसे जानते हैं- तेल, प्राकृतिक गैस, खनिज, घने जंगल, अच्छा मानसून और वन्यजीवन इस देश की पहचान माने जाते हैं। लेकिन यहाँ के लोग नहीं। जब मैंने यह सब देखा, मेरी व्यथा की सीमा न रही।* **-(किरणबेदी, सुप्रसिद्ध महिला पुलिस अधिकारी; पंजाबकेसरी, 03/06/2003)**

226) केन्द्रीय कारागार मन्त्री के नाम पत्र :- *पिछले दिनों समाचार पत्र में पढ़ा कि रोहिणी इलाके में एक कारागार यानि जेल बनाई जा रही है, क्योंकि तिहाड़ जेल अब छोटी हो गई है। पढ़कर मुझे और मेरे जैसे कई लोगों को अजीब लगा। हम बिना किसी कसूर के हजारों लोगों को जेल में रखते हैं। जिनके कसूर इतने मामूली*

होते हैं कि उनकी सजा भी कुछ नहीं होती या फिर जमानत के अभाव में लोग जेलों में रहने को मजबूर हैं। अगर हमारे देश के कारागारमन्त्री, जेलर और जज इन लोगों के बारे में थोड़ी बहुत सहानुभूति रखें और इन लोगों का निपटारा जल्दी करें, तो हमारी सरकार को करोड़ों रुपये खर्च करके नई जेलों का निर्माण न करना पड़े। जेलों के निर्माण की बजाय सरकार को उस ओर कदम उठाने की जरूरत है, जिससे अपराध कम हों। अपराधों के बढ़ने का कारण शायद बेरोजगारी है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। ताकि लोगों को रोजगार मिले। जिन वजहों से अपराधी बनते हैं, उन वजहों को खत्म करने की जरूरत है न कि एक और जेल की। उम्मीद है मन्त्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

-(प्रदीप चान्ना, उत्तमनगर दिल्ली, आवाज-ए-खबरदार; पंजाबकेसरी, 02/06/2003)

227) कर्ज में डूबे परिवार के पाँच सदस्यों ने जहर खाया, तीन की मौत :- *मुरादाबाद मझोला थानाक्षेत्र में कर्ज में डूबे एक ही परिवार क पाँच सदस्यों ने जहर खा लिया। पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल पहुँचाया परन्तु दो लड़कियों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया जबकि पिता की मृत्यु अस्पताल में उपचार के दौरान हो गई। पुलिस को घटनास्थल से सुइसाइड नोट भी बरामद हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार महेश चौहान की खुशहालपुर मार्ग स्थित पी.ए.सी. बाईपास के निकट 'वेलकम' नाम से वेल्डिंग की दुकान थी। दुकान में घाटा हो जाने पर उसने अनेक लोगों से कर्ज ले लिया। परन्तु दुकान फिर भी नहीं चली और वह आकण्ठ कर्ज में डूब गया। लोग आए दिन उससे अपना कर्ज वसूलने के लिए आने लगे। कभी-कभी ये लोग उसका अपमान भी करते थे। महेश चौहान ने कर्ज उतारने की तमाम कोशिशें कीं, परन्तु कामयाब न हो सका। तकादेदारों द्वारा किए जा रहे अपमान से तंग आकर उसने परिवार समेत आत्महत्या का भयंकर निर्णय ले लिया।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, 27/05/2003)***

228) रिश्वतखोर कर्मचारी को गंजाकर नंगा घुमाया :- *उड़ीसा में भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ लोग अब प्रत्यक्ष कार्यवाही करने लगे हैं। राज्य के वीरमित्रौर शहर में राजस्व कार्यालय के एक कर्मचारी को गुस्साई भीड़ ने एक विधवा ने रिश्वत माँगने की ऐसी सजा दी कि उसे जीवनभर याद रहे। भीड़ ने इस कर्मचारी का शिर गंजा करके उसे नग्नावस्था में शहरभर में घुमाया। राजस्व विभाग में तैनात कर्मचारी 'पीताम्बर पुहान' ने एक विधवा 'सलबीना प्रधान' से उसके पति की मौत के बदले मुआवजा दिलाने की एवज में बीस हजार रुपये रिश्वत की माँग की। यह कर्मचारी सलबीना को धमकी दे चुका था कि जब तक वह रिश्वत नहीं देगी, तब तक उसे मुआवजा नहीं मिल सकता। सलबीना ने कर्मचारी से अपने साथ उस बैंक तक जाने को कहा, जहाँ से वह 99 हजार रुपये निकालने वाली थी। सलबीना ने इस कर्मचारी को सजा चखाने की ठानी। बैंक पहुँचने के बाद वहाँ पहले से ही सलबीना के जान-पहचान के लोग मौजूद थे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जैसे ही यह कर्मचारी सलबीना के साथ बैंक पहुँचा, वहाँ सैकड़ों लोगों ने उसे पकड़ लिया। गुस्साई भीड़ ने पहले तो उसकी पिटाई की। फिर धरती पर गिरा कर जबरन उसका शिर गंजा कर दिया। उसके चेहरे को काले और उजले पेन्ट से रंग दिया गया। वहाँ मौजूद महिलाओं ने उसकी गरदन में जूते और चप्पलों की माला पहनाई। फिर भीड़ ने उसे नंगा करके शहर की गलियों में घुमाया। बच्चे इस कर्मचारी पर धूल और गोबर फेंक रहे थे। यहाँ तक कि गलियों में कई लोगों ने इस कर्मचारी पर थूका भी। उस वक्त पुहान की हालत देखने लायक थी। वह बार-बार अपनी जान की भीख माँग रहा था। उसने भीड़ से कहा कि यह रिश्वत उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में माँगी थी। शहर की गलियों और सड़कों पर इस दृश्य को देखने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े। स्थिति इतनी विस्फोटक थी कि पुलिस को भी सावधानी से मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 25/05/2003)***

229) *भारत के शीर्ष राजनीतिज्ञ एक-दूसरे के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई तो लड़ते रह सकते हैं परन्तु उनके बीच इस बात को लेकर गुपचुप समझदारी कायम है कि अपने वरिष्ठ राजनीतिक सहयोगियों के खिलाफ किसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप को तूल नहीं देना है। फिर उनमें से किसी ने चाहे देश को दोनों हाथों से ही क्यों न लूटा हो। इसी गुपचुप समझदारी का नतीजा है कि अभी तक शीर्ष राजनीतिज्ञों में से किसी को भी भ्रष्टाचार के आरोपों पर जेल नहीं हुई। हालाँकि उनमें से कुछ भ्रष्टाचार में आकण्ठ डूबे नेता के रूप में जाने जाते हैं। बहरहाल राज्यों में यह रुझान बदला है और कुछ पूर्व मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है। यह प्रक्रिया एक बार जैसी ही भारत में*

थुरु होती है, वैसे ही पूर्व प्रधानमन्त्रियों समेत तमाम शीर्ष राजनीतिज्ञों को भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ेगा। एशियाई और यूरोपीय क्षेत्र के तथा भारत के कुछ पड़ोसी देशों में शीर्ष राजनीतिज्ञों पर सार्वजनिक रूप से मुकदमा चला और उन्हें जेल हुई। दक्षिण कोरिया में एक पूर्व राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल हुई। इसीप्रकार जापान में एक पूर्व प्रधानमन्त्री को और इटली में भी एक पूर्व प्रधानमन्त्री को भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमे का सामना करना पड़ा और जेल हुई। पड़ोसी बांग्लादेश में पूर्व राष्ट्रपति इरशाद को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खानी पड़ी। जबकि पाकिस्तान में बेगम बेनजीर भुट्टो को उनकी गैरहाजिरी में भ्रष्टाचार के आरोप में सजा सुनाई गई और उनके पति को जेल भेजा गया। पूर्व पाक प्रधानमन्त्री मियाँ नवाजशरीफ को देश छोड़कर साउदी अरब में शरण लेनी पड़ी क्योंकि मुशर्रफ ने उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप जो लगाए थे। परन्तु भारत में अभी तक एक भी शीर्ष राजनीतिज्ञ को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल नहीं जाना पड़ा। राजनीतिज्ञों को भय है कि एक बार यह रुझान शुरु हुआ, तो उनमें से कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। क्योंकि उनमें से ज्यादातर के ऊपर सार्वजनिक रूप से तिजोरी भरने के आरोप लगे हैं। वरिष्ठ राजनीतिज्ञ बिना किसी शर्मोहया के जनता को लूटते हैं। अगर कोई वाजपेयी सरकार के मंत्रियों द्वारा दाखिल किए गए आयकर रिटर्न को देखे तो उसे पता चलेगा कि उनमें से ज्यादातर सरकारी ड्राइवर से भी कम आय वाले दरिद्र नारायण हैं। परन्तु वे सब के सब महाराजाओं की भाँति रहते हैं। ***-(जी.एस.चावला, राजनीतिक संवाददाता; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 25/05/2003)***

230) *राजीव गाँधी ने कहा था कि सरकार जो एक रुपया विकास कार्यों के लिए देती है, उसमें से मात्र नौ पैसे ही आम जनता तक पहुँच पाते हैं। शेष राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। इसी कारण भारत को आज विश्व के दस भ्रष्टतम देशों में से एक माना जाता है। कोई भी क्षेत्र भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। बोफोर्स तोप घोटाला ठण्डा भी नहीं पड़ा था कि चीनी, यूरिया, संचार घोटाला, प्रतिरक्षा मामलों का तहलका कांड न जाने कितने भ्रष्टाचार के मामले पिछले वर्षों में सामने आ गए। पिछले कुछ महीनों में ही पंजाब लोकसेवा आयोग में पी.सी.एस. (सिविल व ज्यूडीशियल) में भर्ती घोटाला सामने आया तथा कई जजों को हटा दिया गया। महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग के चेयरमैन भी भर्ती घोटाले में संलिप्त पाए गए। यूनिट ट्रस्ट घोटाले ने लाखों यूनिटधारकों को खून के आँसू रुला दिया और किडनी घोटाले ने पंजाब को हिलाकर रख दिया। सांसदनिधि के दुरुपयोग को मायावती ने उजागर किया। 2000 करोड़ के जाली स्टाम्प पेपरों का देशव्यापी घोटाला मुम्बई में पकड़ा गया। इस वर्ष डी.डी.ए. के चेयरमैन सुभाष शर्मा व अन्य अधिकारियों तथा दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज को डी.डी.ए. घोटाले में गिरफ्तार किया गया। सी.बी.आई. ने हाल ही में कुछ आयकर अधिकारियों को पकड़ा, जो घर में ही कुछ वकीलों द्वारा लिखे गए फैसलों पर ही दस्तखत कर देते थे और इसके लिए उनसे भारी मात्रा में धन लेते थे। कुछ दिन पूर्व ही जालंधर के जिला सेसन जज आर.एम.गुप्ता तथा चण्डीगढ़ के न्यायिक मजिस्ट्रेट एस.एस.भारद्वाज को करतारपुर के एक डाक्टर गुरविन्दर सिंह समरा से 7 लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया। श्री गुप्ता तो पकड़ लिए गए लेकिन श्री भारद्वाज सी.बी.आई. की हिरासत से फरार हो गए। सी.बी.आई. ने अपनी उसी टीम की जाँच शुरु कर दी है, जिसकी हिरासत से भारद्वाज भागे थे।*

बिहार में करोड़ों के चारा घोटाले, जिसमें लालू यादव संलिप्त हैं, की जाँच करने वाले सी.बी.आई. के अतिरिक्त निदेशक यू.एन.विश्वास के कोलकाता स्थित आवास से हैरोइन बनाने में संलिप्त विदेशी किराएदार पकड़े गए। वित्त राज्यमन्त्री जी.रामचन्द्रन के निजी सहायक पेरुमल स्वामी को सी.बी.आई. द्वारा 4 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा गया। पेरुमल ने मुम्बई के एक राजस्व अधिकारी अनुराग वर्धन को उसकी पसन्द की जगह पर तबादला कराने के लिए 4 लाख रुपये की रिश्वत ली थी। दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से भी 69 लाख रुपये नगद व 85 लाख के चेक बरामद किए गए। आयकर व राजस्व विभागों में जो करचोरी व भ्रष्टाचार के रोकथाम करने वाले विभाग माने जाते हैं, में कितना भ्रष्टाचार है!

खुशी की बात है कि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में कुछ समय से भ्रष्टतत्त्व पकड़े जाने लगे हैं। लेकिन इस बात का दुःख भी है कि देश की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से लेकर निजीक्षेत्र तक कोई भी भ्रष्टाचार की बुराई से बचा हुआ नहीं है। ***-(विजय, सम्पादकीय; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 24/05/2003)***

231) पूर्व राष्ट्रपति श्री के.आर.नारायणन ने अमरीका में अपने दिल के इलाज के लिए सरकार से 60 लाख रुपये की सहायता माँगी है। श्री नारायणन ने प्रधानमन्त्री को एक पत्र लिखा है कि मुम्बई और दिल्ली के डाक्टरों ने उनके दिल की जाँच की है और उन्हें अमरीका जाने की सलाह दी है। वह अपने साथ अपनी पत्नी, बेटी और एक सुरक्षागार्ड को लेकर जाना चाहते हैं, जिस पर कुल लगभग 60 लाख रुपये खर्च होंगे। नारायणन चाहते हैं कि यह सारा खर्च सरकार सँभाले, क्योंकि वह पूर्व राष्ट्रपति हैं और पूर्व राष्ट्रपति का दर्जा एक कैबिनेट मन्त्री का है, जिन्हें मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्राप्त है।

क्या उनके स्वास्थ्य पर सरकारी खजाने से 60 लाख रुपये खर्चना जायज रहेगा? जिस देश में एक आम नागरिक को न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएँ भी प्राप्त नहीं हैं, उस देश में एक नेता पर विदेशी मुद्रा में 60 लाख रुपये इसप्रकार खर्च करना कितना जायज है? इनसे पहले कई नेताओं पर भी लाखों-करोड़ों रुपये इसी प्रकार खर्च हो चुके हैं। देश के लगभग हर राष्ट्रपति ने विदेशों में अपना उपचार करवाया है। वी.पी.सिंह के उपचार पर करोड़ों रुपये लगे हैं और मुरासोलीमारन के उपचार पर करोड़ों रुपये लग रहे हैं।

यह दोहरा मापदण्ड कितना जायज है कि जो देश अपने लोगों को न्यूनतम सेवाएँ नहीं दे सकता, अस्पतालों का बुरा हाल है, वहाँ नेताओं पर इतना पैसा क्यों खर्च किया जाए? जबकि के.आर.नारायणन तथा वी. पी.सिंह जैसे नेता खुद को 'गरीब जनता का आदमी' कहते नहीं थकते। तब जो स्वास्थ्य सेवाएँ आम जनता को मिलती हैं, वह इनके लिए पर्याप्त क्यों नहीं हैं? लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब अपनी बारी आएगी, तो न नारायणन दलितों के प्रतिनिधि रहेंगे और न ही वी.पी.सिंह को सामाजिक न्याय की चिन्ता होगी। उस वक्त इनकी स्थिति होती है कि माल-ए-मुफ्त, दिल-ए-बेरहम। उस वक्त जनता का पैसा खर्चने में किसी को गुरेज नहीं होता और न ही उन्हें कोई दूसरा नेता इन्कार करेगा। क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें खुद इस सुविधा की जरूरत पड़ सकती है।

-(चक्रमोहन, स्तम्भकार; मर्यादाएँ, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 21/05/2003)

*232) **नई सुबह के इंतजार में मजदूर महिलाएँ:-** तमिलनाडु की 13 साल की मजदूर लड़की निर्मला की कहानी सचमुच हृदयविदारक है। अपने गाँव में जब वह चावल मिल में काम कर रही थी, तो उसकी बाँयी बाँह कट गई। आज उसका पूरा परिवार छोटे भाई-बहन तक आम के बागान में काम कर रहे हैं। ताकि निर्मला की जिन्दगी बचाने के लिए उधार ली गई रकम चुकाई जा सके। परन्तु इस दु:खद घटना के बाद भी निर्मला कहती है- मैं अपने छोटे भाई-बहन को मेरी तरह मजदूरी करते नहीं देखना चाहती। मैं उन्हें स्कूल में देखना चाहती हूँ। यही मेरा सपना है। बालमजदूरी पर हुए राष्ट्रीय सम्मेलन 'नई सुबह' में दूसरे बच्चों की तरह निर्मला भी यहाँ आई। जिस उम्र में बच्चे खेलते, सीखते और खुशियाँ मनाते हैं, उसमें निर्मला बालमजदूर बन गई। वह बताती है- ''चूँकि मैं चावल मिल की मशीनों में काम करने से डरती थी, इसलिए मैंने मालिक से कहा कि वह मुझे मशीन से जुड़ा कोई काम न दे। पर मेरी गुहार का बहरे कानों पर असर नहीं हुआ।'' आशंका सच निकली और वह खौफनाक वक्त आ गया, जब वह मिल की मशीन में काम कर रही थी, तो मशीन ने उसकी बाँयी बाँह पकड़ ली और बाँह शरीर से एकदम अलग हो गई। तिरुवेल्लुवर जिले के अरम्बकम गाँव की निर्मला की करुणकथा यहीं नहीं रुकती। वह बताती है- ''इस हादसे के बाद मेरे मालिक ने मेरे इलाज पर हुए खर्च को देने से मना कर दिया। मेरी जिन्दगी बचाने के लिए मेरे माँ-बाप ने एक आम बागान वाले से कर्ज लिया और मेरा इलाज कराया। तब से यानि पिछले तीन साल से निर्मला का परिवार कर्ज चुकाने के लिए आम बागान में काम कर रहा है। काम के बदले परिवार के हर सदस्य को 10 रुपये रोजाना मिलते हैं, जो परिवार चलाने के लिए एकदम कम हैं।*

महाराष्ट्र की बारह साल की माया वी.के. का मामला भी इसी तरह दिल दहलाने वाला है। माया अपने गाँव की शराब भट्ठी में काम करती है। माया का मामला इस बात का सबूत है कि बच्चों से खतरनाक कामधन्धों में मजदूरी कराई जाती है। माया कहती है- ''भट्ठी में काम करते हुए मेरी आँखे जलने लगती हैं। मुझे अक्सर खाँसी हो जाती है। अल्कोहल में पानी और दूसरी चीजें मिलाते वक्त मेरे हाथ में मोटे-मोटे दाने निकल आए हैं।'' यह कहते हुए वह अपना हाथ दिखाती है। वह कहती है- ''हालाँकि मैं शराब भट्ठी में काम नहीं करना चाहती। मुझे परिवार की गरीबी के कारण मदद करनी पड़ती है। मेरी सभी बहनें मजदूरी करती हैं।'' परन्तु माया मैसूर आकर खुश हुई। उसने कहा- ''मुझे मेरे जैसे दूसरे बच्चों के साथ नाचने, गाने और खेलने का मौका मिला। जिन्दगी में मुझे ऐसा अनुभव पहले नहीं हुआ।'' ऐसी लड़कियों को अपनी जिन्दगी में नई सुबह का इन्तजार है, पर यह सुबह कैसे आएगी? कौन उनके सपने पूरे करेगा?

-(शंकरबेनुयर, ग्रासरूट फीचर्स; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 20/05/2003)

233) सामूहिक आत्महत्याएँ लोकतन्त्र पर कलंक :- *भारतवर्ष में आत्महत्या की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है। सामूहिक रूप से परिवारजनों द्वारा जहर खाकर, ट्रेन से कटकर, फाँसी लगाकर, पति–पत्नी व बच्चों सहित बेकारी, भुखमरी व कर्जे के बोझ के मारे लोग आत्महत्याएँ कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे देश के सभी राजनैतिक दलों के नेतागण गरीब जनता की खूनपसीने की कमाई पर मौजमस्ती कर रहे हैं। ये सभी नेतागण सत्ता के नशे में चूर हैं। अनेक नेता सत्ता पाने के लिए बेताब हैं। कोई जनता में त्रिशूल बाँट रहा है, तो कोई लाठी, तो कोई तलवारें बाँट रहा है। परन्तु जनता के भूखे पेट को रोटियाँ और प्यासे पेट को पानी का प्रबन्ध नहीं कर रहा है। करोड़ों टन गेहूँ, चावल और दूसरा अनाज गोदामों में पड़ा सड़ रहा है, तो दूसरी तरफ गरीब जनता भूखी मर रही है। यह कैसा गाँधी का रामराज्य है ?* ***-(उमाशंकरशर्मा, बिहारीपुर, बरेली, आवाज-ए-खबरदार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 20/05/2003)***

234) फावड़ा चलाकर घर पालती हैं राजस्थानी महिलाएँ :- *'वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के तट पर' के अलावा अगर निराला चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों में घूँघट निकाले कुदाली, फावड़ा चलाकर अपने हुक्केबाज शौहर का पेट पालने वाली महिला को देखते तो शायद कुछ और भी कहते। राजस्थान में भीषण अकाल में चलाए जा रहे राज्यव्यापी राहतकार्यों में 60 से 80 फीसदी तक महिलाएँ कार्यरत हैं। कई जगहों पर तो आलम यह है कि राहत कार्यों पर इक्का–दुक्का पुरुष ही काम करते नजर आते हैं। कार्यरत एक महिला का कहना था कि घर के पुरुष हुक्का गुड़गुड़ाने, राजनीति और गप्पबाजी में मशगूल रहते हैं। ऐसे में उनके पास मजदूरी करके परिवार चलाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 20/05/2003)***

235) संसद में धुआँ :- *हर फिक्र को धुएँ में उड़ाने के जजबे को संसदभवन में ग्रहण लगने जा रहा है। लिहाजा अब आप संसद के गलियारे में अपने पाइप से कश भरते प्रणव मुखर्जी, मँहगे सिगार के सुभाषित धुओं के छल्लों में अपनी सदाबहार दाढ़ी में दमकते शराबकिंग विजयमाल्या और सस्ते सिगरेट से गुजारा करने वाले वामपन्थी कामरेडों को उनके चिरपरिचित अन्दाज में नहीं देख पाएँगे। धुएँ से गुरेज रखने वाले सांसदों की लाबी इस बात के लिए खासी सक्रिय है कि अब संसद के गलियारे में धूम्रपान करने वालों को ताकीद दी जाए। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश से अवगत कराया जाए, जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर पाबन्दी है। ध ूम्रपान विरोधी इस खेमे ने गलियारों से राखदानी (Ashtray) पहले ही हटवा दी है। अब गलियारों में उमड़ते–घुमड़ते धुओं के छल्लों से भी निजात मिल ही जाएगी।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 11/05/2003)***

236) माफ करें महामहिम :- *महामहिम राज्यपाल के पद को अपेक्षाकृत साफ–सुथरा व मर्यादित लोगों के लिए माना जाता है। परन्तु मौजूदा वाजपेयी सरकार ने तो मर्यादा और नैतिकता की न्यूनतम सीमारेखा को भी ध्वंसित कर दिया है। खुफिया विभाग ने अभी प्रधानमन्त्री को एक रिपोर्ट सौंपी। उसके निष्कर्ष बेहद चिन्ताजनक व चौंकाऊ हैं। पिछले दिनों जो सरकार ने नये राज्यपालों की नियुक्तियाँ की हैं, उनमें से कई के काले चिट्ठे खुफिया विभाग ने अटल आडवाणी को सौंपे हैं। इनमें एक कानूनी पृष्ठभूमि वाले महामहिम, जो राजग सरकार के एक मन्त्री के निकट रिश्तेदार भी हैं, उनकी भ्रष्टाचार की लम्बी फेहरिस्त एक महामहिम को अपने सरकारी नौकरीकाल में ही दो बार बर्खास्त हो चुके थे। एक का तो बायोडाटा ही झूठा पाया गया और भ्रष्टाचार में लिप्तता तो एक आम बात है।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 11/05/2003)***

237) *दलित ईसाइयों के जीवनस्तर में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शैक्षिक बदलाव लाने के मद्देनजर उनके संगठन 'पुअर क्रिश्चियन लिबरेशन मूवमेन्ट' ने नई दिल्ली घोषणापत्र जारी करते हुए बाइबिल के इस वृत्तान्त का हवाला चर्चनेतृत्व को दिया कि वह भ्रष्टाचारी जक्कई के जीवन से शिक्षा लेकर प्रभुमार्ग का अनुसरण करके दलित ईसाइयों का हक चर्चों में समान अधिकार एवं भागीदारी उन्हें तुरन्त उपलब्ध करवाए। दलित ईसाइयों ने अपने भविष्य के लिए भारत के चर्च नेतृत्व के सामने अपनी दस माँगे रखीं। चर्चनेतृत्व तब से लेकर आज तक इन माँगों पर टालमटोल वाला रवैया अपनाता रहा :–*

1) **भूमि :** *अपने सामाजिक एवं आर्थिक अस्तित्व को बचाए रखने हेतु ग्रामीण दलित ईसाई परिवार को तीन एकड़ कृषियोग्य भूमि उपलब्ध करवाने के लिए ठोस योजना बनाई जाए। दलित ईसाइयों के पास घर बनाने के लिए भी जमीन उपलब्ध नहीं है। जहाँ दलित ईसाई भूमिहीन और खेतमजदूर हैं, वहीं दूसरी ओर भारतसरकार के बाद चर्च के पास सबसे अधिक भूमि है।*

2) शिक्षा : *दलित ईसाई बच्चों को चर्च, स्कूलों व अन्य शिक्षण संस्थानों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। चर्च के अधिकार में भारत के सबसे बेहतर संस्थाएँ हैं। जिनका उपयोग राजनेताओं, पूँजीपतियों एवं ब्यूरोक्रेट लोगों के बच्चों की शिक्षा के लिए होता है। मौजूदा समय में देशभर के अन्दर चर्चों द्वारा 40 हजार शिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। इसके बावजूद दलित ईसाइयों के बच्चे निरक्षर एवं बालमजदूरी जैसे कार्यों में लगे हुए हैं। मौजूदा समय में चर्चों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान व्यापारिक केन्द्र बन गए हैं। चर्च की सारी सम्पत्ति पर मुट्ठी भर विशपों–पादरियों का कब्जा है।*

3) धर्मप्रचार और धर्मपरिवर्तन : *दलित ईसाई चर्चों में भीड़ (संख्याबल) बढ़ाने का औजार बनकर रह गए हैं। ईसाई मिशनरी धर्मप्रचार और धर्मपरिवर्तन के कार्य को 100 साल तक स्थगित कर दलित ईसाइयों के विकास के लिए कारगर कदम उठाए, क्योंकि वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हाशिए पर खड़े हैं। धर्मप्रचार और चर्चों पर खर्च होने वाले धन को गरीब मसीहियों के विकास पर खर्च किया जाए। धर्मप्रचार का यह धन्धा दलित वर्गों को गर्त में ले जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसकी आड़ में चर्चों का नेतृत्व विकास की सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा है।*

4) आरक्षण नहीं भागीदारी : *चर्चनेतृत्व द्वारा शुरु किए गए आरक्षण स्तुतिगान (दलित ईसाइयों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने की माँग) हमारे लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। चर्चनेतृत्व पिछले एक दशक से दलित ईसाइयों को आरक्षण का लालीपाप दिखा रहा है। वह सरकार से दलित ईसाइयों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने की माँग 1950 से करता आ रहा है। चर्चनेतृत्व अपनी माँग के समर्थन में मजहबी सिखों एवं नव बौद्धों को इस सूची में शामिल किए जाने का तर्क देता है। परन्तु उसने यह कभी बताने का प्रयास नहीं किया कि इस सूची में शामिल करने से इन दोनों वर्गों के जीवन में क्या बदलाव हुए।*

-(आर.एल.फ्रांसिस, दलित ईसाई स्वतन्त्रता आन्दोलन के अध्यक्ष; धर्मकर्मअंक; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 05 एवं 12 मई, 2003)

238) माया की माया : अब न्याय के क्षेत्र में भी आरक्षण :- *उत्तरप्रदेश के मुख्यमन्त्री साहिबा ने अब न्यायपालिका के क्षेत्र में अपनी असीम अनुकम्पा का परिचय देते हुए यह फरमान जारी किया है कि उनके प्रदेश में श्रम न्यायालय तथा औद्योगिक ट्रिब्यूनल दोनों में प्रिजाइडिंग ऑफीसर्स की नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओ.बी.सी. यानि दूसरे पिछड़े हुए लोगों का आरक्षण 50% होगा और दो हफ्तों के अन्दर इसका क्रियान्वयन आरम्भ हो जाएगा। यह खबर इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसी भी क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान राष्ट्र के लिए बड़ी घातक अवधारणा है और जो कुछ राष्ट्रहित में नहीं, हर हाल में उसका विरोध होना चाहिए। आरक्षण के नाम पर योग्यता के मापदण्डों से समझौता करना देश को विनाश के मार्ग पर डालना है। चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे जनजाति, चाहे पिछड़े हों या कोई और इनके उत्थान के लिए, इनको योग्य बनाने के लिए जी भरकर उन्हें संरक्षण दें। परन्तु जहाँ तक नियुक्तियों का प्रश्न हो, चाहे वह इंजीनियरिंग, मेडिकल कालेज में एडमीशन हो, सांसदों, विधायकों का चुनाव हो या अन्य कोई क्षेत्र हो आरक्षण की व्यवस्था करना एक दोषपूर्ण कृत्य है और हर हाल में इसे मिटना चाहिए। बाबा साहब की खुद की मंशा थी कि मात्र दस वर्ष के लिए आरक्षण दिया जाए और अविलम्ब इसे हटा लिया जाए। अन्यथा भारत में प्रतिभा का विकास नहीं होगा, वह कुंठित रह जाएगी।*

बिहार राज्य से मेरी जान–पहचान के एक व्यक्ति दिल्ली आए थे, जो अपने परिवार की किसी महिला के अल्सर का आपरेशन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में कराना चाहते थे। मूलतः रहने वाले वह गया नामक शहर के हैं। जब बात का सिलसिला चला, तो मैंने जिज्ञासावश पूछा– ''क्या आपके अपने शहर में इतना छोटा सा आपरेशन संभव नहीं हो सका।'' वह बोले– ''रिजरभेशन में कोटा से एम. बी.बी.एस. पास तो अपना भतिजवा भी है। पर का ओका से आपरेशन कराके जान का रिस्क उठाएँ?'' नेताओं के अपने रिश्तेदारों के आपरेशन तो एम्स और अपोलो में ही होंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि राजनीति कुछ और है, हकीकत कुछ और। रिजर्वेशन कोटा वालों से इलाज करवाने के लिए तो निरीह जनता है ही।

इसीप्रकार मध्यप्रदेश के किसी इंजीनियरिंग कालेज में दाखिले का मामला तो हाईकोर्ट तक जा पहुँचा। प्रवेश परीक्षा में जिसके 68% नम्बर आए, वह प्रवेश से वंचित रह गया परन्तु अत्यन्त पिछड़े के लिए आरक्षित सीट पर शून्य प्रतिशत वाले का नामांकन हो गया।

रिजर्वेशन अर्थात् आरक्षण की अवधारणा तो समाज के लिए ही नहीं, पूरे राष्ट्र को विनाश के गर्त में ढकेलने की एक क्रूर साजिश है। अब मायावती की ही बात लें। क्या अयोग्य व्यक्ति अब न्याय देंगे ? इसके साथ ही एक प्रश्न मैं राष्ट्र के प्रबुद्ध नागरिकों के समक्ष रखना चाहता हूँ। जिस क्षेत्र में संसदीय चुनाव लड़ने के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति की सीट आरक्षित कर दी जाती है, वहाँ कोई अन्य अगर चुनाव में खड़ा होना भी चाहता है, परन्तु खड़ा नहीं पाता, तो क्या ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यह आरक्षण की अवधारणा संविधान के मूल ढाँचे और मौलिक अधिकारों के विरोध में खड़ी है ? क्या यह सरासर प्राकृतिक न्याय का घोर उल्लंघन नहीं है ?

एकलव्य जैसा धनुर्धर द्रोणाचार्य से आरक्षण की भीख माँगने नहीं गया था। उसने गुरु की मजबूरी को समझा और अपने में इतनी योग्यता पैदा की कि गुरु द्रोण भी काँप उठे। एकलव्य का कटा अगूँठा गुरु द्रोण की कर्तव्यहीनता का एक उदाहरण है, जिसकी कीमत उन्हें शिर देकर चुकानी पड़ी। जो आरक्षण माँगते हैं, वही इसका प्रतिरोध करें। वही आवाज उठाएँ कि हमें इस भीख की जरूरत नहीं। इन दलित नेताओं को दलितों से कितना लगाव है, वह तो जगजाहिर है। दलितों को शिक्षित बनाया जाए, उन्हें योग्य बनाया जाए, उन्हें स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ दी जाएँ, परन्तु आरक्षण के नाम पर उनका राजनीतिक शोषण बन्द हो। आरक्षण के नाम पर राजनीति करने वाले, राष्ट्र के मूल्यों से खिलवाड़ कर रहे हैं।

-(अश्विनीकुमार, सम्पादकीय; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 09/05/2003)

239) जिसकी लाठी उसकी भैंस :- खबर है कि बिहारी नेताओं को लाठी बहुत भा गई है। इसलिए वे तथा उनके चेले आजकल अपने पास लाठियाँ रखने लगे हैं। बिहार और यू.पी. वाले बहुत पहले से लाठियाँ अपने कन्धों पर रखते थे। लेकिन आजकल जमाना बन्दूकों और तमंचों का आ गया है। यू.पी. और बिहार में सरेआम आजकल लोग अपने कन्धों पर बन्दूक उसी शान से लटकाए हाट-बाजार में घूमते हैं, जैसे कभी लाठी रखकर घूमते थे। लाठी की महिमा के भला क्या कहने ? कहावत बनी है कि 'जिसकी लाठी उसकी भैंस'। इसका वास्तविक अर्थ होता है कि- जिसके पास शक्ति है, उसी के पास सत्ता है। इस लाठी को फिर से मिल रही शोहरत से एक डर मुझे अवश्य लगने लगा है कि कहीं बरेली के बाँस ही न खत्म हो जाएँ। और फिर 'न रहे बाँस न बजे बाँसुरी' वाली कहावत चरितार्थ होने लगे। अब लाठी वापस अपने पुराने रंग-ढंग में लौट रही है, तो मुझे खुशी भी है और गम भी। इसलिए कि जिसकी लाठी में दम होगा, वही भैंस को हाँक कर ले जाएगा और चुनाव में जीतेगा। अब भैंस कितना लाभ-हानि पहुँचाती है, यह तो लाठी के दम पर भैंस हाँककर ले जाने वाला ही बताएगा कि उसकी लाठी में कितना जोर था और कितने काम की रही।

-(हरिप्रसादचौरसिया, 26/7 राधागंज, देवास, म.प्र.; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 09/05/2003)

240) रिजर्व बैंक ने ब्याजदर में कमी का सिलसिला जारी रखा :- रिजर्व बैंक ने ऋण को सस्ता रखने की अपनी नीति को जारी रखते हुए आज बैंकदर और आरक्षित नगद अनुपात (सी.आर.आर.) में चौथाई प्रतिशत की कमी करने के साथ ही कृषि, आवास और निर्यात क्षेत्र के लिए ऋण सुविधाएँ बढ़ाने के कई उपायों की घोषणा की। बैंकदर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है, सवा छह प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत कर दी गई है। **-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 30/04/2003)**

241) बहुत जल्द खत्म होगा पास-फेल का झंझट :- केन्द्र सरकार ने परीक्षा में विफल होने वाले छात्रों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति को गंभीरता से लेते हुए शिक्षापद्धति में व्यापक पैमाने पर सुधार करने की योजना बनाई है, जिसमें प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भारी-भरकम बस्तों से मुक्ति दिलाने के साथ ही पास-फेल का झंझट खत्म करना भी शामिल है। मानवसंसाधनविकासमन्त्री मुरलीमनोहर जोशी ने लोकसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान विभिन्न सवालों के जबाव में बताया कि बच्चों के दिलोदिमाग से पास-फेल की मानसिकता और बस्ते के बोझ को खत्म करने के लिए परीक्षापद्धति में व्यापक सुधार की योजना है। **-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 30/04/2003)**

242) भारतीय राजनीति में नैतिकता का निरन्तर ह्रास :- केन्द्र और राज्यों में सरकारें अराजकता (अनुशासनहीनता) का वातावरण निर्मित कर रही हैं। ताकि वे अपने दयनीय क्रियाकलाप के लिए जबावदेह सिद्ध न हों। सावजनिक जीवन को आधारच्युत करने का वही पुराना प्रयास है। पुनः लोकतान्त्रिक मूल्यों के क्षरण की स्थिति है। प्रभावी विमत

का गला घोंटा जा रहा है। उद्धत और मनमानी कार्यवाहियाँ बेखौफ के की जा रही हैं। प्रजापीड़क सभी स्तरों पर अपनी पकड़ बना चुके हैं। मंत्रियों और उनके चाटुकारों ने अपनी धमकियों से ऐसा भय पैदा कर दिया है कि आम तौर पर लोकसेवक अब प्रजाउत्पीड़न के सुलभ उपकरण बनकर रह गए हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के बाहुबलियों द्वारा जनता को धमकाने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। वे अपने आप को गुटों में संग्रहित कर रहे हैं। विश्वहिन्दूपरिषद के त्रिशूलवितरण के आग्रह ने बिहार में लालूप्रसादयादव को लाठी चमकाने पर प्रेरित कर दिया। आन्ध्रप्रदेश और उड़ीसा में आतंकवाद आम है। त्रिशूल हिन्दुत्व का नया नकाब बन गया है। जब लक्ष्य सत्तामात्र ही हो तो साधनों का महत्त्व नहीं रह जाता। जब साधनों की शुचिता महत्त्वहीन हो जाए, तो लक्ष्य भी प्रदूषित होना सुनिश्चित है। यह एक त्रासदी ही है कि महात्मा गाँधी का भारत किस तरह से अपराधियों और दुष्चक्रों में लिप्त लोगों की क्रीड़स्थली बनकर रह जाए। ***-(कुलदीप नैय्यर, स्तम्भकार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 07/05/2003)***

243) भाजपा और काँग्रेस को वोट देना मतदाताओं की मजबूरी :- *राजनीतिक क्षितिज पर स्थानापन्न के अभाव में वह सार्थक परिवर्तन नहीं हो पाता, जो राष्ट्र की गरिमा के अनुरूप हो। वर्तमान परिदृश्य में काँग्रेस और भाजपा की स्थिति नागनाथ और साँपनाथ ही तरह है, जिन्हें वोट देने की जनता की मजबूरी है। भ्रष्टाचार, नशा, हिंसा, अश्लीलता के पक्षधरों से राष्ट्र का कल्याण संभव नहीं। आत्मबलविहीन, सत्तालोलुप राजनेता घनानन्दों की तरह राष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। आज देश को उस महामनस्वी चाणक्य की आवश्यकता है, जो इन्हें हटाकर सत्ता की बागडोर ईमानदार चरित्रनिष्ठ के हाथों में सौंपे। दूसरी तरह* ***'वयं राष्ट्रे जागृयां पुरोहिताः'*** *के संकल्पधारी ब्रह्मपरायण जनचेतना को जागृत, संगठित, सुलक्षनिष्ठ बनाकर कुरीतियों को मिटाना होगा।* ***-(एक पाठक; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 07/05/2003)***

244) सद्दाम ने हमले से पहले बैंक से एक अरब डालर निकलवाए :- *इराक की राजधानी बगदाद पर अमरीकी बमबारी शुरु होने से कुछ ही घण्टे पहले राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के दोनों पुत्रों और एक निकट सलाहकार ने देश के सेन्ट्रल बैंक से करीब एक अरब डालर नगद निकाले। बैंक से धननिकासी का आदेश सीधे सद्दाम हुसैन ने दिया था, क्योंकि उनके दोनों पुत्र राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला पत्र लेकर गए थे, जिसमें धन निकालने के लिए उन्हें अधिकृत किया गया था। हुसैन शासन के दौरान बैंक में ऊँचे ओहदे पर काम कर चुके इराकी अधिकारी ने कहा– कि न तो ध न निकासी का कोई वित्तीय कारण बताया गया और न ही किसी ने यह बताया कि उसे कहाँ ले जाया जाएगा ? उन्होंने कहा कि जब सद्दाम हुसैन का आदेश हो तो उस पर आप बहस नहीं कर सकते। अधिकारी ने कहा कि बैंक से निकाली गई राशि इतनी अधिक थी कि उसे ले जाने के लिए तीन ट्रैक्टर ट्रॉली की जरूरत पड़ी। ट्राली पर नकदी लादने में श्रमिकों को करीब दो घण्टे लगे।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 07/05/2003)***

245) दहशतगर्द मुसलमानों को आइना दिखाने की कोशिश :- *इस लेख से मैं दहशतगर्द मुसलमानों को आइना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बेगुनाहों के खून से हमारी जमीन लाल कर रहे हैं। आज से तकरीबन 1500 साल पहले रसूल अल्लाह की पैदाइश हुई। उस वक्त अरब में बुराइयों का बोलबाला था। जिहालत और कट्टरपंथिता का दौर था। लड़कियों को पैदा होते ही मार देना। शराबनौशी, सूदी (ब्याजखोरी), माशराँ जैसी चीजें अरब में चारों ओर फैली थीं। मोहम्मद साहब ने दर्स देना शुरु किया। जबान और अपने किरदार से लोगों का दामन बुराइयों से पाक करना शुरु किया। उन्हें समझाया कि इस्लाम अमन और इंसानियत का पैगाम है। इसमें बुराइयों और कट्टरपंथिता के लिए कोई जगह नहीं है। रसूल का मकसद वह मुसलमान कतई नहीं था, जो कि नमाजें पढ़कर कत्ल करे और घर उजाड़े। उनका मकसद इंसानियत और अमन था। इसलिए तारीख गवाह है कि रसूल ने कभी हाथ में तलवार नहीं ली। रसूल का जमाना इस्लाम का वक्ते अव्वल था। मोहम्मद साहब ने अपने खानदान के साथ मिलकर लोगों को चैन से जीना सिखाया और इस्लाम का दर्से अव्वल जो इंसानियत (इंसाफ) और अमन (शान्ति) था, लोगों तक पहुँचाया। इस तहरीक में मोहम्मद साहब का साथ दिल से सिर्फ उनके खानदान ने दिया।*

रसूल ने अपने जमाने में जो दर्स दिया था, जिन बुराइयों को दूर किया था, वह अरबवासियों की जरी–ए–मुआश थी। वह बलात्कार और सूद की रोटी खाते थे। रसूल के सामने वे चुप रहे। मगर रसूल के बाद कर्बला में उन मुसलमानों ने हुसैन को कत्ल करके ये पैगाम दे दिया कि हम कभी न सुधरने वाली

मखलूख हैं। कल हुसैन का कत्ल करके इंसानियत को अरब की जमीन पर सुलाकर ये मुसलमान कट्टरपंथिता का लबादा ओढ़कर जमाने हाल तक आ पहुँचा। यह आग भी लगाएगा, लाशों पर घोड़े दौड़ाएगा, बरछी के फल सीने में तोड़ेगा, औरतों को नंगे सर बाजार में घुमाने से नहीं हिचकेगा। यहाँ है हुसैन का कातिल इससे वफा की उम्मीद करना बेकार है। जब कल ये रसूल और हुसैन के साथ वफा नहीं कर सके, तो आज ये जमाने हाल के साथ क्या वफा करेंगे? खून बहाना इनकी तारीख का एक अहम हिस्सा है वह हम कर्बला के मैदान में देख चुके हैं। ऐ खुदा! तेरी बारगाह में इल्तजा है कि दुनिया में हुसैनी मुसलमान पैदा कर, जो वतन से प्यार करें, इंसानियत और हक के लिए हुसैन की तरह जान दे दें। मगर इन जालिमों की तरह किसी बेगुनाह की जान लें नहीं।

आज की दुनिया को मुसलमाँ की है दरकार।
जो कल नहीं शरीक था कत्ले हुसैन में॥

-(हसन अब्बास नकवी, कानपुर; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 05/05/2003)

246) हमारे नेताओं व अधिकारियों में अपने मुँह मियाँ मिठ्ठू बनने की प्रवृत्ति : क्या कोई इन्हें रोक सकता है? *:-*
मैं उन तथाकथित उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में सभी प्रमुख समाचार पत्र-पत्रिकाओं में बराबर छपने वाले विज्ञापनों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इनके नमूने एक जैसे ही होते हैं। प्रधानमन्त्री का चित्र, कभी-कभी राष्ट्रपति का चित्र, सम्बन्धित मन्त्री अथवा कभी किसी वरिष्ठ नौकरशाह का चित्र होता है, तारीफ करने की भाषा भी एक सी होती है। आमतौर से लिखा जाता है- 'श्री या श्रीमती फलाने-फलाने के शानदार नेतृत्व में यह देश या राज्य महानतम भविष्य की ओर बढ़ रहा है', या फिर इसी तरह के दूसरे शब्द होते हैं। जो स्त्री या पुरुष विभिन्न मन्त्रालयों के प्रचार विभाग चलाते हैं, उनका शब्दकोष बहुत ही सीमित होता है। वे यह भी जानते हैं कि कोई भी यह सब पढ़ने की जरूरत नहीं समझता और जो पढ़ते भी हैं, उनकी बातों को गम्भीरता से नहीं लेते। क्या आपको कुछ आइडिया है कि इन सब विज्ञापनों पर कितनी लागत आती है और इन सबका पैसा कौन देता है? अनुमान है कि इन पर लगभग 2000 करोड़ रुपये की लागत आती है और यह विशाल राशि प्रतिवर्ष इन विज्ञापनों पर खर्च होती है। यह दसियों बरस से चल रहा है और यह बढ़ता ही जा रहा है। क्या कोई इन्हें रोक सकता है? जिन समाचार पत्र-पत्रिकाओं को इनसे कमाई होती है, वह तो कभी नहीं चाहेंगे, न ही मन्त्रालयों के जन सम्पर्क विभाग जिनकी इन विज्ञापनों से जबरजस्त शान बढ़ती है, न ही वो राजनीतिज्ञ और मन्त्री जिन्हें मुफ्त की पब्लिसिटी मिलती है। सार्वजनिक धन की इस बर्बादी को कोई एक नागरिक ही रोक सकता है।

-(सुप्रसिद्ध पत्रकार सरदार खुशवंत जी; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 03/05/2003)

248) भारत ऐसे तो आर्थिक शक्ति बनने से रहा : बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल आदि माँगों में कोई अन्तर नहीं आया :- *मुझे हमारे 'बड़े शहरों' और 'वास्तविक भारत' के बीच की खाई देखने का अवसर मिला। खुली अर्थव्यवस्था के परिणामस्वरूप यह और भी गहरी होती दिखाई दी। वास्तविक भारत में लोग बिजली और पानी से अधिक कुछ नहीं चाहते। हमारे देश के 20 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं और हमारी 73 फीसदी देहातों में रहती है, जिनकी प्रति व्यक्ति आय चीन के प्रति व्यक्ति आय से आधी है। हमारी 60 फीसदी ग्रामीण जनता बिना बिजली के काम चला रही है और 50 फीसदी कृषियोग्य क्षेत्र मानसून पर निर्भर है। स्वयं को भ्रमित कर यह सोचना बहुत आसान था कि भारत विकास की राह पर है। जब मैं भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तरप्रदेश गई, तो वास्तविक भारत का भयावह चेहरा अधिक भयानक दिखा। हर एक शहर भले ही एक स्लम नजर आ रहा था और बाजारों में सूअर सड़ा-गला खा रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ समृद्धि और आधुनिकता का कुछ असर तो दिखाई दिया। लेकिन इसके बाद मैं हाइवे से गाँवों को जाने वाली सड़कों तक पहुँची। यहाँ पहुँच कर ऐसा लगा मानो मैं किसी और सदी की टाइम मशीन में चल रही हूँ। यह क्षेत्र जगमगाती नई दिल्ली से मात्र 100 किलोमीटर दूर था। फिर भी आर्थिक सुधारों का कोई लाभ यहाँ तक नहीं पहुँचा। गाँवों को जोड़ने वाली सड़कें धूल व गढ्ढों से भरी होती हैं। गाँवों में सिर्फ सड़कों और मेडिकल सुविधा की ही कमी नहीं है, बल्कि हर एक चीज की कमी है। जिस दिन मैं वहाँ गई तो पता चला कि यहाँ चार दिन से बिजली नहीं आयी। जब भी बिजली आती है, पूरे वोल्टेज में नहीं आती और बाकी समय आती ही नहीं है। फिर भी माह के अन्त में उनके पास बिल पहुँच जाते हैं। यदि हम अपनी*

फसलें उगाने में सफल होते हैं, तो किसानों की मेहनत के कारण ही। लेकिन किसानों को राज्य सरकार से जरूरत की कोई चीज नहीं मिलती। इन गाँवों को बिजली और साफ पानी के अलावा उचित स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं की भी जरूरत है ताकि ये गाँव सोलहवीं सदी से इक्कीसवीं सदी में प्रवेश कर सकें।

मैं जहाँ भी गई हर जगह यही स्थिति थी और अन्ततः वही शब्द सुनाई दिए– बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल। ये शब्द इतनी बार दोहराए जाते हैं कि राजनीतिक पत्रकार होने के नाते सभी चुनाव याद आ गए। लोगों की माँगों में कोई अन्तर नहीं आया। जब तक सरकार इन मूलभूत जरूरतों को पूरा नहीं करेगी, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारत कभी भी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता।

-(तवलीन, स्तम्भलेखिका; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 03/05/2003)

249) *भारत को क्षुद्र राजनीतिक षड़यन्त्रों से निकलना होगा। भारत में एक आन्तरिक अनुशासन कायम करना होगा। यहाँ कोई एक करोड़ रुपये (सरकारी धन) लगाकर जन्मदिन मना रहा है। कोई संसदीय कोष से कमीशन माँग रहा है। कोई पशुओं का चारा गटक रहा है। कोई लाठियाँ भाँझ रहा है। कोई त्रिशूल बाँट रहा है। कोई हीलिंग टच में लगा हुआ है। कोई आतंकवादियों को दूध पिला रहा है और सारे के सारे मरे जा रहे हैं कि अगले चुनाव में क्या होगा? ये लोग भूल गए हैं कि जब राष्ट्र के मूल्य ही नहीं बचेंगे, तो राजनीति कहाँ करोगे? भारत इन्हीं विडम्बनाओं के कारण महाविनाश की ओर बढ़ रहा है। क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या प्रतिपक्ष हैं तो सभी भारतीय ही। तो इस बेला में राष्ट्र की समस्याएँ गौण क्यों? संविधान आमूल–चूल संशोधित करो या नया लिखो। पर चुनावी दलदल और ओछी राजनीति से बचो। इसका रास्ता खोजो। सारे नेताओं से एक ही बात कहना चाहूँगा :–*

पक्षी मानव फूल जल, अलग-अलग आकार।
माटी का घर एक है, सारे रिश्तेदार॥

-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 02/05/2003)

250) लोकतन्त्र का यह रूप :- *उत्तरप्रदेश व बिहार जनसंख्या व आकार की दृष्टि से भारत के दो बड़े राज्य हैं तथा इन्हीं से लोकसभा के सबसे अधिक सदस्य चुनकर आते हैं। सबसे अधिक प्रधानमन्त्री उत्तरप्रदेश ने ही दिए हैं। लेकिन प्रशासन, विकास तथा आर्थिक क्षेत्र में दोनों का ही भट्ठा बैठा हुआ है। आज बिहार की चर्चा करते हैं, जहाँ राजनैतिक स्थिरता तो है, लेकिन आए दिन अपहरण, नरसंहार तथा लूटपाट की घटनाएँ होती रहती हैं और कानून व्यवस्था बुरी तरह चरमरा रही है। लालू यादव पर अपने मुख्यमन्त्रित्व काल में चारा घोटाने का आरोप लगा। वह जेल भी गए और अनेक मुकदमों का सामना कर रहे हैं। वह मुख्यमन्त्री पद से हटे लेकिन अपने स्थान पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमन्त्री बना दिया। इसप्रकार लालू परिवार का 13 वर्षों से बिहार में राज है। अराजकता के कारण बिहार में कोई भी पूँजीपति निवेश नहीं करना चाहता। वहाँ के व्यापारी व उद्योगपति माफियाओं के भय से बाहर जा रहे हैं। स्वयं को गरीबों का मसीहा कहने वाले लालू के राज में गरीबी और बेरोजगारी इतनी है कि लाखों लोग रोजी–रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। लालू को अपनी राजनीतिक गोटियाँ बिठाने, सस्ते नारे व नौटंकी करके अपने परिवार को सत्तासीन रखने से ही फुर्सत नहीं है। वह हर बात पर रैली को तैयार रहते हैं। चुनाव मैदान में उतरें तो रैली, गिरफ्तार हों तो रैली और जेल से बाहर आएँ तो भी रैली। उन्होंने 30 अप्रैल को पटना में 'लाठी घुमावन तेल पिलावन' महारैली निकाली। जनता को सम्बोधित करते हुए लालू ने नाटकीय अन्दाज में कहा– ''हमारी यह लाठी गाँधी जी की और भारतीय ग्रामीण जनता की शक्ति का प्रतीक है। भारत की जनता अपनी इस शक्ति का उपयोग करते हुए भाजपा को सत्ता से हटा दे। यह लाठी शक्ति भगवा ब्रिग्रेड द्वारा बाँटे जा रहे त्रिशूल को समाप्त कर देगी।*

बिहार में कुछ जगहों पर गोलीबारी भी हुई। एक सप्ताह से ही पटना में तनाव था। लाठियाँ खरीदने की होड़ में बिहार की बाँस मंडियों में लाठियों तथा बाजार में सरसों के तेल का अभाव हो गया। एक दिन पहले स्कूल–कालेज बन्द कर दिए गए। पटनावासी अपनी घरों से बाहर नहीं निकले। भय के कारण पटना के बाजार और पेट्रोलपम्प बन्द रहे व सड़कों पर रैली के वाहनों को छोड़कर कोई अन्य वाहन नहीं चला। रैली के समर्थकों और विरोधियों में तनाव के कारण पटना में रैली की पूर्व रात्रि में राजद के पूर्व विधायक रणधीर यादव के भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी तथा दो अन्य को घायल कर दिया। रैली में हिस्सा लेने आ रहे राजद वर्करों तथा भाजपा समर्थकों में दानापुर के जमालुद्दीन चक में वाहनों पर कब्जे के लिए हुई गोलीबारी में खगौल के भाजपा

नेता सत्यनारायण सिन्हा की मृत्यु हो गई तथा दो व्यक्ति घायल हो गए। इस घटना से उत्तेजित भीड़ ने 14 वाहनों को आग लगा दी। गोलीबारी की घटना लालू यादव की बेटी मीसा की ससुराल के पास हुई।

लालू ने संभवतः इस रैली द्वारा यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि बिहार में उनका ही एकाधिकार है। उन्होंने लोगों को जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत का संदेश देते हुए भाजपा से सत्ता की भैंस छीन लेने का आह्वान किया।

भारतीय राजनीति में लाठियों, त्रिशूलों और तलवारों का खुला प्रदर्शन हैरान करने वाला है। विश्व हिन्दू परिषद के नेता प्रवीण भाई तोगड़िया राजस्थान में त्रिशूल बाँट रहे हैं। दिल्ली के तालकटोरा मैदान में क्षत्रिय प्रतिष्ठा समारोह में सपा नेता अमरसिंह को तलवार भेंट की गई तथा उन्होंने अपने समर्थकों को भी तलवारें भेंट कीं। राजनेता कुर्सी बचाने या पाने के चक्कर में ही लगे हुए हैं तथा जनहित के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। लोग इन नौटंकियों से हैरान होकर पूछने लगे हैं– 'यह डेमोक्रेसी हैं या डाँगोक्रेसी''। आखिर लाठियों, तलवारों, त्रिशूलों की राजनीति अपनाकर हम किधर जा रहे हैं ? ***-(विजय, सम्पादकीय; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 02/05/2003)***

251) *राजधानी में किसान रैली थी और गरीब मजदूर लोगों को किसानों के कपड़े पहना–पहना कर ट्रकों में भरकर दिल्ली की सैर कराने ले जाया गया था। उसी रैली में नेताओं ने एवं राजधानी के चारों तरफ बड़े–बड़े फार्महाउसों के मालिकों ने किसानों के नाम पर खूब मगरमच्छी आँसू बहाए। ऐसे ही एक नेता से उसका भाषण समाप्त होने के बाद पूछा गया कि ज्वार और बाजरे में क्या अन्तर है तो वह खिसियानी हँसी हँसता हुआ बोला– ''मुझे ज्वार बाजरे से क्या काम ? मैं तो कृषि पर आयकर न लगे, इसलिए मंच पर बोला था। ताकि अपनी दो नम्बर की कमाई को कृषिआय की आड़ में एक नम्बर की कमाई में बदल सकूँ।''*

-(शिवशंकर गोयल, व्यंग्यकार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 02/05/2003)

252) सद्दाम के महलों व जेलों में घर बसा चुके हैं बेघर लोग :- *कभी इन आलीशान महलों और कुख्यात जेलों की ओर नजर घुमाकर देखने से पहले ईराकियों को कई बाद हिम्मत जुटानी पड़ती थी। लेकिन आज इनमें वे बेखौफ होकर अपनी जिन्दगी काट रहे हैं। सद्दाम हुसैन के आलीशान बंगलों और जेलों पर इन दिनों कई बेघर ईराकियों ने कब्जा जमा लिया है। सद्दाम के बेटों, नौकरों और अंगरक्षकों के बंगलों पर भी बेघर ईराकियों का कब्जा हो चुका है। सद्दाम के असली बंगले पर अहमद चालाबी की पार्टी के लोग कब्जा जमा चुके हैं। इस बंगले से कुछ फर्लांग दूर बने एक अन्य भव्य बंगले पर भी फ्रीडम एण्ड डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का कब्जा है। यह बंगला सद्दाम के सौतेले भाई वतबन इब्राहिम अलहसन का था। अब इसे पार्टी का मुख्यालय घोषित कर दिया गया है। फातिमा हवर और उनके छह बच्चे सद्दाम की एक जेल पर कब्जा जमाए हुए हैं। सद्दाम के एक बंगले पर कब्जा जमाए हुवैदी की पत्नी कितबा ने कहा कि इस बंगले में उन्हें काफी सुकून मिल रहा है। इसमें कमरों की भरमार है। मेरे बच्चे बेखौफ होकर अपने कमरों में चैन की नींद सोते हैं। दक्षिणी बगदाद में अबू नुवास स्ट्रीट में कई परिवारों में सद्दाम के महल से जुड़े कर्मचारियों के बंगलों पर कब्जा जमा रखा है। एक शिया मुसलमान अली ने कहा– ''पहले हमें इस गली से गुजरते हुए भय होता था। लेकिन अब हम इसी गली के निवासी हैं।''*

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 01/05/2003)

253) आखिर भ्रष्टाचार को कौन समाप्त करेगा :- *अक्सर सेमिनारों में चर्चाओं–परिचर्चाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन हमारी समाज व्यवस्था व शासन प्रणाली में सुधार करना चाहता है या कर सकता है ? क्या राजनीतिज्ञ या नौकरशाह ऐसा कर सकते हैं ? जनसामान्य की दृष्टि में आज ये दोनों ही भ्रष्ट हैं। सी. बी.आई. द्वारा नई दिल्ली में डी.डी.ए. के शीर्षस्थ अधिकारियों पर 27 मार्च, 2003 को छापे मारे गए तथा वहाँ से भारी मात्रा में अवैध धनराशि आदि बरामद की गई। हमारे नौकरशाह भ्रष्टाचार की किस सीमा तक पहुँच गए हैं ? उनकी ईमानदारी किस हद तक समाप्त हो गई है ? हमारे नौकरशाह व राजनेता भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें अधिकाधिक धन कमाने का अवसर मिलता है। इस ध्यान से वे अपने बच्चों के लिए अधिकाधिक कमाई वाले पद भी खरीदते हैं। इसके अतिरिक्त भ्रष्ट और बेईमान अधिकारियों को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता है। जब भी सतर्कता विभाग भ्रष्टाचार के विरुद्ध कहीं भी कदम उठाता है, तो उसमें ऐसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अधिकारी अपना बचाव कर लेते हैं। इसी प्रकार अन्य पहुँच वाले भ्रष्ट तत्त्वों को भी संरक्षण प्राप्त होता है।*

हमारे देश पर विदेशी ऋणों का बोझ भी निरन्तर बढ़ता जा रहा है। यह 31 मार्च, 2002 को 101. 3 बिलियन डालर (लगभग 5 लाख करोड़ रुपये) था। इस देश के आम आदमी के पसीने की कमाई का एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचारियों की जेब में चला जाता है और देश के आम आदमी को विदेशी कर्ज का बोझ चुकाना पड़ता है। हमारा भारत विभिन्न विरोधाभासों वाला देश है। यहाँ स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाओं पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं लेकिन आम भारतीयों विशेषकर ग्रामीणा क्षेत्रों को चिकित्सा सुविधा नाममात्र को ही मिल पाती है। अनेक स्थानों पर तो स्वास्थ्य सेवाओं का अस्तित्व ही नहीं है। 'सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएँ' का नारा पाखण्डमात्र है। भारतीय चिकित्सा क्षेत्र भी अन्य क्षेत्रों तथा प्रशासन की भाँति ही भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। सभी क्षेत्रों में सुधार की व्यापक आवश्यकता है। हमारी सड़कें और इन पर होने वाला यातायात भी सुरक्षित नहीं है। आज हमारे देश को भ्रष्टाचार और कुशासन के कारण ही इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सबका उपचार सुशासन और सदाचार से ही संभव है। अभी भी समय है कि हमारे नेता आत्मविश्लेषण कर उस गलत मार्ग को छोड़ें, जिस पर वे आँख मूँदकर चल रहे हैं और देश को पतन के गर्त में ले जा रहे हैं।

-(पूर्व सी.बी.आई.प्रमुख सरदार जोगिन्द्र जी; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 01/05/2003)

254) कानून हो या अपराधी शिकार होती हैं औरतें :- *जब कानून स्वयं अपराधी का संरक्षक बन जाए, तो समाज में पैर पसारते आतंक, अन्याय और अत्याचार को कौन रोक सकता है। जब रक्षक ही भक्षक बनने लगे तो सुरक्षा का दायित्व सँभाले कौन? अप्रैल 1998 में असम में घटी घटना में जम्मू-कश्मीर रायफल्स के एक सैनिक ने बन्दूक की नोंक पर 27 वर्षीय गर्भवती प्रेमोदेवी की अस्मिता उसी के घर में कुचल डाली। उत्तर-पूर्व के लगभग सभी राज्यों में सुरक्षाबलों के जवानों द्वारा वहशीपन का यह नाच खुलेआम कायम है। वे लोग घर के पुरुषों को इलाके के बाहर किसी एक स्थान पर बुलाकर एकत्र कर लेते हैं। महिलाओं को घरों में रहने को कहा जाता है। लुटेरों की भाँति बन्दूक की नोंक पर इन पुरुषों को चुप रहने की चेतावनी दी जाती है। किसी पुरुष द्वारा विरोध करने पर उसे मारा-पीटा जाता है।*

अत्याचार की अगली कड़ी में 14 जनवरी, 1999 की सुबह केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के सिपाहियों ने पुखाओ जिले की दो बहनों लेशराम विमोला देवी 32 वर्ष और लेशराम मनीषांग 29 वर्ष को अगवा कर लिया। उन पर अण्डरवर्ल्ड के अपराधियों को शह देने का मनगढ़ंत आरोप भी मढ़ दिया गया। वहशी सिपाहियों ने बेगुनाह महिलाओं के पैरों, जाँघों, कमर और गुप्तांगों पर लोहे की छड़ से वार किए। बाद में उन्हें यह कहकर छोड़ दिया कि उनके विरुद्ध फिलहाल कोई ठोस सबूत नहीं है। पीड़ित मासूम स्त्रियाँ महीनों अस्पताल में पड़ी रहीं। इस घटना के उत्तरदायी सिपाहियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। दर्ज भी हो तो सुनवाई नहीं होती अथवा अपराधी साफ बच निकलता है। उनके पीछे शीर्षस्थ राजनेताओं का हाथ होता है, जो स्वयं ऐसे कुकृत्यों में संलिप्त होते हैं। दिनोंदिन बढ़ते बलात्कार के हादसों से भयभीत, असुरक्षित महिलाओं को सरकार या सरकारी सुरक्षा प्रणालियों से उम्मीद कतई नहीं है। उत्तर-पूर्व के राज्यों में आतंकवाद की खबर तो अखबार की सुर्खियों में आ जाती है, परन्तु घर-घर में चुपचाप पाँव फैलाती यह आग कानून एवं प्रशासन के समक्ष कोई बावेला नहीं मचा पाती।

अब महिलाओं ने अपनी रक्षा का भार स्वयं सँभाल लिया है। स्वयंसेवी संगठनों ने इस दिशा में पहल की है। गाँव-गाँव में समूहों में बँटकर स्थानीय महिलाओं ने अपनी सुरक्षा को निश्चित करने की कोशिश शुरु कर दी है। 'मैरापैबी' समूह इस आन्दोलन का प्रथम स्थानीय कदम है। किन्तु इधर वे जागृति की मशाल लेकर खड़ी हुई हैं, तो दूसरी ओर से उन्हें अपने क्रिया-कलापों के लिए धमकियाँ मिल रही हैं।

-(पूजाप्रसाद शब्दार्थ; बुधवार्ता, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 30/04/2003)

255) धुएँ में उड़ती बीड़ी मजदूरों की जिन्दगी :- *जिला रामनगर की मझोली उम्र की घरेलू महिला आशाबाई जगने बीड़ियाँ बनाकर 15 रुपये रोज कमाती है। इस मामूली सी रकम के लिए उसे 8 घण्टे काम करना पड़ता है और 1000 बीड़ियाँ बनानी पड़ती हैं। इसके साथ-साथ उस पर 4 बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी भी है। आशा का पति झाड़ूरा मोची है और दिनभर में 30 रुपये कमाता है। मामूली सी कमाई और बड़े होते 4 बच्चों की माँग से परिवार पैसे के लिहाज से कमजोर हालत में है। इसके अलावा बीड़ियाँ बनाने से आशा के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ा है।*

ठीक ऐसी ही कहानी शंकरपुर के मोची शंकर और उसकी मध्य उम्र की पत्नी खेलबाई टांडेकर की है। दोनों रोजाना करीब चालीस रुपये कमाते हैं। इतने पैसे से वे ठीक से न घर खर्च चला पाते हैं और न ही अपने तीन छोटे बच्चों का लालन-पालन कर पाते हैं। इससे जाहिर होता है कि ज्यादातर बीड़ी मजदूर कितनी भीषण गरीबी में जी रहे हैं।

ये दोनों मामले छत्तीसगढ़ की बीड़ी पट्टी के महज उदाहरण भर नहीं हैं। असल में राजनन्दगाँव, रायपुर और दुर्ग जिलों के इस बीड़ी उत्पादन क्षेत्र में कार्यरत 50 हजार से ज्यादा बीड़ी मजदूरों की यही हालत है। जहाँ खेतिहर मजदूर के लिए 52 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी तय है, वहीं हजारों बीड़ी मजदूरों को यह मजदूरी नहीं मिल पाती। राजनन्द गाँव में यह धन्धा कुछ बड़े ठेकेदारों के नियंत्रण में है। उनके ऊँचे राजनीतिक रसूख हैं। रायपुर के कल्याण प्रशासक जे.के.प्रसाद ने बताया कि इस पिछड़े इलाके में रोजगार के वैकल्पिक अवसरों का अभाव है। राजनन्दगाँव के एक ईसाई अस्पताल के डाक्टर थामस अब्राहम के अनुसार बीड़ी उद्योग में लगी ज्यादातर महिलाएँ किसी न किसी तरह की श्वाँस की बीमारी से पीड़ित हैं। बीड़ी बनाने वाली महिलाएँ तम्बाकू खाने की आदत की भी शिकार हैं। अब्राहम ने कहा- ''छत्तीसगढ़ में बीड़ी मजदूरों का शोषण बहुत ज्यादा है। अतः आर्थिक हालत खराब होने से वे इलाज भी नहीं करा पातीं। मजदूरों में मुँह का कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है और इस कारण मौतें भी हो रही हैं। ज्यादातर बीड़ी मजदूर बहुत कम पढ़े-लिखे हैं। इससे भी उनका शोषण होता है।

-(संदीप, ग्रासरूट फीचर्स; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 29/04/2003)

256) अपनी आलोचना करने वालों की जीभें कटवा देता था सद्दाम :- *अमरीका के नेतृत्व में की गई सैनिक कार्यवाही के बाद देश में भले ही लूटमार तथा अफरा-तफरी का माहौल बना हो, किन्तु अब जनजीवन किसी सीमा तक सामान्य होने के संकेत भी मिल रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले एक दशक के दौरान पहली बार शिया मुसलमानों ने देश के दक्षिणी भाग में स्थित पवित्र कर्बला नगर में जाकर अपनी धार्मिक रस्में अदा कीं, क्योंकि सद्दाम हुसैन (सुन्नी) के शासनकाल में शिया मुसलमानों पर अपनी धार्मिक रस्में अदा करने पर प्रतिबन्ध लगे हुए थे। हालाँकि ईराक की 2.40 करोड़ की आबादी में 65% शिया मुसलमान हैं। इसी बीच ईराक में ईसाई समुदाय के लोगों ने भी अपनी धार्मिक रस्में शुरु कर दी हैं। तथापि उन्हें भय है कि यदि ईराक में कोई कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन सत्ता में आया तो उनके लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाएँगी। अब तो ईराकियों ने डिश एन्टिना के माध्यम से विभिन्न देशों के टेलिविजन कार्यक्रम देखने भी शुरु कर दिए हैं, जिन पर सद्दाम के शासनकाल में प्रतिबन्ध लगा हुआ था। जैसे-जैसे देश में सद्दाम समर्थक शक्तियाँ कमजोर हो रही हैं, 'बगदाद का कसाई' नाम से मशहूर सद्दाम हुसैन द्वारा अपनी ही जनता पर ढाए गए अत्याचारों की कहानियाँ भी उजागर हो रही हैं। फिराज अदनान नामक एक 23 वर्षीय युवक का मामला प्रकाश में आया है, जिसने बताया कि सद्दाम समर्थक मिलीशिया ने उसकी जीभ का एक हिस्सा काट डाला, ताकि वह सद्दाम की आलोचना न कर सके।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 29/04/2003)***

257) *'वॉइस ऑफ पार्टनर' के कुछ अंक पहले हमने इस अठारह हजार लोगों की व्यक्तिगत सदस्यता वाले संगठन के बारे में पढ़ा था, जो जन मुद्दों को उठाने में सम्पूर्णतः समर्पित है। इस अंक में 23 मार्च की रैली जिसमें जनशक्ति ने अपनी एकजुटता से साम्राज्यवादी ताकतों को पीछे हटने पर मजबूर किया। जनता की शक्ति का कदम बढ़ता ही गया। बाद में रैली दोपहर को पुरुषोत्तमदासटण्डन पार्क पहुँचकर एक बड़ी आम सभा में बदल गई। आज यहाँ सभा की थी- देश भर से आए मजदूर, किसान, कार्यकर्ताओं ने। आवाजें बुलंद थीं और जमीनी सच्चाइयाँ कह रही थीं। ये समस्याओं को इकट्ठा करके उनके समाधान की ओर बढ़ना था, खास करके खदानों में काम करने वालों की समस्याएँ, सरकारी आतंक, कर्मपाशा पैकेज, काम के अधिकार, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और भ्रष्टाचार तथा भुखमरी के खिलाफ संघर्ष आदि। मंच पर देशभर से पहुँचे साथियों ने भाषण दिए। संगठन के महासचिव श्री धीरेन्द्र भाई ने आज की स्थिति पर शीघ्र ही चोट करते हुए आह्वान किया कि लोग बन्द मुट्ठी लड़ें, हम हाथ न पसारें। बनारस के श्री लेनिन ने मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिन्ता जताई। श्री आर.बी.पाल ने वैकल्पिक शिक्षानीति बनाने की बात रखी, जिसका आधार होगा- 'सबको शिक्षा, एक सी शिक्षा'। इसे कॉमन स्कूल सिस्टम के तहत परिभाषित किया जाएगा। वक्ताओं ने जोर दिया कि विदेशी ऋण आधारित योजनाएँ बन्द हों। देश के जनता की सत्ता पर सीध*

ी पकड़ के लिए ग्रामसभा को सम्वैधानिक अधिकार देने की पुरजोर वकालत की गई। शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि कल्याणकारी योजनाओं को ईमानदारी से लागू किया जाए। यह सब देखकर किसी कवि की पंक्तियाँ याद आती हैं :-

गरज बरस प्यासी धरती को फिर पानी दे मौला।
चिड़ियों को दाने बच्चों को गुड़धानी दे मौला।।
दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है।
सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला।।

-(संजीवकौरा, लाइटहाउस; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 29/04/2003)

258) कानपुर में एक और दम्पत्ति ने फाँसी लगाई :- *एक सप्ताह पूर्व कर्ज और गरीबी से जूझ रहे पूर्व सैनिक तथा उसके परिवार के पाँच सदस्यों सहित की गई सामूहिक आत्महत्या के बाद शहर के दक्षिण क्षेत्र में ही एक और दम्पत्ति ने कर्ज, गरीबी और भूख से परेशान होकर फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दर्दनाक हादसे ने समूचे शहर को हिलाकर रख दिया। एक सप्ताह के अन्दर सामूहिक आत्महत्या की इस दूसरी घटना ने सामाजिक व्यवस्था पर भी प्रश्नचिन्ह लगा दिया।*

घटनाक्रम के अनुसार शहर के दक्षिणक्षेत्र में बर्रा थाना अन्तर्गत विश्वबैंक निवासी रामकिशोर गुप्ता और उनकी पत्नी पूनम का शव उनके कमरे में लटका हुआ पाया गया। इस बात का पता उस समय चला जब देर शाम कुछ महिलाएँ अपना कर्ज वसूलने रामकिशोर के यहाँ गईं। काफी देर तक आवाज लगाने के बाद कोई जवाब न मिलने पर ये महिलाएँ वहाँ से चलीं गईं और रात लगभग 8 बजे पुनः आईं तथा गुप्ता परिवार को आवाज दी। अन्दर से दरवाजा बन्द होने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलने पर पड़ोसियों को शक हुआ और वहाँ भीड़ एकत्र हो गई। कुछ लोगों ने पड़ोसियों के मकान की छत पर जाकर गुप्ता परिवार के मकान में झाँका तो आँगन से दोनों के शव लटके दिखे। पड़ोसियों और मृत दम्पत्ति के पुत्र रामू ने बताया कि उसके पिता की पहले गल्ले की दुकान थी लेकिन 1984 के दंगों में उसकी दुकान दंगाइयों ने बर्बाद कर दी। एक लाख रुपये कर्ज लेकर पुनः व्यापार शुरु किया। लेकिन घाटा लग गया। इसके बाद उन्होंने सुरक्षा गार्ड की नौकरी की और फिर माँ के साथ एक फैक्ट्री में नौकरी की। कर्ज का ब्याज न दे पाने के कारण बोझ बढ़ता गया। इसी बीच 8 माह पूर्व रामकिशोर ने अपने एकमात्र बेटे का विवाह बिना दहेज लिए किया था।

ज्ञातव्य है कि अभी गत दिवस नौबस्ता के संजयगाँधी नगर निवासी एक ही परिवार के छह सदस्यों ने इन्हीं परिस्थितियों में सल्फास खाकर आत्मघात किया था। ऐसी ही परिस्थितियों में बीते छह माह के अन्दर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 250 लोगों ने फाँसी, जहर अथवा ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन की कहानी का अन्त कर लिया। इन सभी मृतकों के सामने आर्थिक तंगी, गरीबी, भुखमरी और बच्चों का पेट पालने के लिए दूसरों से लिए गए कर्ज और उसके ब्याज की समस्याएँ थीं। शहर की औद्योगिक व्यवस्था डगमगाने के बाद गरीबी और आर्थिक तंगी से जूझते सैंकड़ों परिवारों पर सूदखोरों ने अपना शिकंजा कस रखा है। बन्द मिलों के कर्मचारी अथवा व्यवस्था में घाटा उठाने वाले लोगों की मजबूरी का फायदा पेशेवर सूदखोरों के साथ-साथ पुलिस कर्मियों ने भी उठाया। नौबस्ता के संजयगाँधी नगर में छह लोगों की सामूहिक हत्या के पीछे एक सिपाही से लिया गया कर्ज ही था। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि पुलिस इन सूदखोरों की मदद करती है। ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 29/04/2003)***

259) *पूर्वोत्तर भारत का दुर्भाग्य है कि गत 50 वर्षों में वहाँ पर कभी शान्ति नहीं हुई। हर रोज कहीं न कहीं बेगुनाहों के खून से होली खेली जाती है। अब तो समाचार पत्रों ने इन हिंसक घटनाओं को छापना तक कम कर दिया है। गत दो सप्ताह में कछार घाटी में रहने वाले दो आदिवासी कबीलों में हुई झड़पों में कम से कम 35 लोग मारे गए। ये खूनी झड़पें दिमासास और हमरा कबीलों के बीच हो रही थी। दिमासास कबीला हिन्दू हैं। इनका दावा है कि वे कभी प्राचीन राज्य दीमापुर के शासन थे, जिनको बर्मा से आने वाले नागाओं ने गुलाम बनाकर उनका राजपाट छीन लिया था। ये आदिवासी विगत तीन दशक से एक अलग राज्य बनाने की माँग कर रहे हैं। इनके द्वारा प्रस्तावित राज्य में क्योंकि नागालैण्ड का काफी हिस्सा शामिल है, इसलिए नागा विद्रोही उनके दुश्मन बने हुए हैं। नागा विगत 50 वर्षों से भारतसरकार के खिलाफ*

विद्रोह का झण्डा उठाए हुए हैं। नागा अधिकांश ईसाई हैं इसलिए उन्हें चर्च और पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त रहा है। इस अवधि में ये 35 हजार भारतीय फौजियों और अर्धसैनिक संगठनों के कर्मचारियों के खून से अपने हाथ रंग चुके हैं। नागाओं की माँग नागालैण्ड नामक आजाद देश का सृजन करना है। असम में बिगड़ती हुई स्थिति के लिए केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ही दोषी हैं। दोनों की तुष्टिकरण की राजनीति से उग्रवाद को प्रोत्साहन मिला है। उग्रवाद से भयभीत केन्द्र सरकार ने असम को सात राज्यों में विभाजित कर दिया। मगर इससे पृथकतावादी तत्त्व शान्त नहीं हुए। उनकी माँग बढ़ती ही जा रही है। कहा जाता है कि अब पृथकतावादी पूर्वोत्तर में 40 नये राज्यों के सृजन के लिए खूनी होली खेल रहे हैं। बोडो-सन्थाल खूनी संघर्ष के कारण गत चार वर्षों में 2600 व्यक्ति मारे जा चुके हैं।

-(नवनीहन शर्मा, स्तम्भकार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 28/04/2003)

260) भारत : मूल्यों की राजनीति बनाम राजनीति के मूल्य :- *एक फिल्म आयी थी जिसमें एक ऐसा गाना था, जो मैं आज तक नहीं भूल पाया। उसकी पहली मुख्य पंक्तियाँ थीं-*

बता मुझे ऐ जहाँ के मालिक, ये क्या नजारे दिखा रहा है।
तेरे समन्दर में क्या कमी थी, जो आदमी को रुला रहा है॥

जहाँ के मालिक के समन्दर की कमी के बारे में तो मैं नहीं जानता। परन्तु देश के जो नजारे आज नजर आ रहे हैं, वैसे नजारे तो शायद उस गीतकार की कल्पना के बाहर होंगे, जिसने तब उपरोक्त गीत रचा था। आज का शायर तो कह रहा है-

हर इक सफर को है महफूज रास्तों की तलाश।
हिफाजतों की रिवायत बदल सको तो चलो॥
यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता।
मुझे गिरा के अगर तुम सँभल सको तो चलो॥

आज हर व्यक्ति दूसरे को गिरा कर खुद कुछ पाने की तलाश में केवल दौड़ता चला जा रहा है। इस अन्धी दौड़ में वह खुद इस हद तक गिर चुका है कि राष्ट्र के मूल्य न जाने कहाँ गुम हो गए। ऐसी गन्दी राजनीति ने नाग की तरह हमारी विधायिका को डस लिया है कि उसका जहर शिर चढ़कर बोल रहा है। सारा समाज, सारा परिवेश, सारा राष्ट्र इस जहर के प्रभाव में आ गया है। हम चाहे स्वयं को कितना भी तटस्थ रखें और मानें कि हम प्रभावित न होंगे, ऐसा सोचना भी पागलपन है। दिनकर ने हमें यूँ ही अपराधी घोषित नहीं किया। यह एक चेतावनी थी, जो आज भी मुँह बाए खड़ी है :-

समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध।
जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास॥

सचमुच इतिहास के पन्नों पर वक्त की कलम इस अपराध को अंकित करती है। ईराक की हालत क्या आपसे छिपी है। 65% वहाँ शिया थे, 20% कुर्द थे, 2 या 4% सुन्नी भी थे। 90% लोग सद्दाम की तानाशाही को झेल रहे थे तथा जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे। केवल कुछ लोगों ने मुल्क को जहन्नुम बनाकर रख दिया था। सद्दाम के शिर पर जेहादी फण्डामेन्टलिज्म का भूत सवार था। आज सारी दुनिया इस मुल्क का हाल देख रही है। एक हँसता-खेलता मुल्क जिसे प्रकृति ने अकूत तेल सम्पदा बख्शी थी, वह बम के गोलों से तबाह हो गया। हजारों वर्ष पुरानी सारी सांस्कृतिक धरोहर नष्ट हो गयी। वहाँ मेसोपोटामिया, सुमेरियन, बेबीलोनियन सभ्यता की जो अमूल्य चीजें थीं, वे लुट गयीं। ईराक वीरान हो गया। कारण था- आम नागरिक जो हमारी ही तरह सोया हुआ था। पिछले 5 हजार वर्षों में सिर्फ एक ही मुल्क ऐसा है, जो पूर्णतः जागा हुआ है, वह है- इज्राइल; और एक ही मुल्क है, जो पूर्णतः सोया हुआ है, वह है- हमारा प्यारा भारतवर्ष। इस सोए हुए मुल्क के लोगों को बार-बार इसलिए झकझोरता हूँ ताकि उनमें से कुछ तो जाग जाएँ। सारी क्रान्तियाँ पहले मनस के तल पर ही होती हैं। हमें जागना होगा। वेदमन्त्र का भी यही आह्वान है- 'वयं राष्ट्रे जागृयां पुरोहिताः'। अर्थात् हम सावधान होकर राष्ट्र का नेतृत्व करें।

-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 28/04/2003)

261) ईराक में पढ़ाने के बजाय बोझा ढोते हैं शिक्षक : शिक्षा की घोर दुरावस्था :- *अज्ञानता का अन्धकार दूर करने वाले शिक्षक ईराक में बच्चों को 'पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब' सिखाने के बजाय खुद बोझ ढोने के लिए मजबूर हैं क्योंकि वहाँ पढ़ाने वालों को उतना भी वेतन नहीं मिलता, जितना दिहाड़ी मजदूरी उन्हें उपलब्ध कराती है। पश्चिम एशिया के जाने-माने विशेषज्ञ दिलीप हीरो ने अपनी पुस्तक 'ईराक : एक रिर्पोट फ्रॉम इनसाइड' में लिखा है- 'कम वेतन के कारण कई शिक्षक ज्यादा आमदनी वाला शारीरिक या अर्ध कुशलता की आवश्यकता वाले धन्धों में लग गए हैं ताकि उनकी रोटी ठीक से चल सके। ड्राइवर थेयर यूनुस तीस या पैंतीस साल का लम्बा और पुष्ट मांसपेशियों वाला आदमी है। वहाँ ईराक में 1997 से 1999 तक शिक्षा को होने वाले नुकसान को संयुक्त राष्ट्र मानवीय समन्वय के प्रमुख जर्मनी के हान्सवान सम्ओनेक ने बौद्धिक संहार कहा है।* **-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 28/04/2003)**

262) नातिन के सवाल पर लड़खड़ाए कलाम :- *राष्ट्रपति ए.पी.जे.अब्दुलकलाम की नातिन ने कल रात 12 बजे अपने नाना को फोन करके पूछा कि 'जज कैसे बनते हैं?' और जबाव सुनकर फोन का चोंगा रख दिया। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में 'न्याय तक पहुँच' विषय पर आयोजित एक विचारगोष्ठी में खुलासा किया कल रात जब वह अपने कम्प्यूटर पर बैठे गोष्ठी का भाषण तैयार कर रहे थे तभी रात 12 बजे उनकी बहन की नातिन का फोन आया। पहले तो उन्होंने उससे कहा कि वह एक जरूरी भाषण तैयार करने में लगे हैं इसलिए वह अभी खलल नहीं डाले और बाद में फोन करे। लेकिन उनकी नातिन ने आग्रह किया कि उसका सिर्फ एक सवाल है, जिसका वह अभी जवाब चाहती है। उन्होंने सवाल पूछा तो नातिन ने कहा- ''जज कैसे बना जाता है?'' जिस पर उन्होंने कहा- ''यह तो कुछ ज्यादा मुश्किल सवाल है।'' नातिन के इसरार पर उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा- ''अगर कोई जज बनना चाहता है तो उसे ऊँचे आदर्शों वाला होना चाहिए।'' इतना सुनकर उसने फोन का चोंगा रख दिया।*

गोष्ठी में उन्होंने कहा कि जज का पद बहुत ऊँचे आदर्शों और धर्मतत्त्वज्ञ का पेशा है। इसलिए इस पद पर आसीन होने वाले व्यक्तियों को पूरे सभ्य समाज के लिए एक आदर्श और अनुकरणीय उदाहरण होना चाहिए। **-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 27/04/2003)**

263) *हालाँकि हमारे देश ने 5 दशक पहले राजनीतिक तौर पर आजादी हासिल कर ली थी, लेकिन हमारे सामने अभी भी सबको सामाजिक न्याय दिलाने, चहुँमुखी विकास और अनुसूचित जाति तथा जनजाति और पिछड़े तबकों को सामाजिक दृष्टि से शक्तिसम्पन्न करने का एक अपूर्ण एजेंडा है। इस दिशा में हमने पिछले 5 दशकों में थोड़ी बहुत प्रगति अवश्य की है लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जनाकांक्षाओं को सामाजिक सौहार्द, परस्पर सहयोग और सुशासन के व्यापक संदर्भों में ही पूरा किया जाना चाहिए। (छत्रपति शाहूजीमहाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में दिए गए भाषण के अंश)*

-(उपप्रधानमन्त्री लालकृष्णआडवाणी; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 27/04/2003)

264) *संसद के हमारे दोनों सदन बहुत ज्यादा मेहनताने वाली 'डिबेट सोसायटियाँ' बन गए हैं। इन सदनों को राष्ट्रीय हितों पर विचार करने और कानून बनाने के लिए बनाया गया था। परन्तु किसी भी सदन में जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त होता है, सदस्य सेन्ट्रल हॉल से गप्पबाजी करने या अपने घरों पर आराम करने चले जाते हैं। जब किसी विचाराधीन बिल को पेश किया जाता है, तो इतने सदस्य भी नहीं होते कि कोरम पूरा हो सके और संसद के गलियारों में कोरम की घण्टी की आवाज गूँजती रहती है कि सदस्य अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए सदन में आ जाएँ। सांसदों पर भी अपने काम को पूरी तरह से अंजाम न देने के लिए दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि चाहें वे कानून बनाएँ या न बनाएँ, हमारे शहरों, कस्बों और देहातों में उनका नहीं बल्कि स्वायंभू नेताओं का शासन चलता है, जो हथियारबन्द लोगों के साथ रहते हैं। जब वे चाहते हैं, हड़ताल हो तो दुकानदान चुपचाप दुकानें बन्द कर देते हैं। जब वह चाहते हैं कि भारी रैलियाँ निकाली जाएँ और बाजारों के बीच से जुलूस ले जाया जाए, तो सामान्य जीवन और यातायात जाम हो जाता है। जब वे चाहते हैं कि उनके विरोधियों की पिटाई हो, तो वे यह भी करवा देते हैं। वह अपनी गिरफ्तारी को मजाक में बदल देते हैं। आप उन्हें पुलिस की गाड़ी में चढ़ते समय उंगलियों से 'वी' (Victory) का संकेत*

करते देख सकते हैं। अपने प्रशंसकों की ओर खुशी से हाथ हिलाते देख सकते हैं। घण्टे भर बाद उन्हें छोड़े जाते देख सकते हैं और वे विजयी मुद्रा में अपनी वातानुकूलित गाड़ियों में बैठकर वातानुकूलित बंगलों में लौट जाते हैं। उनके इशारों पर रेलगाड़ियाँ रोक दी जाती हैं और प्रमुख राजमार्गों पर रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। अगर यह दादागिरी नहीं तो और क्या है। दादागिरी आमतौर से वे राजनीतिज्ञ ही करते हैं, जो सत्ता में नहीं हैं, लेकिन सत्ता को हासिल करने के लिए तत्पर रहते हैं। सत्ता में बैठे राजनीतिज्ञ भी इस काम में थोड़ा अलग ढंग से शामिल रहते हैं, जिसे तानाशाही कहा जा सकता है। यह सब कुछ हमारे देश में इसलिए चलता रहता है कि जिन स्त्री-पुरुषों पर कानून बनाने और उसे अमल में लाने की जिम्मेदारी है, वह अपना काम नहीं करते। ***-(सुप्रसिद्ध पत्रकार, सरदार खुशवन्त जी; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 26/04/2003)***

265) *दिल्ली पर पुनः संकट के बादल मँडराने लगे हैं। इतिहास साक्षी है कि दिल्ली कई बार उजड़ी और फिर सज-सँवर कर आबाद होती रही। एक समय की इन्द्रप्रस्थ ने बाद में कई जख्म झेले। समझा जा रहा था कि आजादी के बाद राजधानी में सुराज का सपना साकार होगा। जबकि आज 55 साल की आजादी के बाद भी दिल्ली अभूतपूर्व बिजली संकट, लालफीताशाही की निष्क्रियता और निकम्मेपन का शिकार हो रही है। पानी घट रहा है, प्यास बढ़ रही है। राजनेताओं के विश्वासघात ने इसे सैकड़ों घाव दिए हैं। एक पक्ष है, जो स्वयं को दिल्ली का पुजारी कहता है। दूसरा जो सत्तारूढ़ है, वह स्वयंभू, जनसेवक, जनसेविका बनकर सब्ज बाग दिखा रहा है। घटनाक्रम गवाह है कि दिल्ली आज खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। शायर कहता है :-*

अच्छा तू जुल्म हम पे सैय्याद करे है।
पर बोंच के पिंजरे से आजाद करे है॥

निजी कम्पनियाँ सरकार के साए तले जनता को लूट रही हैं। आवश्यक सेवाओं व रख-रखाव का बजट कहाँ लुप्त है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। मौसम गर्म हो रहा है। बिजली व पानी की किल्लत से दिल्ली बेहाल है। प्रदूषण सीवरेज की घटिया व्यवस्था टूटी सड़कें, अस्पतालों की दुर्दशा, स्कूलों में शिक्षकों का अभाव, दिल्ली परिवहन निगम व अन्य परिवहन की चरमराती व्यवस्था, बिगड़ रहे कानूनी प्रबन्ध, अपराधों के बढ़ते ग्राफ, आम आदमी में घर कर रही असुरक्षा की भावना कुल मिलाकर यही लेखाजोखा है, उस इन्द्रप्रस्थ का।

-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 25/04/2003)

266) *प्रेत ही प्रेत हैं यहाँ दानव ही दानव हैं। खून चूसते दाँत हैं कहाँ हैं जो मानव हैं।। युद्ध मानव के उग्र स्वभाव का परिचायक है। मानव की हिंसक प्रकृति, उसकी कटुता, अहंकार व अविवेकी बुद्धि का मूर्तरूप है- युद्ध। एक हिटलर ने विश्व को युद्ध के नरक में ढकेल दिया था। विश्व का इतिहास इस तरह के विकृत मानसिकता वाले लोगों से भरा पड़ा है और भारत का इतिहास इससे कोई अलग नहीं है। छोटी-छोटी रियासतों से लेकर बड़े साम्राज्यों तक परस्पर युद्ध हुए हैं। शायद इसीलिए अहिंसा का सन्देश देने वाले महान धर्मविचारक, चिन्तक भी यहाँ खूब हुए हैं। 11 मई, 1998 को परमाणु परीक्षण के बाद हमें बताया गया कि भारत महाशक्तिशाली बन गया है। मिठाइयाँ बाँटी गईं। यह दिन विजय दिवस के नाम से मनाया गया। भारत द्वारा पोखरण द्वितीय ने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि देश की सब समस्याएँ सुलझ चुकी हैं। तुरन्त बाद पाकिस्तान द्वारा चगाई परमाणु विस्फोटों से मालूम पड़ा कि परमाणु बम तो वह राष्ट्र भी बना सकता है, जो लगभग पूरी तरह नहीं तो आधी से ज्यादा विदेशी सहायता पर टिका है।*

हम खुश हैं कि अब हम विश्वशक्ति बन गए हैं। बिना यह जाने-समझे कि परमाणु शक्ति का अर्थ क्या होता है? इसमें कितना खर्च होता है? फिर क्या सचमुच देश में बेरोजगारी खत्म हो गई? बालमजदूरी समाप्त हो गई? सब बच्चे स्कूल गए? सभी गर्भवती माताओं की देखभाल और बच्चों का स्वस्थ पालन-पोषण शुरु हो गया? सब ओर पानी पहुँच गया? बड़ी परियोजनाओं से उजड़े 4 करोड़ लोगों का पुनर्वास हो गया? देश में शान्ति छा गई? किसानों ने आत्महत्याएँ करनी बन्द कर दीं?

कारगिल युद्ध के बाद छह अगस्त को विश्वशान्ति दिवस पर शान्ति समर्थकों की बहुत बड़ी रैली हुई, जो लगातार हर वर्ष होती है। रैली के नारे थे- नाभिकीय हथियार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नाभिकीय हथियारों से मुक्त दुनिया चाहिए। हिरोशिमा-नागासाकी काण्ड नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भारत-पाकिस्तान की आवाम को नाभिकीय हथियार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। शस्त्रीकरण पर रोक लगाओ, रोक लगाओ। पोखरण और चगाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। शान्ति को एक मौका और दो, और दो। बम नहीं रोटी चाहिए, रोटी

चाहिए। नाभिकीय पागलपन खत्म करो, खत्म करो। ये नारे जनता की पूरी सोच को बताते हैं।

कुछ महत्त्वपूर्ण आँकड़े इस दौरान प्रसारित हुए। जैसे अगले दस सालों में सरकार परमाणु हथियारों पर 50 से 60 हजार करोड़ खर्च करेगी। किन्तु गरीबी मिटाने के लिए कितना? 3 हजार करोड़ से से भी कम। अन्तरिक्ष से परमाणु हथियारों का पता लगाने वाले उपग्रहों पर सरकार कितना खर्च करेगी? 2.5 हजार करोड़। किन्तु उड़ीसा में चक्रवात के बाद कितना खर्च किया गया? 850 करोड़। परमाणु हथियार के नियंत्रण पर कितना खर्च आएगा? 3525 करोड़। किन्तु गुजरात के भूकम्प में मृतकों और घायलों को मुआवजा दिया गया, 340 करोड़। वायुसेना जिन बेस कैम्पों से परमाणु हथियारों को छोड़ा जा सकता है, उनकी रक्षा के लिए खतरे को भाँपने वाले रडार और उसे नष्ट करने वाले मिसाइल पर कितना खर्च आएगा? 6250 करोड़। शहरों में कितना पानी और स्वच्छता पर खर्च किया गया? 223 करोड़। एक अग्नि मिसाइल का खर्च 15 हजार प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र चलाने के खर्च जितना। मिसाइल बनाने के इंतजाम के लिए खर्च 37 हजार गाँवों में पानी पहुँचाने के खर्च जितना। सिर्फ 150 परमाणु बम के लिए गोदाम पर खर्च की राशि सभी जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे मलेरिया, तपेदिक, ऐड्स में जितना पैसा लगता है, उसके बराबर है। एक परमाणु पनडुब्बी की कीमत एक हजार मेगावाट की बिजली बनाने वाले प्लान्ट की कीमत के बराबर है। दिल्ली में अगर बिजली न आए? जरा सोचिए!

छह अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया, जिसके तीन दिन बाद नागासाकी पर वैसा ही बम गिराया गया। तब दो लाख से अधिक लोग मारे गए और उसके बाद बम के दुष्प्रभाव के कारण हर वर्ष हजारों लोग मारे जाते रहे। अब जनता को देर तक भ्रमित नहीं किया जा सकता। मूर्ख तो बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। यह तो सिद्ध है कि परमाणु बम से सुरक्षा नहीं बल्कि असुरक्षा बढ़ती है। इस नष्ट होती संस्कृति के दौर में हर जीवन के मुँह से यही पुकार आती है :-

और कितनी आग उगलोगे, और कितना खून पीना है।
हम नाजुक फूल भगवान के हैं, हमें मौका दो हमें जीना है॥

-(संजीवकौरा, लाइटहाउस; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 22/04/2003)

267) चर्च ढाँचे पर एकाधिकार जमाए वर्ग ने भारत के दलित ईसाइयों को बियाबान व रेगिस्तान में परिवर्तित कर दिया है। इस कारण वह भेदभाव का शिकार होते रहने के बावजूद अपना विरोध नहीं जता पा रहे हैं। उनके अन्दर अपने अधिकारों के प्रति चेतना पैदा करना भी कठिन हो गया है। वंचितों के साथ चर्चनेतृत्व द्वारा भेदभाव कोई नया नहीं है। समाज के कमजोर वर्गों पर अपना शिकंजा कसने के मकसद से उनके ऊपर धार्मिक कर्मकाण्डों का इतना बोझ चर्चनेतृत्व ने लाद दिया कि वह उसे ढोते-ढोते ही स्वर्ग सिधार जाते हैं। यूरोप में जब अमानवीय जमींदारी या जागीरदारी प्रथा में लोग भूख अत्याचार और शोषण से बेहाल थे, उस जमाने में भी चर्च खुद बहुत बड़ा जागीरदार था और हजारों लाखों मजदूर उसकी जमीन पर काम करते थे। चर्चनेतृत्व इस सच्चाई को बहुत अच्छी तरह जानता था कि जब भी कोई जनक्रान्ति होगी, तो उसकी मार से न तो जमींदार बच सकेंगे और न ही पादरियों का गिरोह बच सकेगा। चर्चनेतृत्व अन्यायी व शोषकों का समर्थक था। इसलिए जब भी शोषित जनता जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती या बगावत करने की कोशिश करती, तो पादरी व बिशप उन्हें धर्म के नाम पर थपकियाँ देकर सुलाने लगते। चर्चनेतृत्व ने स्वर्ग के हसीन ख्वाब दिखाकर लोगों को जुल्म के खिलाफ लड़ने से रोके रखा।

अपने उदयकाल से ही भारत में भी चर्चनेतृत्व ने अपना संख्याबल बढ़ाने के मकसद से दलितों को अपने खेमे में भले ही शामिल किया हो, परन्तु अपने अधिकारों से सदैव ही वंचित रखा है। साइमन कमीशन के सामने दक्षिण भारतीय महिला ईसाइयों ने चर्चनेतृत्व के समानता वाले सिद्धान्त की पोल खोलते हुए एक माँगपत्र पेश किया था कि हम रोमन कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेन्ट दोनों ही प्रकार के ईसाई उसी अवस्था में हैं, जिस अवस्था में हमारे हिन्दू दलित भाई हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि चर्चनेतृत्व की हमारे विकास में किसी प्रकार की रुचि का न होना।

'पुअर क्रिश्चियन लिबरेशन मूवमेन्ट' का साफ मत रहा है कि आज भी दलित ईसाइयों की दशा हिन्दू दलितों से ज्यादा खराब है और चर्चनेतृत्व अपने ढाँचे में उन्हें अधिकार देने को तैयार नहीं है। ईसाई धर्म में 70% जनसंख्या वाला यह वर्ग मुठ्ठीभर पादरियों व बिशपों की दया पर जी रहा है। चर्च के तमाम

संसाधनों से दलित ईसाइयों को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया है। इस शब्द के चलते दलित ईसाई अपना कोई आन्दोलन खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। अगर कहीं कोई कोशिश की जाती है, तो चर्चनेतृत्व ऐसे लोगों को हतोत्साहित करने की कोशिशें तेज कर देता है। इसी कड़ी में पिछले वर्ष एक कैथोलिक बिशप ने मूवमेन्ट के विरुद्ध एक फतवा जारी कर उसके कार्यकर्ताओं को गालियाँ निकालने में भी गुरेज नहीं किया। चर्चनेतृत्व यह शिक्षा देता है, यही उसके पतन का कारण है और चर्च उनके इस पाप के लिए ईश्वर से क्षमा दिलाएगा। नतीजा यह है कि दलित ईसाई नकारा होकर रह गया है। हालात से लड़ने और परिवेश को अपने हक में बदलने के लिए संघर्ष करने के बजाय यह धारणा कायम कर लेता है कि संघर्ष करना व्यर्थ है क्योंकि उसके दुःखों का कारण उसके आदि पूर्वजों के पाप हैं। चर्चनेतृत्व अपनी असफलता को छिपाने के लिए यह कहते नहीं थकता कि दलितों, वंचितों का ईसाई बनना केवल आध्यात्मिक है, इसलिए दुनियादारी बीच में नहीं आनी चाहिए। फैसला दलित ईसाइयों को करना है कि वह खामोश रहकर अपने अधिकारों का हनन होते देखना चाहते हैं या अपने अधिकारों की सुरक्षा और आर्थिक विकास की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए वह अपने कदमों को उठाने के लिए तैयार हैं। (लेख : आर.एल.फ्रांसिस, अध्यक्ष, पुअर क्रिश्चियन लिबरेशन मूवमेन्ट) ***-(धर्मकर्म अंक; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 21/04/2003)***

268) *भावर क्षेत्र के अन्तर्गत आर्यसमाज ध्रुवपुर में हुई बैठक में चंडीगढ़ में हुए दलितों के धर्मपरिवर्तन की कड़ी आलोचना की गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि दलितों पर लगातार हो रहे अत्याचारों के कारण ही वे अपना मूल धर्म परिवर्तित करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। वक्ताओं ने सभी दलितों से आर्यसमाज से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि आर्यसमाज देश व दलितों के उद्धार के लिए तन, मन, धन से समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि दलितों का उत्पीड़न रोका जाना चाहिए ताकि वे धर्मपरिवर्तन जैसे कदम न उठाएँ।*

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 20/04/2003)

269) *आओ इक्कीसवीं सदी में हम एक नये प्रजातन्त्र के इस्तकबाल की तैयारी करें। फिर इस प्रजातन्त्र की परिभाषा गढ़ी जा रही है। बिहार में इसे नाम दिया गया– **'लाठी चलाओ प्रजातन्त्र'**, हजारों लाठियाँ बँटी, धन्य है लालूमहिमा। दिल्ली में **'तलवार चलाओ डेमोक्रेसी'** का आह्वान किया गया, क्षेत्रीय स्वाभिमान याद किया गया, तलवारें बँटी। अजमेर में **'त्रिशूल उठाओ प्रजातन्त्र'** की नींव पक्की हो गई। झारखण्ड तो कबका **'तीर-कमान प्रजातन्त्र'** का शैदाई है। हो सकता है कल को यू.पी. में **'जूता मारो प्रजातन्त्र'** की कल्पना की जाए, यह भी तो शस्त्रों से कम नहीं। आज हम हिंसा और सशस्त्र प्रजातन्त्र की ओर बढ़ रहे हैं। सारे देश को बधाई हो! –*

षड्यन्त्रों की साधना बटमारों का साथ।
लोकतन्त्र की भैंस है लठमारों के हाथ॥

-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 19/04/2003)

270) मच्छरों दिल्ली छोड़ो :- *देश की राजधानी दिल्ली में फिर एक नारा उभरा है– 'मच्छरों दिल्ली छोड़ो'। पता नहीं यह नारा जनता ने थोथे नेताओं को दिया है या खेल प्रेमियों ने विभिन्न खेलसंघों के पदाधिकारियों को दिया है या व्यापारियों ने भ्रष्ट इंस्पेक्टरों को दिया है। लेकिन नारा लगा है। जगह–जगह इसकी तख्तियाँ भी लगी हैं।*

आपको याद होगा कि स्वतन्त्रता संग्राम में सन् 1942 में नारा लगा था– 'अँग्रेजों भारत छोड़ो'। देश की जनता उनके पीछे पड़ गई और 1947 में उन्हें भारत छोड़ना ही पड़ा। आप मच्छर को कोई मामूली हस्ती समझने की भूल मत करना। आजकल मच्छरों के भाव कितने ऊँचे हो रहे हैं, यह नीचे के उदाहरण से आपको भी स्पष्ट हो जाएगा।

दो मच्छर मित्र काफी दिनों बाद एक–दूसरे से मिले। पहले ने दूसरे से पूछा–''क्या बात है काफी दुबले हो रहे हो?'' दूसरा बोला–''जब से आदमी का खून पीना बन्द किया है, भूख नहीं मिटती। इसलिए दुबला हो रहा हूँ।'' पहले ने पूछा–''आदमी को काटना क्यों छोड़ दिया?'' दूसरा बोला–''एड्स का खतरा कौन मोल ले?''

अब आप ही बताएँ मच्छर अथवा कीड़े–मकोड़े कोई छोटी–मोटी हस्ती हैं। अभी पिछले दिनों दिल्ली की ही बात है। दो नेता आपस में लड़ रहे थे। एक ने दूसरे से कहा– ''तेरे शरीर में कीड़े पड़ें। इस पर कीड़ों ने एतराज किया और अब कीड़े आपसी लड़ाई में एक–दूसरे को कोसते हैं तो कहते हैं– ''तेरे शरीर में नेता पड़ें।''

इसलिए हो न हो यह नारा भ्रष्ट राजनीति में धर्म संलिप्त नेताओं के लिए ही उछाला गया है। वैसे भी मच्छरों की नेताओं से कई बातों में समानता है। मच्छर सीजनल (मौसमी) होते हैं। कभी बिल्कुल गायब हो जाएँगे, कभी झुण्ड के झुण्ड आ जाएँगे। जैसे चुनावी वर्ष में गली-गली आपको नेता ही नजर आने लगेंगे और चुनाव खत्म होते ही ऐसे गायब होंगे, जैसे गधे के शिर से सींग। फिर अगले चुनाव में मुलाकात। नेता हो या मच्छर अपने सीजन आते ही आपसे आगे होकर टकराएँगे, चाहे आपकी इच्छा हो या न हो। आपका कोई मतलब हो या न हो। इनका मतलब तो है। दोनों ही अपने-अपने ढंग से आपका खून पीते हैं और ऊपर से सीनाजोरी। हालाँकि खटमल भी इसी श्रेणी का प्राणी है और जब वह अपनी रंगत पर आ जाए, तो किसी से कम नहीं। लेकिन वह हर जगह पंगा नहीं लेता। न ही व मच्छरों की तरह डबल ड्यूटी या ओवरटाइम करता है।

यह भी हो सकता है कि यह नारा जनता के प्रबुद्ध वर्ग ने ही ओछे राजनीतिज्ञों के लिए उछाला हो, कि बहुत हो लिया। देश में व्याप्त गरीबी, बेकारी, आतंकवाद की समस्याएँ ही बहुत हैं। पहले मिल-बैठ कर इनको हल कर लिया जाए, मन्दिर-मस्जिद का मुद्दा तो बाद की बात है।

-(शिवशंकर गोयल, व्यंग्यकार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 18/04/2003)

271) लगता है अब एक नया संयुक्त राष्ट्र बनाना होगा :- *क्या अमरीका विश्व में नये प्रकार के साम्राज्यवाद का विस्तार कर रहा है। दरअसल अमरीका के विश्वव्यापी साम्राज्य की स्थापना के सिलसिले की शुरुआत 19वीं शताब्दी में तभी शुरु हो गया था, जब इस नये राष्ट्र के घुड़सवारों ने वहाँ के मूल निवासियों का सफाया कर दूसरों की भूमि हड़पने और उनके शोषण का सिलसिला शुरु कर दिया। अमरीका अन्य देशों में अपने हस्तक्षेप के लिए किसी न किसी प्रकार का बहाना जुटाता था और येन केन प्रकारेण अधिसंख्य पश्चिमी देशों के एक गठबन्धन में अपने को खड़ा करता रहा था और उस पर संयुक्त राष्ट्र का बिल्ला अपने इरादों की पूर्ति के प्रयासों में लगाता रहा था। सोवियत संघ के अवसान ने अमरीका को ही वैश्विक सफर में एक सुपरपावर की हैसियत प्रदान कर दी है और उसे भूगोल को भी मिटाने का उन्माद प्रदान कर दिया है, क्योंकि उसे अपने रास्ते में पूर्व के प्रतिद्वन्द्वी सुपरपावर ने अवरोध उपस्थित करने का ही कोई भय नहीं रहा। अमरीका ने पूरी तरह जाहिर कर दिया है कि उसे विश्व जनमत और खासतौर पर संयुक्तराष्ट्र की भी कोई परवाह नहीं। संयुक्तराष्ट्र वह ढाँचा है, जिसे युद्ध की विभीषिका से भावी पीढ़ियों को बचाने वाली व्यवस्था माना जाता रहा है। ईराक पर अमरीका के हमले ने यह दर्शा दिया है कि संयुक्त राष्ट्र एक सोचनीय नपुंसक छवि के कगार पर आकर खड़ा है। यह स्थिति विश्व के शान्तिकामी सामान्य जनों को कहाँ ले जाएगी? वाशिंग्टन का अन्य देशों पर धावे बोलना और वहाँ के लोगों को गुलाम बना लेने से भला कौन रोक पाएगा? पाँचवी शताब्दी में हूणों ने जो कुछ किया था, अमरीका भी इक्कीसवीं शताब्दी में दुनिया में वैसा ही करने जा रहा है। सवाल यह है कि यह दुनिया ऐसा होने देगी? क्रोध में अपने हाथ मलते रहने अथवा भय से प्रकम्पित होते रहने के बजाय सभी सही सोच वाले और शान्तिवादी राष्ट्रों को अब इस बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि एक नया और वास्तविक अर्थों में लोकतान्त्रिक विश्वनिकाय गठित किया जाए, जिसमें सभी निर्णय समानता और न्याय के आधार पर बहुमत के समर्थन से ही लिए जाएँ। मेरी यह कामना है कि भारत इस सूची में शीर्ष पर रहे। कभी भारत में संप्रभुता के चिन्तन और न्याय, समानता तथा ईमानदारी आदि को शिरोधार्य किया था। किन्तु भारतीय राजनीति के शब्दकोश से आज ये शब्द चुपचाप विदा हो गए लगते हैं। किन्तु सौभाग्य से ये भारत की जनता एवं दुनिया के लोगों के मानस और आकांक्षाओं में अभी भी निहित है। यदि यह स्थिति बने कि ज्यादातर सरकारें एक नये विश्वसंगठन के प्रतिष्ठापन में हिचकिचाएँ तो लोग अर्थात् सामान्यजन स्वयं यह कार्य कर सकते हैं। कुछ ऐसा भी है, जिसके लिए सरकारी स्वीकृति अथवा पहल की कोई जरुरत नहीं है। यह कार्य तत्काल और प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।*

-(सुमेरकौल, स्तम्भकार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 17/04/2003)

272) दुनिया की आलीशान इमारतों में से एक है सद्दाम का महल :- दुनिया की सबसे आलीशान इमारतों में से एक गिने जाने वाले ईराक के अपदस्थ राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के महल को जनपरिषद् कहा जाता था। लेकिन अधिकतर जनता के लिए कभी देख पाना तक नसीब नहीं हुआ। यह बगदाद के रिपब्लिकन पैलेस की मुख्य इमारत है। इसे विश्व की आलीशान इमारतों में से एक माना जाता है। वर्ष 1991 के खाड़ी युद्ध में क्षतिग्रस्त हुई इस इमारत को सद्दाम हुसैन ने ठीक करवाया था। इस इमारत में एक संगमरमर के पत्थर पर लिखा है– ''तीस देशों की सेनाएँ यहाँ घुस आयीं, लेकिन वह फिर भी विजेता बनकर उभरा।'' एक पत्थर पर इसका विवरण दर्ज है कि 1991 में नष्ट होने के बाद इंजीनियरों ने इसे किस तरह से एक वर्ष में फिर से बना दिया। लेकिन इस बार विदेशी सेनाओं के हमले से सद्दाम हुसैन नहीं बच सके और उन्हें अपदस्थ कर दिया गया। पत्रकारों ने इस महल का मुआयना किया। ईराक में दूसरे महलों की तरह सद्दाम हुसैन का यह महल भी विलासिता और शानोशौकत से भरपूर है। इसके दरवाजे स्वर्ण से मढ़े हुए हैं और गुसलखानों में स्वर्ण के नल आदि लगे हैं। महल के सैंकड़ों कमरे खाली पड़े हैं और उनमें मँहगा संगमरमर लगा हुआ है। महल की दीवारों पर जगह–जगह कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। महल में प्रवेश करने पर एक बड़ा कमरा है। इसमें सद्दाम हुसैन का चित्र लगा हुआ है।

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 15/04/2003)

273) सद्दाम से त्रस्त लोगों के चेहरे पर लौटी रौनक : अन्यायी का अन्त :- सद्दाम के वफादार बगदाद के फिरदौस चौराहे में अपने नेता की आदमकद मूर्ति गिरते देखकर भले ही जहर का घूँट पी रहे हों, लेकिन उनके शासन से आजिज आकर विदेशों में निर्वासित जीवन बिता रहे लोगों के चेहरे पर रौनक लौट आयी। अक्टूबर 1981 में सद्दाम के सैनिकों से प्रताड़ित होने के बाद लंदन आ गयी जारा मुहम्मद ने कल रात यहाँ संवाददाताओं से बातचीत में कहा–''हम न्याय के लिए तरस रहे थे। सद्दाम की मूर्ति गिरते देख मैं खुशी से फूली न समायी।'' सद्दाम के शासन के दौरान जारा ने अपने चार भाई और कई रिश्तेदार खो दिए।

इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त तुर्कमान मूल का निशात अहमद भी सद्दाम के जुल्मों का शिकार रहा है। उसे इतना प्रताड़ित किया गया कि वह अपंग हो गया। उसके माता–पिता और भाइयों सहित उसके परिवार के ग्यारह सदस्य मारे गए।

बगदाद में जन्में कुर्द जाति के माहिर सुल्तान ने जब ईरान के खिलाफ जंग के दौरान ईराकी सेना में भर्ती होने से इन्कार कर दिया तो उसे प्रताड़ित करने के बाद अबू गरीब जेल भेज दिया गया। सात साल तक उसका बाहरी जगत से सम्पर्क कटा रहा। उसकी माँ को डेढ़ साल की कैद हो गयी। माहिर ने संवाददाताओं को बताया कि वह गठबन्धन सेनाओं द्वारा यातना चैम्बरों को तबाह करने की खबर से बेहद खुश हुआ।

डाक्टर ओसाम बलाल ईराकी शिया हैं। उन्हें अबू वक्त सरकार ने सत्तर के दशक में अन्य मेडिकल छात्रों के साथ गिरफ्तार कर लिया। उनके हाथ–पाँव बाँधकर और आँखों में पट्टी लपेटकर उन्हें पीटा जाता। उन्हें जब पीटा जाता तो उनके परिवार वालों को यह सब होते देखने के लिए वहाँ बुलाया जाता। बलाल को उम्मीद है कि अब ईराक में लोकतन्त्र की स्थापना होगी। **-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 12/04/2003)**

274) कौटिल्य के प्रिय वचन हैं :–

➪ जो राजा अपनी प्रजा के हित का ध्यान नहीं रखता, वह विनष्ट हो जाता है।

➪ जो राजा अन्याय करता है, उसका समूल नाश हो जाता है।

➪ जो राजा अन्याय घटित होते देख उसको रोकता नहीं, वह नष्ट तो होता ही है, नर्कगामी भी होता है।

आज सदियाँ बीत गईं, परन्तु लगता है, चाणक्य के ये उपदेश आज भी बड़े प्रासंगिक हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि अन्यायी राजा की अन्ततः विजय हुई हो। वह हर हाल में अन्ततः मारा ही जाता है। रावण बड़ा विद्वान था। रावणसंहिता दक्षिणप्रदेश में प्रचलित एक अद्भुत ग्रन्थ है। उसमें इतनी शिक्षाएँ दी गई हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन रावण क्यों मारा गया। सारे का सारा राक्षसकुल क्यों समाप्त हुआ, क्योंकि विद्वता आचरण में नहीं उतरी। लंका पाप की नगरी में परिणत हो गई। हमारी गरिमा पर आघात हुआ। राजदूतों से दुर्व्यवहार हुआ। नीतिशास्त्र (न्याय–नियम) अप्रासंगिक हो गए। अहंकेन्द्रिता आसमान चढ़कर बोलने लगी। चाहे रावण हो, चाहे दुर्योधन, चाहे कंस, चाहे ओसामा या सद्दाम, अन्याय की एक ही परिणति होती है। नीति तो वही है, पर आज के दौर के राजा बदल गए हैं। पहले एक

राजा होता था, आज 500 से अधिक हैं। राज्यों के राजाओं की गिनती भी हजारों में है। हम इन्हें सांसद और विधायक कहते हैं। ये राजा अपने महाराजाओं का चयन करते हैं। वे क्रमशः प्रधानमन्त्री और मुख्यमन्त्री कहलाते हैं। कमोवेश यही आज के प्रजातन्त्र का ढाँचा है। ऐसे तन्त्र में एक अजब असूल है– जब प्रजा कोई अपराध करती है, तो उसके लिए डण्डा है, पुलिस है, कानून है। लेकिन जब ये अन्याय करते हैं, तब कोई पूछता नहीं। दोषी कौन? आज प्रजा सबसे बड़ी दोषी है, क्योंकि वह अन्याय घटित होते देखती है, किन्तु उसको रोकने के लिए आवाज नहीं उठाती। अतः सबसे बड़ा दोष प्रजा का है। 50 वर्षों से ज्यादा हो गए। आज भी लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, प्रताड़ित हैं, क्योंकि नग्न आँखों से सत्य को देखते हुए भी ये भ्रष्ट नेताओं के हाथों भेड़ों की तरह हाँके जा रहे हैं। डाकू भी छिपकर डकैती करते हैं, लेकिन आकस्मिक निधि से 76 लाख रुपये की विशुद्ध डकैती कर ली गई और आपराधिक मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। यह कैसा प्रजातन्त्र है? सांसदों को बीच बाजार में नंगा कर दिया गया कि हर सांसद चाहे वह शरीफ से शरीफ क्यों न हो, वह संसदीय कोष से पाँच लाख कमाता (लूटता) ही है। आज सारे अपराधों के प्रणेता ही नैतिकता के उपदेशक बन गए हैं। ***-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 12/04/2003)***

275) *भले ही सद्दाम हुसैन एक बुरा शासक और बुरा आदमी था लेकिन क्या किसी विदेशी सेना को ईराक पर हमला करने का अधिकार है। अधिकांश भारतीय टिप्पणीकारों ने जंग के दोनों पहलुओं को देखा। यह आक्रमण गलत है, क्योंकि इससे किसी राष्ट्र के अपनी समस्याएँ खुद हल करने के सम्प्रभु अधिकार का उल्लंघन होता है। इन टिप्पणीकारों का कहना है कि सद्दाम को हटाना ईराकियों के हाथ में है। यदि सद्दाम शानदार महलों में रहता था, सोने के फिटिंग वाले बाथरूम में नहाता था और आम ईराकी को जीवन की आधारभूत सुविधा, साफ पानी तक भी मुहैया नहीं है, तो भी ईराकी ही उसका विरोध कर सकते हैं। अब यदि ईराकी जनता को कोई परेशानी नहीं है, तो दूसरों को क्यों हो?*

-(तवलीन, स्तम्भलेखिका; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 12/04/2003)

276) परिवार के पाँच सदस्यों ने ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या की :- *कर्जदार द्वारा अपने ब्याज की दर बढ़ाने और पैसों की तुरन्त वापसी न करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने पर एक परिवार के पाँच सदस्यों ने रेल से कटकर आत्महत्या कर ली। यह वारदात कल रात को नरेला रेलवे लाइन पर हुई। पुलिस ने कर्जदार के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। कल रात रामकिशन, उसकी पत्नी रामकली, पुत्र अशोक, पुत्री प्रियंका और पुत्र नीरज ने नरेला रेलवे लाइन पर एक रेलगाड़ी से कटकर आत्महत्या कर ली। ये पाँचों लोग रेलवे लाइन पर आधे अन्दर व आधे बाहर लेटे थे। रेल ने सभी को बीच में से काट दिया। रामकिशन की जेब से मिले आत्महत्या पूर्व लिखे गए अपने बयान से पता चला कि उसने माडल टाउन सोनीपत निवासी बख्तावर मल से 2% प्रतिमाह की ब्याज दर पर 50 हजार रुपये उधार लिए थे। उसने अचानक अपनी ब्याजदर बढ़ाकर 5% कर दी। तो इस पर रामकिशन ने आपत्ति की। उसके आपत्ति करने पर बख्तावर मल अपने बेटे के साथ उसके घर गया और धमकी दी कि यदि उसने 5 अप्रैल तक उसका पैसा वापस नहीं लौटाया तो वह पूरे परिवार को जान से मार डालेगा। जब रामकिशन 4 अप्रैल की शाम तक उसके 50 हजार रुपयों का इंतजाम नहीं कर सका, तो उसने अपने परिवार के चार अन्य सदस्यों के साथ रेल से कटकर आत्महत्या कर ली।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 06/04/2003)***

277) बचा लो यारों ये देश अपना है :- *जन आन्दोलनों का राष्ट्रीय समन्वय वास्तव में 1992 से चली करीबन 12 राज्यों में फैलती रही एक प्रक्रिया है। इसमें देश भर के सैकड़ों जनसंगठन एकत्रित हुए हैं, जो जातीयता और साम्प्रदायिकता (वर्गसंघर्ष) के विरोधी तो हैं ही किन्तु सरकार की आर्थिक नीतियों को भी चुनौती देने आए हैं। सशक्त लोकजागृति और संगठन के द्वारा परिवर्तन का रास्ता अपनाना, सत्ताधीश और जनता के बीच न्यायपूर्ण जनतान्त्रिक रिश्ता बनाना उनका उद्देश्य है। परिवर्तन अपेक्षित है। समता, सादगी, स्वावलम्बन के मूल्यों पर आधारित यह प्रक्रिया एक दृष्टि से राजनीति का विकल्प है। दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर, महिला, वंचित, शोषित आदि समाज के सभी घटकों का सहभाग है। इन सबकी एकत्रित शक्ति से खोज है– वैकल्पिक विकास की, न्याय और निरन्तरता की।*

जन आन्दोलनों से उभरकर सामने आए बुनियादी मुद्दों को समेटकर समन्वय ने संकल्प लिया, जिसमें ये मुद्दे हैं– अन्यायी आर्थिक नीति का पूर्णरूप से विरोध; अन्यायकारी व अवास्तविक विदेशी कर्ज को रद्द कराना; स्वतन्त्रता का उद्घोष करना; सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से निर्बल समूहों की समस्या के स्थायी समाधान तथा उन्हें शिक्षा एवं रोजगार उपलब्ध कराना अन्य जरूरतों पर बल देना; समान बँटवारा व सभी की भौतिक व अन्य जरूरतों का समाधान हो, ऐसी व्यवस्था करना; श्रमिकों को लाभों का समान बँटवारा; जमीन, जंगल, जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निरन्तर चिरंजीवी विवेकपूर्ण इस्तेमाल व उस पर समूह के समान अधिकार को बढ़ावा देना; सृजनशील जीवनशैली अपनाना; शोषण, असमानता, प्राकृतिक संसाधनों का विनाश व प्रदूषण न करना; भ्रष्टाचार, राजनैतिक अपराधीकरण का विरोध करना; महिलाओं के प्रति भेदभाव का विरोध करना और उनकी सहभागिता के लिए प्रयास करना; युद्ध, आक्रामकता और विनाशकारी अस्त्र–शस्त्र का विरोध करना; किसी भी प्रकार के वर्चस्व, उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष करना; समानता, निरन्तरता, जनाधिकार व शान्ति के आधार पर नये अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय ढाँचे के लिए प्रयास करना; इन्हीं बिन्दुओं पर या ऐसे और मुद्दों के आधार पर देश भर के संगठनों, आन्दोलनों, राजनैतिकदलों से संवाद–विचारविमर्श करना। 'मुण्डे–मुण्डे मतिर्भिन्ना' को एक ताकत के रूप में उभारने का काम समन्वय ने किया है। जनचेतना को विकसित करने से लेकर देश की व्यवस्था में नीतिगत बदलाव का संघर्ष भी समन्वय ने किया है। देश के कोने–कोने में दबे–कुचलों की आवाज को मजबूती देने के साथ निर्माण की प्रक्रिया भी समन्वय ने चलायी है। समन्वय ने जनमंचों का आयोजन किया, जिसमें देश के प्रमुख जननेताओं ने राजनेताओं से सवाल किए। अपेक्षा के अनुरूप ही उनके गोल–मोल जवाब मिले। देश साम्प्रदायिकता (वर्गसंघर्ष) में झुलसकर, बिखरकर देशी, विदेशी कम्पनियों के हाथों न बिक जाए, इसके लिए जरूरी है कि देश में बड़े स्तर पर आन्दोलन हो और देश का आन्दोलन एक हो। **''अभी बहुत टूटा नहीं हूँ, अभी मुझे कुछ आशा है। अभी कुछ लोग डटे हुए हैं, इनके बिन घोर निराशा है।।'' ''बचा लो यारों ये देश अपना है। फिर न कहना आजादी सपना है।।''**

-(संजीवकौरा, लाइटहाउस; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 25/03/2003)

278) ***''हे पतियों! तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवननिर्वाह करो और उनका सम्मान करो यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं।'' -(बाइबिल)***

समस्त विश्व में औरतों के साथ दुर्व्यवहार को कहीं संस्कृति की रक्षा के नाम पर तो कहीं धर्म के नाम पर उचित ठहराने का क्रम चलता रहा है। मसीहियत में उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए हैं, परन्तु मसीही परिवारों में भी औरतें कहीं गरीबी की वजह से तो कहीं अन्य वजह से दमनचक्र में पिसती रहती हैं। मसीही कानून पुत्रियों को पुत्रों के समान उत्तराधिकार तथा अन्य सुरक्षा प्रदान करता है। विधवाएँ मसीहियत में अपनी प्रतिष्ठा और महत्त्व खोती नहीं हैं। मसीहियत में गरीब विधवाएँ और जरूरतमन्द औरतों की देखभाल का जिम्मा कलीसिया पर छोड़ा गया है, परन्तु चर्चनेतृत्व इस ओर से आँख बन्द करके अपने ही व्यवसाय में लगा हुआ है। मौजूदा समय में दलित मसीह औरतों की स्थिति बेहद दयनीय बनी हुई है। चर्चनेतृत्व मसीह महिलाओं के शोषण को रोकने के नाम पर भी अपना फायदा देखता है। पिछड़ी जनजाति मसीही महिलाओं को घरेलू नौकरानी के रूप में काम पर लगवाने का ठेका भी कैथोलिक चर्च ने हथिया लिया है। अब बाकायदा लिखा–पढ़ा कर उन्हें बड़े लोगों के घरों में भेजा जाता है। या ऐसा कहें कि चर्चनेतृत्व ने अमीरों व पूँजीपतियों को शिक्षा के साथ–साथ दूसरी सुविधाएँ भी मुहैया करवानी शुरु कर दी हैं, और यह सब होता है गरीब मसीही महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर। मौजूदा समय में हमारे देश के अन्दर चर्चनेतृत्व के दो चेहरे बनते जा रहे हैं– एक चेहरा देहाती (रूरल) और एक चेहरा शहरी (अर्बन)। जहाँ देहाती क्षेत्र में वह मृत्यु के बाद मुक्ति का व्यापार कर रहा है, वहीं शहरी क्षेत्र में वह धन्ना सेठों के मौजूदा जीवन को सजाने में लगा हुआ है। ***-(आर.एल.फ्रांसिस, धर्मकर्मअंक; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 17/03/2003)***

279) आम जनता अभी यह नहीं समझ पा रही। जब तक उसे इसका अहसास होगा, तब तक राजनीतिक दल उसे ईंधन बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेंकते हुए देश को तबाह और स्वयं को मालामाल करते रहेंगे। सामाजिक उत्थान, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता और सम्पन्नता (परम् वैभव) का सपना दिखाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वर्गसंघर्ष और जातिवादी उन्माद पैदा करने वाले राजनीतिक दल

यह जानते हैं कि देशवासियों को देने के लिए भौतिक तौर पर उनके पास कुछ भी नहीं है। न रोजगार है, न शिक्षा के पर्याप्त साधन, न कल्याण के लिए कोष है और न सामाजिक चेतना जगाने की सार्थक सोच। इसलिए वंचितवर्ग के खाली पेट और रिक्त मन में वर्ग और जाति का उन्माद भरा जा रहा है। सामाजिक समरसता की प्रेरणा देने के बजाय सामाजिक प्रतिशोध लेने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में गुण्डों, मवालियों और बाहुबलियों की फौज तैयार की जा रही है। दलाली और मक्कारी की प्रेरणा दी जा रही है। पुलिसथानों से वसूली करने और कानून के मार्ग में अड़चनें पैदा करने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। महापुरुषों का उपयोग सत्ताप्राप्ति के एक माध्यम के रूप में किया जा रहा है। शिक्षा, रोजगार, सुविधा और सम्मान में बराबरी के बजाय दिखावे और उद्दण्डता में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया जा रहा है। देश के लगभग सभी राजनीतिक दल लोकतन्त्र का जातिवादी प्रयोग अपना दलीय हित साधने, सँवारने के लिए कर रहे हैं। इस दौड़ और होड़ में वे भूल गए कि उनका गम्भीर राष्ट्रीय दायित्व यह भी है कि एक सबल, समृद्ध, समरस (न्यायशील) और चरित्रवान भारतीय समाज का निर्माण हो। यह दायित्व उस दल (भाजपा, आर.एस.एस., बजरंगदल आदि) पर अन्य दूसरे दलों की अपेक्षा अधिक है, जो राष्ट्रीय चरित्र और चिन्तन की कोख से पैदा हुआ था, जिसके जन्मदाताओं ने एक उज्ज्वल, सुरक्षित और खुशहाल भारत की कल्पना की थी और सर्वजनहिताय, सर्वजनसुखाय के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। लेकिन अफसोस! कि वह दल भी सामाजिक समरसता के स्वयंसिद्ध सूत्रों को छोड़कर राजनीतिक लाभहानि के फन्दे में फँसकर अपनी और समाज दोनों की क्षति होते देख रहा है। राष्ट्रीय एकात्मता के सूत्र हाथ में होते हुए भी वह सामाजिक विखण्डन को प्रोत्साहित करने वाली शक्तियों का गुलाम बनता जा रहा है।

समाज का वर्गों में विभाजन यदि अर्थ (संसाधन) के आधार पर हो, तो संभव है कि अमीरी-गरीबी की खाई घटे। लेकिन यदि इस विभाजन का आधार जातिवादी घृणा बन रहा है, तो यह समझो कि व्यापक रक्तपात का आधार तैयार हो रहा है। ***-(भानुप्रतापशुक्ल, स्तम्भकार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 17/03/2003)***

280) *13 मार्च को माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो (प्रत्याशियों की आपराधिक पृष्ठभूमि और चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा देने सम्बन्धी) ऐतिहासिक फैसला दिया है, उससे कुछ राजनीतिक दलों को भले ही आघात पहुँचा हो, पर इस फैसले ने यह साबित कर दिया है कि किसी भी प्रजातन्त्र में मूल्यों की रक्षा का भार या तो प्रजातन्त्र के तीसरे स्तंभ न्यायपालिका पर है या चौथे स्तंभ मीडिया पर, अन्यथा यह सच ही इन वतन के नेताओं के बारे में कहा गया है :-*

जमीं बेच देंगे जमाँ बेच देंगे, ये मुर्दों के शिर का कफन बेच देंगे।
न्याय के प्रणेता अगर चुप रहे तो, वतन के ये नेता वतन बेच देंगे॥

केवल एक उदाहरण देखें। मेरा किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं। किसी भी राज्य में आकस्मिक निधि कोष क्या मुख्यमन्त्री के जन्मदिन मनाने के लिए होता है? 'बहन जी' ने उत्तरप्रदेश में न केवल अपने जन्मदिन के अवसर पर 76 लाख रुपये उस कोष से खर्च कर दिए, बल्कि एक वीडियो टेप में स्पष्टरूप से संसदीय कोष से कमीशन का आह्वान करती देखी गईं। कहाँ है हमारा राष्ट्रीय चरित्र।

-(अश्विनीकुमार, सम्पादकीय; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 17/03/2003)

281) *घर से भागकर होटल में रह रहे एक प्रेमी युगल की सल्फास खाने से मृत्यु हो गई। होटल मैनेजर ने दोनों को बीते दिवस प्रातः ही बेहोशी की हालत में कमरे में देखकर खटीमा सामुदायिक स्वास्थ्यकेन्द्र में भर्ती कराया जहाँ दोनों की मृत्यु हो गई। प्रेमीयुगल द्वारा एक सुइसाइड नोट छोड़ा गया है, जिसमें लड़के ने पहले अपने परिवार के सभी सदस्यों का जिक्र करते हुए मृतका आरती से अपने प्रेमसम्बन्धों के बारे में बताया। इसी पत्र में लड़की ने भी आलोक से अपने प्रेमसम्बन्धों को लेकर माँ व भाई द्वारा परेशान किए जाने की बात लिखी।*

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 17/03/2003)

282) *हमारा समाज बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो गया है। तहलका और मायावती टेपकाण्ड ने तो सिर्फ उस कड़वी सच्चाई को उजागर किया, जिसका सामना हम अपनी जिन्दगी में रोज करते हैं। बिजल विभाग, पुलिस विभाग, कर विभाग, अस्पताल सब जगह भ्रष्टाचार के काले नाग ने अपना फन फैला रखा है। सबसे ज्यादा*

भ्रष्टाचार तो सेना में है। तहलका भण्डाफोड़ के बाद अब किसी को इस बारे में शक नहीं रह जाना चाहिए। वहाँ छोटी से छोटी खरीदी पर कट और कमीशन लिया जाता है। हालाँकि भ्रष्टाचार पूरी व्यवस्था को जकड़ चुका है, तो यह मामला व्यक्तिगत आचरण से जुड़ा हुआ है। हमारे अन्दर कहीं गहरे तक लालच भरा हुआ है। इसलिए मौका मिलते ही हम फिसल जाते हैं। मसलन जब तहलका काण्ड में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रँगे हाथ पकड़े गए तो बचाव में उन्होंने कहा कि वह तो पार्टी फण्ड के लिए उगाही कर रहे थे। वैसे इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था कि तथाकथित हथियार दलालों का काम करवाने के बदले वह डालर क्यों माँग रहे थे? पार्टी के लिए डालर की क्या जरूरत थी? जाहिर है यह सीधे व्यक्तिगत लालच का मामला था। हर्षद मेहता और केतन पारिख के शेयर घोटाले फिर चीनी घोटाला, यूरिया घोटाला, सरकारी बैंक घोटाला, टेलीकॉम घोटाला, तहलका टेपकाण्ड जैसे अनगिनत मामलों में हजारों करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार सामने आया; लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आर्थिक नीतियों से बेकारी व गरीबी बढ़ रही है। आर्थिक असमानता में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। लेकिन इन मुद्दों पर किसी का ध्यान नहीं है। यह भी सच है कि जनता इन समस्याओं के प्रति अपने गुस्से को किसी न किसी रूप में बाहर करती रहती है। जब उसे कुछ समझ में नहीं आता तो वह भ्रष्ट सत्ता को बदल देती है। लेकिन बीते अनुभव से उसे यह सीख मिल चुकी है कि इस हमाम में सब नंगे हैं। किसी को भी चुन लो, वह भ्रष्टाचार से बाज नहीं आएगा। कहना न होगा कि भ्रष्टाचार का कीड़ा सारे समाज को चाट रहा है।

जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहे भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए किसी राजनीतिक पहल की कोई उम्मीद नहीं है। हमारी पीढ़ी तो पूरी तरह निराश हो गई है। हमने सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। ***-(केवल शर्मा, स्वतन्त्र टिप्पणीकार; अमर उजाला, देहरादून, 2003)***

283) ज्वालामुखी फूटने का इंतजार : आखिर हमारा समाज कब तक सहेगा भ्रष्टाचार :- *तहलका व मायावती टेपकाण्ड में कोई फर्क नहीं है। दोनों ही मामलों में ऊँचे पदों पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ। सरकार को उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए, जिन लोगों ने हमारे महत्त्वपूर्ण व संवेदनशील तन्त्र में फैले भ्रष्टाचार को उजागर किया। जो काम सरकार की गुप्तचर एजेन्सियों को करना चाहिए था, वह कोई और कर रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जनता यह सपना देखने को भी तैयार नहीं है कि कभी वह दिन भी आएगा जब बिना रिश्वत दिए उनके काम होने लगेंगे। कहीं भी चले जाइए, चाहें पानी का बिल ठीक करवाना हो या बिजली का, नौकरी लेनी हो या नगरनिगम में मकान का नक्शा पास करवाना हो, भ्रष्टाचार के बिना आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। यह भयावह स्थिति है। कोई दूध का धुला नहीं है। न तो वे जो आरोप लगा रहे हैं और न वे जिन्हें कठघरे में खड़ा किया जा रहा है। इस स्थिति से बचने के लिए राजनीतिक दलों को मिलबैठकर रास्ता निकालना होगा। आखिर कभी तो जनता को राहत देने के बारे में सोचना ही होगा। इस सवाल का जवाब ढूँढा जाए कि भ्रष्टाचार की जड़ कहाँ है, तो खोट हमारे चरित्र में दिखती है। हमारा राजनीतिक चरित्र गदला हो गया है। एक ऐसी स्थिति आ गई है कि एक अच्छे से अच्छा इंसान भी राजनीति में आए तो वह हमें भ्रष्ट होता हुआ दिखता है। यही कारण है कि जनता के प्रति जवाबदेही खत्म हो गई है। उसे खिलौने की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एक सामान्य राजनेता के भी जलवे देखिए!*

यहाँ हमें यह देखना होगा कि धन का गबन करना ही भ्रष्टाचार नहीं हैं, बल्कि कानूनों का उल्लंघन करना भी उतना ही बड़ा भ्रष्टाचार है। लालबत्ती गाड़ी और जबरन या बहाने से हासिल किए गए सुरक्षाकर्मी राजनेताओं की पहचान बन गए हैं। ये सुरक्षाकर्मी रौब गाँठने या घरेलू काम करवाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। राजनेताओं को शर्म आनी चाहिए कि वे जनता से वोट लेकर आते हैं और जब उनके बीच जाते हैं, तो सायरन बजाते हुए। ऐसे नुमाइन्दे जिन पर जनता की कोई श्रद्धा नहीं है। जब लालबत्ती लेकर सायरन बजाता हुआ बाजार से निकलता है, तो जनता उसका मजाक उड़ाती है, तिरस्कार करती है, उसके काफिले और सुरक्षा ताम-झाम की ओर हिकारत की नजर से देखती है। अफसोस है! कि इस तरह की बुराइयाँ हमारे राजनीतिक चरित्र में भीतर तक समा गई हैं। देश में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का पहला मामला जीप घोटाला है। उस समय कृष्णमेनन रक्षामन्त्री थे। उसके बाद मूँदड़ाकाण्ड सामने आया, जिसमें बीमे की भारी रकम की हेराफेरी की गई। इन्दिरा गाँधी के जमाने में भ्रष्टाचार की रफ्तार कुछ तेज हुई। धीरे-धीरे घोटालों की फेहरिस्त लम्बी होती गई।

यह सही है कि लोगों का नेताओं पर से विश्वास उठ गया है। जनता में नेतृत्व के प्रति गहरी निराशा है। सवाल यह है कि जब राजनेताओं के प्रति जनता में गहरी निराशा व्याप्त है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ेगा। मेरी नजर में इसके खिलाफ गैर राजनीतिक मंच से मुहिम शुरु की जानी चाहिए। मौजूदा हालात देखकर किसी भी विचारवान इंसान को गहरी निराशा हो सकती है। लेकिन मुझे इस अँधेरी सुरंग के अन्त में रोशनी दिख रही है, क्योंकि देश के अधिकांश लोग ईमानदार हैं और ईमानदार रहना चाहते हैं। कायदे से गुजर-बसर करना चाहते हैं। केवल मुट्ठीभर लोग हैं, जो अपने और अपने कुनबे के फायदे के लिए देश को लूट रहे हैं। इसमें वे लोग शामिल हैं, जो ऊँचे और महत्त्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर हमें उम्मीद का दामन पकड़े रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कि समाज में भ्रष्टाचार के विरोध की सुगबुगाहट या अन्तर्धारा हो। विवेकानन्द ने कहा था-''सब कुछ सहने वाली धरती की तरह समाज भी बहुत समय तक बहुत कुछ सहता है। लेकिन अन्त में उसका ज्वालामुखी फूटता ही है और उसके लावे में समाज की तमाम मलिनता धुल जाती है। मुझे यकीन है कि भारत का समाज मृत नहीं हुआ है। इसलिए उम्मीद है कि ज्वालामुखी फूटेगा। हमें उसका इन्तजार है। -(लेखक : तरुणविजय, सम्पादक, पान्चजन्य) ***-(लेखप्रकाशक : अमर उजाला, 2003)***

284) मात्र ढाई साल में करोड़पति हो गए मन्त्री जी : ऊँची छलाँग :- *राज्यमन्त्री बनते ही राम आसरे पासवान की किस्मत खुल गई। सिर्फ ढाई साल के भीतर वह करोड़ों की सम्पत्ति के मालिक बन गए। जबकि मन्त्री बनने से पहले वह बमुश्किल एक एकड़ जमीन तथा एक समान्य पैतृक आवास के मालिक थे। दिलचस्प बात यह है कि उनके पास जो महकमा था, उसकी गिनती मलाईदार विभागों में नहीं होती। राज्यमन्त्री रहते हुए अवैध तरीके से अकूत सम्पत्ति अर्जित करने की शिकायत पर लोकायुक्त ने जाँच-पड़ताल की, तो इस भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। लोकायुक्त ने जाँच रिपोर्ट मुख्यमन्त्री मायावती के पास भेजकर पासवान के खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश की है। ढाई वर्ष के कार्यकाल में सरकारी खजाने से सबसे ज्यादा लगभग 1.33 करोड़ जेबखर्च लेकर चर्चा में आए पासवान के खिलाफ उनके गृहजनपद सन्तकबीरनगर के देवनारायण ने लोकायुक्त से शिकायत की थी कि पासवान ने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध तरीके से अकूत सम्पत्ति अर्जित की। लोकायुक्त ने पूरे मामले की जाँच की तो न सिर्फ पासवान पर लगाए गए आरोप सही पाए गए, बल्कि यह भी खुलासा हुआ कि उन्होंने विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित भी किया। मन्त्री की शह पाकर उनके निजी स्टाफ ने भी लाखों का वारा-न्यारा किया। इसी ढाई वर्ष के कार्यकाल में पासवान ने अपने गृहजनपद सन्तकबीरनगर में अपने बेटों के नाम नौ गाड़ियाँ खरीदीं। इनमें एक लक्जरी कोच, दो ट्रैक्टर, दो महिन्द्रा जीप, एक टाटा सूमो, एक बुलेरो तथा दो मोटरसाइकिलें शामिल हैं। जहाँ एक सामान्य पैतृक आवास था, वहाँ तीन-तीन आलीशान कोठियाँ बन गईं। इसी दौरान एक पिस्टल व दो राइफलें खरीदी गईं। मन्त्री बनने से पहले पैतृक गाँव रैमा मैनसिर में उनके पास सिर्फ 1.5 एकड़ जमीन थी, जिसमें से आधा हिस्सा उनके भाई का था। राज्यमन्त्री बनने के बाद उन्होंने अपनी पुत्रवधुओं के नाम 20 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीद ली। जहाँ तक परिवार में आमदनी के स्रोत का सवाल है, तो पासवान के तीन बेटों में एक सिपाही है, बाकी दो बेटे कुछ नहीं करते। सूत्रों के मुताबिक श्री पासवान का मामला राजाराम पाण्डेय, रामआसरे कुशवाहा तथा मार्कण्डेय चन्द्र के मुकाबले ज्यादा गंभीर है। कार्यवाही का फैसला सरकार को करना है।* ***-(एक समाचार; अमर उजाला, 11/03/2003)***

285) भारत का मुसलमान पाकिस्तान नहीं हिन्दुस्तान जिन्दाबाद कहता है :- *हम अब तक बहुत आपसी भेदभाव कर चुके हैं। एक-दूसरे का खून बहा चुके, एक-दूसरे को नीचा दिखा चुके। अब समय नहीं कि हम आपस में छोटी-छोटी बातों पर लड़ते रहें। अब दीवार को तोड़कर बाहर आना होगा। हिन्दुओं व मुसलमानों को एक माला में पिरोना होगा। हिन्दुओं को मुसलमानों से भिड़ाने का कार्य सुनियोजित ढंग से वोटों की राजनीति खेलने वाले राजनीतिबाजों के द्वारा किया जाता रहा है। जब मुसलमान को हिन्दुस्तान में ही रहना है, तो उन्हें आपसी सद्भावना को दर्शाना होगा। हिन्दू-मुस्लिम दंगों के पीछे चौधराहट जमाने का उद्देश्य होता है, जैसा कि गुजरात में हुआ, परन्तु दंगों व रक्तपात के बावजूद वहाँ लोग इस प्रकार की अनेक घटनाओं का उल्लेख करते हैं, जहाँ हिन्दुओं ने मुसलमानों को और मुसलमानों ने हिन्दुओं को अपनी जान पर खेलकर शरण दी। अतः समाज से ऐसे लोगों को अलग करना होगा, जो साम्प्रदायिक राजनीति से अपनी दुकानें चमकाते हैं। यदि नेता हो, तो मौलाना आजाद जैसा जो न केवल उच्च कोटि के आलिम व लेखक थे, बल्कि*

सही सोच रखने वाले हर बात को नाप-तोल कर चलने वाले नेता भी थे। वह मुसलमानों के नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के नेता थे। धर्मभेद कभी भी उनकी राजनीति के मार्ग में नहीं आया, क्योंकि इस्लाम स्वयं एक उदारवादी जीवन व्यतीत करने का मार्ग है। मौलाना साहब ने इसको अपनी जेब गरमाने का धन्धा कभी नहीं बनाया। इसीप्रकार महात्मा गाँधी एक उच्चकोटि के व्यक्ति थे और शाकाहारी थे। मगर इसके बावजूद उनमें और मौलाना में गाढ़ी मित्रता थी, क्योंकि दोनों ही दिग्गज नेताओं ने धर्मभेद को राजनीति के साथ अपने स्वार्थ के लिए कभी भी नहीं मिलाया। यदि कुछ किया तो बस जनता के हित के लिए ही किया। आज मुस्लिम वर्ग में अब यह बात पनप रही है कि उन्हें एक नये और साफ-सुथरे प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। आज के दौर में आवश्यकता इस बात की है कि सत्ता के विलासकारी भोग-मोह से हटकर हमारे राजनेता सर्वधर्म-समदृष्टि-समभाव द्वारा ही निरापद मार्ग पर चलें। इस देश की असली मिल्कियत देश कि उन 100 करोड़ नागरिकों के पास है, जो न हिन्दू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं और न ही ईसाई हैं। वे मात्र भारतीय हैं। एक ऐसे देश में कि जिसमें ये सभी लोग मिलजुलकर एक-दूसरे के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भारत के उदारवादी हिन्दुओं ने न केवल जवानी जमाखर्च किया है, बल्कि जमीन से जुड़कर मुसलमानों की सेवा की है तथा साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया है।

-(लेख : फिरोजबख्त अहमद; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 12/03/2003)

286) चुनाव वैतरणी पार करने के लिए पुनः मंदिर का सहारा :- *हाल के चुनाव में भाजपा को फिर करारा झटका लगा है। हिन्दुत्व कार्ड एवं मोदी मन्त्र विफल रहे हैं। इसके बावजूद इस वर्ष देश के चार राज्यों में होने वाले चुनावों में चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए संघ परिवार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर हिन्दुओं में धार्मिक उन्माद भड़काकर भाजपा को सत्ता में लाने के लिए प्रयत्नशील है। संघ परिवार की यह रणनीति कितनी सफल होती है, इसका उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। संघ परिवार ने हवा के रुख को देखते हुए राम मंदिर निर्माण रूपी काठ की हाड़ी को केन्द्र में पुनः सत्ता प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करने का पहले से ही मन बना लिया था। इसी उद्देश्य से दिल्ली में विश्वहिन्दूपरिषद ने दसवीं धर्मसंसद का आयोजन करने का फैसला किया। राम मंदिर के मुद्दे से भाजपा सरकार ने जिस ढंग से हाथ खींच लिया था, उससे सन्त, महन्त सख्त नाराज थे। धर्मसंसद में भारत को हिन्दूराष्ट्र घोषित करने, गोवध पर कानूनन पाबन्दी लगाने, धर्मान्तरण पर रोक लगाने, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने, कामन सिविल कोड बनाने तथा जेहादी दहशतगर्दों के उन्मूलन की माँग की गई। धर्मनिरपेक्षता पर जोरदार प्रहार किए गए। अशोक सिंहल ने तो यहाँ तक कह डाला कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई थी, वैसे ही धर्मनिरपेक्षता को भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। परिवार नियोजन की भी सख्त आलोचना हुई। हिन्दुओं से आग्रह किया गया कि वह बहुपत्नीप्रथा को अपनाएँ और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, ताकि हिन्दू जनसंख्या में वृद्धि हो सके। भाजपा किसी भी कीमत पर सत्ता काँग्रेस से छीनना चाहती है। राम मंदिर के मामले को गरमाने के साथ-साथ गौरक्षा का मुद्दा भी उछाला जा रहा है, क्योंकि हिन्दुओं का इससे भावनात्मक लगाव है।*

-(मनमोहनशर्मा, स्तम्भकार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 10/03/2003)

287) यूरोपीय देशों में भी लोग अंग बेचकर पेट पालने को मजबूर :- *ब्रुसेल्स, तीसरी दुनिया के गरीब देश ही नहीं, बल्कि अब यूरोपीय देशों में भी गरीबी से त्रस्त लोग अपने पेट पालने के लिए अपने शरीर के अंग बेचने को मजबूर हैं। मोल्दोवा की एक महिला ने अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपना एक गुर्दा 3 हजार डालर में बेचने का फैसला किया है, जो उस महिला के एक साल के वेतन से कहीं अधिक है।*

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 10/03/2003)

288) आरक्षित सीट का चुनाव :- *वह बड़े मुखिया के खेत में मजदूरी कर रही थी। बड़े मुखिया ने नौकर से हवेली में बुलवाया। उसका घरवाला घबराते हुए नौकर के पीछे-पीछे चल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर उसका घरवाला बैठ गया। बड़े मुखिया दरवाजे पर आए, उससे हाल-चाल पूछा। फिर धीमे से उससे कहा- ''छबीला तेरी घरवाली का क्या नाम है ?'' ''शारदाबाई नाम है माईबाप!'' -उसने काँपते हुए कहा था। पुनः हिम्मत करके उसने पूछा- ''माईबाप! कौनो कसूर हो गओ ?'' ''नहीं रे! थोड़ो सो काम थो।'' -बड़े मुखिया ने कहा। ''कैसो काम हुजूर ?''*

–उसने बड़े आश्चर्य से पूछा। ''वाहे हम सोच रहे हैं, गाँव की सरपंच बनावे की'' –बड़े मुखिया ने कहा। ''माईबाप काहे मजाक कर रहे हो ? वह मूरख, बेपढ़ी वहका ऐसे ओहदा पर बैठहै ?'' –शारदा के पति ने डरते–डरते अपनी सलाह दी थी। ''तू फिकर मत कर। बात ऐसी है कि ये गाँव की सरपंची सीट हरिजन महिला की आयी है। हम सोच रहे हैं, सीट घर की घर में ही रहे।'' –बड़े मुखिया ने कुटिल मुस्कान लाकर कहा। ''माईबाप वह तो बिल्कुल भी पढ़ी–लिखी नहीं है'' –शारदा के पति ने कहा। ''वह की तू चिन्ता मत कर। मैं तो पढ़ा–लिखा हूँ। वाहे कछू नहीं करनो, बस अँगूठा भर लगानो है। बाकी तो मैं सब सँभाल लेहूँ'' –बड़े मुखिया ने बात को समझाते हुए कहा। ''ठीक है माईबाप, वा से पूछ के बता देहूँ'' –शारदा के पति ने कहा। ''अबे जोरू से पूछे है.... । अरे जाके कह दे कि वाहे कल ब्लाक ऑफिस में चलनो है। फार्म भरवे, समझो!'' –बड़े मुखिया ने अपना निर्णय उसे सुना दिया और उसका उत्तर सुने बिना लौटकर हवेली में चले गए।

शारदा के घरवाले ने लौटकर शारदा को यह सब बात बताई। पहले तो वह संकोच में मना करती रही। लेकिन बड़े मुखिया के हुकुम को भला कौन टाल सकता था ? उसकी क्या औकात ? यदि मना कर देती, तो टट्टी–पेशाब के सब रास्ते बन्द दिए जाते। क्योंकि टोले के चारों तरफ उन्हीं की तो जमीन है। अगले दिन शारदा और उसका पति हवेली पर सुबह पहुँच गए। बड़े डाकुर 10–11 बजे हवेली से निकले। एक सरसरी दृष्टि उन्होंने शारदा और उसके घरवाले पर डाली और इतने में ड्राइवर ट्रैक्टर लेकर आ गया। पीछे ट्रॉली में थोड़े से गेहूँ मण्डी में बेचने के लिए रख लिए थे और उन्हीं बोरों पर शारदा और उसका पति भी बैठ गया। ट्रैक्टर हिचकोले खाता एक घण्टे में शहर पहुँचा। पहले मण्डी में गेहूँ उतारा। फिर ब्लाक ऑफिस में गए। इस बीच बड़े मुखिया ने 5 का एक नोट शारदा के घरवाले को देते हुए कहा कि ''ये ले 5 रुपया, बीड़ी–माचिस ले ले।'' उसने नीचे गिरे नोट को उठाया और खुश होकर बड़े मुखिया को आभार के साथ अभिवादन किया। शारदा को यह अच्छा नहीं लगा। उसे भूख लग रही थी। लेकिन किससे क्या कहती ? वह तो घूँघट में चुपचाप बैठी थी।

ब्लाक ऑफिस से एक फार्म लाकर एक बाबू ने उसका नाम, उसके पति का नाम पूछकर फार्म में लिखा, उसका अँगूठा लगवा लिया और शाम को वे अपने गाँव लौटकर आ गए। ट्रैक्टर ट्रॉली के दचकों में उसके हाथ–पाँव दुःखने लगे। उस पर भूख से अँतड़ियाँ खिचने लगीं। लेकिन वह किससे कहती ? उसका घरवाला तो बस बीड़ी का धुआँ नाक से निकाल–निकाल कर मस्त बैठा था। बड़े मुखिया ने सरपंची के लिए उसका फार्म भरवा दिया था। फिर भला किसकी हिम्मत पड़ती कि उसके खिलाफ कोई भी टोले में अपना फार्म भरता। ***–(कहानी : डा.गोपालनारायण आवटे; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 15/04/2003)***

289) महिला आरक्षण का भूत :- *नारी को आज संरक्षण की जरूरत है, आरक्षण की नहीं। आरक्षण चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, एक आत्मघाती अवधारणा है। मैं मात्र दो उदाहरण रखना चाहूँगा :–*

मध्यप्रदेश का एक मामला उच्चन्यायालय तक जा पहुँचा। एक इंजीनियरिंग कालेज में अत्यन्त पिछड़े के लिए एक सीट रिजर्व थी। बड़ा अच्छा कालेज था। एक सामान्य जाति के लड़के को 67% अंकों पर भी प्रवेश नहीं मिला। परन्तु एक दलित को 0% अंक मिले, वह प्रवेश पा गया। मैं पूछता हूँ इस सरकार से कि ऐसे इंजीनियर जो आरक्षण की बैसाखियों पर झूल रहे हैं, राष्ट्र को क्या देंगे ?

दूसरा उदाहरण मेरे एक बिहारी मित्र का है। अपने ससुर के अल्सर के ऑपरेशन के लिए बार–बार दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दौड़ रहे थे। नेतापुत्र हैं, बिहार में ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे। बातचीत में बोले– ''मेरा अपना छोटा भाई सर्जन है, परन्तु दलित कोटे से है। का जाने इधर–उधर कैंची चला दे।''

फिर भी किसी न किसी पर कैंची तो चल ही रही है। इन सभी नेताओं का इलाज ऐसे ही डाक्टरों से हो, क्या इन्हें मंजूर है ? अगर नहीं तो राष्ट्र के साथ छल क्यों ? ये लाइसेंस प्राप्त हत्यारे किसकी जान लेने के लिए पैदा हुए हैं ? इन्हें आप संरक्षण दें, पूरी सुविधा दें। इन्हें योग्य बनाएँ और कहें कि हीन भावना मत पालो, तुम आर्यपुत्र हो! किसी को पिछड़ा कहना, शोषित कहना कितना बड़ा अपराध है कि पूछें मत। इनका अपमान करने का किसी को हक नहीं। दलित नेता इन फितरतों से बाज आएँ। वैसे भी आज राजनीति में बचा क्या है ? आजादी की आधी सदी के बाद भी 5 मार्च को उत्तरप्रदेश विधानसभा में जो नजारे देखने को मिले, क्या अब भी कुछ देखने को बाकी रह गया है, कि हम यह समझें कि भेड़तन्त्र क्या है ? क्या जरूरत है महिलाओं को उस गन्दगी में झोंकने की ? भारतवर्ष में नारी की गरिमा और सम्मान की रक्षा नहीं हो पा रही है।

आरक्षण के नाम पर भारत की जनता के मौलिक अधिकारों के सिद्धान्त की अवधारणा पर खूब प्रहार हुआ है। नारियों को किसी भी प्रकार के आरक्षण का सशक्त विरोध स्वयं उन्हें करना चाहिए। कहें– ''हमें आरक्षण की भीख नहीं चाहिए।'' क्रेन से उठाकर किसी अयोग्य व्यक्ति को 'माउण्ट एवरेस्ट' पर चढ़ाकर यह सोचना कि वह 'तेनजिंग' हो जाएगा, आरक्षण ठीक उसी प्रकार की बात है। महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री शिन्दे पाँच बार शोलापुर से चुनाव जीतकर आए। परन्तु उन्होंने हमेशा कहा– ''रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ने से अच्छा है, मैं राजनीति छोड़ दूँ।'' इसे कहते हैं, वास्तविक स्वाभिमान। जरा बाबासाहब अम्बेडकर के शब्द देखें– ''प्रारम्भिक 10 वर्षों के लिए तो आरक्षण ठीक है, परन्तु आने वाले कल में इसे प्रश्रय देना एक आत्मघाती कदम होगा, क्योंकि योग्यता की इस राष्ट्र को बड़ी अधिक आवश्यकता है और यह आरक्षण हीनभावना को जन्म दे सकता है।'' केन्द्र सरकार चूँकि राष्ट्रहित में कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं उठा सकती, फिर भी मैं अपना विरोध अवश्य दर्ज कराता रहूँगा। ***-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 09/03/2003)***

290) दलित परिवार दो वर्षों से भुगत रहा है अन्तर्जातीय विवाह की सजा : हर चौखट पर दस्तक किन्तु उत्पीड़न जारी : मानवाधिकार आयोग की चिट्ठियाँ भी बेअसर :- *राजधानी दिल्ली का एक दलित परिवार पिछले दो वर्ष से अपने घर से उजड़कर आतंकित होकर भागा फिर रहा है और मानवाधिकार आयोग अनुसूचित जाति–जनजाति आयोग से लेकर विभिन्न पार्टियों के सांसदों के हस्तक्षेप के बावजूद आज तक अपने उत्पीड़न का मामला भी पुलिस में दर्ज नहीं करा पाया। इस परिवार का गुनाह सिर्फ यह है कि इस परिवार के एक बेटे ने गाँव के ही एक दबंग जाट परिवार की बेटी से प्रेमविवाह करने की जुर्रत कर डाली। सात महीनों तक महिलाओं सहित पूरे परिवार के मारे–मारे फिरने, पुलिस द्वारा बर्बर पिटाई और तमाम रिश्तेदारों के घरों पर पुलिस के अवैध छापों का सिलसिला तो दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अपहरण का फर्जी मुकदमा खारिज कर दिए जाने के बाद तो बन्द हो गया, लेकिन निर्भय होकर जीने के अधिकार और न्याय पाने के लिए ये परिवार अब भी भटक रहा है। परिवार के कुछ सदस्य अब भी घर जाने ही हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। कानून के तहत कार्यवाही तो दूर आज तक पुलिस ने मामला भी दर्ज नहीं किया है।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 06/03/2003)***

291) मुहर्रम : कर्बला की जंग में शहीदों की याद :- *पाप और पुण्य के बीच हमेशा से ये जंग होती आयी है। शैतान हारता रहा है और सच्चाई की जीत होती रही है। लेकिन इंसान को सोचने के लिए अल्लाह ने बुद्धि दी है कि वह चाहे तो शैतान बने और चाहे तो अल्लाह का सच्चा बन्दा। परवरदिगार को– सच कहने वाले, सच (सत्य) और इंसाफ (न्याय) के लिए कुर्बानी देने वाले और दीन–दुनिया की भलाई (पुण्य) करने वाले पसन्द हैं।*

पाप करने वालों के दिल नहीं होता। दिल होता तो दिल दहला देने वाले काम नहीं करते। हाड़–माँस का इंसान ऐसे काम भी कर लेता है कि उसको अपने आगे न तो कोई सत्ता का डर होता है और न ही इंसान की परवाह। वह अपने को तानाशाह समझ लेता है और ऐसे जुल्म करता है, मानो उसकी मौत तो कभी आएगी ही नहीं। किन्तु संसार में सम्मान तो वही लोग पाए, जिन्होंने भला किया। भले गुणों और भले कामों के लिए जान दे दी। ऐसे लोग किसी एक फिरके में ही नहीं, बल्कि सारे फिरकों में हैं। गाँधी जी अगर कहते हैं कि उनको आजादी की जंग किसी कर्बला के मैदान से मिली तो क्या गलत कह गए। कर्बला की जंग है ही ऐसी कि कोई भी फख्र कर सके।

शाम (पूर्व अरब) का शासक 'यजीद' तानाशाही रवैए से शासक बन बैठा। वह अपने को इस्लाम का सच्चा खैर–ख्वाह होने का दावा करता था। लेकिन उसका आचरण इसके ठीक विपरीत था। वह लोगों को सताता और नबियों के रास्तों से उलट व्यवहार करता। हर किसी ने उसके जुल्मों से डरकर हार मान ली थी। लेकिन मुहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन कैसे हार मान सकते थे? यजीद ने उनको भी वैत करने के लिए दबाव डाला। लेकिन उन्होंने वैत करने के बजाय इंसाफ (न्याय) के लिए जंग करना मुनासिब समझा। जंग किसी भी समस्या का हल नहीं। इमाम हुसैन ने अपनी ओर से जंग भी नहीं की। लेकिन जब जंग शिर पर आ जाए, तो किया भी क्या जा सकता है? वह तो इस्लाम अर्थात् इंसाफ की मशाल लेकर निकले थे। इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन इस्लाम (इंसाफ) के परचम को झुकने नहीं दिया।

हुसैन ने कई बाद यजीद से समझाया। यहाँ तक कहा कि उनको हिन्दुस्तान जाने दो। लेकिन यजीद को कुछ भी स्वीकार नहीं था। एक तानाशाह आखिर कर ही क्या सकता है, उसने जुल्म का रास्ता

अख्तियार किया। कर्बला के मैदान में जब हुसैन अपने 72 जाँनशीनों के साथ थे, उसने नहरे फराद का पानी बन्द कर दिया। तीन दिन तक भूखे-प्यासे बच्चों का बुरा हाल था। हुसैन के भाई जनाबे अब्बास से बच्चों की प्यास देखी नहीं गई। उन्होंने इमाम हुसैन से पानी लेने जाने की इजाजत माँगी। हुसैन ने मना कर दिया, लेकिन बाद में इस शर्त पर इजाजत दी कि तुम जाओगे तो सही लेकिन बिना हथियार के। कल को दुनिया यह नहीं समझे कि हुसैन ने जंग की। तब अब्बास पानी लेने जाते हैं। पानी लेकर लौट की रहे थे कि यजीद की फौज ने पीछे से हमला करके उन्हें शहीद कर दिया :-

धरती तपती थी तप्त तवे सी, नभ से आग बरसती थी।
लपट से लगते हवा के झोंके, सारी देह झुलसती थी।।
नदी पे पहरा बैठा था, पानी भरने पर सख्ती थी।
आबाल वृद्ध सब प्यासे थे, जल को जीभ तरसती थी।।

इस बाद तो एक-एक करके हुसैन के सारे जाँनशीनों को शहीद कर दिया गया। हुसैन का एक-एक साथी बहादुरी से लड़ा और शहीद हो गया- मजहबे इस्लामिया के लिए, इंसानियत के लिए और इंसाफ के लिए। हुसैन अगर जंग चाहते तो क्या उनके साथ केवल 72 लोग होते, वो भी बच्चे और महिलाएँ? हुसैन ने तो आखिरी वक्त तक जंग टालने की कोशिश की, लेकिन जब जंग आ ही गई, तो क्या करते? वातिल से लोहा लेने के लिए जंग भी जरूरी है। इस जंग की दर्दनाक शहादत छह माह के बालक अली असगर की है। उनको भी यजीद की फौज ने शहीद कर दिया। बेरहमों को रहम कहाँ से आती?

मुहर्रम का मातम गम का मातम है। ऐ हुसैन! अगर हम होते तो तुमको अकेले शहीद नहीं होने देते, तुम्हारे साथ हम भी शहीद हो जाते। कर्बला की याद में मुहर्रम का सोग होता है। सोगवार जंजीरों से मातम करते हैं और अपने शरीर को लहूलुहान करके संदेश देते हैं कि इंसाफ की खातिर हम भी जान दे सकते हैं। **-(लेख : सूर्यकान्त द्विवेदी; अमर उजाला, देहरादून, 01/03/2003)**

292) आप कर्तव्यों की बात करते हो, अधिकार कौन देगा? आम आदमी तो दूर, हमारे देश के प्रथम नागरिक के पास भी कर्तव्य तो बहुत हैं, लेकिन अधिकार क्या हैं? शून्य! कृपया आम आदमी का दर्द भी समझें व उन्हें हक दिलवाएँ। **-(सतीशकुमार, दिल्ली; आवाज-ए-खबरदार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 05/03/2003)**

293) गाँधी जी के तीन बन्दर :-

संसदभवन में गाँधी जी आँख बन्द किए देख रहे हैं- सांसदों की कुर्सी की उठापटक।
कान बन्द किए सुन रहे हैं- बहस में होने वाली गाली-गलौज।
और मुँह बन्द किए हुए हैं- कि कहीं चीख न निकल जाए।

-(जितेन्द्रकुमार, जका, बागपत; आवाज-ए-खबरदार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 01/03/2003)

294) बेरोजगारी की समस्या : लोकसभा में हंगामा :- सरकार की नीतियों की बदौलत देश में बेरोजगारी की वृद्धि से श्रमिक वर्ग में बढ़ रहे गुस्से को लेकर आज लोकसभा में भारी हंगामा हुआ। प्रधानमन्त्री अटलबिहारीवाजपेयी ने स्वीकार किया कि यह एक विकराल समस्या है। सदन की कार्यवाही शुरु होते ही विपक्ष ने राजधानी में श्रमिक संघों की विशाल रैली का जिक्र करते हुए बढ़ती बेरोजगारी और सरकार की नीतियों के खिलाफ कामरोको प्रस्ताव दिए। वाजपेयी ने कहा कि सभी दल बेरोजगारी से लड़ना चाहते हैं और रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहते है, पर सभी विशेषतः सत्ता में बैठे दल, चाहे वे दिल्ली के हों या कलकत्ता के, यह जानते हैं कि इस समस्या से लड़ने में बहुत कठिनाइयाँ हैं। उन्होंने मार्क्सवादी सोमनाथ चटर्जी से मुखातिब होते हुए कहा कि ''सोमनाथ बाबू! मजदूरों में जाकर भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना अत्यधिक कठिन है। हम भी यही धन्धा किया करते थे। लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं निकलता। सोमनाथ ने धन्धा शब्द पर आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि वह मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं न कि कोई धन्धा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमन्त्री ने 70 लाख नये रोजगार उपलब्ध कराने की बात तो कहीं, लेकिन लोग रोजगार खोते जा रहे हैं। उनका जिक्र नहीं किया गया। आज प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरु होते ही काँग्रेस सहित समूचे विपक्ष ने राजधानी में किसानों और बेरोजगारों की समस्या को लेकर एकत्र हुए मजदूर संगठनों का मामला उठाया। सदन में

इस पूरे मुद्दे पर लगभग 45 मिनट तक हंगामा होता रहा। लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी ने कहा कि सरकार बेरोजगारी दूर करने के पूरे प्रयास कर रही है। हमने एक करोड़ लोगों को रोजगार दिलाने का वायदा किया था। उनमें से 70 लाख लोगों को रोजगार दिलाए जा चुके हैं। लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ। उसका आरोप था कि एक करोड़ लोगों को रोजगार दिलाने की बात तो दूर, सरकार की गलत नीतियों की बदौलत इससे कहीं अधिक लोग प्रतिवर्ष बेरोजगार हो रहे हैं। इससे पहले पूर्व प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर ने कहा कि देश में एक करोड़ से अधिक लोग हर साल बेरोजगार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने तुरन्त प्रभावी कदम नहीं उठाए, तो स्थिति हाथ से निकल सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर विचार कर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 27/02/2003)***

295) *एक था चूहा। उसका नाम था– मीकू। मीकू को बहुत काम करना पड़ता था। दिन भर वह स्कूल में पढ़ता और शाम होते ही अपनी भैंस चराने के लिए खेतों की ओर ले जाता। छुट्टी के दिन तो वह भैंस के लिए चारा भी ले आता था और उसे मशीन से काटकर भैंस को डाल भी देता था। इससे उसकी कसरत हो जाती थी और उसकी मम्मी उसे पीने के लिए एक कप दूध भी देती थी। दूसरे लोगों की तरह उसकी मम्मी सारा दूध बेचती नहीं थी।*

एक दिन मीकू अपने खेत में भैंस चरा रहा था और साथ ही किताब लेकर अपना पाठ भी पढ़ रहा था। वह जोर–जोर से बोल रहा था– 'जिसकी लाठी उसकी भैंस'। वह इस कहावत का अर्थ भी याद कर रहा था। पास ही एक झाड़ी थी– उसमें छिपा बैठा था एक भेड़िया। मीकू की बात सुनकर उसने मन ही मन भैंस को हथियाने की ठानी और एक लाठी लेकर मीकू के पास आ गया। वह बड़े क्रोध से बोला– 'इधर लाओ भैंस की रस्सी'। 'तुम्हें रस्सी क्यों दूँ'? –मीकू ने हैरान होते हुए पूछा। भेड़िया कहने लगा– 'तुम्हें मालूम नहीं सरकार ने अब नया कानून पास कर दिया है कि जिसके पास लाठी होगी, भैंस रखने का हकदार भी वही होगा'। भेड़िए की बात सुनकर मीकू बहुत हैरान हुआ। मगर बड़े इत्मीनान से बोला– 'मैंने तो वह कानून कहीं नहीं पढ़ा। तुमने यह कानून कौन सी पुस्तक में पढ़ा है'? भेड़िए को पढ़ना तो आता नहीं था। वह तो झूठ बोल रहा था। उसने मीकू को लाठी दिखायी और बड़े रौब से बोला– 'तू भैंस की रस्सी मुझे पकड़ा, नहीं तो एक मारूँगा और तुझे पता चल जाएगा किताब का'। मीकू बेचारा सचमुच ही डर गया कि इस दुष्ट का क्या भरोसा? सचमुच ही न मार दे। उसने भैंस की रस्सी उसको पकड़ा दी। उसने भैंस की रस्सी भेड़िए को पकड़ा दी। भेड़िया जब जाने लगा तो मीकू ने कहा– 'भेड़िया जी! तुम्हें तो पता है कि अगर मुफ्त में कोई चीज ली जाए, तो पाप लगता है। हमारे शिक्षक भी ऐसा ही कहते हैं कि मुफ्त में चीज लेने वाले की टाँग टूट जाती है। तुम भैंस के बदले में कुछ तो देते जाओ'। भेड़िया चिन्ता में पड़ गया। उसने सोचा– 'यह पढ़ा–लिखा है। यह कहता है, तो जरूर ही पाप लगता होगा। मेरी टाँग अगर सचमुच में टूट गई, तो भैंस ले जाने का क्या फायदा'? किन्तु भेड़िया के पास उस समय लाठी के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसने लाठी ही मीकू को थमा दी और आगे चल पड़ा।

मीकू ने फौरन दिमाग से काम लिया। उसने पूरे जोर से लाठी भेड़िए की टाँग पर दे मारी और दूसरी भैंस को मार दी। इससे भेड़िए की टाँग टूट गई और भैंस बिदक कर वहाँ से दूर भाग गई। भेड़िया मीकू को पकड़ने के लिए भागा। परन्तु उससे दो कदम भी न चला गया। दूर से ही मीकू ने ऊँचे स्वर में भेड़िए से कहा– 'भेड़िए भाई यह सच है कि तुम मुझसे काफी बड़े और ताकतवर हो। पर एक चीज होती है– बुद्धि, जो तुम्हारे पास नहीं है। बुद्धि आती है– पढ़ने–लिखने से। लेकिन तुमने तो कभी स्कूल की ओर मुँह भी नहीं किया, इसलिए तुम्हारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। अरे बेवकूफ! तुम भैंस तो क्या लाठी भी नहीं रख सकते। इसीलिए तो सयाने लोगों ने कहा है– 'अक्ल बड़ी या भैंस'। इसी अक्ल की वजह से तुम्हारी न लाठी रही न भैंस। ***-(बाल-कहानी : बलतेज कोमल; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 26/02/2003)***

296) पेट की खातिर इंसान को क्या कुछ नहीं करना पड़ता? जैसे भी हो दो वक्त की रोटी मयस्सर हो जाए, वही काफी है। अहमदाबाद में मिर्चें छाँटने वाले मजदूरों पर यह बात अक्षरशः लागू होती है। ये लोग अपने पूरे परिवार के साथ मौसमी लाल मिर्चों की सफाई व छँटाई का काम करते हैं तथा आँखों से पानी निकाल देने वाली बीस किलों मिर्च की सफाई व छँटाई पर मात्र छह रुपये मेहनताना पाते हैं, जो किसी भी मापदण्ड से बेहद कम है। **-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 25/02/2003)**

297) भारतीय संविधान दुनिया के प्रगतिशील संविधानों में से एक है, जिसने औरतों को वोट देने का अधिकार दिया है तथा जो औरतों और मर्दों को समान अधिकारों के आश्वासन देता है। संविधान के अनुसार भारतीय औरत समाज में पूरी तरह स्वतन्त्र है और समान रूप से देश की नागरिक है। किन्तु आए दिन सुर्खियों में छपने वाली खबरें स्त्री उत्पीड़न के विविध दृश्य प्रस्तुत करती हैं। घर और बाहर दोनों जगह स्त्रियों को यातनाओं से गुजरना पड़ता है। स्त्री और पुरुष के समन्वय से चलने वाले भारतीय समाज में ज्यादातर स्त्रियों को ही अन्याय सहना पड़ता है। वर्ष 2001 की जनगणना में हर 1000 मर्दों पर 933 औरतें पायी गई थीं। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्यसेन के तर्क के अनुसार भारत को अपनी वर्तमान जनसंख्या 1.03 अरब में से 3.2 करोड़ गायब हुई औरतों का हिसाब देना है। यहाँ औरतों की कम होती संख्या का कारण जान लेना भी जरूरी है। यह दुर्भाग्य ही है कि घर में सबको भोजन देने वाली अन्नपूर्णा स्त्री स्वयं ही सबसे अधिक अपोषित है। अधिसंख्य परिवारों में कन्याशिशु के प्रति उपेक्षा का व्यवहार होता है। कन्याशिशु को जन्म के बाद से ही पोषण सम्बन्धी भेदभाव से जूझना पड़ता है। लड़कों की तुलना में लड़कियाँ बहुत कम संख्या में सकूल जाती हैं। अगर जाती हैं, तो उन्हें अधिक पढ़ने से रोका जाता है। मर्दों की तुलना में मजदूर स्त्री को कम वेतन मिलता है। जमीन और सम्पत्ति के अधिकारों में औरतों के साथ भेदभाव किया जाता है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार देश में हर 26 मिनट पर एक औरत के साथ यौन छेड़-छड़ और हर 34 मिनट में एक बलात्कार होता है। हर 43 मिनट में एक औरत का अपहरण होता है। हर 93 मिनट पर एक औरत मार दी जाती है।

यह सवाल सहज ही उठता है कि क्या भारत में औरतों को अपने विकास के लिए पूरी आजादी प्राप्त है? क्या उन्हें अपने जीवन के बारे में चुनाव करने का वास्तविक अधिकार व स्वतन्त्रता प्राप्त है? क्या उन्हें ज्ञान प्राप्त करने, रचनात्मक और उत्पादक होने की वास्तविक आजादी प्राप्त है? क्या वे आजादी छीनने वाले मुख्य स्रोतों से सुरक्षित हैं। इन सवालों के परिप्रेक्ष्य में सरकारी योजनाओं और आँकड़ों का सारा गणित लड़खड़ा जाता है। तमाम त्रासदियों के बीच स्त्रियों की परतन्त्रता के कई आयाम हैं। हमारे सामाजिक रीति-रिवाज महिलाओं के पक्ष में नहीं है। महिलाओं की एक बड़ी आबादी निरक्षर है। सार्वजनिक प्रक्रिया में महिलाओं का योगदान न के बराबर है। स्त्रीविकास के लिए यह आवश्यक है कि स्वतन्त्रता में बाधक बनने वाले तत्त्वों को घटाया जाए। **-(विभा देवसरे; अमर उजाला, देहरादून, 22/02/2003)**

298) सरकार का गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयास करने का दावा खोखला : सरकार ३० हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष गरीबी हटाने के लिए खर्च करने का दावा करती है, परन्तु गरीबी निरन्तर बढ़ रही है :- हमारे देश के एक शहर में एक भव्य होटल के बाहर परित्यक्त बच्चों का एक झुण्ड रहता है। वहाँ छोटे-छोटे लड़के-लड़कियाँ रहते हैं। इनमें से कुछ तो मुश्किल से ही चल पाते हैं। इन सभी की एक जैसी कहानी है। इन बच्चों को किसी चाचा या चाची द्वारा शहर में लाया गया, जो उन्हें सड़क पर छोड़कर लापता हो गए। भारत के शहर दर शहर की यही कहानी है। मेरा इस तरह के परित्यक्त बच्चों के एक दल से परिचय है। हुआ यूँ कि सुबह की सैर के समय मैं फुटपाथ पर इडली-डोसा और पूरी-भाजी बेचने वाले स्टालों पर मँडराते हुए उन्हें देखा करती थी और एक दिन मैंने उनके लिए नाश्ता खरीदने की पेशकश की। समय के साथ बढ़ते चले जाने वाले बच्चों के इस दल के लिए शीघ्र ही यह रोजाना की व्यवस्था हो गई। स्टाल का मालिक कुछ अतिरिक्त पैसे कमाकर खुश था और बच्चे मग्न। सड़क पर नाश्ते का यह कार्यक्रम कुछ महीनों से चल रहा था कि इडली वाले ने मुझे बताया कि एक पुलिस वाले ने उसे प्रताड़ित करना शुरु कर दिया है। उसने मुझे बताया कि वह पुलिस वाला चाहता है कि मैं बच्चों को खिलाना बन्द कर दूँ, क्योंकि वे गरीब और गन्दे हैं, और यह सड़क ऐसी है, जिस पर बड़े लोग आते-जाते हैं। मैंने स्टाल वाले से पुलिस वाले को आगाह करने के लिए कहा कि उसे मुझसे उलझना होगा और इस तरह उसकी प्रताड़ना उस समय से बन्द हो गई। मैंने आपको यह

कहानी इसलिए सुनाई ताकि यह साफ किया जा सके कि हमारा प्रशासन किस कदर बुरा बन चुका है। यहाँ मैं वही कर रही थी, जिसे बेसहारों और वंचितों के लिए सरकार को करना चाहिए। विडम्बना देखिए कि राज्य की मशीनरी को अपने लिए उपयुक्त जो एकमात्र भूमिका नजर आयी, वह थी काम को अपने हाथ में लेने के बजाय मेरे काम में अड़ंगा डालना।

भारतीय राज्य दावा करता है कि वह करदाताओं के हजारों-हजार करोड़ रुपये (30 हजार करोड़ रुपये सालाना से अधिक) गरीबी उन्मूलन पर खर्च कर रहा है। परन्तु यहाँ हम देख सकते हैं कि दरअसल हो क्या रहा है। इसके ठीक विपरीत जनता को पुलिस और अधिकारियों जिन्हें कि उन्हें जिन्दा बने रहने के वास्ते कमाने की इजाजत पाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, की खुशामद और चिरौरी करते देखेंगे। राज्य-मशीनरी जब सड़क किनारे के ठेलों और रिक्शेवालों के पास पहुँचती है, तो उसकी भयावहता कहीं अधिक साफ दिखाई देती है। उन्हें हर दिन राज्य-मशीनरी के हाथों अपमानित प्रताड़ित और लूट का शिकार होना पड़ता है। दरिद्र नारायण के मूलभूत अधिकारों को कुचलना बहुत आसान होता है, क्योंकि उनकी कोई आवाज नहीं।

दिल्ली के हॉकरों के लिए रोजी-रोटी कमाने की इजाजत पाने के लिए पुलिसकर्मियों एवं अधिकारियों को रिश्वत देने की बाध्यता बनी हुई है। बिहार एवं उत्तरप्रदेश से रोजगार की तलाश में राजधानी आए हताश युवकों का भी सच यही है, जिन्हें कि भयंकर गरीबी से निजात पाने के लिए साइकिल रिक्शा चलाना पड़ता है। लाइसेंस-कोटा-परमिटराज अभी भी बना हुआ है। और अगर आप लाइसेंस के बिना रिक्शा चलाते हैं, तो नगरनिगम अधिकारियों को उसे जब्त करने और बेकार कर देने का पूरा अधिकार है। इसीप्रकार हॉकरों के सामान आए दिन जब्त किए जाते रहते हैं। मानुषी की सम्पादक मधु का तर्क है कि यह न केवल आजीविका कमाने के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन है, बल्कि इस बात का साफ सबूत है कि आर्थिक सुधार केवल मुठ्ठीभर अमीरों के लिए हैं। ***-(तवलीन, स्तम्भलेखिका; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 22/02/2003)***

299) हिन्दुत्व क्या है? :- *भाजपा या अन्य किसी भी राजनैतिक संगठन का उद्देश्य मात्र राजनीतिक प्रभुत्व (धन, पद, सामर्थ्य) प्राप्त करना है। हिन्दुत्व (ज्ञान, विवेक और मानवकल्याण) की पुनर्स्थापना अथवा प्रचार-प्रसार से इनका कुछ लेना-देना नहीं है। यह तथ्य सही है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्ममानववाद (वसुधैव-कुटुम्बकम्), प्रखर हिन्दुत्व और अध्यात्म (मुखर्जी और उपाध्याय जी के सिद्धान्त) को त्यागकर (किन्तु उन्हें बैसाखी बनाकर) भाजपा सत्ता तक पहुँची है। अन्यथा हिन्दुत्व (ज्ञान, विवेक, मानवकल्याण) की शून्यता आज इस राष्ट्र में व्याप्त न होती। भ्रष्टाचार, अपराध और आतंक सभी राष्ट्रघात मानवताविरोधी हैं। उनका नियन्त्रण करें अन्यथा नियन्ता (परमेश्वर) तो अपना काम करेगा ही।*

-(डा.देवकुमार, रायपुर, राजस्थान; आवाज-ए-अबरदार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 21/02/03)

300) *अखिल भारतीय क्षत्रिय (जाति) महासभा द्वारा जातिगत आरक्षण के विरोध में प्रदेशव्यापी आन्दोलन के तहत शहर के प्रमुख मार्गों से एक सर्वजातीय जुलूस निकाला, जो मौन धारण किए हुए हाथों में तख्तियाँ लेकर कलेक्टर कार्यालय गोरखी कार्यालय पहुँचा। गोरखी पहुँचकर राष्ट्रपति के नाम सम्बोधित विज्ञापन कलेक्टर टी. धर्माराव को सौंपा। ज्ञापन देते समय अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, ब्राह्मण महासभा, कान्यकुब्ज सेवासंघ, वैश्य समाज, सिंहवाहिनी, प्रतापवाहिनी, प्रतापसेना, राष्ट्रीय बेरोजगारी मोर्चा, महिला मोर्चा एवं दर्जनों सामाजिक संस्थाओं ने इस जुलूस में भागीदारी करके जातिगत आरक्षण के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सम्बोधित था। ज्ञापन देने से पूर्व सभी सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, युवा, महिलाएँ, पुरुष हजारों की संख्या में गाँधी-उद्यान, फूलबाग पर एकत्रित हुए, जहाँ से बैनर और तख्तियाँ हाथों में लेकर मौन जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ गोरखी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँचा।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 19/02/2003)***

301) मननाशी और बोझिल किताबें : डी.ए.वी. का अन्धेर :- *इस समय भारत में गैरसरकारी शिक्षासंस्थाओं में डी.ए.वी. सबसे बड़ी संस्था है। इस संस्था ने बच्चों का भविष्य उन्हें तनावग्रस्तकर और बोझिल बनाकर छोड़ दिया है। एल.के.जी. से लेकर आठवीं कक्षा तक डी.ए.वी. ने अपनी खुद की किताबें छापी हैं। एन.सी.ई.आर.टी. की सरकारी किताबों को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया है। डी.ए.वी. की इन किताबों*

में ढेरों गलतियाँ हैं और ये किताबें बच्चों की कक्षा के दिमाग के हिसाब से नहीं बनाई गई हैं। कठिन से कठिन और लम्बे से लम्बे पाठ रखे गए हैं। दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा के बच्चों की किताबों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आज इन्हें डी.ए.वी. संस्था बी.ए. करा देगी। पाँचवी और छठी की किताबें तो इन्हें प्रोफेसर बनाने के लिए हैं। इन्हें पढ़कर बच्चे टेंशन से भरे रहते हैं। डी.ए.वी. अपनी मनमानी किताबों की मनमानी कीमतें वसूल करती है और शिक्षा से पैसे कमाने की नीति को बनाये रखती है। डी.ए.वी. की सब मनमानी किताबें रद्द की जाएँ और सरकारी किताबों को सख्ती से लागू किया जाए। जो स्कूल एन.सी.ई.आर.टी. की किताबें न लगाएँ, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाए। डी.ए.वी. की भयानक योजना है कि अगले वर्ष अपने अन्तर्गत आने वाले सभी 450 स्कूलों से एन.सी.ई.आर.टी. की किताबों को खदेड़ दिया जाए। –(डी.ए.वी. कमेटी का एक सदस्य और अभिभावक) ***-(आवाज-ए-अबरदार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 05/08/2005)***

302) क्या होता है पुलिस धर्म :- *जब नाच उठे तो घूँघट क्या? वक्त आ गया है कि सरकार साफ ऐलान कर दे कि पुलिस वास्तव में होती किसलिए है? सेवा, सुरक्षा, सहयोग के स्लोगन पर कालिख पोत ही दी है, तो अच्छा है कि उसे मिटा ही दिया जाए और उसकी जगह लिख दिया जाए कि पुलिस का असली काम क्या है? सेवा, सुरक्षा, सहयोग जैसे शब्द तो किसी परोपकारी धर्मात्मा के दरवाजे पर लिखे हुए शोभा पाते हैं। इन शब्दों को अब और कलंकित न करें। पुलिस का न्याय से दूर तक कोई नाता नहीं है। अँग्रेजों के जमाने से ही पुलिस का काम जनता में डर पैदा करना है, उसे गुलाम बनाए रखना है। शराब पीकर ड्यूटी देना, बेकसूर लोगों को मारना–पीटना, गाली–गलौज करना पुलिस का पहला अधिकार बन चुका है। शरीफ आदमी को इनसे बचकर रहना चाहिए। तमाम गैरकानूनी काम करने वाले आपराधिक तत्त्वों से भाईचारा बनाए रखना पुलिस का कर्तव्य बन चुका है। हर जुए–शराब के अड्डे से रोज अपना हिस्सा लेना पुलिस का अधिकार व कर्तव्य सिद्ध है। देश में, राष्ट्र में अपराध को बढ़ावा देना पुलिस का दूसरा बड़ा मकसद है, ताकि विभाग फलता–फूलता रहे। पुलिस की निष्ठा राज्य, देश व जनता के प्रति नहीं रह गई है। उसके लिए तो सत्ता ही पूजनीय है और इसलिए पुलिस का काम देश को लूटने वाले भ्रष्ट नेताओं व भ्रष्ट अफसरों का साथ देना, उनकी सुरक्षा करना है, ताकि चोर–चोर मौसेरे भाई का यह रिश्ता तब तक बना रहे, जब तक देश या राष्ट्र का सर्वनाश नहीं कर लेते।*

आज पुलिस का काम है– हर वाहनचालक से वक्त–बेवक्त सड़कों पर वसूली करे। लेकिन जब तस्करी का माल जा रहा हो, हथियारों–गोलाबारूद का अवैध कारोबार चल रहा हो, तो खुद उसमें शामिल होकर देश व समाज का बेड़ा गर्क करने में लग जाए। सत्ताधारी नेताओं, अफसरों के गैरकानूनी आदेशों का पालन करना, शरीफ आदमी को झूठे मुकदमें में फँसाना, खुद अफीम ले जाकर निरपराध व्यक्ति के घर से बरामद दिखला देना आदि को ही आज पुलिस का कर्तव्य और अधिकार समझा जाए। आज पुलिस के लिए देश में लोकतन्त्र नाम की कोई चीज नहीं है। आम नागरिक का न तो कोई मानवाधिकार है, न उसके लिए कोई न्याय पाने का विभाग या प्रशासन है। पुलिस के लिए इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, न ही किसी कानून को पालन करने की कोई व्यवस्था। जब जो चाहे उसे करने की छूट है। निहत्थे, निर्दोष लोगों पर लाठी–डण्डे बरसाना आदि जो कायरता के काम हैं, पुलिस वालों की वही बहादुरी मानी जाती है, क्योंकि जब पुलिस को अपराधियों से लड़ना पड़ जाए, तो वह अक्सर जान बचाकर भागती नजर आती है।

-(डा.लोकसेतिया, फतेहाबाद, हरियाणा; आवाज-ए-अबरदार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 05/08/05)

303) नरसंहार और शर्मिन्दगी का एहसास :- *जिन्होंने 'न्याय की देवी' की प्रतिमा देखी होगी, उन्होंने यह भी देखा होगा कि उसकी आँखों पर पट्टी है और हाथ में तराजू। न्याय की देवी बड़े–छोटे, अमीर–गरीब या ऊँचे–नीचे को नहीं देखती। वह केवल साक्ष्य (सत्य) के तराजू पर तोलती है और न्याय करती है। भारतवर्ष में चूँकि न्यायप्रक्रिया बड़ी जटिल है अतः यह न्याय का तराजू अक्सर काँपता है और दोषी सजा से बरी हो जाते हैं। (पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता।) इन्हीं सब कारणों से भारत में ही नहीं सारे विश्व में नेचुरल जस्टिस यानि प्राकृतिक न्याय की अवधारणा विकसित हुई। इसके दो प्रमुख बिन्दु हैं :–*

1. *कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता, जो प्राकृतिक न्याय के दैविक सिद्धान्त की अवहेलना करे। अगर गलती से ऐसा कानून बन भी जाता है, तो न्यायपालिका का यह कर्तव्य है कि कोई भी निर्णय सुनाते समय प्राकृतिक न्याय को कभी न नकारे।*

2. *न्याय केवल मशीनी प्रक्रिया न लगे बल्कि लोगों को महसूस भी होना चाहिए कि न्याय हो रहा है। महाराजा रणधीर के समय की एक घटना बताना चाहूँगा। एक बार वह पूरे लाव-लश्कर के साथ कहीं जा रहे थे। अचानक उनके माथे पर एक पत्थर लगा और रक्त का प्रवाह चल पड़ा। सैनिकों ने अविलम्ब दोषियों को पकड़ा। वे पाँच वर्ष और सात वर्ष के दो बच्चे थे। जब उनसे महाराजा ने कारण पूछा, तो बच्चों ने कहा– ''हमारी माँ बीमार है और भूखी है। हमें दो दिन से भोजन नहीं मिला। वही घर चलाती है। हम पत्थर से बेरी पर लगे बेर तोड़ रहे थे कि गलती से आपको चोट लग गयी।'' महाराजा ने साथ चल रहे खजांची से पाँच सौ स्वर्ण मुद्राएँ लेकर बच्चों को दीं। प्यार किया और बोले– ''जब एक वृक्ष पत्थर खाकर स्वादिष्ट बेर दे सकता है, तो मैं तो पंजाब का महाराजा हूँ, मैं कैसे निर्दयी हो जाऊँ?'' इसे कहते हैं– न्याय।*

-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 12/08/2005)

304) *आज झारखण्ड की स्थिति यह है कि यहाँ अराजकता अपने उफान पर है, यहाँ बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ सड़कें टूटी और जर्जर हैं। लेकिन यहाँ बलात्कारों और लूट का बाजार गर्म है। जिस ढंग से झारखण्ड के पुलिसवालों की बर्बरता की कहानियाँ सुनने और फिल्में देखने को मिल रही हैं, उसके बाद से तो पूरे झारखण्ड में खाकी वर्दी देखकर लोग उत्तेजित हो रहे हैं। डी.आई.जी. स्तर के अधिकारी परवेज हयात पर बलात्कार की प्राथमिकी दर्ज होने जा रही है। सचमुच यह अत्याचार, कुशासन और बर्बरता की पराकाष्ठा है। जिस ढंग से राजद, काँग्रेस, जनतादल और भाजपा के नेताओं ने बिहार और झारखण्ड में अपने गन्दे खेल खेले हैं, उससे पिछले एक दशक में बिहार और झारखण्ड आतंकवादियों के गढ़ बन चुके हैं।*

-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 04/08/2005)

305) बेलगाम स्कूलों पर लगाई जाएगी लगाम :- *देश भर के गली-मुहल्लों में कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे निजी विद्यालयों के काम-काज पर निगरानी रखने और उन्हें विनियमित एवं नियन्त्रित करने के लिए एक निजी विधेयक लाया गया है, जिसका उद्देश्य बच्चों को अच्छी शिक्षा सुनिश्चित करना और लोगों को शोषण से बचाना है। लोकसभा में पेश किए गए इस निजी विधेयक में प्राइवेट विद्यालयों के काम-काज पर निगरानी रखने और उसे विनियमित और नियन्त्रित करने के लिए एक समुचित तन्त्र विकसित करने का प्रावधान किया गया है। 'प्राइवेट विद्यालय विनियम विधेयक 2005' के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि आजकल गैरसरकारी निजी विद्यालय चलाना एक व्यवसाय बन गया है। ऐसे विद्यालय कुछ मुट्ठीभर लोगों द्वारा चलाए जाते हैं। इनमें से ज्यादातर का मुख्य उद्देश्य अच्छी शिक्षा प्रदान करना नहीं बल्कि पैसा कमाना है। ऐसे विद्यालय दान (डोनेशन), भवननिर्माणकोष, कम्प्यूटरफीस आदि के नाम पर भारी शुल्क वसूल कर रहे हैं। ये विद्यालय करों में आवश्यक रियायतों का लाभ उठाने के बावजूद धनराशि का उपयोग विद्यालयों और शिक्षा के विकास पर खर्च नहीं करते। साथ ही शिक्षकों का भी आर्थिक शोषण करते हैं। इन विद्यालयों के संचालक एक ओर तो बहुत अधिक फीस लेते हैं तथा दूसरी ओर अपने शिक्षकों को बहुत ही कम वेतन देते हैं। उनके यहाँ 'कर' नियमों का भी उल्लंघन किया जाता है।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 01/08/2005)***

306) *मैं भारत में किसी भी तरह के आरक्षण के विरुद्ध हूँ। आज राष्ट्र को विवेकानन्द जैसी ओजस्विता की जरूरत है। हमें आरक्षण की बैसाखियों की जरूरत नहीं। यह मनुष्य को पंगु बनाने की एक प्रक्रिया है। बाबासाहब डा.भीमराव अम्बेडकर ने भी दलितों के लिए दस वर्ष तक इसे माना तो किन्तु स्पष्ट कहा– ''जो दलित कहे जाने वाले लोग इस बात से मुझसे नाराज हैं कि मैंने उनका साथ नहीं दिया और दिया भी तो खुले मन से नहीं दिया, उन्हें मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा की स्पर्धा की इस दौड़ में हमें अपनी योग्यता को विकसित करने के लिए संरक्षण की तो जरूरत हो सकती है, ताकि हमारे साथ अन्याय न हो, मगर आरक्षण विवेकहीन अवधारणा है।''* ***-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 12/08/2005)***

307) जलते चूल्हे बुझ जाते हैं :- *उनकी आँखों में दहशत और डर के मिले-जुले भाव हैं। पल्लू के छोर से आँखे पोंछती हुई वो बताती हैं- सामने बिस्तर पर जो घायल युवक लेटा है, वह उनका इकलौता बेटा है। 28 साल का सुरेश कोटियाल शादीशुदा है, दो बच्चे हैं। वह घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य है। सुरेश की हालत ठीक नहीं, पैर और हाथ की हड्डी टूट गई है। चेहरे पर भी चोट लगी है। माँ की पथराई आँखों में कई सवाल हैं। बेटे के ठीक होने, नौकरी पर वापस बहाल होने और सबसे बड़ा सवाल परिवार चलाने का है। दो महीने से हड़ताल चल रही है। सुरेश घर पैसे नहीं भेज पा रहा था। माँ कुछ कह नहीं पाती। उसे इस बात का डर है कि कहीं उसके बेटे को अस्पताल से उठाकर पुलिस जेल में न डाल दे।*

हमारे सामने ताजा घटना है, गुड़गाँव में हॉण्डा फैक्ट्री के कर्मचारियों की हड़ताल, पुलिस की बदसलूकी और कम्पनी से बाहर हुए 1600 कर्मचारियों का अन्धेरा भविष्य। क्या इनका हश्र भी वही होगा, जो क्रमशः दो और तीन दशक पहले मुम्बई और कानपुर के मिल कर्मचारियों का हुआ था? गुड़गाँव की श्रीमती शिन्दे और शान्ता करमाकर की कहानी में बहुत अन्तर नहीं है। शान्ता का पति पाण्डुरंग फिनिक्स मिल में काम करता था। हड़ताल हुई, तब शान्ता की उम्र तीस के आसपास थी। घर चलाने के लिए शान्ता ने पहले अपने गहने बेचे, फिर कुछ काँसे के बर्तन थे, वे भी गिरवी रख दिए। घर के नाम पर एक कमरे की खोली थी, वह भी गिरगाँव की बैठी चाल में। उसका भी किराया भरना मुश्किल हो गया। पाण्डुरंग इसी आश में रहा कि हड़ताल खत्म होगी और उसे नौकरी पर बहाल कर लिया जाएगा। शान्ता इस दिलासे से घर कैसे चलाती। तीन बच्चे, उनका रोज का खाना-पीना। बहुत बुरे दिन थे, बहुत ही बुरे। उधार इतना लिया कि माँगते शर्म आने लगी। बच्चों के स्कूल छूट गए। वे सहमें से घर के अन्दर रहते। बच्ची को दमा हो गया। शान्ता उसका इलाज नहीं करवा पायी। शान्ता ने आखिरकार बहुत ही कड़ा कदम उठाया, वह धन्धे पर जाने लगी। उसे और कोई काम नहीं आता था। मजबूरी इतनी ज्यादा कि .....।

मुम्बई के मिल हड़तालों की कारुणिक दासताँ यहीं खत्म नहीं हो जाती। मफतलाल मिल बन्द होने पर वहाँ के पाँच मजदूरों ने खुदकुशी कर ली और दो दिल के दौरे से चल बसे। खटाऊ मिल ने जब हाईकोर्ट में एफीडेविट दाखिल कराया, तो उसमें 59 लोगों के भूख से मरने की बात दर्ज करायी गई। मुम्बई के मिल मजदूरों की हड़ताल में ढाई लाख से ज्यादा मजदूरों की नौकरियाँ चली गईं। उनमें से 50 हजार मजदूरों को नौकरी फिर मिली बाकी 2 लाख मजदूर और उनका परिवार बेघर हो गया। उनकी पत्नियों ने सब्जी के ठेले से लेकर घरों में नौकरानी का काम करना शुरु किया। शान्ता जैसी भी कुछ थीं, जो मजबूरन देहव्यापार करने लगीं। उनके सामने सबसे बड़ा संकट था- घर में चूल्हा जलते रहने का।

गुड़गाँव की हॉण्डा कम्पनी में कार्यरत महाराष्ट्र का शिन्दे भले ही अपने घावों को सहलाता चुपचाप अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हो, उसकी साँवली दुबली-पतली पत्नी फट पड़ती है- ''हमें कुछ नहीं चाहिए, न कम्पनी का पैसा। हम घर वापस जाएँगे।'' वह बेहद क्षुब्ध है, हड़ताल से, पति की घायल अवस्था से और कम्पनी वालों के व्यवहार से।

गणेश के परिवार की भी हालत कमोवेश ऐसी ही है। गणेश की पत्नी शिन्दे की तरह बोल तो नहीं रही। गणेश रुककर कम्पनी का रुख देखना चाहते हैं। शायद कम्पनी वापस रख ही ले। नौकरी आसानी से मिलती भी तो नहीं। दो महीने की हड़ताल ने कमर तोड़ दी। उधारी पर जी रहे हैं। कुरेदने पर कहती हैं- ''कल कैसे खाना बनेगा, पता नहीं? ऊपर से आज इनकी यह हालत।'' गणेश को भी काफी चोटें आयी हैं।

-(जयन्ती, फीचर सम्पादक; अमर उजाला, देहरादून, 05/08/2005)

308) आमरण अनशन पर बैठे मजदूर :- *दिव्य योग मन्दिर आश्रम ट्रस्ट कनखल द्वारा संचालित फार्मेसी के कर्मचारियों का आन्दोलन आज इक्यासीवें दिन में बेमियादी आमरण अनशन में तब्दील हो गया। फार्मेसी की दस महिलाओं सहित 21 मजदूर आमरण अनशन पर बैठ गए। इन्टक के प्रान्तीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक टण्डन ने कहा कि स्वामी रामदेव को देश का संविधान और कानून मानना होगा। माकपा नेता ने स्वामी रामदेव पर प्रहार करते हुए कहा कि वह एक ओर तो लोगों की आयु बढ़ाने के लिए योग सिखा रहे हैं और दूसरी ओर अपने ही संस्थान के मजदूरों को भूखों मरने के लिए विवश कर रहे हैं।*

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 29/07/2005)

309) दूसरे दिन भी गुड़गाँव में हिंसा का तांडव :- *हॉण्डा कम्पनियों के बर्खास्त कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा घेराबन्दी कर किए गए लाठीचार्ज में घायल सैकड़ों की संख्या में गुड़गाँव के सिविल अस्पताल में भर्ती कर्मचारियों के परिजनों तथा सगे-सम्बन्धियों का गुस्सा आज गुड़गाँव के उपायुक्त सुधीर राजपाल पर फूट पड़ा। अस्पताल में मौजूद महिलाओं ने भी उपायुक्त का घेराव किया तथा उनके साथ धक्का-मुक्की की गई। अस्पताल में मौजूद परिजनों तथा अन्य लोगों ने पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी शुरु कर दी तथा पुलिस ने आँसूगैस के गोले छोड़े।* **-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 27/07/2005)**

310) जापानी राजपरिवार में चार दशकों से बेटा न होने पर खड़ी हुई समस्या :- *विश्व की सबसे पुरानी राजशाही व्यवस्थाओं में शुमार जापान में पिछले चार दशक से पुरुष उत्तराधिकारी का इंतजार चल रहा है। लेकिन राजपरिवार में किसी बालक शिशु का जन्म नहीं होने के कारण अब सदियों पुरानी परम्परा को बदलकर बालिका को उत्तराधिकारी घोषित किए जाने की संभावना प्रबल हो गई है। लेकिन कट्टरपंथी वर्ग 2600 वर्ष पुरानी परम्परा को बदलने के सख्त खिलाफ हैं। प्रगतिवादी जापानी वर्ग के मुताबिक महिला उत्तराधिकारी के चुनाव की अनुमति ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। लेकिन ऐसे में नया सवाल यह खड़ होता है कि पहली सन्तान बालिका और दूसरी सन्तान बालक होने पर क्या बालिका को ही उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा अथवा पुरुष होने के कारण दूसरी सन्तान को राजगद्दी पर बैठाया जाएगा ?* **-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 27/07/2005)**

311) वसुधैव-कुटुम्बकम् का सिद्धान्त ही सर्वश्रेष्ठ :- *बाबू जगजीवनराम एजूकेशनल फाउण्डेशन के तत्त्वावधान में आज बाबू जी स्मृति व्याख्यानमाला की चतुर्थ कड़ी 'इण्डिया इण्टरनेशनल सेन्टर' नई दिल्ली में आयोजित की गई। वेदान्त और सामाजिक न्याय विषय पर प्रमुख विचारक व सांसद डाक्टर कर्णसिहं ने अपना सारगर्भित व्याख्यान दिया। वेदों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा- ''मेरा यह स्पष्ट मानना है कि वेदान्त के मूल सिद्धान्त में संकीर्णता का कहीं कोई स्थान नहीं है। वेदान्त की शक्ति हर एक प्राणी में निवास करती है और समस्त मानवजाति में ईश्वर का निवास है, जिसकी चेतना उदार होती है, वह वसुधैव-कुटुम्बकम् के मूल सिद्धान्त में आस्था रखता है।''* **-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 20/07/2005)**

312) *भारत में जिसप्रकार से शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, वह समाजहित में नहीं है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जिसमें संस्कार (गुणवत्ता), उपार्जनशीलता (रोजगार), स्वावलम्बिता (आत्मनिर्भरता) का समावेश हो।*
-(यशपाल आर्य, विधानसभा अध्यक्ष, उत्तरांचल; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 22/07/05)

313) राजनीति में सबकुछ ठीक-ठाक नहीं : प्रधानमन्त्री मनमोहन जी :- *श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने जो इशारा कॉमनवेल्थ के सांसदों को किया था, उसमें एक सबसे बड़ी बात यह भी थी कि राजनीति में पढ़े-लिखे चरित्रवान और कर्तव्यनिष्ठ लोग आएँ। आज बिहार की पार्टियों से मैं पूछना चाहूँगा कि 37 सांसद उन्होंने चुनकर भेजे, उनमें से सभी पार्टियों की ओर से आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों की एक लम्बी सूची है। अपराधियों की जगह जेल में हो या फाँसी के तख्ते पर, इन्हें हमने संसद में बैठा दिया। आने वाली नस्लों को सोचना पड़ेगा। आज विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के ठीक लोग ये सोचते हैं कि राष्ट्र में सांसद बनने के लिए केवल ग्रेजुएट होना ही जरूरी न हो, ग्रेजुएट के बाद भी इण्डियन पोलिटिकल साइंस और इण्डियन लॉ के नाम से शिक्षा और परीक्षा का प्रबन्ध हो और जो भी इसे उत्तीर्ण करे, वही चुनाव में खड़ा हो सके। क्या ऐसा नहीं हो सकता है ? क्या अब ऐसा करने का समय नहीं आ पहुँचा है ? प्रश्न उठता है कि हम क्यों न इस (पात्रतामूलक) प्रणाली को अपनाएँ और अपना भविष्य निर्धारित करें। सच कहूँ तो उपरोक्त प्रश्न पर कोई भी (राजनेता) कुछ भी नहीं सोचना चाहता। राष्ट्र किसी के केन्द्र में नहीं है। सबके केन्द्र में है- राजनीति। राजनीति का मतलब है- पाँच वर्षों तक राष्ट्र को लूटने का अवसर। भारतवर्ष की जनता में सहने की बहुत क्षमता है। हम जानते हैं कि फलाँ व्यक्ति कातिल है, अपराधी है, भ्रष्टाचारी है, फिर भी हम क्यों उसका नागरिक-अभिनन्दन करते हैं ? जिन्हें जूतों की माला पहनायी जानी चाहिए, उन्हें मान्यवर कहकर क्यों पुकारते हैं ?* **-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 08/07/2005)**

314) बिहार प्रदेश नहीं बीमार प्रदेश कहिए :- *बिहार प्रदेश में दुश्मन को गालियाँ देकर छोड़ देने का रिवाज नहीं है। वहाँ तो 'या तू नहीं, या हम नहीं' वाला फार्मूला ही अपनाया जाता है। जब पूरा प्रदेश ही एक-दूसरे का जानी दुश्मन हो, तो कौन किसको रोके? शासन-प्रशासन सबके सब दुःशासन बने जनता का भरी सभा में चीरहरण करने पर उतारू दिखते हैं। हम सोचते हैं कि जंगलराज में कानून की जरूरत ही कहाँ होती है? वहाँ तो हर बड़ा जानवर छोटे जानवर को निगल जाना चाहता है। यानि जिसके पंजे-दाँत तेज हुए, वही शिकार करने में सफल होता है। अब कुछ लोग उसे बिहार प्रदेश के स्थान पर बीमार प्रदेश भी कह दें, तो कोई क्या कर सकता है? खुदा के बन्दे हमें मारें या छोड़ें, हमें इस बात की कोई चिन्ता नहीं, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। जब से हमने बिहारी लीडरों के मुख से फूल झड़ते देखे हैं, हमारी तबियत हरी और आत्मा बाग-बाग हो गयी है। बिहार के जानी दुश्मनों ने वहाँ सरकार को बदनाम करने की गर्ज से हत्याओं, अपहरणों और फिरौतियों का बेवजह शोर मचा रखा है, जिससे हम सहमत नहीं हैं। बिहार की जनता इस तरह के वातावरण में विचरने की अभ्यस्त हो चुकी है। उसे शान्त और अनुशासित वातावरण देकर मुश्किल में डाला ही क्यों जाए? लाठी रैली, लँगोट रैली, ढोलकपीट रैली, चना-चिवड़ा रैली में जब लोग खुश हों, तो अकारण उन्हें रोजी-रोटी, अमन-शान्ति तथा सुरक्षा आदि के चक्करों में क्यों उलझाया जाए? हम जानते हैं कि बिहार के दबंग लीडर इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं। जब भगवान ने जुबान दी है, तो उसे कैंची की तरह क्यों न चलाया जाए? कैंची की तरह चलती जुबान के भरोसे श्याम को श्वेत सिद्ध कर ही लेंगे। हमें उन पर पूर्ण भरोसा है। उनकी बातों में जादू हैं, उनके मुखड़े पर अनोखी चमक है। सौ-पचास हत्याएँ, बीस-पचीस डकैतियाँ और तीस-पैंतीस फ्रॉड हो जाने से बिहार के मानचित्र में कोई अन्तर नहीं आ जाएगा। दस-पन्द्रह अपहरण भी राजधानी पटना में भूकम्प लाने से रहे।*

हम यह लिख कर देने को तैयार हैं, बल्कि कोरे कागज पर हमारा अँगूठा लगवा लीजिए, क्योंकि हम मानते हैं कि बिहार के सौ फीसदी लीडर ईमानदार और प्रजातान्त्रिक हैं। यह अपने आप में एक मिसाल है। यह बात हम पूरे होशो-हवाश में कह सकते हैं कि इस बार भी बिहार में चुनाव पूरे अमन के साथ होंगे। कहीं भी बूथकैप्चरिंग नहीं होगी और जाति-पाति का वहाँ कोई बखेड़ा नहीं। जी चाहता है कि इस प्रदेश की संस्कृति पूरे देश में लागू कर दी जाए (हँसिए मत)। यह सब बातें हमने झूठ नहीं कहीं। जो हमारी बातों को ऐसा मानते हैं, हमें उनसे कोई बात नहीं करनी है। समझे आप!

-(व्यंग्य : दीपक जालंधरी; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 08/07/2005)

315) पाँच करोड़ रुपये में बेची जाती है राज्यसभा की सदस्यता :- *विपक्ष के नेता नारायण राणे द्वारा शिवसेना प्रमुख के प्रति लगाए गए अरोपों की आग अभी ठण्डी नहीं पड़ी थी कि शिवसेना के पूर्व सांसद एवं वर्तमान काँग्रेसी नेता संजय निरूपम ने शिवसेना को बिहारीविरोधी बताकर नया मोर्चा खोल दिया। इस विरोध के दौरान चेम्बूर के एक सभागृह में संजय निरूपम ने अपने भाषण में यह भी खुलासा किया कि राज्यसभा की सदस्यता पाँच-पाँच करोड़ रुपये में बेची जाती है।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 09/07/2005)***

316) राष्ट्रसेवा की परिभाषा बदल दी है राजनीतिज्ञों ने :- *ऐसा लगता है कि इस समय अपने देश में जीवनमूल्यों पर आधारित मुद्दों पर सार्थक, गंभीर और ईमानदार बहस तथा पारस्परिक संवाद बन्द सा हो गया है। हर संवाद केवल राजनीतिक समीकरण बनाने-बिगाड़ने तक सीमित रह गया है। समाजसेवा का क्षेत्र हो या शिक्षा का, नैतिकता-अनैतिकता का प्रश्न हो या सामाजिक शोषण-उत्पीड़न का, इनसे जुड़े कारणों का ईमानदार निराकरण न खोजकर प्रतिक्रिया और प्रतिशोध की आग जलाकर उस पर अपने स्वार्थ की रोटी सेंकने को सेवाधर्म मान लिया गया है। यदि व्यक्तियों और राजनीतिक दलों का चरित्र तथा उनके चिन्तन और व्यवहार का विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि आज की यह राजनीतिक दाँवपेंच स्वतन्त्रताप्राप्ति के पूर्व से चली आ रही उस साजिश का अंग है, जिसके अन्तर्गत देश को तोड़कर अपना कुनवा जोड़ने के लिए कुछ ताकतें प्रयत्नशील थीं। काँग्रेस के अन्दर और बाहर रहकर जिन ताकतों ने लोकतन्त्र तथा लोकनेतृत्व के प्रति अनास्था उत्पन्न की और अन्य दलों के सत्तारूढ़ होने के बाद वे ताकतें उनसे भी चिपक जाती हैं। अनास्था एवं अराजकता के कूड़े में पलने वाले ये कीड़े यह चाहते हैं कि इस देश की जनता अपने शाश्वत जीवनमूल्यों (सत्य, प्रेम, न्याय, पुण्य) को त्याग दे और ये जीवनमूल्यों को*

उनके निर्देश के अनुसार बनाए और अपनाए। यह न केवल आत्मघाती होगा अपितु एक ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर करेगा, जो गुलामी से भी अधिक घिनौना होगा।

इस गंभीर विषय पर विचार करते समय देश के राजनीतिज्ञों से यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि क्या उन्हें सचमुच देश और समाज की चिन्ता है? क्योंकि यदि उनके हृदय में समाज के दुःख का दर्द होता, तो जिस समाज और देश की शान्ति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन की आवश्यकता होती है, उसी शासन के माध्यम से जनता पर अत्याचार, अन्याय और उनका शोषण करना क्या किसी सभ्य इंसान को शोभा देता है? राष्ट्र की अवधारणा हिन्दू, मुसलमान के दृष्टिकोण पर आधारित न होकर पारिवारिकता पर आरुढ़ है। सर सैय्यद अहमद खाँ ने 3 फरवरी, 1884 को लाहौर में इण्डियन एसोसिएशन द्वारा अभिनन्दन पत्र के उत्तर में कहा था– ''राष्ट्र शब्द का अभिप्राय हम हिन्दू और मुसलमान आदि सभी से लगाते हैं। यही एक रास्ता है, जिसके माध्यम से राष्ट्र शब्द को परिभाषित कर सकते हैं।'' मेरे विचार में यह विषय उनके धार्मिक विश्वास से सम्बन्धित नहीं है, क्योंकि हम उसमें ऐसा कुछ भी नहीं देखते हैं। बल्कि हम सब उसमें जो देखते हैं, वह यह है कि चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान एक ही मिट्टी पर पलते हैं, एक ही शासन द्वारा शासित होते हैं। लाभ अर्जित करने के समान स्रोत हैं और हम अपने अधिकारों के समान भागीदार हैं। यही वह आधार है, जिस पर भारत में रहने वाले सभी वर्गों को राष्ट्र के नाम से जाना जा सकता है। क्या संघ और सर सैय्यद अहमद खाँ के इन विचारों में कोई अन्तर है? यदि नहीं तो संघ को लेकर यह चीख-पुकार क्यों की जा रही है? शायद इसलिए कि भारत को तोड़ने के मार्ग में संघ एक अभेद्य चट्टान के रूप में खड़ा है। देश के निर्माण और विकासकार्य में सभी की अपनी-अपनी भूमिका है। सरकारी सत्ता एवं सत्ता की राजनीति इस महान कार्य का एक अत्यल्प सा अंश है। सम्पूर्ण समाज को जाग्रत करने के पवित्र कार्य में लगे संगठनों, संस्थाओं और संघ को भी राजनीति निरपेक्ष रहकर अबाधरूप से कार्य करने देने में ही देश का हित है। ***-(भानुप्रताप शुक्ल, स्तम्भकार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 04/07/2005)***

317) सत्ता समाज की व्यथा नहीं सुनती :- *व्यक्ति राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर पर परेशान है कि कहीं कोई कुछ सुनता ही नहीं है। एक अजीब सा यतीमी एहसास भरा हुआ है। शासन और जनता के बीच संवेदनात्मक समझ का इतना अभाव है कि उसकी तकलीफों पर नजर दौड़ाने की कोई आवश्यकता ही नहीं समझी जाती। सत्ता, शासन, सरकार, समाज, देश और राष्ट्र परस्पर पूरक न होकर मानो विपरीत दिशा में बढ़ रहे हैं। राष्ट्र की सुव्यवस्था के लिए जन्मा राज्य असुरक्षा और अस्थिरता को जन्म दे रहा है और राष्ट्रजन ऐसी बेसहारा नाव में बैठे होने का अनुभव कर रहे हैं, जिसका माझी धारा है और जिसने अपनी रक्षा की व्यवस्था करके नाव को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। राजनैतिक इतिहास में ऐसे बहुत ही कम प्रसंग आए हैं, जब सत्ता या शासन ने व्यक्ति और समाज की व्यथा-कथा सहज रूप में सुनी हो। सत्ताधीश सदैव अपने भविष्य के प्रति शंकित रहता आया है। बहरा होना या बहरा बन जाना उसकी सत्तानीति का अंश रहा है और आज भी है। परन्तु इतिहास इसका भी साक्षी है कि जिस शासन ने समाज की नहीं सुनी, उसे उसका परिणाम भोगना पड़ा और जिस शासन ने स्वयं को व्यक्ति और समाज से सम्बद्ध रखा, वह आज भी दिव्य शासन, स्वर्णयुग, सुराज एवं रामराज्य आदि के नाम से प्रसिद्ध है। राम के पश्चात शासन एवं शासक ने समाज एवं व्यक्ति की बात नहीं सुनी। उसकी आँहों को विद्रोह की आवाज माना। महाभारत काल के राजा तथा राज्य ने क्या सत्य, समाज और व्यक्ति का पक्ष सुना था। यदि सुना होता, तो महाभारत का महासमर नहीं होता। अपनी अपरिमित शक्ति, प्रतिभा एवं लोकप्रियता के बावजूद योगेश्वर श्रीकृष्ण कौरवपक्ष को यह न समझा सके कि धर्म अथवा न्याय पाण्डवों के पक्ष में है। यदि शासन और शासकों ने समाज की सृजनात्मक चेतना का संरक्षण एवं संवर्धन सहजता से किया होता, तो महावीर वर्धमान, गौतमबुद्ध, शंकराचार्य, समर्थरामदास, विवेकानन्द, दयानन्द, डा.हेडगेवार, महात्मागाँधी और जयप्रकाशनारायण जैसे महापुरुषों की जरूरत ही न होती। सभी शासकों एवं शासन का एक समान स्वभाव तथा प्रवृत्ति है। अपने भविष्य के प्रति सदा सशंकित बने रहना और किसी भी कोने से कोई तिनका उभरता दिखे, तो उसे कुचल देना। उसे हर आदमी, हर विचार, हर चिन्तन अपने लिए चुनौती के रूप में दिखाई देता है। आज भी वैसी ही स्थिति है। सत्य, न्याय, मर्यादा, परम्परा, सज्जनता, सामाजिकता, शासकीय रीति-नीति, व्यक्ति का निजत्व, राष्ट्र की जिजीविषा आदि सभी एक कोने में पड़े हुए हैं। कंस, हिरण्यकश्यपु, रावण, दुर्योधन, महापद्मनन्द और अन्य ऐसे अनेक शासको की भाँति आज के*

शासक भी आज के कृष्ण, प्रह्लाद, सीता, पाण्डव, द्रौपदी एवं चाणक्य को अपमानित ही नहीं कर रहे, बल्कि अपने सम्मान, अपनी पहचान और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए छटपटा रहे हैं। जब शासक सत्ता में अन्धा हो जाता है, जब शासन व्यक्ति को तिरस्कृत करने लगता है, जब शासक अपने निजत्व में सिमट जाता है, तो व्यक्ति के पास एकमेव रास्ता बचा रहता है कि समाज की शरण में जाए। आम आदमी को उसके वैशिष्ट्य का एहसास कराए, उसका असली भाग्यलेख उसे पढ़ाए कि सर्वशक्तिमान ने उसे यातना भोगने, शासन का संत्रास झेलने के लिए नहीं, बल्कि उस ईश्वरीय सत्ता के संरक्षण के लिए जन्म दिया है, जहाँ शोषण का निषेध है, जहाँ संवेदनाएँ इतनी प्रबल होती हैं कि किसी एक की पीड़ा की अनुभूमि उन तमाम लोगों को स्वाभाविक रूप से होती है।

यदि शासन उद्दण्ड, उदासीन, भ्रष्ट, कुनवापरस्त और अपनी निजता में सिमटकर संकट तथा संत्रास को जन्म दे रहा हो, तो समाजरूपी परमेश्वर को उसकी नींद तोड़कर जगाना ही होगा। उसके जागे बिना शासन एवं शासक की उद्दण्डता का अन्त असंभव है। भारतीय पुराण, इतिहास, महापुरुषों के जीवन, विश्व की तमाम क्रान्तियाँ इसकी गवाह हैं। उनकी गवाही को अपने मन में धारण करना होगा कि जब समाजपुरुष जागेगा, तभी शासन का दानव विनम्रभाव से सेवारत होगा। शासन कुछ व्यक्तियों के जागने और चीख-पुकार मचाने की परवाह नहीं करता। नित्यजाग्रत, कर्तव्यबोध से परिपूर्ण, अन्याय और अत्याचार के प्रति असहिष्णु, सत्य एवं सदाचार के प्रति सहिष्णु तथा राजद्वार पर दैन्यभाव से दस्तक न देने वाला, स्वाभिमानी समाज ही शासन और शासक को अपना सेवक बनाकर रख सकता है। कुछ व्यक्ति यदि अलग-थलग रोते रहे, तो कल उनके साथ रोने वाले भी नहीं मिलेंगे और शासन की दानवी प्रवृत्ति एक-एक को कुचलकर अपनी निरंकुशता को चिरस्थायी बनाने का खेल इसीप्रकार खेलती रहेगी।

-(भानुप्रतापशुक्ल, वरिष्ठ स्तम्भकार; अमर उजाला, देहरादून, 06/06/2005)

318) *जर्मनी में उन्होंने पहले वामपंथियों को निशाना बनाया है,*
मैं नहीं बोला क्योंकि मैं वामपंथी नहीं था।
इसके बाद उन्होंने यहूदियों पर आक्रमण किया,
तब भी मैं चुप रहा क्योंकि मैं यहूदी नहीं था।
तब वे मजदूर संघों के विरुद्ध उठे,
मैं चुप रहा क्योंकि मैं उन मजदूरों में से नहीं था।
इसके पश्चात उन्होंने होमोसैक्सुअल्स पर हमला किया,
मैं नहीं बोला क्योंकि मैं होमो नहीं था।
उसके बाद वे कैथोलिक्स पर हमलावर हुए,
मैं तब भी चुप रहा क्योंकि मैं प्रोटेस्टेंट था।
तब वे मेरी ओर आए,
किन्तु उस समय ऐसा कोई नहीं बचा था, जो मेरे लिए बोलता!

-(पास्टर नीमोलर, जर्मनी; नाजी अत्याचार पर लिखा गया लेख)

319) *जम्मू की अनारा गुप्ता को पहले कानून के तहत बन्दी बनाया गया, उसके अश्लील चित्र मार्केट में दिखाए गए। अनारा को अखबारों की चीज बना दिया गया और हालत यहाँ तक पहुँची कि निर्दोष अनारा नग्न फिल्म तैयार करवाने वाली खलनायिका घोषित कर दी गई। पुलिस हिरासत में उसे कितनी शारीरिक और मानसिक यातनाएँ सहनी पड़ीं। सच यह है कि यह अनारा की ही कहानी नहीं, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में ऐसे सैंकड़ों, हजारों बेकसूर हैं, जिन्हें इसलिए टार्चर किया जाता है, क्योंकि पुलिस को शक है या इसलिए कि वह कानून के रक्षकों की नजर में आरोपी हैं और आरोपी को अपराधी बनाने में पुलिस को ज्यादा देर नहीं लगती। अनारा के माता-पिता ने महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया और फिर बात उच्च न्यायालय तक पहुँची। परिणाम यह हुआ कि अनारा दोषमुक्त है। अब उसके विरुद्ध कोई केस नहीं परन्तु भारत के कितने लोग ऐसे भाग्यशाली हैं, जिनमें न्यायालयों के सभी दरवाजे खटखटाने की हिम्मत है।*

अब देखना यह है कि अनारा के केस में कानून के रक्षक कितनी सजा पा सकेंगे? अब तो वे स्वयं अपराधी सिद्ध हो चुके हैं। इलाहाबाद गंगापार आने में जिसे पत्नी का कातिल सिद्ध कर दिया, उसकी

पत्नी जिन्दा थी। पुलिस की जाँच पुलिसिया ढँग से चली किन्तु अब वह भी दोषमुक्त है। कोई न्याय का पण्डित, कोई मानवाधिकारी, कोई शासक व प्रशासक इन सरकारी अपराधों को रोकने की हिम्मत कर सकेंगे? और इन पीड़ितों को देने योग्य कोई मुआवजा क्या सरकार के पस है? सरकार घोषणा करे कि इन सरकारी अपराधियों को क्या दण्ड दिया जाएगा?

-(लक्ष्मीकान्त वावला, अमृतसर; आवाज-ए-खबरदार पंजाबकेसरी, दिल्ली, 05/04/05)

320) अफगानिस्तान में परिवर्तन की बयार : कट्टरपंथी समाज में बदलाव का संकेत है महिला जिम : विकास का सूर्योदय :- *अफगानिस्तान के हेरात शहर में अफगानी मुस्लिम महिलाएँ शफाक महिला व्यायामशाला क्लब में शरीक होकर महिलाओं के बीच एक आन्दोलन शुरुकर कट्टरपंथी समाज में एक बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं। व्यायामशाला में काम करने वाला पचीस वर्षीय मसूदा ने बताया– ''मैं हमेशा आजादी की समर्थक रही हूँ और जब से इस क्लब में आ रही हूँ, तब से खुलेपन की अनुभूति कर रही हूँ।'' मसूदा कहती हैं कि यह एक प्रकार का संघर्ष है, ताकि महिलाओं के विचारों में बदलाव लाया जा सके। उन्हें घर की चारदीवारी से बाहर निकालना, महिला दोस्त बनाना, अपने अधिकारों को जानना और उसके लिए प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करना इस क्लब का मकसद है।*

शफाक क्लब शहर में अपनी तरह का तीसरा क्लब है, जिसे हाल ही में खोला गया है। सिर्फ चार साल पहले तालिबान शासन के दौरान महिलाओं को बिना नकाब के बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। वहाँ इस तरह के क्लब का खुलना बेहद महत्त्वपूर्ण है। तालिबान शासन के पतन के बाद भी 27 वर्षीय नजीफा सिद्दीक को अपने शौहर से चोरी छिपे व्यायाम करना पड़ता था। हाल-फिलहाल तक वह नीले नकाब में कसरत करने आया करती थीं लेकिन अब वह केवल काले स्कार्फ को लगाकर क्लब आती हैं। वह कहती हैं कि व्यायाम करने से परम्परा और रूढ़िवाद के खिलाफ लड़ने में उन्हें मदद मिली है। उन्होंने कहा अब 13 साल के अन्तराल के बाद मैंने फिर से स्कूल जाना शुरु किया है, जो शादी के कारण छूट गया था। राष्ट्रपति हामिद करजई द्वारा गत वर्ष सितम्बर में पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात शहर में नये गवर्नर की नियुक्ति के बाद से महिलाओं के लिए बेहतर माहौल का निर्माण हुआ है। महिलाओं के लिए नौकरियाँ, स्कूल, व्यायामशाला जैसी चीजें विकसित हुई हैं। अफगान ओलम्पिक समिति के उपनिदेशक सईद महमूद जिया ने कहा कि यह पहला मौका है कि अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए कोई व्यायाम शाला बनी है। शफाक क्लब की प्रबन्धक 36 वर्षीय जाहरा मूरी ने बताया कि यह महिलाओं की प्रगति की दिशा में उठाया गया एक महत्त्वपूर्ण कदम है। महिलाओं को अब घर से बाहर निकलकर सामाजिक कार्य-कलापों में भी शिरकत करनी चाहिए। ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 22/06/2005)***

321) *हमारे भारतवर्ष के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज कराने के बजाय एक संघ का निर्माण करना चाहिए। वह एक ऐसा मंच होगा, जहाँ से सरकार के कानों में जनता की आवाज पहुँचेगी। यही संघ एक नये भारत का निर्माण करने में सक्षम होगा। संघ को जनता में जाग्रति फैलानी होगी कि किसप्रकार हमारा देश लोकतन्त्र की आड़ में लूटा जा रहा है! इस संघ के माध्यम से उन्हें सरकार से हक मिल सकता है, क्योंकि इस समय देश में लगभग 13 करोड़ बेरोजगार हैं। यदि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो पहला काम जो करना चाहिए, वह है– जनसंख्यावृद्धि पर नियन्त्रण। इसके लिए बेरोजगार नवयुवक सरकार पर दबाव बनाएँ कि सभी देशवासी एकसमान नागरिक संहिता अपनाएँ। विवाह-शादी केवल सरकारी कार्यालय में कराएँ और इसे पंजीकृत करें। विवाह के समय दम्पति के समय एक शपथनामा लें कि वे केवल एक ही बच्चा पैदा करेंगे। यदि कोई दम्पति शपथपत्र को भंग करता है, तो उसे शासन द्वारा मिलने वाले तमाम लाभ बन्द कर दिए जाएँ। दूसरा कार्य जो करना चाहिए, वह है– सरकारी नौकरियों में सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से घटाकर कम किया जाए, ताकि कुछ दूसरे लोगों को भी रोजगार नसीब हो।*

-(बलराजशर्मा, जीवनपार्क, उत्तमनगर, नईदिल्ली; आवाज-ए-खबरदार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 18/06/2005)

322) जनप्रतिनिधियों के ये शाही ठाठ-बाट :- हमारे जनप्रतिनिधियों में शाही ठाठ-बाट से जिन्दगी जीने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। सांसद हो या विधायक, सभी में जनता की खून-पसीने की कमाई पर गुलछर्रे उड़ाने की होड़ लगी हुई है। हर कोई बहती गंगा में ज्यादा से ज्यादा हाथ साफ कर लेना चाहता है। सभी चाँदी काट रहे हैं। हाल ही में एक विख्यात टेलीविजन चैनल ने यह रहस्योद्घाटन किया था कि देश के प्रत्येक सांसद पर जनता की खून-पसीने की कमाई का प्रतिमाह छह लाख रुपये तक खर्च होता है और विधायकों के शाही ठाठ-बाट को बरकरार रखने पर औसत पाँच लाख रुपये तक हर महीने फूँके जाते हैं। यह खर्चा प्रत्यक्ष की बजाय परोक्षरूप में ज्यादा किया जाता है। इस खबर का किसी ने खंडन नहीं किया। यह तथ्य भी सर्वविदित है कि भारत विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है। यहाँ की दो-तिहाई आबादी गरीबी रेखा से भी निचले स्तर पर जीवनयापन कर रही है। इस देश में 40 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, इनमें 6 करोड़ शिक्षित बेरोजगार भी शामिल है। हालत यह है कि उड़ीसा और बंगाल में माताओं को अपने जालिम पेट की आग से मजबूर होकर अपने जिगर के टुकड़ों (बच्चों) को 25-25 रुपये में बेचना पड़ता है। इसके बावजूद हमारे जनप्रतिनिधियों को हमेशा यह शिकायत रही है कि उनके वेतन और अन्य भत्ते बहुत कम हैं। हालाँकि हालत यह है कि गत एक दशक में पाँच बार सांसदों ने अपने वेतन और भत्तों में खुद ही बेतहाशा वृद्धि कर ली। खास बात तो यह है कि पाँचों बार यह फैसला सर्वसम्मति से बिना किसी विरोध के हुआ। गत महीने दिल्ली के विधायकों और मन्त्रियों के वेतन और भत्तों में तीन गुना वृद्धि हुई है। राजस्थान में यह चार गुना बढ़ी है। यह सिलसिला अन्य राज्यों में भी चल रहा है। अब तक यह परम्परा रही है कि गर्मियाँ शुरु होते ही हमारे सांसद निरीक्षण की आड़ लेकर हिल स्टेशनों या विदेशों के भ्रमण पर निकल जाते थे। उनकी इस मौज-मस्ती पर हर साल औसतन 50 करोड़ रुपये फूँके जाते थे। संसद में 30 मन्त्रालयों की संसदीय समितियाँ हैं। इनमें से प्रत्येक में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के ग्यारह सदस्य होते हैं। ये समितियाँ हर साल कई-कई बार, किसी न किसी बहाने देश और विदेश के दौरे पर निकल जाती हैं। पाँचतारा होटलों में ठहरते हैं और सम्बन्धित मन्त्रालयों के बजट से मौज-मस्ती उड़ाते हैं। यही सिलसिला विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में भी चल रहा है। अब लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने राज्यसभा के अध्यक्ष भैरोसिंह शेखावत के मशविरे से मन्त्रालयों की इन संसदीय समितियों के दौरों पर रोक लगा दी है कि यह समितियाँ साल में दो बार से अधिक दौरे न करें। सांसद मितव्ययिता से काम लें और सरकारी गेस्टहाउसों या सरकारी होटलों में ही ठहरें। लोकसभा अध्यक्ष के इन निर्देश से सांसदों के मुँह का जायका बिगड़ गया है।

कुछ वर्ष पूर्व गृहमन्त्रालय की राजभाषा संसदीय समिति के विश्व के 110 देशों के दौरे समाचार पत्रों में गर्मागर्म चर्चा का केन्द्र बने थे। इस समिति में हिन्दी की प्रगति का जायजा लेने के लिए विश्वभ्रमण का प्रोग्राम बनाया था। समिति में 51 सांसद शामिल थे। समाचार पत्रों के विरोध के बावजूद यह समिति इस दौरे पर 100 करोड़ रुपये फूँक आयी थी।

स्वाधीन भारत के निर्माताओं को यह आशा थी कि फिरंगियों के जाते ही देश में जनता का राज होगा। मगर उनके सपने धूल में मिल गए हैं। देश की राजनीति पर परिवारवाद, धन-दौलत और बाहुबल का शिंकजा दिन-प्रतिदिन कसता जा रहा है। एक समीक्षक के अनुसार भारत की राजनीति 60 परिवारों के कब्जे में है। राजनीति से देश की आम जनता का सरोकार दिन-प्रतिदिन खत्म होता जा रहा है। यह कड़वी सच्चाई है कि देश की राजनीति धनवानों की चेरी बनती जा रही है। आज लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जेब में कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपये होने चाहिए। जबकि राज्य विधानसभाओं के चुनावी दंगल में उतरने के लिए एक से पाँच करोड़ रुपये जेब में होने चाहिए। जाहिर है कि देश के 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति ही यह जुआ खेल सकता है। इसलिए जनप्रतिनिधि बनने के इच्छुक दोनो हाथों से दौलत बटोरने की तमन्ना से ही चुनावी दंगल में उतरते हैं। यही कारण है कि हमारे जनप्रतिनिधियों में से काफी लोग दौलत बटोरने के लिए हर हथकंडा अपनाते हैं। वर्तमान लोकसभा में 55% सांसद करोड़पति हैं। इनमें से कानून बनाने वाले 160 सांसद ऐसे भी हैं, जिनका पुलिस के पास आपराधिक रिकॉर्ड है। इनमें से 9 मन्त्री हैं। छह पर अदालतें फर्द जुर्म भी लगा चुकी हैं। इनमें से 306 को केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने सुरक्षा कवच प्रदान कर रखा है, जिस पर हर साल 250 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया जाता है।

शाही ठाठ-बाट के मामले में हमारे मन्त्री जरा भी किसी से कम नहीं हैं। इनके पास महलनुमा बंगले हैं। पंडित नेहरू जिस तीनमूर्ति हाउस में रहते थे, उसका क्षेत्रफल 30 एकड़ था और उसमें 42 कमरे थे। वर्तमान प्रधानमन्त्री निवास भी 27 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें भी 30 से अधिक कमरे हैं। काँग्रेसाध्यक्ष श्रीमती सोनिया गाँधी का बंगला दस जनपथ 20 एकड़ में फैला हुआ है। पूर्व प्रधानमन्त्री अटल जी का बंगला

13 एकड़ में है। पूर्व उपप्रधानमन्त्री लालकृष्ण आडवाणी का पृथ्वीराजरोड स्थित बंगला 11 एकड़ में फैला हुआ है। अर्जुनसिंह का 17 अकबररोड स्थित बंगला 8 एकड़ में है, तो शरदपवार का बंगला 7 एकड़ का है। लालूप्रसादयादव का 25 तुगलक लेन बंगला 8 एकड़ का है। कमलनाथ का बंगला 8 एकड़ का है। मुरली मनोहर जोशी का बंगला 11 एकड़ का है। जार्ज और जसवंत सिंह के बंगले 6–6 एकड़ के हैं। गरीबों के मसीहा रामविलासपासवान का जनपथ पर स्थित बंगले का क्षेत्रफल 14 एकड़ है। यही स्थिति अन्य नेताओं के बंगलों की भी है। इन नेताओं के बंगलों में कई लाखों का फर्नीचर है। इनमें से एक–एक सोफा चालीस हजार से एक लाख में खरीदा गया था। एक सर्वेक्षण के अनुसार मन्त्रियों के पास 6 से 15 तक सरकारी कारें हैं, जिनमें उनका स्टाफ सब्जी तक खरीदकर लाता है। इसके अतिरिक्त मन्त्रियों के घरों पर 5 से लेकर 11 तक एअरकण्डीशनर लगे हैं। बिजली–पानी का सारा खर्चा जनता के शिर पर है। गतवर्ष इन मन्त्रियों और स्टाफ के देश–विदेश के दौरों पर 700 करोड़ रुपये खर्चे का अनुमान है। इन बंगलों में अक्सर शाही दावत होती ही रहती है। ***-(मनमोहनशर्मा, स्तम्भकार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 06/06/2005)***

323) जाति की रूढ़ियों ने ली प्रेमी जोड़े की जान :- *जातिगत रूढ़ियों के कारण विवाह की अनुमति नहीं मिलने से निराश एक और प्रेमी जोड़े ने मोगा में खुदकुशी कर ली। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आलमवाला गाँव के युवक गुरतेज और उसकी प्रेमिका कुलविन्दर कौर ने जहर खाकर जान दे दी। दलित वर्ग का गुरतेज पेशे से ट्रक ड्राइवर था और कुलविन्दर के परिजन कतई नहीं चाहते थे कि उसका विवाह किसी दलित युवक से हो। कुलविन्दर ने रविवार को खुद को एक कमरे में बन्द कर लिया और जहरीला पदार्थ खा लिया। बाद में गुरतेज को भी कुलविन्दर के घर के पास ही मृत पाया गया।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 31/05/2005)***

324) राष्ट्रमण्डल खेलों के लिए उजाड़े जाएँगे झुग्गीवासी :- *निजामुद्दीन, बड़ापूला, शमशानभूमि और हुमायूँ बस्ती के लोगों ने अपने घरों की रंगाई–पुताई बन्द कर दी है। उन्हें सन्देह ही नहीं पूर्ण विश्वास हो गया है कि वह जिस घर में इस समय रह रहे हैं, उसे बहुत जल्द उजाड़ दिया जाएगा। यह अभियान 2010 में होने वाले राष्ट्रमण्डल खेलों के लिए चलाया जा रहा है। यमुनापार की झुग्गियों को उजाड़ा भी गया और कुछ को नोटिस मिल चुका है। पश्चिमी विनोद नगर, शान्तिमार्ग और पटपड़गंज के रिट्रीट अपार्टमेन्ट के पास की झुग्गियों को बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के बीच पी.डब्लू.डी. वालों ने उजाड़ दिया। इन झुग्गियों में रहने वालों का कहना है कि दिल्ली सरकार राजधानी को पेरिस बनाने की तैयारी में तो जुट गई है, परन्तु हमारी चिन्ता उन्हें नहीं है। अपने उजाड़े जाने के भय से इन झुग्गीवासियों ने दिल्ली प्रदेश झुग्गी–झोपड़ी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अपनी लड़ाई की योजना बनानी शुरु कर दी है।*

चाणक्यपुरी स्थित लोकनायक कैम्प के जगदीश और सलीमखान ने बताया कि सरकार हमारी वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना हमें नोटिस दे रही है। हमारे बच्चे अभी पास के स्कूलों में पढ़ते हैं। हम लोगों ने इण्डिया गेट पर स्थायीरूप से बैलून, घड़ी, पेन और खिलौने बेचकर आजीविका का उपाय कर लिया है। सरकार यदि हमें उजाड़ेगी, तो फिर हमें कहाँ भेजेगी, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। उत्तरप्रदेश के मूलनिवासी अशफाक का कहना है कि दस साल से दिल्ली में हूँ, बड़ा बेटा सरकारी विद्यालय में पाँचवी का विद्यार्थी है और बेटी शबनम तीसरी में पढ़ती है। पैसे की कमी के कारण अब अपने गाँव वापस जाने से भी उन्हें डर लगता है।

राष्ट्रमण्डल खेलों के लिए दिल्ली को सुन्दर बनाने का काम शुरु हो चुका है। नोएडा मोड़ के अक्षरधाम मन्दिर के पास की जमीन को इस खेल के लिए अधिग्रहण कर लेने की योजना है। इसके आसपास किसी भी प्रकार की झुग्गियाँ नहीं रहेंगे, ऐसा सरकार का आदेश है। जबकि यहाँ करीब 1000 के आसपास झुग्गियाँ हैं। दिल्ली प्रदेश झुग्गी–झोपड़ी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जवाहर सिंह का कहना है कि अब दिल्ली में मजदूरों ने भी अपने हक के लिए कमर कसना शुरु कर दिया है। राजधानी में हुए नौवें एशियाई खेलों के दौरान उजाड़े गए मजदूरों को शिर पर छत आज भी नसीब नहीं हुई है। एशियार्ड 1982 से अब तक लोगों के उजड़ने और उससे पहले के कई मामले उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। 2002 में कोर्ट ने अधिकांश मामलों को बन्द कर दिया और पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। कई परिवारों ने तो सामूहिक रूप से खुदकुशी भी की। कई परिवारों को मुआवजे के रूप में 5 से 10 हजार रुपये की रकम मिली। सरकार के पास पीड़ित परिवारों का रिकार्ड भी नहीं है। अब राष्ट्रमण्डल खेलों के लिए शुरु हुए निर्माणकार्य की शुरुआत में ही जिस तरह से झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, उससे लगता है राजधानी झुग्गीविहीन हो जाएगी। ***-(लेख : अमलेश राजू, ग्रासरूट फीचर्स; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 07/06/2005)***

325) बस अब और नहीं सहा जाता :- *हमें अब और इन्तजार नहीं करना। सही विचारों को यथार्थ में बदलने का समय आ गया है। बहुत पढ़ चुके अखबार! समस्याएँ तो सब जानते हैं। लेकिन उनको दूर करने के लिए व्यावहारिक कदम नहीं उठाते। आज भारतवर्ष में भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार है। बेरोजगारी की वजह से आज के जो खुद्दार युवा हैं, वे भीख नहीं माँगते किन्तु काम न मिलने पर खुदकुशी कर लेते हैं। बाकी अपराधी बन रहे हैं। इसी मई माह में खबर छपी है कि मुम्बई में बेरोजगार युवा आजकल नकली हिजड़े बन रहे हैं। पढ़कर आत्मा लहूलुहान हो गई। अरे युवाशक्ति! कहाँ गई व्यवस्था को बदल देने वाली तुम्हारी ताकत! आज के युवक चूड़ियाँ पहन रहे हैं, सलवार सूट पहन रहे हैं और नकली हिजड़े बनकर जैसे-तैसे अपना आधा पेट ही भर रहे हैं जबकि 70 साल से ऊपर के मन्त्री करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं। स्वर्गीय प्रधानमन्त्री नरसिंहाराव ने अपने शासनकाल में 5 हजार करोड़ का घोटाला किया। मुझे युवाशक्ति से यही कहना है कि आपका भविष्य बहुत ही अन्धकार में है। सड़ी-गली शासनपद्धति केवल राजनेता का पोषण कर रही है। सभी राज्य सबको एक समान खाना-रहना प्रदान करे, क्योंकि सभी भगवान की सन्तान हैं और परमात्मा की नजर में सभी बराबर हैं। जयहिन्द!* ***-(एक पाठक; आवाज-ए-खबरदार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 31/05/2005)***

326) एकीकृत संविधान : यूरोपीय यूनियन :- *आखिर यूरोपीय यूनियन का क्या भविष्य होगा? ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में फ्रान्स एवं नीदरलैण्ड द्वारा यूरोपीय यूनियन संविधान को समर्थन देने से किए गए स्पष्ट इन्कार से यूरोपीय यूनियन के विस्तार और एकीकरण के प्रयासों को आघात पहुँचा है। यूरोप के लोग यूरोप के एकीकरण के मुद्दे पर सशंकित हैं। इनको डर है कि एकीकृत संविधान के पारित होने से यूरोप के गरीब देशों के लोग उनके देशों में आ जाएँगे, जिससे उनके लिए रोजागार के अवसर कम हो जाएँगे। गौरतलब है कि इस संविधान को यूरोप के 25 देशों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर ही लागू किया जा सकता है। स्पेन, लिथुआनिया, हंगरी, आस्ट्रिया, जर्मनी, ग्रीस, इटली, लातविया, स्लोवाकिया एवं स्लोवानिया संविधान के अनुमोदन पर अपनी मोहर लगा चुके हैं। इसके अलावा ब्रिटेन, लग्सम्बर्ग, डेनमार्क, पुर्तगाल, पोलैण्ड, आयरलैण्ड, बेल्जियम, साइप्रस, ऐस्टोनिया, फिनलैण्ड, माल्टा एवं स्वीडन को अभी फैसला लेना है। अगर नवम्बर 2006 तक इस संविधान पर सभी 25 देशों ने अपना अनुमोदन नहीं दिया तो यह खारिज हो जाएगा।* ***-(सज्जादनिर्जा, स्तम्भकार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 07/06/2005)***

327) *लोकतन्त्र में राजनीतिज्ञ ही सर्वेसर्वा होते हैं, जिन्हें जनता चुनती है। सिद्धान्ततः ये राजनीतिज्ञ ही हैं, जो देश के विकास की राह तय करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी राजनीति में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है। राजनीति में विकार आ गए हैं। लोकतन्त्र में राजनीति को उद्देश्यपूर्ण और सामाजिक बुराइयों में परिवर्तन का अस्त्र होना चाहिए। इन विकारों के सबक हमें बेहतरी की ओर ले जाएँगे। एक न्यायोचित समाज बनाने के लिए प्रशासन को विनम्र बनना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन के लिए तकनीकी ज्ञान अथवा तेजस्वी व्यक्तित्व और वैसी मानसिकता चाहिए।* ***-(प्रधानमन्त्री मनमोहनसिंह; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 21/05/2005)***

328) क्यों उपेक्षित से हैं- नये भारत का सपना दिखाने वाले स्कूल :- *किसी भी देश को नये युग में प्रवेश कराने का जिम्मा वहाँ की शिक्षाव्यवस्था यानि वहाँ के स्कूलों पर होता है। सो अन्य देशों की भाँति भारत में भी उच्चस्तर की शिक्षा मुहैया कराने का मुख्य स्रोत प्राइवेट स्कूल ही हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली और प्लानिंग में लाख सुधार करने के बावजूद भी सरकारी शिक्षा का स्तर हमेशा जस का तस ही बना रहा है। कभी शिक्षकों की कमी तो कभी बिल्डिंगों का अभाव तो कभी माहौल से सामंजस्य की कमी आम आदमी के दिल में सरकारी स्कूलों के प्रति माहौल दिनोंदिन बद से बदतर ही होता चला जा रहा है। सरकार की इसी असफलता ने आम आदमी के जेहन में प्राइवेट शिक्षा के प्रति गहरे तक रुचि पैदा कर दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि इन स्कूलों ने अपनी मनमानी शुरु कर दी। ट्रस्ट द्वारा चालित स्कूलों को नो प्रॉफिट नो लॉस और समाज के सभी वर्गों को शिक्षा में समान हिस्सेदारी जैसे नियमों की धज्जियाँ उड़ायी जाती रहीं। करोड़ों की जमीन कौड़ियों में लेने के बाद भी ये स्कूल जनता से मोटे डोनेशन, डेवलपमेन्ट चार्ज, मनोरंजन, स्पोर्ट्स आदि के नाम पर खुली लूट के चलते आम जनता और कोर्ट ने कई बार इन स्कूलों पर नकेल कसने की भरसक कोशिशें कीं। लेकिन जनता को दोनों हाथों से लूटने की इन स्कूलों की नीति में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया।* ***-(आर.सी.जैन, ऑक्सिनदेखी, मंगलवार्ता; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 24/05/2005)***

329) *देश को नेता दीमक की तरह खा रहे हैं। जैसे चारा घोटाला, स्टाम्प घोटाला में नेता भी शामिल थे। देश की कई करोड़ की सम्पत्ति हजम करके डकार भी नहीं लेते। नेता पर केस भी तब तक चलता रहता है, जब तक वह मर न जाए और मरने के बाद केस खतम, पैसा हजम। मैं इसलिए लिख रही हूँ कि भारतमाता के पास अब वो बेटे नहीं हैं, जो शहीद हो सकें। भारत अब पुनः गुलामी डगर पर खड़ा है।*

-(मंजूगौड़, गहाँगीरपुरी नईदिल्ली; आवाज-ए-खबरदार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 24/05/2005)

330) राजनेता की परिभाषा :- *हिन्दी शब्दावली में जितने भी अभद्र और गन्दे शब्दों को जोड़कर यदि कोई वाक्य बना दिया जाए, तो भी राजनेता की परिभाषा शायद पूरी न हो। वर्णन के लिए फिर भी दूसरी भाषाओं से डिक्शनरी लेकर खोजना पड़ेगा। आज एक ऐसे ही श्रीमान पर सी.बी.आई. ने एक और चार्जशीट तय कर दी है। सुना है आजकल महाराष्ट्र में बिजली का इतना जबरजस्त संकट है कि 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तापमान में बगैर पंखे, बगैर कूलर, बगैर पानी कैसे जी रहे होंगे लोग, भगवान ही जाने? किन्तु वहाँ के बिजली मन्त्री के घर में दस-दस ए.सी. और 24 घण्टे बिजली तथा महीने का बिल 30 हजार रुपये वह भी सरकारी खजाने से। जनता जनार्दन का पैसा। तौबा! तौबा! लाज, हया, शर्म, ईमानदारी, चरित्र आदि इनकी ही भाषा में ठण्डे बस्ते में डाल दी गई हैं। बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर लड़ाई और मारपीट तत्पश्चात ए.डी.आर.एम. का सस्पेंशन और फिर महादबाव में आकर उसका रिवोक। क्या ऐसे व्यक्ति को आमसभा या मन्त्रिमण्डलीय बैठक में बुलाना चाहिए? नहीं कदापि नहीं! और नहीं बस और नहीं! जब बाड़ ही खेत की फसल खाए, तो कौन बचाए?*

-(श्रीकान्तचुमेदार, प्रीतमपुरा दिल्ली; आवाज-ए-खबरदार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 23/05/2005)

331) *आज 58 वर्षों में तूफान से यहाँ तक जो कश्ती निकालकर लाए हैं, उसके लिए इस देश की सीमा पर पहरा दे रहे सैनिक और हमारी तीनों सेनाएँ, राष्ट्र के वैज्ञानिक, शिक्षाविद, विधिविशेषज्ञ, इंजीनियर, डाक्टर, वकील, कम्प्यूटर विशेषज्ञ, न्यायपालिका, कार्यपालिका और निस्सन्देह मीडिया की ही कुछ भूमिका है और इन सबके ऊपर हैं, सच्चरित्र नागरिक। परन्तु इस देश को अगर अब्दाली, नादिरशाह, महमूदगजनवी और गौरी से भी ज्यादा किसी ने लूटा है, तो यह उन्हीं बेईमान और बदमाश राजनेताओं ने लूटा है, जो आज तक सुधरे नहीं, अपितु इनकी हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती चली आ रही है। राजनीति में अपवाद के रूप में कुछ नेताओं को देखता हूँ, तो लगता है कि इनका इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रनिर्माण की दिशा में कहीं बेहतर हो सकता था। अगर अपवादों को छोड़ दें, तो बाकी जो ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री के रूप में खड़े हैं, इनके चेहरे दूरदर्शन में नजर आते हैं और कहीं ये आदर्शवादी वाक्य बोलते भी नजर आते हैं, तो मन करता है कि बाटा कम्पनी की सारी मेहनत इनके शिरों पर कुर्बान कर दी जाए। दुनियाभर के चोर, उचक्के और बेईमान परन्तु अपेक्षा यह कि हम इन्हें आदरणीय कहें, मान्यवर कहें। समाज का यह कैसा पतन हो चुका है? क्या राष्ट्र में मीडिया, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर आधारित कोई शासनव्यवस्था प्रजा के हित में बन सकती है? इस पर उपरोक्त तीनों स्तम्भों से जुड़े लोगों को विचार करना होगा। भारत के सारे सच्चरित्र नागरिक उनके साथ होंगे। क्या चन्द ऐसे राजनीतिज्ञ लोग राष्ट्र की सम्प्रभुता को लील जाएँगे? क्या हम भारत के सच्चे नागरिक चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहेंगे? क्या इसके विरोध में हममें से कोई भी नहीं उठेगा? कौन देगा इन यक्षप्रश्नों के उत्तर?*

-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 16/05/2005)

332) *ऑक्सफोर्ड द्वारा प्रकाशित इण्डिया डेवलपमेन्ट रिपोर्ट 2004-05 के अनुसार- ''भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर बासिन्दों को साफ पीने का पानी, शौचालय, सफाई की नालियाँ और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध नहीं है। देहात की 17.5 करोड़ महिलाएँ जलाने की लकड़ी के रूप में ईंधन की तलाश में फिरती हैं। धुएँ ने ग्रामीण महिलाओं की जिन्दगी में रोगों को न्यौता दिया है। देहातों में 2.5 करोड़ नवजवानों को श्वाँस सम्बन्धी रोगों ने घेर लिया है। आर्थिक विकास अन्ततः आम आदमी के लिए है किन्तु यदि देहाती और शहरी दोनों ही गरीब हैं, बेरोजगार हैं, उनका जीवन खतरे में हैं, उन्हें शुद्ध पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं है, उन्हें स्वच्छ ईंधन नहीं मिलता है, उन्हें समुचित स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलती, वे असन्तुष्ट हैं, उस स्थिति में यह आर्थिक विकास का दम्भ फिजूल है।''*

पंचायती राज मन्त्री मणिशंकर अय्यर ने लोकसभा में कहा था– ''देश के देहातों में आधे लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। पेयजल की बात चली तो देश के 6 लाख गाँवों में शुद्ध पीने का पानी तक पहुँचना 58 वर्षों में भी मुमकिन नहीं हुआ। गाँव के पोखर, तालाब, बावड़ी और कुओं के पेंदे सूखे खनकने लगे। अनेक गाँवों में जहरीला पानी पीने से देहातियों के कूबड़ निकल आयी है। प्रदूषित पानी से गाँव वालों के हाथ–पैर टेढ़े–मेढ़े हो गए हैं। प्रदूषित पानी से आधे गाँव वालों के दाँत खराब है। कुछ गाँवों में प्रदूषित पानी से भयानक कष्टदायक नारू रोग से जूझना पड़ता है। प्रदूषित पानी से कुछ गाँवों में अन्ध ता का आलम है। प्रदूषित पानी से देहातियों को पेट के रोगों का ग्रास बनना पड़ रहा है। गाँव के कुएँ, बावड़ी आदि की सफाई का कोई बन्दोबस्त नहीं है। गाँव के पेयजल की नियमित जाँच का कोई सवाल ही नहीं उठता है। देहातों में लगे 50 प्रतिशत से अधिक हैण्डपम्प बेकार हैं। शेष में से भी हैण्डपम्पों का पानी पीने योग्य नहीं है। हैण्डपम्पों के घोटाले अलग से हैं। सरकारी पानी छोटे गाँव और ढाँड़ियों में महिलाएँ मीलों दूर पानी लेने जाती हैं। गाँव में प्रतिव्यक्ति पानी की खपत शहरों के मुकाबले पाँच प्रतिशत है।

जीवन के लिए प्राथमिक आवश्यकता पानी देहातियों को देना सरकार का सर्वोच्च उत्तरदायित्व है। मैं पूछता हूँ कि कागजी योजनाओं, बजट के आँकड़ों और घोषणाओं से इतर गाँव में जल पहुँचाने के लिए क्या किया जा रहा है। शुद्ध खनिज पानी पीने में अपनी शान समझने वालों को देहाती पानी के कष्टों का स्वाद कैसे पता चलेगा ? ***-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 25/05/2005)***

333) बालमजदूरी रोकने के लिए प्रयासरत हैं कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएँ :- *नवसृजित प्रदेश (उत्तरांचल) में जहाँ सरकार प्रगति के मायनों पर खरा उतरने के लिए लगातार प्रयासरत है, वहीं प्रदेश में बालश्रम व बंधुआमजदूरी को रोकने के लिए सरकार के साथ–साथ कई गैरसरकारी संस्थाएँ भी कार्यरत हैं। सुभाषरोड स्थित एक होटल में ए.डी.पी.महिलाविजन द्वारा बालश्रमदिवस समारोह में जहाँ प्रदेश के कई मलिन बस्तियों के बच्चे स्टार होटल के मखमली कुर्सियों पर विराजमान होकर प्रदेश की विकासोन्मुखता के पर्याय बन रहे थे, वहीं अँग्रेजी भाषा में पारंगत वक्ता एवं बुद्धिजीवी अपने शब्दों से इन अनपढ़ मजदूरों व मलिन बस्तियों के बच्चों की स्थितियों को बयाँ कर रहे थे। इस अवसर पर प्रदेश के परिवहन व तकनीकी मन्त्री हीरा सिंह बिष्ट बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए बोल रहे थे कि प्रदेश को बालश्रम व बंधुआ मजदूरी के कोढ़ से वंचित रखने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश में लगभग 1 करोड़ 66 लाख बालश्रमिक कार्यरत हैं। उन्होंने बालश्रम व बंधुआ मजदूरी को विकसित या विकासशील देशों में एक व्याधि बताते हुए कहा कि सरकार समूचे प्रदेश की मलिन बस्तियों में शिक्षा के प्रसार–प्रचार हेतु नई प्राइमरी विद्यालयों की स्थापना करेगी एवं बच्चों को निःशुल्क किताबें आवंटित कर उनको शिक्षा की ओर अग्रसारित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश को समृद्धिशाली एवं सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षा, परिवहन, उद्योग व अन्य क्षेत्रों की प्रगति करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में मध्यान्ह भोजन से लेकर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं व पुरुष मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 73 रुपया प्रतिदिन तय करने वाला देश का पहला राज्य है।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 13/05/2005)***

334) *भारतभूमि पर अब तक जो महान विभूतियाँ अवतरित हुई हैं, उन्हें किसी दैवी चमत्कार ने महान नहीं बनाया बल्कि उत्तम गुण व माता–पिता और गुरु से मिले अच्छे संस्कार ही उनके लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। आज समाज में जो बेईमानी, भ्रष्टाचार, हिंसा और अराजकता का माहौल कायम है, यदि इसे जड़ से उखाड़ फेकना है, तो आप सभी को सच्चे सिद्धान्तों और जीवनकल्याण के गूढ़ रहस्यों को समझना होगा और उसी पर आगे बढ़ना होगा। यह आर्यसमाज का मार्ग ऐसा मार्ग है, जहाँ ऊँच–नीच, स्त्री–पुरुष, अमीर–गरीब, बालक–वृद्ध सब एक समान हैं। आर्यसमाज का उद्देश्य है– कर्तव्यबोध कराना; हित–अहित, सत्य–असत्य, न्याय–अन्याय को पहचानने की क्षमता उत्पन्न करना और उस राह पर अग्रगामी करना है, जहाँ सिर्फ आनन्द ही आनन्द है। आर्यसमाजरूपी पाठशाला की हर ईंट यही कामना करती है कि :–*

हों सभी के दिल तथा, संकल्प अविरोधी सदा।
मन भरे हों प्रेम से, जिससे बढ़े सुख-सम्पदा॥

-(महाशय धर्मपाल, सुप्रसिद्ध उद्योगपति; आवाज-ए-खबरदार, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 14/05/2005)

335) जाँच आयोग : गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं :- *लोग जाँच कमीशनों में न्याय की तलाश करते हुए मुझे अक्सर ऐसे प्रतीत होते हैं, जैसे कोई दीवाना पाकिस्तान में जम्हूरियत (लोकतन्त्र) की तलाश कर रहा हो। सारा इतिहास उठाकर देख लें, किसे मिला आज तक इन आयोगों से न्याय? जब भयंकर घटनाएँ हो जाती हैं, तो राजनीतिक दबाव को न सहन कर पाती सरकारें आयोग बैठा देती हैं। थोड़ी देर के लिए तूफान थम जाता है और समय की आँधी सबकुछ उड़ाकर ले जाती है। इन आयोगों का क्या नतीजा हुआ, शायद आप भी जानना चाहें। नतीजा यह था–*

जिनने लूटा है सरेआम मुल्क को अपने।
लफंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता।।
गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं।
समंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता।।

ऐसा नहीं है कि समंदरों पर उंगलियाँ नहीं उठीं। परन्तु कौन लेता उनकी तलाशी? जरा एक नजर इधर भी डाल लें– जीप घोटाला, पंडित नेहरू (काँग्रेस); सुभाषबाबू विमान काण्ड, पंडित नेहरू (काँग्रेस); नागरवाला, इन्दिरागाँधी (काँग्रेस); अवैध चुनाव में अन्तर्लिप्तता, इन्दिरागाँधी (काँग्रेस); तुर्कमानगेट काण्ड, संजयगाँधी (काँग्रेस); बोफोर्सतोप खरीद काण्ड, राजीवगाँधी (काँग्रेस); जर्मन पन्डुब्बी खरीद काण्ड, राजीवगाँधी (काँग्रेस); यूरिया, लक्खूभाई, सांसद खरीद–फरोख्त काण्ड, नरसिंहराव (काँग्रेस); पेट्रोलपम्प काण्ड, कैप्टन सतीशशर्मा (काँग्रेस); तहलका काण्ड, जयाजेटली (राजग); हवाला काण्ड, आडवाणी (भाजपा); अयोध्या मन्दिर काण्ड, आडवाणी (भाजपा); तेलगी काण्ड, छगन भुजबल (एन.सी.पी.); ताबूत काण्ड, जार्ज फर्नान्डीज (राजग); शिवानी हत्या काण्ड, प्रमोदमहाजन (भाजपा); पेट्रोलपम्प आवंटन काण्ड, रामनाइक (भाजपा); प्लाट आवंटन काण्ड, अनंतकुमार (भाजपा); सेंटूर होटल बिक्री काण्ड, अरुण शौरी (भाजपा); गुजरात दंगा काण्ड, नरेन्द्रमोदी (भाजपा); साड़ी काण्ड लखनऊ, लालजी टण्डन (भाजपा); ताज कोरीडोर काण्ड, मायावती (बसपा); 1984 सिखविरोधी दंगा (कई बड़े काँग्रेसी नेता शामिल थे)। कैसे लिखूँ भारत की इस दुर्दशा को? और कश्मीर में आज क्या हो रहा है? भारत को अगर स्कैमलैण्ड घोषित कर दिया जाए, तो आश्चर्य न होगा। एक न्यायिक पदाधिकारी जो अपने फैसले में यह लिखने को बाध्य हो जाए– ''भारत में भगवान के मन्दिर और इंसाफ के मन्दिर में एक साम्यता है। यहाँ अमीरों, शक्तिशालियों और नेताओं के लिए एक तरह का व्यवहार किया जाता है और आम आदमी के लिए दूसरी तरह का। आप वी.आई.पी. हैं, तो मन्दिरों में लाइन लगाने की जरूरत नहीं। आप जेब ढीली कीजिए और सबसे आगे खड़े होंगे। इसीप्रकार इंसाफ के मन्दिर में बड़े से बड़ा वकील आपको फीस देने पर मिल जाएगा। और अगर आप पूँजीपति हैं, तो रात को 12 बजे घर बैठे जमानत मिल जाएगी।'' जिनकी यह टिप्पणी है, उन्हें मैं नमन करता हूँ। ज्यादा बातें नहीं लिखीं, नहीं तो ये नेता बीच सड़क पर अपनी स्वाभाविक स्थिति में खड़े नजर आते। ये राजनैतिक प्राणी कितने घातक हैं? क्या लिखूँ? ***–(अश्विनीकुमार, विशेष सम्पादकीय; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 06/05/2005)***

336) *ब्रिटेन की एक टीचर साराह फारसिथ के मुताबिक युवराज हैरी पढ़ाई में बेहद कमजोर हैं और एटन कालेज में 'ए' लेबल की परीक्षा के दौरान बेहतर अंक हासिल करने के लिए शिक्षकों ने नकल करने में उनकी मदद की थी। जाँच आयोग को दिए बयान में उक्त शिक्षिका ने बताया कि एक टीचर ने हैरी के बनाए चित्रों के लिए लेख लिखे थे। जबकि एक अन्य टीचर ने प्रोजेक्ट तैयार करने में उनकी मदद की थी। एटन कालेज में कला विभाग के प्रमुख शिक्षक ने हैरी के उस लेख को लिखा था, जो बाद में दुनिया भर के अखबारों में प्रकाशित किया गया था। सोमवार से प्रिंस हैरी ने सैन्डहर्स्ट स्थित आर्मी ऑफीसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण लेना शुरु किया है। एटन कालेज में उनकी पूर्व शिक्षिका साराह फारसिथ का कहना है कि हैरी को जिस रिजल्ट के आधार पर इस इंस्टीट्यूट में प्रवेश मिला है, वह नकल करके प्राप्त किया गया है। फारसिथ ने बताया कि कला विभाग के प्रमुख ने उनसे हैरी की कापी में प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहा था ताकि उन्हें अधिक नम्बर दिए जा सकें।* ***–(एक समाचार; अमर उजाला, 11/05/2005)***

337) वक्त की नजाकत पहचाननी चाहिए नेपालनरेश को :- *नेपाल की शासन व्यवस्था कैसी हो, इसका फैसला तो वहाँ की जनता करेगी। परन्तु अगर नेपालनरेश यह समझते हैं कि माओवादी संकट का बहाना लेकर वे निरंकुश राजशाही की स्थापना कर सकेंगे, तो यह उनका दिवास्वप्न ही सिद्ध होगा। बीसवीं सदी बड़े-बड़े तानाशाहों और निरंकुश बादशाहों की दुर्दशा की गवाह है। ईरान, मिश्र और तुर्की के बादशाह कैसे बेआबरू होकर अपने देशों से भागे, यह सब हाल के इतिहास की घटनाएँ हैं। नेपालनरेश को उनसे सबक लेना चाहिए। यूरोप में भी जो राजशाहियाँ बची हैं, वे प्रजातान्त्रिक ढाँचे में ही बची हैं। भारत और नेपाल दोनों को ही कुछ बातें स्पष्ट समझ लेनी चाहिए और अपनी नीतियों का निर्धारण भी उसी के अनुसार करना चाहिए। पहली बात तो यही है कि माओवादी समस्या का समाधान केवल सैनिक कार्यवाही से नहीं हो सकता। गरीबी और बदहाली में जिन्दगी जी रही जनता की जिन आकांक्षाओं को उबारकर माओवादी उनके बीच अपनी पैठ बनाने में सफल हुए हैं, उनका समाधान किए बिना माओवादी समस्या का उन्मूलन संभव नहीं है। यह अकल्पनीय है कि नेपालनरेश सेना के बल पर ऐसा कर सकेंगे। एक वास्तविक जनप्रतिनिधि सरकार ही इस काम को कर सकती है। हिन्दू धर्म के कुछ तथाकथित रक्षक नेपालनरेश के प्रति जो एकजुटता दिखाते हैं, उससे अगर नेपालनरेश किसी तरह की गलतफहमी पालेंगे, तो वे अपना ही नुकसान करेंगे। तमाम अन्तर्विरोधों के बावजूद भारत के राजनीतिक दल नेपाल में शीघ्रातिशीघ्र प्रजातन्त्र की बहाली चाहते हैं। सभी राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं की रिहाई, मीडिया की आजादी और लोकतन्त्र की बहाली ही नेपाली जनता, भारतीय जनमानस और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को सन्तुष्ट कर सकेगी। हम उम्मीद करते हैं कि नेपालनरेश वक्त की नजाकत को समझेंगे और लोकतन्त्र बहाली के लिए कदम उठाएँगे।*

-(पूर्व प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 14/05/2005)

338) मन्दिरों-मठों पर टैक्स :- *ट्रस्टों की अकूत सम्पदा पर वित्त मन्त्रालय की कड़ी नजर है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरकप्रश्न के जबाव में वित्तमन्त्री चिदम्बरम ने कहा कि 13 मई तक धर्मादा संस्थाओं की कर व्यवस्था में संशोधन के लिए एक विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा। मैं इस मामले पर सावध ानीपूर्वक तथा संवेदना के साथ कार्य करना चाहता हूँ। वामपन्थी दल यह माँग करते हैं कि मठों और मन्दिरों को कर के दायरे में लाया जाए, परन्तु भाजपा और विश्वहिन्दूपरिषद ऐसे किसी भी कदम का पुरजोर विरोध करती रही है। चिदम्बरम ने कहा कि बहुत सारे निकाय शिक्षा और स्वास्थ्य के जरिए धर्मादा कार्यों में लिप्त हैं और इस तरीके से इन निकायों ने अकूत सम्पदा एकत्र कर ली है। वित्तमन्त्री का संकेत इस तथ्य की ओर था कि धर्मादा संस्थाएँ नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर चलाई जाती हैं ओर संग्रहीत पैसे का इस्तेमाल भी ध र्मादा कार्यों के लिए किया जाता है। इसी के मद्देनजर इन संस्थाओं को आयकर अधिनियम की धारा 80-जी के अन्तर्गत कर की छूट दी जाती है। पर ये संस्थान धन एकत्र करने और काला धन को सफेद करने के साध ान बन गए हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में कुल 5 लाख ट्रस्ट हैं, जिनमें कुल मिलाकर 5 लाख करोड़ रुपये संग्रहित हैं। यह धन कमोवेश आयकर से मुक्त है। ऐसे में वित्तमन्त्री की नजर इस धन पर जाना स्वाभाविक है।*

-(एक समाचार; अमर उजाला, देहरादून, 12/05/2005)

339) शिक्षा की दुर्दशा :- *प्रत्येक देश के लिए शिक्षा का अत्यधिक महत्त्व है। किन्तु हमारे देश में शिक्षा की दशा अत्यन्त शोचनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। छोटे स्कूलों से लेकर बड़े स्कूलों तक भ्रष्टाचार की नदी बह रही है। सरकारी प्राइमरी पाठशालाओं की स्थिति अधिक शोचनीय है। अध्यापक केवल वेतन पाने में मग्न हैं। इन स्कूलों में पढ़ाई के बारे में सोचना भी बेकार है। शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि अच्छे माँ-बाप अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाना पसन्द नहीं करते। जब मैंने कुछ अभिभावकों से पूछा- 'क्या आप अपने बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना चाहोगे?' तब मुझे उत्तर मिला- 'इन सरकारी स्कूलों से भगवान बचाए।' इसी कारण निजी स्कूल मनमानी रकम वसूल रहे हैं। गरीब का पढ़ना मुश्किल हो रहा है। आखिर इस देश में शिक्षा का व्यापार कब तक चलता रहेगा?*

-(अशोकशर्मा, अमरोहा; आवाज-ए-खबरदार, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 10/05/2005)

340) *अगर हमें सामाजिक न्याय नहीं मिला, तो चाहे हिन्दुस्तानी कितना भी धार्मिक क्यों न हो, उसका भगवान पर से विश्वास उठता ही जाएगा और एक दिन चाहे वह विदेशी या हिन्दुस्तानी व्यक्ति जो गुरुगोविन्दसिंह, भगवान कृष्ण, भगवान राम, हजरत मुहम्मद व ईसामसीह जैसा व्यक्ति सामाजिक न्याय दिलाएगा, तो वही भगवान कहलाएगा। आज के परिवेश में सब बाहुबली तो हैं, आतंकवादी तो हैं, किन्तु कोई भी भगवान राम व गुरु तेगबहादुर व आजादी के शहीदों की तरह से जनहित के लिए मरने-मिटने वाला नहीं है।* **-(मुकेशगुप्ता, दरियागंज; आवाज-ए-खबरदार, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 10/05/2005)**

341) मुठ्ठीभर चावल के बदले बच्चा बेचा :- *गरीबी इंसान से क्या नहीं करा देती। इसका एक ताजा उदाहरण देखने को मिला। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में जहाँ गरीबी के मारे माँ-बाप ने अपना सवा साल का बेटा मात्र कुछ चावल, हल्दी की एक गाँठ और चन्द सिक्कों के एवज में बेच दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मालदा कि विधाननगर इलाके में एक व्यक्ति सुकुमार और मीरामण्डल अपने सवा साल के बेटे और तीन बेटियों को खिलाने-पिलाने में गरीबी के कारण असमर्थ थे। इसीलिए उन्होंने अपने इस कलेजे के टुकड़े को बेच दिया, ताकि परिवार के अन्य सदस्यों की जठराग्नि को कुछ हद तक शान्त कर सकें। उनकी तंगहाली से वाकिफ इलाके के किसी भी व्यक्ति ने इस सौदे का विरोध नहीं किया। सुकुमार रिक्शा चलाता था लेकिन कुष्ठ रोग हो जाने के कारण उसने अपना काम छोड़ दिया था और अब सिर्फ मीरा की कमाई पर घर चल रहा था, जो लोगों के घरों में काम करके थोड़ा बहुत कमाती है।* **-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 10/05/2005)**

342) एक अनूठा सम्मेलन : आदमीयत से खतरा :- *भारतवर्ष के एक राज्य में किसी घने जंगल में अखिल भारतीय श्वान सम्मेलन तीन दिनों तक चला, जिसमें विदेशी डेलिगेट्स ने भी भाग लिया। जो कुछ भी उस सम्मेलन में हुआ वह बड़ा चौंकाने वाला था। सबसे पहले कुत्तों के वंश पर ही एक शोधपत्र प्रस्तुत किया गया। उसका सार था कि हम श्वान वंश के लोग भले ही कुत्ते कहे जाते हैं, परन्तु हमारी चारित्रिक समग्रता कि बारे में आज तक पूरे देश में कहीं उंगली नहीं उठी। हमारी स्वामिभक्ति पर कोई दाग नहीं लगा सकता। हम जिसका नमक खाते हैं, उसका हक बराबर अदा करते हैं। हम किसी कीमत पर स्वामी को धोखा नहीं देते। हर हाल में प्रसन्न रहते हैं। रात-रात भर जागकर मालिक की रक्षा करते हैं। चोरी बदमाशी घोटालेबाजी से सर्वथा दूर रहते हैं। इतनी सारी खूबियों के होते हुए भी मनुष्य जब किसी को अपमानित करने के लिए कुत्ता शब्द प्रयुक्त करता है, तो हमारा दिल छलनी हो जाता है। किसी मनुष्य को कुत्ता कहना वास्तव में उसका बहुत बड़ा सम्मान है। वह अनायास ही सच्चरित्रता के न जाने कितने प्रमाणपत्र पा जाता है। परन्तु इस कुत्ता शब्द का अपमान अब सहनीय नहीं रहा। इसका इस्तेमाल सावधानी से ही किया जाना चाहिए।*

एक और कुत्ते ने भाषण दिया- ''मनुष्य अपनी आबादी नहीं देखता कि वह कहाँ भागी जा रही है। आज वे भारत में 1 अरब 20 करोड़ हो गए हैं। भारत की सारी प्रगति उनकी यह आबादी लील जाएगी। परन्तु धर्मनिरपेक्षता का मारा वह कोई कानून नहीं बनाता। हमारे पीछे ये लोग न जाने क्यों पड़े हैं ? हमारे मामले में मनुष्य नस्लनिरपेक्ष नहीं है। हर देशी कुत्ते की नसबन्दी शहर में ये कुत्ता पकड़ो वैन के लोग जबरजस्ती करवा रहे हैं। परन्तु विदेशी कुत्तों की नस्ल की संख्या बढ़ाने के लिए उपाय खोजे जा रहे हैं। ऐसे में आज हर घर में यह संदेश भेजा जाना आवश्यक है- छोटा परिवार सुखी परिवार, मनुष्य दो कुत्ते चार।

सम्मेलन में एक और दर्शनिक टाइप कुत्ते ने कुछ गम्भीर बातें कहीं। वह बोला- ''हम भैरव वंश के प्रतिनिधि हैं। हमारा अपमान होगा, तो विध्वंस हो जाएगा।'' एक धार्मिक दिखने वाले कुत्ते ने कहा- ''युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग में कौन पहुँचा ? भीम, अर्जुन, द्रौपदी सब पीछे रह गए। पर वाह रे श्वानकुल! हम सत्य और धर्म के प्रतीक हैं। इस पर एक विदेशी कुत्ते ने कहा- ''आपकी हम सब बातें मानते हैं, परन्तु देशी कुत्तों में आज निडरता की भावना लुप्त हो गई है। मनुष्यों को तो आप बहुत गालियाँ दे रहे हैं, पर उनसे पूछते क्यों नहीं कि घर की शोभा बढ़ाने के लिए तो टेरियर, डाबरमैन, जर्मनशेफर्ड आदि सिर्फ विदेशी ही चाहिए। वहाँ तो नस्लों की खूब परख करते हो। परन्तु सर्वनस्लसमभाव की भावना को केवल मनुष्यों तक ही क्यों सीमित रखते हो ? वहाँ आरक्षण क्यों ? जरा एक भी नेता बता दो, जिसने एक भी देशी कुत्ता पाला हो ?'' इस बात पर चुप्पी छा गई। देशी भारतीय कुत्तों के कैम्प में मानो साँप सूँघ गया। जब नेताओं की बात आई तो एक लाल चमड़ी वाले कुत्ते ने कहा- ''इन नेताओं के कारण हमारा बड़ा अपमान हुआ है।

देशी हो या विदेशी हमारा कुल तो श्वान कुल ही है। ये नेता धोखाधड़ी, द्रोह, चोरी, घोटाले आदि सारे अपराधों में लिप्त रहते हैं और हम उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे में जो भी कुत्ता किसी नेता के यहाँ हो, वह वहाँ से गुलामी की बेड़ियाँ तोड़े किसी वेश्या का कुत्ता हो जाना मंजूर है, पर नेताओं से बचना होगा। यह हमारी कुल की मर्यादा का प्रश्न है।

सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को मान लिया गया। सन् 2002 में गुजरात में जो कुछ घटा, उसकी स्मृति एक कुत्ते ने भावुक होकर सुनाई। उसने कहा– ''मैं गुजरात की घटनाओं को सुनने के बाद व्यथित होकर वहाँ पहुँचा। राह में देखा एक बड़े कुत्ते ने 18–20 छोटे कुत्तों को काटकर भयानक रूप से जख्मी कर दिया है। इस दृश्य को देखकर मैंने उस जालिम कुत्ते से पूछा :–

अपनी ही नस्लों पर इस कदर और इतना जुल्म।
कहाँ से तुमने ऐसी जहनियत सीख ली।

इस पर उस निर्दयी कुत्ते ने कहा –

गलत सोहबत का असर मुझ पर पड़ा कुछ इस कदर।
आदमी के साथ रहकर आदमीयत सीख ली।।

अन्त में सर्वसम्मति से एक ही बड़ा प्रस्ताव वहाँ पारित हुआ– ''हर हाल में कुत्तों को अपना कुत्तापन बचाना होगा। उसे आदमीयत से बचना होगा। अपना स्तर नीचे न गिरे, इसके लिए हर संभव उपाय करना होगा।'' अन्त में इस नारे के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ–

श्वानदेह पायी मगर, फिर भी रहे महान।
संसदीय प्राणी बता, क्या तेरी पहचान।।

-(अश्विनीकुमार, विशेषसम्पादकीय; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 08/05/2005)

343) भ्रष्टाचार है हमारा शत्रु :- जिस देश के रक्षक ही भक्षक बन जाएँ, तो ऐसे देश का क्या बचेगा? जरा सोचें! जिस देश का नागरिक भ्रष्टाचारी हो, वह देश कभी शक्तिशाली नहीं बन सकता। वर्तमान में रिश्वत भी सुविधाशुल्क कहलाती है। भविष्य में नेताओं, अफसरों व सरकारी कर्मचारियों का हित ही जनहित कहलाएगा। भगवान स्वयं हमारे देश में सबकुछ ठीक करने आएँगे? नहीं! कभी नहीं! हमारा सबसे बड़ा आत्मघाती आन्तरिक शत्रु भ्रष्टाचार है, जो अन्ततः हमारे देश को नष्ट कर देगा। क्या अपने ही देशवासियों का शोषण करना, शोषण करवाना, शोषण होते हुए देखना उचित है? अतः ईश्वरभक्ति में नहीं, देशभक्ति में डूबिए। बढ़ते भ्रष्टाचार को स्वीकारते चले जाना देशहित में कदापि नहीं। अपने देश व देशवासियों को भगवानभरोसे मत छोड़ें। आइए मिल-जुलकर हम जातिभेद और धर्मभेद की सभी दीवारों को तोड़ दें। जाति से हम इंसान बनें। इंसानों की सेवा करना ही अपना धर्म बना लें। आइए! भ्रष्टाचारमुक्त आदर्श भारत के निर्माण हेतु हम सभी मिल-जुलकर प्रयासरत हों।

-(विजयकुमार अग्रवाल, जालंधरी सराय, बदायूँ; आवाज-ए-खबरदार, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 03/05/2005)

344) घरेलू हिंसा :- 31 साल की गोमती कुछ ही दिनों पहले अपने गाँव मौड़म से पिथौरागढ़ के निराश्रित आश्रम में आई। उसकी 7 और 4 साल की दो नन्हीं बेटियाँ भी उसके साथ हैं। पति ने पहले तो पैर काट दिया और जब वह किसी काम की नहीं रह गई, तब सास ने घर से निकाल दिया। गोमती और उसकी बेटियों के लिए अब इस आश्रम का ही सहारा रह गया है। उसकी दो नन्हीं बेटियाँ बेबसी से अपनी माँ की ओर देखती हैं और फफक-फफक कर रो रही गोमती को चुप कराने का असफल प्रयास करती हैं। गोमती ने बताया कि उसका पति खूब चरस और शराब पीता था। एक दिन रोज की तरह मार-पीट की और फिर गुस्से में कुल्हाड़ी से पैर काट दिया। गाँव के कुछ लोगों ने मिलकर उसका इलाज करवाया। तीन महीने का लम्बा दर्दनाक समय उसने अस्पताल में बिताया। इस दौरान उसका कोई अपना उसके साथ नहीं था। गोमती की शादी को 14–15 साल हो गए हैं। मारना-पीटना तो हमेशा चला पर तीन बेटियों की माँ होना उसके लिए सबसे बड़ी सजा थी। वह बताती है कि मेरा कोई बेटा नहीं है, इसलिए मेरी सास ने मुझे खाना देना बन्द कर दिया। गोमती की 11 साल की सबसे बड़ी बेटी आज अपनी दादी के साथ है।

इस बारे में जब एक बुजुर्ग महिला से बात की तो वह हामी भरते हुए बोली कि ''हाँ-हाँ हमारे

समय में भी ये होता था। हर घर में औरत मार खाती थी और ये कोई बड़ी बात भी नहीं थी। ज्यादातर घरों में मार-पीटकर घरों से निकाल दिया जाता था।'' उत्तरांचल में रोजाना घर, खेत और जंगल में पिसने वाली औरत का कोई महत्त्व नहीं है। इन महिलाओं के नाम पर कोई जमीन या सम्पत्ति नहीं होती। समाज में नाते-रिश्ते भी आर्थिक और सामाजिक रूप से बँधे हैं। एक अन्य औरत कुन्ती आज करीब 47 साल की है और पिथौरागढ़ का निराश्रित आश्रम ही अब उसका सबकुछ है। वह मानसिक रूप से बीमार है। किसी ने गाँव में उसके साथ बलात्कार किया था। उसके बाद उसके पति ने उसे छोड़ दिया। कुन्ती जैसी औरतों को इन आश्रमों में खाना और रहने के लिए छत तो मिल भी जाती है, लेकिन उस जैसी सैकड़ों गरीब परित्यक्ता औरतें उत्तरांचल की सड़कों पर मिल जाएँगी, जिनके साथ यौनशोषण से लेकर मानसिक शोषण भी होता रहता है।

महिलाओं के प्रति हिंसा और उन्हें घर से निकालने के जिम्मेदार लोगों के पास कई बहाने हैं। कई बार महिलाओं को चरित्रहीन करार दिया जाता है, तो कई बार चोरी के इल्जाम में फँसा दिया जाता है। कईयों को उनके पति ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह बेटे को जन्म नहीं दे सकीं, तो कुछ गाड़ियाँ भर दहेज नहीं ला पायीं।

अस्कोट इलाके में औरत के हक के लिए काम करने वाली संस्था अर्पण की रेणु ठाकुर बताती हैं कि उत्तरांचल में पत्नी छोड़ने के मामले दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं। वह कहती हैं कि लगातार मारपीट करने के बाद भी यदि पत्नी घर छोड़ने को तैयार नहीं होती है, तो करेंट लगाकर या संगीन मामलों में फँसाकर उसे प्रताड़ित किया जाता है। रेणु ठाकुर इसकी प्रमुख वजह अशिक्षा को मानती हैं। उनके मुताबिक उत्तरांचल में महिला साक्षरता दर में कोइ इजाफा नहीं हुआ है। यदि कहीं लड़कियाँ पढ़ भी रही हैं, तो वह शिक्षा भी उन्हें अत्याचार से मुकाबला करने को तैयार नहीं कर पाती। वह बताती हैं कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए बना महिला आयोग और पुलिस किसी पीड़िता को न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है। जिसके चलते तमाम महिला संगठनों के हाथ बँधे हैं। ऐसे में ये महिलाएँ लगातार टूट रही हैं।

-(कात्यायनी उप्रेती, आँखिनदेखी; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 03/05/2005)

345) नारी तेरी यही कहानी : दिल में दर्द आँख में पानी :- *भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार जिस हिंसा को अपराध कहा जाता है, उससे भी कहीं भयानक अपमान एवं कष्टदायक हिंसा का शिकार महिलाओं को होना पड़ता है और कानून की किसी भी किताब में उस हिंसा के लिए दण्ड का प्रावधान नहीं है। कटुसत्य तो यह है कि इस पीड़ादायक कृत्य को हिंसा माना ही नहीं जाता, बल्कि उस पर समाज और धर्म-सम्प्रदाय की मोहर लगी रहती है। पीड़ाभोगी भी बेबस बनी यह जानती ही नहीं कि इससे छुटकारा मिल सकता है।*

गरीब की बेटी योग्य वर पाने की कल्पना ही नहीं कर सकती। उसके पिता की पगड़ी न जाने कितने दरवाजों से ठुकरायी जाती है और थैले-थैलियों की शादी होती है और उसके बाद की सच्चाई यह है कि देश में प्रतिवर्ष लाखों विवाहित महिलाएँ आत्महत्याएँ करती हैं, दहेज की खातिर हत्याएँ होती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तान की अधिकतर औरतें आज भी गुलाम हैं। यूँ कहिए कि गुलामी की मानसिकता बन चुकी है। प्रसिद्ध विद्वान डुमण्ड ने कहा है- ''जो तर्क नहीं कर सकता, वह मूर्ख है। जो तर्क नहीं सुन सकता, वह असहिष्णु है और जिसे तर्क करने की आजादी नहीं, वह गुलाम है।'' मेरा सीधा प्रश्न है कि हमारे देश की कितनी महिलाओं को तर्क करने का अधिकार है। परिवार में पत्नी को पीटने वाले ज्यादा पुरुष उसका यही दोष बताते हैं कि यह मेरे सामने, बड़ों के सामने जुबान चलाती है। सीधा अर्थ है- तर्क करने का साहस करती है।

मेरा निश्चित मत है कि सही शिक्षा मिले बिना महिलाओं की आँखों में पानी की कहानी छोटी होने वाली नहीं है और भारत की आधे से ज्यादा महिलाएँ निरक्षर हैं। छोटे-छोटे बच्चे-बच्चियाँ स्कूलों से दूर हैं। भारतसरकार एवं सभी प्रान्तीय सरकारों को यह नियम बनाना और कठोरता से लागू करना होगा कि हर बच्चे को शिक्षा अवश्य मिले। निश्चित ही इसके बाद बहुत से बच्चे अपनी राह स्वयं बना लेंगे। गरीब बच्चों के भोजन एवं शिक्षाकोष की व्यवस्था सरकारी कोष से ही होनी चाहिए। किसी भी धर्मगुरु को महिलाओं के प्रति अपमानजनक शब्द कहने या उन्हें किसी धर्मस्थान में प्रवेश करने से रोकने की आज्ञा क्यों दी जाए? पाठ तो यह सुनाया-पढ़ाया जाता है कि एक नूर से ही सारे जीव पैदा हुए हैं, या सभी कुदरत के बन्दे हैं, या सभी जीव आत्मवत समझे जाएँ। परन्तु बेटे और बेटी में उन्हें एक जीव दिखाई नहीं देता।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और अपराध अथाह हैं। पर इसके विरुद्ध मोर्चा भी महिलाओं को ही लगाना होगा। याद रखिए– 'गजानां पंकमग्नानां गजा एव धुरन्धरः।' अर्थात् दलदल में फँसे हुए हाथी को निकालने का कार्य हाथी ही कर सकते हैं। **–(लक्ष्मीकान्ता चावला, स्तम्भकार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 04/05/2005)**

346) EDUCATION IS OUR BIRTHRIGHT :- *Unduobtedly India has made tremendous progress since it atained Independence in 1947. But illiteracy in India has become a curse. 35% of world's illiterates are Indians. Out of every 30 people in the world, 3 are Indians and of these 3, 2 are illiterate. This literacy rate in our country comes down to 64%, in which 56% are men and 76% are women. Thus India will enter the 21st century with more than half the population illiterate. In a nutshel illiteracy is a curse. The illiterates have to depend on others for most of the things in life. They can easily be befooled, cheated and discriminated. Being illiterate they are deprived of getting any benifits of many schemes. So awake arise and get going the removal of illiteracy from this holy land of our's.*

–(Jeevan Singh, 11-C, Young World, The Hindu, 10/02/2006)

347) BOUNDARIES IN OUR MINDS? :- *'Kenichi Ohmae' in his book 'Beyond national Borders' has written— "Political boundaries are virtually meaningless today. In our new economic system, cooperation and interdependence, not conflict and independence, are prerequisites for survival."*

This thought compels us to think— 'should national boundaries matter?' For years we have based our beliefs, our positions, our values on the country of our birth and / or our residence. Political boundaries have dramatically influenced our lives. Trade and all sorts of economic issues are governed by international borders, as are lifestyles and opportunities for human rights and human fulfilment.

The early man must have made boundaries to prevent trespassing and encroachment. As man became more civilised and advanced, he started dividing areas to show his supremacy and power. Thus, nations were born. These national boundaries were meant to foster external peace and internal unity.

But, sadly enough in recent times, these political boundaries have become more of a 'people divider' than a medium to differentiate between economies. The nations of the world spend most of their energy, money and emotional strength in quarrelling with words and weapons. Hatred, violence, cross-border terrorism, infiltration, environmental pollution are common phenomena. A true offensive against the common problems that threaten human survival remains a secondary issue.

We have learned to fly in the air like birds and swim the sea like fish, but have not learned the simple art of living together, as brothers. It must be noted that national boundaries are artificially established and can change after wars, civil conflict or natural calamities. The recent earthquake in Kashmir made headlines— 'Line of Control breaks. Indian soldiers cross over to save Pak troops. Perhaps it took an earthquake and the consequent tragedy to find redemption in Kashmir. This proved that even nature does not like borders. There are no boundaries on the real planet Earth. No United States, no Russia, no India, no China. Rivers flow uninterrupted across the swaths of continents. The tides of the sea, do not discriminate. They push against the varied shores on Earth.

John David, an astronaut has rightfully remarked — 'As I looked down from the moon, I saw a large river meandering slowly along for miles, passing from one country to another, without stopping. I also saw huge forests, extending along several borders. And I watched the extent of one ocean touch the shores of separate continents. Two words leaped to mind as I looked on all this: commonality and interdependence. We are one world.'

In recent times, it is visible that national boundaries are making little economic sense. Regions have become primary actors in the global division: rich regions, poor regions, communing and competing with each other even within national lines. We should learn to look beyond manmade boundaries and prejudices. The love of one's country is a splendid thing but why should it stop at the border?

The world needs to be interconnected not only on the material level of economics, trade, communication and transportation, but interconnected through human consciousness, through the human heart and through the heart of the world.

–(Elly Varma, XI, Young World, The Hindu, 10/02/2006)

348) दुनियाभर में प्रेस स्वतन्त्रता दौर जारी :- दुनियाभर के पत्रकारों के लिए काम करने वाले संगठन 'रिपोर्टर विदआउट बार्डर' (आर.डब्ल्यू.बी.) ने कहा है– ''साल दर साल पत्रकारों के सामने खतरे बढ़ते जा रहे हैं और 2004 भी उनके लिए खतरों से भरा साल रहा, जिस दौरान 53 पत्रकार काम के दौरान अपनी जान गवाँ बैठे और अभी भी चीन पत्रकारों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी जेल है। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस के मौके पर जारी की गई अपनी 2004 की सालाना रिपोर्ट में संगठन ने कहा है कि प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए यह कठिन दौर है। दुनियाभर में उस पर हमले किए जा रहे हैं। उसे कुचला जा रहा है। उसकी उपेक्षा की जा रही है। संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईराक लगातार दूसरे साल पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक जगह रही है और 2004 में वहाँ कुल 19 पत्रकार मारे गए और एक दर्जन से अधिक का अपहरण कर लिया गया है। इसके अलावा 16 पत्रकार एशिया में मारे गए। अफ्रीका और अमरीका के कुछ हिस्सों में भी पत्रकारों को शारीरिक नुकसान पहुँचा है। रिपोर्ट के अनुसार 2004 में कम से कम 907 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 1146 पर हमला किया गया। इसके अलावा इस साल 622 मीडिया संस्थानों को सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। संगठन ने आरोप लगाया है कि उत्तरकोरिया, तुर्कमेनिस्तान और इरीट्रिया में प्रेस स्वतन्त्रता का सबसे अधिक उल्लंघन होता है। ईराक के बाद फिलीपीन्स और बांग्लादेश को पत्रकारों के लिए सबसे दुरूह जगह बताया गया है। उत्तरकोरिया में कोई मान्यताप्राप्त पत्रकारिता ही नहीं है। **-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 04/05/2005)**

349) पारस्परिक सद्भाव को मजबूत बनाना होगा :- गरीबों, दलितों एवं असहाय वर्ग की सेवा करके हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं और इसके लिए हमें समाज के सभी वर्गों में बन्धुत्व, समरसता और पारस्परिक सद्भाव को और भी मजबूत बनाना है। हमें जाति, क्षेत्र, धर्म एवं सम्प्रदाय से ऊपर उठकर मानवकल्याण के लिए एकजुट होकर कार्य करना है और समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए जनसहयोग से कार्य करना है। इस संसार में जो व्यक्ति जन्म लेता है, उसे एक दिन मृत्यु का वरण भी करना होता है। लेकिन मानवजीवन में हमें ऐसे कार्यों को करना चाहिए, जिससे मृत्यु के पश्चात भी समाज उस व्यक्ति को हमेशा अपना आदर्श माने।

-(मुख्यमन्त्री नारायणदत्त तिवारी; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 01/05/2005)

350) ये विडम्बना नहीं तो और क्या है, जिन लोगों के ढोल बजाए बिना भगवान शिव की पूजा आरम्भ नहीं होती, खुद वे ही लोग भारत जैसे लोकतन्त्र में आज भी मन्दिरों में प्रवेश करने के अधिकार से वंचित हैं। ये स्थिति उस पश्चिम बंगाल राज्य के एक गाँव में है, जहाँ पिछले अठ्ठाइस सालों से वामपंथियों की सरकार है। भले ही ये कहा जाता हो कि भारत में छुआ-छूत के खिलाफ कार्यवाही होती है, लेकिन इस गाँव में छुआ-छूत के खिलाफ न तो सरकार ने और न ही किसी और ने कार्यवाही करना तो दूर आवाज तक नहीं उठाई है। जिन लोगों के साथ यह छुआ-छूत का भेद होता है, वे यहाँ की एक जनजाति 'रूईदास' से ताल्लुक रखते हैं। जब मन्दिर में शिवलिंग की पूजा होती है, तो उनको मन्दिर में जाने और भगवान शिव के दर्शन करने का अधिकार नहीं होता है। इस प्राचीन और विचित्र परम्परा के खिलाफ गाँव में कोई भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता। क्योंकि यदि कोई आवाज बुलन्द करने का प्रयास करेगा, तो उसे गाँव से भी निकाला जा सकता है। इस परम्परा के शिकार यहाँ के निवासी बाबू ने बताया– ''कुछ साल पहले हम लोगों ने यह फैसला किया था कि जब हमें मन्दिर में प्रवेश करने की ही अनुमति नहीं है, तो फिर हम पूजा के समय ढोल भी नहीं बजाएँगे। लेकिन गाँव की ऊँची जाति के लोगों ने हमें गाँव से निकालने की धमकी दी, जिससे हमें मजबूरन ढोल बजाना पड़ा और अब तक ऐसे ही बजाते चले आ रहे हैं।'' इसी जाति के रामू ने बताया कि उन्होंने गुप्तरूप से गाँव की इस भेदभाववादी व्यवस्था की शिकायत कई बार पुलिस और सरकार से भी की है। लेकिन सब लोग हमारी बातों पर अपने कान बन्द कर लेते हैं। रामू ने ये भी कहा कि भगवान के दर्शन का अधिकार तो सबको होता है, तो फिर हमारे साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों ? **-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 01/05/2005)**

351) *विश्वस्तर पर बदलते परिवेश की चुनौतियों से निपटने तथा विकास गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए छह दशक पुरानी इस विश्वसंस्था 'संयुक्तराष्ट्रसंघ' के नियमों में व्यापक परिवर्तन किया जाना चाहिए। आज सामूहिक सुरक्षा को बढ़ाने, वैश्विक विकास के लिए व्यापक स्तर पर व्यावहारिक नीति बनाने, लोकतन्त्र और मानवाधिकार को बढ़ावा देने और उन्हें प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किए जाने की जरूरत है। बदलाव का यह उचित समय है क्योंकि आज संगठित अपराध बढ़े हैं, ऐड्स जैसे खतरनाक रोग मुँह बाए खड़े हैं, आतंकवादी युवापीढ़ी को गुमराह करने पर तुले हैं और जैवतकनीकी विकास के दुरुपयोग की बढ़ी संभावनाओं के साथ ही न्याय के प्रति लोगों का जिसप्रकार रुझान घटा है, उन चुनौतियों से निपटने के लिए छह दशक पुराने विश्वसंगठन में परिवर्तन अनिवार्य हो गया है। नागरिक अधिकारों की रक्षा करने तथा दुनिया से गरीबी हटाने के लिए संयुक्तराष्ट्रसंघ को और मजबूत बनाये जाने की जरूरत है।*

-(कोफी अन्नान, महासचिव, संयुक्तराष्ट्रसंघ; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 28/04/2005)

352) किसानों ने आस्तीनें चढ़ाईं : बिग 'बी' ने कैसे खरीदी कौड़ियों के भाव खेती की जमीन :- *महाराष्ट्र के लोनावाला के निकट पवन डैम के साथ लगते पोलगाँव में शताब्दी के फिल्मी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन द्वारा खरीदी गई कृषिभूमि को लेकर तूफान उठ खड़ा हुआ है। स्थानीय किसानों ने भी अपनी आस्तीनें चढ़ानी शुरु कर दीं। इस मामले में मावल तालुका के उप मण्डल मजिस्ट्रेट जाँच शुरु कर दी कि अमिताभ इस कृषिभूमि के मालिक कैसे बने? अँग्रेजी पत्रिका आउटलुक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अमिताभ को दी गई कृषिभूमि है, लेकिन श्री बच्चन और उनके परिवार का खेतीबाड़ी से दूर का भी रिश्ता नहीं है। अगर जाँच में कोई बाधाएँ उत्पन्न नहीं की गईं और यह निष्कर्ष निकला कि इस कृषिभूमि का हस्तांतरण गैरकिसान परिवार को किया गया है, तो इस भूमि को जब्त कर लिया जाएगा और इस सौदे को अवैध करार दिया जाएगा। सरकार ने भूअधिग्रहण कानून 1894 के तहत इस भूमि को कब्जे में लिया और इसकी एवज में सरकार ने भूमि से बेदखल होने वाले 1203 परिवारों को आवास, पुनर्वास और प्रत्येक परिवार को मुआवजे के रूप में 4 एकड़ भूमि देने का वायदा किया था। किन्तु आज लगभग 863 परिवार वहाँ भूमिहीन हैं और तब से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। सामाजिक कार्यकर्ता डाक्टर बाबा आघव ने आरोप लगाया है कि किसानों को भूमिहीन बनाने और मुम्बई के मगरमच्छों को भूमि हड़पवाने के पीछे सरकार की और राजनीतिज्ञों की पूरी भागीदारी है।*

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 26/04/2005)

353) *'हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हैं भाई-भाई' का नारा भी समानान्तरता निर्माण करने की प्रक्रिया में से ही बना है। यह किसी व्यक्ति को दर्पण के सामने खड़ा करके उसे ही उसका प्रतिद्वन्द्वी एवं समानान्तर व्यक्तित्व बना देने जैसी बात है। लोकसभा में हरिजनों पर अत्याचार की समस्या पर कई बार बहस चली। हिन्दू-मुस्लिम दंगों पर साम्प्रदायिकता के कारण उत्पन्न होने वाले तनावों पर समय-समय पर बहस होती रहती है। बहस कराने के लिए सांसद किसी भी सीमा तक चले जाते हैं और वक्ता जो कुछ बोलते हैं, उसमें समाज को जोड़ने की संवेदना एवं स्वर नहीं होता। राजनीति और राजनीतिक नेतृत्व सामाजिक पीड़ा को भुलाकर अपना एक अलग समाज तथा संसार बनाने में व्यस्त है। उस समाज या संसार में मनुष्य कहीं नहीं है। वहाँ है केवल चुनावी हार-जीत का हिसाब, केवल सत्तास्वार्थ।*

सामाजिक न्याय से जुड़ी समस्याओं का समाधान क्षितिज की छत छू लेने और पाताल की सैर करने में तो नहीं, बल्कि धरती के सत्य का साक्षात्कार करने में है और धरती का सत्य सामाजिक समानान्तरता नहीं, विविधता में एकता, अपनापन एवं दायित्वबोध से रचा-बसा एकमन और एकप्राण सामाजिक जीवन से। यह कार्य विज्ञान तथा भौतिक विकास से नहीं होगा, भावनात्मक सम्बन्धों की स्थापना से होगा। समाज की भावना को भ्रष्ट करके सामाजिक न्याय प्रदान और प्राप्त करने की मुहिम को केवल छल, कपट, कुटिलता और क्रूरता की ही श्रेणी में रखा जा सकता है। यह मनुष्य के जीवनधर्म के विरुद्ध है। अवसरवादी बहस और चर्चाएँ इस कलंक को मिटाती नहीं, केवल शत्रुता एवं सामाजिक समानान्तरता प्रदान करके इसे स्थायित्व प्रदान करती हैं।

-(भानुप्रतापशुक्ल, स्तम्भकार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 25/04/2005)

354) संसद से मतलब नहीं सांसद को : साल में सिर्फ 73 दिन चलती है संसद :- *अगर पिछले पाँच वर्षों के सदन चलने के औसत दिन पर नजर दौड़ाई जाए, तो यह गिनती महज 73 दिन के आसपास ठहरती है। यानि साल भर के 365 दिनों में आम जनता की चिन्ताओं और उनकी बेहतरी की योजनाओं को लेकर हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि साल भर में मात्र 73 दिन संसद में बैठते हैं। उसमें भी कोई गारण्टी नहीं कि संसद का काम-काज सुचारू रूप से चलेगा। सन् 1998-1999 तक चलने वाली 12वीं लोकसभा मात्र 88 दफे बैठी। सन् 1999 से 2004 की 13वीं लोकसभा में कुल 356 बैठकें हुईं। जबकि 14वीं लोकसभा बजटसत्र के पहले चरण तक 68 दफे बैठ पायी है। ऊपरी सदन राज्यसभा का हाल भी लोकसभा से मिलता-जुलता है। सन् 1998-99 में 82 बैठकें, सन् 1999 से 2004 के बीच 351 बैठकें और मौजूदा सत्र के पहले बजट सत्र तक 66 बैठकें हो चुकी हैं।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 26/04/2005)***

355) शिक्षा के आधारभूत ढाँचे में एकरूपता की आवश्यकता :- *शिक्षा पर जब कोई शिक्षाविद, नेता या अधिकारी भाषण देता है, तो उसके मुख से प्रायः ये वाक्य अवश्य निकलते हैं- शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है; शिक्षाप्रणाली बिगड़ रही है, इसमें सुधार की आवश्यकता है; शिक्षा का स्तर गिर रहा है, इसमें नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है; शिक्षा रोजगारपरक नहीं है; शिक्षा में व्यापक सुधार की आवश्यकता है आदि आदि। सवाल यह है कि यह काम करेगा कौन? यह काम होगा कैसे? कब होगा? कितना अटपटा लगता है जब सत्तासीन वे लोग ही 'चाहिए' वाली भाषा का प्रयोग करते हैं, जिनके हाथों में शिक्षा की बागडोर है, जिन्होंने शैक्षिक उन्नयन का जिम्मा लिया है। किन्तु यह होना चाहिए, वह होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बस इसी में समय बीतता जा रहा है। जो कुछ होना चाहिए, हम उसे कहने मात्र से काम चला रहे हैं, परन्तु इसके सहारे ज्यादा दिन काम चलेगा नहीं। वस्तुतः शिक्षा में उत्थान, विकास, सुधार या उन्नयन की बात करना तब तक बेमानी है, जब तक इसके आधारभूत ढाँचे में एकरूपता नहीं आती।* ***-(महेन्द्रपाल काम्बोज; भास्करदर्शन, सहारनपुर, 29/04/2005)***

356) पुलिस वालों ने दुकानदार को पीटकर जख्मी किया :- *रुद्रपुर, अटरियादेवी के मेले में शान्ति व सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन द्वारा पुलिसबल को तैनात किया गया है। बीती रात कुछ पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत्त होकर मेले में ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान उनसे शहर के मुहल्ला रमपुरा निवासी एक प्रसादविक्रेता से टक्कर हो गई। पुलिसकर्मियों ने उससे गाली-गलौज की। जब उसने विरोध किया, तो पुलिसवालों ने उसे डण्डों से जमकर पिटाई कर दी। घटना के समय मेले में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। बड़ी संख्या में लोग इधर-उधर भागने लगे। बाद में कुछ लोगों ने मौके पर पहुँचकर पुलिसकर्मियों को समझाकर मामला शान्त कराया। बताया गया कि ड्यूटी में लगे कुछ पुलिसकर्मी दुकानदारों से सुविधाशुल्क की माँग करते हैं। जो दुकानदार सुविधाशुल्क देने में असमर्थता जताता है, उसे बेइज्जत किया जाता है।*

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 26/04/2005)

357) बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के पैतृक आवास और रिश्तेदारों के घरों पर छापे :- *बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली सांसद मुहम्मद शहाबुद्दीन और उनके रिश्तेदार के सीवान जिला स्थित पैतृक गाँव प्रतापपुर से पुलिस ने आज अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया। जिलाधिकारी श्री अनिल ने बताया कि आज प्रतापपुर में छापेमारी की गई, जिसमें सांसद के घर से रात के अँधेर में दूर तक देखने वाला एक यन्त्र, एक वाकी-टाकी, विभिन्न हथियारों के बड़ी संख्या में कारतूस, एक एस.एल.आर., दो राइफलें हथियारों को सुरक्षित ले जाने के लिए बैग, एक हिरण, एक हिरण की खाल, एक शेर की खाल, एक लूटी गई मोटरसाइकिल तथा एक टाटा सूमो बरामद की गई।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 25/04/2005)***

358) महिला की पत्थर मार-मार कर हत्या :- *अफगानिस्तान में एक महिला को अदालती आदेश के तहत परगमन का दोषी पाते हुए पत्थर मार-मार कर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस के अनुसार अदालत ने 29 वर्षीय विवाहिता अमीना को दूसरे पुरुष से सम्बन्ध रखने का दोषी पाते हुए गुरुवार को यह सजा सुनाई गई। प्रान्तीय पुलिस प्रमुख जनरल शाहजहाँ नूरी ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पत्थर*

मार-मार कर उसकी हत्या कर दी गई। अमीना को स्थानीय अधिकारियों एवं उसके पति ने उसके अभिभावक के घर से घसीटकर बाहर निकाला और उसके पति तथा स्थानीय अधिकारियों ने पत्थर मार-मार कर मौत की नींद सुला दिया। अमीना का जिस पुरुष से सम्बन्ध था, उसे सौ कोड़े मारकर छोड़ दिया गया। इस मुस्लिम देश में परगमन प्रतिबन्धित है और शरियत कानून के तहत इसके लिए दोषी पाये गए व्यक्तियों को कोड़े से पीटने से लेकर पत्थर मार-मार कर मौत की सजा तक दी जाती है।

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 25/04/2005)

359) मुलायम ने रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने की वकालत की :- *समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तरप्रदेश के मुख्यमन्त्री मुलायम सिंह यादव ने रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने की आज जबरदस्त वकालत करते हुए कहा कि उनकी पार्टी आने वाले दिनों में इसके लिए व्यापक संघर्ष शुरु करेगी। मुलायम आज अपनी पार्टी के तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के आखिरी दिन खुला सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि रोजगार को मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ महिलाओं को समानता का अधिकार भी प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को हमेशा से बदनाम करने की साजिश की गई है, क्योंकि उनकी पाटी किसानों, गरीबों, मजदूरों और अल्पसंख्यकों के हितों के लिए हमेशा आगे रहती है और सामन्तवादी तथा साम्प्रदायिक ताकतें इस देश में समाजवाद को पनपने नहीं देना चाहतीं। लेकिन उनकी पार्टी का कारवाँ रुकने वाला नहीं है। यह आगे बढ़ता ही रहेगा।*

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 24/04/2005)

360) बेटे के लौटने पर माँ हत्या के आरोपों से बरी :- *अपने 10 साल के बेटे की हत्या करने के अरोप में दूसरे पति के साथ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रही एक महिला को अदालत ने उसके बेटे के लौटने के बाद आरोपों से मुक्त करते हुए रिहा कर दिया। शेरपुर जिले की कमालाखातून तथा उसके दूसरे पति मिजानूर को पहले पति से पैदा हुए बेटे फारुख की 8 साल पहले हत्या करने तथा लाश को छिपाने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसने अदालत में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का पुरजोर विरोध किया, लेकिन उसके पहले पति जुलहास मियाँ द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों के कारण मामला हार गई। 28 मार्च, 1997 को शेरपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कमाला तथा मिजानूर को दोषी पाते हुए उन्हें सींखचों के पीछे डाल दिया था। लेकिन हाल ही में फारुख शेरपुर लौटा और अपनी माँ से मिलने के लिए जेल गया। वह अब 18 साल का हो चुका है। जेल में उसने पुलिस को बताया कि उसके पिता जुलहास मियाँ ने दूसरी शादी करने के कारण उसकी माँ से बदला लेने के लिए उससे गायब होने को कहा था।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 20/04/2005)***

361) भगवान महावीर के सिद्धान्तों की प्रासंगिकता :- *भगवान महावीर को महान लोकनायक, धर्मनायक, क्रान्तिकारी चिन्तक, सच्चे पथप्रदर्शक, प्राणियों के परमहित चिन्तक के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने साधना, संयम, तप एवं निष्ठा के बल पर मानवसमाज के साथ-साथ पशुओं तक को भी अहिंसा तथा प्रेम सिखाकर उनकी क्रूर और हिंसक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया था। वैशाली (बिहार) के कुण्डग्राम में राजा सिद्धार्थ एवं उनकी रानी त्रिशला ने अब से 2604 वर्ष पूर्व चैत्रशुक्लत्रयोदशी को वर्धमान महावीर को जन्म दिया। उस समय वर्गभेद, विषम आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति, दास-दासियों के रूप में स्त्री-पुरुषों का क्रय-विक्रय, धर्म के नाम पर पशुबलि आदि का वातावरण व्याप्त था, जिसने युवा वर्धमान को झिंझोड़ दिया। 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्यज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान महावीर ने दलित और नारी समाज को पुरुष के बराबर सभी अधिकार दिलाने की क्रान्तिकारी बात कही। उन्होंने कभी किसी का विरोध नहीं किया।*

-(नरेशचन्द्रजैन, आशियाना इस्पातसमूह; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 22/04/2005)

362) दो जून की रोटी के लिए आँख बेचने का विज्ञापन :- *पेट की आग क्या-क्या न कराए? बांग्लादेश की एक परित्यक्त महिला ने गरीबी से तंग आकर अपनी एक आँख ही बेचने की घोषणा कर दी है, ताकि इससे मिले पैसों से अपने लिए और अपनी ढाई वर्षीय बेटी के लिए दो जून का खाना जुटा सके। ढाका की एक झुग्गी बस्ती में रहने वाली 26 वर्षीया शैफाली बेगम ने बताया कि पति ने मुझे छोड़ दिया है। मैंने नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें खाईं, पर नहीं मिली। तब मैंने अपनी एक आँख बेचने का फैसला किया। आँख बेचने के फैसले को सही ठहराने के लिए उसका तर्क है कि मैं दो आँखें रखकर ही क्या करूँगी, जबकि मेरी बेटी दूध और भोजन के बिना तड़प-तड़प कर मर जाएगी। अभी तक बांग्लादेश में पैसे के लिए गुर्दा, यकृत बेचने की घटना तो सामने आयी है, पर अब तो एक महिला ने आँख बेचने की भी घोषणा कर दी है। इसके लिए शैफाली बेगम ने बाकायदा अखबार में विज्ञापन दिया है। उसका कहना है कि आँख बेचने से इतने पैसे तो आ ही जाएँगे, जिससे वह कुछ खिलौने खरीदकर सड़कों, गलियों में बेचने का कारोबार शुरु कर सके। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश की आधी से ज्यादा आबादी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रही है।*

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 23/04/2005)

363) डांसबार पर पाबंदी :- *जितने बेईमान सिद्धान्तहीन लोग मुझे राजनीतिक गलियारों में मिले हैं, किसी और पेशे में नहीं दिखे हैं। अतः जब कोई राजनेता, कोई मन्त्री हमको नैतिकता, धर्म, ईमान सिखाने लगता है, तो मुझे सख्त गुस्सा आता है और जब नैतिकता के नाम पर वह उन लोगों की रोजी-रोटी को लात मारने की कोशिश करता है, जो अपना खून-पसीना बहाकर कमा रहे होते हैं, तो मेरा गुस्सा और बढ़ता है। एक डांसबार के मालिक ने बताया कि मुम्बई की बारबालाओं के बारे में अखबारों में जो छप रहा है, उनके जीवन, उनकी कमाई के बारे में, वह बिल्कुल गलत है। ज्यादातर लड़कियाँ गरीब से गरीब परिवारों की हैं और उनकी मजबूरियाँ उनको यहाँ लाती हैं। कई तो इतनी गरीब होती हैं कि उनके कपड़े भी हम बनवा कर देते हैं। हर लड़की की कहानी इतनी दुःखभरी है कि आपको सुनकर रोना आएगा। कई ऐसी हैं, जिनके पति ने उनको छोड़ दिया है और कोई जो किसी मर्द के शोषण का शिकार है। थोड़ा बहुत जो यहाँ कमाती हैं, उस पर पूरे परिवार का गुजारा होता है। हजारों में नहीं कमा रही हैं। आप जाकर देखें वे रहती कैसे हैं। दस-पन्द्रह लड़कियाँ एक छोटे से कमरे में रहती हैं। यदि हजारों में कमा रही होतीं, तो क्या ऐसे ही रहतीं? बार में एक हाल का तकरीबन 50 हजार रुपये महीना अफसरों और पुलिसवालों को बारमालिक अदा करता है- उनका हफ्ता। चाहे ग्राहक आए या न आए, हफ्ता अदायगी अनिवार्य है। डांसरूम जहाँ दस-पाँच सजी-धजी लड़कियाँ थीं। कोई अपने माँ-बाप के लिए, कोई अपने भाई-बहन के लिए, कोई बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जी रही हैं। उनका कहना है- ''बार बन्द हो जाएगा, तो हम कहाँ जाएँगे?'' दुःख की बात तो यह है कि महाराष्ट्र की सरकार न इन बालिकाओं के भविष्य के बारे में सोच रही है और न ही वह इस तरह के सभी धन्धों को खत्म करने जा रही है, जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा हैं। डांसबार उस मुजरा और लावनी का आधुनिक रूप है। क्या अब लावनी नृत्य पर भी पाबन्दी लगाएँगे? डांसबारों पर पाबन्दी लगाना निहायत ही बेवकूफ कदम है।* ***-(तवलीन सिंह, स्तम्भकार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 23/04/2005)***

364) राष्ट्रपति के नाम एक खुला पत्र :- *महामहिम, देश की दुर्दशा पर संभवतः आप भी उतने ही चिन्तित होंगे, जितना इस देश में जन्म लेने वाला हर देशभक्त भारतीय। इस देश व देशवासियों के उज्ज्वल भविष्य, उन्नति, देश की एकता-अखण्डता, गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार जातिवाद के प्रति आप भी चिन्तित होंगे। न जाने देश में कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं- गरीबी के कारण। एक समय भोजन करके फुटपाथ पर सोकर वह कैसे अपना जीवनयापन करते हैं। शायद किसी भी नेता को चिन्ता नहीं। देश का लोकतन्त्र लड़खड़ा रहा है। चारों स्तम्भ भ्रष्टाचाररूपी राक्षस से पराजित हो रहे हैं। आज यदि समाचारपत्र और दूरदर्शन का अवलोकन करें, तो पता चलता है कि देश को आजाद कराने वाले, अपनी जान देने वाले शहीदों ने जो स्वप्न सँजोया था, वह केवल स्वप्न ही बनकर रह गया है। देश कहीं फिर गुलाम न हो जाए! देश के तथाकथित रहनुमा-आका भ्रष्टाचार में डूबे पड़े हैं। किसी भी अधिकारी या नेता के घर यदि छापा पड़े, तो करोड़ों-करोड़ों रुपये की चल-अचल सम्पत्ति मिलेगी। दूसरी ओर आधी से ज्यादा आबादी भूखे पेट सोती है। देश में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हजारों रुपये का कर्जदार हो जाता है। आखिर क्या कारण है? ये खद्दरधारी*

नेता जिन पर विश्वास करके जनता इन्हें अपना सांसद–विधायक चुनती है, उसी जनता के खून–पसीने की गाढ़ी कमाई से मौज उड़ाते हैं और कभी जाति के नाम पर कभी धर्म के नाम पर जनता को मूर्ख बनाते हैं। जिसे भी जनता ईमानदार या हितैषी मानती है, कलई खुलने पर वह धूर्त निकलता है। इस देश का बंटाढार करने में इन नेताओं का बड़ा हाथ है। अधिकारी और नेता लूट रहे हैं। नागरिक बेचारा क्या करे? मैं खुला पत्र आपको लिख रहा हूँ, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप जरूर उन गरीब, कमजोर, दुर्बल, सड़क पर रात गुजारने वाले लोगों के हित में और यह कि देश फिर आजादी न खोने पाए, आपसे कुछ आग्रह कर रहा हूँ। भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने से जो धन इकठ्ठा होगा, उससे सारा विदेशी कर्ज अदा हो जाएगा, देश में खुशहाली आएगी। यह देश के खद्दरधारी चोर नहीं चाहेंगे। लेकिन इससे देश का भविष्य सुधरेगा अन्यथा देश के नेता व अधिकारी देश को कंगाल कर देंगे। गरीब आत्महत्या कर लेगा, मध यम वर्ग की कमर टूट जाएगी और देश को विश्वभर में अपमानित होना पड़ेगा। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी कुछ कीजिए, इन खून पीने वाले नेताओं और अधिकारियों का इलाज।

-(डा.सत्येन्द्रकुमारशर्मा, चाँदपुर, बिजनौर; आवाज-ए-अबरदार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 23/04/2005)

365) *राष्ट्रीय सामाजिक न्याय कृति मंच द्वारा आयोजित राष्ट्रीय दलित चिन्तनशिविर में यह बात उभरकर सामने आयी कि सामाजिक न्याय के लिए राजनैतिक दलों के भ्रमजाल से अलग होकर राष्ट्रव्यापी आन्दोलन खड़ा किया जाए तथा संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं सुविधाओं को लागू कराने का दबाव सत्ताधारियों पर बनाया जाए।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 18/04/2005)***

366) *केन्द्रीय रेलमन्त्री लालूप्रसाद यादव का एक भतीजा कृष्णा यादव पटना की एक अदालत द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किए जाने पर फरार बताया जाता है। पुलिस प्रशासन ने उसकी गिरफ्तारी के लिए आज कई स्थानों पर छापेमारी की है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला है। कृष्णा यादव पर स्थानीय व्यापारियों से जबरन धनवसूली का आरोप है। व्यापारिक संघ ने बताया है कि पटना के आशियाना और राजा बाजार के क्षेत्रों के व्यापारी कृष्णा यादव के आतंक से डरे–सहमे से रहते हैं। उल्लेखनीय है कि पुलिस लालूप्रसाद यादव के एक और भतीजे नागेन्द्र राय के ऊपर करीब आधा दर्जन मामले दर्ज कर चुकी है। इन पर पुलिस अधिकारियों को धमकाने और व्यापारियों से जबरन धनउगाही के मामले दर्ज किए गए हैं। बिहार में अब लालूप्रसाद की सरकार नहीं रही। निश्चित रूप से लालू के इन भतीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।*

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 18/04/2005)

367) सूद के पैसे से इमामों को वेतन :- *हमारी कौम के रहनुमा मुल्ला, मौलवी और उलेमा साहेबान हैं। ये हमेशा कुरान, शरियत, हदीस के नाम पर आम बेपढ़े और गरीब मुसलमान को गुमराह करते रहते हैं। सूद के पैसे से इमामों को वेतन ऐसा ही एक शिगूफा है। आज दुनिया में 60 के करीब मुसलमानी मुल्क हैं। क्या आलमी बैंक से कर्जा नहीं लेते? यदि कर्जा लेते हैं, तो क्या उनको सूद नहीं देते? यदि सूद लेना हराम है, तो सूद देना तो उससे भी बड़ा गुनाह है। एक उलेमाओं का ग्रुप फरमाता है कि बैंक में बचत खाते पर जो सूद देते हैं, वह तो हलाल है लेकिन मियादी जमा पर जो सूद देते हैं, वह हराम है। यह दोगलापन क्यों? हिन्दुस्तान में पठानिया ब्याज सबसे बुरा और नापाक मानते हैं। इससे अधिक कड़ा ब्याज तो जर्मनी के यहूदी लिया करते थे। क्या पठानों को हमने इस्लाम से खारिज कर दिया? बम्बई के बोहरे मेमन और शेख बिरादरी के मुसलमान तो धन्धा ही सूद का करते हैं। क्या ये सब खुदा के गुनहगार हैं या काफिर हैं? हमारी ही रकमें जो अमरीका के बैंकों में रहती हैं, उसके ब्याज से ही वे असलहा खरीदते हैं या बनाते हैं। पाकिस्तान जैसे इस्लाम के गद्दार मुल्क को मदद देकर उसका ईमान खरीदते हैं। उसी से अफगानिस्तान, ईराक और ईरान जैसे इस्लाम के बन्दों का कत्लेआम करते हैं। मौलाना साहेबान से गुजारिश है कि वे हमें आज की दुनिया के लायक तालीम दें। हमारी आँखों पर जेहालत की पट्टी मत बाँधें। खुदा गवाह है, जिस इस्लाम के आप जैसे रहबर हों, उन्हें दुश्मन तलाशने की जरूरत नहीं है। कौम का बहुत नुकसान कर चुके हो। अब और मेहरबानियाँ मत बरसाओ।*

-(हाजी सोबुद्दीन हंगल, कोटा, राजस्थान; आवाज-ए-अबरदार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 18/04/2005)

368) कितने शर्म की बात है :- *हमारे देश को आजाद हुए 58 वर्ष हो गए हैं। इससे पहले अँग्रेजों ने जी भरकर लूटा। फिर भिखारी नेता और भ्रष्ट अफसर लूटते आ रहे हैं। यह नेता क्या करते हैं? जनता को मूर्ख बनाना। अपने अहंकार के लिए विधानसभा, संसदभवन जैसे पवित्र जगह पर जूते-चप्पल चलाना, गाली-गलौज करना इन नेताओं का परम कर्तव्य कहलाता है। वाह रे हमारे देश के भाग्यनिर्माता! नेताओं का आत्मसम्मान और नैतिकता खत्म हो चुकी है। अब तो इन नेताओं की वजह से लूट-खसोट, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार हो रहा है। हत्यारे तक नेता की श्रेणी में आ चुके हैं। पतन की पराकाष्ठा कहाँ तक पहुँच चुकी है, यह सारा देश देख रहा है। क्या कोई नेता दावा कर सकता है कि मैं ईमानदार हूँ? नहीं! लेते हैं शपथ देशसेवा की और करते हैं अपने परिवार की सेवा। आरक्षण के नाम पर इन नेताओं में खुली लूट मची हुई है। संविधान कहता है- सब नागरिक समान हैं, तो क्यों महिला आरक्षण? जाति-जनजाति आरक्षण? हत्यारा भ्रष्टाचारी भी सांसद और विधायक बन जाता है। यह हमारे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मुँह पर कितना बड़ा तमाचा है।*

-(विजयनाथ झा, विजय इनक्लेव पालम, नई दिल्ली-४५; आवाज-ए-खबरदार, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 18/04/2005)

369) *लोकतन्त्र सरकार का ऐसा रूप और तरीका है, जिसमें किसी खून-खराबे के बिना जनता के आर्थिक और सामाजिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाए जाते हैं।*

-(डा.भीमराव अम्बेडकर, सरकारी विज्ञापन; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 14/04/2005)

370) काँग्रेस कल्ट की जड़ काटे बिना कल्याण नहीं :- *महात्मा गाँधी की चलती तो काँग्रेस समाप्त हो गई होती। काँग्रेस समाप्त हो गई होती, तो भारत की राजनीति को अनैतिकता, अविश्वास, सत्तालोभ, कुनबापरस्ती (वंशवाद), जातिवाद, सम्प्रदायवाद, भाषाई और क्षेत्रवादी राजनीति का कोढ़ न लगता। तब भारतीय राष्ट्रीयता अल्पसंख्यकवाद की बन्दी न होती। राजनीतिक आजादी के बाद आर्थिक आजादी का दूसरा संघर्ष शुरु किया जाता। हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्वबैंक की पूँजी व कर्ज के क्रूस पर न टँगे होते। अँग्रेजों के पदचिन्हों पे चलना छोड़कर हम अपनी नैतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व्यवस्था का निर्माण करते। हम अपने राष्ट्रजीवन की सनातनता का त्याग न करते। भारत को उसके सहस्रादिक वर्षों के अनुभव से जोड़ते और राष्ट्रीय अनुभूति के आधार पर आधुनिक भारत का निर्माण करते। अपने चिरपुरातन किन्तु नितनूतन भारत को वर्तमान के प्रश्नों के उत्तर के रूप में प्रस्तुत करते। न गाँधी जी की चली और न काँग्रेस समाप्त हुई। न भारतराष्ट्र अपने आदि से जुड़ा, न आगत-अनागत के अनुरूप उसका पुनर्निर्माण हो पाया। परिणाम में पाई मिथ्या सिद्धान्तों की जूठन, घृणा एवं संघर्ष में से उपजी सोच। शब्द पाखण्ड, भाव दारिद्रय और तन्त्र की गुलामी। विश्व के तमाम राष्ट्रों के स्वयंवर में हम नारद की भाँति वानरवेश में जा बैठे। हमने स्व को भुलाकर स्वाधीनता की बात की और जिसे स्वतन्त्र कहा वह स्वदेशी नहीं विदेशी तन्त्र था। आजादी के बाद जिस भारत की कल्पना विवेकानन्द, तिलक, अरविन्द, सुभाष और गाँधी जी ने की थी, वह काँग्रेस के बूते की बात नहीं थी, न है। भावी भारत का निर्माण करने के लिए सुचिन्तित सिद्धान्तों, व्यावहारिक नीतियों तथा आदर्शों से जुड़े राष्ट्रार्पित आचरणों की आवश्यकता थी और है। जब यह प्रश्न मन में उठता है, तो काँग्रेस कल्चर का कोढ़ पीड़ा देने लगता है। काँग्रेस ने यदि किसी संस्कृति को जन्म दिया होता, तो देश को आज यह संताप न भोगना पड़ता। उसने संस्कृति का नहीं, कल्ट की कोख से जन्मने वाले कल्चर के बबूल का बीज बोया है। उस बीज में से संवेदना, अनुभूति, आत्मीयता, समरसता एवं एकात्मता का सांस्कृतिक वटवृक्ष उग ही नहीं सकता। काँग्रेस कल्ट की जड़ें काटे बिना देश को उसका अपेक्षित स्वरूप प्रदान नहीं किया जा सकता। किन्तु उससे मुक्ति के लिए अपनाया गया प्रत्येक उपाय नाकाम रहा है। चाहे लोहिया का 'गैरकाँग्रेसवाद' हो, चाहे जय प्रकाश की 'सम्पूर्ण क्रान्ति' हो, चाहे विश्वनाथप्रताप का 'नैतिकतावाद' हो, चाहे चन्द्रशेखर का समाजवाद हो और चाहे वाजपेयी-आडवाणी का उदारवाद हो, कोई भी काँग्रेस कल्ट और कल्चर से मुक्त नहीं है। सभी के स्वर-ताल में काँग्रेस की सरगम थी और है। गाँधी जी की कल्पना की कोई नयी धारा बनाने का प्रयास इनमें से किसी में भी नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि सरकारें बदलतीं हैं, काँग्रेस हटती भी है, किन्तु व्यवस्था नहीं बदलती, वाणी नहीं बदलती, व्यवहार नहीं बदलता। आजादी के बाद भारत की सनातनता एवं उसकी जीवनधारा से प्रेरित राजनीति का वैकल्पिक प्रथम प्रमाणिक प्रयास डा.श्यामाप्रसादमुखर्जी के नेतृत्व में प्रारम्भ हुआ। 1951 में जनसंघ की स्थापना भारत में*

वैकल्पिक बीजारोपण था। देश का दुर्भाग्य था कि 1953 में श्यामाप्रसादमुखर्जी, 1962 में डा.रघुवीर, 1968 में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु हो गई। फलस्वरूप 1951 से चली जनसंघ की वैकल्पिक धारा 1977 के जनतापार्टी के जंगल में भटक गई, तो 1980 में मुम्बई से निकली भाजपा की वैकल्पिक धारा काँग्रेसी कल्चर के मरुस्थल में समा गई। दीनदयाल जी ने जनसंघ की जीवनीशक्ति को जिस सनातन राष्ट्र की अस्मिता के साथ जोड़ा था, वह पुनः प्रकट हो पाएगी, इसकी संभावना नहीं दिखाई देती। उपाध याय जी ने कहा था कि न केवल भौतिकता (रोटी) से काम चलेगा और न केवल भगवत्ता (भक्ति) से काम चलेगा, बल्कि भूख और भक्ति के बीच तालमेल होना राष्ट्रीय समृद्धि की प्रथम शर्त है।

काँग्रेसी कल्ट के विकल्प की खोज के अब तक अनेक असफल प्रयास किए जा चुके हैं। देशवासी अब किसी सफल और सार्थक विकल्प की तलाश में हैं। इस असंभव को संभव केवल पण्डित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्ममानवदर्शन ही कर सकता है। **-(भानुप्रतापशुक्ल, स्तम्भकार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 11/04/2005)**

371) शिक्षा के नाम पर लूट :- मैं उच्चशिक्षा अधिकारियों का ध्यान खस्ताहाल शिक्षा, शिक्षक और प्रधानाचार्यों की मनमानी की ओर आकृष्ट कर रहा हूँ। मेरा पुत्र आशीष चौहान आठवीं में पढ़ता है। मैं खुद भी एक शिक्षक हूँ। मैं अक्सर स्कूल जाता और सम्बन्धित शिक्षक से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता। अक्सर कक्षाएँ खाली देखता। शिक्षा की इस बदहाली को देख मैं बेहद दुःखी होता। मैंने उपप्रधानाचार्य जी से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की कि वह अपने उच्च अधिकारियों से बात कर स्कूल में शिक्षक और शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध करें। उन्होंने कहा– हम किसी शिक्षक की छुट्टी नहीं रोक सकते। वह एक सलाह भी देती हैं कि मैं अपना पढ़ाने का काम इसी विद्यालय में करूँ, ट्रांसफर करवा लूँ और अपने पुत्र को किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़वाऊँ। मैं राजी नहीं हुआ, क्योंकि विद्यालय में पढ़ रहे सभी छात्र एवं छात्राएँ मेरे पुत्र एवं पुत्री के समान हैं। मैं तो अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में पढ़ा लूँगा किन्तु औरों को क्या होगा? यदि हम सभी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षक सम्पूर्ण मेहनत से सभी बच्चों को अपना बच्चा समझकर पढ़ाएँ, तो दुनिया का कोई भी स्कूल हमारे मुकाबले खड़ा नहीं हो सकता। हम इस सेवा में सोने की फसल उगा सकते हैं, क्योंकि हम ही राष्ट्र के माली हैं। ज्ञानरूपी अनन्त धारा है हमारे पास। हम अपने निस्स्वार्थ सेवा से ही भारत को विकसित, शिक्षित संभवतः बेरोजगारी को मिटाने में सक्षम, प्रथम शिखर का ज्योतिर्मय प्रतिमान बना सकते हैं।

मैंने उस स्कूल में पढ़ाने की बात मान ली। गत दस दिसम्बर से मैं आशीष के स्कूल में पढ़ाने लगा। उसे भी अच्छा लगा। उपप्रधानाचार्य जी ने मुझसे कहा– ''जितने भी बच्चे इस स्कूल के कमजोर हैं, आप उनका ट्यूशन लें। सबको पास करवाकर ट्यूशन फीस में से 20 प्रतिशत मुझे दे दें।'' मैंने मना किया तो वे नाराज हो गईं। मुझसे कहने लगीं– ''यह सरकारी स्कूल हैं दीपक जी। यहाँ वेतन के अलावा और भी जुगाड़ बनाओ। उन्नति करो, कार खरीदो, परिवार को खुश रखो। यहाँ हम रुपये कमाने बैठे हैं। इन बच्चों के माता–पिता की जागरूकता नहीं है तो हम क्या करें? रुपये भी न कमाएँ? स्कूल में बहुत से ऐसे शिक्षक हैं, जो मुझे 25 प्रतिशत कमीशन देते हैं। मगर आप ज्यादा ईमानदार और मेहनती हैं। 20 प्रतिशत चलेगा।'' मैं कुछ नहीं बोला। वह आगे बोली– ''आठवीं में कुछ बच्चों के अभिभावक से आप प्रति बच्चा 1000 रुपये लो। उसे प्रमोटेड या ग्रेस पास करेंगे।'' मैं उनकी बात सुनकर मन ही मन खून का घूँट पी रहा था। उन्होंने कहा– ''आप ट्यूशन से भी दस हजार रुपये भी कमा सकते हैं, जिसमें से मुझे केवल 2000 रुपये प्रतिमाह आप देंगे।'' मैं काफी परेशान हूँ। मैं करप्शन पर नहीं उतरना चाहता। स्कूल में केवल चोरी के जरिए सरकारी खजाने और पी.टी.ए. खजाने को मनमाने ढंग से खर्च किया गया है।

मैं अब बिना वेतन ही बच्चों को अपने सम्पूर्ण जीवनकाल तक पढ़ाना चाहूँगा, जिससे सभी सरकारी स्कूल के भ्रष्ट शिक्षकों व प्रिंसिपलों को एक नया सबक मिले। वे शिक्षकों के कर्तव्य को समझें। आजादी के बाद जो जिम्मेदारी हमें निभानी थी, वह हम नहीं निभा रहे हैं– केवल पैसों के लिए।

-(दीपककुमार, मंगोलपुरी, दिल्ली-83; आवाज-ए-खबरदार, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 13/04/2005)

372) शिक्षा बनी सियासत का अखाड़ा :- आज से ठीक पचास साल पहले मानवाधिकार के वैश्विक घोषणापत्र में शिक्षा को मूलभूत मानवाधिकार करार दिय गया था। इसके बावजूद विश्व के एक तिहाई अशिक्षित बच्चे भारत में हैं। इसके लिए न सिर्फ केन्द्रसरकार बल्कि राज्यसरकारें भी दोषी हैं। संविधान के प्रारुप के मुताबिक शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है और इसकी जिम्मेदारी केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों की है। हुआ यह कि शिक्षा को न तो राज्य सरकारों ने ही महत्त्व दिया और न ही केन्द्र सरकार ने। आज भी शिक्षा पर समूचे बजट की 6 प्रतिशत धनराशि भी नहीं खर्च की जाती। 1990-91 में 3.84 प्रतिशत तथा 2001-02 में 4.11 प्रतिशत शिक्षाखर्च निर्धारित किया गया। जबकि आदर्श स्थिति यह है कि शिक्षा पर 10 प्रतिशत खर्च हो। राजीवगाँधी के कार्यकाल में नवोदय विद्यालय स्थापित हुए। उनके बाद देश के किसी भी प्रधानमन्त्री ने शिक्षा को प्रमुख कार्यक्रम (एजेण्डा) नहीं बनाया। शिक्षा और रोजगार की गारण्टी आज भी हमारी संसद में न तो बहस का मुद्दा बन सका है और न ही राजनैतिक दलों में इसके प्रति कोई खास लगाव नजर आता है। राजग सरकार के कार्यकाल में लागू हुए सर्वशिक्षा अभियान का असर अभी भी निचले स्तर तक नहीं पहुँच सका है। संप्रग सरकार के एजेण्डे में भी शिक्षा को पर्याप्त महत्त्व नहीं मिल सका है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, रक्षा जैसे मुद्दों को दलगत राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन ऐसी समझदारी हमारे राजनैतिक दलों के नेता अभी तक नहीं विकसित कर सके हैं। आज देश में हर पाँच में से एक बच्चा ऐसा है, जो स्कूल नहीं जा पाता। बालश्रमिकों की तादाद बढ़ती जा रही है। उन्हें विद्यालय का मुँह देखना तक नसीब नहीं है। देश में लड़कियों की संख्या का दो तिहाई हिस्सा परिवार के काम में हाथ बँटाने या मजदूरी करने के कारण शिक्षा से वंचित रह जाता है। अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को आरक्षण की सुविधा के बाद भी इन वर्गों के लोग न तो पर्याप्त संख्या में शिक्षित हो सके हैं और न ही रोजगार पा सके हैं। गरीबी, भ्रष्टाचार और तेजी के साथ बदलता राजनैतिक माहौल भी शिक्षा के विकास में बाधा है। एक ओर शिक्षा इतनी मँहगी होती जा रही है कि निम्न वर्ग क्या मध्य वर्ग के लिए भी दुष्कर होती जा रही है। मेधा और प्रतिभा का सम्मान नहीं रहा। मेडिकल कालेजों, इंजीनियरिंग कालेजों, एम.बी.ए., एम. सी.ए., सी.ए., होटल मैनेजमैंट जैसे पाठ्यक्रमों की फीस हजारों में नहीं बल्कि लाखों में पहुँच गई है। इन कोर्सों की डिग्री हासिल कर लेने के बाद भी रोजगार की गारण्टी नहीं है। राजग सरकार ने हर साल एक करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था। वह उसे भूल गई। संप्रग सरकार भी शिक्षा और रोजगार को लेकर वचनबद्ध है। लेकिन उसने अभी तक कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं किया है। शिक्षा कब तक यूनिसफ, वर्ल्डबैंक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त अनुदान पर टिकी रहेगी? एक ओर पाँच सितारा होटलों को मात देते मँहगे प्राइवेट स्कूल हैं, तो दूसरी तरफ गाँवों और कस्बों में ऐसे स्कूल हैं, जहाँ न तो फर्नीचर हैं, न ब्लैकबोर्ड और न ही पीने का पानी। स्कूल की छतें मासूम बच्चों पर गिर जाती हैं और वे दबकर मर जाते हैं। आग की लपटों से झुलसकर बच्चे मर जाते हैं। उनको दोपहर का भोजन देने तथा छात्रवृत्ति दी जाने वाली योजनाओं में सबसे अधिक घपले होते हैं। बच्चों को मिलने वाला पुष्टाहार ग्राम प्रधानों, अध्यापकों, आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और विभागीय अधिकारियों द्वारा मिलकर चट कर लिया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के पर्चे आउट हो जाते हैं और रंजीत डान जैसे लोगों की तिजोरियाँ भरती चली जाती हैं। गरीब एकलव्य से गुरुदक्षिणा में अँगूठा दान लेने वाली परम्परा आज भी कायम है। शिक्षक पहले कभी समाज का आदर्श हुआ करता था। आज वह वेतन, भत्तों तथा ट्यूशनफीस की भूल-भुलैया में उलझता जा रहा है। पढ़ाने के अलावा सभी कार्य करने के लिए उसके पास फुर्सत है। प्राइवेट कोचिंग संस्थानों का बढ़ता चलन, मँहगी फीस, स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम न सिर्फ शिक्षा के निजीकरण के प्रतीक हैं, बल्कि इस दिशा में सरकार की चुप्पी आम जनता को भयभीत कर रही है। अब उसके हितों की परवाह करने वाला कोई नहीं है। इस क्षेत्र में हम सबको मिलजुलकर प्रयास करना होगा।

-(प्रदीप उपाध्याय, स्तम्भकार; भास्करदर्शन, हिन्दीसाप्ताहिक, सहारनपुर, 15/04/05)

373) कैसे सृजित होंगे रोजगार :- स्वतन्त्रता प्राप्ति के 58 वर्ष बाद भी रोजगार कैसे मिल सकता है, इसमें मात्र कानूनरूपी विधेयक ही सरकार ला रही है, वह भी आधे-अधूरे। आजादी के 58 वर्ष बाद भी उसी पहले नेतृत्व के परपौत्रों की सरकार है। उस समय के लोगों ने जैसे अधूरे मन से अपने ही मन को डिस्कवर किया, वैसे ही मौजूदा सरकार ने लगातार गैरकानूनी होते जा रहे कानून के माध्यम से देश के बेरोजगारों को रोजगार देने के

लिए संसद पटल पर मात्र राजनैतिक कर्मकाण्ड की ही फाइल रखी है। क्या आज तक किसी सरकार ने देश में ऐसा कोई वातावरण तैयार किया जिसमें सबको रोजगार मिल सके। आज जब काम करने वालों से ही सौदेबाजी करके उन्हें निकाला जा रहा है, तो नवागन्तुकों को सरकार कैसे काम दे पाएगी ? जैसे प्रत्येक घर में राम जी के कैलेण्डर टाँगने से रामराज्य नहीं आ सकता, वैसे ही मात्र कानून बनाने से सबको रोजगार नहीं मिल सकता। एक पुराना विधेयक जो राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी के नाम पर था, उसका नाम बदलकर ग्रामीण रोजगार गारण्टी विधेयक 2004 रख दिया। गरीबी रेखा के नीचे वालों को सौ दिन के काम की तो गारण्टी है, लेकिन बाकी दिन आप रोजे रख सकते हैं। फिर न्यूनतम मजदूरी क्या होगी ? क्या अराजक धुन्ध साफ हो पाएगी ? शायद नहीं, क्योंकि सरकार ने दूर-सुदूर किसी गाँव में रोजगार पहुँचाने की बात तो कही है। लेकिन क्या आज वहाँ तक बाकी जीने लायक सुविधाएँ पहुँच पायी हैं ? फिर एक बात तो स्पष्ट है कि कोई भी सरकार जरा इण्डियागेट की छत पर खड़े होकर सीना ठोककर कहे तो कि हजारों प्रकार के ऐसे कानूनों और योजनाओं ने देश के किस रिसते हुए जख्म पर मरहम लगाया है। इसलिए हे राज करने वालों! रोजगार पैदा करने के लिए पहले देश के दुःखों को सूचीबद्ध करो। फिर उनके निवारण से निकलेंगे रोजगार।

आज तक जिन योजनाकारों की बनाई योजनाओं से पड़ोसी तक को लाभ नहीं हुआ, उनकी मानसिक गरीबी का स्तर चेक करने के लिए भी कोई रेखा तय होनी चाहिए। उनकी देहाड़ियाँ काटने का भी कोई प्रावधान हो सके, तो वह और भी अच्छा इसलिए हे आँकड़ों को ही सरकार चलाना समझने वालों! कानूनों के ढेर लगाने की आवश्यकता नहीं। देश पहले ही योजनाओं और व्यर्थ कानूनों के कारण डायलेसिस पर है। आज तब कानून ही सबसे गैरकानूनी हो चला है, तो नया कानून भी सफेदे का पेड़ ही साबित होगा, जिसकी न छाया, न फल, न फूल, बस फाइलों के ढेर जितनी लम्बाई ही लम्बाई।

-(सुरेन्द्रबंसल, स्तम्भकार; भास्करदर्शन, हिन्दीसाप्ताहिक, सहारनपुर, 15/04/05)

374) ईसाई मिशनरी के निशाने पर दलित :- *भास्करदर्शन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि जिस दलित ने भी आत्मसम्मान पाने के लिए हिन्दूधर्म छोड़कर ईसाईधर्म अपनाया है, वह मौजूदा समय में पहले से ज्यादा अपमानित और उपेक्षित है। क्योंकि ईसाईधर्म के पुराने अनुयायी नये लोगों को न तो धार्मिक कार्यों में महत्त्व देते हैं और न ही उनसे रिश्ते-नाते जोड़ते हैं। भास्करदर्शन द्वारा जुटाए गए आँकड़ों से पता चलता है कि सन् 1991 में मिजोरम राज्य में ईसाइयों की संख्या 85.5% हो गयी थी। तथा तब से इस संख्या में निरन्तर वृद्धि भी हो रही है। सन् 1951 में नागालैण्ड में ईसाइयों की संख्या 46% थी, जबकि यह सन् 1971 में 66% एवं 1991 में 87.5% हो गई। मेघालय में सन् 1951 में ईसाई धर्मानुयायियों की जनसंख्या 22.6% थी, जबकि 1971 में 46% तथा 1991 में 64.58% हो गई। मणिपुर में 1951 में ईसाइयों की संख्या 11.8% थी, जो 1991 में 34.11% हो गई। अरुणाचलप्रदेश में भी इस संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो 1991 में 10.2% थी।* ***-(एक समाचार; भास्करदर्शन, हिन्दीसाप्ताहिक, सहारनपुर, 15/04/05)***

375) *धर्मपरिवर्तन के नाम पर चर्च नेतृत्व ने दलित वर्गों के साथ विश्वासघात किया है। जो एक आशा लेकर चर्चनेतृत्व की शरण में आए थे। अब सवाल पैदा होता है कि चर्च नेतृत्व देश की आजादी के छह दशक बाद करोड़ों दलित ईसाइयों को हिन्दू दलितों की सूची में शामिल करने की माँग कर रहा है। लेकिन जो सुविधाएँ एवं लाभ उन्होंने छोड़ दिए थे क्या चर्च नेतृत्व उनकी भरपायी के लिए तैयार है ? क्या चर्च नेतृत्व उनकी आस्था के प्रति किए गए विश्वासघात का उन्हें मुआवजा देगा ? भारत में अधिकतर दलितों ने अपना धर्म आत्मसम्मान के कारण ही बदला है और आज भी वे आत्मसम्मान की तलाश में भटक रहे हैं। अब समय आ गया है कि धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस करवायी जाए। धर्म परिवर्तित लोगों के साथ न्याय करते हुए उन्हें मुआवजा और आत्मसम्मान दिलाया जाए। केवल अनुसूचित जाति का दर्जा दे देने भर से उनके घावों को नहीं भरा जा सकता। दरअसल दलित ईसाइयों के विकास के प्रति चर्च नेतृत्व की कोई रुचि ही नहीं है। उत्पीड़न, रोजमर्रा का संघर्ष, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, सामाजिक न्याय की तलाश और चर्च ढाँचे में अपने अधिकारों को पाने का उनका संघर्ष- इनमें से किसी में भी चर्च नेतृत्व की कोई रुचि नहीं है। यहाँ तक कि चर्च नेतृत्व ईसाइयत के अन्दर जातिवाद खत्म करने की बजाय उन्हें पुनः हिन्दू दलितों की सूची में शामिल करने की माँग करके उनकी आस्था के साथ छल कर रहा है।*

-(लेख : आर.एल.फ्रांसिस, धर्मकर्म संस्करण; पंजाबकेसरी, दिल्ली, अप्रैल, 2005)

376) दामन यहाँ पसारे बचपन निहारता है, आगे न जाने क्या हो लम्बा अभी सफर है :- *भूख, प्यास एवं अशिक्षा की मार झेलता बचपन जब शहरों और महानगरों में लगे कूड़े के ढेरों से रद्दीकागज व पन्नी बीनकर दो जून की रोटी तलाश करता है, तो ऐसे में देश के राष्ट्रीय पर्वों पर प्रमुखता से गाए जाने वाले इस गीत– 'इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चलके, यह देश है तुम्हारा नेता तुम्हीं हो कल के' की ये पंक्तियाँ केवल मजाक सी महसूस होती हैं। वर्तमान समय में जिसप्रकार सरकारी कायदे–कानूनों को ताक पर रखकर समाज के तथाकथित संभ्रान्त एवं पूँजीपतियों द्वारा गरीब नन्हें–मुन्ने बच्चों से अपने घरों में झाड़ू–पोंछा लगाने से लेकर अन्य भारी–भरकम काम लिए जा रहे हैं। वे न केवल बालमजदूरी को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि बालश्रम उन्मूलन को लेकर केन्द्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के लिए सामन्तवादियों की एक खुली चुनौती भी है। कानूनों की रक्षा करने वाले सरकारी अधिकारियों एवं लोकसभा तथा विधानसभा में बैठकर कानून बनाने वाले नेताओं के घरों पर नाबालिग बच्चों को झाड़ू–पोंछा करते या फिर चाय या पानी पिलाते देखा जा सकता है। इन बच्चों को भले ही ये नेता या उद्योगपति बालमजदूर न मानते हों, परन्तु शिक्षा से वंचित कर ऐसे बच्चों से उपरोक्त काम लिया जाना भी संविधान में प्रदत्त बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन दण्डनीय अपराध है। संविधान के अनुच्छेद में 21–क 2002 के अनुसार 4 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा मूल अधिकारों में शामिल कर दी गई है। किन्तु पूरे देश एवं प्रदेश की बात छोड़कर यदि केवल उत्तरप्रदेश के सहारनपुर मण्डल में बालमजदूरी पर नजर डालें तो पता चलता है कि हजारों बच्चे बालमजदूरी के कारण क–ख–ग के ज्ञान से दूर अशिक्षा के अन्धकार में खोए हुए हैं और रद्दी कागज या फिर टूटे–फूटे लोहे–लक्कड़ एवं प्लास्टिक की पन्नियाँ बीनकर अपने पेट की भूख शान्त करते हैं अथवा खतरनाक कलकारखानों एवं चाय की दुकानों व होटलों में काम कर अपना व अपने परिवार का गुजर–बसर करते हैं। सहारनपुर एवं मुजफ्फरनगर में संचालित लगभग 200 से अधिक ईंटभट्ठों पर काम में लगे 10 हजार से अधिक मजदूरों के बच्चे भी अपने माँ–बाप की तर्ज पर अपनी जिन्दगी को ईंटों की मिट्टी में ही खपा रहे हैं। पिछले दिनों स्वयंसेवी संस्था बाल अधिकार क्रान्ति मोर्चा ने सर्वेक्षण करके जो बालमजदूरों की संख्या प्रदेश एवं केन्द्र सरकार को भेजी थी, उससे जिला श्रमविभाग के अफसरों की नींद उड़ गई थी। कारण कुछ भी हो परन्तु यह कड़वा सच है कि श्रमविभाग की सतर्कता के बाद भी बालमजदूरी खूब फल–फूल रही है तथा शिक्षा से वंचित बच्चे हजारों कल–कारखानों में दो जून की रोटी पाने की खातिर अपने बचपन को गवाँ रहे हैं। इस हालात में देश का भविष्य क्या होगा? कहना मुश्किल है।*

–(एक समाचार; भास्करदर्शन, हिन्दीसाप्ताहिक, सहारनपुर, 15/04/05)

377) *उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध और बीसवीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध विश्वभर में पूँजीवाद और साम्राज्यवाद के क्रूर शिकंजे से आम मानवसमाज को मुक्ति दिलाने के क्रान्तिकारी दर्शनों के उद्भव एवं संघर्षों का साक्षी रहा। श्रम के शोषण से समृद्धि के अथाह संचय के खिलाफ कार्ल मार्क्स ने मजदूरों के संगठन और संघर्ष का रास्ता दिखाते हुए सर्वहारा की सत्ता को विकल्प के रूप में पेश किया। दुनिया में शोषण और समानता के खात्मे के संदर्भ में मार्क्सवाद या साम्यवाद की विचारधारा सबसे अधिक लोकप्रिय चर्चास्पद एवं विवादास्पद रही। मार्क्स की सोच में कुछ अपनी समझ के हिसाब से जोड़–घटाकर रूस में 1917 में ब्लादिमीर इवानोविच लेनिन ने और चीन में 1948 में माओत्से तुंग ने साम्यवादी क्रान्तियाँ करके सर्वहारा की सरकारें भी स्थापित कर दीं। पूर्वी यूरोपीय सहित कुछ अन्य देशों में भी कम्यूनिस्ट सरकारें बनीं। ये सारे सत्ता परिवर्तन आमतौर पर रक्तरंजित रहे।*

महात्मा गाँधी के दिशानिर्देशन में पहले दक्षिण अफ्रीका और बाद में भारत में भी पूँजीवादी उपनिवेश की गुलामी से मुक्ति के लिए प्रत्यक्ष प्रयोग में लाया गया। गाँधी का आन्दोलन उच्चतम नैतिक मूल्यों पर आधारित था और राज्यशक्ति पर लोकशक्ति के नियंत्रण के साथ–साथ समाज के अन्तिम व्यक्ति को केन्द्र मानकर विकास की रूपरेखा तय करता था। महात्मा गाँधी और कार्ल मार्क्स दोनों ही क्रान्तिकारी दार्शनिकों ने अपनी–अपनी विचारधारा सर्वोदय और साम्यवाद को अन्त्योदय और सर्वहारा के सशक्तिकरण को मुख्य बिन्दु मानकर गढ़ा। दोनों ही विद्वानों ने अन्ततः राज्यसत्ता के विसर्जन और मानवीय मूल्यों पर आधारित नये समाज की संरचना की बात कही। उन्होंने पूर्णतया शोषण, असमानता, अन्याय, अत्याचार से मुक्त समाज का लक्ष्य सामने रखा। इसप्रकार जहाँ तक उद्देश्य की बात है, दोनों ही विचारधाराओं में

समानता दिखाई देती है। महात्मा गाँधी के सर्वोदय दर्शन में सत्य और अहिंसा को बुनियादी मूल्य माना गया। गाँधी का लोकतन्त्र जिस भी अवस्था में था, उससे अधिक लोकतन्त्र की ओर जाने का रास्ता मंजूर था। उन्होंने आम जनता के व्यापक संगठन के आधार पर जनसत्याग्रह के द्वारा शोषक वर्ग से लड़ने का और जनजाग्रति व जनसंगठन के आधार पर वैकल्पिक समाज के निर्माण का तरीका सुझाया। उन्होंने मुख्यतः सारा जोर हर इंसान के दिल में छिपी इंसानियत को जगाने पर दिया। उन्हें अनैतिकता पर नैतिकता की विजय के बारे में पूर्ण श्रद्धा थी। किन्तु मार्क्स लोगों की मन बदलने की बात आमतौर पर नहीं कहते थे और इसीलिए उन्होंने पूँजीपति शोषकवर्ग के सफाए की बात कही। आम जनता के दुःखों, कष्टों ने दोनों महान विचारकों के अन्तर्तम तक को झकझोर दिया था और उन्होंने इसका हल ढूँढने को ही अपने जीवन का मिशन बना लिया।

आज मार्क्सवाद और गाँधीवाद उस निर्णायक बिन्दु पर आ पहुँचे हैं, जहाँ पूँजीवादी चुनौतियों का या तो उन्हें दुनिया के सामने प्रभावी हल पेश करना होगा अथवा उनका अपना वजूद ही बेमानी होकर रह जाएगा।

-(लेख; भास्करदर्शन, हिन्दीसाप्ताहिक, सहारनपुर, 15/04/05)

378) मंगलराज : हथिनी के प्रेम में हाथी बेमौत मारा गया :- *राँची के दलमा अभयारण्य में एक जवान हाथी ने हथिनी को हथियाने के लिए एक उम्रदराज हाथी की जान ले ली। हथिनी के लिए इन दोनों के बीच तीन दिनों तक युद्ध चला और अन्ततः एक हाथी को अपनी जान गँवानी पड़ी। वन अधिकारियों के मुताबिक इस अभयारण्य में एक हाथी और एक हथिनी पिछले कई वर्षों से झुण्ड से अलग होकर प्रेमी-प्रेमिका के रूप में रह रहे थे। इन दोनों के बीच मोहोब्बत परवान चढ़ रही थी कि अचानक कुछ रोज पहले एक युवा बिगड़ैल हाथी उनकी जिन्दगी में आ धमका। इस युवा हाथी ने हथिनी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, जिस पर हथिनी का प्रेमी खफा हो गया। युवा हाथी हथिनी के इर्द-गिर्द मँडराने लगा और उसे आकर्षित करने के लिए तरह-तरह की क्रीड़ाएँ दिखाने लगा। यह सब हथिनी के प्रेमी को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने युवा हाथी से पंगा ले लिया। दोनों हाथियों के बीच जंग शुरु हो गई। इस जंग में कई हाथियों ने भी दखल दिया लेकिन दोनों हाथी हार मानने को तैयार नहीं थे। इन दोनों की लड़ाई में दलमा अभयारण्य के कई पेड़ भी टूट गए। दोनों हाथी लहूलुहान हो गए और हथिनी सहमी हुई पूरी जंग देखती रही। उसने कई बार अपने प्रेमी की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन युवा हाथी उन दोनों पर भारी पड़ा। तीन दिनों की लड़ाई के बाद हथिनी का प्रेमी बुरी तरह टूट गया और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। हाथियों में इस हारे व टूटे हुए प्रेमी को उठाने की भरपूर कोशिश की लेकिन उनकी मेहनत रंग नहीं लाई और हाथी ने दम तोड़ दिया।*

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 05/04/2005)

379) यशवंत सिन्हा ने सच बोला :- *यशवंत सिन्हा अध्यापक से आई.ए.एस. बने और फिर राजनीति में आकर भाजपा में शामिल हो गए। वह वाजपेयी सरकार में पहले वित्तमन्त्री रहे और फिर विदेशमन्त्री। एक समय प्रधानमन्त्री से मिलना आसान था परन्तु श्री सिन्हा से मिल पाना कठिन। अब जब केन्द्र में न उनकी सरकार रही और न ही वे मन्त्री रहे, तो उन्होंने एक टी.वी. पत्रकार से कुछ आत्मस्वीकृतियाँ करते हुए महत्त्वपूर्ण सच्ची बातें कहीं :-*

1. *पहले मैं हवाई जहाज से घूमा करता था, तो देश की असली तस्वीर का उतना ही पता चलता था, जितना अधिकारी, कर्मचारी, पार्टी के नेता व कार्यकर्ता बताते थे। अब मैं सड़कों पर घूम रहा हूँ, तो सब कुछ साफ दिख रहा है कि ये लोग किस तरह मुझे पूर्णतः झूठी सूचनाएँ देते थे।*
2. *मन्त्रियों को आरामदेह जीवन व्यतीत करते हुए लगता है कि असली भारत वही है, जो वह देख रहे हैं, जबकि वास्तविकता कुछ अलग ही होती है।*
3. *केन्द्र सरकार जिस मद के लिए पैसा जारी करती है, वह उस पर खर्च नहीं किया जाता। आखिर यह पैसा कहाँ जाता है? सड़कों के लिए धन दिया जाता है, फिर भी सड़कें खस्ताहाल हैं।*

हमें खुशी है कि एक राजनेता तो निकला, जिसने ये स्वीकार किया कि उन्हें मन्त्री रहते हुए जमीनी हकीकतों का पता नहीं चल पाता था और उनके सामने सिर्फ वही तस्वीर होती, जो अधिकारी, कर्मचारी या निहित स्वार्थीतत्त्व उन्हें बताते। भाजपा जब सत्ता में थी, तो उसके नेता व मन्त्री भी ऊँचे

आसमानों पर उड़ने लगे तथा जमीनी हकीकतों से दूर हटते चले गए। परिणामस्वरूप भाजपा के फीलगुड और शाइनिंग इण्डिया के नारे विफल हो गए और उन्हें सत्ता गँवानी पड़ी। हालात आज भी उससे भिन्न नहीं हैं। आप केन्द्र सरकार में किसी को पत्र लिखें तो पत्रप्राप्ति की सूचना तक नहीं मिलती। प्रधानमन्त्री कार्यालय से निचले स्तर तक यही हालात हैं। आम जनता प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्रियों को तभी पत्र लिखती है, जब निचले स्तर पर अधिकारी उसकी समस्याओं का समाधान नहीं करते और लोग जिला दफ्तरों और सचिवालयों के चक्कर काट-काटकर निराश हो जाते हैं।

निजी क्षेत्र के व्यावसायिक एवं औद्योगिक संस्थानों के उत्पादनों व सेवाओं में किन्हीं खामियों (त्रुटियों) के बारे में जब भी लोगों की शिकायतें आती हैं, तो सम्बन्धित संस्थान एक सप्ताह के भीतर उस खामी को दूर करके की गई कार्यवाही की जानकारी देते हैं और धन्यवाद देने के साथ उपभोक्ता को हुई परेशानी के लिए क्षमा-याचना भी करते हैं। परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से ऐसे पत्रों का आमतौर पर कोई जवाब नहीं आता। श्री यशवंत सिन्हा ने छह साल सत्ता में रहने के बाद अब जो कुछ स्वीकार किया है, वही सरकारों की असली तस्वीर है। हमारे राजनेताओं को इससे सबक सीखकर अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाना चाहिए तथा देश की जमीनी हकीकतों और आम लोगों की समस्याओं की ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। **-(विजय, सम्पादक, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 05/04/2005)**

380) भ्रष्ट अफसरों के घरों से मिले नगदी और सोने के ढेर : सी.बी.आई. का देशव्यापी अभियान :- भ्रष्टाचार में लिप्त होने के सन्देह में देशभर के वरिष्ठ सरकारी नौकरशाहों के खिलाफ इस साल दूसरी बार देशव्यापी अभियान चलाते हुए सी.बी.आई. ने आज 60 शहरों में 200 स्थानों पर छापे मारे और लाखों रुपये नगद बरामद किए। सी.बी.आई. के सूत्रों ने बताया अब तक 25 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस उपायुक्त के घर और कार्यालय से करीब 1 किलोग्राम सोना और 1 लाख रुपये नगद बरामद किये गए। पटना में एक कार्यकारी इंजीनियर बंशीलाल के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक करीब 21 करोड़ रुपयों की सम्पत्ति तथा 3 लाख रुपयों का बैंक बैलेंस रखने का मामला दर्ज किया गया। सीबीआई ने उनके आवास से 3 लाख रुपये भी बरामद किए। **-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 07/04/2005)**

381) पेटेन्ट कानून :- उत्पाद पेटेन्ट का अर्थ है- पेटेन्टशुदा उत्पाद का कोई अन्य व्यक्ति अथवा संस्था किसी दूसरी प्रक्रिया से भी उत्पादन नहीं कर सकेगा। गत 23 मार्च को भारतीय संसद द्वारा पारित पेटेन्ट संशोधन विधेयक में उत्पादन की प्रक्रिया के अलावा उत्पाद पर भी पेटेन्ट (एकाधिकार) देने का प्रावधान है। इससे नई दवाओं पर विकसित देशों का अधिपत्य स्थापित होने की आशंका हो गई है, क्योंकि अधिकांश शोध एवं विकास उन्हीं देशों में होते रहे हैं। बहुराष्ट्रीय दवाकम्पनियों का अनुमान है कि जेनेरिक संस्करण के चलते उन्हें प्रतिवर्ष 50 करोड़ डालर का नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन अब उन्हें नये पेटेन्ट कानून के कारण भारतीय कम्पनियों की वजह से अधिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी दवाओं के सस्ते संस्करण नहीं बेच सकेंगी। नये पेटेन्ट कानून में उत्पाद पर पेटेन्ट दिए जाने का प्रावधान होने के चलते ऐसा संभव नहीं होगा। ऐसा करने पर उन्हें बहुराष्ट्रीय दवाकम्पनियों को बड़ी मात्रा में जुर्माना अदा करना पड़ेगा।
-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 06/04/2005)

382) कितना सुनहरा सीजन है, अपराधियों और दागियों का :- हमारे देश में अपराधियों और दागियों की संख्या दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। उच्चतम न्यायालय में भी इन्हीं की गूँज सुनाई देती है, चुनाव में भी इन्हीं का बोलबाला है। दागी लीडरों का स्टाक यूँ ही बढ़ता रहा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सभी अपराधी विधानसभा और लोकसभा में सुशोभित हो जाएँगे और फिर संविधान में संशोधन करके चोर-उचक्कों को संभ्रान्त नागरिक होने का सर्टिफिकेट दे देंगे।

कल एक लीडर जी बहुत से नामचीन अपराधियों को लेकर नगर में घूम रहे थे। हमने निवेदन किया कि ''इनसे आप सम्बन्ध क्यों रखते हैं? आप बदनाम हो जाएँगे।'' वह मुस्कुराकर बोले- ''हम आप जैसे अलगाववादियों के मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। देश की एकता, अखण्डता के लिए चोर, डाकू, भ्रष्ट, हत्यारे, बलात्कारी अर्थात् हरप्रकार के अपराधी को गले लगाकर चलना होगा।'' हमने कहा- ''वह तो ठीक है साहिब,

लेकिन इससे हमारे देश की आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बिगड़ जाएगा।'' इस पर नेताजी बोले– ''यदि हमने इन्हें नजरअन्दाज किया, तो हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाएगा। अरे भइये! गद्दी तक पहुँचने के लिए कई दागी गधों की सवारी भी करनी पड़ती है। बूथकैप्चरिंग, जाली वोटिंग और नशे–पानी की सीढ़ियों पर चढ़कर जो कुर्सी प्राप्त होती है, उस पर बैठने वाला क्या हुआ– सज्जन कि शैतान ? नेताजी आपकी सियासत से देश को क्या लाभ होगा ? क्या विदेशों में हमारी बदनामी नहीं होगी ? बिल्कुल नहीं! कई भयानक अपराधियों जैसे सैकड़ों ऐसे महापुरुष जब इस देश में विचरेंगे, तो यूरोप, अमरीका, कनाडा, फ्रांस, जापान, इंग्लैण्ड आदि सभी देशों के पर्यटक लालकिला अथवा ताजमहल नहीं, बल्कि इनको ही देखने के लिए पधारेंगे। हमने कहा– ''बहुत दूर की सोच रहे हैं आप।'' नेता वही जो अपने आज और जनता के कल की चिन्ता करे, यह कहकर लीडर महोदय गम्भीर हो गए। अपराधी सज्जनों को हमारी वार्तालाप बकवास ही लग रही थी। एक ने नेता जी के कान मे कहा– ''पार लगा दें।'' ''शी! शी! हमारा वोटबैंक है।'' ''तो फिर अपहरण कर लेते हैं, अड्डे पर बैठकर इससे बतिया लीजिएगा।'' दूसरा आँखें लाल करता हुआ बोला– ''नहीं रे! फिजूल वाहियात और मूर्ख व्यक्ति है। ऐसी भीड़ ही तो प्रजातन्त्र की रीढ़ है। नेताओं के भाग्य में पुष्पमालाएँ और नारे इन्हीं के दमखम से हैं। ऐसे लोग मरखप गए तो राज किस पर करेंगे ?'' यह कहकर नेताजी मुस्कुराए– ''मान लीजिए देश में जनता अपराधी और नेता दागी हो जाएँ, तो देश उन्नति के शिखर को आनन–फानन में छू लेगा।'' ''वह कैसे ?'' स्मगलिंग को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। लूट–पाट जायज करार दे दी जाएगी। पूरा देश खुशहाल हो जाएगा। भूख, गरीबी का नामो–निशान तक नहीं होगा। शान्ति ही शान्ति होगी। आन्दोलन और सत्याग्रह जैसे शब्द सुनने को भी नहीं मिलेंगे। बिहार में न सड़कें हैं, न बिजली–पानी की व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ सुनने को भी नहीं मिलतीं, तो क्या वहाँ कोई आन्दोलन कभी हुआ है क्या ? आने वाली नस्लों को शिक्षा–दीक्षा देने के लिए ही फिल्में बनाई जाती हैं। तीन घण्टे की फिल्म में पौने तीन घण्टे विलेन हीरो को पीटता है। क्लाइमेक्स में विलेन पिट जाता है। जनता गब्बरसिंह पर ताली बजाती है, जय और वीरू पर नहीं। लीडर जी की बात में दम था। आज देश में विलेन यानि खलनायकों की भीड़ है। लगभग हर लीडर जाली वोटों के ढेर पर कुर्सी रखे बैठा है। एक बार की बात है, किसी पोलिंगबूथ पर कुल 700 वोट थे, परन्तु पोल 850 हो गए। यह अजब तमाशा एक करिश्मा ही था, जो भारत जैसे महान प्रजातान्त्रिक देश में संभव हो सकता है। यहाँ जो देशभक्षक होता है, वही देशरक्षक कहलाता है, बाकी सब झूठ।

-(दीपक जालंधरी, व्यंग्यकार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 08/04/2005)

383) मूलधारा से जुड़े मलिन बस्तियों के लोग :- *उत्तरांचल की कार्यकारी राजधानी देहरादून में मलिन बस्तियों में नारकीय जीवन जीने वाले लोग अब संस्कारित और स्वावलम्बी बनकर विकास की मूलधारा से जुड़ रहे हैं। यहाँ की 22 से अधिक बस्तियों के लोग 5 या 7 साल पहले जूते पालिश करने कूड़ा एकत्रित करने जैसे काम करके अपना जीवन बसर कर रहे थे। आये दिन शराब, मारपीट, चोरी के आरोप में पुलिस यहाँ के लोगों को पकड़कर ले जाती थी। लेकिन अब यहीं के बच्चे पढ़–लिखकर नौकरी करने लगे हैं। लोगों ने शराब पीना करीब–करीब बन्द कर दिया है। रेलवे स्टेशन के पीछे मद्रासी कालोनी के पास करीब 52 परिवार मलिन बस्ती में रह रहे हैं। ये लोग अपने आप को राजस्थान के झालावाड़ जिले का बताते हैं। रोजगार की तलाश में कुछ साल पहले आकर यहाँ रहने लगे थे। मुख्यरूप से ये जूतेपालिश का काम करते थे। शराब, मारपीट, चोरी आदि के आरोप में पुलिस आये दिन इन लोगों को पकड़ लेती थी। लेकिन पिछले 5 या 7 सालों में इनके जीवन का रुख ही बदल गया है। 7 साल पहले यहाँ संस्कार भारती का एक केन्द्र खुला, जिसके महासचिव जयनारायण अग्रवाल के अथक प्रयासों से लोगों ने जीवन की वास्तविक धारा में प्रवेश किया।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 09/04/2005)***

384) पाकिस्तान में बलोच, पख्तून और सिन्धियों पर जुल्म की दास्ताँ (6) :- *आज पाकिस्तान दुनिया की नजरों में भले ही एक मुल्क हो, परन्तु बलोच, पख्तून और सिन्ध कानूनी रूप से उसके हिस्से होते हुए भी वास्तविक रूप से टूट चुके हैं। यह टूटन कोई अचानक नहीं हुई है। यह आजादी के 58 वर्षों की सतत् प्रक्रिया है। ये सूबे तिल–तिल करके टूटे हैं। इनका तिनका–तिनका बिखरा है। इनकी रग–रग में दर्द का एहसास है। अतः इनका इलाज क्षणभर में नहीं हो सकता। निदा फाजली का एक शेर है– 'जमीन दी है तो थोड़ा सा आसमान भी दे। मेरे खुदा मेरे होने का कुछ गुमान भी दे।।'* ***-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 09/04/2005)***

385) नशानुक्ति आन्दोलन फिर शिर उठाने लगा है : सरकार के विरुद्ध जनता में आक्रोश :- *बेरोजगारी से त्रस्त युवा शराब की बजाय रोजगार की माँग करने लगा है। गढ़वाल मण्डल में आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तावित शराब की कई नई तथा पुरानी दुकानों के विरोध में जनता सड़कों पर उतर रही है। एक समय ये समूचा पर्वतीय क्षेत्र मद्यनिषेध क्षेत्र था। कहीं-कहीं शराब की दुकानें थीं। उस वक्त नशे के आदि लोगों ने शराब के अवैध उत्पादन को कुटीर उद्योग के रूप में अपना लिया था, जिसका रोष पूरे क्षेत्र में पनपा तथा महिलाओं ने जगह-जगह नशाविरोधी अभियान के द्वारा शराब भट्ठियों को उजाड़ दिया तथा जहाँ कहीं शराब बिकती थी, बन्द करा दी गई। समय बीतते-बीतते अब यह स्थिति है कि सरकार ने पहाड़ी क्षेत्र में चप्पे-चप्पे पर शराब की दुकानें खोल दी हैं। हाल ही में हुए देशी-विदेशी शराब के ठेकों के अवसर पर चम्बा, मसूरी, नागनी, पौढ़ी, रुद्रप्रयाग, जारकधार, गन्ना, धनोल्टी, चमियाला, उत्तरकाशी सहित राजधानी के भी कुछ इलाकों में शराब दुकानों के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। युवाओं तथा महिलाओं ने 'नशा नहीं, रोजगार दो' की माँग की। कई मार्गों पर कई-कई दिनों तक जाम लगाए गए तथा नई दुकानों को खुलने नहीं दिया। शराब के नशे से विमुख युवावर्ग रोजगार के अच्छे अवसरों की माँग कर रहा है।*

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 08/04/2005)

386) *भारत में अशिक्षित बच्चों की संख्या विश्व के अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक होने तथा 6 से 18 वर्ष के भारतीय बच्चों में से 50% के स्कूल न जाने की गम्भीर समस्या से निपटने के लिए मंगलवार को राजधानी में शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। समाज के विभिन्न क्षेत्रों की जानीमानी हस्तियों किरणबेदी और मंदिराबेदी की उपस्थिति में शुरु किए गए इस अभियान के तहत शिक्षा से वंचित गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रोक्टर एण्ड गैम्बल देश के शीर्ष बाल अधिकार संगठन 'चाइल्ड रिलीफ एण्ड यू' तथा सोनी एण्टरटेनमेन्ट टेलीविजन के सहयोग से यह अभियान चला रहा है।*

पी एण्ड जी के बिक्री एवं विपणन निदेशक चेस्टर ट्विग ने कहा कि पी एण्ड जी विश्वभर में बच्चों की सहायतार्थ वैश्विक अभियान 'पी एण्ड जी लिव लर्न एण्ड थ्राइव' चला रही है और शिक्षा उसी अभियान का एक हिस्सा है। शिक्षा अभियान में अपना सहयोग देते हुए विभिन्न क्षेत्रों की कई हस्तियों काजोल, मंदिराबेदी, परीजाद जोराबियन, पल्लवी जोशी, रेवती, कीर्ति रेड्डी, क्रिकेट कमेन्टेटर हर्ष भोगले, शिक्षाविद डा. स्नेहलता देशमुख और टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने बालशिक्षा के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता जताई।

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 06/04/2005)

387) राजशाही से लोकतन्त्र की ओर :- *भूटान निरंकुश राजशाही से दो दलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली की ओर कदम बढ़ाने की तैयारी में है। इस ऐतिहासिक बदलाव से पहले देश के सभी वयस्क नागरिकों की राय ली जाएगी। भूटान ने 34 सूत्रीय संविधान अपनाकर दो दलीय व्यवस्था की ओर बढ़ने का संकेत दिया है। इस प्रस्तावित संविधान में राजशाही, पुरोहितवर्ग और अन्य विभागों की सम्वैधानिक स्थिति का स्पष्ट उल्लेख है।*

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 29/03/2005)

388) गरीबों के लिए सपना : जनस्वास्थ्य सेवाएँ :- *जैसे-जैसे समय बीत रहा है, भारतीय संविधान और कानून व्यवस्था की कमजोर नसों का पता सबको हो गया है कि इतने महान देश का महान संविधान हर प्रकार के अपराधी को संसद में आने से नहीं रोक पा रहा। जब सरकार में सत्ताभोग के लिए कई पिछले दरवाजे खुले हैं, तो नेताओं को गरीबों के स्वास्थ्य की चिन्ता नहीं होना स्वाभाविक है। गरीबों को मौत के घाट सुलाने वाली टीबी, मलेरिया, कालाजार, कुष्ठ जैसी भयंकर बीमारियों पर अभी तक नियंत्रण नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि गरीबों के बच्चों की मृत्युदर में बढ़ोत्तरी जारी है। दुनियाभर के टीबी मरीजों की एक तिहाई संख्या भारत में है, जहाँ प्रतिवर्ष 5 लाख लोग इसके शिकार होकर दम तोड़ देते हैं। मलेरिया और कालाजार की स्थिति तो भयावह है ही। कुष्ठरोगियों की 60% संख्या अकेले भारत में है। जबकि यह रोग उतना असाध्य अथवा संक्रामक नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐड्स की नई जानलेवा बीमारी से भी इस आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबके को ही सबसे ज्यादा खतरा है। गरीब चाहें गाँव के हों या शहर के दोनों की नियति एक जैसी है। गरीबों के लिए पीने को शुद्ध पानी नसीब नहीं होता। अशुद्ध जल वैसे भी कई बीमारियों का कारण होता*

है। निजी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएँ गरीबों की पहुँच से काफी दूर हैं, क्योंकि निजी अस्पतालों के मालिक जनहित को गौण मानते हुए इसे व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं। जबकि सरकार का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से नौकरशाही और लालफीताशाही के चंगुल में फँसा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को जनस्वास्थ्यसेवाओं की उतनी चिन्ता नहीं होती। इनकी पगार और वेतन बढ़ोत्तरी हर स्थिति में सुरक्षित होती है। एक स्वस्थ समाज के लिए जरूरी है कि सरकार शुद्ध जल, वायु और रोगविहीन वातावरण की सुविधाएँ लोगों के लिए उपलब्ध कराए। और जब अमीरों और गरीबों के बीच बहुत बड़ी विषमता हो, आधी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहने को अभिशप्त हो, ऐसे भूखे और बीमार समाज में खुशहाली नहीं आ सकती। गरीबी के कारण गर्भवती महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और उससे जुड़ी बीमारियाँ, शिशुमृत्युदर में वृद्धि जैसी समस्याओं से मुक्ति दिलाना किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है। विकासशील देशों की सूची में भारत का नाम सबसे ज्यादा बीमार देशों में पहले नम्बर पर आ गया है।

-(लेख : राधेश्याम, आँखिनदेखी; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 22/03/2005)

389) ये जनता है, सब जानती है :- *आज हमारे देश में भ्रष्टाचार चरम पर है। भारत एशिया का चौथा भ्रष्टतम देश है। सरकारी महकमा और भ्रष्टाचार एक-दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। एक निजी समाचार चैनल ने बिक्रीकर विभाग ने 82 अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहयाई से रिश्वत लेते हुए टी.वी. पर दिखाया, जिनमें से मात्र 30 को निलम्बित किया गया है और 10 पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून लागू किया गया है। पूर्व के अनुभवों के आधार पर लगता है कि ये मामला भी समय के साथ ठण्डा हो जाएगा। राजस्व विभाग किस कदर भ्रष्टाचार में आकण्ठ डूबा है, यह जो एक नमूना है। यही हाल सभी सरकारी विभागों का है। कुछ दिन पहले आबकारी आयुक्त पी.के.अजवानी पाँच करोड़ रुपये की अवैध सम्पत्ति का पता चला। आज हालात इतने भयावह हैं कि देश का 90% सरकारी तन्त्र भ्रष्टाचार में लिप्त है। अधिकतर मामले सामने ही नहीं आते। आते भी हैं तो रिश्वत देकर रफा-दफा हो जाते हैं। भ्रष्टाचार की सीढ़ी हमेशा ऊपर से शुरु होती है- 'यथा राजा तथा प्रजा'। सफेदपोश लोग अन्दर से कितने काले हैं, यह सभी जानते हैं। इस देश के नेतागण सबसे अधिक भ्रष्ट हैं। जिस सरकार में दह काबीना मन्त्री ऐसे हों, जिन पर हत्या, अपहरण और घोटालों के गम्भीर आरोप हों और फरार घोषित हों, उसके शासन में भ्रष्टाचार और कुशासन की ही अपेक्षा की जा सकती है। यहाँ चार-पाँच सौ रुपये की रिश्वत लेने वाले पकड़े जाते हैं और सजा पाते हैं, लेकिन करोड़ों के घोटालेबाजों को मन्त्रीपद देकर सम्मानित किया जाता है। यही इस देश का दुर्भाग्य है। प्रभावशाली लोगों के कितने ऐसे मामले हैं, जो दबा दिए गए- बोफोर्सकाण्ड, हर्षदमेहता केस, सेंट किट्स मामला, चारा घोटाला, यूरिया घोटाला, ताबूत घोटाला, आदि। तेलगी केस का भी यही हश्र होना है, क्योंकि इसमें भी देश के प्रभावशाली लोगों का हाथ है। ये जनता है, सब जानती है, सब देखती है, फिर भी खामोश है। शायद ये तूफान से पहले की खामोशी है। हमें उम्मीद है, यह खामोशी जरूर टूटेगी।*

-(जगनोहन गौड़, महाराणाप्रतापबाग, नईदिल्ली; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 20/03/2005)

390) *राजनीति में इस हद तक गिरावट आने से राष्ट्र को संकट और विनाश का सामना कर सकता है। मुझे विश्वास है कि मुझे कुछ ऐसे कटु सत्य बोलने की अनुमति है, जिनसे हम सब परिचित हैं और जो एक तथ्य है पर हम उसे मानने से इन्कार करते हैं। हमारी चुनावप्रक्रिया काफी समय से घातक हिंसा के कठोर दबाव में रही है। आवश्यक संख्या की वीभत्सता और शायद संदेहास्पद और अलोकतान्त्रिक तरीकों से जीती हुई वैधानिक सीटों की कथित खरीद-फरोख्त बहुत बार जनता के सामने हमारी प्रजातान्त्रिक प्रणाली को शक के घेरे में खड़ा कर देती है। राजनीति जब स्वयं को राजनीतिक दुस्साहस तक गिरा देती है, तब राष्ट्र अवश्यंभावी संकट और विनाश की ओर जाने वाले अनर्थकारी मार्ग पर चल पड़ता है। हमें अपने देश को विनाश और अनर्थकारी मार्ग की ओर ढकेलने का जोखिम नहीं उठाना है। यही समय है, जब हम सभी मिलकर आत्मविश्लेषण करें और उन अपेक्षाओं पर खरे उतरें, जो हमारे संस्थापकों ने बहुत परिश्रम और उम्मीद के साथ स्थापित की थीं। ताकि भारत स्वयं को सँभाल सके और एक परिपक्व, स्वस्थ, जीवन्त और प्रजातान्त्रिक राष्ट्र के रूप में विकसित हो सके। हमारे 25 वर्ष से कम आयु के 54 करोड़ युवाओं को संसद सदस्यों में से ऐसे महान नेता ढूँढने चाहिए, जो उनके आदर्श नेता बन सकें, और अपने प्रत्येक कार्य से*

प्रगतिशील मिशन और राजनीति में सक्रिय परिवर्तन लाने में सक्षम हों। जनता भारतीय संस्कृति और विरासत को संरक्षित करके अपनी जीवनशैली में परिवर्तन लाने के लिए लालायित है। मान्य सांसद उचित कानून और नीतियाँ लागू कर सामाजिक परिवर्तन में सहयोग करके इनके चेहरों पर मुस्कान ला सकते हैं। अफसोस है कि हम ऐसी नीतियों और कार्यपद्धतियों को अपनाकर चल रहे हैं, जो बहुधा अविश्वास पर आधारित हैं। भारतीय जनता को जब भी अवसर और विश्वास का माहौल उत्पलब्ध कराया गया, उसने अनगिनत उपलब्धियाँ प्रदर्शित कीं। -(उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति के भाषण का अंश)

-(वक्तव्य : राष्ट्रपति ए.पी.जे.अब्दुलकलाम; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 22/03/2005)

391) *हम संयुक्तराष्ट्रसंघ के सदस्य देश कटिबद्ध हैं कि आने वाली नस्लों को युद्धों की विभीषिका से बचाया जाए, जिसने दो बार हमारे जीवनकाल में ही मानवजाति को अकथ पीड़ा में झोक दिया। हम प्रतिबद्धता प्रकट करते हैं, मानवाधिकारों के प्रति, मनुष्यमात्र की गरिमा के प्रति, स्त्री और पुरुषों के समान अधिकारों के प्रति, सब छोटे और बड़े राष्ट्रों के प्रति कि हम ऐसी स्थिति का निर्माण करना चाहते हैं, जिससे सब देशों को न्याय मिल सके और सब गरिमा से रह सकें।*

-(संयुक्तराष्ट्रसंघ के चार्टर का प्राक्कथन; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 14/03/2005)

392) गमलों पर उगे ये लोग :- *लोकशाही, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, संविधान, मर्यादा- ये शब्द बड़े अच्छे हैं। इनहें बोलना भी अच्छा लगता है और इन्हें सुनना भी आनन्ददायक है। हमारे देश के महान नेता अक्सर इन शब्दों का उपयोग करते पाए जाते हैं। संविधान सदन के अन्दर सांसदों और विधायकों को बहुत सी छूट तो प्रदान करता है परन्तु यह छूट किसी भी कीमत पर असभ्य आचरण की आश्रयदाता नहीं है। डाक्टर अम्बेडकर के शब्दों में- ''सांसदों या विधायकों के आचरण का प्रभाव पूरे जन-जन पर पड़ता है, क्योंकि वे जनता के प्रतिनिधि होते हैं। उन्हें कुछ रियायतें सदन के अन्दर इसलिए हैं कि मतैक्य न होने के बावजूद जनहित में वे अपनी बात दृढ़ता से रख सकें, निर्भय होकर रख सकें। लेकिन उनका कोई भी 'अमानवीय' आचरण किसी कीमत पर सम्वैधानिक करार नहीं दिया जा सकता।''*

विधायिका की सर्वोच्चता का प्रदर्शन इन्होंने दागियों को मन्त्री बनाकर कर दिया। जब सदन या विधानसभा के अन्दर माइक चलते हैं, अभद्र आचरण होता है, गाली-गलौज तक होता है, तो उस समय उन्हें अपनी सर्वोच्चता का ज्ञान नहीं होता। उत्तरप्रदेश, उड़ीसा, गुजरात क्या भूलूँ? क्या याद करूँ? मैंने पूर्व में भी लिखा था- ''राजनेताओं ने अपनी मर्यादा खो दी है। अतः सारे राष्ट्र में उनकी कोई इज्जत नहीं रही।''

चाहे आप लाल बत्ती लगाकर चलें या हरी बत्ती लगा लें या नीली अथवा सायरन की आवाज से सबको आतंकित कर दें, परन्तु बार-बार दौर का शायर यही कह रहा है- 'यह कैसी है त्रासदी, कैसा है संजोग। लाखों में बिकने लगे, दो कौड़ी के लोग।।'

जो लोग माननीय उच्च न्यायालयों के जजों तक की बदली इसलिए करवाना चाहते हैं कि करोड़ों, अरबों के घोटाले में उन्हें राहत मिल जाए। वो तो सर्वोच्च हैं और न्यायपालिका के अधिकारों का हनन करने की कोशिश हमारे देश के सभी राजनीतिज्ञ करने पर उतारू हैं। सचमुच शर्म की बात है। प्रजातन्त्र का एक स्तम्भ खण्ड-खण्ड होकर बिखर रहा है और वह कौन सा स्तम्भ है, क्या अब भी इसे समझाना होगा। यहाँ मैं आज ही मिला पटना के किसी रामलगनराम का भेजा पत्र छाप रहा हूँ। जरा उस व्यक्ति की व्यथा को जानें। पत्र अक्षरशः प्रकाशित कर रहा हूँ :-

''परम आदरणीय अश्विनी भइया,
जय राम जी की!

मैं आपका एक मामूली पाठक हूँ। बी.ए. पास हूँ, परन्तु होटल में बरतन माँझकर जीविका चलाता हूँ। बिहार में बूटासिंह का शासन लगा। हम सब खुश हैं। हमें आशा है कि अब सब अपराधी अन्दर हो जाएँगे। हाई कोर्ट ने कहा है- 20 हजार गुण्डों को अन्दर करो। यहाँ के सब गुण्डे नेताओं ने पाले हैं। थोड़े दिन राष्ट्रपति शासन लगा रहे, इसका प्रचार कीजिए, माँ-बहनों की इज्जत बचाइये! सब नेता बेईमान हैं। फिर जोड़-तोड़ हो रहा है। 5 साल तक बूटासिंह रहने चाहिए। बिहार में राष्ट्रपति शासन अगर जरूरत पड़े तो 10 वर्ष तक लागू रहे। यही बिहार के हित में है। चिठ्ठी लिखने का खास कारण यह है कि यहाँ सारी

जानरक्षक दवाइयाँ भी जाली (नकली) बिकती हैं। 90 प्रतिशत दवाइयाँ दो नम्बर की हैं। ये अलीगढ़ से आती हैं। नेता जबरदस्ती बिकवाते हैं। गवर्नर से कहें गरीबों को मरने से बचाएँ। सरकार न बनने दें।
रामलगनराम,
भिखना पहाड़ी, पटना, बिहार।''

इस पत्र की आत्मा को देखें। नारी गरिमा को बचाना है और बेमौत मरने से बचना है, तो राष्ट्रपति शासन चाहिए। नकली दवाइयों से रक्षा कीजिए। प्रजातन्त्र की यह आवाज नेताओं के मुँह पर झन्नाटेदार तमाचा है। इसकी गूँज उन्हें बर्दाश्त करनी ही होगी। अपने मुँह मियाँ मिठ्ठू बनने से क्या होगा ?
-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 17/03/2005)

393) 22 प्रदेशों के काँग्रेसियों में घमासान : सूबेदारों में आलाकमान का भय घूमंतर : जनाधार वाले नेताओं को अपमानित करने का आरोप : सर्वत्र विद्रोह की चिन्गारियाँ : कहीं प्रचण्ड जीत के कारण फूट, कहीं हार से शर्मसारी के कारण फूट :- *काँग्रेस शासित 10 प्रदेशों में पार्टी में विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा है। इसके अलावा 12 दूसरे राज्यों में काँग्रेस में आन्तरिक विद्रोह से घमासान मचा है।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 16/03/2005)***

394) हवाई अड्डे का नामपरिवर्तन : एन.टी.आर. से बदलकर राजीवगाँधी रखे जाने पर संसद में भारी हंगामा :- *हैदराबाद अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम राजीवगाँधी के नाम पर रखने के सरकार के फैसले का विरोध करते हुए विपक्ष ने जहाँ लोकसभा से वाकआउट किया, वहीं राज्यसभा की बैठक जबरदस्त हंगामें के कारण कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान तेलुगूदेशम के येरन नायडू ने यह मामला उठाते हुए कहा कि हैदराबाद हवाई अड्डे का नाम पहले से ही स्वर्गीय एन.टी.रामाराव के नाम पर है और उनकी जगह राजीवगाँधी का नाम रखना न सिर्फ रामाराव का बल्कि आन्ध्रा की तेलुगूभाषी जनता का भी अपमान है। नेता सदन एवं रक्षा मन्त्री प्रणव मुखर्जी ने इस आरोप के जवाब में कहा कि हैदराबाद हवाई अड्डे का नाम पहले राजीवगाँधी हवाई अड्डा था, जिसके कुछ हिस्से को बाद में बदलकर एन.टी.रामाराव हवाई अड्डा कर दिया गया। तब से इसका एक हिस्सा एन.टी.आर. और दूसरा हिस्सा राजीवगाँधी हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। लेकिन विपक्षी सदस्य सन्तुष्ट नहीं हुए और जबरदस्त हंगामें के बीच उच्च सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 16/03/2005)***

394) विश्व शान्ति :- *संयुक्तराष्ट्रसंघ की जनरल असेम्बली के 29वें सत्र अर्थात् 1971 में इस बात पर गहन विचार किया गया कि परमाणु हथियारों से कम खतरा जैविक और रासायनिक हथियारों का नहीं है। 10 अप्रैल 1972 को अमरीका, रूस और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों तथा अन्य 44 देशों के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता हुआ कि ये देश इस दिशा में अपने कदम नहीं बढ़ाएँगे। अमरीका, रूस दोनों ही निर्णय लिया कि युद्ध की स्थिति में भी मिसाइलों का उपयोग नहीं किया जाएगा और परम्परागत हथियारों से ही दोनों देश युद्ध करेंगे। राष्ट्रसंघ की जनरल असेम्बली का निःशस्त्रीकरण पर विशेष सत्र 23 मई 1978 को हुआ। इसमें मुख्य मुद्दा था कि करीब-करीब सारे विश्व के देश जो परमाणु हथियारों का निर्माण करते हैं, उनका खर्च 100 मिलियन डालर आता है, जो कि बेकार चला जाता है, जिससे विकास नहीं होता। विनाश के हथियारों का निर्माण करके विकास की कल्पना करना महामूर्खता है। अतः इस ओर सार्थक कदम उठाए जाने चाहिए। निस्सन्देह इस मद में बड़ी रकम खर्च तो सोवियत संघ और अमरीका की ही हो रही थी। इसके बाद चीन फ्रांस और जर्मनी का स्थान था। ब्रिटेन भी अमरीका से कदम मिलाकर चल रहा था। एक अनुमान के अनुसार हिरोशिमा और नागासाकी में जैसा बम गिराया गया था, वैसे 13 लाख बम इन देशों के पास मौजूद थे। यानि जितनी बर्बादी उन दोनों बमों से हुई थी, उनसे 13 लाख गुना अधिक बर्बादी का सामान इन देशों ने इकठ्ठा कर लिया था। महासभा को सम्बोधित करते हुए संयुक्तराष्ट्र के तत्कालीन महासचिव डा.कुर्तवाल्दहिम ने कहा- ''आज हम उस त्रासदी पर बहस करने के लिए इकठ्ठा हुए हैं, जिससे विश्वमानवता को सबसे ज्यादा खतरा है।'' यूगोस्लाविया के श्री लेजर मैजसोव ने कहा- ''इन शस्त्रों पर जितना खर्च होता है, वह तो सारे देश मिलकर शिक्षा पर भी नहीं करते।'' सोवियत संघ के विदेशमन्त्री एव्द्रे ए ग्रोमयको बोले- ''आज हमारे सामने दो ही विकल्प हैं- या तो सारे विश्व में आर्थिक उन्नति की जाए या खुद को परमाणु*

प्रलय में झोंक दें।'' पाँच हफ्तों तक ये विशेष सत्र चला और लम्बे विचारविमर्श के बाद विश्व के 149 देशों ने मिलकर यह फैसला किया कि सारे विश्व के देशों का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि वह अपने मुल्कों को परमाणु अभिशाप से बचाएँ। ऐसे में सम्मिलित रूप से सारे देशों ने मिलकर यह फैसला लिया– फौजी बजट को यथासंभव कम किया जाएगा। गरीबों के उत्थान के लिए कदम उठाए जाएँगे। बड़ी शक्तियाँ अपना परमाणु परीक्षण बन्द कर देंगी। हथियारों को विनष्ट करने की प्रक्रिया शुरु कर दी जाएगी। एक निःशस्त्रीकरण परिषद का भी गठन किया जाएगा।

अगर एकमात्र उपर्युक्त समझौते को ही लागू करने का संकल्प सारा विश्व ले लेता, तो क्या फिर कुछ भी समस्या कभी होती? लेकिन आज तक होता यही रहा है कि ऐसे समझौते हो तो जाते हैं परन्तु उन्हें लागू करने का दायित्व तो छोटे देशों पर नहीं जाता। वे तो वैसे ही अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं। एक तरफ परमाणु हथियार बढ़ते चले गए, दूसरी तरफ सन्धियों की संख्या बढ़ती रही। निःशस्त्रीकरण की दिशा में जितनी सन्धियाँ हुईं, उतनी और किसी दिशा में नहीं हुईं।

-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 15/03/2005)

396) उत्तरांचल में भ्रष्टाचार ने लाँघीं सभी सीमाएँ:- *नवसृजित उत्तरांचल राज्य में भ्रष्टाचार सारी सीमाएँ लाँघ चुका है। नासूर बनता जा रहा यह भ्रष्टाचार हर तरफ राज्य को चोट पहुँचा रहा है तथा राज्य की तरक्की में व्यवधान व अड़चनें डालकर विकास को रोक रहा है। बड़े–बड़े घोटालों एवं भ्रष्टाचार को राजनेता और अधिकारी मिलकर अंजाम दे रहे हैं। इनके गैरजिम्मेदाराना रवैये से वाकिफ समाजसेवी संगठनों का दिल भी इस ओर बेखौफ बढ़ता गया। समाज में विकास के नाम पर अधिकारी व राजनेता अपना ही विकास करने में लगे हैं। उत्तरांचल में नानगवर्नमेन्टल आर्गनाइजेशन (एन.जी.ओ.) की भरमार है, जिनमें से अधिकांश आर्गनाइजेशन भ्रष्ट एवं पेशेवर मानसिकता वाले लोगों द्वारा संचालित हैं, जो भ्रष्टाचारी अधिकारियों से मिलकर ऐड और फण्ड का फायदा उठाकर समाज के विकास में सबसे बड़े बाधक बन रहे हैं।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 15/03/2005)***

397) शोषण के खिलाफ व्यापक विरोध की जरूरत :- *देहरादून प्रेस क्लब में भारतीय शोषित समाज विकास परिषद द्वारा शोषित समाज में क्षमताएँ एवं चुनौतियों पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि परिषद के उत्तरांचल प्रभारी एवं जिला जज श्री चतुर्भुज ने कहा कि शोषण के खिलाफ व्यापक स्तर पर विरोध किए जाने की आवश्यकता है, तभी हम शोषण को रोक पाने में सफल होंगे। उन्होंने शोषण को रोकने के लिए निःशुल्क न्याय की प्रक्रिया अपनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि हम लोगों को शोषित शब्द का अर्थ समझने की जरूरत है। आज समाज में शोषण किसी एक वर्ग का नहीं, बल्कि सभी वर्गों का हो रहा है। ज्यादातर शिकार महिलाएँ हो रही हैं। दहेज, पारिवारिक झगड़े आदि किसी न किसी रूप में महिला का शोषण हो रहा है। हमें शोषण के बीज को समाप्त करना होगा। आज नारी ही नारी का शोषण करने पर तुली हुई है। प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। शोषण से हर नागरिक त्रस्त है। महिलाओं में ज्ञानवर्धन कर उनको जागरूक किया जाए, ताकि वे अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का सामना कर सकें।*

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 14/03/2005)

398) सचमुच अद्‌भुत तन्त्र है अपना ये गणतन्त्र :- *'फर्स्ट डिजर्व दैन डिजायर'– पहले योग्य बनो तब इच्छा करो। अपवादों की बात नहीं करता वरना आज विधायिका से जुड़े लोग जब मर्यादा की बात करते हैं, तो बड़े ओछे लगते हैं। आज सारा राष्ट्र देख रहा है कि उस वक्त इन्हें मर्यादा नजर नहीं आती, जब–*

- *अपराधियों को टिकट देते हैं।*
- *काले धन से चुनाव लड़ते हैं।*
- *दुर्दान्त आतंकवादियों से साँठ–गाँठ करते हैं।*
- *विधायकों और सांसदों की खरीद–फरोख्त करते हैं।*
- *घोटाले करते हैं और दंगे करवाते हैं।*
- *हर जुल्म की जड़ें अपने हाथ में रखते हैं।*
- *सारी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देते हैं।*
- *दो–दो पैसों के लिए ईमान बेचते हैं।*

कैसी मर्यादा? कौन सी मर्यादा? किसकी मर्यादा? इन नेताओं के पावन चरित्र की जो फाइलें मेरे पास हैं, अगर एक-एक कर प्रकाशित करना शुरु कर दूँ, तो शायद चारों ओर से त्राहिमाम की आवाजें आने लगें। सारे राष्ट्र का बुद्धिजीवी समाज भी यह जानता है कि आज की विधायिका ने तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन तक की कोशिश की। परन्तु न्यायपालिका ने यह संभव न होने दिया। आज मैं भारत के समस्त नागरिकों से यक्षप्रश्न की तरह वर्तमान में एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, जो आज की विधायिका के चरित्र की बेबाक गवाही देता है- ''माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर जब चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए शैक्षणिक योग्यता, चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा और आपराधिक पृष्ठभूमि का विवरण देना अनिवार्य कर दिया, तो ये सारे के सारे नेता, चाहे वह किसी भी पार्टी के थे, 'हम पंक्षी एक डाल के' वाली मुद्रा में सुप्रीम कोर्ट पर छींटे कसने लगे और इसके विरुद्ध कानून बनाने पर उतारु बनाने पर उतारु हो गए। ये हमसे सूचना का अधिकार छीनना चाहते थे। तथापि कानून तो न बन सका, परन्तु ये राजनेता नंगे हो गए, क्योंकि ये मूर्खों और कालाधन के चैंपियनों और दुर्दान्त अपराधियों के संरक्षक की भूमिका निभा रहे थे।''

आज भारतवर्ष में कोई कवि सम्मेलन तब तक सम्पन्न नहीं होता, जब तक इन नेताओं को श्रद्धा सुमन न अर्पित कर ले। जरा निम्नलिखित कवियों की बानगी देखिए। 'नीरज' कहते हैं :-

सचमुच अद्भुत तन्त्र है, अपना ये गणतन्त्र।
सन्त पड़े हैं जेल में, डाकू सभी स्वतन्त्र॥

यादराम शर्मा लिखते हैं :-

सत्तारानी खेलती, कैसे-कैसे खेल।
कुर्सीहित में बेवला, करे साँप से मेल॥

सैकड़ों कवि हैं और कविताओं का एक ही इशारा है- राजनीति की सड़ांधता।

-(अश्विनीकुमार, विशेषसम्पादकीय; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 13/03/2005)

399) चार सदस्यीय परिवार की दर्दनाक मौत :- *आर्थिक तंगी के चलते एक व्यवसायी ने अपने दोनों बच्चों की हत्या कर पत्नी सहित फाँसी लगा ली। यह दर्दनाक हादसा दक्षिण-पश्चिम जिले के द्वारका क्षेत्र में हुआ। मृतकों में राजकमल खुराना (40 वर्ष), रंजीता खुराना (35 वर्ष), अभिषेक (8 वर्ष) और अस्मिता (5 वर्ष) शामिल हैं। बताया जाता है कि राजकमल ने पहले तो दोनों बच्चों को जहर देकर मार डाला। उसके बाद अपनी पत्नी सहित फाँसी लगा ली।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 10/03/2005)***

400) *क्यूओ वाडीस? ये दोनों शब्द लैटिन हैं। इसका अर्थ है- आप कहाँ जाते हैं? ये शब्द मेरे दिमाग में चक्कर लगाते रहे, जब मैंने यह खबर पढ़ी कि गोवा में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बर्खास्त कर दी गई है। राज्य के एक दर्जन से अधिक विधायकों को ऐसी जगहों पर भेज दिया गया है, जहाँ उनको रिश्वत न दी जा सके या किसी एक पार्टी या दूसरी को समर्थन के लिए जबरजस्ती न की जा सके। ऐसी ही घटनाएँ पंजाब और हरियाणा में हो चुकी हैं। यही कुछ अब बिहार और झारखण्ड में हो रहा है। मैंने संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही भी देखी और शोर-शराबा, नारेबाजी और अध्यक्ष द्वारा अगले दिन तक बहस मुल्तवी किए जाने की बात भी देखी। यही चीज अगले दिन और उससे अगले दिन भी हुई। इसलिए मैं अपने आप से बराबर पूछता रहा और अपने पाठकों से पूछता हूँ कि वे इस सवाल पर गौर करें कि- ''हम कहाँ जा रहे हैं?'' साथ ही अपने आप से पूछें कि- ''क्या कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, जिसे हम राजनीतिक शुद्धता के आदर्श माडल के रूप में देख सकें।'' हमें अपने नेताओं से भी पूछने का पूरा हक है कि- ''आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं?''*

-(खुशवन्त सिंह, सुप्रसिद्ध पत्रकार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 12/03/2005)

401) अन्तर्राष्ट्रीय महिलादिवस पर विशेषलेख :- *आज की नारी ने अपने ऊपर खिलाफ अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी शुरु कर दी है। महिलाओं के खिलाफ पिछले तीन वर्षों में अपराध की सर्वाधिक घटनाएँ 20865 मध्यप्रदेश में हुईं। पंजाब में आबादी 19.76% की दर से बढ़ रही है, इसके बावजूद राज्य में 28000 से अधिक बेटियों को प्रतिवर्ष जन्म लेने से वंचित किया जा रहा है। एक अरब से अधिक की जनसंख्या वाले हमारे देश में अनुमानतः 9 लाख सैक्स वर्कस में 30% से अधिक नाबालिग लड़कियाँ बतायी जाती हैं। इस संख्या में हर वर्ष 8% से 10% की वृद्धि हो रही है। नारी को समाज के स्टीलफ्रेम चौखटे में बैठने के लिए कितना-कितना कटना-छँटना पड़ता है, इसका अनुभव नारी ही कर सकती है। दुनिया के लगभग सभी विकासशील देशों में बच्चियों तथा औरतों के प्रति हिंसा को आज एक तरह की मूक सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है। आज सरकारी घोषणाओं में कानूनी अधिकारों की दृष्टि से स्त्री को पुरुष के बराबर अधिकार कहें जाते हैं। फिर भी व्यवहार की तलहटी पर स्त्री को पुरुष के बराबर बैठने का अधिकार कहाँ है। विधवा के लिए जहाँ शादी का नाम लेना पाप था, वहीं विधुर के लिए शादी समाज में जरूरी बताई गई। इतने अत्याचारों के बावजूद हमारे देश की महिलाओं का हौंसला मजबूत है।* ***-(अमिता अग्रवाल; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 05/03/2005)***

402) धर्म परिवर्तन के नाम पर धोखा :- *अपनी बात कहने के लिए मैं बिना कोई भूमिका बाँधे धर्मपरिवर्तन और दलित ईसाइयों की मौजूदा स्थिति को केन्द्रबिन्दु में रखकर अपने विचारों को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ताकि आप यह जान पाएँ कि किस तरह इस धर्मान्तरण के युद्ध में कुछ स्वार्थी लोग दलित ईसाइयों एवं वंचित वर्गों को अपने लाभ के लिए एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। धर्मपरिवर्तन के नाम पर चर्चनेतृत्व ने दलित वर्गों के साथ विश्वासघात किया है। बड़ी आसानी से ईसाइयत की शरण में आने वालों में ज्यादा संख्या वंचित वर्गों की ही रही। वर्तमान में दलित गरीब ईसाइयों की स्थिति को देखकर सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रोटेस्टेन्ट और कैथोलिक दोनों ही चर्चों ने दलितों को धर्मपरिवर्तन के स्वार्थ के परे कभी देखा ही नहीं। दलितों की मुक्ति में चर्चनेतृत्व की कोई रुचि नहीं रही। उत्पीड़न, रोजमर्रा का संघर्ष, जातिवाद, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय की तलाश और चर्चढाँचे में अपने अधिकारों को पाने हेतु उनका संघर्ष- इनमें से किसी भी मुद्दे पर चर्चनेतृत्व की कोई रुचि नहीं है। यहाँ तक कि चर्चनेतृत्व ईसाइयत के अन्दर ही जातिवाद को समाप्त नहीं कर पाया है। इससे यह बात साफ होती है कि वंचित समूहों के लोग चाहें वे दलित, पिछड़े, अछूत या अन्य धर्मान्तरित ईसाई हों, वे धर्मान्तरित होने पर भी अपनी मौजूदा स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं ला पाते हैं। आज सबसे दयनीय अवस्था धर्मान्तरित दलित ईसाई की है। पूरी तरह से दरिद्र और साधनहीन। ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित दलित ईसाई भुखमरी के कगार पर हैं। दरिद्रता और साधनहीनता उन्हें कुछ सोचने का अवसर भी नहीं दे रही है। धर्मान्तरित दलितों को ईसाइयत अपनाते हुए यह विश्वास रहा कि ईसाइयत जैसा संगठित धर्म उनकी सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और उनमें जनचेतना लाकर क्रान्तिकारी स्थिति पैदा कर सकता है। किन्तु उनमें उनके अधिकारों के प्रति जनचेतना पैदा करने की जगह चर्चनेतृत्व उन पर आध्यात्मिकता का लेप लगाकर, ध र्म की थपकियाँ देकर उन्हें सुलाने में लगा हुआ है, क्योंकि वे जानते हैं कि हताश और मायूस हो चुके इन लोगों के पास उनकी बात मानने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं बचा है।*

-(आर.एल.फ्रांसिस; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 23/08/2004)

403) अध्यापिकाओं द्वारा उत्पीड़न के बाद लापता हुई छात्रा का शव बरामद :- *ग्यारह दिन पूर्व अध्यापिकाओं के कथित उत्पीड़न के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मिशनरी द्वारा संचालित स्कूल से लापता हुई 13 वर्षीय छात्रा नेहा का शव आज प्रातः नगर के समीप ही नहर के दाएँ किनारे से बरामद हो गया। छात्रा के शव की बरामदगी के बाद से नगर में तनाव बना हुआ है। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए संवेदनशील स्थानों पर भारी संख्या में पुलिस एवं पीएसी बल तैनात कर दिया है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की ओर से स्कूल के प्रधानाचार्य समेत दो अध्यापिकाओं के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली है।*

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 08/03/2005)

404) पिता को सत्ता से बेदखल करने की योजना बना रहा था उदय :- *ईराक पर अमरीकी सेना के हमले से कुछ ही समय पहले राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का बड़ा बेटा उदय अपने पिता को शासन से बेदखल करने और सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेने की योजना बना रहा था। पत्रकार पीटर अर्नेट ने प्लेब्वाय पत्रिका में लिखा है कि उदय हुसैन अपनी बेरहमी और भड़कीले जीवन जीने के लिए जाना जाता था। पत्रिका के अप्रैल अंक के अनुसार उदय ने अपने पिता को पैंतीस वर्ष के शासन से बेदखल करने के लिए फियादीन लड़कों के नेता का समर्थन हासिल कर लिया था। रिपोर्ट के अनुसार बगदाद के बाहर उदय ने अपनी इच्छा वाली वैकल्पिक सरकार बना ली थी।* **-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 04/03/2005)**

405) काम के बदले अनाज के लिए 11 हजार करोड़ रुपये :- *संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (संप्रग) के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुरूप अगले बजट में काम के बदले अनाज योजना के लिए धन आबंटन में भारी वृद्धि की गई है। विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार के अवसर पैदा करना है।*
-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 01/03/2005)

406) स्वस्थ लोकतन्त्र में राजनीतिक वंशवाद को कोई जगह नहीं :- *पूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरागाँधी के पौत्र और संजयगाँधी के पुत्र वरुण गाँधी का कहना है कि राजनीतिक वंशवाद भारत के संघीय ढाँचे को पीछे ढकेल रहा है और स्वस्थ प्रजातन्त्र में इसका कोई स्थान नहीं है। नेहरू-गाँधी परिवार से जुड़े और मेनका गाँध ी के पुत्र वरुण ने भाजपा टुडे को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा कि राजनीतिक वंशवाद देश के संघीय ढाँचे को पीछे ढकेल रहा है। इसका स्वस्थ प्रजातन्त्र की गतिविधियों में कोई स्थान नहीं है। लेकिन भारत में इसे मान्यता मिली हुई है, चाहे वह व्यापार, फिल्म और कला हो या फिर अन्य कोई पेशा हो, यह कमी वहाँ भी पाई जाती है। वंशवाद की राजनीति को समाप्त करने के लिए युवाओं में बेहतर शिक्षा एवं अवसरों के जरिए आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा।* **-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 02/03/2005)**

407) *गोवा सरकार की भाँति लगभग 3 साल पहले महाराष्ट्र की विलासरावदेशमुख सरकार के समक्ष इसीप्रकार का संकट आया था और उसे अपने विधायकों को सत्ता में होते हुए भी विपक्ष की खरीद-फरोख्त से बचाने के लिए बंगलौर लेकर भागना पड़ा था। बंगलौर में काँग्रेसी विधायकों ने खूब ऐश की, लेकिन गोवा की रंगीनियों में रहने वाले इन विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने कैदियों की तरह रखा है। गोवा में 28 फरवरी को शक्तिपरीक्षण होना है। भाजपा गोवा के अपने विधायकों को खरीद-फरोख्त से बचाने के लिए उन्हें जयपुर ले गयी। इन विधायकों को प्रमोद महाजन की स्वप्न नगरी पंचतारांकित केशवसृष्टि में रखा गया। गोवा जैसा संकट जब महाराष्ट्र की विलासराव सरकार को तीन साल पहले देखना पड़ा था, तब उनके संकटमोचक पूर्व गृहराज्य मन्त्री कृपाशंकरसिंह दो निजी विमानों में काँग्रेस के विधायकों को बंगलौर लेकर उड़ गए। तब इन विधायकों को संजय खान के खूबसूरत एवं अन्तर्राष्ट्रीय सुविधाओं वाले हिल्टन रिजोर्ट में रखा गया। काँग्रेसी विधायकों ने भापस्नान से लेकर ऊँटनी के दूध से क्लियोपैट्रा बाथ का आनन्द भी लिया था। भाँति-भाँति के मसाज करवाकर हफ्ते भर में काँग्रेसी विधायकों ने अपने स्वास्थ्य को चाक-चौबन्द कर लिया था। क्लियोपैट्रा बाथ का एक बार में प्रतिव्यक्ति लगभग 10 हजार रुपये खर्च आता है, क्योंकि इस बाथ में पूरा टब दुर्लभ हो चुके ऊँटनी के दूध से भरा जाता है और तरह-तरह के इत्र डालकर इसे सुगन्धि ात किया जाता है। इतना ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय सुविधाओं के मापदण्ड के अनुसार ऊँटनी के दूध से नहलाने के लिए प्रशिक्षित एवं खूबसूरत सेविकाएँ आकर्षक परिधानों में जो होटल के मेहमानों को ऊँटनी के दूध से नहाने में मदद करती हैं। क्लियोपैट्रा बाथ में ऊँटनी के दूध के स्टीम से भी बाथ लिया जाता है। क्लियोपैट्रा बाथ के अलावा रसियन, तुर्किस, स्वीडिश एवं एक्यूप्रेशर प्रशिक्षित अन्तर्राष्ट्रीय सेविकाओं से मसाज करवाकर लौटे महाराष्ट्र के काँग्रेसी विधायकों ने विलासराव सरकार को शक्तिपरीक्षण में बचा लिया था।*
-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 26/02/2005)

408) सबके उदय पर ही भारत उदय :- *आर्थिक उदारीकरण को मानवीय चेहरा देने, गरीबी को पूरी तरह दूर करते हुए सबको आर्थिक तरक्की में भागीदार बनाने, गाँवों की तस्वीर बदलने, सरकार को जनता के करीब लाने और हाशिए पर खड़े लोगों के प्रति राष्ट्रपति डा.ए.पी.जे.अब्दुलकलाम ने संप्रग सरकार की वचनबद्धता प्रकट की। डाक्टर कलाम ने बजटसत्र के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार भारत उदय चाहती है। लेकिन यह उदय सभी के लिए हो। जब तक ग्रामीण भारत में रहने वाले हमारे नागरिक खासतौर पर छोटे किसान और कमजोर वर्ग आर्थिक और सामाजिक तौर पर सशक्त नहीं होते, भारत उदय नहीं हो सकता। इन शब्दों को पूर्ववर्ती राजग सरकार पर कटाक्ष माना जा रहा है। गाँव की सामाजिक, आर्थिक पुनर्रचना को अपने सम्बोधन का केन्द्र बनाते हुए डाक्टर कलाम ने ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण की बृहद योजना 'भारत निर्माण' लागू करने का सरकार का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत गाँवों में बसता है, यह एक सच्चाई है, जिसे याद रखना होगा।*

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 26/02/2005)

409) हा! हा! भारत दुर्दशा .... :- *भारत के तत्कालीन नेताओं की सबसे बड़ी भूल यह हुई कि उन्होंने भारत को अँग्रेजों से आजाद कराना तो एक लक्ष्य रखा किन्तु यह सोचने की जहमत नहीं उठाई कि जब अँग्रेज चले जाएँगे, तो भारत में किस तरह का संविधान निर्मित करेंगे, जो राष्ट्र के हित में हो। भारत का संविधान और भारतीयता का संविधान। अँग्रेजों ने नेहरू को भारत का भाग्यविधाता बना दिया। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि 'भारत शासन अधिनियम 1935' को ही संविधान का मुख्य आधार बना दिया गया और जो भी महापुरुष इस कार्य में जुटे उन्हें स्वतन्त्र रूप से कार्य ही नहीं करने दिया गया। अँग्रेजों को भगाकर अँग्रेजों का ही संविधान लिखकर भारत में लागू कर दिया गया। जब यह सवाल उठा कि भविष्य में लोग यही कहेंगे कि यह तो भारत शासन अधिनियम 1935 का ही परिवर्तित रूप है, अतः इससे बचने का उपाय भी किया जाना चाहिए। भारत का आम आदमी इन बातों से पूर्णतः अपरिचित था। उसे क्या पता था कि हमारे ये भाग्यविधाता क्या कर रहे हैं। भारत के लोगों से बड़ा गंभीर मजाक (धोखा) किया गया। अँग्रेजों द्वारा बनाए गए भारत शासन अधिनियम 1935 पर ही कुछ दूसरे देशों की भी बातें निम्न प्रकार से मढ़ दी गईं :-*

- ⇨ *संघीय शासन व्यवस्था : कनाडा के संविधान से।*
- ⇨ *मौलिक अधिकार : अमरीका के संविधान से।*
- ⇨ *प्रस्तावना : आस्ट्रेलिया के संविधान से।*
- ⇨ *संसदात्मक शासनपद्धति : इंग्लैण्ड के संविधान से।*
- ⇨ *राष्ट्रपति निर्वाचनमण्डल : आयरलैण्ड के संविधान से।*
- ⇨ *एमर्जेन्सी : आयरलैण्ड के संविधान से।*
- ⇨ *विधिनिर्माण प्रक्रिया : इंग्लैण्ड के संविधान से।*
- ⇨ *समवर्ती सूची : आस्ट्रेलिया के संविधान से।*
- ⇨ *एकल नागरिकता : इंग्लैण्ड के संविधान से।*
- ⇨ *नीति निर्देशक तत्त्व : आयरलैण्ड के संविधान से।*

भारत के संविधान में कुछ भी अपना न था। कहीं भी भारतीयता की कोई छाप न थी। चाटुकारों और चमचों ने इस संविधान की प्रशस्ति में कसीदे पढ़-पढ़कर आसमान शिर पर उठा लिया, पर बाबासाहब ने स्पष्ट कहा था- ''जिस संविधान का आधार केवल राजनीतिक लोकतन्त्र हो, सामाजिक लोकतन्त्र नहीं, वह संविधान अवश्य एक दिन नष्ट हो जाएगा।'' यही कारण था कि 2 सितम्बर 1953 को जब बाबासाहब की आत्मा उद्वेलित हुई तो उन्होंने गरजते हुए कहा- ''मेरा वश चले तो मैं पहला व्यक्ति होऊँ, जो इस संविधान को भस्मीभूत कर दूँ।'' मैं कई बार इस बात को लिख चुका हूँ। मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। संविधान तो राष्ट्र को चलाने की व्यवस्था मात्र है। किन्तु भारत में अजीब सी मानसिकता हो गई है, संविधान राष्ट्र को समर्पित नहीं हुआ बल्कि राष्ट्र ही संविधान को समर्पित हो गया है।

आज मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा, राष्ट्र के लोगों को आगाह कर रहा हूँ। बिहार की विधानसभा में चाहे सरकार किसी की भी बने, कल को सौ से भी अधिक ऐसे-ऐसे अपराधी गुण्डे और हिस्ट्रीशीटर बिहार विधानसभा में घुस जाएँगे, जिन्हें साधारण स्थिति में कोई भी सरकार सूली में लटका देती। नपुंसकों के इस देश में इस संविधान को शिर पर उठाकर हम पूजते रहें, इससे क्या फर्क पड़ेगा। सब तो स्वार्थ में अन्धे हैं। कैसे बचे भारत इस दुर्दशा से ? ***-(अश्विनीकुमार, विशेषसम्पादकीय; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 26/02/2005)***

410) रणवीर सेना माओवादियों को लगा रही है ठिकाने :- भारत में जमींदारों की निजी सेना है– रणवीर सेना। उसी तरह नेपाल की रणवीर सेना भी माओवादियों को ठिकाने लगाने में लगी हुई है। अभी तक भारतीय रणवीर सेना की इस नेपाली शाखा के हाथों कई माओवादी मारे जा चुके हैं। जिस तरह बिहार में रणवीर सेना माओवादियों से टक्कर ले रही है, उसी तरह नेपाल के तराई इलाके में रणवीर सेना के सदस्य माओवादियों से लोहा लेने में लगे हैं। कपिलवस्तु जिले में माओवादियों और रणवीर सेना के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। नेपाली रणवीर सेना की स्थापना इसलिए हुई क्योंकि ग्रामीण इलाके के लोग माओवादियों कों रंगदारी टैक्स देते थक चुके थे। माओवादियों से आजिज आकर जमींदारों ने यह संगठन खड़ा किया। **-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 25/02/2005)**

411) कोई अमीर, कोई गरीब, कोई अज्ञ, कोई विज्ञ बनकर रहे और इस दुनिया में विषमता फैले यह अव्यवस्था ईश्वर को अभीष्ठ नहीं है। वह अपने सभी मानवपुत्रों को लगभग एक ही स्तर का निर्वाह करते हुए, समता को अपनाकर चलते हुए, देखना चाहता है। दूसरों की तुलना में अधिक विलासी और संग्रही होकर जीना स्पष्टतः जीवनोद्देश्य से विपरीत मार्ग पर चलना है।

-(श्रीरामशर्मा आचार्य, 'समय की माँग : घुमते अंश' पुस्तिका से)

पूर्वी लोकतान्त्रिक गणराज्य काँगो में दिसम्बर और जनवरी में हुई लड़ाई में 100 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और 200 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। संयुक्तराष्ट्र मिशन के मानवाधिकार जाँचदल ने पाया कि नियमित सेना के जवान, पूर्व सैनिक और स्थानीय मिलीशिया लड़ाके, इलाके में हुई हत्याओं और दमन के लिए जिम्मेदार हैं। वहाँ पर नागरिकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हुई ज्यादतियों की खबरें हैं। सशस्त्र हमलों और लूट-पाट की घटनाएँ बढ़ी हैं। महिलाओं को डराने-धमकाने के लिए बलात्कार का सहारा लिया जा रहा है। सामूहिक हत्याएँ की गई हैं। **-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 25/02/2005)**

412) मठ एक शंकराचार्य अनेक : ऐसे हैं धर्मगुरु :- भारतवर्ष के उत्तर में स्थित ज्योतिष्पीठ अथवा ज्योतिर्मठ पर कब्जे व इस मठ का शंकराचार्य स्वयं को बताने में तीन शंकराचार्यों वासुदेवानन्द, स्वरूपानन्द एवं माधवाश्रम के बीच कई दशकों से शीतयुद्ध जारी है। कई बार यह युद्ध कानूनी जंग के रूप में कोर्ट-कचहरी में भी लड़ा जा रहा है। मठों के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट भी हो चुकी है। एक ही स्थान पर तीन मठ और तीन शंकराचार्य प्रतिष्ठित हो चुके हैं। जनता दिग्भ्रमित है।

यह लड़ाई विशेषकर इस मठ की 56 नाली भूमि जिसमें एक बड़ा मठ और एक फलदार बगीचा है व जिसका मूल्य करोड़ों रुपया है, उसी को लेकर है। **-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 25/02/2005)**

413) सोमेश्वर मन्दिर के महन्त को जान का खतरा :- तीर्थनगरी ऋषिकेश के प्रसिद्ध पौराणिक सोमेश्वर मन्दिर के वर्तमान महन्त स्वामी रामेश्वर गिरि ने मन्दिर सम्पत्ति पर अवैध कब्जा करने का षड़यन्त्र कर रहे कुछ लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की माँग करते हुए अपनी जान की सुरक्षा की माँग की है। उनके अनुसार मन्दिर की सम्पत्ति को हड़पने के इरादे से कुछ लोगों की शह पर कमलपुरी फर्जी दस्तावेज तैयार करके फर्जी शिष्य बन बैठा। भूस्वामित्व को लेकर नन्दूगिरि ने भी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी घोषित करने का प्रयास किया।

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 25/02/2005)

414) भीख माँगने की आड़ में अपराध करते हैं भिखारी :- स्वर्गाश्रम, लक्ष्मण झूला एवं ऋषिकेश तीर्थक्षेत्र इन दिनों अपराधी प्रवृत्ति के भिखारियों की चपेट में है। इन भिखारियों द्वारा भीख माँगने की आड़ में छोटे-मोटे अपराध भी करने का सन्देह है। ये भिखारी विदेशी पर्यटकों अथवा सैलानियों के पीछे लग जाते हैं तथा उन्हें आतंकित करते हैं। रास्ते में बैठकर आने-जाने वालों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर उनका भूत-वर्तमान-भविष्य बताने का दावा करते हैं और उनके किसी अनिष्ट की आशंका जताकर अथवा उनके सुनहरे भविष्य की भविष्यवाणी करके उनके रकम ऐंठ लेते हैं। घरों में महिलाओं व बच्चों को आतंकित करते हैं। माँगने वालों के वेश में अपराधी तत्त्वों की घुसपैठ पर पुलिस को अंकुश लगाना चाहिए।

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 24/02/2005)

415) चुम्बन देने वाली पाक अभिनेत्री पर जुर्माना :- *पाकिस्तानी सिने अभिनेत्री मीरा द्वारा एक भारतीय फिल्म में अपने सह-कलाकार को चूम लेने मात्र से उनके देश की सरकार इतनी खफा हो गई है कि उसने न केवल इस अभिनेत्री पर भारी जुर्माना लगा दिया है बल्कि वह भारतीय फिल्मों में काम करने से पाकिस्तानी अदाकारों को प्रतिबन्धित करने पर भी विचार कर रही है। फिल्म नजर में मीरा ने अस्मित पटेल के साथ जो चुम्बन दृश्य दिया है, वह इस्लामिक मूल्यों और नैतिक मानदण्डों के विरुद्ध है और इस पर पाकिस्तान सरकार को सख्त आपत्ति है, इसलिए संस्कृति मन्त्रालय ने उसे भारी-भरकम जुर्माना भरने का आदेश दिया है।*

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 24/02/2005)

416) संवेदनाशून्य कानून और मशीनी निर्णय :- *दिल्ली भारत की राजधानी है, जहाँ सन् 2004 में 500 से भी अधिक बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। एक वर्ष, दो वर्ष और पाँच वर्ष तक की बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले दर्ज हुए। और 90% मुकदमे तो दर्ज ही नहीं होते।*

साक्ष्यों पर टिका हमारा 150 वर्ष पुराना कानून हर बार पीड़िता को और भी निराशा के गर्त में डाल देता है। कानून अपेक्षा करता है कि घटना के चश्मदीद गवाह अदालत में हाजिर हों। लेकिन कोई उनसे ये नहीं पूछता कि बलात्कार करने वाले भी कभी साथ में गवाह लेकर जाते हैं क्या? पिछले वर्ष आगरा का एक मामला सामने आया था। यहाँ एक कान्वेन्ट स्कूल की शिक्षिका के साथ विद्यार्थियों ने दुर्व्यवहार किया था। जितनी बार भी इन मामलों में सर्वेक्षण हुए, नतीजा एक ही निकला; 98% से अधिक मामलों में यही पाया गया कि अपराधियों के शिर पर उन्हीं बदमाशों का साया होता है, जो अक्सर हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं। आर.बल्लभशास्त्री नामक एक विद्वान ने हर राज्य से ऐसे दस मामले उठाए और अध्ययन के बाद देखा कि अपराधी के पकड़े जाने से पहले थानों में फोन घनघनाने प्रारम्भ हो जाते हैं- 'सावधान! ये फलाने मन्त्री जी के आदमी हैं।' ऐसे भी मामले प्रकाश में आए हैं, जब थाने के प्रागंण में बलात्कार की शिकार रिपोर्ट दर्ज कराने वाली स्त्री को सुनना पड़ा- 'साली! रण्डी! रिपोर्ट दर्ज कराने आयी है। रात को आना तुम पर हमारा भी हक है। रिपोर्ट हम भी लिखेंगे।' इन पुलिसवालों को क्या कहें? अगर संवेदनाशून्य कानून कुछ और दिन मुर्दा रहा तो वही होगा, जो नागपुर में घटित हुआ। बलात्कार की पीड़ित महिलाएँ बार-बार अदालत में पड़ती तारीखों से तंग आ गई है। बलात्कारी जब उनकी आँखों के सामने बड़े वकीलों की कार में घूमते नजर आया तो इन महिलाओं का गुस्सा बेकाबू हो गया। बीच अदालत के प्रागंण में बलात्कारी को ईंटों, पत्थरों से सजा देने की प्रक्रिया पूरी हुई और वर्षों से फाइलों के बीच कराहता और साक्ष्यों तथा चश्मदीद गवाहों को तलाशता अन्धा कानून चिर निद्रा में सो गया।

भारत की न्यायिकप्रणाली से आम आदमी का विश्वास करीब-करीब उठ चुका है। और आम आदमी जो जिला न्यायालयों से ऊपर पैसों की कमी के कारण जा नहीं पाता, वह आज पूरी शिद्दत से महसूस करता है कि उच्च न्यायालय का मतलब उच्च आर्थिक स्थिति वालों का न्यायालय है तथा उच्चतम न्यायालय केवल उच्चतम आर्थिक स्थिति वालों का न्यायालय है। गरीब तो बेसहारा फटेहाल न्याय की प्रतीक्षा में या तो पागल हो जाता है या दम तोड़ देता है। कब तक न्यायालय झेल पाएँगे इन बेबस बेगुनाहों की आह का असर? कौन सुनेगा आम आदमी का दर्द? आवाजों के बाजारों में गरीब की खमोशी कौन पहचानेगा?

-(अश्विनीकुमार, विशेषसम्पादकीय; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 23/02/2005)

417) *भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान के संरक्षक कलराज मिश्र ने कहा कि भाजपा ने कभी भी जातिवाद, वर्गवाद को बढ़ावा न देकर दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मवाद के मूलमन्त्र के अनुरूप देश की समग्रता की नीति पर चलकर देश के विकास की बात कही है। यह विचार कलराज मिश्र ने जयराम आश्रम में दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान के दो दिवसीय छठे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए कहा कि देश में फैला जातिवाद, वर्गवाद तभी समाप्त होगा, जब हम सभी वर्गों के लिए समग्रता व एकाग्रता से विचार करेंगे।*

उत्तरांचल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमन्त्री भगतसिंहकोश्यारी ने पंडित दीनदयाल के विचारों को जन-जन तक पहुँचाने का आह्वान करते हुए कहा कि उनके 'एक राष्ट्र एक जन' के अनुरूप यदि देश के विकास की योजनाएँ बनाई जाएँ, तो कोई भी इंसान धरती पर बिना छत के और भूखा नहीं सो सकता।

पूर्व राज्यसभा सांसद मनोहर कान्त ध्यानी ने कहा कि आज की राजनीति की राहें रपटीली हैं, जिसमें मनुष्य के जीवन के बारे में कोई भी विचार नहीं किया जाता। जब तक मनुष्य के सामने समस्याएँ रहेंगी, तब तक देश विकसित नहीं हो सकता। **-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 22/02/2005)**

418) गाँधी ने कहा था- काँग्रेस भंग कर दो! संघ कह रहा है- भाजपा भंग कर दो! :- *आजादी के बाद महात्मा गाँधी ने कहा कि काँग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए। अब केन्द्र में भाजपा का राज्य देख लेने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहने लगा है कि भाजपा यदि नहीं सुधरी तो उसे भंग कर दिया जाना चाहिए। गाँधी ने जिस काँग्रेस की परिकल्पना की थी, आजादी के बाद सत्ता मिलने पर वह उनकी परिकल्पना की काँग्रेस नहीं रह गई थी। वह सत्ता की काँग्रेस हो गई थी, उसमें सत्ता के छल-कपट झूठे वादे सब आ गए थे। नेता भ्रष्टाचार में लिप्त होने लगे थे। जनता की अनदेखी करने लगे थे। जातिवाद, परिवारवाद पनपने लगा था। इसी से आहत होकर गाँधी ने काँग्रेस को भंग करने की बात कहीं थी। आज वही हालत भाजपा में है। संघ ने इसकी स्थापना राष्ट्रीय विचारधारा और शुचिता की संस्कृति को पुष्पित-पल्लवित करने के लिए की थी ताकि देश की राजनीति को एक नई दिशा मिल सके, परन्तु सत्ता में आने के बाद भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए वही सारे धतकर्म करने लगी, जो काँग्रेस करती रही।* ***-(एक समाचार, कृष्णमोहनसिंह; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 07/09/2005)***

419) जितना तिकड़मी, भ्रष्ट और अपराधी उतना प्रतिष्ठित :- *देश की राजनीति अब चरित्रवान, प्रबुद्ध, सुप्रतिष्ठित, उदारचेत्ता और समन्वित दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों को आकृष्ट नहीं करती। समाज रचनात्मक और सेवाकार्यों में रत व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मान नहीं दे रहा। लोग भागते उनके पीछे हैं, जो उन्हें डंके की चोट पर दिन-दहाड़े लूटते हैं। किन्तु उपेक्षा और अवमानना की खराद पर उन्हें तराशते हैं, जो लेने नहीं देने जाते हैं। यह उल्टा प्रवाह जनजीवन को पतित बना रहा है। कोई इस प्रवाह को सीधा करने के लिए तैयार नहीं कि राजनीति में श्रेष्ठ व्यक्ति आएँ और सेवाकार्य को सर्वोपरि माना जाने लगे। सार्वजनिक जीवन में खोटे सिक्कों का चलन इतना अधिक है कि अब अच्छे सिक्के यदि कहीं दिखाई भी देते हैं, तो वे नकली मालूम पड़ते हैं।*

आज जो जितना ही अधिक तिकड़मी, भ्रष्ट, असामाजिक और अपराधी वृत्ति का है, वह उतना ही अधिक प्रतिष्ठित, सफल, कुशल और सम्मानित व्यक्ति है। उसके लिए विकास एवं प्रतिष्ठा के सभी द्वार खुले हुए हैं। जो डाकुओं से मिला होगा, वह चुनाव कभी नहीं हारेगा। जिसे काले धन की सहायता मिलती है, वह राजनीति का मुखिया बन जाता है। जिसके पीछे कोई सम्प्रदाय, जाति, वर्ग या मजहब की भीड़ होती है, उसके संकेत पर सत्ता प्रतिष्ठान के नियन्ता उठते-बैठते हैं। जो जितना अधिक क्षेत्रीय और संकीर्ण है, वह उतना ही अधिक सफल है। जो देश और उसकी समस्याओं को उसकी समग्रता में न देखकर उन्हें जितने अधिक टुकड़ों में बाँटकर देखता है, वह उतना ही अधिक बड़ा नेता सिद्ध होता है। जो मंच पर सदाचारी और घर में भ्रष्टाचारी है, उसे महानता की ऊँचाई तक ऊपर उठा हुआ मान लिया जाता है। गद्दार देशभक्ति का उपदेश देता है और विदेशी धन एवं सामान पर पलने वाला स्वदेशी का प्रवक्ता बनता है। देश की अखण्डता को खण्डित करने के लिए प्रयत्नशील तत्त्व राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं।

इसीप्रकार की परस्पर विरोधी ऐसी अनेक बातें हैं, जिनका उल्लेख अविराम किया जा सकता है। किन्तु उल्लेख करनेमात्र से उनका समाधान नहीं है। समाधान इस प्रश्न का उत्तर खोजने में है कि ऐसा क्यों हुआ कि जिसे सम्मान मिलना चाहिए था, वह असम्मानित है और जिसे प्रतिष्ठा की सीढ़ी का सबसे निचला डण्डा बनना था, वह चरम पर है। यह समीकरण बिगड़ा तब जब समाज की व्यवस्था बिगड़ गई और उसमें दोष उत्पन्न होते गए। हिन्दूजीवनदर्शन ने समाज के आम आदमी के सामने यह शर्त रखी थी कि तुम्हारे लिए सम्मान, सत्ता तथा सम्पदा के अवसर समानरूप से उपलब्ध हैं। तुम स्वयं चुनाव कर लो कि तुम्हें क्या चाहिए। इसका चुनाव करने के लिए व्यक्ति स्वतन्त्र था। अपनी रुचि के अनुरूप जीवन की दिशा का चुनाव करने के पश्चात् यह शर्त रखी गई कि सम्मान उसे मिलेगा, जो प्रबुद्ध, अपरिग्रही, त्यागी और निर्हेतुक होगा। शेष सभी को बिना शर्त इस निस्पृह व्यक्ति का आदर करना ही होगा। वह अपने लिए नहीं देश और समाज के लिए जिएगा और मरेगा। उसे पास अपनी स्वयं की कोई सम्पत्ति नहीं होगी। दो समय की रोटी भी वह समाज से केवल इतनी मात्रा में प्राप्त करेगा, जिससे उसका पेट भर जाए और वह भूखा न रहे। किन्तु जिसके पास सत्ता या सत्पत्ति होगी, उन्हें वह आदर नहीं मिलेगा, जो उस निर्हेतुक व्यक्ति को मिलता है। सम्पत्ति या सत्ता लो, या आदर लो। सब कुछ लुटाकर आदर प्राप्त करने की व्यवस्था जिस समाज ने दी थी, उसने सत्ता और सम्पत्ति के चरित्र का गहरा चिन्तन किया था। यही कारण है कि हिन्दूचिन्तन ने सम्मान, सत्ता और सम्पत्ति को कभी एक स्थान पर केन्द्रित होने ही नहीं दिया। जब तक यह व्यवस्था बनी रही, चरित्र का अभाव कभी नहीं रहा। किन्तु व्यवस्था बदलते ही प्रबुद्ध, उदारचेत्ता और श्रेष्ठ व्यक्ति पीछे ढकेल दिए गए। इस व्यवस्था के टूटने का अथ है- समाज का सन्तुलन बिगड़ जाना, उसका समीकरण नष्ट

हो जाना और सम्मान, सत्ता एवं सम्पत्ति का एक स्थान पर केन्द्रित हो जाना। इस अव्यवस्था ने जिस दानवी प्रवृत्ति को जन्म दिया, वह अब सत्प्रवृत्तियों का भक्षण कर रही है। यही कारण है कि अब अपरिग्रही एवं त्यागी को दरिद्री, सेवक को दास तथा प्रज्ञावान निर्हेतुक व्यक्ति को बुद्धिहीन बताकर उसे दुत्कारा जाता है। जिसके पास जितनी अधिक सम्पत्ति है, उसे उतना ही अधिक सम्मान मिलता है। जो सत्ता में है, वही सम्पत्ति का मालिक है, वही समाज का नियन्ता है, उसका ही सत्कार किया जाता है, उसके बिना समाज के सभी अनुष्ठान अधूरे माने जाते हैं। जब ये तीनों एक ही बिन्दु पर आ जुड़ते हैं, तो इनकी रक्षा के लिए वैध-अवैध, सामाजिक-असामाजिक, सदाचार और दुराचार के सभी उपाय अपनाए जाने लगते हैं। मर्यादाएँ जब भंग हो जाती हैं, तो अमर्यादित जीवन कोई भी बन्धन नहीं मानता। नक्श ही उलट जाता है। शब्दों के वास्तविक अर्थ बदल दिए जाते हैं। शील और चरित्र अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं। जब किसी भी क्षेत्र का सर्वोच्च व्यक्ति लोकहित को भूलकर अपनी व्यक्तिगत रुचि और अरुचि को प्राथमिकता देकर उसी के आधार पर नीति और सिद्धान्त के निर्णय करने लगता है, तो व्यवस्था विश्वसनीयता और स्तर में गिरावट आने लगती है। जब गुणवान, क्षमतावान एवं मेधावी व्यक्तियों को तिरस्कृत करके चापलूसों और स्वार्थियों का सत्कार होने लगता है, तो निस्सन्देह रूप से वे ही अगली पंक्ति में खड़े दिखाई देंगे, जिनमें चापलूसी का चमत्कार कर दिखाने का कौशल होगा। ***-(भानुप्रतापशुक्ल, स्तम्भकार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 21/02/2005)***

420) दागी मन्त्रियों को हटाने सम्बन्धी याचिका खारिज :- *उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में शामिल राष्ट्रीय जनता दल के चार दागी मन्त्रियों को हटाने के निर्देश देने की माँग करने वाली पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 19/02/2005)***

421) दागी सांसदों के मामले में कोई दल किसी से पीछे नहीं :- *ऐसे में जब तिहाड़ जेल अपराधी से नेता बने पप्पू यादव के आने का इंतजार कर रही है, सांसदों के दागी चरित्र और दबंग व्यवहार को लेकर बहस तेज हो गई है। दो सांसद महीनों से सलाखों के पीछे हैं, जबकि कई सांसद जमानत पर हैं। विवादास्पद सांसद पप्पू यादव पर ट्रेड यूनियन नेता अजित सरकार की हत्या का अरोप है और वे पिछले चार वर्षों से इस हत्याकाण्ड में सलाखों के पीछे हैं। राजद के एक और सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन जिन पर हत्या, फिरौती, डकैती आदि के करीब तीस मामले चल रहे हैं, पिछले दो वर्षों से भी अधिक समय से जेल में बन्द हैं। शहाबुद्दीन ने जेल से ही चुनाव जीता। उन्हें बीच में सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए जेल से छोड़ा गया था। इसके बाद फिर जेल पहुँच गए। अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 2004 के चुनावों में 545 सदस्यीय लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सांसदों में से एक चौथाई के खिलाफ या तो आपराधिक मामले दर्ज हैं या उनके खिलाफ अदालतों में मामले लम्बित हैं। इन पर फिरौती और हत्या से लेकर बलात्कार तक के आरोप लगे हैं। खुद राजद प्रमुख और रेलमन्त्री लालूप्रसाद यादव बहुचर्चित चारा घोटाले में जेल जा चुके हैं। केन्द्रीय राज्यमन्त्री मोहम्मद तसलीमुद्दीन के खिलाफ धमकी, फिरौती, हत्या का प्रयास करने आदि के कई मामले दर्ज हैं।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 18/02/2005)***

422) सुनामी के मृतकों के नाम प्रार्थना :- *दर्जन भर देशों में आए अलीम तूफान (सुनामी) से करोड़ों जलचर, नभचर तथा पशु और लाखों मानव असमय काल की कोख में चले गए। उनके प्राण निकलते समय की स्थिति की कल्पना से ही हम सभी काँप उठे और परमात्मा से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु! इन करोड़ों प्राणियों की आत्माओं को शान्ति दो तथा ऐसी कष्टकारी मौत हम जीवों को फिर कभी न मिले। तथा सुनामी को प्राप्त जीवों के आश्रित जो अपने मानवीय रिश्तों से अनाथ हो गए हैं, उन्हें हे प्रभु सन्मति तथा अहिंसा का ज्ञान देते हुए सात्त्विक जीवन जीने की सीख व शक्ति दो।*

समय पर हमें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, टलता नहीं है और ये घटनाएँ हमारे द्वारा जीवधारी व पर्यावरणीय असमानताएँ पैदा करने वाले कर्मों का फल हैं। हम व्यर्थ ही तूफान या अनहोनी को कोसते हैं। ये तो उनके स्वाभाविक गुण हैं। तो फिर हम तूफान को क्यों बदनाम करें? बल्कि यदि वास्तव में हम परमात्मा से यह चाहते हैं कि हमारा परिवार अनहोनी से दूर रहे, असह्य दुःख हमें न मिले, असमय हम अपनों से न बिछुड़ें, तो निश्चितरूप से हमें अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा। हमारा कर्म परहित का हो, ईमानदारी का हो, सच्चाई का हो, जीवों के प्रति दया का हो तथा अहिंसा के पालन का हो।

-(गंगेश्वर पाण्डेय, बिंदकी, फतेहपुर; आवाज-ए-अबरदार, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 18/02/2005)

423) देश के हालात और आज की स्थिति :- *सन् 1947 में भारत को विदेशी शासकों से मुक्ति मिली। उसके बाद लगभग एक-डेढ़ दशक तक का समय देश की जनता को नई व्यवस्था को समझने में लग गया। जब कुछ समझ में आया तो पाया कि देश विदेशियों से भले ही मुक्त हुआ हो, परन्तु विदेशियत से नहीं। आजदी तथाकथित नेता, नौकरशाही, पूँजीपति और बाहुबली वर्ग की जागीर बनकर रह गए हैं। कुल जनसंख्या का 95% भाग इसी वर्ग का गुलाम बनकर रह गया। गुलामी के समय की तुलना में आज की आजादी के समय ने 35 करोड़ लोगों के स्थान पर 95 करोड़ लोग गुलामी जिन्दगी गुजार रहे हैं। विदेशी शासकों ने देश के अतुल खजाने को लूटा, परन्तु आज हमारे अपने ही शासकों ने खजाने के साथ-साथ मानवता, नैतिकता यहाँ तक कि देश की अस्मिता को भी लूट लिया। सेवा के स्थान पर शोषण ही शोषण है। समूचा देश मानवाधिकारों की खुली बिक्री का बाजार बन गया है। आजादी खजूर के पेड़ से गिरी और काँटों भरे बबूल पर अटक गई।*

-(रामस्वरूप गुप्ता, बालातोरा; आवाज-ए-खबरदार, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 18/02/2005)

424) मानवाधिकार कार्यकर्ता खालड़ा को दी गईं अमानवीय यातनाएँ : दास्ताव-ए-मौत बेनकाब :- *पंजाब में 1995 में मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवन्त सिंह खालड़ा की हत्या के कुछ दिन पहले राज्य के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक के.पी.एस.गिल उनसे मिले थे। यह रहस्योद्घाटन पंजाब पुलिस के लिए विशेष पुलिस अधिकारी (एस.पी.ओ.) एवं खालड़ा हत्याकाण्ड के मुख्य गवाहों में से एक श्री कुलदीप सिंह ने यहाँ पटियाला में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.पी.बाँगड़ की अदालत में किया। श्री कुलदीप ने बताया कि हत्या से पूर्व खालड़ा को पुलिस सेल में कई दिनों तक यातनाएँ दी गईं। बाद में उनका शव हरिके नहर में फेंक दिया गया, जहाँ मौके पर तरनतारन के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह सन्धू उपस्थित थे। मुख्य गवाह ने यह भी बताया कि पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारियों ने श्री खालड़ा को किस तरह मौत के घाट उतारा। गवाह ने कहा कि श्री सन्धू के जीवित रहते तक उसकी इस राज (खालड़ा हत्याकाण्ड) को खोलने की हिम्मत नहीं हो सकी।* ***-(एक समाचार, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 18/02/2005)***

425) आन्दोलनकारी बेरोजगारों के खिलाफ मामला दर्ज :- *सिडकुल में रोजगार की माँग को लेकर आन्दोलित लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जिला प्रशासन ने डाबर फैक्ट्री के सामने क्रमिक अनशन कर रहे बेरोजगारों के टेन्ट उखाड़ दिए, जिसे लेकर आन्दोलनकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच नोंक-झोंक भी हुई। आन्दोलनकारियों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ शान्ति भंग करने का मामला दर्ज किया है। आन्दोलनकारी नेता मोहनपाठक ने बताया कि प्रशासन ने अपने दमनात्मक रवैये का परिचय देते हुए आन्दोलन को कुचलने का प्रयास किया। उन्होंने कहा- 'रोजगार की माँग को लेकर बेरोजगार कई महीनों से शान्तिपूर्वक आन्दोलन कर रहे हैं। पुलिस द्वारा शान्तिभंग का आरोप गलत है।*

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 18/02/2005)

426) शिक्षा के निजीकरण का विरोध करेगी आइसा :- *आइसा के तीसरा राज्य स्तरीय सम्मेलन में शिक्षा के निजीकरण के विरोध पर विशेषरूप से चर्चा की गई। वक्ताओं ने शिक्षा के निजीकरण का विरोध किया एवं इसके खिलाफ एकजुट संघर्ष का आह्वान किया। वक्ताओं ने शिक्षा व रोजगार के लिए स्पष्ट नीति की भी माँग उठाई। देहरादून नगर निगम के सभागार में आल इण्डिया स्टूडेन्ट्स एसोसिएशन का तीसरा राज्य सम्मेलन सम्पन्न हुआ, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा व रोजगार जनता के मूल अधिकार में शामिल हैं और इन्हें बाजार के हवाले करके जनता को उसके मूल अधिकारों से वंचित करने की साजिश की जा रही है। आइसा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री अवधेश कुमार ने कहा कि अब सरकार द्वारा शिक्षा पर एक विशेष वर्ग के एकाधिकार की तैयारी की जा रही है। इसके खिलाफ छात्रों को ही एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार को भी अब सत्तापक्ष अपनी प्राथमिकता से अलग कर रहा है। भाकपा माले के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य श्री गिरिजा पाठक ने कहा कि राज्य में बैठे भ्रष्ट राजनेताओं का सफाया होना चाहिए। उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान यहाँ के छात्र-छात्राओं ने जो व्यापक भूमिका निभाई थी, वे इसलिए कि एक सर्वसम्पन्न राज्य बने एवं छात्र-छात्राओं को शिक्षा एवं रोजगार मिले।* ***-(एक समाचार, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 17/02/2005)***

427) भारत संविधान का सत्य के धरातल पर मंथन करे :- *नेपाल को भारत सरकार की ओर से बार-बार सलाह दी जा रही है कि लोकतन्त्र बहाल करो। लेकिन हमारे विदेश विभाग के लोग या अन्य जो ऐसी सलाहें दे रहे हैं, उनमें से आप किसी को पूछ लें कि सलाह देने से पूर्व जरा लोकतन्त्र को परिभाषित तो कर दें, तो हो सकता है कि उनकी जुबान लड़खड़ा जाए। किसी भी बड़े से बड़े प्रजातान्त्रिक देश के संविधान में राजतन्त्र छिपा है और तानाशाही भी। फर्क सिर्फ इतना ही है कि हमारी अक्ल कैसी है और वह इन्हें कैसे विवेचित करती है। लोग शब्दों को पकड़ लेते हैं, उनका आशय नहीं समझते। अगर तानाशाही की बात लें, तो मैं पूछना चाहूँगा कि क्या तानाशाही का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं? अगर यह बात न होती, तो 1975 में इन्दिरा गाँधी के आचरण को इमरजेन्सी में तानाशाही की पदवी न दी गई होती। निःसन्देह वह तानाशाही थी और भारत के संविधान में इमरजेन्सी का प्रावधान आज भी है। आज जो लोग लोकशाही-लोकशाही चिल्ला रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा- 'संविधान में राष्ट्रपति शासन से लेकर इमरजेन्सी अर्थात् राजतन्त्र या तानाशाही तक जितने प्रावधान हैं, हिम्मत से इन्हें संविधान से हटाकर लोकशाही को बहाल करें।* **-(अश्विनीकुमार, प्रधानसम्पादक, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 17/02/2005)**

428) *चम्बल के डकैत, अपहरणकर्ता, हत्यारे और हमारे दागी सांसद जो कभी जेल की शोभा बढ़ाते हैं, तो कभी भारत की सबसे बड़ी लोकतन्त्र के पंचायत की। कैसी विडम्बना है भारत के संविधान में कहीं यह नहीं लिखा कि चोर, डकैत, बलात्कारी, अपहरणकर्ता और हत्यारों को जनप्रतिनिधि बनने से नहीं रोका जा सकता। बेचारा मतदाता! कइ बार तो वोट डालने भी नहीं जाता। उसका वोट डाल दिया जाता है। बाहुबली लोग गुण्डागर्दी के बल पर सांसद और विधायक का चुनाव जीत जाते हैं। ईमानदार व्यक्ति तो चुनाव में खड़े होने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। सत्य बड़ा कटु होता है। सच कहने व लिखने का युग नहीं रहा। हमारे देश के दागी कर्णधार जाने कौन सी मिट्टी के बने हैं? इतने चिकने घड़े हैं कि इन्हें शर्म, हया बिल्कुल नहीं आती। इन नेताओं का चरित्र, सिद्धान्त कुछ नहीं। 'त्वमेव माता च पिता त्वमेव' की तर्ज पर केवल कुर्सी इनके लिए सब कुछ है। जनता भाड़ में जाए और भाड़ में जाए- सिद्धान्त, नीति, देशभक्ति।*

-(डा.सत्येन्द्रकुमारशर्मा, चाँदपुर, बिजनौर; आवाज-ए-खबरदार, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 17/02/2005)

429) *कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों में भारत के राजनेताओं के लिए शिखंडी शब्द का प्रयोग छाया रहा था। पंजाब केसरी के सम्पादकीय में भी लिखा गया था कि संभवतः अब भारत के राजनेताओं के लिए शिखंडी शब्द का ही प्रयोग हो। परन्तु भारत के राजनेताओं को शिखंडी कहना शिखंडी का अपमान है। क्योंकि शिखंडी एक महारथी था, जो महाभारत के युद्ध की अन्तिम रात्रि में अश्वत्थामा से युद्ध करता हुआ मारा गया था। और जो व्यक्ति महाभारत के युद्ध में 18 दिनों तक जीवित रहा, वह साधारण योद्धा नहीं होगा। वस्तुतः शिखंडी लड़की पैदा हुआ था और एक यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त कर पुरुष हो गया था। भारत के नेताओं को तो संसद के दिन आपने देखा होगा। अगर ये आतंकवादियों को देख भी लेते तो सभी को धोबियों की जरूरत पड़ती। इनमें से एक नाम भी बताएँ, जो अपने जवानों की हौसला अफजाई के लिए बाहर आया हो। अतः भारत के राजनेताओं की तुलना शिखंडी से करना शिखंडी का अपमान है। भारत के नेताओं की तुलना तो किन्नर (हिजड़ा) से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि किन्नर के भी अपने उसूल होते हैं तथा देश व अपने उसूलों के लिए वह जान भी दे देगा। इन्हें तो कायर किस्म के व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाला एक अपशब्द भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसका भी अपना दीन-ईमान होता है। इनकी तुलना तो कुत्ते से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि कुत्ता तो बहुत अधिक वफादार होता है। वह अपने मालिक की रक्षा में जान दे देता है। मुझे तो डिक्शनरी में भी कोई ऐसा घृणित शब्द नहीं मिला, जिसे भारत के राजनेताओं के लिए प्रयोग कर सकूँ। अब जनता ही सोचकर बताए कि भारत के नेताओं को क्या कहा जाए?*

-(यशपाल, ऋषिकेश; आवाज-ए-खबरदार, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 17/02/2005)

430) हमारा संविधान हकीकत के आइने में :- *हर देश में शासनव्यवस्था चलाने के लिए एक सरकार होती है। उसका अपना संविधान होता है, जिसके आधार पर सरकार के सारे कार्य निष्पादित होते हैं। सन् 1947 ईसवी में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत ने संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली को अपनाया। लोकतन्त्र के सन्दर्भ में अब्राहम लिंकन की सटीक परिभाषा है– 'जनता की, जनता के लिए, जनता द्वारा निर्वाचित सरकार'। अर्थात् जनता द्वारा निर्वाचित वैसी सरकार जो प्रत्येक स्तर पर बिना किसी भेदभाव के देश की सम्पूर्ण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए अपने कर्तव्यों का समुचित तरीके से पालन करते हुए अधिकारों का विवेकानुसार प्रयोग करे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर संविधाननिर्माण का कार्य शुरु हुआ। संविधाननिर्माण का आधार जिन विदेशी संविधानों को बनाया गया, वहाँ की शासनव्यवस्था आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक परिस्थितियाँ आदि बिल्कुल भिन्न थीं। साथ ही अँग्रेजों की जिन नीतियों–नियमों के खिलाफ लड़कर हमने आजादी हासिल की, उन्हीं अँग्रेजों द्वारा निर्मित संविधान का ही हमारे संविधान में प्रमुख योगदान रहा, क्योंकि संविधाननिर्माण का दायित्व जिन लोगों पर था, उनमें अधिकांश राजे–महाराजे, बड़े जमींदार, सम्पन्न घराने से जुड़े थे। अधिक दिनों तक देश के गुलाम रहने से उनके दिलों–दिमाग में अँग्रेजों द्वारा शासन–प्रशासन चलाने के शाही तौर–तरीके रचे–बसे थे। उन लोगों ने गरीबों को दूर से देखा था, उनकी गरीबी नहीं देखी थी, तो उन्हें संविधान की त्रुटियों का अहसास कैसे होता। भारतीय संविधान के अनुसार कानून की नजर में देश का हर नागरिक समान है। लेकिन कितनी अजीब बात है कि एक ओर साधारण आदमी को पुलिस भयभीत किए रहती है, किन्तु दूसरी ओर बड़ा अपराधी लोकसभा और विधानसभा में बैठकर पुलिस एवं प्रशासन को भयभीत किए रहता है। अतः इन सब बातों को गम्भीरता से लेते हुए न्यायपालिका चुनाव आयोग, संविधान विशेषज्ञ एवं विधिवेत्ताओं का प्रमुख दायित्व बनता है कि वे संविधान का गहन अध्ययन करके स्पष्ट करें कि आरोपी या सजायाफ्ता (अर्थात् आपराधिक चरित्र वाले) व्यक्ति को चुनाव लड़ने या शासन में किसी पद पर बने रहने का कानूनी अधिकार है या नहीं। अगर यह स्पष्ट नहीं होता, तो गंभीर मामलों जैसे– हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण, घोटाला, घपला आदि से जुड़े लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए उन्हें सरकार को कानून बनाने हेतु ठोस सुझाव देना चाहिए, ताकि यह झमेला हमेशा के लिए दूर हो जाए।*

-(सुरेशप्रसाद; आवाज-ए-खबरदार, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 16/02/2005)

431) *भगतसिंह से सुभाषचन्द्रबोस तक की कुर्बानियाँ व्यर्थ गईं। यह देश सदियों से सोया हुआ है। यह देश तो आजाद होने के लायक ही नहीं था। यह तो क्रान्तिकारियों की मति मारी गई थी, जो बेचारे खुद तो जवानी में शहीद हो गए और देश को ऐय्याशों के हवाले कर गए। बी.जे.पी. वाले नारा लगाते हैं– 'गर्व से कहो, हम हिन्दू हैं'। मैं तो हिन्दू होने के बावजूद कहता हूँ– 'कायरता से, स्वार्थीपन से कहो, हम हिन्दू अव्वल दर्जे के कायर और बुजदिल हैं, जो आज तक चाहते हैं कि क्रान्तिकारी पैदा तो हों, पर पड़ोसी के घर में।' वाकई मेरा भारत महान है।*

क्या आम आदमी के पास अधिकार है। इस देश का एक ही हल है– हिंसा। जब तक एक–एक भ्रष्टाचारी, नेता, अपराधी को चुन–चुन कर नहीं मारा जाता, तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। मगर यह काम करेगा कौन ? इस देश की जनता से तो कोई उम्मीद नहीं। न जाने वह सुनहरा दिन कब आएगा ?

-(सतीशकुमार, दिल्ली; आवाज-ए-खबरदार, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 17/02/2005)

432) भारतीय राजनीति में विरोधाभास :- *अगर पूरे चुनाव पर गौर करें, तो एक बात स्पष्ट दिखाई देती है कि चुनाव प्रचार बिल्कुल ही व्यक्ति केन्द्रित था। विकास की बात भी रस्मी तौर पर भाषणों में जरुर की जाती रही, परन्तु मूल मुद्दा 'अमुक को हटाओ और अमुक को उसकी जगह पर लाओ' रहा। स्वाभाविक था कि ऐसे में मूल मुद्दे पीछे छूट जाएँ और कुल जोर व्यक्तिगत कीचड़ उछालने के इर्द–गिर्द ही रहे। यह एक रिवाज जैसा बन गया है कि चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर–शोर से उठाकर अपने विरोधी पर जितनी भी कालिख पोती जा सके, पोती जाए। परन्तु इस पहलू पर निगाह दौड़ाने से बिल्कुल साफ हो जाता है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा उछालने वालों को भ्रष्टाचार आरोपित व्यक्तियों से गले मिलने में कोई परहेज नहीं है। बशर्ते ऐसा करने पर उन्हें दो–चार सीटों का फायदा हो सके। वही मामला बाहुबलियों (गुण्डों) को लेकर भी है। अगर बाहुबली अपनी पार्टी में है, तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन यदि वह दूसरी ओर है, तो वह एक चुनावी मुद्दा है। इस तरह की राजनीति देश को कहाँ ले जा रही है, यह सोचने की जहमत न कोई उठाना चाहता है और न किसी के पास इसकी फुर्सत है।* ***-(पूर्व प्रधानमन्त्री, चन्द्रशेखर; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 17/02/2005)***

433) आज की राजनीति सचमुच गुण्डों की चारागाह है :- *पंडित कमलापति त्रिपाठी राजनीति का अपराधीकरण हो जाने के कारण दुःखी थे। उनकी भविष्यवाणी थी कि यदि अपराधियों से राजनीति को मुक्त न किया गया तो गुण्डाशक्ति ही इस देश पर शासन करेगी। पंडित जी का यह आँकलन शत-प्रतिशत सच है। उनकी इस बात में सम्पूर्ण देश की वेदना समाहित है। भुजबल आज की वोट राजनीति का सबसे सबल और निर्णायक तत्त्व है। धनशक्ति और सत्ताशक्ति उसको संरक्षण तथा अतिरिक्त शक्ति प्रदान करती है। राजनीति में जनप्रशिक्षण, प्रखर सिद्धान्त, नीति एवं घोषणापत्र निरर्थक हो गए हैं। बन्दूक के बल पर चुनाव जीते जाने लगे हैं।*

एक वरिष्ठ पत्रकार ने त्रिपाठी जी के इस आँकलन को किसी असहाय विधवा का विलाप करकर अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए कहा– ''यह महाभारत के भीष्म की तरह पाण्डवों का मंगल चाहने और दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने जैसा है। शरशैय्या पर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे भीष्म पितामह की तरह त्रिपाठी जी भी अपने किए पर विलाप कर रहे हैं कि यह सब क्यों हो रहा है? राज्य सिंहासन और सामाजिक सांस्कृतिक पीठ अपराधकर्मियों के प्रभाव में कैसे आ गया? इन प्रश्नों का उत्तर त्रिपाठी जी के सीने में शूल की तरह चुभा होगा, तो वे आत्मग्लानि से भर उठे होंगे कि राजनीति का अपराधीकरण करने में कहीं न कहीं, किसी न किसी स्तर पर उनका भी योगदान था। किन्तु अपनी आयु के अन्तिम दौर में वह न तो अपने सहयोगियों के इस राजनीतिक और राष्ट्रीय अपराध का प्रायश्चित कर सकते थे और न उन्हें नया राजनीतिक अपराध करने से रोक ही सकते थे।''

राजनीति का अपराधीकरण अभी और आज की राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। यह काँग्रेस की सत्तावादी राजनीति की एकान्तिक प्रेरणा का प्रतिफल है। अपराध तथा विश्वासघात की सीढ़ियाँ चढ़कर ही काँग्रेस शासनारूढ़ हुई थी। गाँधी जी की अवज्ञा करके काँग्रेसियों ने आजादी के इस राष्ट्रीय मंच को राजनीतिक दल में बदल दिया था। आजाद भारत में काँग्रेस के पाँव अपराध की डगर पर ही बैठे थे। विश्व के सर्वाधिक भयंकर वीभत्स हत्याकाण्ड के कारण रक्त से सनी सड़कों पर चलकर काँग्रेसी नेताओं ने वायसराय भवन में जाकर मन्त्रीपद तथा गोपनीयता की शपथ ली थी। जिसप्रकार खोटे सिक्के अच्छे सिक्कों को बाजार से बाहर धकेल देते हैं, ठीक उसीप्रकार चरित्र और चिन्तन के धनी नागरिकों को भ्रष्ट एवं गुण्डा तत्त्वों ने राजनीतिक क्षेत्र से बाहर धकेल रखा है। आज की राजनीति सचमुच गुण्डों का चारागाह है। राजनीति केवल इसलिए अपराध बन गई है कि देश की सज्जन शक्ति असंगठित है, उदासीन है, कायर है, विवश विलाप कर रही है कि कोई उसकी रक्षा करे! गुण्डों से गुण्डे और अपराध से अपराध लड़ेगा। गुण्डे और अपराध ही जीतेंगे। सज्जन एवं सदाचार नहीं। आज के राजनीतिक माहौल में सज्जन पक्ष अनुपस्थित है।

-(भानुप्रतापशुक्ल, स्तम्भकार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 14/02/2005)

434) शिक्षा के नाम पर छात्रों का शोषण करने वालों को सुप्रीमकोर्ट की कड़ी चेतावनी :- *शिक्षा के नाम पर छात्रों का व्यावसायिक शोषण करने वालों को उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि किसी भी राज्य में अगर निजी विश्वविद्यालय के पास परिसर, प्राध्यापक, ग्रन्थालय और अन्य सुविधाएँ नहीं हैं, तो राज्य उनके पंजीयन की अनुमति नहीं दे सकता।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 14/02/2005)***

435) अँधेरे में गाँव, प्यासे ग्रामीण :- *बिजली उत्पादन के क्षेत्र में उत्तरांचल को देश का भावी पावर हाउस मानकर जहाँ एक ओर उस पर गर्व किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर वहाँ आज भी न जाने कितने गाँव अँधेरे में अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं, जहाँ के ग्रामीणों के लिए अपने घरों में बिजली देखना सिर्फ एक कल्पनामात्र ही है। या जिन्होंने अपने गाँव में सिर्फ बिजली के खम्भों को ही देखा है, उसमें चमकती बिजली को नहीं। दूसरी ओर यही हाल पेयजल का है, जहाँ पानी की पाइपलाइनें यदि हैं भी तो पानी नहीं। जिस कारण ग्रामीणों को न जाने कितनी समस्याओं से रुबरू होना पड़ता है और अपनी प्यास बुझाने के लिए बहुत दूर पैदल जाना पड़ता है। राज्य के मुख्यमन्त्री द्वारा तमाम घोषणाओं के बावजूद यहाँ की समस्याएँ ज्यों की त्यों हैं, क्योंकि वे घोषणाएँ सिर्फ घोषणाओं तक ही सीमित रह जाती हैं, उन पर कोई कार्य नहीं किया जाता। गाँधी जी के अनुसार भारत तो गाँवों में बसता है। तो सर्वप्रथम गाँवों का विकास होना चाहिए। तभी देश का सही मायने में विकास होगा। गाँव की प्रत्येक समस्या के हल की दिशा में सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।* ***-(कुमारी शना, चनोली; आवाज-ए-खबरदार, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 12/02/2005)***

436) बिहार में नर्तकियों के भाव बढ़े : हथियारों का टोटा : अवैध हथियार फैक्ट्रियों में दिन-रात काम : कारीगरों की हालत दयनीय : मुनाफे की रकम माफिया की जेबों में : सभी हथियार ठिकाने पुलिस की पहुँच से बाहर :- *बिहार विधानसभा चुनाव में अवैध हथियार की माँग तो बढ़ ही गई है, अब नर्तकियों को भी चुनाव के प्रचार में उतारा जा रहा है। इससे एक ओर जहाँ इन हथियारों की किल्लत हो गई है, वहीं दूसरी ओर नर्तकियों के भाव बढ़ते जा रहे हैं। बन्दूकों के निर्माण के लिए मुंगेर के सरकारी बन्दूक कारखाने की एक अलग पहचान रही है। इन दिनों बन्दूकों की सरकारी बिक्री में कमी के कारण इस कारखाने के 50% से अधिक मजदूरों की छँटनी हो गई है, जिनकी संख्या लगभग 2000 है। समझा जाता है कि इनमें से अनेक अपनी जीविका चलाने के लिए माफिया के साथ मिलकर अवैध अग्नेयास्त्रों के निर्माण में लगे हुए हैं। इस विधानसभा चुनाव में अवैध हथियारों की अचानक बढ़ी माँग को पूरा करने के लिए कारीगरों को भी दिन-रात मेहनत करनी पड़ रही है। इसके बावजूद हथियारों की किल्लत बनी हुई है और माँग के अनुरूप हथियारों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अवैध हथियार बनाने में लगे एक कारीगर ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि हम गरीब बन्दूक कारीगर सिर्फ अपने जीवनयापन के लिए इस नाजायज धन्धे में लगे हैं। उन्होंने अपना ठिकाना बताने से भी इन्कार किया और सिर्फ इतना कहा कि हमारे ठिकाने ऐसी जगहों पर हैं, जहाँ पुलिस कभी नहीं पहुँच सकती। कारीगरों की दयनीय स्थिति का पता इसी से लगाया जा सकता है कि अधिकांश कारीगरों की पुत्रियाँ पैसे के अभाव के कारण अविवाहित रह गई हैं और बच्चे भी शिक्षा से वंचित रह गए हैं। बन्दूक के कारीगर ने बताया कि बिहार, उत्तरप्रदेश और झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही उनका काम दिन-रात शुरु हो जाता है। माफिया मुनाफे की अधिकांश राशि हड़प जाते हैं। उन्हें मामूली रकम ही मिल पाती है। चुनाव के दौरान नालंदा, गोपालगंज, मुंगेर और जमुई में बन्दूक बनाने की कई अवैध कारखाने पुलिस ने बरामद कर इस सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। विधानसभा चुनाव में अपराधी, बाहुबली तथा उनके रिश्तेदार चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनमें से कई ने चुनावप्रचार के लिए नर्तकियों का भरपूर इस्तेमाल किया है। नर्तकियों के प्रचार अभियान में लगाये जाने से इनका भाव बढ़ गया है।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 13/02/2005)***

437) न्याय हो तो ऐसा! :- *आज देश में करोड़ो मुकदमे विचाराधीन हैं। बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में अदालतों तथा जजों की संख्या कम है। जब कोई मुकदमा शुरु होता है, तो उसे निचली अदालत से हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक जाते-जाते कई दशक बीत जाते हैं। कई मामलों में तो मुकदमा चलते-चलते पीढ़ियाँ ही बीत जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग थाना कचहरियों के चक्कर लगाने से तंग आकर कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। कुछ लोग विरोधी को कानूनी व अदालती चक्कर में डालने के लिए उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर देते हैं। आपराधिक फौजदारी मामले भी इसी तरह लम्बे खिंचते हैं। पहले पुलिस एफ. आई.आर. दर्ज नहीं करती। दर्ज भी हुई तो जाँच7पड़ताल में काफी समय लग जाता है। कभी अपराधी हाथ नहीं आता। आता है, तो उसके सगे-सम्बन्धी पुलिस जाँच को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं और लम्बे समय तक आरोपपत्र अदालत में पेश नहीं हो पाते। अदालत में मामला पेश होता है, तो लम्बी तारीखें पड़ती हैं। अधीनस्थ अदालत फैंसला सुनाती है, तो दण्डित पक्ष ऊपरी अदालतों में अपील करता जाता है। इस तरह अपराधी लम्बे समय तक सजा पाने से बचा रहता है या किसी कानूनी चुक्ते पर आरोप से मुक्त हो जाता है। जेलों में अनेक ऐसे लोगों के मामले भी हैं, जो छोटे-छोटे अपराधों के आरोप में जेल भेज दिए गए तथा पुलिस उनके मामले अदालतों में भेजना ही भूल गई। वे सम्बन्धित अपराध के दण्ड से भी कई गुना अधिक अवधि तक जेलों में ही जीवन बिताने को मजबूर रहे। इन्हीं बातों का दृष्टिगत कहा जाता है कि 'जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड'। अर्थात् न्याय मिलने में विलम्ब का अर्थ है- 'न्याय का न मिलना'। अब न्याय मिलने में विलम्ब होना एक सामान्य सी बात हो गई है।*

विदेशों में मुकदमों की सुनवाई में विलम्ब नहीं होता। वहाँ पुलिस की जाँच-पड़ताल व अदालती कार्यवाही तेजी से होती है और समुचित अवधि के भीतर अदालतें फैसले भी सुना देती हैं। अदालतों द्वारा दोषियों को त्वरित सजा सुनाए जाने व निर्दोषों को आरोपमुक्त घोषित करने से कानून और न्याय के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती है और लोग जुर्म करने से डरते हैं। ***-(विजय, सम्पादकीय; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 12/02/2005)***

438) *बिहार विधानसभा चुनाव के सन्दर्भ में जहाँ विपक्षी दलों ने अपने-अपने घोषणापत्रों में राज्य की कानून व्यवस्था दुरुस्त करने को प्रमुख मुद्दा बनाया है, वहीं बड़ा हास्यास्पद है कि लालू यादव भी वहाँ कानून व्यवस्था चाक-चौबन्द करने की बात कर रहे हैं। आखिर जिस बिहार ने उनके शासनकाल में विगत 15 वर्षों में पिछड़ने की निम्नतम गहराइयों को छुआ हो, जहाँ लोगों के अपहरण व हत्याओं की घटनाएँ आम बात हो चुकी हों, जहाँ से लोग बदहवास होकर पलायन कर रहे हों, जहाँ मजदूर तबका सुरक्षित काम व उचित मजदूरी के अभाव में अन्य प्रदेशों की खाक छानने पर विवश हो, उस राज्य का मुखिया पुनः इसी कानून व्यवस्था, विकास व रोजगार की गारण्टी जैसे मुद्दे पर वोट माँगे, तो राज्य की जनता के साथ इससे ज्यादा भद्दा मजाक और क्या होगा ? बिहार व उत्तरप्रदेश जैसे बड़े राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति लगभग हाथ से निकल चुकी है। दोनों ही राज्य सरकारें काँग्रेस के समर्थन से चल रही हैं। जिसकी एवज में लालू व मुलायम ने केन्द्र की काँग्रेस सरकार को समर्थन दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में काँग्रेस द्वारा भी कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार व विकास को मुद्दा बनाकर विधानसभा चुनाव में वोट माँगा जाना जनता की आँखों में धूल झोंकने की वृत्ति की पराकाष्ठा है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र जहाँ 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' का ही फार्मूला चलता है। आश्चर्य है कि इसप्रकार की चुनावी जीत को कथित जनादेश की संज्ञा दे दी जाती है।*

-(संजीव बनौथिया, गढ़ीकैण्ट, देहरादून; आवाज-ए-खबरदार, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 11/02/05)

439) लोकतन्त्र की बहाली के लिए राजनेताओं ने राजशाही के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूँका : नेपाल का शाही शासन आखिरकार जनता के अधिकार क्यों छीन रहा है, लिहाजा लोग एकजुट होने लगे हैं :- *राजा ज्ञानेन्द्र द्वारा लगाए गए आपातकाल के बाद नेपाल से भागकर भारतीय क्षेत्रों में निवास कर रहे नेपाली काँग्रेस के नेताओं ने राजशाही के विरुद्ध युद्ध का बिगुल फूँक दिया है। उन्होंने नेपाल सरकार पर जनता के अधिकार छीनने का आरोप लगाते हुए भारतीय क्षेत्रों में जनसम्पर्क अभियान चलाकर समर्थन जुटाया। साथ ही लोकतन्त्र शीघ्र बहाल होने की बात की। गिरफ्तारी के भय से पिछले काफी समय से भारतीय क्षेत्रों में शरण लिए हुए नेपाल काँग्रेस के केन्द्रीय सदस्य व पूर्व सांसद विजयध्वजचन्द, नरेन्द्र सिंह बिष्ट, विष्णुदत्त जोशी व मदन गिरी ने सीमान्त क्षेत्रों में जनसम्पर्क अभियान चलाया और जनता से समर्थन की अपील की। उन्होंने कहा कि नेपाल में लोकतन्त्र की लड़ाई लड़ रहे माओवादियों के साथ अब वह भी लोकतन्त्र की माँग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल में लोकतन्त्र बेहद जरूरी है। चूँकि नेपाल में आज भी आधे से अधिक जनता गरीबी व शोषण का शिकार है, जिनकी माँग को राजनेता ही सरकार तक पहुँचा कर उन्हें न्याय दिलाता है। उन्होंने कहा कि नेपाल नरेश ने सत्ता अपने हाथ में लेकर जनता के अधिकार छीनने का कार्य किया है। नरेश के राज में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है और न ही सुनहरे भविष्य की कल्पना कर सकता है। उन्होंने जनमत को साथ लेकर लोकतन्त्र बहाली के लिए आन्दोलन करने का ऐलान किया।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 11/02/2005)***

440) अबूगरेब जेल में मानवता पर अभिशाप बनकर बरपे रहस्यों का खुलासा : दुर्व्यवहार का नया अध्याय :- *अमरीकी सैनिकों के अमानवीय बर्ताव के कारण दुनिया भर में कुख्यात हुई ईराक की अबूगरेब जेल की कार्यप्रणाली के बारे में कुछ और सनसनीखेस और रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे हुए हैं, जिनसे दुर्व्यवहार के नये अध्याय की रचना हो सकती है। मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक ईराक की यह दुर्भाग्यशाली जेल तकलीफों के बड़े जखीरे में तब्दील थी, जहाँ साध्य और असाध्य रोगों की पीड़ा से कराहते सैकड़ों कैदियों को उपचार तो दूर ढाढस भी नहीं बँधाया जाता था और जेल की बेजुबान दीवारें उनके जख्म की चीखों को सोखती जाती थीं। टाइम पत्रिका ने एक चिकित्साधिकारी और जेल में काम कर चुके कुछ अन्य लोगों से बातचीत के जरिए मानवता पर अभिशाप बनकर बरपे रहस्यों को उजागर किया।*

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 09/02/2005)

441) कैसे सपने? कैसा स्वरोजगार? :- *गत दिनों असम में 5000 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के लिए विज्ञापन दिया गया। इनके लिए दस लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिनमें इंजीनियर, डाक्टर, एम.बी.ए., एम.ए., स्नातक आदि शामिल थे। चयन कि लिए सभी उम्मीदवार भर्ती केन्द्रों पर पहुँचे और वहाँ भीड़ लग गई। चयन प्रक्रिया में अनियमितता के गम्भीर आरोप लगे। जगह-जगह असन्तुष्ट युवाओं ने प्रदर्शन किए तथ कोकराझार में*

उग्र भीड़ ने काँग्रेस कार्यालय को जला दिया। कुछ समय पूर्व पटना में सेना में कुछ सौ रंगरूटों की भर्ती के लिए हजारों युवा भर्तीकेन्द्र में इकट्ठा हो गए थे। वहाँ मची भगदड़ में अनेक युवा पास में बहने वाले बरसाती नाले में डूब गए। अन्य भर्तीकेन्द्रों में भी हमेशा बेरोजगार युवाओं की भारी भीड़ एकत्र होती रहती है।

आज सरकारी नौकरियाँ हैं नहीं। सरकारी विभागों में रिटायर होते जा रहे लोगों के स्थान पर नई भर्तियाँ नहीं की जा रही हैं। पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में 2.5 लाख युवाओं के आवेदन वर्षों से पड़े हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वी.आर.एस. देकर कर्मचारियों की संख्या घटाई जा रही है। सार्वजनिक उपक्रम घाटे में चल रहे हैं तथा वहाँ भी अब रोजगार के क्षेत्र समाप्त हो गए हैं। नौकरियाँ अब केवल निजीक्षेत्र के उद्योगों, व्यवसायों में हैं, लेकिन वहाँ कुशल व उच्च प्रशिक्षित युवाओं को ही प्राथमिकता मिल पाती है। भारी बेरोजगारी को देखते हुए बड़ी संख्या में वहाँ भी युवाओं को रोजगार मिल पाना संभव नहीं है।

प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह कहते हैं कि सरकार के पास नौकरियाँ नहीं हैं अतः युवा छोटे-छोटे स्वरोजगार करके अपने पाँव पर खड़े हों। राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम युवाओं का आह्वान करते हैं कि सपने देखें। अगर सपने नहीं देखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? जब अन्य नेताओं से भी रोजगार वृद्धि की बात की जाती है, तो वे भी युवाओं को स्वरोजगार करने की बात कहते हैं। अब सवाल यह है कि ये युवा छोटे-छोटे रोजगार करें तो कैसे? उनके माता-पिता मुश्किल से जीवनभर मेहनत की कमाई से उन्हें पढ़ाते हैं। छोटे उद्योग भी सरकार की कुनीतियों विश्व व्यापार संगठन सन्धि तथा अन्य वैश्विक आर्थिक दबावों व प्रतिद्वन्द्विता के कारण धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में 9 लाख छोटे उद्योग देश भर में बन्द हो चुके हैं।

ग्रेजुएट स्तर की पढ़ाई के लिए आज 10 हजार से 16 हजार रुपये तक वार्षिक फीस देनी पड़ती है और अन्य खर्चे अलग हैं। उच्चतर शिक्षाा का खर्च तो इससे भी कहीं अधिक है। सरकारी स्कूलों व कालेजों में पढ़ाई की दुर्दशा है। माता-पिता वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। उच्च रोजगारपरक शिक्षा के लिए भारी मात्रा में डोनेशन देनी पड़ती है। अधिकांश बच्चे जब पढ़-लिख कर जब तक उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, तब तक माँ-बाप बूढ़े होने लगते हैं और युवा तब भी नौकरियों के लिए भटकते रहते हैं। माँ-बाप ने बच्चों के लिए जो सपने देखे होते हैं, वे उन्हें धुँधले पड़ते नजर आते हैं। जब युवाओं को बार-बार के आवेदनों, इण्टरव्यू, रोजगार दफ्तरों की लम्बी लाइनों में वर्षों नाम दर्ज कराने के बाद भी नौकरियाँ नहीं मिल पातीं, तो वे कुण्ठित होकर हताशा के गर्त में गिरते जाते हैं या ड्रग्स के आदि बनकर अपना जीवन समाप्त करने लगते हैं अथवा लूटपाट, अपहरणों आदि जैसे अपराधों से जुड़ जाते हैं।

गत दिवस असम में जो कुछ हुआ है, वह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि स्थितियों में सुधार नहीं हुआ जो आने वाले समय में ये और भी विस्फोटक बनने वाली हैं। इस बारे में सभी पार्टियों को गम्भीरता से सोचना व रास्ता निकालना चाहिए। असम तथा पूर्वोत्तर के युवाओं के आतंकवाद की ओर जाने का कारण वहाँ शिक्षा के विस्तार के साथ रोजगार का विस्तार नहीं होना है, जिससे युवाओं में असन्तोष बढ़ा है।

-(विजय, सम्पादकीय; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 09/02/2005)

442) नक्सलवाद : अभी भी वक्त है ...! :- *ऋग्वेद का एक बहुत ही जाना पहचाना श्लोक है, जिसका अनुवाद मैं यहाँ दे रहा हूँ। यह नीतिशतक में भी है- ''मगरमच्छ के मुख की दाढ़ों के नीचे से मणि को भले ही साहस करके निकाल लाया जाए, वेगवती लहरों से लहराते समुद्र को भी भले ही पार कर लिया जाए, क्रुद्ध नागराज को भी माला की भाँति शीश पर भले धारण कर लिया जाए, परन्तु मूर्खों के चित्त में सद्गुणों का संचार करना संभव नहीं है।''*

पुराने जमाने में न जाने किस मनोदशा में उक्त बातें लिखी गई होंगी पर आज अपने अनुभव के पैमाने पर मैं यह स्पष्ट देख रहा हूँ कि केन्द्र में जो भी सरकारें आती हैं, उन्हें राष्ट्रहित में अच्छी से अच्छी बात भी कहीं जाए, राष्ट्र पर मँडराते संकटों की ओर इशारा भी किया जाए, परन्तु ये ऐसे मूर्ख लोग हैं कि इन्हें कुछ सुनाई ही नहीं देता। उदाहरणार्थ- हम नग्न आँखों से ये देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल को नर्क बनाने में माओवाद की क्या भूमिका है? हम नग्न आँखों से यह भी देख रहे हैं कि माओवाद ने बिहार और झारखंड को भी अपने कब्जे में ले रखा है। हम यह भी देख रहे हैं कि इन इलाकों में समानान्तर सरकारें भी चल रही हैं। परन्तु पिछले 15 वर्षों में हमने इस दिशा में क्या कदम उठाए? इसे सारा देश जानता है। कश्मीर का मामला भी सरकारों की आपराधिक निष्क्रियता से बिगड़ा। माओवाद को

भारत में अपने पाँव जमाने का आधार कहाँ से मिला? दक्षिण बिहार और आज के झारखंड कहे जाने वाले भोलेभाले आदिवासी 95% तो जंगलों की कटाई और खनिज सम्पदा से भरपूर हजारों छोटी-छोटी खदानों में कार्यरत थे। पर्यावरण का भूत जब एकाएक सारी दुनिया में सवार हुआ, तो बिहार झारखंड में भी जंगलों की कटाई बन्द हो गई। रिपोर्टें चीख-चीख कर कह रही थीं कि चन्द महानगरों में परिवहन प्रदूषण और फैक्ट्रियों से वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण हो रहा था, वह इससे अधिक समस्या नहीं थी। किन्तु जंगलों की कटाई बन्द हो गई। रातोराज लाखों लोग बेरोजगार हो गए। ये जंगल कभी समाप्त न होते क्योंकि जंगलविभागों का वर्किंग प्लान बड़ा वैज्ञानिक था। हर 30 वर्ष बाद ही यह चक्र एक स्थान पर कटाई की इजाजत देता था। पर्यावरण की दृष्टि से 30 वर्षों पर इनका काटा जाना ही वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक था। जो बाँस के जंगल थे, वहाँ और भी वैज्ञानिक प्रक्रिया थी। किन्तु ठेकेदारी बन्द करके सरकार ने अपने हाथ में व्यापार ले लिया और सारे जंगलों को वनविभाग के छोटे-बड़े कर्मचारियों ने लूट लिया। ठेकेदारों के साथ तो इतना अन्याय हुआ जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य सरकारों की धृष्टता और दुष्टता का अन्दाजा आप भी इस बात से लगा सकते हैं कि दो दशकों से झारखंड में जंगलों की कटाई कानूनी रूप से बन्द है और सैकड़ों आरा मिलें अभी भी वहाँ चल रही हैं। कहाँ से आता है यह माल? बिहार, झारखंड से बाहर किसी अन्य राज्य से दो-चार ट्रक माल की खरीद दिखाकर उससे हजार गुना ज्यादा जंगल आज भी कट रहे हैं। कहाँ हो रही है यह बन्दरबाँट?

बिहार और झारखंड के लाखों लोग भूख से घबराकर पंजाब और हरियाणा में आजीविका ढूँढने चले जाते हैं और शेष लोगों ने मजबूरी में राष्ट्रद्रोही गतिविधियाँ अपना ली हैं। यहाँ नक्सलवादियों में 2% ही अपराधी है, 98% नहीं हैं। सरकार को नये सिरे से सारी समस्या पर सोचना होगा। 2% को फाँसी पर लटका दो परन्तु 98% को सन्मार्ग पर लाना होगा। जंगल में रहने वालों को उनके जंगल लौटाने होंगे। बीड़ी पत्ते के व्यवसाय को अपराधियों से मुक्त करना होगा। माओवाद को मिटाना है तो राजनीति से ऊपर उठकर पहले सहानुभूति से इस समस्या को समझा जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो यह विध्वंसक आग भविष्य में सारे राष्ट्र को भस्मीभूत कर देगी। ***-(अश्विनीकुमार, विशेषसम्पादकीय; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 10/02/2005)***

443) हवस के बाजार में बेआबरू बच्चे और औरतें :- *भारत में प्रतिवर्ष औसतन काफी संख्या में स्त्रियाँ और बच्चे गुम होते हैं। रिपोर्टों से इस तथ्य की पुष्टि होती है। एक्शन रिसर्च ऑन ट्रैफिकिंग इन विमेन एण्ड चिल्ड्रेन इन इण्डिया 2003 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश गुमशुदा व्यक्तियों को देहव्यापार की मण्डियों में बेच दिया जाता है। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र की एक बच्ची की गुमशुदगी की खबर आई थी। रिपोर्ट के अनुसार उसके साथ एक बियरबार में दुराचार और यौनशोषण किया गया। यद्यपि इस तथ्य की पुष्टि हो गई कि उसे देह व्यापार की मण्डी में बेचा गया है। किन्तु पुलिस ने उसका नाम गुमशुदा लोगों की सूची में ही रखा। यूनीफेम तथा इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा संयुक्तरूप से जारी इस रिपोर्ट में ऐसे अनेक बच्चों का उदाहरण दिया गया है, जिन्हें देहव्यापार की मण्डी में बेचा गया। बहुत दिनों बाद इनमें से अधिकांश बच्चों मुक्ति की वेश्यालय तथा ऐसी ही शोषणकारी स्थितियों से हो सकी। देहव्यापार के अवैध धन्धेबाज अक्सर बच्चों और दलित महिलाओं को अपना निशाना बनाते हैं। यह तबका ही समाज का सर्वाधिक तबका है। देहव्यापार की मण्डी में जबरन धकेले गए कुल 463 पीड़ितों में 23% ऐसे थे, जिन्हें वेश्यालय में 16 वर्ष से कम की अवस्था में भेज दिया गया था। इनमें 2% 13 से 15 वर्ष के थे। पीड़ितों के अनुसार मानव व्यापार के अवैध धन्धे में स्त्री और पुरुष लगभग समान संख्या में संलिप्त हैं। 68% से ज्यादा पीड़ितों को नौकरी का लालच दिया गया। जबकि 17% पीड़ितों को शादी का वादा करके इस धन्धे में लगा दिया गया। वेश्यालयों में कई वर्षों तक शोषण का शिकार होने वाले 61% इन पीड़ितों के पास जरा भी जमा पूँजी नहीं थी। देहमण्डी से बच निकले जिन 561 लोगों का साक्षात्कार लिया गया, उसमें 21% 18 वर्ष से कर्म उम्र के थे। जिन 24% को पहले मुक्त किया गया था, उन्हें दोबारा मानव व्यापार का शिकार होना पड़ा। 32% से ज्यादा को स्वास्थ्य समस्याएँ थीं। इसमें भी 30% व्यक्ति यौन संक्रमित रोगों से पीड़ित थे, जबकि 8% ऐड्स से ग्रस्त पाए गए।*

वेश्यालय के मालिकों ने साक्षात्कार में स्वीकार किया कि ज्यादातर माँग कुँवारी लड़कियों की है। उन्होंने यह भी माना कि देहव्यापार में लगे बच्चों से सर्वाधिक मुनाफा होता है।

-(मालविका कौल, आँखिनदेखी; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 08/02/2005)

444) न्यायपालिका : भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है :- *भारत में विधायिका का हाल हम देख ही रहे हैं। कार्यपालिका नौकरशाही का ही परिष्कृत रूप है। न्यायपालिका स्वतन्त्र है। राष्ट्र की न्यायपालिका दिनानुदिन क्षीण होती जा रही है। प्रजातन्त्र से अपेक्षाओं की आखिरी कड़ी है। जहाँ देर या सवेर एक आशा की किरण अवश्य दृष्टिगोचर होती है और आम जनता को कभी-कभी ये लगता है कि हम मानवीय व्यवस्था में जी रहे हैं। एक आम आदमी जिला अदालत तक तो किसी प्रकार मुकदमों को लड़ पाता है परन्तु उच्च तथा उच्चतम न्यायालय में वकीलों की फीस देना आम आदमी के बस की बात अब नहीं रही। अतः हमारी न्यायपालिका का यह पक्ष प्राकृतिक न्याय के दृष्टिकोण से कितना महत्त्वपूर्ण है, इसे समझा जाना चाहिए। सरकार अपनी दयालुता और दूरदर्शिता का सबूत देते हुए कुछ ऐसे प्रबन्ध कर दे कि आखिरी आदमी भी उच्चतम न्यायालय तक पहुँच सके तो यह एक ऐसा क्रान्तिकारी कदम होगा, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एन.डी.टी.वी. के एक कार्यक्रम में उच्चतम न्यायालय की एक वरिष्ठ महिला अधिवक्ता इन्दिरा जयसिंह ने एक बड़ी मार्मिक बात कही। उन्होंने कहा- ''न्यायालय में प्रवेश करते ही हमें द्वार पर लिखे जो 'सत्यमेव जयते' शब्द दिखाई देते हैं, काश! यहाँ इसे मूर्तरूप दिया जा सकता।'' मुझे उस महिला की बात बड़ी क्रान्तिकारी लगी।* ***-(अश्विनीकुमार, विशेषसम्पादकीय; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 06/01/2005)***

445) *सम्पादक अंकल! आपका राष्ट्रीय दैनिक खबरें छुपाता नहीं, छापता है। अंकल! आजकल बच्चों के अपहरण हत्या व बलात्कार की घटनाएँ बढ़ रही हैं। आप बार-बार सरकार को जगाना चाहते हैं। परन्तु हमारे नेताओं को तो जैसे सिर्फ अपने ही बच्चे प्यारे लगते हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह रहती है। हमारी सुरक्षा की कोई चिन्ता नहीं। अब तो स्कूल से घर व घर से स्कूल के रास्ते में दिल में भय रहता है। हम मानसिक रूप से परेशान हैं। हमारी परीक्षाएँ आने वाली हैं परन्तु हम अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं। रोजाना किसी विद्यार्थी, भाई या बहन के अपहरण दिल को दहला देते हैं। हमारे स्कूल के बाहर भी आवारा आदमी या लड़के खड़े रहते हैं। पुलिस कुछ भी नहीं करती। जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था 26 जनवरी तथा 15 अगस्त के दिन होती है, यदि उसका 50 प्रतिशत भी बना रहे तो अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। परन्तु वह सुरक्षा नेताओं की रक्षा के लिए होती है। अंकल जी हम तो बच्चे हैं। आप अपनी कलम को हमारी आवाज बनाकर सरकार व प्रशासन के कानों तक पहुँचाकर अपना कर्तव्य निभाएँ।*

-(लीनाशर्मा, विद्यार्थी, कक्षा-8, राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्याविद्यालय, जहाँगीरपुरी, नईदिल्ली; आवाज-ए-खबरदार, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 08/02/2005)

446) *आधुनिक युग में बड़े औद्योगिक घराने अपनी घटिया वस्तु को बेचने तथा बढ़िया वस्तु की साख बिगाड़ने के लिए क्या-क्या हथकण्डे अपनाते हैं, यह अमरीकी लेखक 'रोन स्चीम्ड' की प्रसिद्ध पुस्तक 'द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मिल्क' से स्पष्ट हो जाता है। अमरीका में 1944 तक ताजे दूध का प्रचलन था और यह ताजा दूध पुष्ट गायों का था, जो हरा चारा खाती थीं तथा चारागाहों में स्वछन्द घूमती थीं। परन्तु इस ताजे दूध के विरुद्ध प्रचार की नींव 1812 में रखी गई। 1812 में इंग्लैण्ड तथा अमरीका के बीच में स्वतन्त्रता संग्राम हुआ था, जिसके बाद अमरीका स्वतन्त्र हो गया। प्रतिशोध की भावना से ग्रसित होने के कारण इंग्लैण्ड ने अमरीका को शराब बेचना बन्द कर दिया। अमरीका को शराब बनाने के उद्योग अपने देश में स्थापित करने पड़े। यह शराब अनाज के दानों से बनाई जाती थी। शराब बनाने के बाद जो रसायनयुक्त दाने तथा गन्दा पानी बच जाता था, उसका प्रयोग गायों को पालने के लिए किया जाने लगा, जिससे शराब की लागत कम हो जाए तथा उद्योगपतियों का लाभ बढ़ जाए। फलतः डेरियाँ स्थापित हो गईं। इन डेरियों में गायें एक कमरे में बन्द रखी जाती थीं, जिसका फर्श पक्का होता था। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि गायें मोटी होने लगीं और उनका दूध बढ़ गया। परन्तु वे बीमार रहने लगीं तथा कम आयु में मरने लगीं। दूषित भोजन और बीमारी के कारण गायों का दूध भी दूषित होता था। परन्तु यह दूध बहुत सस्ता पड़ता था। अतः औद्योगिक घरानों में दो प्रकार के प्रचार करने शुरु किए। एक तो ताजे पौष्टिक दूध के विरुद्ध प्रचार शुरु किया और दूसरे दूषित दूध को पाश्च्युराइज्ड और उसके गुणों का प्रचार किया। उन्होंने इन दोनों कार्यों को सफलतापूर्वक करने के लिए सबसे पहले तो विद्वानों, वैज्ञानिकों, डाक्टरों तथा अनुसंधान कर्ताओं को आर्थिक सहायता देकर अपनी तरफ किया। वे अपनी विद्वता तथा शोधकार्यों के आधार पर प्रचार सामग्री तैयार करने लगे। भारतवर्ष में भी गत 50 वर्षों से यही कर रहे हैं।*

-(शान्तिस्वरूप गुप्ता, आगरा; आवाज-ए-खबरदार पंजाबकेसरी, दिल्ली, 08/02/2005)

447) भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर 9 वर्ष से वेतन नहीं : हरीराम को थीना ग्रहर :- *संप्रग सरकार के दूरसंचार मन्त्री दयानिधि मारन के विभाग में दया और न्याय कितनी दूर है तथा विभाग के भ्रष्ट अधिकारी अपने ही कर्मचारी की निधि कैसे मारे बैठे हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हरीराम है। हरीराम से गलती इतनी हुई कि उसने भ्रष्टाचार और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई, तो विभागीय चोर मौसेरे भाई बन बैठे और उन्होंने हरीराम को बिना निलंबन ही उसका सालों का वेतन और मेडिकल बिल आदि रोककर उसे तो राम भरोसे लायक बना दिया है। जबकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ते-लड़ते आर्थिक तंगी की वजह से हरीराम का पुत्र राम को प्यारा हो चुका है। भ्रष्टाचार, जालसाजी, धोखाधड़ी एवं पद के दुरुपयोग की यह दास्ताँ ऐसी है कि हरीराम एम.टी.एन.एल. के खुर्शीद लाल भवन स्थित मुख्यालय के प्रशासनिक एवं सतर्कता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को 200 से भी अधिक शिकायती पत्रों की मार्फत खुद के साथ हो रही बाबूराज की अन्धेरगर्दी का विस्तृत विवरण देकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की माँग कर चुका है किन्तु उसकी आवाज नक्कारखाने में तूती की आवाज साबित हो रही है। दूरसंचार मन्त्री दयानिधिमारन पर स्वयं ही अनियमितताओं के इतने आरोप हैं कि वे उनसे ही बेदाग निकल जाएँ, तो गनीमत है। मुखिया चाहें कैसा भी हो, अन्ततः पारिवारिक या विभागीय शिकायत उसी के पास जाती है और उससे ही न्याय की अपेक्षा की जाती है।* **-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, फरवरी, 2005)**

448) झारखंड और नेपाल : कुछ तथ्य और कुछ कटु सत्य :- *3 फरवरी यानि ठीक चुनाव के दिन झारखंड की पुलिस ने वहाँ के अखबारों में एक-एक पृष्ठ के लम्बे विज्ञापन छपवाए। मैं उस विज्ञापन को उद्धृत करना चाहूँगा :-*

''झारखंड में उग्रवाद क्यों? जानिए जो सच है। ये उग्रवाद के नाम पर लेवी के रूप में पैसे वसूलकर स्वयं धनवान बनते हैं। अपनी महिला सहकर्मियों को बलात्कार कर उन्हें मजबूर करते हैं। धनोपार्जन के नाम पर बैंक लूटते हैं। ये देश के विकास में बाधक भी हैं। पहचानिए! अपने बीच छिपे हुए मानवरूपी भेड़ियों को जो मार्क्सवाद और साम्यवाद के नाम पर चल रहे आन्दोलनों की आड़ में विभिन्न उग्रवादी संगठनों द्वारा आपकी स्वतन्त्रता, सम्मान व अधिकार का हनन करते हैं। बस, अब और नहीं! आइए मिलकर हम उग्रवाद, आतंकवाद व अत्याचार को खत्म करें। -निवेदक : झारखंड पुलिस।''

उपरोक्त विज्ञापन से स्पष्ट यह सन्देश निःसृत होता है कि इन सारे उग्रवादी संगठनों के संरक्षक या प्रेरणास्रोत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वामपंथी हैं। भारत की सरकार भी वामपंथियों की मेहरबानी पर टिकी हुई है। यहाँ से अब मैं सीधा नेपाल पर आता हूँ। जो माओवादी किसी भी कीमत पर वहाँ लोकतन्त्र लाने की बात कर रहे हैं, वे कैसा लोकतन्त्र लाना चाहते हैं, उसे सहज ही समझा जा सकता है। भारत भी जिसे प्रजातन्त्र कहकर पुकार रहा है, क्या वह सचमुच प्रजातन्त्र है। भारत की सरकार ने जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपराधियों मन्त्री बने रहने के पक्ष में हलफनामा दाखिल किया, उसी दिन भारत से प्रजातन्त्र सही मायनों में धूलधूसरित हो गया। सरकार प्रजातन्त्र की लाश ढोने को मजबूर है। नेपाल में जो माओवादी हैं, उन्हीं के लोग सम्पूर्ण झारखंड में प्रजातन्त्र के तथाकथित प्रणेता बने हुए हैं।

-(अश्विनीकुमार, विशेषसम्पादकीय; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 04/02/2005)

449) मतदान के पहले दौर में 21 मरे : झारखंड में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग से पुलिस वाहन उड़ाया, हथियार लूटे, सात मरे : बिहार में अनेक स्थानों पर बूथ कब्जे, पुलिस फायरिंग, तीन महिलाएँ, दो होमगार्ड और दो अन्य मरे : हरियाणा में काँग्रेस प्रत्याशी के ड्राइवर की हत्या रोड़ी और मरवाना में भी झड़पें :- *हरियाणा, बिहार और झारखंड में 178 विधानसभा सीटों पर आज कराए गए चुनाव में नक्सली तथा चुनावी हिंसा में 21 लोगों की मौत के बीच तकरीबन 55 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।*

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 04/02/2005)

450) *अमरीका ने नेपालनरेश ज्ञानेन्द्र द्वारा सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेने के बाद नये शासन से सम्पर्क स्थापित कर लिया। प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबा की सरकार बर्खास्त होने से खिन्न अमरीका ने तत्काल सम्वैधानिक राजशाही के तहत बहुदलीय लोकतन्त्र की बहाली की बात कही है। अमरीकी विदेश मन्त्रालय के प्रवक्ता एडम इरेली ने कहा- ''हमारा मानना है कि नेपाल सरकार को बहाल किया जाना चाहिए और नागरिक व मानवाधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। साथ ही राजनीतिक और छात्रनेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई की जानी चाहिए और सम्वैधानिक राजशाही के तहत बहुदलीय लोकतन्त्र की बहाली की जानी चाहिए।* **-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 05/02/2005)**

451) हाईकोर्ट जज बिहार में ड्यूटी निभाने में असमर्थ : तबादला चाहा :- *पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर.एस.गर्ग ने कहा कि बिहार में हाईकोर्ट जज का काम करना बेहद मुश्किल है। इसलिए वे सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करेंगे कि उनका तबादला कहीं अन्यत्र कर दिया जाए। उल्लेखनीय है कि कार्य के दौरान पटना हाईकोर्ट से सटे मजार से नमाज की अजान को लाउडस्पीकर से प्रसारित करने अदालती कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण न्यायमूर्ति गर्ग ने अपनी अदालत में पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को अदालत में चार बजे उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए सम्मन जारी कर दिया, लेकिन पटना पुलिस ने जुम्मे की नमाज के दौरान ही मजार के मौलवी और मस्जिद कमेटी के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और लाउडस्पीकर जब्त कर लिया। इसके बाद नाराज अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 05/02/2005)***

452) *जब भी मैं अपने तिरंगे की तरफ देखता हूँ, मेरे मस्तिष्क में इसकी रक्षा करने वालों के बलिदान का दृश्य उमड़ पड़ता है। क्या हमारा तिरंगा हमसे यह सवाल नहीं कर रहा है कि हम लोग प्रत्येक भारतीय अपने 24 घण्टे में से देशसेवा और मातृभूमि के कर्तव्यपालन के लिए कितना समय निकाल पा रहे हैं? क्या आज पुनः स्वतन्त्रता संग्राम को प्रारम्भ करने की आवश्यकता नहीं है, उन शक्तियों के विरुद्ध जो देश को पुनः भ्रष्टाचारियों और निकम्मे प्रशासन के हाथों गिरवी रख चुके हैं? क्या पुनः भारत छोड़ो आन्दोलन प्रारम्भ करने की आवश्यकता नहीं है, उन रिश्वतखोर भ्रष्टाचारी निकम्मे अधिकारी एवं कर्मचारी और देशवासियों को बाँटने वाले तथा एक भारतीय को सहस्रों टुकड़ों में तोड़ने वाले दोगले भ्रष्ट नेताओं के विरुद्ध जो आज देश में धर्म, जाति, भाषा, सम्प्रदाय तथा क्षेत्रीयता की बेड़ियों में भारतमाता को जकड़े हुए हैं, जिनसे स्वतन्त्र होने के लिए भारतमाता छटपटा रही है। क्या हम आज के भारतीयों को अपनी भारतमाता की ये बेड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही हैं, जिनमें जकड़ी हुई यह अभागिन मातृभूमि तड़प रही है। यदि हमने तुरन्त इसको स्वतन्त्र नहीं कराया, तो निश्चय ही हमारी अकर्मण्यता पर भारतमाता और अमरशहीद क्रान्तिकारियों को अपने आत्मबलिदान पर पछतावा होगा, क्योंकि उनका बलिदान रंग ही नहीं ला पाया है। तभी तो हम अपनी भारतमाता को सरे बाजार नीलाम होते देखते रहते हैं। भारत पुत्रों उठो! भारत वीरों उठो! मातृभूमि तुम्हें पुकार रही है। आओ इसे आजाद कराएँ! आजाद कराएँ उस मातृभूमि को जो आज बाहुबली, स्वार्थी, अक्षम, अयोग्य राजनेताओं तथा भ्रष्टाचारी नौकरशाही के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है।*
-(अयूबख़ाँ भारतीय, बुलन्दशहर; आवाज-ए-ख़बरदार, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 05/02/2005)

453) गोवा की भाजपा सरकार बर्खास्त : विश्वासमत पेश होने पर स्पीकर ने एक विपक्षी विधायक को सदन से निकाल दिया और अपने वोट से सरकार जिता दी :- *गोवा विधानसभा में हुए शक्तिपरीक्षण में विवादास्पद ढंग से विश्वासमत हासिल करने वाली 32 माह पुरानी मनोहर पारिक्कर सरकार को बर्खास्त कर दिया तथा काँग्रेस को सरकार बनाने का न्यौता दिया। राज्य विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मुख्यमन्त्री के विश्वासप्रस्ताव के पक्ष में अपना मत देने और काँग्रेस को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक को सदन से अयोग्य ठहराने के निर्णय से विश्वासमत विवादों से घिर गया। विधानसभा में विश्वासमत पूरा होने के तुरन्त बाद राज्यपाल ने मुख्यमन्त्री को बर्खास्त कर दिया। भाजपा ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल का यह कदम अनुचित है और पार्टी इस निर्णय के खिलाफ राष्ट्रपति से शिकायत करेगी।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 03/02/2005)***

454) असन्तुष्ट सुन्नी ईराक के संविधान में पैदा कर सकते हैं गतिरोध : मतदान में भाग नहीं लिया : सद्दाम के अपदस्थ होने के साथ ही सुन्नियों का वर्चस्व समाप्त :- *ईराक के अल्पसंख्यक सुन्नी समुदाय के अधिकतर लोगों ने रविवार को हुए मतदान में भाग नहीं लिया। लेकिन अभी भी उनके पास नये संविधान पर रोक लगाने की शक्ति है। अप्रैल 2003 तें तत्कालीन सद्दाम हुसैन सरकार के अपदस्थ किए जाने के साथ ही ईराक में सुन्नी समुदाय का वर्चस्व समाप्त हो गया था। अब उन्हें शिया और कुर्द समुदाय का सामना चुनाव में करना पड़ा है। ईराक की कुल 2 करोड़ 70 लाख आबादी में सुन्नी समुदाय की आबादी मात्र 20% है। एकसमान राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया के तहत पूरे ईराक में एकसाथ कराए गए चुनावों में सुन्नी समुदाय को एक भी असेम्बली सीट मिलने की सम्भावना नहीं है। नई असेम्बली के सदस्य राष्ट्रपति और दो उपराष्ट्रपति का चयन करेंगे। प्रमुख सुन्नी समूह मतदान से अलग रहा।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 03/02/2005)***

455) वेंकैया को हुआ बिहार में भयानक स्थिति का अनुभव : ग्रामीणों के हाथ में बन्दूकें :- *भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने आज कहा कि बिहार में किस तरह की भयानक स्थिति है, इसका अनुभव उन्हें कल हुआ। बिहार के उग्रवाद प्रभावित गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के परड़िया गाँव से 13 किमी की दूरी स्कूटर पर तय करके सकुशल राँची लौटने पर श्री नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि कल कि घटना से उन्हें अनुभव हुआ कि वास्तव में बिहार में भयंकर स्थिति है और चुनाव आयोग को इसे गम्भीरता से लेकर सुरक्षा के तमाम उपाय करने चाहिए। उन्होंने बताया कि जब उनके हेलीकाप्टर को आपातकालीन स्थिति में बाराचट्टी थानाक्षेत्र के एक गाँव में उतारना पड़ा तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस थाने को दी गई। लेकिन पुलिस घटना स्थल पर नहीं पहुँची और मजबूरन वह एक स्थानीय व्यक्ति के स्कूटर पर पीछे बैठकर 13 किमी दूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुँचे, जहाँ पुलिस उनका इंतजार कर रही थी। पुलिस से पूछने पर पता चला कि उसके पास वाहन, वायरलेस और पुलिसकर्मियों की कमी है, जिसके कारण उनका मनोबल काफी गिरा हुआ है। वेंकैया ने उग्रवाद प्रभावित जिलों की खतरनाक स्थिति के बारे में बताया कि मैंने खुद अपनी आँखों से देखा कि ग्रामीण इलाकों में लोग बन्दूक लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने कहा–''पिछले 15 वर्षों में बिहार में सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएँ मुहैया नहीं कराई गई हैं।'' नायडू ने कहा कि बिहार में लालू ने रोजगार का बँटवारा तो अपहर्ताओं, अपनी पत्नी और सालों के बीच ही किया। जबकि राज्य की जनता त्रस्त है और लालू निश्चिन्त हैं। पति–पत्नी ने मिलकर बिहार की दुर्गति कर दी है। बिहार के 40000 गाँव में बिजली नहीं है। बिहार के 90% ग्रामीण चिकित्सा सुविधा से वंचित हैं। जबकि 50% जनता अशिक्षित है। केन्द्र और राज्य में राजद और काँग्रेस की सरकार है, फिर भी ये लोग एक मौका और माँग रहे हैं। बिहार की बदहाली के लिए काँग्रेस भी बराबर की जिम्मेदार है।*

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 31/01/2005)

456) बिहार की कानून और व्यवस्था :- *वेंकैया जी (भाजपा अध्यक्ष) का हेलीकाप्टर 'गया' जिले के बाराचट्टी नामक स्थान में क्या जला, हाहाकार मच गया। एक मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर डरते–काँपते जब वह थाने पहुँचे, तो मौत का खौफ उनके चेहरे से स्पष्ट झलक रहा था। जिस रास्ते से वह होकर आए, उसके बारे में कहा– ''मैंने ऐसा खराब रास्ता जिन्दगी में नहीं देखा।'' उसके बाद आडवाणी जी ने बिहार की स्थिति पर मनमोहन सिंह से लेकर चुनाव आयोग तक के लिए जो उपदेशात्मक बातों की झड़ी लगा दी है, उसे सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अटल जी तक कह रहे हैं– ''किसलय मेरा बेटा है।'' अरुण जेटली भी सुर में सुर मिला रहे हैं। यह अचानक क्या हो गया? जब ये सारे लोग सत्तासीन थे और बिहार में बार–बार ट्रेनों में बलात्कार के मामले गूँजते थे, व्यापारियों के अपहरण हो रहे थे, बैंक अधिकारियों और डाक्टरों की शामत आई हुई थी, ट्यूशन पढ़ाने वालों को भी नहीं बख्शा जा रहा था, तब कहाँ थे ये भाजपा नेता? मेरी यह कलम भी बार–बार चीख–चीख कर इन सत्ताधारियों की आँखें खोलने के लिए कहती रही, पर इनकी आँखों पर पट्टी बँधी हुई थी।*

यह कितनी विचित्र त्रासदी है कि जब जनता के साथ अत्याचार होते हैं, आम आदमी मारा जाता है, आम आदमी की बहू–बेटियाँ उठा ली जाती हैं, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। परन्तु नेताओं को जब इसकी जरा भी आँच लगती है, तब कानून व्यवस्था की बातें शुरु हो जाती हैं। मैं राष्ट्र के लोगों को स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि इन रँगे सियारों की नजरों में जनता की कोई कीमत नहीं और जनता को अपनी रक्षा के लिए स्वयं जाग्रत होना होगा। इन्हें रँगे सियार कहकर सियारों से भी क्षमायाचना करने की इच्छा होती है, क्योंकि ये सियासतदाँ (राजनीतिज्ञ) वे लोग हैं, जो एक तरफ तो चुनाव आयोग को गुहार लगा रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव कराओ और दूसरी ओर माननीय उच्चतम न्यायालय में यह हलफनामा दाखिल किया जाता है कि अपराधियों को मन्त्री बनने से संविधान का अनुच्छेद–75 नहीं रोक सकता। पिछले दो दशकों में बाबाछाप संविधान की आड़ में सिर्फ अपराध, आपराधिक संस्कृति और अपराधियों का ही महिमा मण्डन हुआ है और ये अपराधी जब गगन बिहारी बनकर हेलीकाप्टरों पर सवार होकर बिहार झारखंड जैसे क्षेत्रों में वोट माँगने जाते हैं, तो इनकी आँखों में शर्म भी नहीं दिखाई देती। नक्सलवाद भी इन्हीं की अदम्य धनलोलुपता से उपजा है। अतः ये सफेदपोश अपराधी इस सभ्य समाज के लायक नहीं रहे। जो मनुष्यों का समाज है। यह पशुवत हो चुके हैं। इन्होंने राष्ट्र के मूल्यों को गिरवी रख दिया है। इस राजनीति ने जाति–पाति, धार्मिक विद्वेष, घृणा, उन्माद, अपराध, संकीर्णता, दुष्टता बढ़ाया है। वक्त ने दस्तक दे दी है। जिस दिन जनता का लावा फूटा, वैसे राजनेता जो अपराधों के बल पर राष्ट्र के कर्णधार हो गए हैं, उन्हें अपने कुकृत्यों की सजा भोगनी ही होगी।

-(अश्विनीकुमार, विशेषसम्पादकीय; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 01/02/2005)

457) मानवाधिकार आयोग में सर्वाधिक मामले पुलिस प्रताड़ना के :- *राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट फिर से खाकी वर्दी में पैबन्द की भाँति सामने आई है, जिसमें मानवाधिकार के उल्लंघन के सबसे ज्यादा मामलों में पुलिस ज्यादती और पुलिस हिरासत में हुई मौतों और फर्जी मुठभेड़ के मामले दर्ज हैं। आयोग द्वारा वर्ष 2002-03 के लिए जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट में मानवाधिकार उल्लंघन की 67354 शिकायतें आई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 1340 हिरासत में हुई मौतों से सम्बन्धित हैं। मानवाधिकार अयोग के पास पहुँचे मामलों में 3595 मामले अवैध गिरफ्तारी के, 2783 मामले झूठे मामलों में फँसाने के, 706 मामले हिरासत में हिंसा के और 9622 शिकायतें दूसरी पुलिस ज्यादतियों की थीं। सबसे ज्यादा मामले उत्तरप्रदेश से दर्ज किए गए, जहाँ इसकी संख्या 40612 रही। उसके बाद बिहार है तथा तीसरे स्थान पर दिल्ली है, जहाँ मानवाधिकार उल्लंघन के 3796 मामले दर्ज किए गए।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 31/01/2005)***

458) भारतीय उपमहाद्वीप अशान्ति की ओर :- *भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव तथा म्याँमार आते हैं। अँग्रेजों ने बाँटो और राज्य करो की नीति अपनाते हुए बर्मा (म्याँमार) तथा श्रीलंका को भारत से अलग कर दिया। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका व म्याँमार 1947 के आस-पास ही ब्रिटिश गुलामी से मुक्त हुए। अँग्रेज जाते-जाते भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बनवा गए, जो पश्चिमी व पूर्वी पाकिस्तान कहलाए। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के सात देशों ने मिलकर दक्षिण एशियाई सन्धि संगठन (सार्क) का गठन किया। इस क्षेत्र के देशों को आजादी देते समय अँग्रेज ऐसे काँटे बो गए, जो आजादी के 57 साल बाद भी इस क्षेत्र के लिए समस्या बने हुए हैं। अफगानिस्तानी सरकार तालिबान व अलकायदा के आतंकवादी हमलों से त्रस्त है। पाकिस्तान में ऐसा कोई राज्य नहीं है, जहाँ अशान्ति व्याप्त न हो। बांग्लादेश दो राजनैतिक दलों के आपसी संघर्ष से त्रस्त है। श्रीलंका लिट्टे उग्रवादियों की खूनी हिंसा से ग्रस्त है। नेपाल माओवादियों की हिंसा से बुरी तरह ग्रस्त है। भारत को यद्यपि इस क्षेत्र की महाशक्ति माना जाता है, लेकिन इसे भी अपनी आन्तरिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। जम्मू-कश्मीर व पूर्वोत्तर में कोई दिन ऐसा नहीं जाता, जब आतंकवादी कोई हिंसक काण्ड न करते हों। बिहार, झारखंड व आन्ध्रप्रदेश नक्सली हिंसा से ग्रस्त हैं। उत्तरप्रदेश राजनीतिक अपराधीकरण से ग्रस्त हैं। दिल्ली तक जघन्य अपराधों से मुक्त नहीं है।*

यह सभी देश जहाँ आन्तरिक अशान्ति से ग्रस्त हैं, वही इनके बीच विभिन्न कारणों से कुछ में एक-दूसरे के प्रति टकराव की स्थितियाँ भी हैं। कुल मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप के इन देशों में किसी न किसी कारण अशान्ति है और यह उपमहाद्वीप हिल रहा है। ***-(विजय, सम्पादकीय; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 30/01/2005)***

459) *प्रजातन्त्र के बारे में एक इतालवी कहावत है- 'यह एक ऐसा अद्भुत राजतन्त्र है, जिसमें एक राजा नहीं होता, बहुत से राजा होते हैं और ये सब मिलकर उस राजा से अधिक खतरनाक, अत्याचारी और अन्यायी होते हैं, जो अकेला राज्य करता है।'*

यह कहावत प्रजातन्त्र को निकृष्ट राजतन्त्र की संज्ञा देती है। राज्यपाल की प्रतिबद्धता यदि किसी विशेष राजनीतिक पार्टी से ही हो, तो वह व्यक्ति भी रीढ़विहीन ही समझा जाना चाहिए। आप उस दृश्य की कल्पना करें कि हजारों की संख्या में छोटे-छोटे बच्चों ने राजभवन को घेरा हुआ है। बच्चे भूखे-प्यासे हैं। राज्यपाल से मिलकर किसलय नामक छात्र को छुड़ाने की बात करना चाहते हैं। 'वी वान्ट जस्टिस, वी वान्ट जस्टिस' चिल्लाते हुए उनके सूखे होठ बड़ा कारुणिक दृश्य भी पैदा करते हैं। परन्तु लाटसाहब राजभवन से नहीं निकलते। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, उसे इशारों से समझा जाए। एक महान विचारक वाल्टेयर ने कहा था- 'इवेन इफ देयर इज नो गॉड, वी विल हैव टु क्रिएट वन'। अर्थात् अगर भगवान नहीं भी है, तो भी हमें एक भगवान का सृजन करना होगा। अगर कानून नहीं भी है, तो भी बचाइए बिहार को। किसलय का मामला कान्वेन्ट यानि डी.पी.एस. का आया तो इसीलिए इतनी बात भी सामने आई, वरना यहाँ तो सैकड़ों छात्र हर वर्ष अपहरण का शिकार होते हैं, हजारों नारियों की अस्मत हर वर्ष लुटती है। ये भी बेचारे बच्चे हैं, रो-रोकर अन्ततः चुप हो जाएँगे। ***-(अश्विनीकुमार, विशेषसम्पादकीय; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 30/01/2005)***

460) आज का सच : सबसे बड़ा धर्म क्या? :- *कई अतिमहत्त्वपूर्ण लोगों के पत्र मैं सँजोकर रखता हूँ। उत्तरप्रदेश की एक 80-85 वर्षीया वृद्धा डाक्टर का पत्र मन को झकझोर जाता है। लिखती हैं :-*

''मैं तब युवा थी। कोलकाता से डाक्टरी की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1940 का जमाना था। विद्यार्थी काल में अकेली ही इण्टर क्लास में सफर करती थी। प्रशासनिक व्यवस्था इतनी अच्छी थी, क्या कहूँ? किन्तु आज पोतियों के साथ मैटिनी शो सिनेमा देखकर घर पहुँचती हूँ, तो भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ।''

बिहार के पूर्णिया जिले की एक समाजसेविका का पत्र है :-

''कौन जनतन्त्र की बात करता है? सामने लाओ! ये गुण्डातन्त्र है। ये बदमाशतन्त्र है। मध यकालीन बर्बर व्यवस्था तो इससे भी अच्छी रही होगी।

मूलतः ऊधमपुर के निवासी और अब बलाचौर पंजाब के रहने वाले एक सरदार साहब लिखते हैं :-

''उम्र 90 वर्ष है। 1947 में गुजरावाला (पाकिस्तान) में रहता था। सारा परिवार लुटाकर हंडूर (हिन्दुस्तान) 1948 से 1984 तक पटनासाहिब में बरफ बेचता रहा। दो कमरे भी डाल लिए थे। 1984 के दंगों में सबकुछ लुट गया। 1985 में मैं वापस कश्मीर पहुँचा। 1991 में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों की गोली का शिकार हो गया। अब वापस आकर लँगड़ा बुद्धू बना गलियों की धूल फाँक रहा हूँ। हिन्दुस्तान में सबकुछ कहना, कभी प्रजातन्त्र या गणतन्त्र जैसे शब्दों की बात मत करना।''

उड़ीसा की सुनीता प्रधान लिखती हैं :-

''मेरा नाम भी छाप दें, कोई फिक्र नहीं। आज हमारा वजूद कहाँ है। कौन कहता है, यह गणतान्त्रिक राष्ट्र है? कैसे वोटिंग होती है? वोट देता कौन है? खून, खराबा, हत्या, बलात्कार, फिरौती? मात्र दो या ढाई सौ घराने भारत पर हुकूमत कर रहे हैं।''

झारखंड के जीतवाहन मुण्डा लिखते हैं :-

''आपकी मेहनत देखकर हैरान हूँ। लिखते रहिए! यह मुल्क कभी जागेगा नहीं। ये सारे लोग अफीम खाकर सोए हुए हैं। जहाँ भी कोई जागने की बात करता है, उसे अफीम खिलाकर सुला देते हैं। आप भी अफीम चखिए और सो जाइए। ये गुण्डातन्त्र है, गणतन्त्र कहाँ है।''

और अब एक अजीबोगरीब पत्र। लिखने वाली स्वयं को दसवीं की छात्रा कहती है। नाम निरूपमा लिखा है। सुदूर रायगढ़ से लिखती हैं :-

''ये उग्रवाद नेताओं की उपज है। ये मंचों पर लम्बे-चौड़े भाषण देते हैं। वोट लेने के लिए नोट बाँटते हैं। जाति-पाति को बढ़ावा देते हैं, हथियार खरीदते हैं। मैं वोट उसको दूँगी, जो इन बड़े नेताओं को समुद्र में डुबो दे।''

मैं हैरान हूँ एक भी तो पत्र ऐसा मिलना चाहिए था जो इस जनतन्त्र, प्रजातन्त्र या गणतन्त्र के बारे में वह बात लिखता, जो हम आज तक किताबों में पढ़ते थे कि :-

''भारत एक महान देश है। हमें 1947 में अहिंसा के अग्रदूत बापू ने आजादी दिलाई। यह आजादी बिना खड्ग और बिना ढाल के मिली। नेहरू चाचा की दूरदर्शिता इस कार्य में बड़ी सहायक सिद्ध हुई। आजादी में चरखे का बड़ा योगदान रहा। हमारा संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। इससे बड़ा लिखित संविधान कहीं नहीं है। इसका श्रेय बाबा साहब को जाता है। पंडित नेहरू ने कहा था- हम जैसा भारत बनाना चाहते थे, वैसा हमने बना दिया है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों सँभाल के।''

अगर बच्चों को निबन्ध लिखना हो, तो उपरोक्त बातें ही उन्हें परीक्षा में सबसे अधिक अंक दिला सकती हैं। किन्तु अगर उन्होंने पूर्व के पत्रों को उद्धृत किया, तो अनुत्तीर्ण होना निश्चित है। हो सकता है स्कूल से ही निकाल दिया जाए। ऐसे में चाटुकारनीति कहती है- ''वक्त के साथ चलो! सच को सँभालकर बोलो! नहीं तो न बोलो! स्वप्नलोक में विचरण ही श्रेयष्कर है! जिसका खाओ, उसके गुण गाओ! नेताओं का कभी निरादर न करो!'' चाटुकारिता कई बार आपको महानता का प्रमाणपत्र भी दिला सकती है। बिना प्रमाणपत्र के महान नहीं हुआ जा सकता। आप पद्मश्री, पद्मभूषण तो क्या भारतरत्न से भी आगे ब्रह्माण्डरत्न और ब्रह्माण्डसुन्दरी भी हो सकते हैं। आप महान बनें। चाटुकारों की कहावत है- 'जब तक जियो, सुख से जियो। कर्जा खाओ विशुद्ध घी पियो।' परन्तु सत्य न बोलना, यही सबसे बड़ा धर्म है।

-(अश्विनीकुमार, विशेषसम्पादकीय; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 28/01/2005)

461) विवाहिता के साथ सामूहिक बलात्कार :- *एक विवाहिता स्त्री मजदूरी के लिए जा रही थी। तमंचों की नोंक पर उसका अपहरण करके करीब आधा दर्जन लोगों ने डेढ़ महीने तक न केवल उसे बन्धक बनाए रखा, बल्कि उससे सामूहिक बलात्कार भी किया। अभियुक्तों के चंगुल से किसी तरह छूटकर अपने घर पहुँची स्त्री ने जब पति व ससुर के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया, तो थाना पुलिस ने उन्हें टाल-मटोल कर भगा दिया। इसके बाद पीड़िता ने एस.एस.पी. से न्याय की गुहार लगाई।*

-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 29/01/2005)

462) राजनीति : चोर-चोर मौसेरे भाई! :- *जब 30 का दशक था, भारत में अँग्रेजों की हुकूमत थी, सरदार भगतसिंह अपनी बात अँग्रेजों को सुनाना चाहते थे, पर वे सुन नहीं रहे थे। अतः भगतसिंह ने असेम्बली में धमाका किया। आज वक्त बदल गया है। आज प्रजातन्त्र का जमाना है। आज वैसे धमाकों की कोई आवश्यकता नहीं है। अखबार, टीवी, धरना, अनशन बहुत से माध्यम हैं। सरकारों के कानों तक आवाज पहुँचाई जा सकती है। हाँ एक बात तब भी थी, वह आज भी है। सरकारें सदा ऊँचा सुनती हैं। आज धमाकों की परिभाषा बदल गई है। आज बिहार में चुनाव हो रहे हैं और छोटे परदे पर रोज वहाँ की विभिन्न प्राइवेट सेनाओं की झलकियाँ दिखाई जा रही हैं। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। नक्सलवाद के खिलाफ एकजुट होने की दलील, ए.के.47 से लेकर राकेटलांचर तक हाथ में, पाँव में चप्पल नहीं और रिमोट द्वारा संचालित होते से लगने वाले ये चेहरे जब चुनाव आता है, तो अपनी-अपनी गुफाओं से निकलते हैं और समाज काँपने लगता है। न जाने 70 के दशक के बाद कितनी सेनाएँ बनी और बिगड़ीं। कुँवर सेना, ब्रह्मर्षि सेना, लौरिक सेना, दलित सेना, रणवीर सेना, श्रीराम सेना, लिबरेशन आर्मी। न जाने कितने समीकरण बने और बिगड़े। बिहार में अपराधों की परिणति हम देख रहे हैं। आज समाज के बच्चे और महिलाएँ सड़कों पर हैं। जब बच्चों के अपहरण हों, तो माताएँ रौद्ररूप धारण करेंगी ही। तटस्थ पुरुषसमाज वहाँ नपुंसक हो चुका है, पूर्णतः पुरुषत्वविहीन। वह धीमी आवाज में कमरे के दरवाजे और खिड़कियाँ बन्द करके सरकारी आतंकवाद की निन्दा करता है, सड़कों पर उतरना नहीं चाहता। अतः लोकसभा से लेकर विधानसभा तक वैसे लोग छा जाना चाहते हैं, जिन्होंने जाने-अनजाने इण्डियन पैनल कोड की सारी धाराओं से बेपनाह मुहब्बत करने को ही जीवन की सार्थकता माना है। जब संसद में ऐसे महारथी हैं, तो अपने घर विधानसभा के क्षेत्र में 'लॉ एण्ड आर्डर' के आलम का अन्दाजा पाठकगण खुदा लगा सकते हैं। मैं चाहता हूँ 28 अक्टूबर, 1975 को जो कुछ इन्दिरा जी कॉमनवेल्थ पार्लियामेन्टरी कान्फ्रेन्स को सम्बोधित करते हुए बोलीं, काँग्रेसी न केवल उसको जानें, बल्कि उसका प्रचार भी करें। श्रीमती इन्दिरा गाँधी 'को' तो काँग्रेसियों ने बहुत माना, अब श्रीमती इन्दिरा 'की' मानने से ही कल्याण होगा। उनकी दो बातें उद्धृत कर रहा हूँ :-*

''कभी-कभी कुछ देश ये सोचते हैं कि उन्होंने प्रजातन्त्र का जो माडल अपना रखा है, वह सारे ब्रह्माण्ड के लिए ठीक है। वे ये भूल जाते हैं कि जो बात वर्षों पूर्व प्रासंगिक थी, उसका अब कोई मूल्य नहीं रहा। आने वाली नस्ले जरूर पुराने सिस्टम को तराजू पर तोलेंगी और पुराने को नकार देंगी।''

उसी भाषण का दूसरा अंश देखें :-

''वही सिस्टम राष्ट्र के लिए ठीक है, जो बदलते हुए समय के साथ स्वयं को ढाल सके। मुख्य बात यह है कि यह जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरा है। जब बहुसंख्यक जनता अपने लिए दो जून के भोजन के लिए संघर्ष कर रही हो, तो क्या वह उनको कभी माफ करेगी, जो उनकी बदौलत चुने जाने पर ऐश की जिन्दगी पाँच वर्ष तक बिताना अपना अधिकार समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता की भलाई जिसमें हो वही व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है।''

आज पटना में महिलाओं ने अपने कायर पतियों को सन्देश भेजा है- ''तुम चूड़ियाँ पहनकर बैठो। सड़कों पर हम लड़ेंगे।''

इन्दिरा जी के वचन मूर्तरूप ले रहे हैं। चोरों, डाकुओं को जनता कब तक बर्दाश्त करेगी। काश! इन्दिरा जी देख पातीं, आज तो इसके विपरीत उनके ही अपने चोर-चोर मौसेरे भाई हो गए हैं।

-(अश्विनीकुमार, विशेषसम्पादकीय; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 29/01/2005)

463) ईराक में आधी सदी बाद हुए चुनाव : आतंकवादी संगठनों के हमलों में 31 मरे : सुन्नीबहुल इलाकों में वोट नहीं पड़े : कई इलाकों में मतदान केन्द्रों के दरवाजे तक नहीं खुले : शियाबहुल इलाकों में लम्बी कतारें :- *ईराक में लगभग आधी सदी बाद हुए ऐतिहासिक आम चुनाव में मतदान के दौरान गड़बड़ी फैलाने पर आमादा आतंकवादी संगठनों द्वारा अनेक हमलों में कम से कम 31 लोग मारे गए। देश के सुन्नी अरब बहुल इलाकों में बहुत से लोगों द्वारा चुनाव के बहिष्कार की वजह से मतदान बहुत कम रहा। लेकिन उत्तर के कुर्द क्षेत्रों तथा शियाबहुल इलाकों में मतदान केन्द्रों के बाहर लम्बी कतारें देखी गईं।* ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 31/01/2005)***

464) थोड़ी सी इज्जत पर उनका भी हक है :- *गरीब तबके के लोगों से जानवर से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। पता नहीं लोग क्यों भूल जाते हैं कि गरीब भी इन्सान हैं। उनका भी जमीर है। वे भी प्यार के भूखे हैं। दासप्रथा तो बहुत पहले खत्म हो गई, लेकिन हकीकत यह है कि गरीब तबके के लोगों की जिन्दगी अब भी दासों से बढ़कर नहीं है। जैसे दासों पर उनका मालिक हुक्म चलाता था, मनमाने तरीके से काम लेता था, ठीक उसी तरीके से मजलूमों के साथ व्यवहार किया जाता है। कहीं भी देख लीजिए आपको गरीब लोगों पर धौंस दिखाने के वाकये मिल जाएँगे। ढाबों, होटलों में ही देखिए– ऐ छोटू इधर आ! अबे तूने यहाँ पानी नहीं रखा! चल फटाफट थोड़ी सलाद लेकर आ! कुर्सी पर जमे ग्राहकों के मुँह से ऐसे जुमले सुनने को मिल जाएँगे। इन जुमलों में तो फिर भी कोई खास बात नहीं बल्कि खास होता है, कहने का अन्दाज। ऐसा कहते वक्त ज्यादातर लोगों का अन्दाज घुड़की भरा होता है। अगर छोटू ने आदेश का पालन करने में देर कर दी तो गाली–गलौज तक पहुँचते देर नहीं लगती। और अगर गलती से ग्राहकों के कपड़ों पर थोड़ी बहुत सब्जी, पानी वगैरह बिखर गया, तो समझो उसकी पिटाई निश्चित है, वह भी दोहरी। पहले ग्राहक अपना गुस्सा उतारेगा और रही–सही कसर ढाबा, होटल वाला पूरी करेगा। यह हकीकत तो हुई ढाबे–होटलों के छोटुओं की। इसके अलावा भी जहाँ कहीं भी आपको छोटू नजर आएँगे, वहीं पर उनके साथ बड़े–बड़े अत्याचार भी होते दिख जाएँगे। जिन लोगों का रौब कहीं नहीं चलता, वे भी छोटुओं पर अपनी भड़ास निकालते हैं। घर से लेकर दफ्तर तक बड़ी दुकानों से लेकर रेहड़ी पटरियों तक हर जगह मजलूमों की सामर्थ्य है। आपने ऐसे वाकये जरूर देखे होंगे, जब कोरियर की डिलिवरी में थोड़ी सी देर होने पर रिसीवर यानि लेने वाला व्यक्ति उसके साथ गाली–गलौज पर उतर आता है। डिलिवरी ब्वाय की हर दलील झूठी और कोरियर रिसीव करने वाले का हर अन्देशा सच्चा है। इन गरीबों की क्या गलती? उनकी गलती है गरीब होना। उनकी गलती है ढँग का रोजगार न मिलना और पेट पालने के लिए चोरी, डकैती करने के बजाय मेहनत का रास्ता चुनना भी उनकी गलती है। रेहड़ी, पटरी लगाने वालों को ही लीजिए। यदि रेहड़ी किसी दुकान के आसपास लगा ली, तो आधा दिन तो दुकानदार की सेवापानी में ही गुजर जाएगा। अब यह ला, वह ला, फलाँ काम कर, वहाँ चला जा, इस तरह के अनावश्यक आदेशों का पालन करते–करते बेचारे की चकरघिन्नी बन जाएगी। शारीरिक मेहनत हुई सो अलग। उधर दुकानदारी भी पिट जाएगी। इसके बावजूद एक बार भी भूलचूक से उसने ना–नुकर कर दी तो गाली खानी ही पड़ेगी। साथ ही वहाँ से ठेली हटाने की धमकी भी मिल जाएगी।*

कहने का मतलब है– 'छोटू' उपनाम वाले लोगों की कहीं खैर नहीं। हजार में से कोई ही ऐसा छोटू होगा, जिसे इस दौर से गुजरना नहीं पड़ता। ज्यादातर छोटू तो बेचारे होश सँभालते ही इस दुश्चक्र में फँस जाते हैं और आजीवन इसमें पिसते रहते हैं। जब भी देखों उनके साथ जानवरों जैसा ही व्यवहार किया जाता है। एक बार भी विरोध किया, तो फिर और अधिक दुर्दशा होनी निश्चित है। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, जो सालों तक काम कराने के बाद अपने छोटू को मार–पीट करके भगा देते हैं। इसे तो क्रूरता की हद ही कहा जाएगा, लेकिन ऐसा करने वाले लोगों की नजर में इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मानो गरीब लोग जुल्म का शिकार होने के लिए ही बने हैं। ***-(नरेन्द्रकुमार, ऑखिनदेखी, मंगलवार्ता; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 25/01/2005)***

465) नेपाल में बिगड़ते हालात :- *भारत का पड़ोसी नेपाल आजकल माओवादियों की हिंसा से ग्रस्त है। महाराजा वीरेन्द्र, महारानी ऐश्वर्या सहित राजपरिवार के छह सदस्यों की हत्या के उपरान्त उनके छोटे भाई ज्ञानेन्द्र नेपाल के सम्राट और श्री शेरबहादुरदेउबा प्रधानमन्त्री बने। तब से नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति है। एक के बाद एक कई प्रधानमन्त्री बदले जा चुके हैं। भाई व उनके परिवार की हत्या के बाद*

सिंहासनारूढ़ ज्ञानेन्द्र के पाँव अभी तक नहीं जम पा रहे हैं। महाराजा महेन्द्र के समय से ही चीन ने नेपाल में सड़क निर्माण आदि में सहायता देकर वहाँ अपने पाँव जमाने शुरु कर दिए थे। नेपाल-चीन मैत्री की आड़ में अनेक युवाओं को चीन में अध्ययन आदि के लिए ले जाया गया तथा माओवाद की घुट्टी पिलाई गई। नेपाल में राजशाही, गरीबी, पिछड़ापन, बेरोजगारी आदि ऐसी बातें थीं, जिनके कारण माओवादियों को बढ़ते जन असन्तोष का लाभ उठाने का अवसर मिला। 1996 में राजशाही का तख्ता पलटने का संकल्प लेने वाले माओवादियों ने हिंसा का मार्ग अपनाया। इस समय 17 जिलों में वे खूनी पंजे फैला चुके हैं और छह जिलों में उनका समानान्तर शासन है। अब तक वे सैनिकों व पुलिसकर्मियों सहित 3000 से अधिक लोगों की हत्या कर चुके हैं। शाही सेना इनके खिलाफ अभियान चला रही है, जिसमें अनेक माओवादी मारे जा चुके हैं। लेकिन इन विद्रोहियों पर अंकुश नहीं लग पाया। इन उग्रवादियों द्वारा अक्सर धनियों, सरकारी कर्मियों व अधिकारियों के अपहरण, अपनी माँगे मनवाने अथवा धन ऐंठने आदि के लिए किए जाते रहे हैं। लेकिन गत दिवस उन्होंने पूर्वी नेपाल में धुपो और मत्स्यपोखरी गाँव के स्कूलों से 1100 छात्रों तथा 47 शिक्षकों का अपहरण कर लिया। इनको उत्तरी नेपाल में ले जाया गया ताकि उनकी विचारधारा को माओवाद से प्रभावित किया जा सके और अपने कैडर को बढ़ाया जा सके। माओवादी चाहे स्वयं को निर्धनों, दलितों, पिछड़ों व आम जनता के जितना भी हितचिन्तक कहें, लेकिन उनकी गतिविधियों से आम नेपाली दोहरी चक्की में पिस रहे हैं। एक ओर माओवादी उनसे जबरी धनवसूली करते हैं, उनका या उनके बच्चों का अपहरण करते हैं या उन्हें जबरी भर्ती के लिए दबाव डालते हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस उन पर शक करती है तथा आतंकवादी होने के संदेह में पकड़कर ले जाती है और यातनाएँ देती है। नेपाल के अनेक निर्धन युवा भारत में विभिन्न शहरों में रोजगार करते हैं। वे जब अपने गाँवों में वापस जाते हैं, तो उन्हें माओवादियों का खतरा बना रहता है। नेपाल में माओवादियों के बढ़ते प्रभाव के कारण भारत के लिए भी खतरा बढ़ रहा है। जहाँ नेपाल में खतरे बढ़ गए हैं, राजा और प्रशासन कमजोर हुए हैं। प्रधानमन्त्री अधिक देर तक टिक नहीं पाते। पुलिस माओवादियों से डरती है। वहीं साथ लगे भारतीय इलाकों में भी हालात बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। ऐसी स्थिति में भारतसरकार को नेपालसरकार से मिल-जुलकर कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे माओवादियों पर अंकुश लग सके। ***-(विजय, सम्पादकीय; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 29/01/2005)***

466) भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में बेरोजगारी सबसे बड़ी बाधा : राष्ट्रपति :- *देश को वर्ष 2020 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने में बेरोजगारी को सबसे बड़ी बाधा बताते हुए राष्ट्रपति ए.पी.जे.अब्दुलकलाम ने आज कहा कि देश के 54 करोड़ युवाओं की चिन्ता के इस प्रमुख कारण को दूर करने के लिए शिक्षाप्रणाली में बदलाव करना होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के ज्यादा से ज्यादा साधन उपलब्ध कराने होंगे। राष्ट्रपति ने 56वें गणतन्त्र दिवस की पूर्वसंध्या पर राष्ट्र के नाम अपने पारम्परिक सम्बोधन को रोजगार की समस्या पर केन्द्रित करते हुए कहा कि रोजगार की चिन्ता केवल स्कूल या कालेज की शिक्षा प्राप्त करने वालों की ही नहीं, बल्कि हमारी भी मुस्कान फीकी कर रही है। हमारे उन सपनों को बिखेर रही है और उस चमक को समाप्त कर रही है, जो हमने देश के हर तबके युवाओं की आँखों में देखी थी। उन्होंने कहा कि बचपन से लेकर युवावस्था तक मुस्कान बनाए रखने का समाधान रोजगार पैदा करना ही है। यह हमारे राष्ट्र के करीब 54 करोड़ युवाओं की आभिलाषाओं और चिन्ताओं का प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि यही समय है, जब राष्ट्र को कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा ढाँचागत सुविधाओं के विकास और महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता जैसे पाँच क्षेत्रों में विभिन्न मिशन योजनाएँ आरम्भ करनी चाहिए। इनसे भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र में बदल जाएगा। कलाम ने देशवासियों का आह्वान किया कि आइए 56वें गणतन्त्र दिवस के इस अवसर पर हम स्वयं को एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए समर्पित करें, जो सभी को रोजगार दे सके, जहाँ आर्थिक समृद्धि हो और जिस राष्ट्र की नैतिक मूल्यों से युक्त शिष्टाचार पूर्ण विरासत हो।*

उन्होंने कहा कि इससे पूर्व 58वीं स्वतन्त्रता दिवस की पूर्वसंध्या पर राष्ट्र के नाम अपने सन्देश में मैंने आपसे 'मानवजीवन की गरिमा के लिए शिक्षा' पर चर्चा की थी। भारत जैसे देश में शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य हमारे मानवसंसाधनों की क्षमता को विकसित करना और उन्हें बढ़ाना है और धीरे-धीरे उन्हें ज्ञानवान समाज में बदलना है। ज्ञानवान समाज ऐसे उत्पाद और सेवाएँ निर्मित करने वाला समाज होगा। इस ज्ञानवान

समाज की असली पूँजी इसके पढ़े-लिखे नागरिक होंगे। हमारी शिक्षाप्रणाली को स्वयं जल्द से जल्द संगठित होकर वर्तमान चुनौतियों को पूरा करने और सामाजिक परिवर्तन में भागीदार बनने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाना चाहिए। 2020 तक हमारा रोजगार स्वरूप 44 प्रतिशत कृषि, 21 प्रतिशत विनिर्माण और 35 प्रतिशत सेवाक्षेत्र होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विनिर्माण और सेवाक्षेत्रों में काम की तलाश में शहर आने से रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएँ उपलब्ध करवा कर रोजगार पैदा करने में सहयोग देना है। ***-(एक समाचार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 26/01/2005)***

467) राजनीति एक छल है, कपट है, धोखा है, फरेब है! :- *''अब मैं समझने लगा हूँ कि राजनीति एक छल है, कपट है, धोखा है, फरेब है। मैं राजनीति से ऊब गया हूँ। राजनीति के कपटपूर्ण और आडम्बरयुक्त वातावरण से निकलकर सुख और शान्ति का अनुभव कर रहा हूँ।'' उपरोक्त सुभाषित मेरे लिए एक शाश्वत सत्य ही है। शाश्वत इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उपरोक्त बात मेरे पूज्य पितामह स्वर्गीय लाला जगत नारायण जी ने कही थी, बल्कि शाश्वत सत्य इसलिए कि यह एक ऐसे दधीचितुल्य महाप्राण का उद्घोष है, जिन्होंने आयुपर्यन्त सत्य और लोकमंगल का मार्ग न छोड़ा। परन्तु जीवन के अन्तिम वर्षों में उन्हें यह अनुभूति अवश्य हो गई थी कि ''राजनीति से बड़ा छल और धोखा कुछ भी नहीं। इससे बड़ा कपट और फरेब कुछ भी नहीं।''* ***-(अश्विनीकुमार, विशेषसम्पादकीय; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 24/01/2005)***

468) जो हुआ सो हुआ, अब भी है सही दिशा निर्धारण का मौका :- *भारतीय जनतन्त्र को अबाधरूप से गतिमान और सुव्यवस्थित रखने के लिए दिशानिर्देश सम्बन्धी एक दस्तावेज तैयार किया गया, जिसको नाम दिया गया- भारतीय संविधान। इस संविधान को स्वीकार करने के साथ ही सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय एकात्मता, सर्वधर्म समभाव बनाए रखने और सामाजिक आर्थिक विषमता को समाप्त करने की सोद्देश्य पूर्ण प्रतिबद्धता को मान्यता प्रदान की। इस संविधान के माध्यम से बिना किसी भेदभाव के सभी को चिन्तन-मनन, जीवनयापन, विचार-अभिव्यक्ति, और स्वतन्त्रता का समान अवसर प्रदान किया गया। दुर्भाग्य से सांविधानिक यात्रा उस समरसता और सामन्जस्यपूर्ण ढँग से शुरु नहीं हुई, जिसकी अपेक्षा संविधान निर्माताओं और देश के मूर्धन्य लोगों ने की थी। फिर संविधान लागू होने के बाद से अब तक लगभग 100 संशोधन किए जा चुके हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों महसूस की गई?*

26 जनवरी, 1950 को भारतीय जनतन्त्र के संविधान को देश की करोड़ों जनता की ओर से आत्मार्पित किया गया था और एक सम्प्रभुतासम्पन्न गणराज्य की स्थापना करने की घोषणा हुई थी। घोषणा के साथ यह भी कहा गया था कि न्यायधर्म और सामाजिक स्तर सभी के लिए समान होंगे। लेकिन संविधान के निर्माणकाल में और उसको आत्मार्पित करने के बाद भी देश के अनेक चिन्तकों एवं विचारकों ने एकदम स्पष्ट बात कही थी कि यह संविधान हमारी अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति के अनुकूल नहीं है। यह भारत का संविधान नहीं बल्कि दुनिया के देशों से उधार लेकर जोड़ा गया एक संयुक्त दस्तावेज मात्र है। इस संविधान में एकता का मन्त्र नहीं विघटन का मन्त्र निहित है। यह सत्तारुढ़ दल की सनक एवं स्वभाव का दास बनकर रह जाएगा। उपरोक्त आशंकाएँ कितनी सच थीं अथवा कितनी गलत, इसका विश्लेषण कर पाना अब कठिन नहीं है। 'जन' और 'तन्त्र' के बीच खाई बढ़ती गई। 'जन' से 'सत्ता' कटती गई। परिणामस्वरूप समाज का जीवन असन्तुलित होता गया। एक आत्मनिर्भर स्वावलम्बी 'जन' के स्थान पर सत्तासापेक्ष और शासनतन्त्र की बैसाखी पर टिके परावलम्बी 'जन' की तादाद बढ़ गई और बढ़ रही है। 'कुछ करने' की सात्त्विक तमन्नाएँ कुछ पाने की तामसी अन्धकार में विलीन हो गईं और हो रही हैं। प्रेरणाओं का स्रोत सूखता जा रहा है और आसेतु हिमाचल भारत बोलियों, भाषाओं, जातियों तथा क्षेत्रों के घरौंदों में बँटकर कंगाल बनता गया और बनता जा रहा है। सम्पूर्ण राष्ट्र की अखण्ड प्रतिमा की अवधारणा मात्र भाषणों तक सीमित रह गई। 'तन्त्र' इतने भयानक रूप से अपने करतब दिखाता है कि 'जन' की आत्मा तक काँप उठती है। अतएव आज की परिवर्तित परिस्थिति में इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर शासन और समाज एक-दूसरे से कटे-कटे से क्यों हैं? राजनेता और जनता के बीच यह दूरी क्यों है? राष्ट्रजीवन में जनसामान्य की भागीदारी क्यों नहीं बढ़ रही है? पाँच वर्ष में केवल कुछ क्षणों के लिए वोट देते समय की वह साझेदारी क्या पर्याप्त है? क्या मात्र वोट देने को ही सहभागिता कहा जा सकता है? देश के केवल 15 से 20

प्रतिशत मुठ्ठी भर लोग देश की ४० से ४५ प्रतिशत आबादी पर इसप्रकार अपना कब्जा जताते हैं, मानो उन पर शासन और शोषण करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या न्याय की तुला पर समानरूप से सबको तोलने की घोषणा का लाभ उस भूखे-नंगे को आज मिल रहा है, जो हजारों रुपया खर्च करके दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय तक आने की कल्पना भी नहीं कर सकता? क्या विचार-अभिव्यक्ति व्यक्ति स्वतन्त्रता और सामाजिक समता का सुख ४५ प्रतिशत लोगों को उपलब्ध है, जिसे शासनतन्त्र एवं समाज का सम्पन्न वर्ग ढोरों (पशुओं) की भाँति हाँका करता है? क्या रोजगार के अवसर सुविधाभोगी वर्ग के चंगुल से निकलकर उसके पास तक पहुँच पाए हैं? समाज के मुठ्ठीभर निहित स्वार्थी वर्ग की मुठ्ठी में देश की तकदीर बन्द है। न्याय और स्वतन्त्रता, सामाजिक-आर्थिक समता की चर्चा शहरी बुद्धिजीवियों की मानसिक विलासिता की सन्तुष्टि करने का साधनमात्र है। वह जीवन की वास्तविकता नहीं बन पाई है। स्वतन्त्र भारत ने आज से लगभग पाँच दशक पूर्व जो साहसपूर्ण कदम उठाया था, ऐसा लगने लगा है कि वे कदम अब लड़खड़ाने लगे हैं। प्रश्न यह है कि अत्यन्त ही गहन निष्ठापूर्वक भारतीय जनतन्त्र के सर्वसमावेशी मार्ग पर चलने का संकल्प धारण करने के बाद यह स्थिति क्यों निर्मित हो गई कि निष्ठा और संकल्पों को बार-बार दोहराया तो जाता है किन्तु जनविश्वास क्षीण होता जा रहा है।

दरअसल आज कुछ ऐसी स्थिति है कि जिन राजनीतिक दलों के प्रति जनमत की अभिव्यक्ति होती है। उनका चरित्र और उन दलों के संचालकों का संकुचित चिन्तन देश और सम्वैधानिक मर्यादाओं की चिन्ता न करके केवल सत्तासुख भोगने की तिकड़म में लगा हुआ है। हर दल का दोहरा व्यक्तित्व और हर नेता के दो चेहरे बन गए हैं। एक है, चुनाव के समय का चेहरा और चरित्र। दूसरा है, सत्ता में आने के बाद का व्यवहार। इन दोनों के बीच इतना लम्बा फासला है कि दलों और व्यक्तियों की निष्ठा की पहचान कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। कारण स्पष्ट है- जब यात्रा के प्रारम्भ में ही पग गलत दिशा में पड़ गए, तो सही राह पर चलना कैसे संभव होगा? अब मात्र यही हो सकता है कि जहाँ तक आ गए हैं, वहीं ठहर कर अपनी सही दिशा का निर्धारण कर लें। अनुभव की कसौटी पर अपने संविधान को कसें, परखें, इसका परिष्कार करें। देश का सम्पूर्ण जीवन एवं भविष्य जिस किताब में बन्द है, उसका शान्त चित्त से पारायण तथा परीक्षण करें। अब कुछ ऐसा करने का समय आ गया है कि देश की अन्तरात्मा को अभिव्यक्त करने वाला कोई इस प्रकार का दस्तावेज बनाया जाए, जिसमें भारत की समग्र जीवनशक्ति सन्निहित हो।

-(भानुप्रतापशुक्ल, वरिष्ठ स्तम्भकार; पंजाबकेसरी, दिल्ली, 24/01/2005)

अटका कहाँ स्वराज्य? बोल दिल्ली! तू क्या कहती है?
तू रानी बन गयी वेदना जनता क्यों सहती है?
सबके भाग्य दबा रखे हैं जिसने अपने कर में?
उतरी थी जो विभा, बता बन्दिनी हुई किस घर में?
समर शेष है यह प्रकाश बंदीगृह से छूटेगा।
और नहीं तो तुझ पर एक दिन महावज्र टूटेगा।।

-(रामधारी जी दिनकर)

अधिकार खोकर बैठना भी तो महादुष्कर्म है।
न्यायहित में बन्धु को भी दण्ड देना धर्म है।।
जब तक मानव-मानव का सुखभाग नहीं सम होगा।
शमित न होगा कोलाहल संघर्ष नहीं कम होगा।।

-(रामधारी जी दिनकर)

कुछ समझ नहीं आता रहस्य ये क्या है।
जाने भारत में बहती कौन हवा है।।
गमलों में हैं जो लगे सुरम्य सुदल हैं।
धरती पर हैं जो फूल दीन दुर्बल हैं।।
जब तक है ये वैषम्य समाज सड़ेगा।
कैसे हो करके एक ये देश बढ़ेगा।।

-(रामधारी जी दिनकर)

देशवासियों जागो क्योंकर फँसे हो झूठे नारों में।
जन्म ले रही क्रान्ति जलाओ दीप आज अँधियारों में।।
गलाघोट सरकारें आतीं जाति धर्म का भेद बढ़ातीं।
शासक चोर बने बैठे हैं नहीं अमन की बात सुहातीं।।
वेश्या बन गयी राजनीति तुम उलझ गए मक्कारों में।
भ्रष्ट खिवैया है शासन डूबेगी नाव किनारों में।।
सभ्य समाज बनाना है बर्बर को मार भगाना है।
देखा सपना जो गाँधी ने उसके पथ पर ही जाना है।।
आवाज बुलन्द गगन में हो न बनेगी बात इशारों में।
बिगुल बजे सबके विकास का हिल-मिल रहो विचारों में।।
प्रहरी बनो हिमालय के सागर की गहराई जानो।
हर नीति फरेबी शासन की है इसकी बात नहीं मानो।।
सब काम देशहित के करने हैं मत बैठो दरबारों में।
अर्ज खुदा से यही है 'अहमद' सृजन हो सब गलियारों में।।

-(अहमद विद्रोही, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 20/01/2004)

इन्साफ की डगर पे, बच्चों दिखाओ चलके।
ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्हीं हो कल के।।
दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुँह से कहना।
सच्चाइयों के बल पर आगे को बढ़ते रहना।।
रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के।
इन्साफ की डगर पे, बच्चों दिखाओ चलके।।
अपने हों या पराये सबके लिए हो न्याय।
देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए।।
रस्ते बड़े कठिन हैं चलना सँभल-सँभल के।
इन्साफ की डगर पे, बच्चों दिखाओ चलके।।
इन्सानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना।
तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना।।
जीवन नया मिलेगा अन्तिम चिता में जल के।
इन्साफ की डगर पे, बच्चों दिखाओ चलके।।

-(फिल्म : 'गंगा-जमुना')

संघ चाहता है व्यक्ति-व्यक्ति का विकास हो।
राज्य अर्थ रूढ़ि शक्ति भेद का न दास हो।।
मुक्त हो कदम बढ़ें अबाध प्रगति के लिए।
समग्र का विकास हो अभिन्नभाव से जिए।।
दीन की न बेबसी अमीर का विलास हो।
सांस्कृतिक परम्परा सजीव शक्तिस्रोत हो।।
अंधकार रात्रि में अखण्ड दीपज्योति हो।
बन्धुभाव एकता सुबुद्धि गर्व हास हो।।
संघ चाहता है व्यक्ति-व्यक्ति का विकास हो।।

-(राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पुस्तक : राष्ट्रवन्दना)

पथ का अन्तिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना।
सब समाज को लिए साथ में, आगे है बढ़ते जाना।।
इतना आगे इतना आगे, जिसका कोई छोर नहीं।
जहाँ पूर्णता मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं।।
सभी दिशाएँ मिल जाती हैं, उस अनन्त नभ को पाना।
सब समाज को लिए साथ में, आगे है बढ़ते जाना।।
वैभव तब ही सच्चा समझें, सब सुख पाएँ लोक सभी।
बाधाओं भय कुंठाओं से, मुक्त धरा गतशोक सभी।।
गुरु की पूजा 'न्याय व्यवस्था', निखिल विश्व में सरसाना।
सब समाज को लिए साथ में, आगे है बढ़ते जाना।।
इस महान उद्देश्य प्राप्ति हित, लगे भले जीवन सारा।
एक जन्म क्या बार-बार ही, इसी हेतु जीवनधारा।।
जिएँ इसी हित और मृत्यु को, इसी हेतु है अपनाना।
सब समाज को लिए साथ में, आगे है बढ़ते जाना।।

-(राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पुस्तक : राष्ट्रवन्दना)

सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से।
अँधेरे ने दी चुनौती है, किरण अन्तिम अस्त होती है।
दीप निष्ठा का लिए निष्कंप, वज्र टूटे या उठे भूकंप।
यह बराबर का नहीं है युद्ध, हम निहत्थे विरोधी सन्नद्ध।
हर तरह के शस्त्र से है सज्ज, और पशुबल हो उठा निर्लज्ज।
किन्तु फिर भी जूझने का प्रण, पुनः अंगद ने बढ़ाया चरण।
होमने सर्वस्व हैं तैयार, समर्पण की माँग अस्वीकार।
दाँव पर सबकुछ लगा है, रुक नहीं सकते।
टूट सकते हैं मगर हम, झुक नहीं सकते।।

-(भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, अटलबिहारी वाजपेयी)

उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों में न पहुँचा।
खुला पींजरा है मगर रक्त अब भी, थके पंक्षियों के परों में न पहुँचा।।
मिले जा रहे धूल में रत्न अनगिन, कदरदान अपनी कदर कर रहे हैं।
मिला बाँटने जो अमिय था सभी को, प्रजा का गला घोट घर भर रहे हैं।।
प्रजातन्त्र की धार उतरी गगन से, मगर नीर जन सागरों में न पहुँचा।
खुला पींजरा है मगर रक्त अब भी, थके पंक्षियों के परों में न पहुँचा।।
बिंधा जा रहा कर्ज से रोम तक भी, न थकते कभी भीख लेकर जगत से।
बिछाए चले जाल जाते विधर्मी, मगर स्वप्नदर्शी नयन हैं न खुलते।।
बचा देश का धन लिया तस्करों से, मगर मालिकों के करों में न पहुँचा।
खुला पींजरा है मगर रक्त अब भी, थके पंक्षियों के परों में न पहुँचा।।

-(राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पुस्तक : राष्ट्रवन्दना)

तुमने दीवारों की जड़ में, दफनाया जिंदा लाशों को।
अंगारों की तह के ऊपर, बुला रहे हो मधुमासों को।।
स्वर्ण अक्षरों में लिखते हो, अपने काले अभ्यासों को।
चाँदी के टुकड़े पा करके, तोड़ दिया सत् विश्वासों को।।
सुन्दर तन के काले मन से, तो काला तन ही अच्छा है।
अतः नीच सुन्दरताई को, मैंने नमन नहीं सीखा है।।
अपने सुख के लिए फूल सी, मुस्कानों को लूट रहे हो।
बनते हो प्रिय मित्र मगर तुम, अहसानों को लूट रहे हो।।
आमंत्रित कर रंगमहल में, ईमानों को लूट रहे हो।
बहका करके भोले-भाले, इन्सानों को लूट रहे हो।।
यह तो सच है इतने पर भी, लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं।
ऐसी ओछी चतुराई को, मैंने नमन नहीं सीखा है।।
मेहनत की सूखी रोटी से, अच्छे नहीं तुम्हारे व्यंजन।
मेरे हाथों की मिट्टी से, अच्छा नहीं तुम्हारा चन्दन।।
मेरे फटे हुए कपड़ों से, बुरा तुम्हारा उजला दामन।
क्योंकि रक्त चूसा है तुमने, मैंने सदा बहाए श्रम कन।।
बेच-बेच कच्ची कलियों को, माली तुम बन गए चमन के।
लेकिन तुमसे अन्यायी को, मैंने नमन नहीं सीखा है।।

-(सन्तचेतना, धर्म एवं राजनीति : वैकल्पिक चिन्तन)

धीरे-धीरे सुलग रही है, कहीं रुई में आग।
अरे! देश के रखवाले तू, जाग सके तो जाग।।
घोर निराशा है अभाव से, जनता टूट चुकी है।
भूख गरीबी को सहने की, सीमा छूट चुकी है।।
छिपे पेट के अन्दर अब तो, लावा मचल रहा है।
शंका भरी हुई आँखों में, गुस्सा उबल रहा है।।
बचा सके तो पहल आज कर, उजड़ न जाए बाग।
अरे! देश के रखवाले तू, जाग सके तो जाग।।
तिनके जैसा टूट गया है, मिला हुआ विश्वास।
अब सुख सूरज रोज सबेरे, उगने लगा उदास।।
महल आसमाँ चढ़े झोपड़ी, थककर बैठ गई है।
झूठ बात समता की सुनकर, मन पर चोट हुई है।।
ऐसे में यह लोकतन्त्र का, फीका लगता राग।
अरे! देश के रखवाले तू, जाग सके तो जाग।।
तिनका-तिनका प्रजातन्त्र है, राजनीति दल-दल में।
जनता भटक गई नारों के, झंडों के जंगल में।
कुर्सी की सत्ता चुनाव का, केवल करती सोच।।
मांसहीन गाँधी की काया, यही खा गई नोंच।
खादी जैसी आजादी पर, बढ़ते जाते दाग।।
अरे! देश के रखवाले तू, जाग सके तो जाग।।
शासन की ऊँची कुर्सी तक, भ्रष्टाचार पहाड़।
सभी झूठ को छिपा रहे हैं, ले तिनके की आड़।।
नेता अधिकारी शोषण का, नया खेलते खेल।
इस धरती के आम्रकुंज पर अमर छा गई बेल।।
कोयल नहीं कहीं दिखती है, उड़ते हैं सब काग।
अरे! देश के रखवाले तू, जाग सके तो जाग।।
जिसकी लाठी भैंस उसी की, यही आज का न्याय।
स्वयं खेत की बागड़ अब तो, खड़ी फसल खा जाय।।
कैसी है आतंक व्यवस्था, सच पर करती चोट।
असली अपराधी छिप जाते, ले कानूनी ओट।।
आस्तीन की वामी में छिप, दूध पी रहे नाग।
अरे! देश के रखवाले तू, जाग सके तो जाग।।

-(सन्तचेतना, धर्म एवं राजनीति : वैकल्पिक चिन्तन)

अर्चन उनका सत्यपंथ पर अडिग सदा जो रहते।
अर्चन उनका अनाचार को जो न मूक हो सहते।।
अर्चन उनका जो दुष्टों को दण्ड यथोचित देते।
अर्चन उनका जो समाज की पीड़ा को हर लेते।।
माननीय वे अखिल विश्व से जो बन्धुत्व निभाते।
माननीय वे जो अन्तस का सबको प्यार लुटाते।।
माननीय वे पाठ एकता का सदैव जो पढ़ते।
माननीय वे जो दलितों के त्राण हेतु हैं बढ़ते।।
उन्हें प्रणाम त्याग तप का जो शुभादर्श रखते हैं।
उन्हें प्रणाम सुधा-वसुधा को दे जो विष चखते हैं।।
उन्हें प्रणाम लोकहित में जो जीवन अर्पित करते।
उन्हें प्रणाम स्वयं जलकर जो, तिमिर जगत का हरते।।
अभिनन्दन उनका जो शूलों में भी राह बनाते।
अभिनन्दन उनका जो कष्टों में भी हैं मुस्काते।।
अभिनन्दन उनका जो विघ्नों से भी कभी न डरते।
अभिनन्दन उनका संघर्षों का जो स्वागत करते।।
वे ही श्लाघ्य कभी विपदा में धैर्य नहीं जो खोते।
वे ही श्लाघ्य दुःखों का गुरुतर भार सहज जो ढोते।।
वे ही श्लाघ्य जिन्होंने अपना साहस कभी न छोड़ा।
वे ही श्लाघ्य जिन्होंने भय से नाता कभी न जोड़ा।।
पूज्य वही आभूषण जिनका वीर्य-पराक्रम होता।
पूज्य वही जो सत्यसिन्धु में सदा लगाते गोता।।
पूज्य वही जो बल-पौरुष की मूर्ति स्वयं बन जाते।
पूज्य वही धीरता-वीरता जो सदैव दिखलाते।।
वे आराध्य न्याय की रक्षा होती जिनके द्वारा।
वे आराध्य दीन-दुखियों को जिनसे मिले सहारा।।
वे आराध्य परोपकार में जिनको सुख मिलता है।
वे आराध्य प्रीति का जिनमें सरस सुमन खिलता है।।
वे श्रद्धेय स्वकर्तव्यों से जो न विमुख होते हैं।
वे श्रद्धेय बीज उन्नति का जो जग में बोते हैं।।
वे श्रद्धेय मनुजता को जो उसके स्वत्व दिलाते।
वे श्रद्धेय अनीति-अनय को जो समाप्त कर जाते।।
धन्य-धन्य वे इतिहासों के बनते जो निर्माता।
धन्य-धन्य वे जो धरती के बनते भाग्यविधाता।।
धन्य-धन्य जो काल-कसौटी पर निज को कसते हैं।
धन्य-धन्य वे महापुरुष के जिनमें गुण बसते हैं।।

-(जयसुभाष, रचयिता : विनोदचन्द्रपाण्डेय, मा.शि.प.उ.प्र.)

वक्त की गर्दन पे इतनी तेज तलवारें न तान।
कत्ल हो जाएगा माँझी चीखता है वर्तमान।।
इस तरह से मिट रहे जैसे पड़े हों रेत पर।
युगपुरुष पैगम्बरों के पाँव के पावन निशान।।
अब न चिंगारी इबादत की जगाती रूह में।
मंदिरों की आरती हो या कि मस्जिद की अजान।।
विश्व का सर्जक नियन्ता इक अकेला ब्रह्म है।
उपनिषद् का सार ये ही घोषणा करता कुरान।।
एक है अल्लाह लेकिन नाम हैं उसके हजार।
वरुण अग्नि यम कहो या मातरिश्वा गरुत्मान।।
हाँ हमीं ने सबसे पहिले विश्व को चिन्तन दिया।
हमने घोषा सारी दुनिया एक ही है खानदान।।
सैकड़ों सदियाँ चले हैं हमसफर ये एक साथ।
एक साँझे कारवाँ का नाम है हिन्दोस्तान।।
हम लुटे हैं हम पिटे हैं हम हुए खण्डित 'मयूख'।
भेद पैदा कर चलाई जब सियासत की दुकान।।

-(कविवर बशीर अहमद 'मयूख', राजस्थान)

सर ऊँचा करके ये कह दो, अब नंगी तलवारों से।
अपना हक हम छीन के लेंगे कुर्सी के बीमारों से।।
जिस माँ ने अपने बच्चे को जहर पिलाकर मार दिया।
क्या-क्या उम्मीदें थीं या रब उस माँ को सरकारों से।।
कमजोरी को कहें जो ताकत, खुदगर्जी को सरदारी।
क्या रिश्ता है इस मिट्टी का ऐसे कुछ सरदारों से।।
जो सीनों में सूरज रख दे, सर काटे तारीकी का।
माँग रहे हैं हम वो ताकत, आज सभी अखबारों से।।
अब तक 'अंजुम' कई नशेमन जिन्हें छुपाकर बैठे हैं।
राजमहल भी जल सकते हैं, ऐसे कुछ अंगारों से।।

-(सरदार 'अंजुम', पंजाबकेसरी)

ऐ मेरे वतन के नेताओं तुम भी तो करो कुछ कुर्बानी।
लोगों ने तो आँखें भर ली हैं तुम चुल्लू में भर लो पानी।।
यह आयाराम और गयाराम बहुरूप तुम्हारे यह भी हैं।
ये मरियल अधनंगे बच्चे ये सूखे सिकुड़े मर्दोजन।।
देखा है कभी इनकी जानिब फाँकों के मारे ये भी हैं।
दो चार वर्ष जो गुजरे हैं थी तुम्हें लगन बस नोटों की।।
आया चुनाव का मौसम तो है फिक्र तुम्हें बस वोटों की।।

-(डा. रतनचन्द, एम.बी.बी.एस., 124-एच.ब्लाक, श्रीगंगानगर राजस्थान, पंजाबकेसरी, 18/09/2003)

जियो बहादुर खद्दरधारी,
काटो मजा खूब सरकारी।
मंत्री जी की गाड़ी आए,
सड़क बेचारी चूना खाए।
तेरी जय हो गंगा मइया,
सबसे बड़ा रुपइया भइया।
दोनों में अब खूब बन रही,
चुपके-चुपके रोज छन रही।
तुकाराम को पता चला है,
चड्डी पहनके फूल खिला है।
दोस्त हो रहे दुश्मन जानी,
गिर जाएगा आँख का पानी।
जनता अन्धी नहीं है प्यारे,
देख रही है वारे-न्यारे।
जब चुनाव शिर पर आएगा,
कुर्ते पर संकट छाएगा।
नहीं चलेगी तीरंदाजी,
पोल खुलेगी बासी-ताजी।
मंगल भवन अमंगलहारी,
जनता ही पड़ती है भारी।
जियो बहादुर खद्दरधारी।

-(तुकाराम; दैनिकजागरण, देहरादून, 26/07/2003)

शृंगारहीन विधवा के जैसा गाँव ये उजड़ा रहता था।
कीचड़ वाला गन्दा पानी मुख्य सड़क पर बहता था।।
आवारा कुत्ते शान से कूड़ा सड़कों पर फैलाते थे।
मक्खी मच्छर कीचड़ का पूरा आनन्द उठाते थे।।
किन्तु मुख्यमन्त्री के दौरे का फरमान जो आया है।
तुरन्त उन्होंने गन्दी सड़कों को दुल्हन बनवाया है।।
तुरत-फुरत आनन-फानन अफसर हरकत में आए हैं।
डरे हुए थे कहीं-कहीं पर त्रुटियाँ न मिल जाए हैं।।
कटे-फटे बिजली के तारों में सुधार करवाया है।
पड़े हुए बेकार मलों को शीघ्र ठीक करवाया है।।
बाद मुद्दतों सड़कों पर सबने झाड़ू लगते देखी।
यातायात सुचारू करके सही व्यवस्था भी दे दी।।
धन्यवाद है मन्त्री जी का गाँव साफ करवाने का।
वादा करिए जल्दी से जल्दी फिर वापस आने का।।

-(शालिनी, मोदीनगर, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 15/07/2003)

वो होठ कि जिनकी जुम्बिश से, वो जिनकी आँख की लरजिश से।
कानून बदलते रहते हैं और मुजरिम पलते रहते हैं।
उन चोरों के सरदारों से इंसाफ के पहरेदारों से।
जो औरत को नुचवाते हैं, बाजार की जिन्स बनाते हैं।
फिर उसकी अस्मत के गम में, तहरीकें भी चलवाते हैं।
उन जालिम और बदमाशों से, बाजार के उन मयमारों से।
मैं बागी हूँ मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो।
मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत की खातिर जिन्दा हूँ।
मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा-बच्चा बोलेगा।
मैं बागी हूँ मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो।

-(एक पाकिस्तानी शायर)

राजनीति उस तवायफ के समान है,
जो हर किसी से हमबिस्तर होती है,
पर मोहोब्बत को नहीं पहचानती,
क्योंकि इसकी नजर में इंसान कुछ भी नहीं,
जो कुछ है पैसा है, सियासत है,
और एक कभी न बुझने वाली प्यास,
जो सबकुछ पीकर भी कभी शान्त नहीं होती।

-(एक कवि)

खून अपना हो या पराया हो, नस्ले आदम का खून है आखिर।
जंग मगरिब में हो या मसरिक में, अपने आलम का खून है आखिर।
बम घरों पे गिरें या सरहद पर, रूहे तामीर जख्म खाती है।
खेत अपने जलें या गैरों के जीस्त फाँकों से तिलमिलाती है।
बम घरों पे गिरें या सरहद पर, कोख धरती की बाँझ होती है।
फतह का जश्न हो या हार का सोग, जिन्दगी मय्यतों पे रोती है।
जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसअलों का हल देगी।
आग और खून आ बख्शेगी, भूख और इम्तिहान कल देगी।।
इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है।
आप और हम सभी के आँगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है।।

-(साहिर लुधियानवी)

हे भारतवासियों! सुन लो खोलकर अपने-अपने कान।
दुनिया के भ्रष्टतम देशों में नम्बर चार पर पहुँच गया है हिन्दुस्तान।
लूट खसोट हत्या बलात्कार कालाबाजारी यहाँ कर रहे हैं इंसान।।
अरबों खरबों के घोटाले कर रहे हैं भ्रष्ट अधिकारी और नेता महान।
कोईभी भयंकर अपराधी और दागी मन्त्री बनो, छूट देता है संविधान।।
कुर्सी पाकर करें ऐसे नीच कर्म खोटे धन्धे कि देखकर शमिन्दा हो जाए शैतान।
जागो वतन के लोगों! अब तो बदलो बाबा ब्राण्ड संविधान।।
अब भी यदि निद्रा में सोए रहोगे तो क्षमा नहीं करेंगे श्री भगवान।
देश को लूट-लूट कर खा रहे हैं पंचवर्षीय भिखारी, इनसे हो जाएँ सावधान।।

-(वेदप्रकाशशर्मा, हापुड़; आवाज-ए-खबरदार, पंजाबकेसरी, दिल्ली, 25/02/2005)

कब तक काली रात ढलेगी, धरती नूर को यह तरसेगी।
कब तक ये गद्दार बचेंगे, और सियासत धोखा देगी।।
सारी खलकत बूँद को तरसे, इक छत पर बारिश बरसेगी।
कब तक चुप ये होठ रहेंगे, कब तक आह नहीं निकलेगी।।
कब तक बाजू बँधे रहेंगे, कब तक गरदन झुकी रहेगी।।
कभी न तुमको मिलेगी मंजिल, सदा अँधेरों में तुम रहोगे।।
अगर बचाना हो मुल्क अपना, तो सारे रस्मोरिवाज बदलो।।
निजामे नौ से हर इक सतह पर, समाज बदलो समाज बदलो।।

-(एक शायर)

सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है?
इस देश में हर युवा परेशान सा क्यों है?
आँखों में निराशा है मुख पर है अविश्वास।
हाथों में हाई डिग्री फिर भी है बेरोजगार।
इतनी है ज्ञानराशि तो मोहताज सा क्यों है?
मेहनत के बावजूद भी जीवन में ठोकरें हैं।
अमीरों के लिए ही क्यों महफिल हैं ओहदे हैं?
खुशियों में भी हर शख्स ये हैरान सा क्यों है?
भगवान गर है एक तो झगड़े फसाद क्यों?
ज्ञानी गुलाम क्यों है अज्ञानी सरताज क्यों?
इंसान के हर वेश में शैतान सा क्यों है?

-(मृदुला मेहरा, बाँकनेर, दिल्ली)